आई आई एफ सी एल
IIFCL

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

भविष्य की नींव का निधिकरण...



वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

दृष्टि (विजन)

भारत में विश्व स्तरीय अवसंरचना के संवर्धन व विकास के लिए नवोन्मेषी वित्तपोषण के साधन उपलब्ध कराना।

लक्ष्य (मिशन)

अवसंरचना क्षेत्र के वित्त पोषण में सर्वोत्तम पद्धतियां अपनाना एवं अवसंरचना क्षेत्र के विकास को सुविधापरक बनाते हुए मूल क्षमताओं का विकास करना। व्यावसायिक तरीके में सेवाएं प्रदान करने एवं सभी हितधारकों की संतुष्टि के लिए अत्यंत समर्पित कर्मचारीगण की टीम तैयार करना।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड
एफसीआरएन : 06496661
तीसरी मंजिल, 72 किंग विलियम स्ट्रीट
लंदन EC4N 7HR, यूनाइटेड किंगडम
फोन : सामान्य पूछताछ: +44-20-7776 8950
ईमेल : info@iifc.org.uk
वेबसाइट : www.iifc.org.uk

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
सीआईएन : U74999DL2012GOI231473
पंजीकृत कार्यालय : पाँचवीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट A, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110 023
फोन : +91-11-2465573
ईमेल आईडी : contact@iifclprojects.com
वेबसाइट : www.iifclprojects.com

आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
सीआईएन : U65991DL2012GOI233601
पंजीकृत कार्यालय : पाँचवीं मंजिल, ब्लॉक 2, प्लेट A, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110 023
फोन : +91-11-24665900-10
ईमेल : complianceofficer@iifclmf.com
वेबसाइट : www.iifclmf.com



वार्षिक रिपोर्ट
2025-26

आई आई एफ सी एल
IIFCL

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

भारत सरकार का एक उद्यम

21वीं

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक

दिन: सोमवार • **दिनांक:** 28 सितंबर 2026 • **समय:** दोपहर 12:30 बजे

स्थान: कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

पंजीकृत कार्यालय

5वीं मंज़िल, ब्लॉक 2, प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टावर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
फ़ोन: +91-11-24662777 • वेबसाइट: www.iifcl.in
सीआईएन: U67190DL2006GOI144520

बैंकर

- आईडीबीआई बैंक
- भारतीय स्टेट बैंक
- पंजाब एंड सिंध बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- बैंक ऑफ इंडिया
- सेंट्रल बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- केनरा बैंक
- महाराष्ट्र बैंक
- पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
- साउथ इंडियन बैंक
- यूको बैंक
- जम्मू एंड कश्मीर बैंक
- एचडीएफसी बैंक
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- फेडरल बैंक
- एक्सिस बैंक
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक
- इंडसइंड बैंक
- आईसीआईसीआई बैंक

न्यासी

विस्ट्रा आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड
(पहले आईएलएंडएफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सेंटर, प्लॉट सी-22, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा (पू.) मुंबई-400051, फ़ोन: +91-22-26593215
ईमेल: vivek.choudhary@ilfsindia.com
वेबसाइट: www.vistra.com

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विस लिमिटेड
एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 17आर, कमानी मार्ग बैलार्ड एस्टेट,
मुंबई-400001,
फ़ोन: +91-22-40807000, ईमेल: deepakkumar@idbitrustee.com
वेबसाइट: www.idbitrustee.com

बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड
4सी और डी सिद्धिविनायक चैंबर्स, गांधी नगर, एमआईजी क्रिकेट क्लब के सामने,
बांद्रा ईस्ट (पू.), मुंबई – 400051 टेलीफ़ोन: +91-22-26558759
ईमेल: compliance@beacontrustee.co.in
वेबसाइट: www.beacontrustee.co.in

कैटलिस्ट ट्रस्टीशिप लिमिटेड
जीडीए हाउस, पहली मंज़िल, प्लॉट नंबर 85, S. No. 94 &95,
भुसारी कॉलोनी (दाएं) कोथरूड पुणे-411038
टेलिफोन नंबर 022-43029101, ईमेल: dt@ctltrustee.com
वेबसाइट: www.catalysttrustee.com

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स एडीबी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या: 005593C)
फ्लैट संख्या 42, सनव्यू अपार्टमेंट, सेक्टर 11,
पॉकेट 4, द्वारका, दिल्ली – 110075

मैसर्स एबीपी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(फर्म पंजीकरण संख्या: 315104E)
आर-13, तृतीय तल, राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली – 110027

सचिवीय लेखा परीक्षक

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली – 110054

विषय सूची

आई आई एफ सी एल
IIFCL

प्रबंध निदेशक की ओर से 2

11 वार्षिक आम बैठक की सूचना

बोर्ड की रिपोर्ट 17

100 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 121

123 स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ 240

244 समेकित वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरण 256

353 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ





प्रबंध निदेशक के डेस्क से

देवियों और सज्जनों

भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी वित्तीय प्रणाली ने महत्वपूर्ण बाहरी झटकों के बावजूद उल्लेखनीय मजबूती का प्रदर्शन किया है, जो देश के व्यापक आर्थिक आधार, संस्थागत ढांचे और नीतिगत प्रतिक्रिया तंत्र की मजबूती को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर, घरेलू मांग के समर्थन से भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जबकि मुद्रास्फीति निर्धारित लक्ष्य के दायरे में बनी हुई है। बैंकों और गैर–बैंकिंग संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर्याप्त पूंजी और चलनिधि उपलब्धता के साथ मजबूत बनी हुई है, जिससे वित्तीय झटकों के वास्तविक अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का जोखिम सीमित हो रहा है।

भारत की आर्थिक यात्रा निरंतर मजबूती, स्थिरता और अवसंरचना–आधारित विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से परिभाषित होती रही है। जैसे–जैसे देश विकसित भारत/2047 के विजन की ओर आगे बढ़ रहा है, अवसंरचना सतत आर्थिक विकास, बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता और समावेशी समृद्धि की आधारशिला बनी हुई है। भारत सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय पर लगातार दिए जा रहे जोर के साथ–साथ निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी ने परिवहन, ऊर्जा, शहरी विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना के अन्य उभरते उप–क्षेत्रों में विश्वस्तरीय अवसंरचना के निर्माण के अवसर पैदा किए हैं।

अवसंरचना वित्तपोषण का परिदृश्य महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आने वाले दशकों में आवश्यक निवेश के स्तर को देखते हुए ऐसे वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता है, जो पारंपरिक बैंक ऋण से आगे हों। पेंशन निधि, बीमा कंपनियां, संप्रभु संपत्ति निधियां और वैश्विक अवसंरचना निवेशकों सहित संस्थागत पूंजी से भारत की दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। इस संदर्भ में, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की बाजार की कमियों को दूर करने, जोखिमों को कम करने और निवेश योग्य अवसर विकसित करने की विशेष जिम्मेदारी है।

इस बदलते परिदृश्य में, आईआईएफसीएल अवसंरचना वित्तपोषण के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है। भारत की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं के साथ मजबूती से जुड़ी यह कंपनी, मजबूत और निरंतर व्यावसायिक विस्तार के माध्यम से देश की अवसंरचना विकास यात्रा को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है।

सातत्यता अवसंरचना विकास का अभिन्न हिस्सा है। भारत का स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों, जलवायु–सक्षम अवसंरचना और संसाधन–कुशल विकास की दिशा में बदलाव हरित निवेश के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। आईआईएफसीएल जिम्मेदार वित्तपोषण पद्धतियों, पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) सिद्धांतों के समावेशन तथा वैश्विक स्तर पर स्वीकृत सततता मानकों को अपनाने के माध्यम से पर्यावरणीय रूप से संधारणीय अवसंरचना को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मानना है कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ–साथ आगे बढ़ना चाहिए।

प्रौद्योगिकी और संस्थागत उत्कृष्टता हमारे रूपांतरण के एजेंडे के केंद्र में बनी हुई हैं। वर्ष के दौरान, हमने अपनी डिजिटल प्रक्रियाओं को और मजबूत किया, आंकड़ा–आधारित निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाई, जोखिम प्रबंधन ढांचे को उन्नत किया और परिचालन दक्षता में सुधार किया। मानव पूंजी, अभिशासन और नवाचार में निवेश ने हमें एक अधिक चुस्त, उत्तरदायी और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार संस्थान बनाने में सक्षम बनाया है, जो अवसंरचना क्षेत्र की बदलती जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आईआईएफसीएल ने मजबूत वित्तीय अनुशासन और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन को बनाए रखते हुए अपनी विकास यात्रा जारी रखी। कंपनी ने राजमार्गों, हवाई अड्डों, विद्युत, नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी अवसंरचना और भारत की विकास आकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अन्य क्षेत्रों में अपना समर्थन बढ़ाया।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए आईआईएफसीएल की 21वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह वर्ष कंपनी के लिए असाधारण प्रदर्शन का एक और वर्ष रहा, जो अवसंरचना वित्तपोषण गतिविधियों में निरंतर वृद्धि, ऋण पोर्टफोलियो के निरंतर विस्तार, मजबूत परिचालन प्रदर्शन और आस्ति गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है।

आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान ₹57,680 करोड़ की अब तक की सर्वाधिक वार्षिक स्वीकृतियां दर्ज कीं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% की वृद्धि है, जबकि

वार्षिक संवितरण में वर्ष–दर–वर्ष 16% की वृद्धि हुई और यह ₹32,972 करोड़ रहा। 31 मार्च, 2026 तक संचयी स्वीकृतियां और संवितरण क्रमशः ₹3,64,491 करोड़ और ₹1,89,476 करोड़ रहे, जो देशभर में अवसंरचना निर्माण के लिए निरंतर वित्तपोषण सहायता को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अपनी मुख्य वित्तपोषण गतिविधियों में मजबूती का प्रदर्शन किया। कंपनी की परिचालन आय पिछले पांच वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2021–22 के ₹3,618 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹6,962 करोड़ हो गई। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान ₹1,984 करोड़ का कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) और ₹1,379 करोड़ का कर–पश्चात लाभ (पीएटी) दर्ज किया। आईआईएफसीएल की निवल संपत्ति पिछले वर्ष के ₹16,395 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹17,898 करोड़ हो गई, जो कंपनी के पूंजी आधार और ऋण देने की क्षमता में निरंतर मजबूती को दर्शाती है।

आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अपनी आस्ति गुणवत्ता में और सुधार किया, जिसमें सकल एनपीए पिछले वर्ष के 1.11% से घटकर 0.40% हो गया, जबकि निवल एनपीए 100% प्रावधान कवरेज अनुपात के साथ शून्य हो गया। बाहरी ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा 'ए' श्रेणी और उससे ऊपर की रेटिंग वाली आईआईएफसीएल की आस्तियों का अनुपात 31 मार्च, 2025 के लगभग 93% की तुलना में 31 मार्च, 2026 को बढ़कर लगभग 96% हो गया। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में लगभग ₹880 करोड़ के एनपीए की महत्वपूर्ण वसूली भी की।

अप्रैल 2026 में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक विशेष प्रयोजन माध्यम के जरिए व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना, जिसे सामान्यतः एसआईएफटीआई के रूप में जाना जाता है, को बंद किए जाने के बाद, आईआईएफसीएल में अधिक परिचालन स्वतंत्रता, वित्तपोषण समाधान तैयार करने में लचीलापन और विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं में व्यापक भागीदारी के माध्यम से तेजी से विकास होने की उम्मीद है। यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है, जिससे नए और नवोन्मेषी ऋण उत्पादों के माध्यम से ऋण विस्तार को तेजी से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अब, मैं सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और अवसंरचना क्षेत्र का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि इसका आपकी कंपनी की भविष्य की संभावनाओं पर प्रभाव पड़ता है।

आर्थिक विहंगावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत निजी उपभोग और स्थिर निवेश की मदद से वित्तीय वर्ष 2025–26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की (पिछले तीन वर्षों में औसत वृद्धि 7.3%)। जून 2026 के अधिकांश उच्च आवृत्ति वाले संकेतक आर्थिक गतिविधियों में निरंतर मजबूती की ओर संकेत करते हैं, जिससे पता चलता है कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वित्तीय वर्ष 2026–27 की पहली तिमाही में वृद्धि मजबूत बनी रही। हालांकि, आयातित तेल और अन्य प्रमुख वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ऊर्जा मूल्य संबंधी झटकों और आपूर्ति–श्रृंखला में व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। इसके अलावा, वैश्विक वृद्धि में कमजोरी से वित्तीय वर्ष 2026–27 में भारत की घरेलू वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस पृष्ठभूमि में, भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है।

मुद्रास्फीति नियंत्रित बनी हुई है, हालांकि हाल के महीनों में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। समग्र मुद्रास्फीति मई 2026 में 3.9% से बढ़कर जून 2026 में 4.4% हो गई, जो अन्य बातों के साथ–साथ तेल की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव उपभोक्ताओं तक पहुंचने में हुई बढ़ोतरी को दर्शाती है। हालांकि, संकट के कारण उत्पन्न आपूर्ति संबंधी झटका और कमजोर मानसून के अनुमान से चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति सहनशीलता सीमा के ऊपरी स्तर तक बढ़ सकती है।

भारतीय रुपया (आईएनआर) पिछले कई महीनों से भू–राजनीतिक तनाव, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनिश्चितता और निवेशकों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे उभरते क्षेत्रों के प्रति प्राथमिकता के कारण लगातार दबाव में रहा है। पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा हाल ही में किए गए उपायों के साथ–साथ कच्चे तेल की कीमतों में कमी से भारतीय रुपये के प्रति बाजार धारणा में सुधार होने की उम्मीद है। समग्र भुगतान संतुलन (बीओपी) में घाटे के बावजूद, विभिन्न संकेतकों के आधार पर भारत का बाह्य क्षेत्र सहज स्थिति में बना हुआ है।

बैंकिंग और वित्त क्षेत्र

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) मजबूत पूंजी और चलनिधि उपलब्धता के सहारे मजबूत बने रहे। आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार हुआ, जिसमें अनर्जक आस्तियों के अनुपात में कई दशकों के न्यूनतम स्तर तक गिरावट आई, जबकि लाभप्रदता स्थिर बनी रही। वित्तीय वर्ष 2025–26 की दूसरी छमाही के दौरान ऋण और जमा वृद्धि में गति आई।

एससीबी की ऋण वृद्धि वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान वर्ष–दर–वर्ष 14.5% तक बढ़ी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की तुलना में लगातार अधिक वृद्धि दर्ज करते रहे। मार्च 2026 में एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ, जिसमें जीएनपीए अनुपात घटकर कई दशकों के न्यूनतम 1.8% स्तर पर आ गया। पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक स्लिपेज अनुपात में लगातार कमी आई और वित्तीय वर्ष 2025–26 में यह 1.2% रहा, जिसका कारण पीएसबी और पीवीबी में ह्रासित आस्तियों में नई वृद्धि का कम होना रहा। अधिक ऋण मात्रा के समर्थन से, मार्च 2026 में एससीबी की निवल ब्याज आय (एनआईआई) में वर्ष–दर–वर्ष 4.0% का मामूली सुधार दर्ज किया गया।

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) मजबूत पूंजीकरण, स्वस्थ लाभप्रदता और बेहतर होती आस्ति गुणवत्ता के सहारे वित्तीय रूप से मजबूत बनी रहीं, हालांकि गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (उच्च और मध्यम स्तर) की समग्र ऋण वृद्धि मार्च 2026 में वर्ष–दर–वर्ष घटकर 16.6% रह गई। गैर–बैंकिंग वित्तीय

कंपनियों – अवसंरचना वित्त कंपनियों (एनबीएफसी–आईएफसी) ने 11.6% की ऋण वृद्धि दर्ज की और एनबीएफसी ऋण में 35.2% हिस्सेदारी के साथ दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी बनाए रखी।

अवसंरचना क्षेत्र एवं वित्तपोषण प्रवृत्तियाँ

भारत भौतिक, डिजिटल और सामाजिक क्षेत्रों में व्यापक प्रयासों से प्रेरित होकर अवसंरचना विकास के एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहा है। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के प्रमुख साधन के रूप में पहचाने जाने के कारण, अवसंरचना को देश के विकास एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। इसे आगे बढ़ाते हुए, वित्तीय वर्ष 2026–27 के केंद्रीय बजट में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में लगभग 9% की वृद्धि दर्शाता है। यह निरंतर वृद्धि भारत सरकार की अवसंरचना–आधारित विकास के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.3% पर रखा गया है, जबकि सकल बाजार उधारी ₹17.2 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जिससे अवसंरचना वित्तपोषण को निरंतर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

केंद्रीय बजट 2025–26 में की गई घोषणा के अनुपालन में, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने जनवरी 2026 में तीन वर्षीय सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना पाइपलाइन जारी की, जिससे निवेशकों, विकासकर्ताओं और अन्य हितधारकों को संभावित पीपीपी परियोजनाओं की अग्रिम जानकारी उपलब्ध हुई। इस पाइपलाइन में केंद्रीय अवसंरचना मंत्रालयों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 850 से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत (टीपीसी) ₹17 लाख करोड़ से अधिक है। क्षेत्रवार, इस पाइपलाइन में परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स (368 परियोजनाएं), सामाजिक एवं वाणिज्यिक अवसंरचना (258 परियोजनाएं), जल एवं स्वच्छता (143 परियोजनाएं) और ऊर्जा (95 परियोजनाएं) शामिल हैं। इसके अलावा, गतिशक्ति, समुद्री दृष्टिकोण, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति, राष्ट्रीय रेल दृष्टिकोण और उड़ान योजना जैसे परिवर्तनकारी कार्यक्रम सामूहिक रूप से भारत के अवसंरचना परिदृश्य को नया स्वरूप दे रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, पूर्ण हो चुकी और राजस्व अर्जित करने वाली अवसंरचना आस्तियां निश्चित आय बाजार में एक अलग आस्ति वर्ग के रूप में तेजी से उभर रही हैं। इस संदर्भ में, सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2029–30 के बीच सड़कों, रेलवे, विद्युत, तेल एवं गैस, नागरिक उड्डयन, बंदरगाहों, दूरसंचार, कोयला और खनन सहित प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक आस्तियों के परिचालन से ₹16.7 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें निजी क्षेत्र का ₹5.8 लाख करोड़ का निवेश शामिल है। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने भी वित्तीय वर्ष 2025–26 में टोल–ऑपरेट–ट्रांसफर (टीओटी), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) और प्रतिभूतिकरण मॉडल के माध्यम से आस्तियों के मुद्रीकरण के लिए 1,472 किलोमीटर राजमार्गों की भावी आस्ति पाइपलाइन जारी की है। पांच औद्योगिक क्षेत्रों – विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरियों और रसायनों – में कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण (सीसीयूएस) प्रौद्योगिकियों के लिए पांच वर्षों में ₹20,000 करोड़ के परिव्यय का भी प्रस्ताव किया गया है, जिससे हरित अवसंरचना वित्तपोषण का एक नया अवसर खुल रहा है।

केंद्रीय बजट 2026–27 में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को और विकसित करने के लिए बाजार–निर्माण ढांचे सहित सुधार भी किए गए हैं। इसके अलावा, ₹1,000 करोड़ से अधिक का एकल नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाले शहरों के लिए ₹100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव किया गया है, जिससे उप–संप्रभु अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा मिलेगा।

अवसंरचना परियोजनाओं को अक्सर शुरुआती चरण में परियोजना निर्माण एवं विकास संबंधी जोखिम, देरी और क्रियान्वयन में अनिश्चितता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों के समाधान के लिए, सरकार ने केंद्रीय बजट 2026–27 में अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि की शुरुआत की, ताकि निवेशकों का विश्वास मजबूत हो और परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके। यह निधि ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी प्रदान करेगी, जिससे परियोजना वित्तपोषण को समर्थन मिलेगा।

समानांतर रूप से, अवसंरचना वित्तपोषण की गतिशीलता में बदलाव आ रहा है, जिसमें एनबीएफसी–विशेष रूप से एनबीएफसी–आईएफसी–प्रमुख संस्थाओं के रूप में उभर रही हैं। आईसीआरए अनुसंधान के अनुसार, अब अवसंरचना ऋण में एनबीएफसी की हिस्सेदारी 57% है, जबकि बैंकों की हिस्सेदारी 43% है। वित्तीय वर्ष 2026 में समग्र अवसंरचना ऋण वृद्धि बढ़कर 10% हो गई, जो वित्तीय वर्ष 2025 में यह 6.8% थी। बैंकों के अवसंरचना ऋण में 13% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि एनबीएफसी–आईएफसी के ऋण बही में 8% की वृद्धि हुई।

महत्वपूर्ण रूप से, एनबीएफसी–आईएफसी की आस्ति गुणवत्ता में लगातार सुधार हुआ है। एनबीएफसी–आईएफसी की सकल शुद्ध अनर्जक आस्तियां मार्च 2025 के 1.2% से घटकर मार्च 2026 में 0.6% हो गईं। यह सुधार कुछ दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान/वसूली और बट्टे खाते में डालने, ऋण बही में वृद्धि तथा सीमित गिरावट के कारण हुआ।

आगे देखते हुए, एनबीएफसी–आईएफसी अवसंरचना ऋण वृद्धि का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। आईसीआरए ने वित्तीय वर्ष 2027 में 10–12% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसे भारत सरकार के अवसंरचना क्षेत्र पर जोर के कारण अवसंरचना क्षेत्र में स्वस्थ गतिविधियों तथा एनबीएफसी–आईएफसी की मजबूत होती वित्तीय स्थिति का समर्थन मिलेगा।

अवसंरचना क्षेत्र में क्षेत्रवार निष्पादन की प्रमुख झलकियाँ

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान प्रमुख अवसंरचना उप–क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय विकास और आगे की दिशा इस प्रकार है:

सड़क और राजमार्ग

वित्तीय वर्ष 2025–26 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा लगभग 7,000 किलोमीटर सड़कों के लिए ठेके प्रदान किए गए, जो वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रदान किए गए 7,538 किलोमीटर के ठेकों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम हैं। इसका कारण परियोजनाओं के ठेके प्रदान करने से पहले भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों और पर्यावरणीय मंजूरियों के समाधान पर मंत्रालय का ध्यान केंद्रित करना रहा। वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमान में बजटीय आवंटन में 8% की वृद्धि के साथ, वित्तीय वर्ष 2026–27 में एमओआरटीएच द्वारा ठेके प्रदान करने की गतिविधि बढ़कर 8,000–8,500 किलोमीटर होने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में एमओआरटीएच द्वारा सड़क निर्माण की गति लगभग 9,000–9,500 किलोमीटर पर स्थिर रहने की उम्मीद है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025–26 में यह 9,350 किलोमीटर थी। इसका कारण पिछले दो वर्षों में परियोजनाओं के लिए ठेके प्रदान करने की गति में कमी और पश्चिम एशिया संकट के बाद बिटुमेन की कीमतों में वृद्धि है। एचएएम और ईपीसी परियोजनाओं के लिए बोली संबंधी मानदंडों को हाल में सख्त करना एमओआरटीएच का एक सकारात्मक कदम है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में मुद्रास्फीति से जुड़ी टोल दर में वृद्धि नई परियोजनाओं के लिए 3.4% और पुरानी परियोजनाओं के लिए 4.0% रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025–26 में यह 2.3–4.0% थी। टोल दरों में अधिक वृद्धि के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2026–27 में टोल संग्रह की वृद्धि घटकर 6–8% रहने की संभावना है, जबकि वित्तीय वर्ष 2025–26 में यह 10% थी। इसका कारण यातायात में वृद्धि का वित्तीय वर्ष 2025–26 के 6% की तुलना में घटकर 3–4% रहना है।

एनएमपी 2.0 के तहत, सड़क क्षेत्र का हिस्सा ₹4.14 लाख करोड़ है, जो कुल मुद्रीकरण लक्ष्य का 25% है। एनएचएआई ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए आस्ति मुद्रीकरण का लक्ष्य ₹30,000–35,000 करोड़ निर्धारित किया है। आस्तियों की मजबूत सूची और मुद्रीकरण के बढ़ते अवसरों के साथ, मध्यम अवधि में यह गतिविधि मजबूत बने रहने की उम्मीद है।

विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र

विद्युत क्षेत्र अवसंरचना का एक मौलिक स्तंभ और आर्थिक विकास का एक प्रमुख प्रेरक है। 31 मार्च, 2026 तक, देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के 475 गीगावाट से बढ़कर 526 गीगावाट हो गई। नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) का विस्तार लगातार अग्रणी बना हुआ है और वित्तीय वर्ष 2025 में जोड़ी गई 34.1 गीगावाट से अधिक क्षमता तक पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2026 में क्षमता वृद्धि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सबसे अधिक रही, जिसके बाद ताप विद्युत क्षेत्र का स्थान रहा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि को परियोजनाओं की प्रस्ताव सूची उल्लेखनीय विस्तार, सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल की कम कीमतों और जून 2025 से अंतर–राज्यीय पारेषण शुल्क से छूट समाप्त होने की संभावना का समर्थन मिला है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2027 में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा 1.5 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता भी जोड़े जाने की उम्मीद है, (जिसमें से 700 मेगावाट क्षमता पहले ही चालू हो चुकी है)। वित्तीय वर्ष 2027 में पूरे वर्ष के लिए सकल क्षमता वृद्धि लगभग 50 गीगावाट रहने का अनुमान है, जबकि वित्तीय वर्ष 2026 में यह 61.6 गीगावाट थी। यह मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि को बढ़ाने के कारण होगा।

विद्युत क्षेत्र के पारेषण खंड के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा अधिसूचित एनईपी में बढ़ती मांग को पूरा करने और देश के महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) क्षमता लक्ष्यों को समर्थन देने के लिए भारत की पारेषण अवसंरचना के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। प्रमुख पहलों में अंतर–क्षेत्रीय पारेषण क्षमता में वृद्धि और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों का एकीकरण शामिल है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को समायोजित करना है। योजना में मार्च 2026 तक 5,06,513 सर्किट किलोमीटर से मार्च 2032 तक पारेषण लाइनों की लंबाई बढ़ाकर 6,48,190 सर्किट किलोमीटर करने और मार्च 2026 तक 1,450 जीवीए से मार्च 2032 तक उपकेंद्र क्षमता बढ़ाकर 2,345 जीवीए करने का प्रस्ताव है। इसके परिणामस्वरूप, अंतर–क्षेत्रीय पारेषण क्षमता मार्च 2026 के 120 गीगावाट से बढ़कर मार्च 2032 तक 168 गीगावाट हो जाएगी।

आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹6,600 करोड़ का संवितरण करके इस बदलाव को समर्थन दिया।

हवाई अड्डे

हवाई अड्डा अवसंरचना में पूंजीगत व्यय के ऊंचे स्तर पर बने रहने की संभावना है, जिसमें अगले 4–5 वर्षों में ₹1,00,000 करोड़ से अधिक के पूंजीगत व्यय की उम्मीद है। इसमें नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के अंतर्गत हवाई अड्डों का विस्तार शामिल है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के हवाई अड्डों पर अगले पांच वर्षों में हैदराबाद और बेंगलुरु सहित ब्राउनफील्ड क्षमता विस्तार की योजना है। संशोधित उड़ान योजना अगले आठ वर्षों में मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करके क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए तैयार है। पहाड़ी, दूरदराज, द्वीपीय और आकांक्षी क्षेत्रों में संपर्क विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है, साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों में परिचालन के लिए एचएएल हेलीकॉप्टरों और डोर्नियर विमानों की खरीद भी की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में यात्री यातायात में 1.9% की मामूली वृद्धि हुई और यह वित्तीय वर्ष 2025 के 412 मिलियन की तुलना में बढ़कर 420 मिलियन हो गया। इस पर भू–राजनीतिक तनाव, विमानों की कम उपलब्धता, उड़ान ड्यूटी समय सीमाओं (एफडीटीएल) के कारण आपूर्ति में व्यवधान और सीमा–पार तनाव का प्रभाव पड़ा। फिर भी, आईसीआरए के अनुमानों के अनुसार, जारी पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2026–27 में यात्री यातायात वृद्धि मामूली रहने की संभावना है। हालांकि, जारी पश्चिम एशिया संकट से यात्री यातायात वृद्धि प्रभावित होने की संभावना है।

रेलवे

भारत की रेलवे अवसंरचना पूंजीगत निवेश, नेटवर्क के त्वरित विस्तार और क्षमता निर्माण के लिए कॉरिडोर–आधारित दृष्टिकोण से प्रेरित होकर निर्णायक बदलाव के दौर से गुजर रही है। वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट में रेल मंत्रालय के लिए कुल परिव्यय लगभग ₹2.78 लाख करोड़ है, जो अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। यह रेलवे में अवसंरचना व्यय पर मजबूत जोर को दर्शाता है।

आधुनिक अवसंरचना और कनेक्टिविटी पर मजबूत ध्यान केंद्रित करते हुए, भारतीय रेलवे आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बेहतर यात्रा अनुभव और कुशल माल ढुलाई सेवाएं प्रदान करते हुए राष्ट्रीय विकास को गति दे रही है। स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए और नवाचार से प्रेरित होकर, रेलवे पर्यावरण–अनुकूल और हरित परिचालन की दिशा में आगे बढ़ रही है, साथ ही बड़े पैमाने पर अवसंरचना में सुधार और क्षमता विस्तार के माध्यम से देश की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने जुलाई 2026 में हरियाणा राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया।

अवसंरचना विकास की गति बनी रही, जिसमें 35 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों को चालू किया गया, जिससे लॉजिस्टिक्स दक्षता और बहु–माध्यमीय एकीकरण में सुधार हुआ। इसके अतिरिक्त, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 119 स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया, जिससे बेहतर सुविधाएं और यात्रियों के अनुभव में सुधार हुआ।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में 100 बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो देशभर में रेलवे नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ₹1.53 लाख करोड़ के पर्याप्त निवेश के साथ, इस पहल के तहत 6,000 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिचालन दक्षता बढ़ाना, कनेक्टिविटी को मजबूत करना और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को समर्थन देना है।

बंदरगाह

कंटेनर और उर्वरक खंडों में मजबूत वृद्धि के समर्थन से, वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल माल ढुलाई मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में 4–5% की वृद्धि दर्ज होने उम्मीद है, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद खंड में दीर्घकालिक 2–4% की प्रवृत्ति के अनुरूप वृद्धि रहने की उम्मीद है।

मैरिटाइम इंडिया विजन (एमआईवी) 2030 में परिकल्पित वृद्धि के अनुरूप नई परियोजनाओं के लिए भी ठेके प्रदान किए जा रहे हैं। बंदरगाह क्षमता और अवसंरचना को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पूंजीगत व्यय की योजना बनाई गई है। आगे चलकर, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की संभावना है। पिछले कुछ वर्षों में बड़े समूहों द्वारा छोटी/स्वतंत्र कंपनियों के अधिग्रहण के साथ इस क्षेत्र में एकीकरण हुआ है और यह प्रवृत्ति आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।

आईआईएफसीएल का कार्य निष्पादन

इस पृष्ठभूमि में, अब मैं वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान आपकीकंपनी के कार्य निष्पादन को रेखांकित करना चाहता हूँ।

परिचालनात्मक निष्पादन

प्रत्यक्ष ऋण:

- **सकल संस्वीकृतियाँ:** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत ₹11,622 करोड़ की सकल संस्वीकृतियां की गई। इसके साथ ही, प्रत्यक्ष ऋण (उप–ऋण सहित) के अंतर्गत संचयी सकल संस्वीकृतियाँ 31 मार्च 2026 तक ₹1,43,884 करोड़ हो गईं, जो 613 परियोजनाओं हेतु थीं, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹12,25,420 करोड़ है।
- **वित्तीय समापन:** 31 मार्च 2026 की स्थिति में, प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत स्वीकृत 613 परियोजनाओं में से 481 परियोजनाओं ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है।

संवितरण: वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष ऋण (उप–ऋण सहित) के अंतर्गत ₹6.388 करोड़ का संवितरण किया गया। इसके साथ ही, इस योजना के अंतर्गत संचयी संवितरण 31 मार्च 2026 तक ₹65,512 करोड़ हो गया, जो 425 परियोजनाओं हेतु था, जिनकी कुल परियोजना लागत ₹7,54,416 करोड़ है।

टेकआउट वित्त

- **सकल संस्वीकृतियाँ:** 31 मार्च, 2026 तक, टेकआउट वित्तपोषण के अंतर्गत 162 परियोजनाओं हेतु संचयी स्वीकृतियां ₹51,676 करोड़ रहीं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान स्वीकृतियां ₹2,784 करोड़ रहीं।
- **संवितरण:** 31 मार्च, 2026 तक, टेकआउट वित्तपोषण योजना के अंतर्गत संचयी संवितरण ₹32,308 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान संवितरण ₹2,996 करोड़ रहा।

परियोजना बॉण्ड

- वित्तीय वर्ष 2025–26 तक, आपकी कंपनी ने परियोजना बॉण्ड में ₹49,877 करोड़ की स्वीकृतियां प्रदान कीं, जिसमें से ₹29,912 करोड़ विद्युत क्षेत्र में और ₹9,046 करोड़ सड़क क्षेत्र में हैं।
- वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, परियोजना बॉण्ड में संस्वीकृतियां ₹20,775 करोड़ रहीं और संवितरण ₹9,522 करोड़ रहा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स)

- **संस्वीकृतियाँ:** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा इन्विट्स को ₹1,000 करोड़ की संस्वीकृतियाँ प्रदान की गईं।
- **संवितरण:** वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा इन्विट्स को ₹1,017 करोड़ का संवितरण किया गया।

पुनर्वित्तपोषण

- **सकल संस्वीकृतियाँ**: वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹21,500 करोड़ की संस्वीकृतियां प्रदान कीं, जिससे 31 मार्च, 2026 तक योजना के अंतर्गत संचयी सकल संस्वीकृतियां ₹1,01,397 करोड़ हो गईं।
- **संवितरण**: वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा ₹13,050 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया, जिसके फलस्वरूप 31 मार्च 2026 तक इस योजना के अंतर्गत कुल संचयी संवितरण ₹63,151 करोड़ हो गया।

वित्तीय निष्पादन

रिकॉर्ड स्तर की स्वीकृतियों और संवितरण के अलावा, वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कुछ अन्य प्रमुख प्रदर्शन मानदंड निम्नलिखित हैं:

- 31 मार्च 2026 को बकाया ऋण बही लगभग 17 प्रतिशत बढ़कर ₹81,715 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च 2025 को ₹69,904 करोड़ थी।
- जोखिम–भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 31 मार्च, 2026 तक 20.53% रहा, जबकि 31 मार्च, 2025 तक यह 23.44% था। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए निर्धारित 15% की न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता से पर्याप्त रूप से अधिक है।
- प्रावधान कवरेज अनुपात 31 मार्च, 2026 तक बढ़कर 100% हो गया।
- ऋण–इक्विटी अनुपात 31 मार्च, 2026 तक बढ़कर 4.42 गुना हो गया, जबकि 31 मार्च, 2025 तक यह 3.88 गुना था।

अवसंरचना वित्तपोषण के केंद्र में सततता

वित्तीय वर्ष 2025–26 का वर्ष संकल्पों को संस्थागत कार्रवाई में बदलने का वर्ष रहा। आईआईएफसीएल ने पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करने से आगे बढ़ते हुए, अपने वित्तपोषण और जोखिम प्रबंधन ढांचे के केंद्र में सततता को शामिल किया। सततता वित्त विभाग को कार्यान्वित करने, एक मजबूत जलवायु और ईएसजी जोखिम आकलन मॉडल विकसित करने, एडीबी ईएसजीआई ऋण सुविधा के अंतर्गत परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और रणनीतिक वैश्विक साझेदारियां स्थापित करने से लेकर, आईआईएफसीएल ने अगली पीढ़ी के सतत अवसंरचना वित्तपोषण में नेतृत्व करने के लिए आवश्यक संस्थागत आधार तैयार किया है। लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन को संस्थागत रूप देना भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा, जिसके लिए अवसंरचना परियोजनाओं के लैंगिक वर्गीकरण हेतु मानक परिचालन प्रक्रियाओं के विकास की शुरुआत की गई। यह पहल हमारी वित्तपोषण प्रक्रियाओं में समावेशी विकास संबंधी विचारों को शामिल करती है और इस विश्वास को मजबूत करती है कि सतत अवसंरचना को समान और दीर्घकालिक, दोनों प्रकार का मूल्य सृजित करना चाहिए। साझेदारियों और प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करते हुए, आईआईएफसीएल ने भारत में सतत अवसंरचना वित्तपोषण को मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026 में दावोस में फास्ट–इन्फ्रा लेबल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग का उद्देश्य विश्वसनीय और निवेश के लिए तैयार परियोजनाओं की सूचियों को मजबूत करना, संस्थागत क्षमता का निर्माण करना तथा ज्ञान साझा करने और बाजार विकास के माध्यम से जलवायु–अनुरूप वित्तपोषण पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

भारत के प्रमुख अवसंरचना वित्तपोषण संस्थान के रूप में, आईआईएफसीएल संधारणीय पूंजी को बढ़ावा देने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और ऐसी अवसंरचना को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो देश के लिए दीर्घकालिक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक मूल्य सृजित करती है।

जोखिम प्रबंधन रूपरेखाओं को सुदृढ़ करना

जैसे–जैसे हमारे कारोबार का आकार और जटिलता बढ़ती जा रही है, हमारी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक बना हुआ है। वर्ष के दौरान, हमने अपने उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन ढांचे को और मजबूत किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास को मजबूत अभिशासन, विवेकपूर्ण जोखिम लेने और दीर्घकालिक वित्तीय सुदृढ़ता का समर्थन प्राप्त हो।

हम आस्ति गुणवत्ता, चलनिधि प्रबंधन, पूंजी पर्याप्तता तथा ऋण, बाजार, परिचालन और उभरते जोखिमों के सक्रिय प्रबंधन पर निरंतर अधिक ध्यान दे रहे हैं। हमारा जोखिम अभिशासनढांचा एक मजबूत "जोखिम से बचाव की तीन–स्तरीय व्यवस्था" मॉडल, स्वतंत्र जोखिम निगरानी तथा निदेशक मंडल स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति और निदेशक मंडल को नियमित रिपोर्टिंग द्वारा समर्थित है।

कंपनी भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक मजबूत परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आईआईएफसीएल में हमारा दृष्टिकोण सुव्यवस्थित अभिशासन संरचनाओं, प्रक्रियाओं, प्रणालियों और नियंत्रणों पर आधारित है, ताकि परिचालन जोखिमों की सक्रिय रूप से पहचान और उनका प्रबंधन किया जा सके तथा कारोबार की निरंतरता और सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके। वर्ष के दौरान, हमने नियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे की व्यवस्थित समीक्षा करके अपनी परिचालन सुदृढ़ता को और मजबूत किया।

ऋण जोखिम के आकलन को मजबूत करने के लिए, आईआईएफसीएल ने 30 से अधिक अवसंरचना क्षेत्र–विशिष्ट आंतरिक जोखिम रेटिंग मॉडल विकसित किए हैं, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों की अवसंरचना परियोजनाओं की विशिष्ट विशेषताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। इन मॉडलों के साथ एक उन्नत प्रारंभिक चेतावनी संकेतक (ईडब्ल्यूएस) ढांचा और तिमाही पोर्टफोलियो समीक्षा भी की जाती है, जिससे उभरते जोखिमों की समय रहते पहचान करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

वर्ष के दौरान, हमने जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को और मजबूत करते हुए जोखिम वहनढांचे (आरएएफ), उद्यम–व्यापी

तनाव परीक्षण और आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) को निरंतर संस्थागत रूप देने की दिशा में आगे बढ़ाया। इन पहलों ने सामान्य और तनावपूर्ण, दोनों परिस्थितियों में पर्याप्त पूंजी और वित्तीय सुदृढ़ता बनाए रखने की हमारी क्षमता को मजबूत किया है, साथ ही जोखिम प्रबंधन को हमारे रणनीतिक व्यावसायिक उद्देश्यों के अनुरूप बनाया है।

सतत वित्त के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने अपने ईएसजी और जलवायु जोखिम प्रबंधन ढांचे को भी मजबूत किया है। हमारी परियोजना–विशिष्ट ईएसजी और जलवायु जोखिम आकलन प्रक्रियाओं को धीरे–धीरे ऋण मूल्यांकन, पोर्टफोलियो निगरानी, तनाव परीक्षण और रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल किया जा रहा है, जिससे हम दीर्घकालिक जलवायु–संबंधी जोखिमों का प्रबंधन करते हुए सतत अवसंरचना विकास को समर्थन देने में सक्षम हो सकें।

आईआईएफसीएल में हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रभावी जोखिम प्रबंधन केवल अनुपालन का कार्य नहीं है, बल्कि यह सतत विकास को सक्षम बनाने वाला एक रणनीतिक माध्यम है। हम अपनी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को और मजबूत करने तथा भारत के अवसंरचना विकास को जिम्मेदारीपूर्वक समर्थन देने के लिए उन्नत जोखिम विश्लेषण, प्रौद्योगिकी–आधारित निगरानी प्रणालियों, डेटा अभिशासन और मानव पूंजी में निवेश जारी रखेंगे।

हाल ही की रणनीतिक पहलें

आईआईएफसीएल बदलते बाज़ार परिदृश्य के अनुरूप अपनी रणनीतिक पहलों को निरंतर अद्यतन करता रहा है। विगत वर्षों में, कंपनी ने अवसंरचना के विभिन्न उप–क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को सुदृढ़ किया है, और ऋण संवितरण और जोखिम प्रबंधन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जोखिम–आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल लागूकिए हैं।

आईआईएफसीएल ने स्मार्ट मीटरिंग क्षेत्र में प्रवेश करके अपने अवसंरचना वित्तपोषण पोर्टफोलियो को मजबूत किया है, जो अगली पीढ़ी की अवसंरचना और प्रौद्योगिकी–आधारित सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं को समर्थन देने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह लेनदेन आईआईएफसीएल के लिए अपनी तरह का पहला है और राजस्थान में स्मार्ट मीटरिंग परियोजना के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), विश्व बैंक समूह के साथ मिलकर किया गया संस्थान का पहला वित्तपोषण है। यह लेनदेन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने और पूरे देश में सतत अवसंरचना विकास को गति देने के लिए प्रमुख वैश्विक संस्थानों के साथ साझेदारी करते हुए, एक प्रमुख अवसंरचना वित्तपोषक के रूप में आईआईएफसीएल की भूमिका को और मजबूत करता है।

सतत विकास को बढ़ावा देने और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएमएफसीएल) और बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) जैसे संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, जिनमें सतत अवसंरचना वित्तपोषण में क्षमता निर्माण और सह–वित्तपोषण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा, आईआईएफसीएल ने मुंबई, बेंगलुरु और यूनाइटेड किंगडम जैसे वित्तीय केंद्रों में बैठकों और सम्मेलनों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्रमुख हितधारकों के साथ सहभागिता की। इन सहभागिताओं से प्राप्त जानकारी को परिणाम रिपोर्टों में संकलित किया गया और नीति निर्माण में सहायता के लिए संबंधित प्राधिकरणों के साथ साझा किया गया–यह एक ऐसी पद्धति है जिसे कंपनी आगे भी जारी रखने का लक्ष्य रखती है।

अपनी विस्तार रणनीति के तहत, आईआईएफसीएल ने नई दिल्ली के नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक नया कार्यालय शुरू करके अपने कार्यालयी अवसंरचना का विस्तार किया, जिसका संचालन वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान प्रारंभ हो चुका है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलें

आईआईएफसीएल सीएसआर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है और स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, स्वच्छ पेयजल तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में संसाधन उपलब्ध करा रहा है। पिछले चौदह वर्षों के दौरान, कंपनी ने इन उद्देश्यों के लिए संचयी रूप से लगभग ₹204 करोड़ का उपयोग किया है, जिससे एक जिम्मेदार सार्वजनिक संस्थान के रूप में उसकी भूमिका और मजबूत हुई है, जो अवसंरचना–आधारित आर्थिक विकास के साथ समावेशी सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष के दौरान ₹40.54 करोड़ के सीएसआर उत्तदायित्व पर 17 सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹41.38 करोड़ का अंशदान किया। ये परियोजनाएं 12 से अधिक राज्यों में फैली हुई थीं, जिनमें से 70:से अधिक परियोजनाएं सरकारी संस्थानों, जिला प्रशासनों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की गईं। यह संस्थागत साझेदारी मॉडल राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ समन्वय सुनिश्चित करता है और असेवित क्षेत्रों में विकासात्मक प्रभाव को और गहरा करता है। आईआईएफसीएल ने डिजिटल शिक्षा में परिवर्तन, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, पर्यावरणीय स्थिरता और विरासत संरक्षण जैसी नई पहलों तक अपनी सीएसआर पहुंच का विस्तार किया है। सड़क सुरक्षा को शामिल करके, आईआईएफसीएल सड़क अवसंरचना के विकास में अपने योगदान को पूरा करता है और एक जिम्मेदार ऋणदाता के रूप में अपनी विश्वसनीयता को और मजबूत करता है। आईआईएफसीएल आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के विकास में लगातार योगदान दे रहा है, जिसके लिए कुल संस्वीकृतियां ₹14 करोड़ से अधिक हैं।

सीएसआर के क्षेत्र में आईआईएफसीएल के निरंतर प्रयासों को स्वतंत्र रूप से मान्यता और पुष्टि मिली है। वर्ष 2025 में, आईआईएफसीएल को ईएसजी के सामाजिक मानदंड पर आईसीआरए ईएसजी प्रभाव रेटिंग 88 ("उत्कृष्ट") प्राप्त हुई। आईसीआरए ने विशेष रूप से आईआईएफसीएल की "प्रभावशाली और व्यापक सीएसआर पहलों, विशेष रूप से स्वास्थ्य, पोषण और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में" पहलों को मान्यता दी, जिसमें आकांक्षी जिलों को शामिल करना और हाल के वर्षों में सीएसआर बजट में उल्लेखनीय वृद्धि भी शामिल है। रेटिंग एजेंसी ने

आईआईएफसीएल के मजबूत निगरानी और प्रभाव आकलन ढांचे का भी उल्लेख किया, जिसमें समय–समय पर स्थल का भौतिक निरीक्षण और समुदाय के साथ सीधे संवाद शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्वीकृत निधियों का निर्धारित उद्देश्य के अनुसार उपयोग किया जाए और जमीनी स्तर पर मापनीय परिणाम प्राप्त हों।

आगे की राह

आने वाला दशक भारत के इतिहास में सबसे बड़े अवसंरचना निवेश कार्यक्रमों में से एक का साक्षी बनेगा। इस बदलाव के वित्तपोषण के लिए सरकार, वित्तीय संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों, पूंजी बाजारों, बहुपक्षीय एजेंसियों और संस्थागत निवेशकों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होगी।

भविष्य की ओर देखते हुए, आईआईएफसीएल के लिए **"मेरा ध्येय, बेहतर बनाएं, विकसित करें, बदलाव लाएं।"** है। विकसित भारत @2047 की दिशा में इस ध्येय को साकार करने हेतु, हम मुख्य रूप से छह रणनीतिक प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो हैं: अनुशासित ऋण मूल्यांकन और सतर्क निगरानी के साथ अवसंरचना वित्तपोषण में सुधार करना; ईसीबी, बहुपक्षीय वित्तपोषण, बॉण्ड और पूंजी बाजारों के माध्यम से दीर्घकालिक पूंजी जुटाना; प्रौद्योगिकी, आंकड़ों और विश्लेषण के माध्यम से परियोजना निगरानी में परिवर्तन लाना; पोर्टफोलियो में विविधता और सुदृढ़ता का निर्माण करना; अपनी कार्य संस्कृति और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना; तथा दीर्घकालिक मूल्य सृजन के मूल सिद्धांत के रूप में ईएसजी को एकीकृत करना।

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने भारत के अवसंरचना क्षेत्र की बढ़ती वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु ₹34,200 करोड़ के महत्वाकांक्षी संसाधन संग्रहण कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम में घरेलू बॉण्ड, पूंजी बाजार साधनों और बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) को शामिल करते हुए विविधीकृत वित्तपोषण रणनीति की परिकल्पना की गई है। कंपनी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए लागत–प्रभावी दीर्घकालिक वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने हेतु अपनी निधियों की लागत को अनुकूलित करने के लिए निरंतर प्रयास करती है।

भा.रि.बैंक द्वारा हाल ही में घोषित उपायों, जिनमें पात्र ईसीबी हेतु रियायती यूएसडी–आईएनआर स्वैप सुविधा शामिल है, से हेजिंग लागत कम होने और विदेशों से उधार लेना अधिक आकर्षक बनने की उम्मीद है। इससे प्रतिस्पर्धी दरों पर दीर्घकालिक पूंजी जुटाने का एक अतिरिक्त माध्यम उपलब्ध होगा।

इस रणनीति के तहत, आईआईएफसीएल की चालू वित्तीय वर्ष में अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाकर लगभग 1.30 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने की योजना है। कंपनी भारत सरकार और अन्य नियामकीय प्राधिकरणों से आवश्यक मंजूरियों के अधीन, विदेशों से उधारी के माध्यम से अतिरिक्त 1 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने का भी इरादा रखती है।

वर्ष के दौरान प्रस्तावित रूप से जुटाई जाने वाली निधियां परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत, शहरी अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अवसंरचना, जल और स्वच्छता, सामाजिक अवसंरचना, परमाणु ऊर्जा तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं को समर्थन देंगी, जो भारत सरकार के विकसित भारत /2047 के विजन के अनुरूप हैं।

निवेशकों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने हेतु, हम आगामी वित्तीय वर्ष में प्रमुख महानगरों में हितधारक बैठकों के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों पर गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करने की योजना बना रहे हैं, ताकि भारत में अवसंरचना के विकास के लिए उद्योग विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श किया जा सके।

एसआईएफटीआई ढांचे के बंद होने के बाद, विभिन्न क्षेत्रों की अवसंरचना परियोजनाओं में अधिक भागीदारी के लिए बढ़े हुए वित्तपोषण लचीलेपन और परिचालन स्वतंत्रता के माध्यम से आईआईएफसीएल में अधिक मजबूत वृद्धि होने की उम्मीद है। इस महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव से नए ऋण उत्पादों के माध्यम से ऋण विस्तार को तेजी से बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इन सबसे ऊपर, हमारा कार्य राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से दृढ़ता से जुड़ा रहेगा। हम जिस प्रत्येक परियोजना का वित्तपोषण करते हैं और जिस प्रत्येक रुपये की संस्थागत पूंजी जुटाने में सहायता करते हैं, वह भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना के विकास में योगदान देता है। यही उद्देश्य हमारी आधारशिला और मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहेगा।

आभार

मैं भारत सरकार, वित्त सेवाएं विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों, हमारे निदेशक मंडल, नियामकों, शेयरधारकों, लेखापरीक्षकों, ऋणदाता संस्थानों, बहुपक्षीय साझेदारों, निवेशकों, ग्राहकों और हमारे सभी हितधारकों के निरंतर विश्वास, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

इन सबसे ऊपर, मैं आईआईएफसीएल टीम के हर एक सदस्य के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उनकी व्यावसायिकता, कड़ी मेहनत और हमारे उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता संस्थान को निरंतर मजबूत कर रही है और हमारे हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ा रही है।

हम सभी मिलकर उस अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो भारत के विकास को गति दे रही है, उसके नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना रही है और 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश की यात्रा को और गति प्रदान कर रही है।

सधन्यवाद और जय हिंद!

हस्ता/–
(रोहित ऋषि)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर: 11524681

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 24.09.2026

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल



श्री रोहित ऋषि
प्रबंध निदेशक



श्री पलाश श्रीवास्तव
उप प्रबंध निदेशक



श्री चंद्रदीप कुमार झा
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्रीमति लाया मद्दुरी
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री पार्थ सारथी रेड्डी
सरकार द्वारा नामित निदेशक



श्री अमित कुमार श्रीवास्तव
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
नामित निदेशक



श्री आशुतोष चौधरी
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
नामित निदेशक

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

सीआईएनः U67190DL2006G0I144520

विषयः 21वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

प्रिय महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की 21वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को दोपहर 12.30 बजे तीसरी मंजिल, कॉन्फ्रेंस हॉल, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जाएगी।

बैठक की विस्तृत सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, कैग की टिप्पणियाँ और 31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी के अंकेक्षित लेखा इसके साथ संलग्न हैं।

कृपया बैठक में भाग लें।

धन्यवाद।

भवदीय,

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हस्ता./–
रुचि सिंघल
महाप्रबंधक
कंपनी सचिव

दिनांकः 25.09.2026
स्थानः नई दिल्ली

'वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या एफ. सं. 18/6/2013–आईएफ–I दिनांक 09 सितम्बर 2026 के माध्यम से आईआईएफसीएल के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक आम बैठक को निर्धारित अवधि से कम सूचना पर 30 सितम्बर 2026 को डीएफएस में आयोजित किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई।

आई आई एफ सी एल
IIFCL

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

सीआईएन:U67190DL2006G0I144520

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों की इक्कसवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2026 को दोपहर 12.30 बजे वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तीसरी मंज़िल स्थित सम्मेलन कक्ष, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा:–

सामान्य कार्य

1) वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरण (स्टैंडअलोन एवं कंसॉलिडेटेड), साथ ही निदेशकों की रिपोर्ट तथा उस तिथि पर समाप्त अवधि के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकृत करना।

2) विचार करने के लिए, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो बिना या संशोधन सहित निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **साधारण संकल्प** के रूप में पारित करना:–

"संकल्प किया गया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक को निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाता है।"

विशेष कार्य

3) **कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार निजी स्थानन के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचरों का निर्गम**

विचार करने के लिए, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो बिना या संशोधन सहित निम्नलिखित प्रस्ताव को एक विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:–

"यह संकल्प किया गया कि कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 42, 71 तथा अन्य लागू प्रावधानों (जैसा कि समय–समय पर संशोधित या पुनः अधिनियमित किया जाए) के साथ–साथ कंपनियाँ(प्रॉस्पेक्टस एवं प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर्स के निर्गम एवं सूचीबद्धता) विनियम, 2008, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित किया जाए), तथा अन्य सभी लागू विनियमों, दिशा–निर्देशों, कंपनी के ज्ञापन एवं उपविधि, एवं अन्य संबंधित विधिक प्रावधानों के अधीन होकर तथा आवश्यक अनुमतियाँ, स्वीकृतियाँ, सहमतियाँ एवं प्रतिबंध प्राप्त होने की शर्त पर, कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे आगे "निदेशक मंडल" कहा जाएगा) को, निजी निर्गम के माध्यम से, एक या अधिक किश्तों में, बॉन्ड तथा गैर परिवर्तनीय डिबेंचर सहित अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम हेतु प्रस्ताव/निमंत्रण करने तथा/या किए जाने के लिए, अधिकतम रुपए 34,200 करोड़ (केवल चौंतीस हज़ार दो सौ करोड़ रुपये मात्र) तक की राशि के लिए, उस विशेष संकल्प के पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में, लागू दिशा–निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित शर्तों तथा निदेशक मंडल, या निदेशक मंडल की किसी विधिवत् गठित समिति अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित नियमों एवं शर्तों पर, अधिकार प्रदान किया जाता है।"

इसके अतिरिक्त, संकल्प किया गया कि अप्रत्यभूत, अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर्स, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के निजी निर्गम को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कंपनी के निदेशक मंडल (''बोर्ड'') अथवा बोर्ड की किसी भी विधिवत गठित समिति या बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को और विधिवत उन निवेशकों, जिन्हें बॉन्ड/डिवेंचर्स आबंटित किये

जाने हैं, के आकार, श्रेणी सहित जारी करने के निबंधन, प्रत्येक शाखा में आबंटित किए जाने वाले बॉन्ड/डिवेंचर्स की संख्या, जारी करने की कीमत, आशय, ब्याज दर, तत्कालीन विद्यमान बाजार कीमतों पर प्रीमियम/छूट, जारी करने की राशि, बॉन्ड/डिवेंचर्स धारकों की श्रेणी के लिए जारी करने की कीमत पर छूट, सूचीयन, निजी निर्गम प्रस्ताव पत्र में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित किसी घोषणा/शपथपत्र इत्यादि को जारी करना और तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विनियामक अपेक्षाओं निर्धारण के लिए प्राधिकृत किया जाता है।''

इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और ऐसे निर्देश देने के लिए अधिकृत किया जाता है या जो समीचीन, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं।''

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत अनुमोदित उधार सीमा में वृद्धि

विचार करने के लिए, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो बिना या संशोधन सहित निम्नलिखित प्रस्ताव को एक **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

"यह संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) और उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी अन्य लागू प्रावधानों (जिसमें वर्तमान में लागू किसी सांविधिक संशोधन या पुनःअधिनियमन सहित) तथा कंपनी के पार्षद अंतर्नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी के सदस्यों की स्वीकृति एतद्द्वारा निदेशक मंडल को समय–समय पर कंपनी के प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तों और नियमों पर तथा प्रतिभूति के साथ या उसके बिना, जैसा कि निदेशक मंडल अपने विवेक से उचित समझे, किसी राशि या राशियों को उधार लेने के लिए प्रदान की जाती है, भले ही उधार ली जाने वाली राशि या राशियां, कंपनी द्वारा पहले से उधार ली गई राशियों के साथ (कंपनी के बैंकर्स से सामान्य कारोबार के दौरान प्राप्त अस्थायी ऋणों को छोड़कर), कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी तथा उसके मुक्त आरक्षित निधियों और प्रतिभूति प्रीमियम से अधिक हो जाएं, बशर्ते कि किसी भी समय बकाया कुल उधारी, जिसमें पहले से उधार ली गई राशियां भी शामिल हैं, ₹1,50,000 करोड़ (केवल एक लाख पचास हजार करोड़ रुपये) की राशि से अधिक नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त यह संकल्प किया गया कि निदेशक मंडल या बोर्ड की कोई विधिवत गठित समिति या कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य प्राधिकरण को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और चीजों को करने और ऐसे निर्देश देने के लिए अधिकृत किया जाता है या जो समीचीन, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समझे जा सकते हैं।''

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
ह0/–

रूचि सिंघल

महाप्रबंधक–कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या।17837

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25.09.2026

पंजीकृत कार्यालय
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पांचवा तल, ब्लॉक–2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023
सीआईएनः **U67190DL2006GOI144520**
वेबसाइटः **www.iifcl.in**

टिप्पणियां

1. कपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार, मद सं. 3 और 4 के अंतर्गत व्यवसाय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्दिष्ट करते हुए एक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) तथा सामान्य बैठक पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक–2 भी संलग्न हैं।
2. **सभा में उपस्थित होकर मतदान करने के लिए पात्र सदस्य, अपने स्थान पर उपस्थित होकर मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों (प्रॉक्सी/प्रॉक्सीगण) को नियुक्त करने के लिए भी पात्र है, और ऐसे प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। प्रॉक्सी प्रपत्र को प्रभावी होने हेतु विधिवत् स्टाम्पित, पूर्ण रूप से भरा हुआ, हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा उक्त बैठक के आयोजन के समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व जमा कराया जाना आवश्यक है।**
3. प्रॉक्सी प्रपत्र तथा बैठक में उपस्थिति एवं मतदान हेतु प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को अधिकृत करने वाले निदेशक मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भेजी जाएगी।
4. कंपनियाँ अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के तहत उपर्युक्त विशेष व्यवसाय के संबंध में सभी भौतिक तथ्यों को दर्शाते हुए व्याख्यात्मक विवरण इस सूचना के साथ संलग्न है और इस सूचना का अभिन्न अंग है।
5. सदस्य यह भी ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइ www.iifcl.in पर उपलब्ध रहेगी। यह सूचना तथा अन्य दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्य दिवसों में सामान्य कार्य समय के दौरान निरीक्षण हेतु भी उपलब्ध रहेंगे।

सूचना के अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के तहत व्याख्यात्मक विवरण

मद सं. 3: कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार निजी स्थानन के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचरों का निर्गम

कंपनी की भावी वृद्धि योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल का विचार है कि कंपनी के दीर्घकालिक संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए असुरक्षित/सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर जारी किए जाना आवश्यक है, जिनकी बाज़ार में अधिक स्वीकार्यता है तथा जो अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक हैं। उक्त के मद्देनज़र, निदेशक मंडल ने अपनी बैठक दिनांक 27 मार्च, 2026 में, शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन, आईआईएफसीएल द्वारा ₹34,200 करोड़ की संसाधन वृद्धि योजना पर विचार कर उसे अनुमोदित किया। आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल को यह अधिकृत किया गया है कि वह निजी प्लेसमेंट के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड/डिबेंचर–करयोग्य/करमुक्त/इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड/ऑफ़शोर आईएनआर बॉण्ड/अन्य किसी भी प्रकार के बॉण्डों को ₹34,200 करोड़ तक की राशि हेतु, विशेष प्रस्ताव पारित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि में, एक या अधिक किश्तों में, उन शर्तों एवं नियमों पर जिन्हें निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा विधिवत गठित किसी समिति अथवा निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप दिया जाए, जारी कर सके।

कंपनी द्वारा निजी प्लेसमेंट के आधार पर जारी किए जाने वाले एनसीडीज़ के लिए किसी भी प्रस्ताव या सदस्यता हेतु आमंत्रण को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 एवं 71 तथा कंपनियाँ (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति विशेष प्रस्ताव द्वारा आवश्यक है।

शेयरधारकों की स्वीकृति उक्त वर्ष के दौरान किए जाने वाले सभी प्रस्तावों या आमंत्रणों के लिए एक वर्ष की अवधि तक मान्य रहेगी।

निदेशक मंडल का विश्वास है कि प्रस्तावित ऑफ़र कंपनी के सर्वोत्तम हित में है।

कंपनी के किसी भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके संबंधियों का प्रस्तावित प्रस्ताव में कोई हित नहीं है।

आपके निदेशक, सूचना पत्र के मद सं. 3 के अंतर्गत प्रस्ताव को आपकी स्वीकृति हेतु अनुशंसित करते हैं।

मद सं. 4: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत अनुमोदित उधार सीमा में वृद्धि

कंपनी के वर्तमान उधार की सीमा (सामान्य कारोबार के दौरान कंपनी के बैंकरों से लिए गए अस्थायी ऋणों को छोड़कर) 25 सितंबर 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित संकल्प के माध्यम से ₹1,00,000 करोड़ है। निधियों की भविष्य में बढ़ने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो कंपनी की विस्तार योजनाओं/कार्यक्रमों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं, कंपनी को वित्तीय संस्थानों, बैंकों और अन्य से अतिरिक्त ऋण/उधारी लेने की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, निदेशक मंडल की उधार लेने की शक्तियों को वर्तमान सीमा ₹1,00,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,50,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है। कंपनी द्वारा समय–समय पर ली जाने वाली उधारी को सुरक्षित करने के लिए, कंपनी को अपनी सभी या किसी अचल और चल संपत्तियों पर बंधक/प्रभार/हाइपोथिकेशन सृजित करने की आवश्यकता हो सकती है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की सहमति प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

किसी भी निदेशक का उक्त संकल्प में किसी भी प्रकार से कोई सरोकार या हित नहीं है।

आपके निदेशकगण मद संख्या 4 में दिए गए संकल्प को आपकी स्वीकृति हेतु अनुशंसित करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
ह0/–

रूचि सिंघल
महाप्रबंधक–कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A17837

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 25.09.2026

पंजीकृत कार्यालय
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पांचवा तल, ब्लॉक–2 प्लेट ए और बी, एनबीसीसी टॉवर,
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023
सीआईएनः **U67190DL2006GOI144520**
वेबसाइटः **www.iifcl.in**

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

सीआईएनः**U67190DL2006G0I144520**

बोर्ड रिपोर्ट

सेवा में

आईआईएफसीएल के सदस्यगण

आपके निदेशकों को लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, समेकित वित्तीय विवरण और सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक और उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी कंपनी के प्रदर्शन पर 21वीं वार्षिक रिपोर्ट पेश करते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है।

मुख्य वित्तीय विशिष्टताएं

31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश इस प्रकार हैः

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
कुल राजस्व	8,181	6,744
कुल व्यय	6,197	4,442
कर पूर्व लाभ	**1,984**	**2,302**
घटाएं: कराधान के लिए प्रावधान	604	611
जोड़ें: असाधारण मदें	-	473
विनियोजन (करोपरांत लाभ) हेतु उपलब्ध निवल लाभ	**1,379**	**2,164**
अन्य व्यापक आय	**0.04**	**(3.5)**
विनियोजन के बाद उपलब्ध निवल लाभ	**1,379**	**2,161**
₹10 के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए अर्जन (भारित औसत)	1.38	2.16

ऋण क्रियाकलाप

प्रत्यक्ष ऋण

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान ₹11,622 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति के साथ, प्रत्यक्ष ऋण योजना के अंतर्गत आपकी कंपनी की संचयी सकल स्वीकृतियाँ बढ़कर 614 अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ₹1,43,884 करोड़ हो गईं। संचयी सकल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार संवितरण निम्नानुसार हैः

31 मार्च, 2026 के अनुसार प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत संचयी सकल स्वीकृतिया

(₹ करोड)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	324	520,370	64,923
बिजली	195	490,024	55,240
हवाई अड्डा	7	61,529	6,225
बंदरगाह	22	48,773	6,364
शहरी आधारभूत संरचना	18	65,549	5,754

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
रेलवे	3	3,194	639
पीएमडीओ*	38	8,602	260
दूरसंचार	2	4,607	400
सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	3	15,096	3,013
संबद्ध अवसंरचना	2	7,676	1,068
योग	**614**	**1,225,420**	**143,884**

*सामूहिक नगरपालिका ऋण दायित्व

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, 528 परियोजनाओं के लिए आपकी कंपनी की ₹95,264 करोड़ रुपये की निवल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार संवितरण निम्नानुसार है:

प्रत्यक्ष ऋण के तहत संचयी निवल स्वीकृतियां (31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार):

(₹ करोड)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	297	426,128	44,854
बिजली	157	303,825	37,240
हवाई अड्डा	9	61,529	4,012
बंदरगाह	17	28,109	3,366
शहरी आधारभूत संरचना	14	19,606	2,366
रेलवे	1	600	70
पीएमडीओ'	29	5,617	197
दूरसंचार	1	3,750	250
सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना	1	9,215	1,843
संबद्ध अवसंरचना	2	7,676	1,068
योग	**528**	**866,055**	**95,264**

संस्वीकृत परियोजनाओं के तहत वित्तीय समापन की उपलब्धि

31 मार्च 2026 तक, प्रत्यक्ष ऋण के तहत 528 निवल स्वीकृत परियोजनाओं में से, 480 परियोजनाओं यानी 91: ने वित्तीय समापन हासिल कर लिया है। वित्तीय समापन प्राप्त परियोजनाओं का क्षेत्र–वार विवरण निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार वित्तीय समापन प्राप्त परियोजनाएँ

(₹ करोड)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	सकल स्वीकृतियां
सड़क	276	39,372
बिजली	140	29,860
हवाई अड्डा	6	2,609
बंदरगाह	16	3,352
शहरी अवसंरचना	11	870
अन्य	31	1,492
योग	**480**	**77,554**

वाणिज्यिक परिचालन तिथि की उपलब्धि

मार्च 2026 के अंत तक, आपकी कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण व्यवस्था के तहत जिन 480 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है, उनमें से 354 परियोजनाओं में वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) प्राप्त हो चुकी है, जिसमें 202 सड़क परियोजनाएं और 107 विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। सीओडी प्राप्त परियोजनाओं का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार सीओडी प्राप्त परियोजनाएँ

(₹ करोड)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	सकल स्वीकृतियां
सड़क	202	24,853
बिजली	107	18,394
हवाई अड्डा	2	848
बंदरगाह	9	1,204
शहरी अवसंरचना	8	589
अन्य	26	210
योग	**354**	**46,098**



ललितपुर पावर प्लांट

टेक–आउट वित्त

अवसंरचना क्षेत्र में अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराने तथा बैंकों की एक्सपोज़र सीमा और परिसंपत्ति–देयता असंतुलन संबंधी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से, आपकी कंपनी ने टेक–आउट वित्तपोषण योजना को लागू किया है। आपकी कंपनी ने संशोधित टेक–आउट वित्तपोषण योजना को दिसंबर 2011 में क्रियान्वित किया। बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर इस योजना में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। आपकी कंपनी की टेक–आउट वित्तपोषण योजना पारदर्शी, गैर–भेदभावपूर्ण तथा

गैर–विवेकाधीन बाह्य परियोजना रेटिंग–आधारित मूल्य निर्धारण तंत्र का अनुसरण करती है, जिसके अंतर्गत अवसंरचना ऋणों का टेक–आउट किया जाता है।

31 मार्च 2026 तक, टेक–आउट वित्तपोषण योजना के अंतर्गत आपकी कंपनी द्वारा 162 परियोजनाओं के लिए कुल सकल स्वीकृतियाँ ₹51,676 करोड़ रही हैं। सकल स्वीकृतियों का क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार टेकआउट वित्त के तहत संचयी सकल स्वीकृतियां

(₹ करोड)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	66	67,554	11,147
बिजली	83	2,50,706	35,211
हवाई अड्डा	2	2,920	1,911
बंदरगाह	9	16,024	3,380
शहरी अवसंरचना	2	107	26
योग	**162**	**3,37,311**	**51,676**

इसके अलावा, 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी द्वारा टेकआउट वित्त योजना के तहत 100 परियोजनाओं के लिए दी गई ₹33.453 करोड़ की कुल स्वीकृतियों का क्षेत्र–वार वितरण निम्नानुसार है:

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार टेकआउट वित्त के तहत निवल सकल स्वीकृतियां

(₹ करोड)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
सड़क	34	42,575	7,136
बिजली	57	1,74,388	22,733
हवाई अड्डा	2	2,920	1,570
बंदरगाह	5	9,704	1,989
शहरी अवसंरचना	2	107	26
योग	**100**	**2,29,694**	**33,453**

सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं (पीपीपी) हेतु प्राथमिकता

अधिदेश के अनुरूप, आपकी कंपनी सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) अवसंरचना परियोजनाओं को अधिभावी प्राथमिकता प्रदान करती है। सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं को अधिभावी प्राथमिकता के साथ अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की आपकी कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता इसके द्वारा समर्थित पीपीपी परियोजनाओं की संख्या में परिलक्षित होती है।

31 मार्च 2026 तक, प्रत्यक्ष ऋण एवं टेक–आउट वित्तपोषण के अंतर्गत (पीएमडीओ के अंतर्गत 38 परियोजनाओं को छोड़कर) कुल 736 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है, जिनमें से 588 परियोजनाएँ (80%) सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) परियोजनाओं से संबंधित हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्षेत्र	पीपीपी	गैर– पीपीपी	पीएसयू	कुल
सड़क	388	.	1	389
बिजली	134	133	10	277
हवाई अड्डा	9	.	.	9
बंदरगाह	24	6	1	31
शहरी अवसंरचना	15	1	3	19
अन्य	2	8	1	11
कुल	**572**	**148**	**16**	**736**

संवितरण

मार्च 2026 के अंत तक कुल संचयी सवितरण ₹1,89,476 करोड़ रहा, जिसमें पुनर्वित्त के अंतर्गत ₹63,151 करोड़, टेक–आउट वित्तपोषण के अंतर्गत ₹32,308 करोड़, नवीन रूप से प्रारंभ किए गए उत्पाद के रूप में अवसंरचना परियोजना बॉण्डों में निवेश के अंतर्गत ₹22,178 करोड़ तथा इनविट्स के अंतर्गत ₹6,328 करोड़ का संवितरण शामिल है।

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र–वार संचयी सवितरण

(₹ करोड)

क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	सकल स्वीकृतियां
प्रत्यक्ष उधार			
सड़क	242	366,774	32,942
बिजली	124	283,154	25,230
हवाई अड्डा	6	57,804	2,963
बंदरगाह	14	27,932	2,242
शहरी अवसंरचना	10	9,658	1,665
रेलवे	1	600	70
पीएमडीओ	27	4,744	151
दूरसंचार	1	3,750	248
योग (क)	**425**	**754,416**	**65,512**
टेकआउट वित्त			
सड़क	34	42,575	7,105
बिजली	54	170,467	21,704
हवाई अड्डा	2	2,920	1,485
बंदरगाह	5	9,704	1,988
शहरी अवसंरचना	2	107	26
योग (ख)	**97**	**225,773**	**32,308**
बॉण्ड्स (ग)			**22,178**
पुनर्वित्त (घ)			**63,151**
इनविट्स (ङ)			**6,328**
कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)			**189,476**

समेकित नगरपालिका ऋण देयता सुविधा

समेकित नगरपालिका ऋण देयता सुविधा (पीएमडीओ) की स्थापना वर्ष 2008 में चार प्रायोजकों–आईएल एंड एफएस, आईआईएफसीएल, आईडीबीआई बैंक तथा केनरा बैंक–द्वारा अन्य ऋणदाताओं के साथ मिलकर सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु की गई थी। इन परियोजनाओं में लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए साझा अवसंरचना का विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत उत्पादन, अपशिष्ट जल उपचार तथा नगर बस परिवहन जैसी अन्य शहरी अवसंरचना सुविधाएँ सम्मिलित थीं। पीएमडीओ सुविधा परियोजनाओं के लिए संसाधन आवश्यकताओं को बैंक–योग्य स्वरूप में संरचित करने तथा अनिवार्य परियोजनाओं की स्थापना हेतु युक्तिसंगत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

वर्तमान में पीएमडीओ का कुल कोष ₹5,000 करोड़ है, जिसे 16 ऋणदाताओं द्वारा प्रतिबद्ध किया गया है, जिसमें से कंपनी की हिस्सेदारी के रूप में ₹391 करोड़ प्रतिबद्ध हैं। 31 मार्च 2026 तक, इस सुविधा के अंतर्गत कंपनी की संचयी निवल स्वीकृतियाँ ₹197 करोड़ तथा संचयी संवितरण ₹151 करोड़ रहे।

भौगोलिक रूप से विविध उपस्थिति

आपकी कंपनी विभिन्न राज्यों में फैली आधारभूत परियोजनाओं के विकास का समर्थन करती रही है और पूरे देश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। 31 मार्च 2026 तक, प्रत्यक्ष ऋण और टेकआउट वित्त के तहत, आपकी कंपनी ने 26 राज्यों में 522 परियोजनाओं के लिए ₹1,28,098 करोड़ स्वीकृत किए हैं और 522 परियोजनाओं में ₹97,819 करोड़ का संवितरण किया है।

31 मार्च 2026 तक प्रत्यक्ष ऋण एवं टेकआउट वित्त योजना के अंतर्गत परियोजना वित्तपोषण के माध्यम से राज्य–वार संचयी निवल स्वीकृतियाँ एवं वितरण की स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड)

राज्य	निवल स्वीकृति	संवितरण
आन्ध्र प्रदेश	13,415	10,691
अरूणाचल प्रदेश	121	121
असम	2,257	488
बिहार	4,106	2,322
छत्तीसगढ़	1,389	1,389
दिल्ली	1,374	1,374
गोवा	343	343
गुजरात	17,948	14,108
हरियाणा	2,403	2,192
हिमाचल प्रदेश	1,269	1,151
जम्मू एवं कश्मीर	1,370	1,309
झारखण्ड	1,928	1,656
कर्नाटक	5,705	3,363
केरल	461	411
मध्य प्रदेश	8,059	7,748
महाराष्ट्र	23,264	14,222
ओडिशा	2,498	2,437
पुडुचेरी	179	179
पंजाब	1,921	1,418
राजस्थान	8,876	5,889
सिक्किम	1,293	1,283
तमिलनाडु	3,704	3,031
तेलंगाना	3,929	2,110
उत्तर प्रदेश	16,885	15,372
उत्तराखण्ड	464	461
पश्चिम बंगाल	2,940	2,753
योग	**128,098**	**97,819**



हिंदुजा साबरमती परियोजना

पुनर्वित्त

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा ₹21,500 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई तथा ₹13,050 करोड़ का संवितरण किया गया।

ऋण संवर्धन

ऋण संवर्धन योजना आपकी कंपनी द्वारा वर्ष 2012 में इस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी कि अवसंरचना परियोजनाएँ ऋण बाजार जैसे वैकल्पिक स्रोतों से दीर्घकालिक वित्तीय संसाधन जुटा सकें।

अब तक, आईआईएफसीएल द्वारा 20 से अधिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए ₹9,000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड निर्गम के लिए कुल ₹2,400 करोड़ से अधिक की गारंटी स्वीकृत की जा चुकी है।



जीएमआर विशाखापत्तनम हवाई अड्डा

व्यवसाय विकास

आपकी कंपनी अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों और क्षेत्रगत विषयों पर चर्चा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, डेवलपर समूहों, इनविट, निजी इक्विटी निधियों, संप्रभु संपत्ति निधियों, रेटिंग एजेंसियों, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियों, सरकारी अधिकारियों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित रूप से संवाद करती है, ताकि अवसंरचना क्षेत्र में आईआईएफसीएल की भागीदारी और सहायता का विस्तार किया जा सके।

कंपनी देश के प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में नियमित अंतराल पर हितधारक बैठकें भी आयोजित करती है, जिनमें विभिन्न हितधारकों और सरकारी प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता है तथा हितधारकों को व्यवसाय विकास के बारे में अवगत कराने के लिए संवादात्मक सत्र आयोजित किए जाते हैं। बड़े डेवलपर समूहों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, उनके शीर्ष प्रबंधन के साथ वरिष्ठ स्तर पर व्यापक संवाद किया जाता है, ताकि उनकी भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं को सक्रिय रूप से समझा जा सके।

हमारी टीमें बड़े ऋणदाताओं की ऋण–संघटन इकाइयों के साथ सक्रिय रूप से संपर्क करती हैं और उनके द्वारा हामीदारी किए गए प्रमुख सौदों में भागीदारी करने में सफल रही हैं।

विकासकों/उधारकर्ताओं, बैंकों और रियायत प्रदान करने वाले प्राधिकरणों के साथ नियमित संवाद के माध्यम से आगामी परियोजनाओं की वित्तपोषण के लिए निगरानी की जाती है।

संसाधन संग्रहण

घरेलू संसाधन

आईआईएफसीएल विभिन्न उपयुक्त लिखतों के माध्यम से बाजार से ऋण (अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों) जुटाता है। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, आईआईएफसीएल की कुल घरेलू उधारी ₹61,082.72 करोड़ बकाया थी। इस कुल बकाया राशि में से ₹33,605.45 करोड़ गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) के माध्यम से, ₹12,997.43 करोड़ बैंकों से दीर्घावधि ऋण के माध्यम से, ₹12,331.01 करोड़ अल्पावधि उधारी के माध्यम से और ₹2,148.82 करोड़ सावधि जमाओं के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट के माध्यम से थे।

बाह्य संसाधन

आईआईएफसीएल ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, क्रेडिटनस्टाल्ट फ्यूर विडेराउफबाउ (केएफडब्ल्यू), यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) सहित प्रमुख बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास वित्त संस्थानों के साथ मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारियां स्थापित की हैं। इन साझेदारियों के माध्यम से, आईआईएफसीएल ने देश में अवसंरचना विकास को सहायता प्रदान करने के लिए दीर्घकालिक संसाधन जुटाए हैं। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, आईआईएफसीएल ने एडीबी से 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, विश्व बैंक से 195 मिलियन अमेरिकी डॉलर, केएफडब्ल्यू से 50 मिलियन यूरो, ईआईबी से 200 मिलियन यूरो, जेआईसीए से 50 बिलियन जापानी येन और ईसीबी के माध्यम से 26 बिलियन जापानी येन की ऋण–सीमाएं स्वीकृत की थीं।

एडीबी की 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण–सीमा में से 31 मार्च 2026 तक 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर आहरित किए जा चुके थे, जबकि शेष राशि का आहरण बाद में किया जाना निर्धारित था। विश्व बैंक (195 मिलियन अमेरिकी डॉलर), केएफडब्ल्यू (50 मिलियन यूरो), ईआईबी (200 मिलियन यूरो) और जेआईसीए (50 बिलियन जापानी येन) से प्राप्त ऋण–सीमाओं का संबंधित वित्तपोषण करारों के अनुसार पूर्ण रूप से उपयोग किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान आईआईएफसीएल ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीसी) से 26 बिलियन जापानी येन का ईसीबी जुटाया है। इन दीर्घकालिक वित्तपोषण व्यवस्थाओं ने आईआईएफसीएल को अपने संसाधन आधार में विविधता लाने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की अपनी क्षमता को मजबूत करने में सक्षम बनाया है।

वित्तीय वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों सहित बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास भागीदारों के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत करना जारी रखा, ताकि संधारणीय मॉडल पर पर्यावरण–अनुकूल और लचीली अवसंरचना के विकास के लिए कम लागत वाले दीर्घकालिक संसाधनों की संभावनाओं का पता लगाया जा सके और उन्हें जुटाया जा सके। कंपनी ने नए वित्तपोषण अवसरों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया और वित्तपोषण के विविधीकृत तथा संधारणीय स्रोत सुरक्षित करने के लिए अपनी साझेदारियों का विस्तार किया। इन प्रयासों से आईआईएफसीएल की दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने की क्षमता बढ़ने और देश में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के विकास को सहायता मिलने की उम्मीद है। आईआईएफसीएल ने अपनी वित्तपोषण के स्रोतों में विविधता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार की गारंटी के बिना निधियां जुटाने के विकल्पों का भी पता लगाया।

बॉन्ड निर्गम और रेटिंग

आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान बॉन्ड के निजी नियोजन के माध्यम से ₹3,560 करोड़ की राशि जुटाई है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल ने जुटाई गई कुल निधि का 100% उपयोग किया है।

आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण लिखतों (बॉन्ड और एनसीडी) को क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, केयरएज रेटिंग्स और ब्रिकवर्क रेटिंग्स द्वारा उच्चतम रेटिंग 'एएए, स्थिर परिदृश्य' प्रदान की गई है। आईआईएफसीएल को प्रदान की गई रेटिंग को फिच रेटिंग्स द्वारा

'बीबीबी–, स्थिर परिदृश्य' के रूप में पुनःपुष्ट किया गया है, जो संप्रभु रेटिंग के समकक्ष है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करना

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की 18 जनवरी 2016 की अधिसूचना के अनुसार, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण इंड एएस के अनुसार तैयार किए हैं।

पुनर्गठित ऋण, गैर–निष्पादित आस्तियां और वसूली

31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, सकल गैर–निष्पादित आस्तियां ₹325.57 करोड़ थीं और निवल गैर–निष्पादित आस्तियां शून्य थीं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025–26 के दौरान ₹166.15 करोड़ की राशि वाले खातों को बट्टे खाते में डाल दिया गया। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, सकल गैर–निष्पादित आस्ति अनुपात 0.39% और निवल गैर–निष्पादित आस्ति अनुपात 0% था। 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार प्रावधान कवरेज अनुपात 100% था। वर्ष 2025–26 के दौरान ₹880.75 करोड़ की वसूली की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, बट्टे खाते में डाले गए/एआरसी खातों से ₹568.18 करोड़ की वसूली शामिल है, जिसमें प्रतिभूति रसीदों और गैर–परिवर्तनीय डिबेंचरों के मोचन से क्रमशः ₹229.59 करोड़ और ₹15.86 करोड़ शामिल हैं।

शीघ्र समाधान/वसूली के लिए प्रमुख ऋणदाता/संघ के परामर्श से आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। आईआईएफसीएल कई मामलों में रियायत प्रदान करने वाले प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के साथ संवाद करके समाधान प्राप्त करने की दिशा में पहल कर रहा है, जैसे समाप्ति भुगतान, पूर्ण किए गए कार्यों के आधार पर निपटान, समाधान योजना, मध्यस्थता प्रक्रिया, एनएआरसीएल/अन्य एआरसी को आस्ति की बिक्री, वसूली कार्रवाई शुरू करना आदि। उच्च मूल्य वाले खातों की निकटता से निगरानी की जा रही है और उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन मामलों में मध्यस्थता कार्यवाही चल रही है, उनकी भी निकटता से निगरानी की जा रही है। आईआईएफसीएल समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए डीआरटी/सीआईआरपी/एनसीएलटी के अंतर्गत मामलों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।

जोखिम प्रबंधन

आईआईएफसीएल में जोखिम प्रबंधन में जोखिम की पहचान, आकलन, मापन और शमन शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूंजी और लाभप्रदता पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करना है। आईआईएफसीएल अवसंरचना वित्तपोषण में अंतर्निहित विभिन्न जोखिमों के संपर्क में है, जिनमें प्रमुख रूप से ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम शामिल हैं तथा जलवायु और ईएसजी से संबंधित जोखिमों की प्रासंगिकता भी बढ़ रही है। यह मानते हुए कि मजबूत जोखिम प्रबंधन दीर्घकालिक स्थिरता, नियामकीय अनुपालन और मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, आईआईएफसीएल ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक व्यापक एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। यह ढांचा जोखिम प्रबंधन संबंधी निर्णयों के लिए मार्गदर्शक मानदंड प्रदान करता है और संगठन के सभी स्तरों पर सक्रिय जोखिम पहचान, आकलन और शमन को समाहित करते हुए आईआईएफसीएल की जोखिम क्षमता को उसके रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप बनाता है।

विभिन्न प्रकार के जोखिमों को रोकने या कम करने के लिए, आईआईएफसीएल सभी स्तरों पर अधिक जोखिम–जागरूकता की संस्कृति विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और नियंत्रणों तथा सुरक्षा उपायों में निरंतर सुधार के लिए कार्य करता है। आईआईएफसीएल मजबूत नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करके अपनी सभी आस्तियों से संबंधित जोखिमों का व्यवस्थित रूप से मापन, मूल्यांकन, अनुश्रवण और प्रबंधन करता है।

महत्वपूर्ण उद्योगों और आईआईएफसीएल के पोर्टफोलियो पर भू–राजनीतिक संकटों के प्रभाव के साथ–साथ विनियमों और सरकारी नीतियों में होने वाले परिवर्तनों की निरंतर निकटता से निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, उभरते जोखिमों, प्रौद्योगिकियों और प्रवृत्तियों पर विशेष अनुसंधान किया जाता है। सुविचारित ऋण संबंधी निर्णयों में सुविधा प्रदान करने के लिए इन रिपोर्टों को संबंधित व्यावसायिक समूहों को भेजा जाता है।

आईआईएफसीएल में जोखिम प्रबंधन ढांचा बहु–स्तरीय जोखिम शासन संरचना पर आधारित है, जिसमें निदेशक मंडल स्तर और प्रबंधन स्तर दोनों पर निगरानी तंत्र शामिल हैं। निदेशक मंडल स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) पूरे उद्यम के जोखिम पर रणनीतिक निगरानी रखती है। इसे प्रबंधन स्तर की विभिन्न समितियों का सहयोग प्राप्त है, जिनमें ब्याज दर और चलनिधि जोखिम के लिए आस्ति–देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), पोर्टफोलियो स्तर के ऋण जोखिम के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालन हानि घटनाओं और नियंत्रणों के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा पूंजी पर्याप्तता और तनाव परीक्षण की निगरानी के लिए आईसीएएपी संचालन समिति शामिल हैं। ये समितियां प्रमुख जोखिम संकेतकों (केआरआई) की निगरानी करने, जोखिम सीमाओं के अनुपालन की समीक्षा करने और जहां आवश्यक हो, जोखिम क्षमता ढांचे के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए निर्धारित अंतराल पर बैठक करती हैं। इन समितियों के सभी प्रमुख निर्णय और जोखिम संबंधी निष्कर्ष सूचित निगरानी और एकीकृत शासन के लिए निदेशक मंडल स्तर की आरएमसी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं।

आईआईएफसीएल **"तीन रक्षा–पंक्तियों"** के मॉडल का पालन करता है:

पहली पंक्ति: व्यावसायिक इकाइयां अपनी गतिविधियों में जोखिमों की पहचान और उनका प्रबंधन करती हैं।

दूसरी पंक्ति: स्वतंत्र जोखिम और अनुपालन कार्य निगरानी प्रदान करते हैं।

तीसरी पंक्ति: आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करती है।

आईआईएफसीएल जोखिम–जागरूक संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देता है, जिसे सभी स्तरों पर आंकड़ा–आधारित निर्णय लेने और क्षमता निर्माण संबंधी पहलों का समर्थन प्राप्त है। वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल ने प्रमुख जोखिम प्रबंधन नीतियों की व्यापक समीक्षा की, जिनमें ऋण जोखिम, बाजार और चलनिधि जोखिम, परिचालन जोखिम, व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा पुर्नप्राप्ति योजना (डीआरपी) से संबंधित नीतियां शामिल हैं। ये समीक्षाएं बदलती व्यावसायिक गतिशीलता, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियामकीय निर्देशों और अग्रणी उद्योग प्रथाओं के अनुरूप की गईं।

आंतरिक जोखिम आकलन क्षमताओं को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, आईआईएफसीएल अपने अवसंरचना क्षेत्र–विशिष्ट आंतरिक जोखिम रेटिंग मॉडलों का बाहरी सत्यापन भी कराता है। इसके अतिरिक्त, अधिक दूरदर्शी और जोखिम–संवेदी पूंजी नियोजन प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने के लिए कंपनी ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) लागू की और लागू एनबीएफसी नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप आईसीएएपी परिणाम दस्तावेज तैयार किया। इन पहलों ने कंपनी की आंतरिक जोखिम परिमाणीकरण क्षमताओं को मजबूत किया है और पूंजी आवंटन तथा पोर्टफोलियो प्रबंधन के लिए अधिक जोखिम–संवेदी दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता की है।

आईआईएफसीएल अवसंरचना उद्योग के अनुरूप तैयार किए गए विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम आकलन मॉडलों और स्कोरकार्ड का उपयोग करके उधारकर्ता–विशिष्ट ऋण जोखिम का मूल्यांकन करता है। ईएसजी मापदंडों की एक श्रृंखला के आधार पर उधारकर्ताओं का आकलन करने के लिए एक ईएसजी रेटिंग मॉडल विकसित किया गया है, जिसमें आंतरिक जोखिम रेटिंग आकलनों के अंतर्गत ईएसजी जोखिम को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल ने उधारकर्ता स्तर के साथ–साथ पोर्टफोलियो स्तर पर भौतिक और संक्रमण जोखिमों का आकलन करने के लिए जलवायु जोखिम आकलन उपकरण भी विकसित किया है।

आईआईएफसीएल जोखिम–आधारित स्तरीकरण दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए रेटिंग मॉडलों के आवधिक सत्यापन के लिए ऋण जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से मॉडल सत्यापन करता है। मॉडलों को परियोजना के चरण तथा उसके क्षेत्र–विशिष्ट महत्वपूर्ण मापदंडों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। इससे प्रभावी शासन, नियामकीय अनुपालन और मॉडल की सुदृढ़ता सुनिश्चित होती है।

आस्ति–देयता और बाजार जोखिम प्रबंधन

प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी आस्ति–देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ), चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम और विदेशी विनिमय जोखिम के प्रबंधन की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। इन वित्तीय जोखिमों को आईआईएफसीएल की समग्र रणनीतिक और वित्तीय नियोजन रूपरेखा में निकटता से समाहित किया गया है, ताकि सुदृढ़ तुलन–पत्र प्रबंधन और वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित की जा सके।

ऋण उत्पादों का मूल्य निर्धारण उत्पाद स्तर के जोखिमों और विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं से जुड़े असंगत जोखिमों के अनुरूप निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक परियोजना और उधारकर्ता की प्रोफाइल के लिए एक विशिष्ट ऋण जोखिम प्रीमियम निर्धारित किया जाता है, जिसे जोखिम–समायोजित प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए अंतिम मूल्य निर्धारण में शामिल किया जाता है।

इन जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन के लिए कंपनी अंतराल विश्लेषण, चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और स्टॉक अनुपात दृष्टिकोण सहित विभिन्न विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करती है, जिससे सामान्य और तनावपूर्ण दोनों परिस्थितियों में चलनिधि स्थिति का आकलन किया जा सके। ये तंत्र यह सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं कि देयताओं के देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि बफर बनाए रखे जाएं और साथ ही आस्ति–देयता प्रबंधन में जोखिम–प्रतिफल संतुलन को अनुकूलित किया जाए।

ऋण जोखिम प्रबंधन

प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनी ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), कंपनी के ऋण जोखिम एक्सपोजर और समग्र पोर्टफोलियो प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। समिति ऋण जोखिम की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करने, निर्धारित जोखिम क्षमता सीमाओं के विरुद्ध एक्सपोजर की निगरानी करने तथा क्षेत्रगत और उधारकर्ता स्तर पर जोखिम संकेंद्रण की समीक्षा करने के लिए तिमाही बैठक करती है।

अपने जोखिम निगरानी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, सीआरएमसी संवेदनशीलता और परिदृश्य विश्लेषण करती है, प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों (ईडब्ल्यूआई) की निगरानी करती है और पूरे पोर्टफोलियो में उधारकर्ताओं की ऋण–योग्यता का आकलन करती है। इस आकलन में जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऋण जोखिम आकलन मॉडल (आरएएम) का सहयोग प्राप्त होता है, ताकि जोखिम मूल्यांकन में एकरूपता और वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित हो सके। इन प्रयासों का उद्देश्य संभावित ऋण गुणवत्ता में गिरावट की शीघ्र पहचान और उपयुक्त जोखिम शमन उपायों को समय पर लागू करना है, जिससे आस्ति गुणवत्ता बनी रहे और पोर्टफोलियो की सुदृढ़ता कायम रहे।

परिचालन जोखिम प्रबंधन

आईआईएफसीएल ने भारतीय रिजर्व बैंक की नियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप एक मजबूत परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) ढांचा स्थापित किया है। यह ढांचा सभी व्यावसायिक गतिविधियों में परिचालन जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी और शमन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करता है, जिसके निष्कर्षों को क्रमशः निर्णय लेने की प्रक्रिया में समाहित किया जा रहा है।

उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) कार्यान्वयन की निगरानी करती है और जोखिम एवं नियंत्रण स्व–मूल्यांकन (आरसीएसए), प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई), परिचालन हानि घटनाओं तथा नियंत्रण प्रभावशीलता के मूल्यांकन सहित प्रमुख उपकरणों की समीक्षा करती है। आईसीएएपी ढांचे को मजबूत करने के लिए परिचालन जोखिम हेतु पूंजी का आवंटन मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का उपयोग करके किया जाता है।

आईआईएफसीएल ने विक्रेता–संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तृतीय–पक्ष जोखिम प्रबंधन (टीपीआरएम) ढांचा लागू किया है। व्यवधानों के दौरान सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए आईटी प्रणालियों के लिए व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा पुनर्प्राप्ति (डीआर) केंद्र परिचालन में हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की नवंबर 2025 की परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन सुदृढ़ता संबंधी मार्गदर्शिका के अनुरूप, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान एक स्वतंत्र तृतीय–पक्ष परामर्शदाता के सहयोग से अपने परिचालन जोखिम प्रबंधन ढांचे की संरचित समीक्षा शुरू की है।

परिचालन जोखिम संबंधी कार्यप्रणालियों की प्रभावशीलता की समय–समय पर आंतरिक नियंत्रणों के माध्यम से समीक्षा की जाती है तथा आंतरिक लेखापरीक्षा, वैधानिक लेखापरीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी जांच से स्वतंत्र आश्वासन प्राप्त किया जाता है। कंपनी संगठन में मजबूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संरचित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित करती है।

आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया

आईआईएफसीएल सामान्य और तनावपूर्ण परिस्थितियों में एकल तथा समूह दोनों स्तरों पर पूंजी की पर्याप्तता की निगरानी के लिए वार्षिक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संचालित करता है। इसमें प्रथम स्तंभ के अंतर्गत ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम का मूल्यांकन तथा द्वितीय स्तंभ के अंतर्गत चलनिधि जोखिम, अनुपालन जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, संकेंद्रण जोखिम और अन्य जोखिमों का आकलन शामिल है, जबकि आवश्यकता के अनुसार पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। आईसीएएपी में नए और उभरते जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन भी शामिल है।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आईआईएफसीएल अपने जोखिम प्रोफाइल और व्यावसायिक योजनाओं के अनुरूप पर्याप्त पूंजी बनाए रखे। आईसीएएपी महत्वपूर्ण जोखिमों की निरंतर पहचान, आकलन और निगरानी के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है तथा आईआईएफसीएल की रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुरूप उसकी पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

इस प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने के लिए आईआईएफसीएल ने प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर एक आईसीएएपी संचालन समिति (आईएससी) गठित की है। आईएससी जोखिम आकलन के परिणामों की समीक्षा करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है।

जलवायु और ईएसजी जोखिम प्रबंधन

आईआईएफसीएल एक व्यापक जलवायु जोखिम प्रबंधन ढांचे के माध्यम से उभरते जलवायु जोखिमों के प्रति अपनी सुदृढ़ता को मजबूत कर रहा है। यह ढांचा अवसंरचना ऋण संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया के अंतर्गत भौतिक और संक्रमण, दोनों प्रकार के जोखिमों का आकलन और समाधान करने के लिए तैयार किया गया है। जलवायु जोखिम आकलन उपकरण सभी प्रमुख ऋण योजनाओं और वित्तपोषण संरचनाओं के साथ पूरी तरह अनुकूल है, जिससे जलवायु जोखिम संबंधी विचारों का निर्बाध एकीकरण संभव होता है। तृतीय–पक्ष की सहायता से तैयार यह उपकरण परियोजना और पोर्टफोलियो, दोनों स्तरों पर भौतिक जोखिमों (तीव्र और दीर्घकालिक) तथा संक्रमण जोखिमों का व्यवस्थित मूल्यांकन करता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में, आईआईएफसीएल ने भारत के सभी जिलों में संभावित आपदा जोखिमों का मानचित्रण करने के लिए एक मॉडल विकसित करके जलवायु जोखिम पर अपना ध्यान और बढ़ाया है तथा परियोजना नियोजन में जलवायु जोखिम आकलन को समाहित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यह व्यापक रणनीतिक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य हरित संक्रमण को सहायता प्रदान करना और स्थिरता–आधारित उपायों के माध्यम से अवसंरचना वित्तपोषण की लागत को कम करना है।

अपने दीर्घकालिक स्थिरता उद्देश्यों के अनुरूप, आईआईएफसीएल ने हरित, सामाजिक और स्थिरता बांड/ऋण के निर्गम के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु एक मजबूत स्थिरता और ईएसजी वित्तपोषण ढांचा विकसित किया है। यह ढांचा सुनिश्चित करता है कि प्राप्त निधियों का आवंटन पात्र अवसंरचना आस्तियों के लिए किया जाए, जो राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में योगदान करती हैं तथा पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हैं। कंपनी ने जलवायु रणनीति 2030 भी शुरू की है, जिसमें जलवायु जोखिम के एकीकरण के लिए एक संरचित रूपरेखा निर्धारित की गई है।



1200 मेगावाट अवादा आरजेएचएन, सनसे, सनरेज़, संधारणीय

इसी के अनुरूप, आईआईएफसीएल ने आईसीआरए से बाहरी ईएसजी प्रभाव रेटिंग प्राप्त की, जिसमें उसे 'अच्छा' ग्रेड मिला, जो पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन संबंधी कार्यनिष्पादन के उच्च मानकों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपनी स्थिरता संबंधी पहलों को रणनीतिक दिशा और निगरानी प्रदान करने के लिए आईआईएफसीएल ने स्थिरता और ईएसजी वित्तपोषण समिति का गठन किया है।

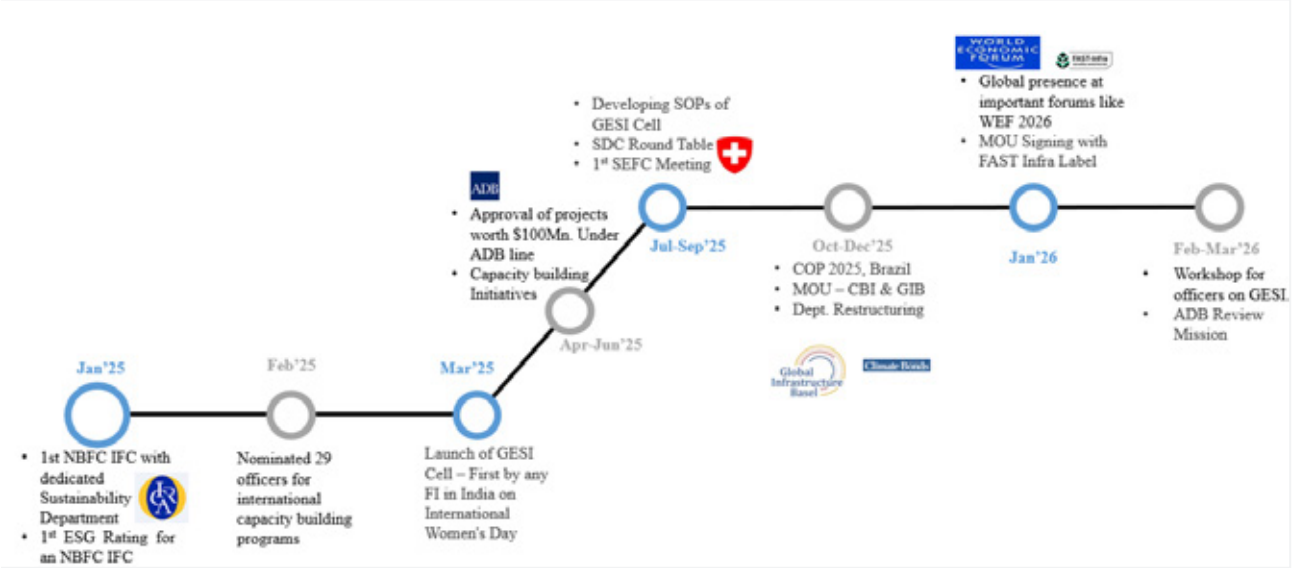
ईएसजी अनुपालन

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने अपनी अवसंरचना वित्तपोषण गतिविधियों में पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) संबंधी विचारों के एकीकरण को और मजबूत करना जारी रखा। यह वर्ष आईआईएफसीएल की सततता यात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का वर्ष रहा, जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपायों पर केंद्रित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर सतत वित्तपोषण, ईएसजी जोखिम प्रबंधन, लैंगिक और सामाजिक समावेशन, क्षमता निर्माण तथा सततता से संबंधित अभिशासन को समाहित करने वाले व्यापक संस्थागत ढांचे को अपनाया गया।

आईआईएफसीएल ने अपनी स्थिरता संबंधी कार्यप्रणालियों को बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास भागीदारों की आवश्यकताओं तथा उभरते घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता ढांचों के अनुरूप बनाना जारी रखा। ईएसजी जोखिमों की पहचान, परियोजना–स्तरीय जांच, पर्यावरणीय और सामाजिक समुचित सावधानी, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।

वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल ने एडीबी की ईएसजीआई ऋण–सीमा के अंतर्गत तकनीकी सहायता अनुदान के तहत क्रिसिल के सहयोग से जलवायु और ईएसजी जोखिम आकलन मॉडल विकसित करके अपनी ईएसजी जोखिम प्रबंधन क्षमताओं को भी आगे बढ़ाया। यह मॉडल जलवायु संबंधी और ईएसजी जोखिमों के संरचित मूल्यांकन को सक्षम बनाता है तथा परियोजना जांच और जोखिम आकलन में सहायता करता है। अधिकारियों को इसकी कार्यप्रणाली और व्यावहारिक अनुप्रयोग से परिचित कराने के लिए एक समर्पित कार्यशाला आयोजित की गई।

सततता और ईएसजी वित्तपोषण समिति (एसईएफसी) ने वर्ष के दौरान अपनी पहली बैठक आयोजित की, जिससे सततता और ईएसजी से संबंधित पहलों के संस्थागत अभिशासन और निगरानी को और मजबूत किया गया।



जिम्मेदार, लचीली और समावेशी अवसंरचना वित्तपोषण के लिए सततता को संस्थागत रूप देना

पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपाय

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, सततता कार्यप्रणालियां प्रभाग के अंतर्गत पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रबंधन इकाई (ईएसएमयू) ने विकास वित्त संस्थानों और बहुपक्षीय भागीदारों से प्राप्त विभिन्न ऋण–सीमाओं से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन को सुगम बनाना जारी रखा। प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल थे:

- उप–परियोजनाओं की पर्यावरणीय और सामाजिक जांच;
- पर्यावरणीय और सामाजिक समुचित सावधानी रिपोर्टों (ईएसडीडीआर) और वार्षिक सुरक्षा उपाय निगरानी रिपोर्टों (एएसएमआर) की समीक्षा और उनके तैयार करने में सहायता;
- जहां आवश्यक हो, परियोजना स्थलों का दौरा;
- विभिन्न ऋण–सीमाओं के लिए उपयुक्त परियोजना पाइपलाइन की पहचान और उसका रखरखाव;
- आंतरिक विभागों, उधारकर्ताओं और विकास भागीदारों के साथ समन्वय; और
- लागू पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन की निगरानी।

अवसंरचना में पर्यावरणीय रूप से संधारणीय विकास (ईएसजीआई) के वित्तपोषण के लिए एशियाई विकास बैंक की 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण–सीमा के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कुल 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनसे संबंधित प्रक्रियाओं ने अवसंरचना वित्तपोषण में ईएसजी संबंधी विचारों को समाहित करने के क्षेत्र में आईआईएफसीएल के संस्थागत अनुभव को और मजबूत किया।

वर्ष के दौरान पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित क्षमता निर्माण संबंधी पहल भी की गईं। एशियाई विकास बैंक की सुरक्षा उपाय टीम द्वारा संचालित अवसंरचना परियोजनाओं में लैंगिक उत्तरदायी और पर्यावरणीय रूप से संधारणीय विकास पर आयोजित कार्यशाला से हितधारक सहभागिता, प्रभाव आकलन तथा पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम निगरानी तंत्र के संबंध में अधिकारियों की समझ और मजबूत हुई।



अवसंरचना परियोजनाओं में लैंगिक दायित्व और पर्यावरणीय रूप से सतत विकास पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जिसका संचालन एशियाई विकास बैंक की सुरक्षा उपाय टीम द्वारा किया गया।

आईआईएफसीएल में सततता विभाग का परिचालन

वित्तीय वर्ष 2025–26, जनवरी 2025 में स्थापित आईआईएफसीएल के सततता वित्त विभाग के परिचालन का पहला पूर्ण वर्ष रहा। इस विभाग की स्थापना आईआईएफसीएल की स्थिरता यात्रा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि थी। पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन इकाई से विकसित इस विभाग की परिकल्पना एक व्यापक अधिदेश के साथ की गई थी, जिसका उद्देश्य अवसंरचना वित्तपोषण, जोखिम प्रबंधन, संस्थागत क्षमता निर्माण और व्यावसायिक रणनीति में स्थिरता को समाहित करना है।

सततता वित्त विभाग में दो प्रमुख प्रभाग शामिल हैं: सततता वित्त प्रभाग, जो हरित, सामाजिक और स्थिरता–संबद्ध वित्तपोषण के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता है; और सततता कार्यप्रणालियां प्रभाग, जो स्थिरता से संबंधित नीतियों, ढांचों और संस्थागत पहलों का नेतृत्व करता है तथा विकास वित्त संस्थानों और बहुपक्षीय ऋण–सीमाओं से जुड़ी पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन को सुगम बनाता है।

सततता कार्यप्रणालियां प्रभाग चार कार्यात्मक क्षेत्रों के माध्यम से कार्य करता है: पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन इकाई (ईएसएमयू); लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन प्रकोष्ठ (जीईएसआई); क्षमता निर्माण; और सततता इकाई।

संस्थागत क्षमता निर्माण

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान क्षमता निर्माण आईआईएफसीएल की स्थिरता रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बना रहा। विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने जलवायु वित्तपोषण, जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने की क्षमता, ईएसजी एकीकरण, पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा उपायों, लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन, अवसंरचना वित्तपोषण, सार्वजनिक–निजी भागीदारी, ऊर्जा संक्रमण और वैश्विक सतत वित्त नीति संबंधी संवाद जैसे विषयों पर केंद्रित कार्यक्रमों में भाग लिया।

इन कार्यक्रमों में कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, सम्मेलन, बाहरी शिक्षण कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय सहभागिताएं शामिल थीं, जिनसे अधिकारियों को सतत अवसंरचना वित्तपोषण में उभरती वैश्विक कार्यप्रणालियों से परिचित होने का अवसर मिला।

रणनीतिक साझेदारियां और वैश्विक सहभागिता

आईआईएफसीएल ने वर्ष के दौरान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्थिरता संबंधी हितधारकों के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत किया। कंपनी ने सतत अवसंरचना वित्तपोषण और ईएसजी कार्यप्रणालियों में सहयोग को मजबूत करने के लिए क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव (सीबीआई) और ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसल (जीआईबी) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। संधारणीय और लचीली अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए फास्ट–इन्फ्रा लेबल के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

आईआईएफसीएल ने विश्व आर्थिक मंच 2026 सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के अवसंरचना वित्तपोषण तंत्र का प्रतिनिधित्व किया और जलवायु वित्तपोषण, संधारणीय अवसंरचना तथा उभरते वित्तपोषण दृष्टिकोणों पर वैश्विक हितधारकों के साथ संवाद को सुगम बनाया।



वर्ष 2026 में विश्व आर्थिक मंच में आईआईएफसीएल की सहभागिता, जिससे सतत और लचीली अवसंरचना के वित्तपोषण पर वैश्विक संवाद को मजबूती मिली।



सतत और लचीली अवसंरचना के वित्तपोषण को आगे बढ़ाने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को सुदृढ़ करना।

सतत अवसंरचना पर क्षेत्र–स्तरीय संवाद को आगे बढ़ाना

वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल ने "शून्य शुद्ध उत्सर्जन और जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने की क्षमता हासिल करने के लिए शहरों में शहरी अवसंरचना का वित्तपोषण: चुनौतियां और अवसर" विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। विचार–विमर्श में संधारणीय वित्तपोषण के अवसरों की पहचान करने, परियोजनाओं को उपयुक्त वित्तपोषण स्रोतों से जोड़ने तथा जलवायु जोखिम और निगरानी, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन (एमआरवी) तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों–अवसंरचना वित्त कंपनियों (एनबीएफसी–आईएफसी), बहुपक्षीय संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, बैंकों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

सतत अवसंरचना के वित्तपोषण और सहयोगात्मक दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाने के लिए हितधारकों की सहभागिता और ज्ञान का आदान–प्रदान चर्चाओं में व्यापक परियोजना तैयारी, बैंक वित्तपोषण के योग्य परियोजनाओं की सुव्यवस्थित पाइपलाइन के विकास तथा व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, ऋण संवर्धन और गारंटी जैसे संरचित जोखिम–न्यूनीकरण साधनों के महत्व को भी रेखांकित किया गया। वास्तविक संधारणीयता परिणामों को प्रदर्शित करने तथा ग्रीनवॉशिंग और सोशल वॉशिंग के जोखिमों को कम करने के लिए सुदृढ़ निगरानी, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन (एमआरवी) और प्रभाव आकलन ढांचों को आवश्यक माना गया।



सतत अवसंरचना के वित्तपोषण और सहयोगात्मक दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाने के लिए हितधारकों की सहभागिता और ज्ञान का आदान–प्रदान

आईआईएफसीएल के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण

जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने की क्षमता, संक्रमण वित्तपोषण, ईएसजी जोखिम प्रबंधन, सततता संबंधी प्रकटीकरण और सतत अवसंरचना के लिए पूंजी जुटाने के बढ़ते महत्व के कारण सततता का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत के प्रमुख अवसंरचना–केंद्रित वित्तीय संस्थान के रूप में, आईआईएफसीएल देश को सतत, जलवायु सक्षम और समावेशी अवसंरचना के विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में सहयोग देने के लिए सुदृढ़ स्थिति में है।

आगे चलकर, आईआईएफसीएल का ध्यान निम्नलिखित पर केंद्रित करने का इरादा है:

- परियोजना आकलन और संस्थागत जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में ईएसजी के एकीकरण को और गहरा करना;
- जलवायु और ईएसजी जोखिम आकलन को सुदृढ़ करना तथा जोखिम–आधारित अवसंरचना वित्तपोषण को क्रमिक रूप से बढ़ाना;
- हरित और जलवायु वित्तपोषण संबंधी पहलों का विस्तार करना तथा नवोन्मेषी संधारणीय वित्तपोषण साधनों की संभावनाएं तलाशना;
- सततता प्रभाव आकलन में सुधार करने और हरितक्षरण के जोखिमों को कम करने के लिए निगरानी, रिपोर्टिंग एवं सत्यापन तंत्र को सुदृढ़ करना;
- ईएसजी संबंधी आंकड़ों के संग्रह, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना;
- लैंगिक समानता और सामाजिक समावेशन संबंधी पहलुओं के बेहतर एकीकरण के माध्यम से समावेशी अवसंरचना वित्तपोषण को समर्थन देना;
- ज्ञान के आदान–प्रदान, तकनीकी सहायता और संधारणीय पूंजी जुटाने में सुविधा प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारियों को सुदृढ़ करना;
- हितधारकों के सहयोग और बेहतर परियोजना तैयारी के माध्यम से बैंक वित्तपोषण के योग्य, जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप अवसंरचना परियोजनाओं की पाइपलाइन के विकास को समर्थन देना; और
- सतत अवसंरचना वित्तपोषण के क्षेत्र में संस्थागत क्षमता और विचार नेतृत्व को बढ़ाना।

इन रणनीतिक पहलों के माध्यम से, आईआईएफसीएल संधारणीय अवसंरचना वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और ज्ञान केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को क्रमिक रूप से सुदृढ़ करना चाहता है। साथ ही, वह ऐसी अवसंरचना को समर्थन देना चाहता है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य, पर्यावरणीय रूप से संधारणीय, सामाजिक रूप से समावेशी और उभरते जलवायु जोखिमों का सामना करने में सक्षम हो।

मानव पूंजी प्रबंधन

आईआईएफसीएल का मानव संसाधन दृष्टिकोण संगठन के दृष्टि एवं रणनीति के अनुरूप भारत के अवसंरचना क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु नवाचारी वित्तपोषण समाधान उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त प्रतिभा वाले उच्च प्रदर्शनकारी कार्यबल को आकर्षित करना, विकसित करना एवं बनाए रखना है।

मानव पूंजी प्रबंधन विभाग कर्मचारियों के विकास में सक्षमकारी भूमिका निभाता रहा है तथा उनके सर्वांगीण व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करता है। 31 मार्च 2026 तक, आईआईएफसीएल में कुल 149 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से 139 नियमित कर्मचारी तथा 10 संविदा आधार पर कार्यरत थे। कुल कर्मचारियों में 26.17% महिला कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल के सभी कर्मचारियों की औसत आयु 40 वर्ष से कम है।

वर्ष के दौरान, 02 अधिकारी (संविदा आधार पर) आईआईएफसीएल में सम्मिलित हुए। साथ ही, विभिन्न ग्रेडों (नियमित एवं संविदा) में 41 रिक्त पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई। नई भर्तियों के साथ–साथ पात्र अधिकारियों के लिए पदोन्नति प्रक्रिया भी संपन्न की गई, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल 19 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी त्याग दर न्यूनतम रही, जो 5.37% रही।

कंपनी के मानव संसाधनों के विकास के उद्देश्य से अधिकारियों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण, अन्य बातों के साथ–साथ, परियोजना वित्तपोषण, लेखांकन, जोखिम प्रबंधन, बॉन्ड बाजार, साइबर सुरक्षा, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर), ईएसजी, केवाईसी/एएमएल, सार्वजनिक खरीद आदि क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण सभी कर्मचारियों को, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, प्रदान किया गया।वरिष्ठ अधिकारियों को एफएसआईबी के माध्यम से आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम "आरोहण" हेतु भी नामित किया गया। वित्तीय वर्ष के दौरान सभी अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया तथा कुल मिलाकर 900 से अधिक मानव दिवस प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, आईआईएफसीएल द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के लिए तथा मध्य एवं कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए रणनीति बैठकें भी आयोजित की गईं।

कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्र, कॉरपोरेट क्रिकेट मैच, कर्मचारियों के लिए डेस्क योग सत्र आदि। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल का स्थापना दिवस, व्यावसायिक हितधारक बैठक, साइबर स्वच्छता पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, स्वास्थ्य संबंधी वार्ताएं, महिला दिवस समारोह, पर्यावरण दिवस, रक्तदान शिविर आदि जैसे अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कर्मचारियों के लाभ के लिए कर्मचारी कल्याण योजनाओं के अंतर्गत भी पहल की गईं।

आईआईएफसीएल में आरक्षण रोस्टर भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार संधारित किए जाते हैं तथा इनका वार्षिक रूप से मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) द्वारा परीक्षण किया जाता है और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है।

वर्ष के दौरान कर्मचारी संबंध शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे। कंपनी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से 'शून्य' शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए। आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली आरक्षण/छूट/रियायत संबंधी सभी सरकारी नीतियों का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025–26 में आयोजित भर्ती प्रक्रिया हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए भर्ती पूर्वप्रशिक्षण भी आईआईएफसीएल द्वारा प्रदान किया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पहलें

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए कारोबारी परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। इसका प्रमुख कारण डिजिटल रूपांतरण और उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाना है। इस रूपांतरण के अनुरूप, आईआईएफसीएल ने कई व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है और अपने मुख्य व्यावसायिक कार्यों का संचालन एसएपी प्लेटफॉर्म पर करता है।

अपनी डिजिटल रूपांतरण यात्रा के तहत, आईआईएफसीएल उन पहली सरकारी स्वामित्व वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक है, जिसने परियोजना सुपर के अंतर्गत अपने एसएपी ईसीसी को सफलतापूर्वक एसएपी एस/4एचएएनए में उन्नत किया है। आईआईएफसीएल ने निर्बाध व्यावसायिक परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रौद्योगिकी समाधान लागू करके अपने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना को और मजबूत किया है तथा उसका प्रभावी उपयोग किया है। इसके मुख्य व्यावसायिक अनुप्रयोगों को सरकारी सामुदायिक क्लाउड (जीसीसी) ढांचे के अंतर्गत नोएडा स्थित प्राथमिक डेटा केंद्र और मुंबई स्थित आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र में होस्ट किया गया है, जिससे उच्च उपलब्धता, सुरक्षा और व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित होती है।

आईआईएफसीएल ने विश्व व्यापार केंद्र (डब्ल्यूटीसी) में स्थित अपने नए कार्यालय में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अवसंरचना सफलतापूर्वक स्थापित की है, जिससे सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल डिजिटल कार्य वातावरण सुनिश्चित हुआ है। नए कार्यालय को आधुनिक नेटवर्किंग, संचार, साइबर सुरक्षा और सहयोगात्मक समाधानों से सुसज्जित किया गया है, ताकि निर्बाध व्यावसायिक परिचालन को समर्थन मिले और कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़े।

इसके अतिरिक्त, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, आईआईएफसीएल ने ग्राहक हितधारक बैठक के दौरान एक ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल शुरू किया है। यह पोर्टल ग्राहकों को जानकारी और सेवाओं तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता, परिचालन दक्षता और हितधारकों की सहभागिता बढ़ती है तथा अधिक तेज और प्रभावी सेवा प्रदान करना संभव होता है।

साइबर सुरक्षा, जिसमें साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाएं, यदि कोई हों, शामिल हैं

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान साइबर सुरक्षा संबंधी कोई घटना दर्ज नहीं की गई।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी पहल

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) एक पूर्णतः प्रतिबद्ध और सामाजिक रूप से उत्तरदायी संस्थान के रूप में पिछले चौदह वर्षों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, स्वच्छ पेयजल और भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण सहित विकास के विभिन्न क्षेत्रों में कुल मिलाकर लगभग ₹204 करोड़ का निवेश कर चुकी है।

कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में आईआईएफसीएल के निरंतर और रणनीतिक निवेश को इसकी 78 (अच्छा) की आईसीआरए ईएसजी प्रभाव रेटिंग के माध्यम से स्वतंत्र रूप से मान्यता दी गई है और इसकी पुष्टि की गई है। इसमें "सामाजिक" रेटिंग 88 (उत्कृष्ट) रही है। आईसीआरए ने विशेष रूप से आईआईएफसीएल की "प्रभावशाली और व्यापक सीएसआर पहलों, विशेषकर स्वास्थ्य, पोषण और ग्रामीण विकास" को मान्यता दी है। इनमें आकांक्षी जिलों में इसकी पहुंच और हाल के वर्षों में सीएसआर बजट में की गई पर्याप्त वृद्धि भी शामिल है। रेटिंग एजेंसी ने आईआईएफसीएल के सुदृढ़ निगरानी और प्रभाव आकलन ढांचे का भी उल्लेख किया है, जिसमें समय–समय पर स्थलों का भौतिक निरीक्षण और समुदायों के साथ प्रत्यक्ष संवाद शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्वीकृत निधियों का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप हो और जमीनी स्तर पर मापने योग्य परिणाम प्राप्त हों। यह "उत्कृष्ट" सामाजिक रेटिंग इस बात की पुष्टि करती है कि आईआईएफसीएल का सीएसआर कार्यक्रम केवल एक वैधानिक दायित्व नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक रूप से संचालित मंच है, जो समुदायों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजित करता है, समावेशी विकास को आगे बढ़ाता है और कंपनी की समग्र संधारणीयता रूपरेखा को सुदृढ़ करता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आईआईएफसीएल ने ₹40.54 करोड़ के अपने वैधानिक सीएसआर दायित्व को पूरा करते हुए ₹41.38 करोड़ मूल्य की 17 परियोजनाओं को स्वीकृति दी। ये परियोजनाएं 12 से अधिक राज्यों में फैली हुई थीं, जिनमें से 70% से अधिक परियोजनाएं सरकारी संस्थानों, जिला प्रशासनों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की गईं। यह संस्थागत साझेदारी मॉडल न केवल पारदर्शी और जवाबदेह परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है, बल्कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ समन्वय, परिसंपत्तियों की दीर्घकालिक संधारणीयता और अपर्याप्त सुविधाओं वाले भौगोलिक क्षेत्रों में विकास के अधिक गहन प्रभाव को भी बढ़ावा देता है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के परियोजना पोर्टफोलियो में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सुदृढ़ करना, डिजिटल शिक्षा का रूपांतरण, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना,

पर्यावरणीय संधारणीयता और विरासत संरक्षण शामिल हैं। ये सभी पहलें मिलकर देश के आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों और दूरदराज के क्षेत्रों में कमजोर समुदायों के सामने मौजूद सबसे महत्वपूर्ण कमियों को दूर करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के सीएसआर निष्पादन की झलक

विवरण	ब्यौरा
सीएसआर का सांविधिक दायित्व	₹40.54 करोड़
स्वीकृत कुल परियोजनाएं	17
स्वीकृत परियोजनाओं का कुल मूल्य	₹41.38 करोड़
वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	₹12.37 करोड़
यूसीएसआरए को अंतरित राशि	₹28.18 करोड़
शामिल किए गए राज्य	12+
सरकारी संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वित परियोजनाएं	>70%
संचयी सीएसआर निवेश (14 वर्षों में)	~₹204 करोड़

आंतरिक नियंत्रण

आईआईएफसीएल ने अपने परिचालनों के आकार, विस्तार और जटिलता के अनुरूप एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण ढांचा स्थापित किया है। इस ढांचे को परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने, आस्तियों की सुरक्षा करने, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता बनाए रखने तथा लागू वैधानिक आवश्यकताओं, नियामकीय दिशानिर्देशों और आंतरिक नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है।

आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नियमित रूप से प्रमुख कार्यात्मक और परिचालन क्षेत्रों की जोखिम–केंद्रित लेखापरीक्षा करता है। इन लेखापरीक्षाओं का उद्देश्य प्रक्रियाओं, नियंत्रणों और नीतियों के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करना तथा उचित सुधारात्मक और निवारक उपायों की सिफारिश करना है। वित्तीय वर्ष 2025–26 की आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया जारी है और लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियां तथा अनुपालन की स्थिति नियमित अंतराल पर समीक्षा, मार्गदर्शन और सिफारिशों के लिए निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचे को और सुदृढ़ करने तथा इसे विकसित होती नियामकीय अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए, आईआईएफसीएल ने भारतीय रिज़र्व बैंक की 3 फरवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2020–21/88, संदर्भ संख्या डीओएस.सीओ.पीपीजी./एसईसी.05/11.01.005/2020–21 के अनुसार जोखिम–आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) दृष्टिकोण अपनाया है। निदेशक मंडल ने जोखिम–आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति को अनुमोदित किया है, जिसकी लागू नियामकीय आवश्यकताओं और उभरते व्यावसायिक जोखिमों के साथ निरंतर अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए जोखिम–आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया जारी है और यह अनुमोदित आरबीआईए ढांचे के अनुसार की जा रही है। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की समय–समय पर समीक्षा करने के लिए कार्यपालकों की एक आंतरिक लेखापरीक्षा समिति (एसीई) का गठन किया गया है और अनुपालन की स्थिति सहित इन रिपोर्टों को निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

वित्तीय लेन–देन और उनसे संबंधित नियंत्रणों की नियमित, व्यवस्थित और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने के लिए, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2019–20 से समवर्ती लेखापरीक्षा तंत्र लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सनदी लेखाकारों की एक फर्म को समवर्ती लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 की समवर्ती लेखापरीक्षा की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, समवर्ती लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों की एसीई द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है और इसके बाद सुधारात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा एवं उन पर मार्गदर्शन के लिए उन्हें निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सूचना प्रणालियों, साइबर सुरक्षा नियंत्रणों और सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता के संबंध में आश्वासन प्रदान करने के लिए, आईआईएफसीएल ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 नवंबर, 2023 के मास्टर निदेश संख्या आरबीआई/2023–24/107, डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023–24 के अनुरूप सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा ढांचा लागू किया है। एक स्वतंत्र सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है और वित्तीय वर्ष 2025–26 की आईएस लेखापरीक्षा की प्रक्रिया जारी है। आईएस लेखापरीक्षा कंपनी की सूचना प्रणालियों की प्रभावशीलता और लागू नियामकीय आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में आश्वासन प्रदान करती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा, जोखिम–आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा और सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा से युक्त कंपनी का व्यापक आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा ढांचा, आंतरिक नियंत्रणों, जोखिम प्रबंधन, गवर्नेंस प्रक्रियाओं और नियामकीय अनुपालन की प्रभावशीलता

के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करता है। ये तंत्र जोखिमों की समयबद्ध पहचान और उनके न्यूनीकरण में सहायता करते हैं, आंतरिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करते हैं, नियंत्रण संबंधी कमियों और कमजोरियों को कम करते हैं तथा कंपनी के अभिशासन और नियंत्रण व्यवस्था में हितधारकों का विश्वास बढ़ाते हैं।

अनुपालन

आईआईएफसीएल में एक स्वतंत्र अनुपालन विभाग है, जो संगठन में अनुपालन की सुदृढ़ संस्कृति को बढ़ावा देते हुए लागू नियामकीय दिशानिर्देशों और आवश्यकताओं के अनुपालन पर नज़र रखने, उनकी समीक्षा करने और निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है। संगठन एक सुदृढ़ अनुपालन निगरानी ढांचा बनाए रखता है, जिसे अनुपालन कैलेंडर तथा व्यावसायिक, सहायता और परिचालन विभागों के साथ निरंतर समन्वय का समर्थन प्राप्त है, ताकि नियामकीय आवश्यकताओं का समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। अनुपालन विभाग अनुपालन की स्थिति की नियमित निगरानी और समीक्षा करता है तथा जहां भी लागू हो, अनुपालन न किए जाने के मामलों की समय पर पहचान करने और उन्हें उच्च स्तर पर भेजने में सहायता करता है। अनुपालन निगरानी प्रक्रिया को और सुदृढ़ करने के लिए, आईआईएफसीएल ने अनुपालन संबंधी जोखिमों और दायित्वों की पहचान, आकलन, निगरानी, प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए एक वेब–आधारित अनुपालन प्रबंधन अनुप्रयोग लागू किया है। यह प्रणाली नियामकीय अनुपालनों की व्यवस्थित निगरानी को सुगम बनाती है तथा अनुपालन संबंधी मामलों की प्रभावी निगरानी और रिपोर्टिंग में सहायता करती है।

आईएसओ 9001:2005 प्रमाणन

आईआईएफसीएल एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित कंपनी बनी हुई है, जिसके पास स्थापित और प्रलेखित गुणवत्ता नीति, गुणवत्ता नियमावली तथा विभागीय प्रक्रियाएं हैं। आईआईएफसीएल एक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) लागू करता है और उसे बनाए रखता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आईआईएफसीएल की सेवाएं निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हों और इसकी प्रभावशीलता में निरंतर सुधार होता रहे। क्यूएमएस ढांचे से संबंधित दस्तावेजों को आईआईएफसीएल की नीतियों में संशोधनों, आईएसओ 9001 मानक में बदलावों या व्यावसायिक प्रक्रियाओं में परिवर्तनों के आधार पर समय–समय पर अद्यतन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आपकी कंपनी ने आईएसओ 9001:2015 मानक प्रमाणन और इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) रूपरेखा की अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं का पालन किया। आईएसओ 9001:2015 मानक की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए, प्रत्येक छह महीने में आंतरिक गुणवत्ता लेखापरीक्षाएं आयोजित की गईं। इसके बाद ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त की गई और प्रबंधन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, ताकि इसकी निरंतर उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके तथा सुधार के अवसरों का आकलन किया जा सके। आईआईएफसीएल प्रबंधन अपने हितधारकों को व्यावसायिक परिचालनों और सेवा प्रदान करने में क्यूएमएस अनुपालन के पालन पर विशेष जोर देता है, जिस पर समय–समय पर आयोजित प्रबंधन समीक्षा बैठकों में लगातार विचार–विमर्श किया जाता है। आईआईएफसीएल का आईएसओ 9001 प्रमाणन 7 फरवरी, 2029 तक वैध है। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आपकी कंपनी ने आईएसओ 9001:2015 मानक के प्रमाणन की निरंतरता बनाए रखने के लिए बाहरी प्रमाणन एजेंसी के माध्यम से अपना आईएसओ प्रमाणपत्र नवीनीकृत कराया।

शेयर पूंजी

आईआईएफसीएल की संपूर्ण चुकता इक्विटी शेयर पूंजी भारत सरकार के पास है और आईआईएफसीएल के सभी शेयरधारक भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं।

31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹10,000 करोड़ थी और चुकता शेयर पूंजी ₹9999,91,62,300 थी, जिसमें ₹10 प्रत्येक के 999,99,16,230 इक्विटी शेयर शामिल थे, जो पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में हैं। वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को कोई इक्विटी अंशदान प्राप्त नहीं हुआ।

लाभांश

आईआईएफसीएल मौजूदा दिशानिर्देशों और वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए लाभांश का भुगतान करने के लिए पात्र है। व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, निदेशक मंडल ने आईआईएफसीएल को वित्त वर्ष 2025–26 के लिए लाभांश के भुगतान के लिए सरकार से छूट मांगने का निर्देश दिया।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

आपकी कंपनी को आधारभूत संरचना सुविधाओं के लिए वित्तपोषण के कारोबार से जुड़ा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी होने के कारण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रासंगिक प्रावधान से छूट प्राप्त है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से वस्तुओं व सेवाओं की खरीद

आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कुल ₹794 लाख की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की। इसमें से ₹629 लाख अर्थात मूल्य के आधार पर 79% की खरीद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से की गई। इसके अतिरिक्त, ₹251 लाख अर्थात मूल्य के आधार पर 31% से अधिक की खरीद भारत सरकार के जीईएम पोर्टल के माध्यम से की गई।

निदेशक मंडल

आज की तारीख के अनुसार, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	डी आई एन	पैन	श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	पुर्नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद की संख्या (सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17क संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक पद की संख्या (सूचीबद्ध ता विनियमों के विनियम 17क(1) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित लेखापरीक्षा/ हितधारक समिति (समितियों) में सदस्यों की संख्या (सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 26(1) का संदर्भ लें)	इस सूचीबद्ध इकाई सहित सूचीबद्ध संस्थाओं में आयोजित लेखापरीक्षा/ हितधारक समिति में अध्यक्ष के पद की संख्या (सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 26(1) का संदर्भ लें)
श्री रोहित ऋषि (टिप्पणी संख्या 1)	11524681	ADTPR2410F	प्रबंध निदेशक	04.02.2026	-	04.04.1969	1	शून्य	1	शून्य
श्री पलाश श्रीवास्तव (टिप्पणी संख्या 2)	02007911	AAKPK5448E	उप प्रबंध निदेशक	28.02.2025	-	15.09.1972	1	शून्य	2	शून्य
श्री चंद्रदीप कुमार झा, (टिप्पणी संख्या 3)	11417133	ADSPJ5706B	सरकार द्वारा नामित निदेशक	09.12.2025	-	16.09.1975	2	शून्य	2	शून्य
सुश्री लाया मादुरी, (टिप्पणी संख्या 4)	11704330	ANVPM8315N	सरकार द्वारा नामित निदेशक	19.06.2025	-	14.04.1985	3	शून्य	3	शून्य
श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी (टिप्पणी संख्या 5)	08941266	AARPC0039J	सरकार द्वारा नामित निदेशक	29.10.2020	-	24.08.1973	1	शून्य	1	शून्य
श्री अमित कुमार श्रीवास्तव (टिप्पणी संख्या 6)	08099846	AENPS1455E	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	27.02.2026	-	29.09.1970	2	शून्य	1	1
श्री आशुतोष चौधरी (टिप्पणी संख्या 7)	09245804	AERPC4817N	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	28..07.2026	-	04.09.1975	2	शून्य	3	1

टिप्पणियां:

1. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ.सं. 18/5/2022–आईएफ–I दिनांक 27 जनवरी, 2026 के माध्यम से सूचित किया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत श्री रोहित ऋषि (जन्म तिथि 04.04.1969) को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के प्रबंध निदेशक (एमडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई है। श्री रोहित ऋषि ने 4 फरवरी, 2026 से आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
2. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ.सं. 18/4/2024/आईएफ–I दिनांक 28 फरवरी, 2025 के माध्यम से सूचित किया कि आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के पद पर कार्यरत श्री पलाश श्रीवास्तव (जन्म तिथि 15.09.1972) को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, की गई है। श्री पलाश श्रीवास्तव ने 28 फरवरी, 2025 से आईआईएफसीएल के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

   इसके बाद, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ.सं. 18/5/2022–आईएफ–I दिनांक 02 जुलाई, 2025 के माध्यम से सूचित किया कि सक्षम प्राधिकारी ने श्री पलाश श्रीवास्तव, उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी), आईआईएफसीएल को अतिरिक्त प्रभार के आधार पर आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक (एमडी) के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का

दायित्व सौंपा है। यह दायित्व 29.05.2025 से 28.11.2025 तक छह (06) महीने की अवधि के लिए सौंपा गया था। वित्तीय सेवा विभाग के पत्र संख्या 18/5/2022–आईएफ–I दिनांक 27 जनवरी, 2026 के माध्यम से इस अतिरिक्त प्रभार की अवधि 28.11.2025 के बाद छह (06) महीने के लिए, अर्थात 28.05.2026 तक या आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी गई थी। श्री रोहित ऋषि द्वारा आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने पर, अतिरिक्त प्रभार के आधार पर प्रबंध निदेशक के रूप में श्री पलाश श्रीवास्तव का कार्यकाल 04 फरवरी, 2026 को पूर्ण हो गया।

3. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 6/2(iv)/2022–बीओ-I दिनांक 03 दिसंबर, 2025 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(i) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय में उप महानिदेशक श्री चंद्रदीप कुमार झा को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, सुश्री एम.जी. जयश्री के स्थान पर आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया है। यह नियुक्ति निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आवंटित किए जाने की तिथि, अर्थात 09 दिसंबर, 2025 से प्रभावी है।

4. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 3/1/2010–आईएफ–I (खंड IV) दिनांक 19 जून, 2026 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के ज्ञापन के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(i) के प्रावधानों और संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री लाया मादुरी को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री आलोक तिवारी के स्थान पर आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

5. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 3/1/2010/आईएफ– I (खंड IV) दिनांक 28 अक्टूबर, 2020 के माध्यम से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के संस्था के अंतर्नियम(एओए) के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(i) के प्रावधानों के अनुसार, श्री संजय कुमार साहा के स्थान पर सलाहकार (पीएएमडी) श्री च. पार्थ सारथी रेड्डी (आईआरएसईई) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी से अवगत कराया है। श्री च. पार्थ सारथी रेड्डी की नियुक्ति 29 अक्टूबर, 2020 से प्रभावी है, अर्थात यह निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आवंटित किए जाने की तिथि है।

6. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ.सं. 3/1/2010/आईएफ– I (खंड IV) दिनांक 27 फरवरी, 2026 के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री अमित कुमार श्रीवास्तव को आईआईएफसीएल के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, श्री कल्याण कुमार के स्थान पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने की सूचना दी है।

7. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7/2022–आईएफ– I (खंड IV) दिनांक 31 जुलाई, 2026 के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री द्वारा 28 जुलाई, 2026 को दी गई मंजूरी से अवगत कराया है। इस मंजूरी के अनुसार, इंडियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक श्री आशुतोष चौधरी को आईआईएफसीएल के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, संजय रुद्र के स्थान पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति माननीय वित्त मंत्री द्वारा 28 जुलाई, 2026 को मंजूरी दिए जाने की तिथि से प्रभावी है और अगले आदेश तक लागू रहेगी।

दिनांक 01 अप्रैल 2025 से अब तक की अवधि के दौरान आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल से पदमुक्त हुए व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:–

नाम	डीआईएन	पैन	श्रेणी	अवधि
श्री आलोक तिवारी (टिप्पणी संख्या 1 का संदर्भ लें)	11409207	AFYPT4553J	सरकार द्वारा नामित निदेशक	04.12.2025 से 19.06.2026 तक
श्री समीर जेरमभाई बोगहरा (टिप्पणी संख्या 2 का संदर्भ लें)	10163651	ABOPB8460C	स्वतंत्र निदेशक	15.05.2023 से 09.05.2026 तक
श्री संजय रुद्र (टिप्पणी संख्या 3 का संदर्भ लें)	09650826	AFMPR9680N	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	01.07.2024 से 30.06.2026 तक
सुश्री एम.जी. जयश्री (टिप्पणी संख्या 4 का संदर्भ लें)	8991135	AGTPM9099G	सरकार द्वारा नामित निदेशक	06.08.2024 से 03.12.2025 तक
श्री कल्याण कुमार (टिप्पणी संख्या 5 का संदर्भ लें)	09631251	AADPY6669A	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	21.09.2022 से 27.02.2026 तक

नाम	डीआईएन	पैन	श्रेणी	अवधि
श्री सोलोमन अरोकियाराज, (टिप्पणी संख्या 6 का संदर्भ लें)	06802660	ADZPA3994P	सरकार द्वारा नामित निदेशक	23.01.2023 से 21.07.2025 तक
श्री बलदेव पुरुषार्थ (टिप्पणी संख्या 7 का संदर्भ लें)	07570116	AMEPP3669G	सरकार द्वारा नामित निदेशक	21.07.2025 से 27.11.2025 तक
श्री पी.आर. जयशंकर, (टिप्पणी संख्या 8 का संदर्भ लें)	06711526	AAHPJ5736F	प्रबंध निदेशक	29.05.2020 से 28.05.2025 तक

कंपनी में उनके अमूल्य योगदान के लिए बोर्ड अपना आभार प्रकट करता है।

टिप्पणियां:

1. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 3/1/2010–आईएफ–I (खंड IV) दिनांक 19 जून, 2026 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के ज्ञापन के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(i) के प्रावधानों और संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, केंद्र सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री लाया मादुरी को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री आलोक तिवारी के स्थान पर आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।
2. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ.सं. 18/7/2022/आईएफ–I दिनांक 10 मई, 2023 के माध्यम से आईआईएफसीएल के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 115(1)(क) के प्रावधानों के अनुसार, श्री समीरभाई जेरमभाई बोगहरा को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, उनकी नियुक्ति के आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया था। तदनुसार, उनका कार्यकाल 09 मई, 2026 को पूर्ण हो गया।
3. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7/2022–आईएफ–I दिनांक 31 जुलाई, 2026 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के ज्ञापन के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(ii) के प्रावधानों और संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, केंद्र सरकार ने इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री आशुतोष चौधरी को आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और इंडियन बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति तक या अगले आदेश तक, श्री संजय रुद्र के स्थान पर नामित किया है। श्री संजय रुद्र 30 जून, 2026 से सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए थे।
4. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 6/2(iv)/2022–बीओ-I दिनांक 3 दिसंबर, 2025 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के ज्ञापन के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(i) के प्रावधानों और संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, केंद्र सरकार ने उप महानिदेशक श्री चंद्रदीप कुमार झा को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, सुश्री एम.जी. जयश्री के स्थान पर आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।
5. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 3/1/2010–आईएफ–I (खंड IV) दिनांक 27 फरवरी, 2026 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के ज्ञापन के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(ii) के प्रावधानों और संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, केंद्र सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री अमित कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, श्री कल्याण कुमार के स्थान पर आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।
6. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 18/7/2022–आईएफ–I दिनांक 21 जुलाई, 2025 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के ज्ञापन के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(i) के प्रावधानों और संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, केंद्र सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव श्री बलदेव पुरुषार्थ को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक, आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री सोलोमन अरोकीयाराज के स्थान पर आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।
7. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27 नवंबर, 2025 के पत्र संख्या 18/7/2022–आईएफ–आई के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के ज्ञापन के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(i) के प्रावधानों और संस्था के अंतर्नियम के अनुसार, केंद्र सरकार ने श्री बलदेव पुरुषार्थ, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के स्थान पर श्री आलोक तिवारी, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग को आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशक के रूप में तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक नामित किया है। यह नियुक्ति निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आवंटित होने की तिथि, अर्थात् 4 दिसंबर, 2025 से प्रभावी हुई।
8. वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 4 जून, 2025 के पत्र संख्या एफ.सं. 18/1/2020–आईएफ–आई के माध्यम से सूचित किया है कि आईआईएफसीएल के प्रबंध निदेशक डॉ. पी.आर. जयशंकर का कार्यकाल 28 मई, 2025 को समाप्त हो गया।

निदेशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) की अपेक्षानुसार, एतत् द्वारा पुष्टि की जाती है:

क. कि 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में लागू लेखा मानकों का पालन किया गया था और इससे किसी भी तरह का महत्वपूर्ण विचलन नहीं हुआ।

ख. कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया और उन्हें निरंतर लागू किया और निर्णय और अनुमान लगाए जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों के बारे में और अंत में समीक्षा वर्ष के लिए कंपनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

ग. कि निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पत्तियो की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की।

घ. कि निदेशकों ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों को एक नियमित संबंधित विषयों के आधार पर तैयार किया।

ङ कि निदेशकों ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किये थे और जिनका पालन कंपनी द्वारा किया जाएगा और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

च. कि निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और बताया गया कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त थी और प्रभावी रूप से कार्य कर रही थी।

कॉर्पोरेट अभिशासन

कॉरपोरेट अभिशासन प्रबंधन द्वारा अपनाए गए उन स्वीकृत सिद्धांतों का समूह है, जिनके अंतर्गत शेयरधारकों के अपरिहार्य अधिकारों को निगम के वास्तविक स्वामी के रूप में मान्यता दी जाती है तथा प्रबंधन अपनी भूमिका को शेयरधारकों की ओर से न्यासी (ट्रस्टी) के रूप में निभाता है। कॉरपोरेट अभिशासन पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी तथा समाज का सुदृढ़ एवं संतुलित आर्थिक विकास संभव होता है। तदनुसार, कॉरपोरेट जगत में कॉरपोरेट अभिशासन प्रथाओं को अपनाने एवं सुदृढ़ करने के प्रति व्यापक जागरूकता एवं प्रतिबद्धता परिलक्षित हो रही है।

आपकी कंपनी ऐसी कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दर्शन के अनुरूप कॉरपोरेट संरचना, व्यवसाय संचालन और प्रकटीकरण प्रथाओं को विकसित करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 22 जनवरी, 2015 के पत्र संख्या एफ.सं. 18/6/2014–आईएफ–आई के माध्यम से सूचित किए गए अनुसार, दिनांक 31.03.2026 को आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है: दो (2) पूर्णकालिक निदेशक, जिनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा, तीन (3) सरकारी नामित निदेशक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो (2) निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित एक (1) निदेशक और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या। दिनांक 03.09.2026 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक (ईजीएम) में आईआईएफसीएल ने पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या दो से बढ़ाकर तीन कर दी है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल ने वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग से अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर विचार करने का अनुरोध किया है।

आपकी कंपनी समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी, वित्तीय विवरणों के समेकन से संबंधित लागू लेखा मानकों के अनुसार करती है। प्रबंधन द्वारा उन सभी महत्वपूर्ण वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेन–देन से संबंधित विवरण निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनमें प्रबंधन की व्यक्तिगत रुचि हो सकती है और जिनसे कंपनी के हितों के साथ संभावित हित–टकराव उत्पन्न हो सकता है। अर्थव्यवस्था की स्थिति, कंपनी के प्रदर्शन तथा अन्य परिचालन संबंधी विषयों पर रिपोर्टों की नियमित रूप से निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाती है।

वर्ष के दौरान बोर्ड–बैठकें

कंपनी का निदेशक मंडल नेतृत्व और रणनीतिक दिशा प्रदान करता है तथा अपने वस्तुनिष्ठ निर्णय प्रस्तुत करता है, ताकि कंपनी के कामकाज पर नियंत्रण रखा जा सके और कुशल प्रबंधन के माध्यम से हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की सोलह बैठकें 08 मई 2025, 20 मई 2025, 17 जून 2025, 18 जून 2025, 20 जून 2025, 04 जुलाई 2025, 11 अगस्त 2025, 19 सितंबर 2025, 29–30 सितंबर 2025, 13 नवंबर 2025, 05 दिसंबर 2025, 30 दिसंबर 2025, 30 जनवरी 2026, 12 फरवरी 2026, 20 मार्च 2026 और 27 मार्च 2026 को आयोजित की गईं।

निदेशक मंडल की समिति

बोर्ड विशिष्ट संचालन क्षेत्रों की निगरानी के लिए गठित पूर्ण बोर्ड या विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करता है। बोर्ड की प्रत्येक समिति संदर्भ की शर्तों द्वारा निर्देशित होती है, जो समिति की संरचना, दायरे और शक्तियों को परिभाषित करती है। समितियां नियमित अंतराल पर बैठकें करती हैं और विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उन्हें दिए गए अधिकार के भीतर निर्णय से अवगत कराती हैं।

31 मार्च, 2026 तक, बोर्ड की निम्न समितियां थीं:

1. लेखा परीक्षा समिति
2. प्रबंधन और निवेश समिति
3. जोखिम प्रबंधन समिति
4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
5. पारिश्रमिक और नामांकन समिति
6. हितधारक सम्बन्ध समिति
7. आईटी रणनीति समिति

निदेशक मंडल तथा मंडल–स्तरीय समितियों की बैठकें सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप आयोजित की गई हैं। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अंतर्गत निर्धारित निदेशक मंडल एवं मंडल–स्तरीय समिति बैठकों की आवृत्ति तथा बैठकों के लिए आवश्यक कोरम की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, समिति सदस्यों को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा–निर्देशों में निर्दिष्ट उनकी शक्तियों, भूमिकाओं एवं दायित्वों के संबंध में अवगत कराया गया है। त्रैमासिक कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्टें विधिवत रूप से निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं। साथ ही, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 62 के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण आईआईएफसीएल की वेबसाइट (www.iifcl.in) पर किए गए हैं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

लेखापरीक्षा समिति का गठन 29 मई, 2006 को आयोजित तीसरी बोर्ड बैठक में किया गया था। लेखापरीक्षा समिति का अंतिम पुनर्गठन 24 जून 2026 के परिपत्र प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था।

आज की तारीख में लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार है:

नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित होने की पात्रता वाली बैठकों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री अमित कुमार श्रीवास्तव (1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक समिति के अध्यक्ष	1	1
श्री पलाश श्रीवास्तव	उप प्रबंध निदेशक	9	9
श्री चन्द्रदीप कुमार झा (2)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	2
सुश्री लाया मद्दुरी (3)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	0
श्री सीएच. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	9	5
श्री समीर जेरामभाई बोघारा (4)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	9	9
सुश्री एम.जी. जयश्री (5)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	6	4
श्री बलदेव पुरुषार्थ (6)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	2
श्री सोलोमन अरोकियाराज (7)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	2
श्री आलोक तिवारी (8)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	0
श्री कल्याण कुमार (9)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	8	2
श्री संजय रूद्र (10)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	1	1

टिप्पणी:

1. दिनांक 27.02.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में तथा दिनांक 29.05.2026 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
2. दिनांक 09.12.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
3. दिनांक 19.06.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
4. दिनांक 09.05.2026 से अध्यक्ष और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
5. दिनांक 03.12.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
6. दिनांक 21.07.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा दिनांक 27.11.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
7. दिनांक 21.07.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
8. दिनांक 04.12.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा दिनांक 19.06.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
9. दिनांक 27.02.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
10. दिनांक 30.06.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की नौ बैठकें 08 मई 2025, 20 मई 2025, 20 जून 2025, 11 अगस्त 2025, 19 सितंबर 2025, 13 नवंबर 2025, 28 जनवरी 2026, 12 फरवरी 2026 और 27 मार्च 2026 को आयोजित की गईं।

प्रबंधन एवं निवेश समिति (एमआईसी)

प्रबंधन और निवेश समिति (एमआईसी) का गठन 20 फरवरी, 2013 को आयोजित निदेशक मंडल की 60वीं बैठक में किया गया था। एमआईसी का अंतिम पुनर्गठन 05 अगस्त, 2026 को आयोजित निदेशक मंडल की 170वीं बैठक में किया गया।

आज की तारीख में प्रबंधन और निवेश समिति की संरचना इस प्रकार है:

नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित होने की पात्रता वाली बैठकों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री रोहित ऋषि (1)	प्रबंध निदेशक (समिति के अध्यक्ष)	2	2
श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	11	8
श्री आशुतोष चौधरी (2)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	0	0
श्री अमित कुमार श्रीवास्तव (3)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री समीर जेरामभाई बोघारा (4)	स्वतंत्र निदेशक	11	11
सुश्री एम.जी. जयश्री (5)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	0
श्री बलदेव पुरुषार्थ (6)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	1
श्री संजय रूद्र (7)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	11	8
श्री सोलोमन अरोकियाराज (8)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	1
श्री पी.आर. जयशंकर (9)	प्रबंध निदेशक	2	2
श्री आलोक तिवारी (10)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	3	0
श्री कल्याण कुमार (11)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	10	1
श्री पलाश श्रीवास्तव	उप प्रबंध निदेशक	11	11

टिप्पणी:

1. दिनांक 04.02.2026 से सदस्य, निदेशक और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया
2. दिनांक 28.07.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया

3. दिनांक 27.02.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
4. दिनांक 09.05.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
5. दिनांक 03.12.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
6. दिनांक 21.07.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा दिनांक 27.11.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
7. दिनांक 30.06.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
8. दिनांक 21.07.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
9. दिनांक 28.05.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
10. दिनांक 04.12.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा दिनांक 19.06.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
11. दिनांक 27.02.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, निदेशक मंडल की प्रबंधन और निवेश समिति की ग्यारह बैठकें 07 मई 2025, 20 मई 2025, 18 जून 2025, 25 जुलाई 2025, 13 अगस्त 2025, 19 सितंबर 2025, 12 नवंबर 2025, 05 दिसंबर 2025, 04 फरवरी 2026, 27 फरवरी 2026 और 27 मार्च 2026 को आयोजित की गईं।

जोखिम प्रबंधन समिति

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 14 नवम्बर 2008 को आयोजित अपनी 21वीं बैठक में निदेशक मंडल की जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति का गठन किया। तत्पश्चात, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ आईआईएफसीएल के एनबीएफसी–आईएफसी के रूप में पंजीकरण तथा आईआईएफसीएल में एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किए जाने के परिप्रेक्ष्य में, दिनांक 3 फरवरी 2014 को आयोजित 68वीं बैठक में निदेशक मंडल की जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति का पुनर्गठन करते हुए इसे निदेशक मंडल–स्तरीय जोखिम प्रबंधन एवं एएलसीओ समिति के रूप में परिवर्तित किया गया, ताकि आईआईएफसीएल में जोखिम प्रबंधन तथा आस्ति देयता प्रबंधन के लिए समग्र मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके। इसके उपरांत, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने दिनांक 26 नवम्बर 2014 को आयोजित अपनी 73वीं बैठक में यह प्रस्ताव अनुमोदित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2014 को जारी मास्टर परिपत्र–कॉरपोरेट अभिशासन (संदर्भ सं. डीएनबीएस (पीडी) सीसी. सं.. 390/03.10.001/2014–15) के विनियमन 3 के अनुरूप, आईआईएफसीएल की मौजूदा जोखिम प्रबंधन एवं एएलसीओ समिति को दो पृथक समितियों, अर्थात् जोखिम प्रबंधन समिति तथा आस्ति–देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) में विभाजित किया जाए। उक्त परिपत्र के अनुसार, ₹20 करोड़ या उससे अधिक की सार्वजनिक जमाराशि रखने वाले अथवा ₹100 करोड़ या उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली प्रत्येक एनबीएफसी के लिए आस्ति–देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के अतिरिक्त एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन अनिवार्य है, ताकि एकीकृत जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। दोनों समितियों के सदस्य समान रखे जाने का निर्णय लिया गया।

बोर्ड द्वारा दिनांक 9 सितम्बर 2020 को आयोजित बैठक में प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार, निदेशक मंडल–स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति में निदेशक मंडल–स्तरीय एएलसीओ की भूमिकाएँ एवं उत्तरदायित्व समाहित कर दिए गए। इसके पश्चात, कार्यकारी स्तर की एएलसीओ समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की सूचना एवं रणनीतिक मार्गदर्शन हेतु निदेशक मंडल–स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट की जाएगी।

जोखिम प्रबंधन समिति का अंतिम पुनर्गठन दिनांक 05 अगस्त, 2026 को आयोजित 170वीं बोर्ड बैठक में किया गया।

वर्तमान में जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित होने की पात्रता वाली बैठकों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री रोहित ऋषि (1)	प्रबंध निदेशक	1	1
श्री पलाश श्रीवास्तव	उप प्रबंध निदेशक	4	4
श्री आशुतोष चौधरी (2)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष)	0	0
श्री अमित कुमार श्रीवास्तव (3)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री समीर जेरामभाई बोघारा (4)	स्वतंत्र निदेशक	4	4
श्री कल्याण कुमार (5)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	3	1
श्री संजय रूद्र (6)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	4	4
श्री पी.आर. जयशंकर (7)	प्रबंध निदेशक	0	0

टिप्पणी:

1. दिनांक 04.02.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
2. दिनांक 28.07.2026 से सदस्य, समिति के अध्यक्ष और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
3. दिनांक 27.02.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
4. दिनांक 09.05.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
5. दिनांक 27.02.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
6. दिनांक 30.06.2026 से अध्यक्ष और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
7. दिनांक 28.05.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए

वर्ष 2025–26 के दौरान, निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की चार बैठकें 18 जून 2025, 17 सितंबर 2025, 13 अक्टूबर 2025 और 23 मार्च 2026 को आयोजित की गईं।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति

सीएसआर समिति का गठन लोक उपक्रम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार दिनांक 23 अप्रैल 2012 को आयोजित 51वीं बोर्ड बैठक में किया गया था। सीएसआर समिति का अंतिम पुनर्गठन 05 अगस्त, 2026 को आयोजित निदेशक मंडल की 170वीं बैठक में निदेशक मंडल की मंजूरी के अनुसार किया गया।

वर्तमान में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित होने की पात्रता वाली बैठकों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री आशुतोष चौधरी (1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष)	0	0
श्री रोहित ऋषि (2)	प्रबंध निदेशक	1	1
श्री पलाश श्रीवास्तव	उप प्रबंध निदेशक	4	4
सुश्री लया मद्दुरी (3)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	0
श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	2
श्री समीर जेरामभाई बोघारा (4)	स्वतंत्र निदेशक	4	4
श्री बलदेव पुरुषार्थ (5)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	0
श्री सोलोमन अरोकियाराज (6)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री पी.आर. जयशंकर (7)	प्रबंध निदेशक	0	0
श्री आलोक तिवारी (8)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1
श्री संजय रूद्र (9)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	0	0

टिप्पणी:

1. दिनांक 28.07.2026 से सदस्य, समिति के अध्यक्ष और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
2. दिनांक 04.02.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
3. दिनांक 19.06.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
4. दिनांक 09.05.2026 से अध्यक्ष और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
5. दिनांक 21.07.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा दिनांक 27.11.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
6. दिनांक 21.07.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
7. दिनांक 28.05.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
8. दिनांक 04.12.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा दिनांक 19.06.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
9. दिनांक 29.05.2026 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया तथा दिनांक 30.06.2026 से पद से कार्यमुक्त हो गए

वर्ष 2025–26 के दौरान, निदेशक मंडल की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की चार बैठकें 20 जून 2025, 19 सितंबर 2025, 30 दिसंबर 2025 और 27 फरवरी 2026 को आयोजित की गईं।

पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति

14 जुलाई 2009 को आयोजित बोर्ड की 25वीं बैठक में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, जिसे बाद में कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकता के अनुसार 11 अगस्त, 2014 को आयोजित 71वीं बोर्ड बैठक में पारिश्रमिक एवं नामांकन समिति का नाम दिया गया।

पारिश्रमिक और नामांकन समिति का अंतिम पुनर्गठन 05 अगस्त, 2026 को आयोजित 170वीं बैठक में निदेशक मंडल की मंजूरी के अनुसार किया गया।

आज की तारीख में पारिश्रमिक और नामांकन समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित होने की पात्रता वाली बैठकों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री अमित कुमार श्रीवास्तव (1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष)	1	1
श्री आशुतोष चौधरी (2)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	0	0
सुश्री लया मद्दुरी (3)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	0
श्री चन्द्रदीप कुमार झा (4)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री समीर जेरामभाई बोघारा (5)	स्वतंत्र निदेशक	1	1
सुश्री एम.जी. जयश्री (6)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	0
श्री बलदेव पुरुषार्थ (7)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	0
श्री कल्याण कुमार (8)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	0	0
श्री संजय रूद्र (9)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	1	0
श्री सोलोमन अरोकियाराज (10)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	0
श्री आलोक तिवारी (11)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	0

टिप्पणी:

1. दिनांक 27.02.2026 से समिति के सदस्य और निदेशक के रूप में तथा दिनांक 29.05.2026 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया
2. दिनांक 28.07.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
3. दिनांक 19.06.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
4. दिनांक 09.12.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
5. दिनांक 09.05.2026 से अध्यक्ष और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
6. दिनांक 03.12.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
7. दिनांक 21.07.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा दिनांक 27.11.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
8. दिनांक 27.02.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
9. दिनांक 30.06.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
10. दिनांक 21.07.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
11. दिनांक 04.12.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा दिनांक 19.06.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए

वर्ष 2025–26 के दौरान निदेशक मंडल की पारिश्रमिक और नामांकन समिति की एक बैठक 27 मार्च, 2026 को आयोजित की गई।

हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार हितधारक संबंध समिति का गठन 1 अगस्त, 2014 को आयोजित बोर्ड की 71वीं बैठक में किया गया था।

हितधारक संबंध समिति का अंतिम पुनर्गठन 05 अगस्त, 2026 को आयोजित निदेशक मंडल की 170वीं बैठक में किया गया।

आज की तारीख में हितधारक संबंध समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित होने की पात्रता वाली बैठकों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री रोहित ऋषि (1)	प्रबंध निदेशक	1	1
श्री पलाश श्रीवास्तव	उप प्रबंध निदेशक	4	4
श्री चन्द्रदीप कुमार झा (2)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री आशुतोष चौधरी (3)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष)	0	0
श्री संजय रूद्र (4)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	4	3
सुश्री एम.जी. जयश्री (5)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1
श्री समीर जेरामभाई बोघारा (6)	स्वतंत्र निदेशक	4	4
श्री पी.आर. जयशंकर (7)	प्रबंध निदेशक	0	0

टिप्पणी:

1. दिनांक 04.02.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
2. दिनांक 09.12.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
3. दिनांक 28.07.2026 से सदस्य, समिति के अध्यक्ष और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
4. दिनांक 30.06.2026 से अध्यक्ष और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
5. दिनांक 03.12.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
6. दिनांक 09.05.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
7. दिनांक 28.05.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए

वर्ष 2025–26 के दौरान, निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति की चार बैठकें 20 जून 2025, 17 सितंबर 2025, 05 दिसंबर 2025 और 27 मार्च 2026 को आयोजित की गईं।

अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम:

1. श्री संजीब कुमार मिश्रा, मुख्य अनुपालन अधिकारी।
2. सुश्री रुचि सिंघल, दिनांक 01.06.2026 से अनुपालन अधिकारी।
   - वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त हितधारकगण की शिकायतों की संख्या: 149
   - हितधारकगण की संतुष्टि के अनुसार हल न की गई शिकायतों की संख्या: 149
   - लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

आईटी रणनीति समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 8 जून 2017 को जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए मास्टर निर्देश–सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचा की आवश्यकता के अनुसार 2 अगस्त 2017 को आयोजित 86वीं बोर्ड बैठक में आईटी रणनीति समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा, आरबीआई ने परिपत्र सं. डीओएस.सीओ.सीएसआईटीईजी/एसईसी.7/31.01.015/2023–24 दिनांक 7 नवंबर, 2023 ने एनबीएफसी क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे पर अपने मास्टर दिशानिर्देशों को संशोधित किया और संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक (सूचना प्रौद्योगिकी प्रशासन, जोखिम, नियंत्रण और आश्वासन अभ्यास) दिशानिर्देश, 2023 जारी किए जो अन्य बातों के साथ–साथ बोर्ड की आईटी रणनीति

समिति के गठन के लिए प्रदान करते हैं। आईटी रणनीति समिति का अंतिम पुनर्गठन 05 अगस्त, 2026 को आयोजित 170वीं बोर्ड बैठक में किया गया था।

वर्तमान में आईटी रणनीति समिति की संरचना निम्नानुसार है:

नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित होने की पात्रता वाली बैठकों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपस्थित बैठकों की संख्या
श्री अमित कुमार श्रीवास्तव (1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष)	1	1
श्री रोहित ऋषि (2)	प्रबंध निदेशक	1	1
श्री पलाश श्रीवास्तव	उप प्रबंध निदेशक	4	4
श्री आशुतोष चौधरी (3)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	0	0
श्री समीर जेरामभाई बोघारा (4)	स्वतंत्र निदेशक	4	4
श्री कल्याण कुमार (5)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	3	2
श्री संजय रूद्र (6)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	4	4
श्री पी.आर. जयशंकर (7)	प्रबंध निदेशक	0	0

टिप्पणी:

1. दिनांक 27.02.2026 से समिति के सदस्य और निदेशक के रूप में तथा दिनांक 29.05.2026 से समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया
2. दिनांक 04.02.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
3. दिनांक 28.07.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
4. दिनांक 09.05.2026 से अध्यक्ष और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
5. दिनांक 27.02.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
6. दिनांक 30.06.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
7. दिनांक 28.05.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए

वर्ष 2025–26 के दौरान, निदेशक मंडल की आईटी रणनीति समिति की चार बैठकें 18 जून 2025, 17 सितंबर 2025, 30 दिसंबर 2025 और 23 मार्च 2026 को आयोजित की गईं।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 की उप–धारा (3) के तहत दिये गये दिशानिर्देशों और अन्य मामलों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीतियां

दिनांक 5 जून, 2015 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के संदर्भ में, आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 के उप–धारा (3) के तहत दिये गये निर्देशों और अन्य मामलों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, स्वतंत्रता निर्धारण और अन्य मामलों के निर्धारण के लिए मापदंडों सहित निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक कंपनी की नीतियों से सम्बन्धित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(ङ) के प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 की उप–धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा दिए गए घोषणापत्र पर वक्तव्य

आईआईएफसीएल पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, इसलिए इसके निदेशक मंडल में निदेशकों को वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं। आईआईएफसीएल ने अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार से अनुरोध किया था। इसके बाद, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 10 मई, 2023 के पत्र संख्या 18/7(i)/2022–आईएफ–आई के माध्यम से श्री समीरभाई जेरमभाई बोगहरा को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। श्री समीर जेरमभाई बोगहरा ने दिनांक 09.05.2026 को आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया।

निदेशक मंडल द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन, अपनी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया को दर्शाने वाला विवरण

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा अपने स्वयं के प्रदर्शन, अपनी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान, सरकारी कंपनियों पर उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब निदेशकों का मूल्यांकन उस केंद्रीय मंत्रालय या विभाग द्वारा किया जाता हो जो प्रशासनिक रूप से कंपनी का प्रभार संभालता है, अथवा यथास्थिति राज्य सरकार द्वारा, अपनी निर्धारित मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता हो। उक्त एमसीए अधिसूचना के दृष्टिगत, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल को अपने स्वयं के प्रदर्शन, अपनी समितियों तथा व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, अतः निदेशक मंडल के सभी सदस्यों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय, अर्थात् भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 (1) के तहत संबंधित पक्षों के साथ संविदा या व्यवस्था का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में, जहाँ भी लागू हो, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन और संबंधित पक्ष लेनदेन का विवरण लागू भारतीय लेखा मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण आदि में बताया गया है।

कारोबार की प्रकृति में बदलाव

कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताओं, यदि कोई हो, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है, और जो कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान हुई हो, जिससे वित्तीय विवरण और रिपोर्ट की तिथि से संबद्ध हो।

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष और कंपनी की रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हुई है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती है।

नियामक प्राधिकरणों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण एवं सारभूत आदेश, जिनका कंपनी की निरंतर परिचालन स्थिति तथा भविष्य की परिचालन गतिविधियों पर प्रभाव पड़े

31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी भी नियामक प्राधिकरण, न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा ऐसा कोई महत्वपूर्ण या सारभूत आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसका कंपनी की चालू संस्था की स्थिति अथवा उसके भविष्य के परिचालन पर कोई प्रभाव पड़े।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता

एक स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्म ने आईआईएफसीएल की आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा की और इसकी रिपोर्ट 29 मई, 2026 को आयोजित निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की गई।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, सूचीबद्ध कंपनी द्वारा नियमों का पालन न करने का विवरण, स्टॉक एक्सचेंज या बोर्ड या किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले पर सूचीबद्ध कंपनी पर लगाए गए अर्थदंड और प्रतिबंधः

स्टॉक एक्सचेंज	विनियम के तहत लगाया गया जुर्माना	स्थिति
एनएसई	शून्य	शून्य
बीएसई	शून्य	शून्य

कॉर्पोरेट अभिशासन

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के साथ पठित अनुसूची–ट के अनुसार कॉर्पोरेट अभिशासन पर विस्तृत रिपोट

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों तथा पिछली वार्षिक आम बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

क्र. सं.	निदेशक	कार्यकाल	बोर्ड बैठकों में शामिल होने के लिए पात्र बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठकों में भाग लेने की संख्या	20वीं वार्षिक आम बैठक दिनांक 26.09.2025
1	डॉ. पी. आर. जयशंकर, प्रबंध निदेशक	29.05.2020 से 28.05.2025	2	2	.
2	श्री रोहित ऋषि, प्रबंध निदेशक	04.02.2026	3	3	.
3	श्री पलाश श्रीवास्तव, उप प्रबंध निदेशक	28.02.2025	16	16	भाग लिया
4	सुश्री एम. जी. जयश्री, सरकारी नामित निदेशक	06.08.2024 से 03.12.2025	10	8	.
5	श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी, सरकारी नामित निदेशक	29.10.2020	17	8	.
6	श्री कल्याण कुमार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	21.09.2022 से 27.02.2026	14	4	.
7	श्री समीरभाई जेरामभाई बोघारा, स्वतंत्र निदेशक	15.05.2023 से 09.05.2026	16	16	भाग लिया
8	श्री संजय रुद्र, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	01.07.2024 से 30.06.2026	16	10	भाग लिया
9	श्री आलोक तिवारी, सरकारी नामित निदेशक	04.12.2025 से 19.06.2026	6	1	.
10	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	27.02.2026	2	1	.
11	श्री बलदेव पुरुषार्थ, सरकारी नामित निदेशक	21.07.2025 से 27.11.2025	4	2	.
12	श्री चंद्रदीप कु. झा, सरकारी नामित निदेशक	09.12.2025	5	4	.
13	श्री सोलोमन अरोकियाराज, सरकारी नामित निदेशक	23.01.2023 से 21.07.2025	6	3	.

- 31 मार्च 2026 को किसी निदेशक द्वारा अन्य निदेशक मंडलों या समितियों में सदस्यता या अध्यक्षता की संख्या, जिसमें पृथक रूप से उन सूचीबद्ध संस्थाओं के नाम भी शामिल हैं जहाँ वह व्यक्ति निदेशक है तथा निदेशकीय श्रेणी भी दर्शाई गई है–

क्र. सं.	नाम	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख	डीआईएन	उन दूसरी कंपनियों के नाम जिनमें वे निदेशक हैं। अगर कोई नहीं है, तो शून्य लिखें।
1	श्री रोहित ऋषि, प्रबंध निदेशक	04 फरवरी 2026	11524681	1. आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड 2. आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
2	श्री पलाश श्रीवास्तव, उप प्रबंध निदेशक	28 फरवरी 2025	02007911	1. आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 2. आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
3	श्री चंद्रदीप कुमार झा, सरकारी नामित निदेशक	09 दिसंबर 2025	11417133	1. मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट 2. पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी
4	डॉ. आलोक तिवारी, सरकारी नामित निदेशक	04 दिसंबर 2025	11409207	1. इंडियन रेलवेज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड 3. एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड 4. इंडियन रेलवे स्टेशन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी, सरकारी नामित निदेशक	29 अक्टूबर 2020	08941266	1. इंडियन रेलवे स्टेशन्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6	श्री संजय रुद्र, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	01 जुलाई, 2024– 30 जून 2026	09650826	1. यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया 2. स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड 3. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ बैंक मैनेजमेंट, गुवाहाटी
7	श्री अमित कुमार श्रीवास्तव, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नामित निदेशक	27 फरवरी 2026	08099846	1. पंजाब नेशनल बैंक
8	श्री समीरभाई जेरामभाई बोघारा, स्वतंत्र निदेशक	15 मई 2023 – 9 मई 2026	10163651	शून्य

- निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंधों का प्रकटीकरण – लागू नहीं।
- गैर–कार्यकारी निदेशकों द्वारा धारित शेयरों और परिवर्तनीय लिखतों की संख्या – लागू नहीं।
- स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण उपलब्ध कराने वाला वेब लिंक – https:@@www-iifcl-in@Disclosures
- निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता को दर्शाने वाला चार्ट या मैट्रिक्स, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख हो:

  – आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में निदेशकों का चयन और नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आईआईएफसीएल की अपने निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं होती है।
- 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष से प्रभावी, निदेशक मंडल द्वारा व्यवसाय/क्षेत्र के संदर्भ में प्रभावी कार्य संचालन हेतु आवश्यक

माने गए मुख्य कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं की सूची तथा वे जो वास्तव में निदेशक मंडल में उपलब्ध हैं; तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष से प्रभावी, ऐसे कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता रखने वाले निदेशकों के नाम – आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल के निदेशकों का चयन एवं नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आईआईएफसीएल की अपने निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है।

- निदेशक मंडल की राय में स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से स्वतंत्र हैं – हाँ
- कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र देने वाले स्वतंत्र निदेशक के त्यागपत्र के विस्तृत कारणों का उल्लेख, तथा ऐसे निदेशक द्वारा यह पुष्टि कि उल्लिखित कारणों के अतिरिक्त कोई अन्य महत्वपूर्ण कारण नहीं है – लागू नहीं
- वरिष्ठ प्रबंधनः 31 मार्च 2025 तक वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों का विवरण इस प्रकार हैः

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/डॉ.)	पदनाम
1	राजीव मुखीजा	मुख्य महाप्रबंधक – मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
2	सुबोध शर्मा	मुख्य महाप्रबंधक
3	राकेश कुमार	मुख्य महाप्रबंधक
4	गौरव कुमार	मुख्य महाप्रबंधक
5	राज कुमार रल्हन	मुख्य ऋण अधिकारी (सीसीओ)
6	आलोक गुप्ता	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (सीटीओ)
7	सलिल गर्ग	मुख्य रणनीति अधिकारी (सीएसओ)
8	किशोर नामदेव कुम्भारे	मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ)
9	श्याम शरण गर्ग	महाप्रबंधक
10	रुचि सिंघल	महाप्रबंधक – कंपनी सचिव (सीएस)
11	सुभाशीष धल	महाप्रबंधक
12	टी हरि कृष्णन	महाप्रबंधक
13	सुमेर सिंह	महाप्रबंधक
14	विशाल राठौड़	महाप्रबंधक
15	राजीव कुमार गुप्ता	महाप्रबंधक
16	विवेक राजावत	महाप्रबंधक
17	कृपासिंधु गुरु	महाप्रबंधक
18	संजीब मिश्रा	मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओएम)



आईआईएफसीएल का वरिष्ठ प्रबंधन

- आम सभा की बैठकें –

(क) असाधारण आम बैठकों और पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों के आयोजन का स्थान और समय;

क्र. सं.	वार्षिक आम बैठक	तारीख	स्थल	पारित विशेष संकल्पों का विवरण
1	8वीं असाधारण आम बैठक	03 सितंबर 2026 सुबह 11.30 बजे	तीसरी मंज़िल, सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001	मद संख्या 2: आईआईएफसीएल के पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या बढ़ाने के लिए संगम अनुच्छेदों में संशोधन
2	वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए 20वीं वार्षिक आम बैठक	26 सितंबर 2025 सुबह 11.30 बजे	सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001	मद सं. 4: कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार निजी स्थानन के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचरों का निर्गम
3	वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 19वीं वार्षिक आम बैठक	27 सितंबर 2024 सुबह 11.30 बजे	सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001	मद सं. 3: कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार निजी स्थानन के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचरों का निर्गम मद सं. 4: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180(1)(ग) के तहत अनुमोदित उधार सीमा में वृद्धि
4	वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 18वीं वार्षिक आम बैठक	29 सितंबर 2023 शाम 4.00 बजे	सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001	मद सं. 4: कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार निजी स्थानन के माध्यम से अप्रतिभूत/प्रतिभूत अपरिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचरों का निर्गम

(ख) क्या पिछले वर्ष पोस्टल बैलेट से कोई विशेष प्रस्ताव पास हुआ था – वोटिंग पैटर्न का विवरण– नहीं

(ग) पोस्टल बैलेट प्रक्रिया किसने आयोजित की– लागू नहीं

(घ) क्या कोई खास प्रस्ताव पोस्टल बैलेट से कराने का प्रस्ताव है– लागू नहीं

(ङ) पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया– लागू नहीं

- संचार के साधनः

(क) तिमाही नतीजे – स्टॉक एक्सचेंज और अख़बार

(ख) जिन अख़बारों में नतीजे आमतौर पर छपते हैं – जनसत्ता, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड

(ग) कोई वेबसाइट, जहाँ दिखाए जाते हैं – https://www.iifcl.in

(घ) क्या यह आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति भी प्रदर्शित करता है – लागू नहीं

(ङ) संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों को दिए गए प्रस्तुतीकरण – लागू नहीं

- सामान्य हितधारक जानकारीः

क्र.सं.	वार्षिक आम बैठक	तारीख	स्थल
1.	वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 21वीं वार्षिक आम बैठक	28 सितंबर 2026 को दोपहर 12.30 बजे	सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

अन्य प्रकटीकरणः

- जिन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं, उनके नाम और पते तथा प्रत्येक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क के भुगतान की पुष्टि – **इक्विटी सूचीबद्ध नहीं है।**

अन्य प्रकटीकरणः

- संबंधित पक्ष लेनदेन से निपटने की नीति उपलब्ध होने का वेब लिंक – https://www.iifcl.in/related-party-transaction-policy
- विनियम 32(7क) के अंतर्गत अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थागत नियोजन के माध्यम से जुटाए गए धन के उपयोग का विवरण – लागू नहीं
- जिन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इकाई की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं, उनके नाम और पते तथा प्रत्येक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को वार्षिक सूचीकरण शुल्क के भुगतान की पुष्टिः

एक्सचेंजों का नाम और पता	
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	एक्सचेंज प्लाजा, सी–1, ब्लॉक जी, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई लिमिटेड)	फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट फोर्ट मुंबई–400001

- वार्षिक सूचीकरण शुल्क के संबंध में पुष्टिः आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान किया है।
- वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा ऐसी किसी समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किए जाने का विवरण, जिसे स्वीकार करना अनिवार्य था, तथा इसके कारणों का प्रकटीकरणः बशर्ते कि यह खंड केवल उन मामलों में लागू होगा, जहां निदेशक मंडल की मंजूरी के लिए समिति की सिफारिश/प्रस्तुति आवश्यक है, और उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां इन विनियमों के अंतर्गत किसी लेन–देन को करने के लिए संबंधित समिति की पूर्व मंजूरी आवश्यक है। – लागू नहीं
- सूचीबद्ध संस्था और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा समेकित आधार पर सांविधिक लेखापरीक्षक तथा उस नेटवर्क फर्म/नेटवर्क संस्था को, जिसका सांविधिक लेखापरीक्षक हिस्सा है, प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए भुगतान किया गया कुल शुल्क–

  वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान आईआईएफसीएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा अन्य सेवाओं के लिए भुगतान किए गए शुल्क का विवरण निम्नानुसार हैः

1. आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेडः वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में ₹ 85,000 और आयकर संबंधी मामलों के शुल्क के रूप में ₹ 15,000.00 लागू करों को छोड़कर।

लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	राशि रु. में
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	85,000
आयकर संबंधी मामलों का शुल्क, लागू करों को छोड़कर	15,000
कुल	**1,00,000**

2. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेडः

लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	यूएसडी	राशि रु. में
लेखापरीक्षा सेवाएं	133,942	1,26,78,186
कराधान अनुपालन सेवाएं	13,778	13,04,147
अन्य सेवाएं	23,498	22,24,187
कुल	**171,218**	**1,62,06,520**

लेखापरीक्षा शुल्क की राशि को 31.03.2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक की 94.6543 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर की संदर्भ दर के अनुसार भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है।

3. आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेडः

लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	राशि रु. में
सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	1,56,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क	46,875
सीमित समीक्षा शुल्क	46,875
कुल	**2,49,750**

4. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन):

लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	राशि (₹ लाख में)
लेखापरीक्षा शुल्क	15.00
कराधान संबंधी मामले	2.40
प्रमाणन संबंधी कार्य	2.50
सीमित समीक्षा	8.10
कुल	**28.00**

- सूचीबद्ध इकाई एवं उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उन फर्मों/कंपनियों को दिए गए ऋण एवं ऋण–सदृश अग्रिमों का प्रकटीकरण, जिनमें निदेशकों की रुचि हो, नाम एवं राशि सहित – लागू नहीं।
- सूचीबद्ध इकाई की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों का विवरण; जिसमें स्थापना की तिथि एवं स्थान तथा ऐसी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों के नाम एवं नियुक्ति की तिथि शामिल है – आईआईएफसीएल की कोई महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।
- उपर्युक्त उप–पैराग्राफ (2) से (10) के अंतर्गत कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट की किसी भी आवश्यकता के अनुपालन न होने की स्थिति में, उसके कारणों का प्रकटीकरण – कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रकटीकृत।

  कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में यह भी प्रकटीकरण किया जाएगा कि अनुसूची–II के भाग–ई में निर्दिष्ट विवेकाधीन आवश्यकताओं को किस सीमा तक अपनाया गया है–
- कंपनी ने सेबी की सूचीबद्धता विनियमन के अंतर्गत निर्धारित लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। कंपनी ने सेबी की सूचीबद्धता विनियमन के अंतर्गत निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन संहिता की लागू गैर–अनिवार्य अपेक्षाओं का भी निम्नानुसार अनुपालन किया है:

क) बोर्ड

बोर्डः एक सरकारी कंपनी होने के नाते, बोर्ड का गठन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी के बोर्ड में एक महिला निदेशक भी थीं।

ख) शेयरधारकों के अधिकार

कंपनी के त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणाम कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत "संचार के साधन" शीर्षक में उल्लिखित अनुसार प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं तथा कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

ख) लेखापरीक्षा योग्यताएँ

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई भी लेखापरीक्षा योग्यता नहीं है।

ग) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पृथक पदः

सरकारी कंपनी होने के कारण अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पृथक पद नहीं हैं।

घ) आंतरिक लेखापरीक्षक की रिपोर्टिंग

आईआईएफसीएल के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख कार्यात्मक रूप से लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं।

ङ) संबंधित पक्षकार लेन–देन पर नीति हेतु वेब लिंक – संबंधित पक्ष लेन–देन नीति

- विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप–विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन का प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट अभिशासन पर अनुभाग में किया जाएगा – प्रकटीकृत।
- प्रैक्टिसरत कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को बोड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या निदेशक के पद पर बने रहने से प्रतिबंधित अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
फोन : 9810690633, 8527087435
ईमेल : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
जीएसटी संख्या : 07ABTFA2714K1Z7

निदेशकों को अयोग्य न ठहराए जाने का प्रमाण पत्र

[सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 34 (3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) के अनुसार,

सेवा में,

सदस्यगण

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हमने इस प्रमाणपत्र के निर्गमन के उद्देश्य से, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) के साथ पठित अनुसूची ट, भाग सी, खंड 10(i) के अनुसरण में, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) U67190DL2006GOI144520 है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, ब्लॉक–2, प्लेट–A एवं B, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 में स्थित है (जिसे आगे "कंपनी" कहा गया है), के नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध निदेशकों द्वारा प्रदान किए गए प्रासंगिक प्रकटीकरणों की जाँच की है।

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और आवश्यक समझे गए सत्यापनों (जिसमें पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति का सत्यापन भी सम्मिलित है) और निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरणों के आधार पर, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि नीचे उल्लिखित कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि तक, प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से अपदस्थ या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

डीआईएन	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
11524681	श्री. रोहित ऋषि	प्रबंध निदेशक	04/02/2026
02007911	श्री. पलाश श्रीवास्तव	उप प्रबंध निदेशक	28/02/2025
11417133	श्री. चंद्रदीप कुमार झा	नामित निदेशक	09/12/2025
11409207	डॉ. आलोक तिवारी	नामित निदेशक	04/12/2025
08941266	श्री. पार्थ सारथी रेड्डी चेवुरु	नामित निदेशक	29/10/2020
09650826	श्री. संजय रूद्र	नामित निदेशक	01/07/2024
08099846	श्री. अमित कुमार श्रीवास्तव	नामित निदेशक	27/02/2026
10163651	श्री समीरभाई जेरामभाई बोघारा	स्वतंत्र निदेशक	15/05/2023

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित व्यक्ति वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान निदेशक थे:

- डॉ. पी.आर. जयशंकर (डीआईएनः 06711526) दिनांक 28/05/2025 से निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
- श्री कल्याण कुमार (डीआईएनः 09631251) दिनांक 27/02/2026 से निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
- श्री जयश्री मदास्सेरी गोपी (डीआईएनः 08991135) दिनांक 03/12/2025 से निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
- श्री बलदेव पुरुषार्थ (डीआईएनः 07570116) दिनांक 27/11/2026 से निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
- श्री सोलोमन अरोकीयाराज (डीआईएनः 06802660) दिनांक 21/07/2025 से निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए।

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर इस संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही इस बात का कि प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन कितनी दक्षता या प्रभावशीलता के साथ किया है।

कृते अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
पंजी. सं. P1995DE072900
सहकर्मी समीक्षा सं. 7777ध्2031

हस्ता./–
सीएस दीपक कुमार
भागीदार
एम.नं.– F 10189
सी.पी. नं. 11372
यूडीआईएनः F010189G001133718

दिनांकः 11.09.2026
स्थानः नई दिल्ली

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
फोन : 9810690633, 8527087435
ईमेल : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
जीएसटी संख्या : 07ABTFA2714K1Z7

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में
सदस्यगण
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U67190DL2006GOI144520
पंजीकृत कार्यालय: पाँचवाँ तल, ब्लॉक–2, प्लेट ए एवं बी,
एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (जिसे आगे "एलओडीआर" कहा गया है) के विनियम 17 से 27 तथा विनियम 62 और अनुसूची ट के पैरा ग, घ एवं ङ के अंतर्गत निर्दिष्ट कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की तथा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों हेतु कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों की जांच की है।

कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारे द्वारा की गई जांच, कंपनी सचिवों के संस्थान, भारत द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन (सर्वोत्तम प्रथाओं के मॉडल) के अनुसार की गई है, जो केवल उन प्रक्रियाओं तथा उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी, जिन्हें कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है। यह न तो लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई मत व्यक्त करना है।

हमने प्रमाणन के उद्देश्य से, अपने सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं तथा हमें ऐसे अभिलेख, दस्तावेज, प्रमाण–पत्र आदि उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी हमारे द्वारा आवश्यकता की गई थी।

हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं उपलब्ध जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने उपर्युक्त सेबी (एलओडीआर) विनियमों तथा 'सार्वजनिक उद्यम विभाग' द्वारा जारी कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय नीचे उल्लिखित बिंदुओं के।

क) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत अपेक्षित निदेशक मंडल की कुल संख्या के आधे से कम थी।

ख) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में 31.12.2025 से 31.03.2026 की अवधि के लिए कोई महिला निदेशक नियुक्त नहीं थी।

ग) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक होने के कारण, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना क्रमशः सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 18 (1) और 19 (1) तथा कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के क्रमशः पैरा 4.1.1 और 5.1 के अनुरूप नहीं थी।

घ) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक होने के कारण, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक आयोजित नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में कोई आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के संबंध में, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
पंजी. सं. P1995DE072900
सहकर्मी समीक्षा सं. 7777/2026

हस्ता./–
सीएस दीपक कुमार
भागीदार
एम.नं.– F 10189
सी.पी. नं. 11372
यूडीआईएनः F010189H001449660

दिनांकः 11.09.2026
स्थानः नई दिल्ली

अनुपालन प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अंतर्गत अपेक्षित अनुपालन प्रमाणपत्र।

हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि:

क. हमने वर्ष के वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

i. इन विवरणों में कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण असत्य कथन नहीं है, न ही किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा गया है और न ही इनमें कोई ऐसा कथन है जो भ्रामक हो सकता है।

ii. ये विवरण समग्र रूप से कंपनी के कार्यकलापों की सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करते हैं तथा प्रचलित लेखांकन मानकों और लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई द्वारा ऐसा कोई लेन–देन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध अथवा कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की संरचना अथवा संचालन में पाई गई किसी भी कमी, जिसकी हमें जानकारी है, के बारे में लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को अवगत कराया है। साथ ही, इन कमियों को दूर करने के लिए उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों की जानकारी भी दी है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों एवं लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित के संबंध में अवगत कराया हैरू

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिनका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया गया है।

iii. ऐसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी की घटनाएँ, जिनकी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, तथा उनमें प्रबंधन के किसी सदस्य या कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो।

हस्ता/–
रोहित ऋषि
प्रबंध निदेशक

हस्ता/–
राजीव मुखीजा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

दिनांक: 29.05.2026
स्थान: नई दिल्ली

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता के अंतर्गत घोषणा

निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की 'निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण एवं नैतिकता संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता./–
(रोहित ऋषि)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन.: 11524681

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 24.09.2026

निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण

आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 11 अगस्त 2014 को आयोजित अपनी 71वीं बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव अनुमोदित किया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप आईआईएफसीएल का सतर्कता तंत्र, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निदेशकों एवं कर्मचारियों द्वारा वास्तविक चिंताओं की रिपोर्टिंग हेतु आवश्यक 'सतर्कता तंत्रश की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। निदेशक मंडल ने यह भी संकल्प लिया कि आईआईएफसीएल के सतर्कता तंत्र में व्यक्तियों के उत्पीड़न से संरक्षण के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय उपलब्ध होंगे तथा सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त अथवा असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक प्रत्यक्ष पहुँच का प्रावधान भी होगा। इसके उपरांत, निदेशक मंडल ने कंपनियां अधिनियम, 2013 की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुसार, इस प्रकार की विजिल मैकेनिज़्म की स्थापना से संबंधित विवरणों का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट तथा बोर्ड रिपोर्ट में करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया। आपकी कंपनी ने सतर्कता तंत्र को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी में एक औपचारिक 'व्हिसल ब्लोअर नीति' भी प्रभावी है, जिसे कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

आईआईएफसीएल में सतर्कता अभिशासन

1. आईआईएफसीएल में सतर्कता अभिशासन के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई है। सतर्कता अभिशासन, एक महत्वपूर्ण प्रबंधन उपकरण के रूप में, आईआईएफसीएल तथा उसकी सभी अनुषंगी कंपनियों में क्रियाशील है। आईआईएफसीएल में सतर्कता प्रभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है।
2. सतर्कता कार्य को व्यापक रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात् दंडात्मक सतर्कता तथा निवारक सतर्कता।
3. वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग का मुख्य ध्यान निवारक सतर्कता पर केंद्रित रहा, जिसके अंतर्गत आईआईएफसीएल में सतर्कता शासन को सुदृढ़ करने, प्रणालीगत सुधार, नीतियों की समीक्षा, संपत्ति विवरणों की जाँच, कार्यशालाओं के आयोजन तथा निवारक सतर्कता से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष प्रयास किए गए।
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी, आईआईएफसीएल एवं प्रबंध निदेशक के मध्य प्रत्येक तिमाही में संरचित बैठक आयोजित की जाती है। प्रत्येक तिमाही बैठक में पूर्व बैठक के एजेंडे पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तथा वर्तमान तिमाही के लिए नए एजेंडे प्रस्तुत किए जाते हैं।
5. शिकायतों के संबंध में, वर्ष 2025–26 के दौरान सतर्कता विभाग को छह शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया। वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2025–26 से संबंधित कोई भी शिकायत लंबित नहीं है। संगठन में कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई (डीए) का मामला सामने नहीं आया है और वर्ष के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अभियोजन की स्वीकृति का कोई अनुरोध नहीं किया गया है।
6. आईआईएफसीएल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर, 2025 से 02 नवंबर, 2025 तक "सतर्कतारू हमारी साझा जिम्मेदारी" की केंद्रीय विषयवस्तु के साथ मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जैसे सभी अधिकारियों को शपथ दिलाना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, कार्यशाला, वॉक–ए–थॉन, रंगोली प्रतियोगिता, आईआईएफसीएल और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों के बीच रील/वीडियो निर्माण प्रतियोगिता तथा राजकीय सर्वोदय विद्यालय 1, उत्तम नगर, नई दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तीन माह के अभियान के दौरान ध्यान केंद्रित किए जाने वाले क्षेत्र निम्नलिखित थे:

   क) लंबित शिकायतों का निपटारा

   ख) लंबित मामलों का निपटारा

   ग) क्षमता निर्माण कार्यक्रम

   घ) संपत्ति प्रबंधन

   ङ) डिजिटल पहल

   सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान, संगठन में सतर्कता जागरूकता को बढ़ावा देने और वर्ष के दौरान संगठन में सतर्कता तंत्र के संबंध में आईआईएफसीएल द्वारा की गई पहल को उजागर करने के लिए 29.10.2025 को नई दिल्ली में एक सतर्कता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अपर सचिव, श्री अजय कनौजिया उपस्थित रहे और उन्होंने सम्मेलन को संबोधित किया। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, श्री निर्मल गोयल द्वारा "निवारक सतर्कता उपायों" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला के बाद, "भ्रष्टाचार–विरोध और सत्यनिष्ठा" का संदेश देने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
7. अन्य पहलें

क) सहायक कंपनियों में सतर्कता प्रशासन – आईआईएफसीएल की सभी तीनों सहायक कंपनियों में सतर्कता प्रशासन की स्थापना की गई है। प्रत्येक सहायक कंपनी में एक–एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो मुख्य सतर्कता अधिकारी को रिपोर्ट करता है। सहायक कंपनियों में सतर्कता संबंधी कार्यों पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनकी समीक्षा सीवीओ द्वारा की जाती है।

ख) सतर्कता पत्रिका – सतर्कता विषयक मामलों में कर्मचारियों के ज्ञान संवर्धन के उद्देश्य से एक त्रैमासिक सतर्कता पत्रिका "जागृति" का प्रकाशन किया जा रहा है तथा इसे कर्मचारियों के बीच प्रसारित किया जाता है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के तहत प्रकटीकरण

कंपनी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाती है तथा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुरूप यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध एवं प्रतितोष हेतु नीति लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल कर्मचारी सेवा विनियमों के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के मामलों को दुराचार की श्रेणी में रखा गया है।

आईआईएफसीएल में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों की रोकथाम एवं निवारण हेतु एक सुव्यवस्थित तंत्र स्थापित है। पीओएसएच अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण हेतु एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी), जिसमें एक बाहरी सदस्य भी सम्मिलित है, क्रियाशील है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के माध्यम से संवेदनशील बनाया जा रहा है। कंपनी सभी कर्मचारियों, विशेषकर महिला कर्मचारियों, के लिए सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखती है। वर्ष के दौरान समिति को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई तथा समिति की कुल आठ बैठकें आयोजित की गईं।

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन

आईआईएफसीएल मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनिवार्य सवेतन अवकाश एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित दायित्वों का पालन करती है, जिससे एक सहायक एवं समान कार्यस्थल वातावरण सुनिश्चित होता है। कंपनी अपने महिला कर्मचारियों के अधिकारों एवं कल्याण की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आईआईएफसीएल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को लागू कर रहा है और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदकों को जानकारी प्रदान कर रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 के अंतर्गत आईआईएफसीएल में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए गए हैं। संगठन के विवरण, कार्यों और कर्तव्यों तथा सीपीआईओ, सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के संपर्क विवरण का प्रकटीकरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(इ) के अनुपालन में आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय–सीमा के भीतर उत्तर दिया जाता है/उन्हें अग्रेषित किया जाता है/अस्वीकार किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की आवश्यकता के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव और प्रसार किया जाता है।

आईआईएफसीएल प्राप्त, निपटाए गए और अस्वीकृत आवेदनों के लिए मासिक विवरण प्रपत्र अपलोड करता है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार आवेदनों का त्रैमासिक विवरण दाखिल करने संबंधी आवश्यकताओं का भी अनुपालन करता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आईआईएफसीएल को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 156 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 150 आवेदनों का निर्धारित समय–सीमा के भीतर उत्तर प्रदान करके निपटारा किया गया, 3 आवेदन संबंधित लोक प्राधिकरण के उपयुक्त केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित किए गए तथा 3 आवेदनों के संबंध में जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत अस्वीकार कर दी गई।

शिकायत निवारण तंत्र

हितधारकों के प्रति संवेदनशील व्यवहार तथा शिकायतों का समयबद्ध निपटान कंपनी की प्राथमिकता है। आईआईएफसीएल ने अपने हितधारकों के लिए शिकायत/अभ्यावेदन दर्ज कराने हेतु एक निष्पक्ष मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है। आईआईएफसीएल एक सुव्यवस्थित शिकायत निवारण तंत्र (जीआरएम) का पालन करती है, जिसे आईआईएफसीएल के नागरिक चार्टर में सम्मिलित किया गया है तथा सार्वजनिक प्रकटीकरण के अंतर्गत इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। शिकायतें निम्नलिखित माध्यमों से दर्ज की जा सकती हैं:

i. केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से

ii. आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रपत्र के माध्यम से

iii. एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (इनग्राम) के माध्यम से

iv. grievancefeedback@iifcl.in पर ईमेल के माध्यम से

v. वित्तीय सेवाएं विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सतर्कता विभाग आदि के माध्यम से

आईआईएफसीएल ने शिकायत निवारण प्रणाली का प्रबंधन करने के लिए एक शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) नियुक्त किया है। जीआरओ का विवरण आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है।

आईआईएफसीएल के विभिन्न बॉन्ड निर्गमों में किए गए निवेश से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, निवेशक आईआईएफसीएल को ईमेल आईडी grievancefeedback@iifcl-in पर सूचित करते हुए सीधे संबंधित रजिस्ट्रार से संपर्क कर सकते हैं।

यदि शिकायत का समाधान संतोषजनक नहीं होता है, तो निवेशक अनुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, जिनका विवरण आईआईएफसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आईआईएफसीएल को सीधे 104 शिकायतें प्राप्त हुईं और सभी शिकायतों का निर्धारित समय–सीमा के भीतर निपटारा कर दिया गया। इस अवधि के दौरान कोई अपील प्राप्त नहीं हुई।

जमा राशि

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 तथा कंपनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2014 के अंतर्गत कोई भी जमा स्वीकार नहीं की। न ही कोई जमा राशि बकाया अथवा दावा रहित रही। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान कंपनी द्वारा जमा राशि की चुकौती अथवा उस पर देय ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की गई।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण

1. ऊर्जा संरक्षण / प्रौद्योगिकी अवशोषण

एक वित्तीय संस्थान के रूप में, आईआईएफसीएल का प्रत्यक्ष परिचालन ऊर्जा प्रभाव मुख्य रूप से इसके कार्यालय संबंधी बुनियादी ढाँचे और व्यावसायिक परिचालनों से जुड़ा हुआ है। कंपनी संसाधनों के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आईआईएफसीएल ने प्रौद्योगिकी–सक्षम प्रक्रियाओं और डिजिटल कार्यप्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना जारी रखा, जिससे प्रक्रियागत दक्षता में वृद्धि हुई और भौतिक दस्तावेजीकरण पर निर्भरता कम हुई। सतत विकास के दृष्टिकोण से, कंपनी ईएसजी डेटा संग्रह, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग की संभावनाओं का क्रमिक रूप से पता लगा रही है। वर्ष के दौरान संरचित जलवायु और ईएसजी जोखिम मूल्यांकन तंत्र का विकास भी अवसंरचना वित्तपोषण में सतत विकास संबंधी जोखिमों के प्रौद्योगिकी–सक्षम और डेटा–आधारित मूल्यांकन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आईआईएफसीएल सतत विकास संबंधी डेटा प्रबंधन, निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन तंत्र तथा संस्थागत ईएसजी रिपोर्टिंग को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के अवसरों का पता लगाना जारी रखेगा।

2. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान उपयोग की गई/अर्जित विदेशी मुद्राएँ इस प्रकार हैं: –

(₹ करोड़)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(क) विदेशी मुद्रा में आय (आईआरएस व्युत्पन्नी संविदाओं के अंतर्गत प्राप्त ब्याज को छोड़कर वास्तविक प्राप्ति):		
(i) ब्याज	-	-
(ii) प्राप्त अनुदान	-	-
(iii) प्राप्त लाभांश	-	-
कुल	**-**	**-**
(ख) ब्याज और अन्य मामलों के कारण विदेशी मुद्राओं में व्यय (वास्तविक व्यय):		
(i) उधार पर ब्याज	811	871
(ii) प्रतिबद्धता शुल्क		-
(iii) विदेश यात्रा		-
(iv) अन्य व्यय		-
कुल	**811**	**871**

कर्मचारियों का विवरण

आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों का विवरण देने की आवश्यकता नहीं है, जिसे कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक नियम), 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कंपनी के निदेशकों अथवा कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए गए।

सचिवीय मानक

आपकी कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानक का पूरी तरह से पालन करती है।

धारा 92(3) के तहत वार्षिक रिटर्न का अंश

अधिनियम के लागू प्रावधान के अनुसार, वार्षिक रिटर्न की प्रति कंपनी की वेबसाइट www.iifcl.in पर रखी जाएगी। हालांकि, अच्छे कॉर्पोरेट अभिशासन के हिस्से के रूप में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के तहत फॉर्म एमजीटी–9 में प्रदान किए गए वार्षिक रिटर्न का अंश अनुलग्नक II के रूप में संलग्न है।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, न तो सांविधिक लेखापरीक्षक और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखा परीक्षा समिति को कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ की गई धोखाधड़ी के किसी भी मामले की रिपोर्ट दी है, जिसका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में उल्लेख करने की आवश्यकता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अंतर्गत लागत अभिलेखों का रखरखाव

केंद्र सरकार द्वारा कंपनी द्वारा निष्पादित गतिविधियों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रखरखाव का कोई प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के कार्यालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए दिनांक 10 सितंबर, 2025 के पत्र द्वारा मेसर्स एडीबी एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 005593C) और मेसर्स एबीपी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (फर्म पंजीकरण संख्या 315104E) को संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के कार्यालय द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक, कंपनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे।

सचिवीय लेखापरीक्षक

शेयरधारकों ने 26 सितंबर, 2025 को आयोजित 20वीं वार्षिक आम बैठक में वित्तीय वर्ष 2025–26 से वित्तीय वर्ष 2029–30 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए मेसर्स अखिल रोहतगी एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी की है और इसे इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक–I में संलग्न किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ और उन टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर, लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति के साथ, वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न किया गया है।

लेखापरीक्षक की योग्यता पर प्रबंधन की टिप्पणी

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए तैयार वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा कोई भी योग्यता व्यक्त नहीं की गई है।

राजभाषा (हिंदी)

आईआईएफसीएल संगठन के भीतर राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रमों और अन्य दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 का अनुपालन सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

राजभाषा नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और आधिकारिक कार्यों में हिंदी का 100% प्रयोग प्राप्त करने के लिए, आईआईएफसीएल ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी अधिकारी भारत सरकार की 'हिंदी शिक्षण योजना' के अंतर्गत "प्रवीण", "प्राज्ञ", "प्रबोध" और

"प्रवीणता" जैसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करें। अब तक, 5% अधिकारियों ने "प्रवीण" पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और 85% अधिकारियों ने "प्रवीणता" प्रशिक्षण पूरा कर लिया हैय शेष 20% अधिकारी अपेक्षित प्रशिक्षण यथाशीघ्र पूरा कर लेंगे। आईआईएफसीएल इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राजभाषा विभाग का मुख्य उद्देश्य केवल हिंदी में कार्य करने को बढ़ावा देना ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों में इस भाषा के प्रति आत्मीयता और सहजता की भावना विकसित करना तथा इसके व्यावसायिक उपयोग को सुदृढ़ करना भी है। इस रिपोर्ट में, हम वर्ष की प्रमुख गतिविधियों, उपलब्धियों और भावी योजनाओं का संक्षिप्त, किंतु व्यापक विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

वर्ष 2025–26 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें हिंदी में कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई और भावी लक्ष्यों पर विचार–विमर्श किया गया। इन बैठकों में समिति नियमित रूप से तिमाही आधार पर हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करती है तथा तिमाही और अन्य रिपोर्टें नियमित रूप से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग को प्रस्तुत की जाती हैं।

(ख) दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दिल्ली बैंक नराकास)

आईआईएफसीएल, दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (दिल्ली बैंक नराकास) का एक प्रमुख सदस्य है। इस समिति के तत्वावधान में, आईआईएफसीएल सदस्य संस्थानों के लिए विभिन्न विषयों पर राजभाषा (हिंदी) से संबंधित वार्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है और अन्य सदस्य संस्थानों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इन प्रतियोगिताओं में कई अधिकारियों ने पुरस्कार जीते हैं। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल दिल्ली बैंक नराकास के सदस्य संस्थानों के लिए दिल्ली–एनसीआर स्तर पर राजभाषा संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन भी करता है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए आईआईएफसीएल को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा वित्तीय संस्थानों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

(ग) राजभाषा पखवाड़ा/हिंदी दिवस समारोह

- भारत सरकार की राजभाषा नीति का पालन करते हुए, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) हिंदी दिवस (14 सितंबर) के उपलक्ष्य में 14 से 29 सितंबर तक बड़े उत्साह के साथ "हिंदी पखवाड़ा" मनाती है। इस दौरान विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
- इस अवधि के दौरान, हिंदी भाषी और गैर–हिंदी भाषी, दोनों प्रकार के प्रतिभागियों के लिए निबंध लेखन, टिप्पणी एवं प्रारूपण, सामान्य हिंदी ज्ञान प्रश्नोत्तरी और कहानी लेखन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है।
- विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाते हैं।

(घ) हिंदी कार्यशालाएं और प्रशिक्षण

- कार्यालय के कर्मचारियों को आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रत्येक तिमाही में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई।
- हिंदी में कुशलतापूर्वक कार्य करने की सुविधा के लिए हिंदी कार्यशालाओं और डेस्क प्रशिक्षण के माध्यम से कंप्यूटर पर यूनिकोड के उपयोग तथा सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाता है।
- वर्ष के दौरान आयोजित चार कार्यशाला प्रशिक्षण सत्रों में कुल 57 कर्मचारियों ने भाग लिया।
- संस्थान के कर्मचारियों के लिए हिंदी संगोष्ठियों और राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है।
- अधिकारियों को हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समय–समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2025–26 हिंदी के सफल और सकारात्मक कार्यान्वयन का वर्ष रहा। विभिन्न गतिविधियों, नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राजभाषा विभाग ने यह प्रदर्शित किया कि हिंदी केवल संचार की भाषा ही नहीं, बल्कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और परिचालन दक्षता का माध्यम भी बन सकती है।

हमें विश्वास है कि आने वाला वर्ष और भी बड़ी उपलब्धियों से परिपूर्ण होगा तथा हम हिंदी को संस्थान के केंद्र में स्थापित करने में सफल होंगे।

"राजभाषा के रूप में हिंदी केवल एक दायित्व नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान और आत्मगौरव का प्रतीक है।"

सहायक, संयुक्त उपक्रम एवं सहयोगी कंपनियाँ

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेडः

आईपीएल की 14वीं वर्षगांठ के अवसर पर, हमें अपनी कंपनी द्वारा अपने व्यवसाय को सुदृढ़ करने और एक सतत स्थिति बनाए रखने की दिशा में की गई निरंतर प्रगति प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। कंपनी ने आईआईएफसीएल समूह के मुख्य ज्ञान भागीदार और परामर्श प्रभाग के रूप में अपनी स्थिति सफलतापूर्वक स्थापित की है।

पिछले वर्ष के दौरान हमारी रणनीति का ध्यान चिन्हित विशिष्ट क्षेत्रों में व्यवसाय विकसित करने पर केंद्रित रहा, ताकि महत्वपूर्ण उभरते बाजारों में विशिष्ट और उच्च प्रभाव वाली परामर्श सेवाएँ प्रदान की जा सकें। नए अवसरों की तलाश करते हुए भी, हम अपने मूल परिचालनों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहे। कंपनी ने अपने स्थापित ग्राहक आधार के लिए निर्धारित मानकों को लगातार पूरा किया और चल रहे कार्यों का निर्बाध निष्पादन सुनिश्चित किया। कठोर परियोजना प्रशासन और गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखते हुए, हमने परिचालन उत्कृष्टता और विश्वसनीय परियोजना निष्पादन के लिए अपनी प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ किया।

लक्षित विकास और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, आपकी कंपनी ने दो–आयामी रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है। परिचालनों को दो अलग–अलग व्यावसायिक क्षेत्रों में संरचित किया गया हैः

- परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) खंड
- गैर–पीएमयू खंड

यह दोहरी कार्यप्रणाली आईपीएल को अपनी मूल क्षमताओं का सफलतापूर्वक उपयोग करने के साथ–साथ व्यापक स्तर की अवसंरचना पहलों की सेवा के लिए अपनी क्षमताओं में विविधता लाने में सक्षम बनाती है।

आज आईपीएल सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों के विविध ग्राहकों को वित्तीय समाधान, लेन–देन संबंधी परामर्श और निधि सिंडिकेशन सेवाएँ प्रदान करने में एक अग्रणी स्थिति रखता है। हम सतत मूल्य सृजन और रणनीतिक नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी क्षेत्रीय विशेषज्ञता को और गहरा करने तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी भावी कार्ययोजना का केंद्र इन उच्च–विकास वाले व्यावसायिक क्षेत्रों का विस्तार करके अधिक बाजार हिस्सेदारी प्राप्त करना है। हम सतत हरित अवसंरचना के क्षेत्र में सक्रिय रूप से परामर्श संबंधी कार्यादेश प्राप्त करेंगे, उच्च–विकास वाले क्षेत्रों का लाभ उठाएँगे और उच्च–मूल्य वाली सार्वजनिक–निजी भागीदारी स्थापित करेंगे। ये रणनीतिक प्राथमिकताएँ हमारे पोर्टफोलियो में विविधता लाएँगी, वित्तीय सुदृढ़ता को बढ़ावा देंगी और हमारे शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक रूप से बेहतर प्रतिफल उत्पन्न करेंगी। आपके निरंतर विश्वास और समर्थन से हमें अपनी विकास यात्रा के अगले चरण में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है।

वर्ष के दौरान आईपीएल के प्रदर्शन की प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैंः

- अपने भौगोलिक विस्तार को बढ़ाते हुए, आईपीएल ने 17 नवंबर, 2025 को आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, श्री चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश अवसंरचना निगम (आईएनसीएपी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईपीएल ने राज्य में प्रमुख विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है, जो राज्य के लिए एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स कंपनी की रूपरेखा तैयार करने और उसकी संरचना विकसित करने का कार्य कर रही है। यह कंपनी पूरे राज्य में प्रमुख लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक अवसंरचना परियोजनाओं के विकास में सहायता करेगी।
- इस वर्ष, आपकी कंपनी ने राज्य में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए मिजोरम सरकार के साथ एक और कार्यभार शुरू करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का और विस्तार किया है। आईपीएल मिजोरम में पर्यटन विकास के लिए विभिन्न पर्यटन सर्किटों की पहचान करने और भूटान को मानक के रूप में लेकर तुलनात्मक अध्ययन करने की दिशा में कार्य करेगा।
- तमिलनाडु और मेघालय के राज्य प्राधिकरणों तथा विदेश मंत्रालय जैसे केंद्रीय मंत्रालयों के साथ चल रहे परामर्श कार्यक्रमों का सफल निष्पादन और उनके प्रति प्रतिबद्धता कंपनी के सतत प्रदर्शन में महत्वपूर्ण और प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं। मेघालय में चल रहे कार्यादेश, प्रतिष्ठित शिलांग पीक तक संपर्क सुविधा बेहतर बनाने के लिए बहुप्रतीक्षित शिलांग रोपवे परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रोपवे क्षेत्र को संस्थागत रूप देने में महत्वपूर्ण रहे हैं। तमिलनाडु ट्रांसमिशन कंपनी (टीएनट्रांसको) के साथ उनकी खरीद प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मानकीकृत निविदा दस्तावेज तैयार करने के लिए अपना कार्यादेश सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, आईपीएल ने खरीद प्रक्रिया में दक्षता लाने के लिए एक अन्य राज्य ट्रांसमिशन कंपनी (एपीट्रांसको) से भी इसी प्रकार का कार्यादेश प्राप्त किया है।
- एयरोस्पेस के क्षेत्र में, आईपीएल ने अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत नियामक निकाय, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (इन–स्पेस) के साथ अपना चल रहा कार्यादेश सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसके अंतर्गत पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के क्षेत्र में भारत की पहली सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) को अंतिम रूप दिया गया। 12 पृथ्वी अवलोकन (ईओ) उपग्रहों के विकास और प्रबंधन

का अनुबंध पिक्सेल इंडिया के नेतृत्व वाले संघ को प्रदान किया गया। जनवरी 2026 में, भारत सरकार ने "एलाइड ऑर्बिट्स" नामक चार कंपनियों के संघ के साथ ₹ 1,200 करोड़ की इस सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) को अंतिम रूप दिया। इसके अंतर्गत संघ को 12 उपग्रहों से युक्त भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन (ईओ) उपग्रह समूह के निर्माण, प्रक्षेपण और संचालन के लिए रियायत प्रदान की गई।

- विश्व बैंक द्वारा समर्थित 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आरएएमपी (एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ावा देना और उसमें तेजी लाना) कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम निगरानी एजेंसी के रूप में, आईपीएल इस विकास एजेंडे के हिस्से के रूप में सबसे महत्वपूर्ण एमएसएमई क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने हेतु विकसित भारत 2047 के मिशन की दिशा में कार्य करना जारी रखे हुए है। योजना की चार वर्षों तक निगरानी के दौरान, आईपीएल ने योजना के अंतर्गत लगभग 400 परियोजनाओं के लिए 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ₹ 3,520 करोड़ के व्यय को सुगम बनाया। 27 जून, 2025 को, एमएसएमई दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, सरकार ने आरएएमपी योजना के अंतर्गत नवविकसित ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल शुरू किया। इसे सूक्ष्म या लघु उद्यमों के घर या कार्यालय से ही विलंबित भुगतान संबंधी विवादों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुगम बनाने के लिए तैयार किया गया है। रैम्प का योजना–आधारित शासन से प्रणाली–आधारित शासन की ओर बदलाव अधिक सशक्त संस्थानों, डेटा–आधारित नीतियों, बेहतर वित्तपोषण और बाजार तक बेहतर पहुँच का आधार बना है। इसमें लैंगिक समानता, हरित विकास और एमएसएमई की उत्पादकता पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए हरित एजेंडे को आगे बढ़ाने हेतु विश्व बैंक से अपना पहला कार्यादेश सफलतापूर्वक पूरा किया। आईपीएल ने इस क्षेत्र के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उपायों की पहचान करने हेतु एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में पूरे भारत में तीन (3) क्लस्टरों के लिए एक प्रारंभिक अध्ययन किया और उसे प्रस्तुत किया। इसमें वस्त्र, फाउंड्री और सिरेमिक क्षेत्र के क्लस्टर शामिल थे। आपकी कंपनी बड़े पैमाने पर हरित एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य करना जारी रखे हुए है।
- आईपीएल ने वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कई रणनीतिक कार्यादेशों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाकर और उनमें सहायता प्रदान करके अपनी सिंडिकेशन तथा कार्यादेश निष्पादन क्षमताओं को और सुदृढ़ किया है। केरल में सिटी गैस वितरण (सीजीडी) परियोजना के लिए ऋण सिंडिकेशन कार्यादेश उन्नत चरण में पहुँच गया है। इसमें आईआईएफसीएल ने प्रमुख बैंक के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है और वित्तीय समापन वित्तीय वर्ष 2027 के दौरान अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, आईपीएल ने आंध्र प्रदेश, मेघालय और तमिलनाडु में सड़क, बंदरगाह, सामाजिक अवसंरचना, शहरी आवागमन और हवाई अड्डा परियोजनाओं सहित विभिन्न अवसंरचना क्षेत्रों में कार्यादेश प्राप्त करने और उन्हें सुगम बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अपने संबंधों का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। आईपीएल निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं की सक्रिय रूप से पहचान करने और उनके साथ संपर्क स्थापित करने का कार्य भी कर रहा है। व्यवहार्य परियोजना प्रस्तावों को आगे विचार और वित्तपोषण सहायता के लिए नियमित रूप से आईआईएफसीएल के साथ साझा किया जा रहा है, जिससे एक सुदृढ़ परियोजना कार्यसूची विकसित करने और संस्थागत सहयोग बढ़ाने में योगदान मिल रहा है।
- आईपीएल एक चालू सेवा समझौते के अंतर्गत इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड को व्यापक द्वितीयक परियोजना मूल्यांकन और निगरानी सेवाएँ प्रदान करना जारी रखे हुए है। आईपीएल, लंदन में इंग्लैंड और वेल्स के कंपनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के लिए शुरू से अंत तक द्वितीयक परियोजना मूल्यांकन और निगरानी सेवाएँ प्रदान करना जारी रखे हुए है। यह कंपनी भारत में अवसंरचना परियोजनाएँ लागू करने वाली भारतीय कंपनियों को ऐसी परियोजनाओं के लिए उनके बाह्य वाणिज्यिक उधारों के सह–वित्तपोषण हेतु ऋण प्रदान करती है।
- आईपीएल वर्तमान में सामंजस्यपूर्ण सूची के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं के एक समेकित पोर्टफोलियो का प्रबंधन कर रहा है, जिसमें लगभग 1.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी निवल मंजूरियाँ शामिल हैं। इस पोर्टफोलियो में पुनर्वित्तपोषित परिसंपत्तियाँ और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के अंतर्गत समाधान की प्रक्रिया से गुजर रही परियोजनाएँ, दोनों शामिल हैं, जिनसे संबंधित मामले राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष चल रहे हैं। प्रदान की जाने वाली सेवाओं के व्यापक दायरे में द्वितीयक परियोजना वित्तीय मूल्यांकन, प्रारूप निदेशक मंडल ज्ञापन तैयार करना, संवितरण और संशोधन अनुरोधों का प्रसंस्करण तथा आईआईएफसी (यूके) की ओर से परियोजनाओं की समग्र निगरानी शामिल है।

कार्यादेशों के सुचारू और कुशल निष्पादन तथा देश में, विशेष रूप से राज्य के ग्राहकों/प्राधिकरणों के बीच, आईआईएफसीएल समूह की पहुँच और स्थिति का विस्तार करने के लिए, आपकी कंपनी ने समर्पित कार्य दल तैनात किए हैं। इन दलों में मुख्य कर्मचारी और/या परामर्शदाता/रिटेनर शामिल हैं, जिन्हें रणनीतिक रूप से निम्नलिखित स्थानों पर तैनात किया गया है:

- नई दिल्ली
- मेघालय
- मिजोरम

- तमिलनाडु
- गिफ्ट सिटी शाखा

यह मानते हुए कि उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करने में विशेषज्ञ मानव संसाधन प्राथमिक उत्प्रेरक हैं, आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान मानव संसाधन संवर्धन में निवेश किया। इस निवेश का उद्देश्य इन कार्यादेशों के निष्पादन के लिए कुशल कार्मिकों का समूह तैयार करना और अपनी सेवाओं को इनके लिए तैयार करना था।

इसके अतिरिक्त, अपने ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएँ निरंतर प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने आवश्यक कौशल वाले नए प्रतिभाशाली कार्मिकों को आकर्षित करने हेतु भर्ती प्रक्रिया शुरू की है।

इस विकास रणनीति के हिस्से के रूप में, आईपीएल स्वयं को अवसंरचना परियोजना के संपूर्ण जीवन चक्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित करेगा। कंपनी प्रत्येक चरण में उच्च प्रभाव वाले समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है:

- अवधारणा विकास एवं योजना: परियोजनाओं का प्रारंभिक चरण में निर्माण और संरचना तैयार करना।
- निष्पादन: सक्रिय तैनाती और परियोजना के कार्यान्वयन में निरंतर सहायता प्रदान करना।
- संचालन एवं रखरखाव: दीर्घकालिक परिसंपत्ति प्रबंधन और निगरानी।

यह व्यापक स्थिति निर्धारण विभिन्न क्षेत्रों में सतत और सुदृढ़ अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

आईपीएल ने ₹ 18.35 करोड़ का कुल राजस्व अर्जित किया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में कुल राजस्व ₹ 21.03 करोड़ था। आईपीएल ने वर्ष के दौरान ₹ 15.60 लाख का निवल लाभ दर्ज किया, जिससे आपकी कंपनी की निवल संपत्ति ₹ 26.55 करोड़ हो गई।

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड:

आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड, आईआईएफसीएल की विदेश में स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी स्थापना अप्रैल 2008 में भारत में अवसंरचना परियोजनाएँ लागू करने वाली कंपनियों को पूंजीगत उपकरणों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की गई थी। आईआईएफसी (यूके) की अधिकृत पूंजी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और कंपनी की वर्तमान चुकता पूंजी 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। 31 मार्च, 2026 तक, कंपनी ने प्रत्यक्ष ऋण के अंतर्गत 53 परियोजनाओं और पुनर्वित्तपोषण के अंतर्गत 5 संस्थानों को क्रमशः 5,368.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 5,075 मिलियन अमेरिकी डॉलर की संचयी सकल और निवल मंजूरियाँ प्रदान की हैं। 31 मार्च, 2026 तक कंपनी ने 2,611 मिलियन अमेरिकी डॉलर का संचयी संवितरण किया है। भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण सुविधा (लाइन ऑफ क्रेडिट) आईआईएफसी (यूके) के लिए निधियों का प्राथमिक स्रोत रही है और 31 मार्च, 2026 तक भारतीय रिजर्व बैंक को देय बॉन्ड की बकाया निवल मूलधन राशि 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण सुविधा के अतिरिक्त, आईआईएफसी (यूके) भारत में अवसंरचना विकास के लिए अपने वित्तीय संसाधनों को और बढ़ाने के उद्देश्य से निधियों के नए स्रोतों की निरंतर तलाश कर रही है। इसी के अनुरूप, कंपनी ने 31 मार्च, 2026 तक 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की द्विपक्षीय ऋण सुविधा जुटाई। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी का कर–पश्चात लाभ 10.05 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान कंपनी की निवल संपत्ति बढ़कर 188.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

स्थापना के बाद से, आईआईएफसी (यूके) का संचालन एसआईएफटीआई के अनुरूप किया जाता रहा है। भारत सरकार ने दिनांक 15 अप्रैल, 2026 के पत्र संख्या एफ. सं. 18/9/2024–आईएफ–I के माध्यम से एसआईएफटीआई को वापस ले लिया है। इसके परिणामस्वरूप, आईआईएफसी (यूके) ने अपने ऋण उत्पाद तैयार किए हैं, जिससे भारत और भारत के बाहर अवसंरचना परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने का दायरा बढ़ गया है।

आईएएमसीएल:

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने प्रायोजक के रूप में आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की स्थापना 17 अगस्त, 2012 को भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के अनुसार एक न्यास के रूप में की थी। आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएएमसीएल) एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 28 मार्च, 2012 को निगमित किया गया था और यह आईआईएफसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) के न्यासियों ने 17 अगस्त, 2012 को आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) के न्यासी मंडल और आईएएमसीएल के बीच निष्पादित निवेश प्रबंधन समझौते (आईएमए) के माध्यम से आईएएमसीएल को आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) के रूप में नियुक्त किया था।

31 जनवरी, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) के न्यासी मंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की दोनों मौजूदा योजनाओं को समय से पहले बंद करने का निर्णय लिया था। इसका मुख्य कारण उच्च अनुपालन लागत तथा आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) और आईएएमसीएल द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 तथा अवसंरचना ऋण निधियों पर लागू परिपत्रों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थता थी। आईआईएफसीएल म्यूचुअल फंड (आईडीएफ) की संबंधित योजनाओं के यूनिटधारकों को मोचन/पुनर्भुगतान की अनुमति देने के लिए सेबी की 23 अगस्त, 2023 की मंजूरी के बाद, आईएएमसीएल ने 25 सितंबर, 2023 को संबंधित योजनाओं के यूनिटधारकों को विधिवत मोचन राशि का भुगतान कर दिया। समापन रिपोर्ट अक्टूबर 2023 में सेबी को प्रस्तुत की गई। इसके अतिरिक्त, म्यूचुअल फंड लाइसेंस के समर्पण के लिए सेबी को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सेबी ने अतरल/चूकग्रस्त प्रतिभूतियों के निपटान के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में सलाह दी है। इसका अनुपालन करने की प्रक्रिया जारी है। इन प्रतिभूतियों का निपटान हो जाने के बाद, आईएएमसीएल म्यूचुअल फंड लाइसेंस के समर्पण के लिए आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करेगी।

महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण संबंधी नीति के प्रकटीकरण हेतु वेबलिंकः

https://www-iifcl-in/images/FileUploaded/Website महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण संबंधी आईआईएफसीएल की अद्यतन नीति पीडीएफ 07072026114904.pdf

एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण, साथ ही उसके कारण

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(vi) के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान एकमुश्त निपटान (ओटीएस) के अंतर्गत निपटाई गई अवसंरचना परियोजना परिसंपत्तियों के लिए मूल्यांकन में अंतर का विवरण नीचे दिया गया हैः

क्र. सं.	परियोजना / एसपीवी का नाम	ऋण स्वीकृति के समय मूल्यांकन (मूल्यांकित परियोजना लागत के अनुसार) (क)	ओटीएस / बट्टे खाते में डालने के चरण में मूल्यांकन (वसूली योग्य मूल्य) (ख)	अंतर (क – ख)	अंतर के प्रमुख कारण
1	शामलाजी एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड	₹ 1,361.00 करोड़	₹ 321.68 करोड़	₹ 1,039.32 करोड़	परियोजना ने कुल लेआउट का 84: भौतिक कार्य पूरा कर लिया था (अलग किए गए हिस्से को छोड़कर 90: से अधिक कार्य पूरा हो चुका था) और स्वतंत्र इंजीनियर (आईई) ने 25 अक्टूबर 2023 से प्रभावी अनंतिम वाणिज्यिक संचालन तिथि (पीसीओडी) घोषित करने की सिफारिश की थी। हालाँकि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा पीसीओडी के लिए अपेक्षित स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। इसके बाद, एनएचएआई ने 11 मार्च 2024 को निलंबन संबंधी नोटिस जारी किया, जिसमें परियोजना के संबंधित हिस्से को पूरा करने, उसकी मरम्मत करने और कमियों को दूर करने के लिए 180 दिनों की सुधार अवधि प्रदान की गई। इस 180–दिवसीय अवधि के समाप्त होने तक कमियों को दूर नहीं किए जाने के कारण, रियायत समझौते के खंड 30.5.2 के अंतर्गत परियोजना को समाप्त माना गया और 31 मार्च 2025 को खाते को अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया। निलंबन के बाद, रियायतग्राही और एनएचएआई, दोनों द्वारा दावे और प्रतिदावे दायर किए गए। परिणामस्वरूप, निपटान के चरण में मूल्यांकन, इन दावों के अनुमानित वसूली योग्य मूल्य और रियायत संबंधी ढाँचे के अंतर्गत लागू समाप्ति भुगतानों के आधार पर निर्धारित किया गया।

क्र. सं.	परियोजना / एसपीवी का नाम	ऋण स्वीकृति के समय मूल्यांकन (मूल्यांकित परियोजना लागत के अनुसार) (क)	ओटीएस / बट्टे खाते में डालने के चरण में मूल्यांकन (वसूली योग्य मूल्य) (ख)	अंतर (क – ख)	अंतर के प्रमुख कारण
2	त्रिची तंजावुर एक्सप्रेसवे लिमिटेड	₹ 390.00 करोड़	₹ 0.00 करोड़	₹ 390.00 करोड़	परियोजना को जून 2018 में गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया था, क्योंकि यातायात की वास्तविक मात्रा मूल मूल्यांकन में अनुमानित मात्रा से कम थी, जिसके कारण ऋण सेवा संबंधी दायित्वों को पूरा करने के लिए नकदी प्रवाह में कमी आई। इसके बाद, मार्च 2023 में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने रियायतग्राही द्वारा अनिवार्य प्रमुख रखरखाव (एमएम) कार्य न किए जाने के कारण रियायत समझौते को समाप्त कर दिया। परिणामस्वरूप, ऋण की वसूली के लिए ऋणदाताओं के पास परियोजना से भविष्य में कोई नकदी प्रवाह या टोल राजस्व उपलब्ध नहीं था।
3	आईवीसीआरएल इंदौर गुजरात टोलवेज लिमिटेड	₹ 1,523.71 करोड़	₹ 527.01 करोड़	₹ 996.70 करोड़	परियोजना का कार्य मूल 2013 की निर्धारित समय–सारणी से काफी अधिक विलंब से पूरा हुआ। इसका कारण एनएचएआई द्वारा रास्ते का अधिकार (आरओडब्ल्यू) सौंपने में हुई देरी और प्रवर्तक की इक्विटी निधि उपलब्ध कराने में असमर्थता थी, जिसके परिणामस्वरूप **30 जून 2017** को खाता एनपीए हो गया। 2018 में अनंतिम वाणिज्यिक संचालन तिथि (पीसीओडी) के बाद, वास्तविक टोल राजस्व मूल अनुमानों के 60: से 80: के बीच रहा है। ओटीएस चरण में मूल्यांकन, 2041 में समाप्त होने वाली शेष रियायत अवधि के दौरान अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के रियायती मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया।

नोटः गैर–आश्रय अवसंरचना वित्तपोषण की प्रकृति के अनुरूप, ऋण स्वीकृति के समय किया गया मूल्यांकन ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित मूल्यांकित परियोजना लागत को दर्शाता है, क्योंकि निर्माण–पूर्व स्वीकृति के चरण में कोई भौतिक परिसंपत्ति अस्तित्व में नहीं होती है।

वित्तीय वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी भी कार्यवाही का विवरण, साथ ही वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थितिः

क्र. सं.	परियोजना खाता का नाम	मूलधन बकाया (रुपये में) (31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)	मौजूदा एनसीएलटी स्थिति
1	अभिजीत हजारीबाग टोल रोड लिमिटेड	26,30,88,000.00	परिसमापन के अधीन, विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत वसूली प्राप्त हुई
2	अभिजीत टोल रोड (कर्नाटक) लिमिटेड	9,07,00,001.00	परिसमापन के अधीन
3	आईवीआरसीएल इंदौर गुजरात टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	2,99,71,69,071.00	आईआईएफसीएल द्वारा प्रवर्तक कंपनी आईवीआरसीएल लिमिटेड के विरुद्ध एनसीएलटी में ₹ 421 करोड़ की राशि का दावा दायर किया गया।
4	जीवीके बागोदरा वासद एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड	1,22,14,74,028.05	प्रवर्तक कंपनी जीवीके ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड के विरुद्ध आईआईएफसीएल द्वारा एनसीएलटी में ₹ 490 करोड़ की राशि का दावा दायर किया गया।

क्र. सं.	परियोजना खाता का नाम	मूलधन बकाया (रुपये में) (31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)	मौजूदा एनसीएलटी स्थिति
5	इंडस्ट्रीज–बराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड	89,24,00,000.00	परिसमापन की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल द्वारा इंड–भारत पावर इंफ्रा लिमिटेड के विरुद्ध ₹ 229 करोड़ की राशि का एक पृथक दावा भी दायर किया गया है।
6	एस्सेल अहमदाबाद गोधरा टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड	1,09,85,06,064.19	सीआईआरपी की कार्यवाही जारी है।
7	ट्रांसस्ट्रॉय तिरूपति तिरुथानी चेन्नई टोलवेज लिमिटेड	23,52,98,782.00	परिसमापन के अंतर्गत वसूली प्राप्त हुई।
8	तूतीकोरिन कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	34,83,42,632.15	सीआईआरपी की कार्यवाही जारी है।
9	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	2,38,62,50,000.00	सीआईआरपी की कार्यवाही जारी है।
10	टीडी टोल रोड प्रा. लिमिटेड	30,33,26,762.18	सीआईआरपी की कार्यवाही जारी है।
11	टॉपवर्थ टोलवेज (बेला) प्राइवेट लिमिटेड	24,71,99,487.00	प्रवर्तक अभय नरेंद्र लोढ़ा के विरुद्ध एनसीएलटी में दावा दायर किया गया है।
12	एस्सेल लुधियाना तलवंडी टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड	1,13,58,90,559.94	सीओसी की कार्यवाही जारी है।
13	इंदौर देवास टोलवेज लिमिटेड	1,16,02,09,098.21	परिसमापन की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल द्वारा प्रवर्तक कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड के विरुद्ध ₹ 494 करोड़ की राशि का पृथक दावा एनसीएलटी में दायर किया गया है।
14	सोलापुर टोलवेज प्रा. लिमिटेड	1,36,51,46,510.00	सीआईआरपी की कार्यवाही जारी है।
15	जीवीके देवली कोटा एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड	1,34,21,68,551.00	आईआईएफसीएल द्वारा प्रवर्तक कंपनी जीवीके ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड के विरुद्ध ₹ 490 करोड़ की राशि का दावा एनसीएलटी में दायर किया गया है।
16	सुप्रीम पनवेल इंदापुर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	1,39,28,30,427.00	सीआईआरपी की प्रक्रिया जारी है।
17	आर्यावर्त टोलवेज प्रा. लिमिटेड	9,72,74,841.62	अभी तक मामला स्वीकार नहीं किया गया है; वर्तमान में बहस हेतु आदेश सुरक्षित रखा गया है।
18	जीवीके पावर (गोइंदवाल साहिब) लिमिटेड	1,80,45,85,775.64	सीआईआरपी की प्रक्रिया जारी है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल द्वारा प्रवर्तक कंपनी जीवीके एनर्जी के विरुद्ध ₹ 610 करोड़ की राशि का पृथक दावा दायर किया गया है।
19	एल एंड टी हलोल शामलाजी टोलवेज प्रा. लिमिटेड	76,71,33,333.32	सीआईआरपी की प्रक्रिया जारी है।
20	साई मातरिनी टोलवेज लिमिटेड (एसएमटीएल)	3,10,94,16,551.10	सीआईआरपी की प्रक्रिया जारी है; इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल द्वारा प्रवर्तक कंपनी गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड के विरुद्ध ₹494 करोड़ की राशि का पृथक दावा एनसीएलटी में दायर किया गया है।
21	एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	1,91,93,32,463.74	आईआईएफसीएल द्वारा प्रवर्तक कंपनी एमईपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ₹671 करोड़ की राशि का दावा एनसीएलटी में दायर किया गया है।
22	एमईपी संजोस तलाजा महुवा रोड प्रा. लिमिटेड	73,73,35,971.46	आईआईएफसीएल द्वारा प्रवर्तक कंपनी एमईपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ₹671 करोड़ की राशि का दावा एनसीएलटी में दायर किया गया है।

क्र. सं.	परियोजना खाता का नाम	मूलधन बकाया (रुपये में) (31.03.2026 की स्थिति के अनुसार)	मौजूदा एनसीएलटी स्थिति
23	एमईपी संजोस मजुवा कागावादर रोड प्रा. लिमिटेड	55,49,76,365.51	आईआईएफसीएल द्वारा प्रवर्तक कंपनी एमईपी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ₹671 करोड़ की राशि का दावा एनसीएलटी में दायर किया गया है।
24	अंसल एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	28,91,31,649.50	आईआईएफसीएल द्वारा प्रवर्तक कंपनी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध ₹82.98 करोड़ की राशि का दावा एनसीएलटी में दायर किया गया है।

वैधानिक और अन्य सूचना आवश्यकताएँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार दी जाने वाली जरूरी जानकारी इस रिपोर्ट के साथ नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	अनुबंध
1	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	I
2	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(क) के अनुसार फॉर्म संख्या एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का सार	II
3	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	III
4	राशि यदि आरक्षित निधियों (रिजर्व) में अंतरित की गई हो	IV

आभार ज्ञापन

निदेशक मंडल केंद्र सरकार, विशेष रूप से वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग एवं आर्थिक कार्य विभाग, नीति आयोग, राज्य सरकारों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय भागीदारों, कर्मचारियों, ग्राहकों तथा अन्य सभी हितधारकों के निरंतर सहयोग एवं समर्थन के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। निदेशक मंडल कंपनी के लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई), भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) तथा समझौता ज्ञापन (एमओयू) के भागीदारों के बहुमूल्य मार्गदर्शन, सहयोग एवं परामर्श के लिए भी उनका आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल कंपनी के सभी कर्मचारियों के समर्पण, कड़ी मेहनत एवं उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए उनके प्रति अपना आभार दर्ज करना चाहता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

हस्ता./–
रोहित ऋषि
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 11524681

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 24.09.2026

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
फोन : 9810690633, 8527087435
ईमेल : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
जीएसटी संख्या : 07ABTFA2714K1Z7

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु]

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,
सदस्यगण
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पाँचवाँ तल, ब्लॉक–2, प्लेट ए एवं बी,
एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023

हमने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, (सीआईएनः U67190DL2006GOI144520) (इसके बाद कंपनी कहा जाए) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और सुलभ कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से धारित किया गया था जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी द्वारा संधारित पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों एवं रिटर्नों, तथा अन्य अभिलेखों/रजिस्टरों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर, और साथ ही सचिवीय लेखा–परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान, नीचे उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त, यह भी कि कंपनी में उपर्युक्तानुसार, यहां आगे की गई रिपोर्टिंग के अधीन, समुचित बोर्ड–प्रक्रियाएं तथा अनुपालन–तंत्र निर्धारित सीमा तक, निर्दिष्ट विधि से एवं उपयुक्त रूप में विद्यमान हैं–

हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुई लेखा परीक्षा अवधि के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजात, कार्यवृत्त बुक, प्रपत्रों और दाखिल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके अधीन बनाए गए नियम;
(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;
(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रवासी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋणों की लागू सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;
(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियमन और दिशा–निर्देश यथाय

(क). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015;

(ख). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का सारभूत अधिग्रहण) विनियम, 2011; [लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं]

(ग). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार का निषेध) विनियम, 2015; [लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं]

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
फोन : 9810690633, 8527087435
ईमेल : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
जीएसटी संख्या : 07ABTFA2714K1Z7

(घ). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं,

(ङ). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियमन, 2021;

(च). कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियमन, 1993; कंपनी किसी इश्यू के रजिस्ट्रार से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं थी और शेयरअंतरण एजेंट के रूप में भी काम नहीं कर रही थी, इसलिए लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपरोक्त विनियमन कंपनी पर लागू नहीं थेय

(छ). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021; [लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं]

(ज). भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2021; [लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं]

(a) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाई बैक) विनियम, 2018; [लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं]

(vi) अन्य श्रम परिवेश और कंपनी पर लागू विशिष्ट अधिनियम/कानून जिसके लिए सचिवीय लेखा परीक्षा एक अवलोकन लेखा परीक्षा के रूप में आयोजित किया गया था और आम तौर पर हमें प्रदान किए गए दस्तावेजों और अन्य पेशेवरों द्वारा दी गई लेखा परीक्षा रिपोर्ट और प्रमाण पत्रों पर आधारित/भरोसा किया गया था, कंपनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू निम्नलिखित अधिनियमों/कानूनों का अनुपालन किया है:

(क). भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (रिजर्व बैंक) निदेश, 2025 के प्रावधानों के साथ, यथासमय संशोधित रूप में;

(ख). श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा कानून (जहाँ तक लागू हों);

(ग). सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;

(घ). सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006;

(ङ). कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013

इसके अतिरिक्त, हमने निम्नलिखित के लागू प्रावधानों के अनुपालन की भी जांच की है:

(क). भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

(ख). भारत सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशा–निर्देश।

हमने लागू वित्तीय कानूनों, जैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों की जांच नहीं की है, क्योंकि ये वैधानिक वित्तीय लेखा–परीक्षा तथा अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन रहे हैं।

हम रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का ऊपर उल्लेखित अनुसार अनुपालन किया है, सिवाय:

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
फोन : 9810690633, 8527087435
ईमेल : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
जीएसटी संख्या : 07ABTFA2714K1Z7

(क). समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अंतर्गत अपेक्षित निदेशक मंडल की कुल संख्या के आधे से कम थी।

(ख). कंपनी के निदेशक मंडल में 03.12.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान कोई महिला निदेशक नहीं थी, जबकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के अंतर्गत ऐसा होना अपेक्षित था।

(ग). समीक्षाधीन अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना क्रमशः सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 18 (1) और 19 (1), कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के क्रमशः पैरा 4.1.1 और 5.1 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की क्रमशः धारा 177 (2) और 178 (1) के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।

(घ). समीक्षाधीन अवधि के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुपालन में आयोजित नहीं की गई, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।

इसके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि

कंपनी का निदेशक मंडल कार्यकारी निदेशकों एवं गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत् गठित है। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक की आवश्यक संख्या उपलब्ध नहीं थी। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में यदि कोई परिवर्तन किए गए, तो वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही किए गए।

सभी निदेशकों को विधिक प्रावधानों के अनुसार बोर्ड एवं समिति बैठकों के आयोजन हेतु पर्याप्त सूचना प्रदान की जाती है। जिन एजेंडा एवं विस्तृत टिप्पणियों को अल्प सूचना पर प्रेषित किया गया, उन्हें कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक–1 के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही विचारार्थ लिया गया। इसके अतिरिक्त, बैठकों से पूर्व एजेंडा बिंदुओं पर अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठकों में सार्थक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु एक सुव्यवस्थित प्रणाली विद्यमान है।

बोर्ड अथवा बोर्ड की किसी भी समिति की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय, यथास्थिति, सर्वसम्मति से लिए गए हैं तथा उन्हें संबंधित बैठकों की कार्यवृत्त में विधिवत् अभिलिखित किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी, उसके निदेशकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम तथा इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अंतर्गत कोई अभियोजन प्रारंभ नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त हम रिपार्ट करते हैं कि सूचनाओं एवं अनुरक्षित अभिलेखों के आधार पर कंपनी के आकार एवं परिचालन के अनुरूप अन्य सभी लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी एवं सुनिश्चितता हेतु कंपनी में पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

इसके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा दो सीरीज में कुल ₹ 3,560 करोड़ के घरेलू बॉण्ड जारी किए गए।

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
फोन : 9810690633, 8527087435
ईमेल : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
जीएसटी संख्या : 07ABTFA2714K1Z7

इसके अतिरिक्त हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित के कोई भी मामले नहीं पाए गए:

क) शेयर/स्वेट इक्विटी का सार्वजनिक/राइट/अधिमान्य निर्गम;

ख) प्रतिभूतियों की बाय–बैक;

ग) विलय/समामेलन/पुनर्गठन आदि।

घ) विदेशी तकनीकी सहयोग।

कृते अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण कोड सं.: P1995DE072900
सहकर्मी समीक्षा सं. 7777/2031

हस्ता./–
सीएस दीपक कुमार
एफसीएस:– F 10189
सी.ओ.पी: 11372
यूडीआईएन सं.: F010189H001449385

दिनांक: 11/09/2026
स्थान: नई दिल्ली

[नोट: इस रिपोर्ट को हमारे सम तिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो "अनुलग्नक क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।]

अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
21, शामनाथ मार्ग, सिविल लाइंस, दिल्ली–110054
फोन : 9810690633, 8527087435
ईमेल : rohatgi_co_secy@yahoo.co.in
csdelhi84@gmail.com
जीएसटी संख्या : 07ABTFA2714K1Z7

अनुलग्नक–"क"

सेवा में,
सदस्यगण
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पाँचवाँ तल, ब्लॉक–2, प्लेट ए एवं बी,
एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023

इस पत्र के साथ हमारी सम तिथि की रिपोर्ट इस प्रकार पढ़ी जानी चाहिए:

1) कंपनी के सचिवीय अभिलेखों का संधारण कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर किए गए हमारे लेखा–परीक्षण के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है।

2) सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने हेतु हमने उपयुक्त लेखा–परीक्षण पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है। सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्यों का प्रतिबिंबन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ हमारे मत के लिए एक युक्तिसंगत आधार प्रदान करती हैं।

3) हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की शुद्धता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

4) जहाँ–जहाँ आवश्यक हुआ, वहाँ कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन तथा घटनाओं के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया गया है।

5) कॉरपोरेट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा केवल परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित रही है।

6) यह सचिवीय लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन न तो कंपनी की भविष्य की निरंतरता का कोई आश्वासन है और न ही इस बात का कि प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन कितनी दक्षता या प्रभावशीलता से किया गया है।

कृते अखिल रोहतगी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण कोड सं.: P1995DE072900
सहकर्मी समीक्षा सं. 7777/2031

हस्ता./–
सीएस दीपक कुमार
एफसीएस:– F 10189
सी.ओ.पी: 11372
यूडीआईएन सं.: F010189H001449385

दिनांक: 11/09/2026
स्थान: नई दिल्ली

क्र.सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
I	कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015	
क)	समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की कुल क्षमता के आधे से भी कम थी, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 और डीपीई दिशानिर्देशों के विनियमन 17(1) के अंतर्गत आवश्यक है।	आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में निदेशकों का चयन और नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आईआईएफसीएल की अपने निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय (डीएफएस) से अनुरोध किया है। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 18/7/2022 – आईएफ – I दिनांक 10 मई 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 115 (1)(घ) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने श्री समीर जेरमभाई बोगहरा को उनकी नियुक्ति के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है।
ख)	कंपनी के निदेशक मंडल में 03.12.2025 से 31.03.2026 की अवधि के दौरान कोई महिला निदेशक नहीं थी, जबकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध ता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) के अंतर्गत ऐसा होना अपेक्षित था।	आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में निदेशकों का चयन और नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आईआईएफसीएल की अपने निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में 3 दिसंबर 2025 तक महिला निदेशक थीं। हालाँकि, सुश्री एम.जी. जयश्री के स्थान पर श्री चंद्रदीप कुमार झा की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, 3 दिसंबर 2025 से महिला निदेशक का पद रिक्त हो गया। इसके बाद, आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में महिला निदेशक की नियुक्ति करने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय (डीएफएस) से अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या 3/1/2010–आईएफ–I (खंड IV) दिनांक 19 जून 2026 के माध्यम से सूचित किया है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों के अनुच्छेद 115 (1)(ख)(i) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने श्री आलोक तिवारी के स्थान पर सुश्री लया मद्दुरी, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नामित किया है।

क्र.सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन का उत्तर
ग)	समीक्षाधीन अवधि के दौरान, लेखापरीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना क्रमशः सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 18 (1) और 19 (1), कॉरपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के क्रमशः पैरा 4.1.1 और 5.1 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की क्रमशः धारा 177 (2) और 178 (1) के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।	आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में निदेशकों का चयन और नामांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आईआईएफसीएल की अपने निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है। आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय (डीएफएस) से अनुरोध किया है।
घ)	समीक्षाधीन अवधि के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुपालन में आयोजित नहीं की गई, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था।	लागू नहीं। भारत सरकार द्वारा आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल में केवल 1 स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है।

अनुलग्नक II

प्रपत्र सं. एमजीटी–9

वार्षिक रिटर्न का सार

31.03.2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2013 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

1.	**सीआईएन**	**U67190DL2006GOI144520**
2.	पंजीकरण की तिथि	5 जनवरी 2006
3.	कंपनी का नाम	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	भारत सरकार का उपक्रम
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	पाँचवाँ तल, ब्लॉक–2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 दूरभाषः 91–11–24662777 फैक्सः 91–11–20815125 ई–मेलः information@iifcl.in
6.	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	हाँ
7.	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (यदि कोई हो) का नाम, पता एवं संपर्क विवरण।	**केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड** संपर्क व्यक्तिः श्री उमेश पांडे पताः सेलेनियम टावर बी, प्लॉट संख्या 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद – 500032, भारत दूरभाष संख्याः 040–67162222, 040–67161595 ई–मेल आईडीः einward.ris@kfintech.com वेबसाइटः www.kfintech.com **आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड** संपर्क व्यक्तिः श्री रविंदर दुआ पताः बी–25/1, प्रथम तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–2, नई दिल्ली–110 020 दूरभाष संख्याः 011–26387320–21 ई–मेल आईडीः investor.services@rcmcdelhi.com वेबसाइटः www.rcmcdelhi.com **बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (पी) लिमिटेड** संपर्क व्यक्तिः श्री पुनीत मित्तल पताः तीसरी मंजिल, बीटल हाउस, 99, लोकल शॉपिंग सेंटर के पीछे, मदनगीर गाँव, मदनगीर, नई दिल्ली, दिल्ली 110062 दूरभाष संख्याः 011–29961281–83 ई–मेल आईडीः beetal@beetalfinancial.com वेबसाइटः www.beetalfinancial.com **अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड** संपर्क व्यक्तिः श्री अभिनव कुमार अग्रवाल पताः 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 दूरभाष संख्याः 7290067787 ई–मेल आईडीः abhinavka@alankit.com वेबसाइटः www.alankit.com

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

(कंपनी के कुल कारोबार में 10 प्रतिशत या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण दिया जाए)

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड *	कंपनी के कुल कारोबार में प्रतिशत योगदान
1	अवसंरचना वित्तपोषण**	649–बीमा एवं पेंशन निधि गतिविधियों को छोड़कर अन्य वित्तीय सेवा गतिविधियाँ	100%

**राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण – सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार*

**इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006 में व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यह वित्तपोषण इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) नामक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना के अंतर्गत किया जाता है, जिसे व्यापक रूप से एसआईएफटीआई के रूप में जाना जाता है। आईआईएफसीएल से वित्तीय सहायता हेतु पात्र क्षेत्र 1 मार्च 2012 को अवसंरचना संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित अवसंरचना उप–क्षेत्रों की समन्वित सूची के अनुसार हैं। इनमें परिवहन, ऊर्जा, जल, स्वच्छता, संचार, सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचना शामिल हैं।

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) सितंबर 2013 से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एनबीएफसी–एनडी–आईएफसी के रूप में पंजीकृत है।

III. धारित, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	कंपनी का पमा	सीआईएन/जीएलएन	धारित/सहायक/सहयोगी	धारित शेयर का %	लागू खंड
1	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	तृतीय तल, 72, किंग विलियम स्ट्रीट, लंदन ईसी4एन 7एचआर, यूनाइटेड किंगडम दूरभाष (सामान्य): 44–20–7776 8950 ई–मेलः info@iifc.org.uk	06496661*	सहायक	100%	2(87)(ii)
2	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	पाँचवाँ तल, ब्लॉक–2, प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 दूरभाषः 91–11–2465573 ई–मेलः contact@iifclprojects.com	U74999DL2012GOI231473	सहायक	100%	2(87)(ii)
3	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	पाँचवाँ तल, ब्लॉक–2, प्लेट ए, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 दूरभाषः +91–11–24665900–10 ई–मेलः cio@iifclmf.com	U65991DL2012GOI233601	सहायक	100%	2(87)(ii)

*इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड को यूनाइटेड किंगडम के कंपनी अधिनियम, 1985 के अंतर्गत 7 फरवरी 2008 को लंदन स्थित इंग्लैंड एवं वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनियों में पंजीकृत किया गया था [कंपनी सं. 6496661]।

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में वर्गीकरण)

i. श्रेणी–वार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल 2025 की स्थिति में)				वर्ष की अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2026 की स्थिति में)				वर्ष के दौरान % बदलाव
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का%	
क. प्रवर्तक									-
(1) **भारतीय**									-
क) वैयक्तिक / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्र सरकार	-	**999.991623 करोड़**	**999.991623 करोड़**	**100%**	-	**999.991623 करोड़**	**999.991623 करोड़**	**100%**	-
ग) राज्य सरकार (एँ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय कॉर्पोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (क) (1)	-	**999.991623 करोड़**	**999.991623 करोड़**	**100%**	-	**999.991623 करोड़**	**999.991623 करोड़**	**100%**	-
(2) विदेशी									-
क) एनआरआई – वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य – वैयक्तिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय कॉर्पोरेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) अन्य कोई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (क) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तकों की कुल शेयरध ारिता (क)(1)+(क)(2)	-	**999.991623 करोड़**	**999.991623 करोड़**	**100%**	-	**999.991623 करोड़**	**999.991623 करोड़**	**100%**	-
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									-
1. संस्थान									-
क) म्यूचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार(एँ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ख) (1) :–	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर–संस्थान									-
क) कॉर्पोरेट निकाय									-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) ₹1 लाख तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या (01 अप्रैल 2025 की स्थिति में)				वर्ष की अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2026 की स्थिति में)				वर्ष के दौरान % बदलाव
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का%	
ii) ₹1 लाख से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (विवरण दें)									
i) योग्य विदेशी निवेशक	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) अनिवासी भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iii) समाशोधन सदस्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
iv) सहायक कंपनियों के पास रखे गए ऐसे शेयर, जिन पर मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
v) अघोषित शेयरों का सस्पेंस खाता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
vi) न्यासी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ख)(2):–	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर एवं एडीआर हेतु कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (क+ख+ग)	**-**	**999.991623 करोड़**	**999.991623 करोड़**	**100%**	-	**999.991623 करोड़**	**999.991623 करोड़**	**100%**	**-**

ii. प्रवर्तक की शेयरधारिता

शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01.04.2025 की स्थिति में)			शेयरधारक का नाम	वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2026 की स्थिति में)			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में प्रतिशत बदलाव
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	कुल शेयरों में गिरवी/भारित शेयरों का प्रतिशत					
भारत के माननीय राष्ट्रपति	999,99,16,223	100	-	भारत के माननीय राष्ट्रपति	999,99,16,223	100	-	मेपकम
प्रतिनिधि शेयरधारिता*	7			प्रतिनिधि शेयरधारिता*	7			
	999,99,16,230	100%			999,99,16,230	100%		मेपकम

*इसमें भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधि के रूप में सात शेयरधारक शामिल हैं।

iii. प्रवर्तक की शेयरधारिता में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01.04.2025 की स्थिति में)				वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31.03.2026 की स्थिति में)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	वृद्धि	तारीख	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में प्रतिशत
वर्ष की शुरुआत में	999,99,16,230	100	-	-	999,99,16,230	100
वर्ष की अंत में	999,99,16,230	100	-	-	999,99,16,230	100

iv. शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता का पैटर्न:

(निदेशकों, प्रवर्तकों तथा जीडीआर एवं एडीआर धारकों को छोड़कर):

शीर्ष 10 में से प्रत्येक शेयरधारक हेतु	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01.04.2025 की स्थिति में)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31.03.2026 की स्थिति में)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में प्रतिशत
वर्ष की शुरुआत में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी का विवरण, वृद्धि/कमी के कारणों सहित (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):	-	-	-	-
वर्ष की अंत में	-	-	-	-

v. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

प्रत्येक निदेशक तथा प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01.04.2025 की स्थिति में)		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (31.03.2026 की स्थिति में)	
	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों में प्रतिशत
वर्ष की शुरुआत में	-	-	-	-
वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तिथि–वार वृद्धि/कमी का विवरण, वृद्धि/कमी के कारणों सहित (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि):	-	-	-	-
वर्ष की अंत में	-	-	-	-

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता, जिसमें देय न हुई परंतु संचित/उपार्जित ब्याज राशि भी शामिल है।

(₹ लाख में)

	जमा राशि को छोड़कर प्रतिभूतिकृत ऋण	अप्रतिभूतिकृत ऋण	जमाएं*/सावधि ऋण	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता (01.04.2025)				
i) मूलधन राशि	11,39,336.50	33,89,874.69	17,83,248.07	63,12,459.26
ii) ब्याज देय लेकिन अप्रदत्त	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन अदेय	31,562.79	83,684.11	-	1,15,246.90
कुल (i+ ii+ iii)	11,70,899.29	34,73,558.80	17,83,248.07	64,27,706.16
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				-
*परिवर्धन	95,446.00	9,92,795.25	8,70,868.69	19,59,109.95
*अपचयन	95,979.31	3,51,125.97	1,21,272.06	5,68,377.34
निवल परिवर्तन	533.31	6,41,669.28	7,49,596.64	13,90,732.61

	जमा राशि को छोड़कर प्रतिभूतिकृत ऋण	अप्रतिभूतिकृत ऋण	जमाएं* / सावधि ऋण	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता (31.03.2026)				-
i) मूलधन राशि	11,38,545.40	40,16,548.99	25,32,844.71	76,87,939.10
ii) ब्याज देय लेकिन अप्रदत्त	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन अदेय	31,820.58	98,679.09	-	1,30,499.67
कुल (i+ ii+ iii)	**11,70,365.98**	**41,15,228.08**	**25,32,844.71**	**78,18,438.77**

*इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), एक एनबीएफसी होने के कारण, सार्वजनिक जमाएँ स्वीकार करने के लिए पात्र नहीं है

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा/अथवा प्रबंधक को पारिश्रमिक:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबंधक का नाम			कुल राशि
	नाम	**श्री रोहित ऋषि, 04 फरवरी 2026 से**	**श्री पी.आर. जयशंकर, 28 मई 2025 तक**	**श्री पलाश श्रीवास्तव**	**-**
	पदनाम	**प्रबंध निदेशक**	**प्रबंध निदेशक**	**उप प्रबंध निदेशक**	**-**
1	सकल वेतन	7.19	9.83	53.55	70.57
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलाभों का मूल्य				
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ				
2	स्टॉक विकल्प	-		-	-
3	स्वेट इक्विटी	-		-	-
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, विवरण दें	-		-	-
5	अन्य (कृपया विवरण दें)	-		-	-
	योग (क)	**7.19**	**9.83**	**53.55**	**70.57**

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक	**श्री समीर जेरामभाई बोघारा**	
	बोर्ड/समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	13.60	13.60
	कमीशन	-	-
	अन्य (कृपया विवरण दें)	-	-
	योग (1)	-	-
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक **(अंशकालिक, गैर–सरकारी निदेशक)**		
	बोर्ड / समिति बैठकों में भाग लेने हेतु शुल्क	-	-
	कमीशन	-	-
	अन्य (कृपया विवरण दें) – यात्रा भत्ता	-	-
	योग (2)	-	-
	योग (ख)=(1+2)	**13.60**	**13.60**

निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
	नाम	श्री राजीव मुखीजा	सुश्री रुचि सिंघल	कुल
	पदनाम	मुख्य वित्तीय अधिकारी	महाप्रबंधक–कंपनी सचिव	
1	वित्त वर्ष 2025–26 के लिए कुल सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के अंतर्गत वेतन	84.37	60.69	**145.06**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलाभों का मूल्य			
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-		-
2	स्टॉक विकल्प	-		-
3	स्वेट इक्विटी	-		-
4	कमीशन	-		-
	लाभ के प्रतिशत के रूप में	-		-
	अन्य, विवरण दें	-		-
5	अन्य (कृपया विवरण दें)	-		-
	योग	**84.37**	**60.69**	**145.06**

VII. जुर्माने / दंड/अपराधों का समाधानः

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माने / दंड / अपराधों का समाधान का शुल्क विवरण	प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी / न्यायालय]	यदि कोई अपील दायर की गई हो, तो उसका विवरण (यदि लागू हो)
क. कंपनी					
जुर्माना					
अर्थदंड					
समझौता					
ख. निदेशक					
जुर्माना					
अर्थदंड			**शून्य**		
समझौता					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
जुर्माना					
अर्थदंड					
समझौता					

[अनुलग्नक–III]

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियाँ

1. कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरण

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल), भारत सरकार का एक उपक्रम, अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत समाज एवं विशेषकर देश के अविकसित क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आईआईएफसीएल की एक कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सीएसआर गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु द्वि–स्तरीय संरचना (बोर्ड स्तरीय समिति तथा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त कार्यान्वयन समिति) निर्धारित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आईआईएफसीएल ने ₹ 40.54 करोड़ के अपने सांविधिक सीएसआर दायित्व को पूरा करते हुए ₹ 41.38 करोड़ मूल्य की 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी। वित्तीय वर्ष 2025–26 के पोर्टफोलियो में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सुदृढ़ करना, डिजिटल शिक्षा में परिवर्तन, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरणीय स्थिरता और विरासत संरक्षण शामिल हैं– ये सभी पहलें मिलकर आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों और देश के दूरस्थ क्षेत्रों में कमजोर समुदायों के सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण कमियों को दूर करती हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

नाम	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान भाग ली गई बैठकों की संख्या
श्री आशुतोष चौधरी (1)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक (समिति के अध्यक्ष)	0	0
श्री रोहित ऋषि (2)	प्रबंध निदेशक	1	1
श्री पलाश श्रीवास्तव	उप प्रबंध निदेशक	4	4
सुश्री लया मद्दुरी (3)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	0	0
श्री चौ. पार्थ सारथी रेड्डी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	4	2
श्री समीर जेरामभाई बोघारा (4)	स्वतंत्र निदेशक	4	4
श्री बलदेव पुरुषार्थ (5)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	0
श्री सोलोमन अरोकियाराज (6)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	1	1
श्री पी.आर. जयशंकर (7)	प्रबंध निदेशक	0	0
श्री आलोक तिवारी (8)	सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	1
श्री संजय रूद्र (9)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा नामित निदेशक	0	0

टिप्पणियां:

1. 28.07.2026 से सदस्य, समिति के अध्यक्ष और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
2. 04.02.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
3. 19.06.2026 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया
4. 09.05.2026 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
5. 21.07.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 27.11.2025 से कार्यमुक्त हो गए
6. 21.07.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए

7. 28.05.2025 से सदस्य और निदेशक के पद से कार्यमुक्त हो गए
8. 04.12.2025 से सदस्य और निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया और 19.06.2026 से कार्यमुक्त हो गए
9. 29.05.2026 से सदस्य और समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और 30.06.2026 से कार्यमुक्त हो गए

3. आप कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ देख सकते हैं:

वेबलिंक:- https://www.iifcl.in/csr-initiative

4. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसार सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण (यदि लागू हो) (रिपोर्ट संलग्न करें)।.

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित आईआईएफसीएल की सीएसआर नीति के अनुसार, प्रभाव आकलन आईआईएफसीएल की सीएसआर परियोजना क्रियान्वयन एवं निगरानी दिशानिर्देशों का एक अभिन्न अंग है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान कोई भी परियोजना प्रभाव मूल्यांकन के लिए पात्र नहीं थी।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसार सेट–ऑफ हेतु उपलब्ध राशि का विवरण तथा वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक समायोजन राशि (यदि कोई हो):

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से सेट–ऑफ हेतु उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ हेतु आवश्यक राशि (यदि कोई हो) (₹ में)
शून्य			

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

सभी आंकड़े – लाख में

विवरण	राशि
वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए निवल लाभ	1,27,764.72
वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए निवल लाभ	2,02,851.13
वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निवल लाभ	2,77,552.92
पिछले तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ	2,02,722.92
वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय की राशि: औसत लाभ का 2%	4054.46

7. (क) कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत, धारा 135(5) के अनुसार: ₹ 4054.46 लाख

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख–7ग): ₹ 4054.46 लाख

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अथवा अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई कुल राशि (₹ में)		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी भी कोष में स्थानांतरित की गई राशि (₹ में)		
राशि	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
12,36,51,762	28,17,94,248	30.04.2026	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना की अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम कृ क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
01	चांगलांग में 4 स्वास्थ्य उप–केंद्र भवनों का निर्माण	स्वास्थ्य	नहीं	चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश		365 दिन	7,52,00,000	6,76,80,000	75,20,000	नहीं	जिला प्रशासन, चांगलांग। कोई सीएसआर पंजीकरण संख्या नहीं।	
02	10 स्मार्ट कक्षाओं (ई–पाठशाला) की स्थापना	शिक्षा	नहीं	गुना, मध्य प्रदेश		180 दिन	71,67,120	43,00,272	28,66,848	नहीं	मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद। कोई सीएसआर पंजीकरण संख्या नहीं।	
03	हाथोड़ी बावड़ी (बावड़ी) का पुनरुद्धार और विकास	विरासत	नहीं	भरतपुर, राजस्थान		360 दिन	3,30,00,000	99,00,000	2,31,00,000	नहीं	समृद्ध ग्राम्य अभियान सोसायटी	CSR00082807
04	ओडिशा के मयूरभंज जिले के कुसुमी ब्लॉक के हटबद्रा में नशामुक्ति और महिला सशक्तीकरण केंद्र का निर्माण	महिला सशक्तिकरण	नहीं	मयूरभंज, ओडिशा		330 दिन	2,50,00,000	1,25,00,000	1,25,00,000	नहीं	जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट, मयूरभंज।	
05	डिजिटल संविधान घरों (डीएसजी) की स्थापना	शिक्षा	नहीं	धौलपुर, राजस्थान		330 दिन	4,18,16,502	2,92,71,490	1,25,45,012	नहीं	जिला परिषद, धौलपुर	
06	आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अंतर्गत बिहार के दरभंगा जिले के बिशोल ब्लॉक के फरसी गांव में स्थित सती पोखर में घाट का निर्माण, सौंदर्यीकरण और अन्य संबंधित कार्य	विरासत	नहीं	दरभंगा, बिहार		330 दिन	2,49,58,300	शून्य	2,49,58,300	नहीं	जिला प्रशासन, दरभंगा, बिहार	
07	हरियाणा के हांसी जिले में इलेक्ट्रिक मोबाइल मेडिकल यूनिट (ईएण्डएमएमयू) की तैनाती हेतु सीएसआर सहायता का प्रस्ताव	स्वास्थ्य	नहीं	हांसी, हरियाणा		180 दिन	3,71,50,400	शून्य	3,71,50,400	नहीं	निटकॉन सोशल फाउंडेशन	CSR00017035
08	क्षेत्रीय कैंसर केंद्र में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी को सुदृढ़ करना – सीएनसीआई में वेसल सीलिंग उपकरणों की तैनाती" के लिए सीएसआर सहायता हेतु प्रस्ताव	स्वास्थ्य	नहीं	कोलकाता, पश्चिम बंगाल		180 दिन	3,71,50,400	शून्य	3,71,50,400	नहीं	जिला प्रशासन, हांसी। कोई सीएसआर पंजीकरण संख्या उपलब्ध नहीं है।	
09	आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अंतर्गत "360" सड़क कवच – सड़क सुरक्षा कार्यक्रम" के कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव	सड़क सुरक्षा	नहीं	मदुरै, तमिलनाडु		15 महीने	2,93,00,000	शून्य	2,93,00,000	नहीं	क्यूब फाउंडेशन	CSR00006801

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना की अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम कृ क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
10	आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अंतर्गत दिल्ली में लोधी रोड रेलवे स्टेशन के पास, लोदी कॉलोनी पार्क में "भारत वन" के विकास हेतु प्रस्ताव	वृक्षारोपण	हाँ	लोधी कॉलोनी, नई दिल्ली		180 दिन	46,50,000	शून्य	46,50,000	नहीं	एनवायरो क्रिएटर फाउंडेशन	CSR00003641
11	आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अंतर्गत राजस्थान और गुजरात के सरकारी विद्यालयों में विद्यालय शैक्षिक सहायता कार्यक्रम के चरण–I के कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव	शिक्षा	नहीं	कच्छ गुजरातय बाडमेर राजस्थान		180 दिन	99,00,000	शून्य	99,00,000	नहीं	सेवा इंटरनेशनल	CSR00000559
12	आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अंतर्गत तमिलनाडु में ईशा विद्या ग्रामीण विद्यालयों में अवसंरचना सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव	शिक्षा	नहीं	तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र		180 दिन	51,00,000	शून्य	20,92,451	नहीं	ईश विद्या फाउंडेशन	CSR00002614
13	गुजरात के भरूच जिले के नेतरंग में "आवासीय उत्कृष्टता विद्यालय" परियोजना के अंतर्गत छात्रावास भवन के निर्माण हेतु सीएसआर सहायता के लिए प्रस्ताव	शिक्षा	नहीं	भरूच, गुजरात		210 दिन	95,00,000	शून्य	95,00,000	नहीं	विद्या भारती वनवासी शिक्षा	CSR00020119
14	लक्ष्मी नगर, दिल्ली में सौर ऊर्जा चालित केंद्रीकृत मेगा रसोई की स्थापना हेतु प्रस्ताव	पोषण	हाँ	लक्ष्मी नगर, दिल्ली		150 दिन	96,01,212	शून्य	96,01,212	नहीं	प्रगति प्रयास फाउंडेशन	CSR00100959
15	आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में "स्वपूर्ण– सामाजिक–भावनात्मक अधिगम और करियर जागरूकता कार्यक्रम" (चरण–I) के कार्यान्वयन हेतु प्रस्ताव	शिक्षा	नहीं	पूरे उत्तर प्रदेश में		24 महीने	54,53,250	शून्य	54,53,250	नहीं	मेधा लर्निंग फाउंडेशन	CSR00004590
16	महाराजगंज (उत्तर प्रदेश) के चिन्हित गांवों में उच्च क्षमता वाली प्रकाश व्यवस्था की स्थापना	ग्रामीण विकास	नहीं	महाराजगंज, उत्तर प्रदेश		365 दिन	2,72,58,472	शून्य	2,72,58,472	नहीं	जिला प्रशासन, महाराजगंज। कोई सीएसआर पंजीकरण संख्या नहीं।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना की अवधि	परियोजना हेतु आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम कृ क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
17	जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्र के सरकारी महाविद्यालय के लिए 100 स्मार्ट बोर्ड उपलब्ध कराना	शिक्षा	नहीं	पूरे जम्मू और कश्मीर में		––	3,00,00,000	शून्य	3,00,00,000	नहीं	जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा विभाग। कोई सीएसआर पंजीकरण संख्या नहीं।	
	कुल						**40,84,53,559**	**12,36,51,762**	**28,17,94,248**			

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य परियोजनाओं के लिए व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरणः

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना स्थल		परियोजना हेतु व्यय की गई राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम – क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
शून्य									

(घ) प्रशासनिक व्यय पर व्यय की गई राशिः शून्य

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि (यदि लागू हो): शून्य

(च) वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय की गई राशि (8घ+8ङ+8च+8छ): – ₹ **12,36,51,762**

(छ) सेट–ऑफ हेतु अधिशेष राशि, यदि कोई होः शून्य

क्र. सं.	विवरण	राशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	₹ 40,54,46,000
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय की गई राशि	₹ 40,84,53,559
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अधिशेष राशि [(ii) – (i)]	₹ 30,07,559
(iv)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट–ऑफ हेतु उपलब्ध राशि [(iii) – (iv)]	शून्य

9. (क) पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरणः

क्र.सं	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित की गई राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार, यदि कोई हो, अनुसूची VII में निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित की गई राशि			आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	अंतरण की तारीख	
1.	वित्तीय वर्ष 2022–23	₹ 3,90,45,000	₹ 80,67,806	स्वच्छ भारत कोष	87,46,340	30.09.2026 से पूर्व अंतरित की जानी है।	शून्य
2.	वित्तीय वर्ष 2023–24	₹ 14,03,87,000	₹ 55,36,833	-	-	-	2,91,33,841
3.	वित्तीय वर्ष 2024–25	₹ 24,72,92,050	₹ 8,41,88,670	-	-	-	13,61,99,989
4.	**कुल**		**₹ 9,77,93,309**	**-**	**87,46,340**	**-**	**16,53,33,830**

(ख) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र.सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना प्रारंभ की गई	परियोजना अवधि	परियोजना हेतु कुल आवंटित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजना पर व्यय की गई राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत तक परियोजना पर व्यय की गई संचयी राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति–पूर्ण / प्रगतिरत
1	-	लखीमपुर और सीतापुर के पिछड़े गांवों में सौर ऊर्जा आधारित आरओ जल संयंत्र की स्थापना	2022-23	150 दिन	22,40,000	15,68,000	22,40,000	पूर्ण
2	-	रामदेवरा (राजस्थान) के ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	2022-23	180 दिन	78,18,690	63,00,000	90,00,000	पूर्ण
3	-	छाबड़ा गांव, देहरादून में पशु आश्रय स्थल पर सौर ऊर्जा आधारित छत की स्थापना	2022-23	180 दिन	19,98,060	1,99,806	19,98,060	पूर्ण
4	-	दिल्ली एनसीआर के चिन्हित विद्यालयों में स्थित 1000 (एक हजार) लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण शिविर	2023-24	110 दिन	93,50,000	18,70,000	93,50,000	पूर्ण
5	-	नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री अकादमी, सिलवासा (दादरा एवं नगर हवेली) में छात्रावास भवन का निर्माण	2023-24	180 दिन	1,22,22,777	36,66,833	1,10,00,499	प्रगतिरत
6	-	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय, डोकटी, बलिया, उत्तर प्रदेश (उ.प्र.) का नवीनीकरण एवं पुनर्विकास	2024-25	180 दिन	1,35,82,984	40,74,895	81,49,790	प्रगतिरत
7	-	कंप्यूटर और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराकर बौद्ध, ओडिशा के सरकारी विद्यालय में अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण	2024-25	90 दिन	48,60,000	29,16,000	29,16,000	प्रगतिरत
8	-	यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता (छात्रवृत्ति योजना)	2024-25	365 दिन	98,32,350	39,32,940	39,32,940	प्रगतिरत
9	-	नागारकुर्नूल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के छात्रों को क्यूआर कोड युक्त एनिमेटेड अवधारणा पुस्तकों का वितरण	2024-25	365 दिन	78,50,500	62,80,400	62,80,400	प्रगतिरत
10	-	सरस्वती विद्या मंदिर, केशव विद्यापीठ, मंडुवाला में चारदीवारी का निर्माण	2024-25	180 दिन	1,59,05,417	95,43,250	95,43,250	प्रगतिरत
11	-	सरकारी प्राथमिक विद्यालय नयांग में विद्यालय भवन का निर्माण	2024-25	180 दिन	2,25,00,000	2,25,00,000	0	पूर्ण
12	-	आकांक्षी जिला गढ़चिरौली के अंतर्गत 26 नए आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण	2024-25	360 दिन	4,97,30,772	99,46,154	99,46,154	प्रगतिरत

10. यदि सीएसआर व्यय के माध्यम से पूंजीगत परिसंपत्ति का सृजन अथवा अधिग्रहण किया गया हो, तो वित्तीय वर्ष के दौरान सृजित/अधिग्रहित परिसंपत्ति का (परिसंपत्ति–वार विवरण) विवरण प्रस्तुत करें।

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) के सृजन अथवा अधिग्रहण की तिथिः शून्य

(ख) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण हेतु व्यय की गई सीएसआर राशिः शून्य

(ग) जिस इकाई अथवा सार्वजनिक प्राधिकरण अथवा लाभार्थी के नाम पर उक्त पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उसका विवरण एवं पता आदिः शून्य

(घ) सृजित अथवा अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्ति(यों) का विवरण (पूर्ण पता एवं स्थान सहित)ः शून्य

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही हो, तो उसके कारणों का उल्लेख करें।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, आईआईएफसीएल द्वारा दीर्घ अवधि वाली नई सीएसआर परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं। आईआईएफसीएल की सीएसआर नीति के अंतर्गत अपेक्षित समुचित जाँच (ड्यू डिलिजेंस) तथा क्रियान्वयन/निगरानी की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए, इन परियोजनाओं को उसी वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना संभव नहीं था। अतः प्रत्येक परियोजना के लिए स्वीकृत राशि को पृथक रूप से चिह्नित करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार समुचित उपयोग हेतु अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित किया गया।

अनुलग्नक–IV

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए रिजर्व से/में अंतरित राशि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	269,357.17	138,724.60
जोड़ें: कर पश्चात लाभ	137,942.17	216,477.44
जोड़ें: कर्मचारी कल्याण आरक्षित से अंतरण	141.38	-
जोड़ें: डिबेंचर विमोचन आरक्षित से अंतरण	105.99	-
घटाएँ: कर्मचारी कल्याण आरक्षित में अंतरण	1,533.07	3,097.17
घटाएँ: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित में अंतरण	42,410.32	39,101.98
घटाएँ: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)	(3.59)	350.31
घटाएँ: आरक्षित निधि में अंतरण, धारा 45–आईसी के अंतर्गत	27,588.43	43,295.49
तुलन पत्र में अग्रेनीत शेष	**336,018.55**	**269,357.17**

कार्यक्रम और गतिविधियाँ



टोक्यो, जापान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ आईआईएफसीएल प्रतिनिधिमंडल की बैठक।



स्मार्ट मीटरिंग अवसंरचना में सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए आईआईएफसीएल और जेमस्टार द्वारा आईएफसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर।



साइबर सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए "साइबर सुरक्षित आईआईएफसीएल" का आयोजन।



'प्रभाव में निवेशरू हितधारकों के साथ संवाद' विषय पर आईआईएफसीएल द्वारा व्यावसायिक हितधारक बैठक 2026 का आयोजन।



किर्गिस्तान में आयोजित एससीओ परिषद की 22वीं बैठक में आईआईएफसीएल की सहभागिता।



नई दिल्ली के लोदी कॉलोनी पार्क में आईआईएफसीएल समर्थित 'भारत वन' मियावाकी वन का उद्घाटन।



सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के दौरान वॉकाथॉन का आयोजन।



राष्ट्र निर्माण का उत्सव मनाने हेतु आईआईएफसीएल द्वारा "निर्माण के सुर" संगीतमय संध्या का आयोजन।



आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अंतर्गत सामुदायिक पुस्तकालय।



कर्मचारियों के बीच समग्र स्वास्थ्य, सजगता और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए आईआईएफसीएल द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन।



एम्स, नई दिल्ली में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट (टीएमजे) शल्य कौशल प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्र।



आईआईएफसीएल की सीएसआर पहल के अंतर्गत सामुदायिक जल अवसंरचना।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर संशोधित)

प्रति,
सदस्यगण
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
नई दिल्ली

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट (संशोधन को * द्वारा चिह्नित किया गया है)

राय

1. हमने **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("कंपनी")** के साथ संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 को समाप्त तुलन–पत्र, लाभ और हानि का विवरण जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल है, उस वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों से संबंधित टिप्पणियां शामिल हैं, जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (दसके बाद "स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित है) भी शामिल है। हमने कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर दिनांक 29.05.2026 की अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी की थी। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अनंतिम टिप्पणियों के अनुसरण में, हम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3) और कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 11 के अंतर्गत मुख्य रिपोर्ट में, अनुलग्नक 'क' की धाराओं (i)(सी), (i)(ई), (iii)(सी), (vii)(ख), (xi)(सी), (xvi)(ख) और (xx), तथा अनुलग्नक 'ख' (निर्देश संख्या II) के अंतर्गत की गई रिपोर्टिंग में संशोधन करके यह संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। यह रिपोर्ट दिनांक 29.05.2026 की पिछली लेखापरीक्षक रिपोर्ट का स्थान लेती है।

   हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को निर्धारित तरीके से प्रदान करते हैं तथा अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक ("इंड एएस"), के साथ पठित यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा समय–समय पर जारी किए गए प्रासंगिक परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ("भा.रि.बैंक दिशानिर्देश") तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु उसके लाभ (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह और इक्विटी में हुए परिवर्तनों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

2. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का आगे वर्णन हमारी रिपोर्ट के "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां" खंड में किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का भी पालन करते हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

3. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और इन पर अपनी राय व्यक्त करते समय हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
ऋणों और अग्रिमों का मूल्यह्रास (अपेक्षित ऋण हानि) 31 मार्च, 2026 तक कुल ऋणः ₹81,714.53 करोड़ 31 मार्च, 2026 तक ईसीएल प्रावधानः ₹1,607.29 करोड़ (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 4 का संदर्भ लें)	
अवसंरचना ऋणों के मूल्यह्रास का आकलन भारतीय इंड एएस 109 वित्तीय लिखतों द्वारा निर्धारित अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करके किया जाता है। चूंकि अवसंरचना परियोजनाओं में लंबी परिपक्वता अवधि होती है और वे नियामकीय देरी तथा लागत में बढ़ोतरी के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसलिए मूल्यह्रास का अनुमान लगाने में प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। जटिलता ऋण के चरण निर्धारण मानदंड (ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की पहचान), चूक की संभावना (पीडी), चूक की स्थिति में हानि (एलजीडी), चूक की स्थिति में जोखिम (ईएडी) की गणना करने तथा भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखने वाले व्यापक आर्थिक चरों को शामिल करने में निहित है।	इस क्षेत्र के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं थीं: क. कंपनी की ईसीएल संबंधी अनुमोदित नीतियों को प्राप्त कर उनका अध्ययन किया और वित्तीय लिखतों के मूल्यह्रास के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया तथा यह सुनिश्चित किया कि वे भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) के दिशानिर्देशों और इंड एएस 109 – वित्तीय लिखतों ("इंड एएस 109") के अनुरूप हैं; ख. मूल्यह्रास प्रावधान प्रक्रिया का चरण–दर–चरण निरीक्षण किया तथा प्रमुख इनपुट (जिसमें 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार ऋण बही भी शामिल है) की पूर्णता और सटीकता तथा मूल्यह्रास प्रावधान की गणना, लेखांकन और निगरानी के लिए विचार किए गए अनुमानों पर प्रमुख नियंत्रणों की रूपरेखा का आकलन और उनकी परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। इन नियंत्रणों में, अन्य बातों के साथ, ऋण पोर्टफोलियो के चरण निर्धारण, साथ ही जर्नल प्रविष्टियां करने और प्रकटीकरण तैयार करने संबंधी नियंत्रण शामिल थे; ग. कंपनी द्वारा अपनाई गई मॉडलिंग तकनीकों, जिनमें प्रमुख इनपुट और अनुमान शामिल हैं, की समझ प्राप्त की। चूंकि मॉडलिंग संबंधी अनुमान और मानदंड ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित थे, इसलिए हमने आकलन किया कि क्या ऐतिहासिक अनुभव वर्तमान परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है और पोर्टफोलियो में हाल ही में हुए मूल्यह्रास के मद्देनजर प्रासंगिक था;

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	घ. ऋण पोर्टफोलियो का विभिन्न श्रेणियों और चूक के विभिन्न स्तरों में अनुमान, वर्गीकरण और चरण निर्धारण करने के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों और इनपुट आंकड़ों का आकलन किया तथा चूक की संभावना (पीडी) और चूक की स्थिति में हानि (एलजीडी) दरों के निर्धारण के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया; ङ. पीडी (चूक की संभावना) और एलजीडी (चूक की स्थिति में हानि) दरों के निर्धारण के लिए उपयोग किए गए इनपुट आंकड़ों का नमूना परीक्षण किया और आंकड़ों का मूल लेखा–बही तथा अभिलेखों से मिलान किया; च. कंपनी द्वारा किए गए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) प्रावधान की गणना की अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया; छ. 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार ईसीएल गणना में शामिल ऋणों की पूर्णता का परीक्षण किया, जिसके लिए ऐसे आंकड़ों का ऋण बही रजिस्टर के अनुसार शेष राशियों से मिलान किया गया; ज. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में इंड एएस 109 – 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटीकरणों की उपयुक्तता का आकलन किया; और झ. प्रबंधन एवं अभिशासन हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों से इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किए कि क्या उनका मानना है कि अपेक्षित ऋण हानि की गणना में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण अनुमान उचित हैं।
व्युत्पन्नी लिखतों का मूल्यांकन और हेज लेखांकन 31 मार्च, 2026 तक कुल व्युत्पन्नी आस्तियां: ₹1,746.74 करोड़ 31 मार्च, 2026 तक कुल व्युत्पन्नी देयताएं: शून्य 31 मार्च, 2026 तक नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि: ₹(79.14) करोड़ (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 3 और 19 का संदर्भ लें)	

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
कंपनी विदेशी मुद्रा में उधारी और ब्याज दर संबंधी जोखिमों से उत्पन्न जोखिमों से बचाव के लिए क्रॉस–करेंसी स्वैप, ब्याज दर स्वैप और वायदा विनिमय करार सहित व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों में प्रवेश करती है। व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन और इंड एएस 109 – वित्तीय लिखतों के अंतर्गत हेज लेखांकन का अनुप्रयोग प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय, अनुमान संबंधी अनिश्चितता और विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों के उपयोग से जुड़ा होता है। उचित मूल्य का निर्धारण विभिन्न बाजार में देखे जा सकने वाले इनपुट, जैसे विदेशी मुद्रा दरें, ब्याज दर प्रतिफल वक्र, छूट कारक और प्रतिपक्षी कोटेशनों पर निर्भर करता है तथा कुछ मामलों में भविष्य की बाजार और आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित अनुमानों पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा, हेज लेखांकन के लिए हेज संबंधों का औपचारिक दस्तावेजीकरण, हेज की प्रभावशीलता का निरंतर आकलन तथा नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि और लाभ एवं हानि के विवरण में लाभ और हानि की पहचान से संबंधित जटिल लेखांकन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए: व्युत्पन्नी जोखिमों की तात्विकता, मूल्यांकन पद्धतियों में निहित जटिलता, प्रबंधन द्वारा अपनाए गए महत्वपूर्ण निर्णय एवं मान्यताएँ, बाहरी प्रतिपक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए मूल्यांकनों की संलिप्तता, तथा एकल वित्तीय विवरणों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को।	व्युत्पन्नी लिखतों के मूल्यांकन और हेज लेखांकन के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं थे: क. कंपनी की व्युत्पन्नी लेनदेन, मूल्यांकन पद्धतियों और हेज लेखांकन से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त की तथा यह आकलन किया कि ये लागू इंड एएस 109, इंड एएस 21 और संबंधित नियामकीय दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप थे या नहीं; ख. व्युत्पन्नी संविदाओं और हेज संबंधों के प्राधिकरण, अभिलेखन, मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा का आकलन किया और उनकी परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया; ग. नमूना आधार पर व्युत्पन्नी करारों और अंतर्निहित उधारी संबंधी दस्तावेजों को प्राप्त कर उनका निरीक्षण किया, ताकि यह आकलन किया जा सके कि व्युत्पन्नी लेनदेन का उचित रूप से अभिलेखन किया गया था और वे संविदात्मक दस्तावेजों द्वारा समर्थित थे; घ. प्रबंधन की मूल्यांकन पद्धति की उपयुक्तता का आकलन किया और उचित मूल्यों के निर्धारण में उपयोग किए गए प्रमुख इनपुट तथा अनुमानों, जिनमें विदेशी मुद्रा दरें, प्रतिफल वक्र, छूट दरें और प्रतिपक्षी कोटेशन शामिल हैं, की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया; ङ. प्रबंधन द्वारा नामित हेज संबंधों का आकलन किया कि क्या वे इंड एएस 109 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें औपचारिक हेज दस्तावेजीकरण और हेज की प्रभावशीलता का आकलन शामिल है। संगठन द्वारा नियुक्त प्रेशेवर से प्रमाणपत्र प्राप्त किया। च. नमूना आधार पर व्युत्पन्नी के मूल्यांकन समायोजनों, हेज आरक्षित निधि के लेखांकन तथा लाभ एवं हानि के विवरण में संबंधित लाभ/हानि की पहचान से संबंधित जर्नल प्रविष्टियों और लेखांकन प्रक्रियाओं का परीक्षण किया; छ. व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों, मूल्यांकन तकनीकों, उचित मूल्य श्रेणीक्रम, हेज लेखांकन और संबंधित जोखिमों के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों का आकलन किया कि क्या वे इंड एएस 107 और इंड एएस 109 की लागू प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप थे;

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	ज. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त व्युत्पन्नी जोखिमों और हेज संबंधों की पूर्णता तथा अनुमानों और मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता के संबंध में प्रबंधन और अभिशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किए;

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

4. अन्य जानकारी हेतु कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट जिसमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन और शेयरधारक संबंधी जानकारी में शामिल जानकारी सम्मिलित है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इन रिपोर्टों के इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं। स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है अथवा अन्यथा उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण प्रतीत होता है। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है।

जब ऐसी अन्य जानकारी हमें उपलब्ध कराई जाएगी और हम उसे पढ़ेंगे तथा यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की सूचना अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को देना आवश्यक है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारी

5. कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट इंड एएस, के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों, भा.रि.बैंक दिशानिर्देशों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव, कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पहचान; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय एवं अनुमान करना; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और रखरखाव करना भी शामिल है, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे और ऐसे विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हों।

विवरण तैयार करते समय, निदेशक मंडल कंपनी की कार्यशील संस्था के तौर पर जारी रहने की क्षमता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है, जहां लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने और कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय परिणाम, समग्र रूप से, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और ऐसी लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण गलत विवरण होने पर उसका हमेशा पता चल जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, उनसे इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

   एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते है:

   - स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना और उन्हें निष्पादित करना, तथा ऐसा पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के आधार के लिए पर्याप्त हो। धोखाधड़ी के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चलने का जोखिम, त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।
   - परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं।
   - उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
   - लेखांकन के कार्यशील संस्था के आधार पर निदेशक मंडल के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है अथवा नहीं जिससे संस्थान की एक कार्यशील संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर पर्याप्त संदेह पैदा हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करने या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर सकता है।
   - प्रकटीकरण सहित विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

   महत्वपूर्णता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर विचार करते हैं।

   हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान अभिज्ञात करते हैं, को भी अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित करते है।

   हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और हम उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में उनसे संवाद करते हैं जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में भी संसूचित करते हैं।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित किए गए मामलों में से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो चालू अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन के तहत उस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रतिबंधित न हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित न करें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक हित में होने वाले लाभों की तुलना में अधिक होने की युक्तिसंगत अपेक्षा होगी।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के तहत भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जहां तक लागू हो, अनुलग्नक 'क' में एक विवरण प्रस्तुत करते हैं।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (5) के अनुसार, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने निर्देश और उप–निर्देश जारी किए हैं। हम अनुलग्नक 'ख' में उन पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं।

9. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारी राय में कंपनी द्वारा नियम अनुसार अपेक्षित उचित लेखा–बहियों का रखरखाव किया गया है जहाँ तक उन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।

(ग) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा–बहियों के अनुरूप हैं।

(घ) 'कंपनी का ऐसा कोई शाखा कार्यालय नहीं है, जिसके लेखों की अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (8) के तहत कंपनी के लेखापरीक्षक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षा की जाती हो। अतः, अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3)(ग) के तहत ऐसे किसी शाखा कार्यालय के लेखों के संबंध में रिपोर्ट हमें भेजे जाने और उससे निपटने के तरीके से संबंधित रिपोर्टिंग आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ङ) हमारी राय में उपरोक्त स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के प्रावधान, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या एफ.सं. 1/2/2014–सीएल–ट के मद्देनजर, इस सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(छ) कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, अनुलग्नक 'ग' में हमारी पृथक रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(ज) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) के अनुसार, निदेशक के पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197 कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है; और

(झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया है, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर:

i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लंबित मुकदमों के अपनी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का प्रकटीकरण किया है। वित्तीय विवरणों के नोट्स में बिंदु 49 का संदर्भ लें;

ii) कंपनी ने दीर्घकालिक करारों, जिसमें व्युत्पन्नी करार भी शामिल हैं, पर लागू कानून या लेखांकन मानकों के अनुसार, यदि कोई हो, तो महत्वपूर्ण पूर्वानुमेय हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है। वित्तीय विवरणों के नोट 4 और 16 का संदर्भ लें;

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

iii) कंपनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा निधि में अंतरित की जाने वाली कोई राशि नहीं थी।

iv) क) प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") भी शामिल है, को या उसमें, (चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम या निधियों के किसी अन्य स्रोत या प्रकार से) कोई निधि अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी गई है या निवेश नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रदान करेगा;

ख) प्रबंधन ने अभ्यावेदन दिया है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("निधि प्रदान करने वाले पक्ष") भी शामिल है, से ऐसी कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, निधि प्रदान करने वाले पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रदान करेगी;

ग) परिस्थितियों में हमारे द्वारा उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप–खंड (i) और (ii) के अंतर्गत दिए गए अभ्यावेदनों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है; अतः कंपनी पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

vi) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत लेखापरीक्षा ऑडिट ट्रेल पर रिपोर्टिंग संबंधी कार्यान्वयन मार्गदर्शन (संशोधित 2024 संस्करण) के अनुसार की गई हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, कंपनी ने अपनी लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए अनेक लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिनमें लेखापरीक्षा ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) दर्ज करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन–देन के लिए यह सुविधा पूरे वर्ष संचालित रही है।

इसके अलावा, अपनी लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखापरीक्षा ऑडिट ट्रेल की सुविधा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला और कंपनी ने रिकॉर्डों को बनाए रखने संबंधी सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा ऑडिट ट्रेल को सुरक्षित रखा है।

कृते **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 315104E

हस्ता/–
सीए कमल कु. चंदुका
साझेदार
सदस्यता सं.: 058790
यूडीआईएनः 26058790XJTNDB4589

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 005593ब

हस्ता/–
सीए अमित तिवारी
साझेदार
सदस्यता सं.: 408603
यूडीआईएनः 26408603QFVWUH2163

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.07.2026

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 7 में संदर्भित जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित है।

i) (क) (i) कंपनी ने पूर्ण विवरण, जिसमें मात्रात्मक विवरण भी शामिल हैं, दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे हैं, सिवाय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा पूंजीगत प्रगतिरत कार्य के विवरण के।

(ii) कंपनी ने अमूर्त आस्तियों का पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे हैं।

(ख) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान नियमित सत्यापन कार्यक्रम के अनुसार भौतिक रूप से सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और उसकी आस्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। ऐसे सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

(ग) वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं।

संपत्ति का विवरण	सकल अग्रेषित मूल्य(रु. लाख)	धारित नाम	चाहे वह प्रमोटर, निदेशक, उनके रिश्तेदार या कर्मचारी हों	स्वामित्व अवधि – जहां उपयुक्त हो, सीमा दर्शाएं।	कंपनी के नाम पर स्वामित्व न होने का कारण
5वीं मंजिल ब्लॉक 2 प्लेट ए और बी एनबीसीसी टॉवर ईस्ट किदवई नगर नई दिल्ली – 110023	27,701.73 लाख	एनबीसीसी लिमिटेड के नाम पर है (पट्टाधिकार के आधार पर)	यह प्रमोटर, निदेशक, उनके रिश्तेदार या कर्मचारी के नाम पर नहीं है	लागू नहीं	एनबीसीसी लिमिटेड से पट्टाधिकार के आधार पर धारित; पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है।
डब्ल्यूटीसी, नौरोजी नगर, नई दिल्ली	15711.48 लाख	एनबीसीसी लिमिटेड के नाम पर है (पूर्ण स्वामित्व आधार पर)	यह प्रमोटर, निदेशक, उनके रिश्तेदार या कर्मचारी के नाम पर नहीं है	लागू नहीं	*एनबीसीसी लिमिटेड से पूर्ण स्वामित्व आधार पर अर्जित; हस्तांतरण विलेख का निष्पादन लंबित है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली आस्तियों सहित) या अमूर्त आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) बेनामी लेन–देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी 'बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

ii) (क) कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो मुख्य रूप से वित्तपोषण गतिविधियों में लगी है और इसलिए इसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। अतः, आदेश के खंड 3(ii)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी को चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर ₹5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमाएं स्वीकृत नहीं की गई हैं। अतः, आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

iii क) कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है और इसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है। अतः, आदेश के खंड 3(iii)(क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गारंटी नहीं दी है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और ऋणों और ऋण प्रकृति के अग्रिमों के नियम और शर्तें प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत पंजीकृत एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विभिन्न विनियमों, परिपत्रों और मानदंडों द्वारा विनियमित है जिसमें अग्रिमों से संबंधित आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर मास्टर परिपत्र भी शामिल है। कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में हम सूचित करते हैं कि मूलधन और ब्याज के चुकौती की अनुसूची निर्धारित की गई है और मूलधन और ब्याज की चुकौती/प्राप्ति नियमित है, सिवाय नीचे उल्लिखित कुछ मामलों के।

विवरण	कुल बकाया राशि (मूलधन और ब्याज) (लाख रुपये में)	मामलों की संख्या
1–30 दिन	759,462.45	29*
31–60 दिन	46.89	02*
61–90 दिन	586.17	03*
90 दिनों से अधिक	60,786.11	05**

'ऊपर उल्लिखित मामलों की संख्या ऋण खातों की संख्या को दर्शाती है और जरूरी नहीं परियोजनाओं की संख्या के अनुरूप हो।

'' 5 मामलों में से एक मामले, टीके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, में 31.03.2026 को कोई मूलधन बकाया या अतिदेय ब्याज नहीं है। केवल 58.22 करोड़ रुपये की राशि का एलओसी बकाया है।

घ) कंपनी द्वारा दिए गए उन ऋणों के संबंध में जो तुलनपत्र की तिथि पर 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हैं और उन ऋणों के संबंध में जिन्हें वर्ष के दौरान मान्यता रद्द नहीं की गई है, जैसा कि हमें बताया गया है और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर प्रबंधन ने मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाए हैं:

मामलों की संख्या	बकाया मूल राशि (लाख रुपये में)	बकाया ब्याज (लाख रुपये में)	कुल बकाया (लाख रुपये में)
04	32,557.08	28,229.04	60,786.11

'उपर्युक्त में 4 ऋण खाते शामिल हैं, जिनमें 31.03.2026 को मूलधन और/या ब्याज 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय था। टीके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड के खाते को इसमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि 31.03.2026 को उसके संबंध में कोई मूलधन बकाया या ब्याज अतिदेय नहीं था और केवल 58.22 करोड़ रुपये का साख–पत्र (एलओसी) बकाया था।

ङ) कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और इसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है। इसलिए, कंपनी पर आदेश के खंड 3(iii)(ङ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

च) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के आधार पर और अभिलेखों की जाँच करने पर यह पाया गया कि कंपनी ने ऐसे कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिए हैं जो या तो मांग पर चुकाने योग्य हों या बिना किसी नियम या पुनर्भुगतान अवधि निर्दिष्ट किए दिए गए हों। अतः, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(iii)(च) के अंतर्गत रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के उल्लंघन में कंपनी पर लागू सीमा तक कोई ऋण नहीं दिया है और कोई गारंटी नहीं दी है या कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

इसके अतिरिक्त, हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते कंपनी ऋण और गारंटी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 और संबंधित नियमों से छूट प्राप्त है। निवेश के संबंध में कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(1) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

v) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अर्थ में कोई जमा या जमा मानी जाने वाली कोई राशि स्वीकार नहीं की है। अतः, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

vi) केंद्र सरकार ने कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेखों के रखरखाव का प्रावधान निर्धारित नहीं किया है। अतः, आदेश के खंड 3(vi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

vii) (क) कंपनी विवादरहित सांविधिक देयताओं, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उपकर और अन्य सांविधिक देयताएं शामिल हैं, को संबंधित प्राधिकारियों के पास सामान्यतः नियमित रूप से जमा करती है। देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी विवादरहित देय राशि बकाया नहीं थी। आयकर और वस्तु एवं सेवा कर के लिए अपेक्षित सांविधिक देयताओं, समाधान और प्रमाण–पत्र।

(ख) विवादों के कारण जमा नहीं की गई वैधानिक देयताओं का विवरण निम्नलिखित है:

कानून का नाम	बकाए की प्रकृति	राशि (₹ लाख) मांग की गई राशि	अवधि	फोरम जहां मामला लंबित है
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	*7656.32	निर्धारण वर्ष 2024–25	सीआईटी(ए) के पास अपील लंबित
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	0.42	निर्धारण वर्ष 2020–21	आयकर विवरणी में सुधार किया गया और सीपीसी की सूचना प्राप्त हुई, मांग ₹51 करोड़ से घट गई।
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	51.65	निर्धारण वर्ष 2017–18	आईटीएटी के पास आदेश सुरक्षित रखा गया
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	*632.66 174.58	निर्धारण वर्ष 2016–17	आईटीएटी से आदेश प्राप्त हुआ– *632.66 लाख रुपये धारा 143(3) के तहत आदेश प्राप्त हुआ– 174.57 लाख रुपये *उपर्युक्त राशि में से, कंपनी ने उसके विरुद्ध ₹1,37,00,000 जमा किए हैं।
जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	*0.91	वित्तीय वर्ष 2017–18	एओ के पास लंबित
जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	270.78	वित्तीय वर्ष 2018–19	अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित
जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	872.45	वित्तीय वर्ष 2019–20	अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित
जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	104.35	वित्तीय वर्ष 2020–21	अपीलीय प्राधिकारी के पास लंबित
जीएसटी अधिनियम	जीएसटी	0.75	वित्तीय वर्ष 2022–23	दंड की सूचना जारी की गई
सेवा कर	सेवा कर	64.72	2015–16 (द्वितीय छमाही) से 2017–18 (अप्रैल–जून) तक	सीईएसटीएटी के पास अपील

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

viii) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान ऐसी पूर्व में अभिलिखित न की गई आय से संबंधित कोई लेन–देन नहीं था, जिसे अभ्यर्पित किया गया हो या आय के रूप में प्रकट किया गया हो।

ix) (क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या उधारी की चुकौती या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकारी प्राधिकारी द्वारा कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) सावधि ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ) अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई निधियों का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) कंपनी ने सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनियों या संयुक्त उद्यमों की देयताओं को पूरा करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति से कोई निधि नहीं ली है।

(च) कंपनी ने वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

ग) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे का सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से धनराशि नहीं जुटाई है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या पूर्णतः/आंशिक रूप से/वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी नियोजन नहीं किया है।

xi) (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी धोखाधड़ी या कंपनी पर किसी महत्वपूर्ण धोखाधड़ी का पता नहीं चला है और न ही इसकी सूचना दी गई है।

(ख) हमारे द्वारा या किसी अन्य लेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 143(12) के तहत प्ररूप एडीटी–4 में कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।

(ग) 'वर्ष 2025–26 के दौरान कंपनी को कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करते समय हमारे द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसी कोई शिकायत नहीं थी।

xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः, आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xiii) हमारी राय में, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन, जहां लागू हो, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार अपेक्षित रूप से वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

xiv) (क) कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान जारी की गई आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

xv) कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेन–देन नहीं किया है और इसलिए, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvi) (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है और उसने अपेक्षित पंजीकरण प्राप्त कर लिया है।

(ख) कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां नहीं की हैं। कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार किया है।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित मुख्य निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(घ) समूह में समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक मुख्य निवेश कंपनी (सीआईसी) हैं/नहीं हैं।

xvii) कंपनी ने हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाले वित्तीय वर्ष और ठीक उससे पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं उठाई है।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं हुआ है।

xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय आस्तियों की आयु और उनके वसूली की अपेक्षित तिथियों तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल तथा प्रबंधन की योजनाओं के संबंध में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख को कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी एक वर्ष की अवधि के भीतर, जब वे देय हों, तब तुलन–पत्र की तारीख को विद्यमान अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है।

xx) (क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं के मामले में, अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरित की जाने वाली अपेक्षित राशियों के संबंध में, ऐसी कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है। 'हालांकि, कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि में पड़ी ₹122.45 लाख की शेष राशि (नोट 19 का संदर्भ लें) 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से संबंधित है और सीएसआर अधिनियम के अनुसार 31.03.2026 तक इसका उपयोग किया जाना लंबित है।

(ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में, कंपनी ने अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (6) के अनुपालन में अप्रयुक्त सीएसआर राशि को एक विशेष खाते में अंतरित कर दिया है।

xxi) यह खंड केवल समेकित वित्तीय विवरणों के मामले में लागू होता है। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की सीएआरओ रिपोर्टों में संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा की गई योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां।

कृते **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 315104E

हस्ता/–
सीए कमल कु. चंदुका
साझेदार
सदस्यता सं.: 058790
यूडीआईएनः 26058790XJTNDB4589

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 005593ब

हस्ता/–
सीए अमित तिवारी
साझेदार
सदस्यता सं.: 408603
यूडीआईएनः 26408603QFVWUH2163

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.07.2026

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

स्वतंत्र लेखापरीक्षा की रिपोर्ट का अनुलग्नक –ख

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 8 में संदर्भित जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित है।

क्र. सं.	निर्देश / जाँच किए गए क्षेत्र	संविधिक लेखापरीक्षकों के प्रत्युत्तर / टिप्पणियां	स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
I	कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पश्चात लाभों के लिए कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या न्यासों के माध्यम से किए गए सभी निवेशों, चाहे वे सूचीबद्ध हों या असूचीबद्ध, के उचित मूल्यांकन का आकलन करें। इसमें मूल्यांकन पद्धतियों का सत्यापन करना, इंड एएस के साथ संगति सुनिश्चित करना और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करना शामिल है। लेखापरीक्षक मूल्यांकन के दृष्टिकोण, उसकी युक्तिसंगतता और लागू विनियमों के अनुपालन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी प्रदान करेगा तथा किसी भी महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण की रिपोर्ट करेगा।	कंपनी के सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी लाभों के लिए किए गए निवेश मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और कर्मचारी उपदान निधि तथा अवकाश नकदीकरण योजनाओं के अंतर्गत अन्य अनुमोदित निधि प्रबंधकों के माध्यम से धारित रखे गए हैं। अपनाई गई मूल्यांकन पद्धतियां इंड एएस 19 (कर्मचारी लाभ), इंड एएस 109 (वित्तीय लिखत) और इंड एएस 113 (उचित मूल्य मापन) के अनुरूप हैं। परिभाषित लाभ दायित्वों का बीमांकिक मूल्यांकन इंड एएस 19 के अनुसार एक स्वतंत्र योग्य बीमांकिक द्वारा पूर्वानुमानित इकाई ऋण पद्धति का उपयोग करके किया गया है। एलआईसी से प्राप्त निधि विवरण, बीमांकिक रिपोर्ट और निवेश अनुसूचियों सहित सहायक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया है। समीक्षा की गई मूल्यांकन पद्धति या सहायक दस्तावेजों में कोई महत्वपूर्ण विचलन या गलत विवरण नहीं पाया गया है।	स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।
II	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन की प्रक्रिया करने के लिए कोई प्रणाली मौजूद है? यदि हाँ, तो क्या इस प्रणाली और कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों तथा साइबर सुरक्षा की समीक्षा, सर्ट–इन द्वारा सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा संगठनों द्वारा कम से कम वर्ष में एक बार की गई है और पाई गई महत्वपूर्ण विसंगतियों, यदि कोई हों, की उचित रूप से रिपोर्ट की गई है? आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देन की प्रक्रिया करने से लेखों की सत्यनिष्ठा पर	कंपनी के पास अपनी आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन–देन की प्रक्रिया करने के लिए एक प्रणाली मौजूद है, जिसमें लेन–देन एसएपी – उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) सॉफ्टवेयर में दर्ज किए जाते हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान, हमने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं अभी भी मैन्युअल हस्तक्षेप के माध्यम से संचालित की जाती हैं और पूरी तरह से प्रणाली–आधारित स्वचालन द्वारा समर्थित नहीं हैं। इनमें शामिल हैं: • अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की पहचान और वर्गीकरण; • प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं की गणना; • प्रणाली द्वारा तैयार अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) की गणना; और • प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) और नियामकीय विवरणियों की तैयारी।	स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

क्र. सं.	निर्देश / जाँच किए गए क्षेत्र	संविधिक लेखापरीक्षकों के प्रत्युत्तर / टिप्पणियां	स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
	पड़ने वाले प्रभाव के साथ–साथ उसके वित्तीय प्रभाव की भी रिपोर्ट की जा सकती है।	उपर्युक्त प्रक्रियाओं में पर्याप्त प्रणाली–आधारित नियंत्रणों और स्वचालन के अभाव में, मैन्युअल त्रुटियों, विलंब और नियंत्रण संबंधी कमियों का जोखिम अपेक्षाकृत अधिक है और परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में लेखापरीक्षा के दौरान अधिक ध्यान देने और अतिरिक्त मूलभूत लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं अपनाने की आवश्यकता थी। *इसके अतिरिक्त, उक्त आईटी प्रणाली तथा कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण नियंत्रणों और साइबर सुरक्षा की समीक्षा, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सर्ट–इन) के साथ सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा संगठन द्वारा की गई है। उक्त समीक्षा वर्ष के दौरान की गई थी और इस प्रकार वर्ष में कम से कम एक बार की निर्धारित न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता पूरी होती है। उक्त समीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली ऐसी कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई, जिसकी रिपोर्ट किया जाना आवश्यक था; पाई गई विसंगतियां प्रक्रियात्मक प्रकृति की थीं और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबंधन के समक्ष उचित रूप से रखी गई हैं।	
III	क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का लागू लेखांकन मानकों या मानदंडों के अनुसार उचित रूप से लेखांकन किया गया है और क्या प्राप्त निधियों का उपयोग उनके नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया है? क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन अनुदान के नियमों और शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों की सूची दें।	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) भारत सरकार का एक उद्यम है, जो गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–अवसंरचना ऋण निधि (एनबीएफसी–आईडीएफ) के रूप में कार्य करता है और मुख्य रूप से अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के कार्य में शामिल है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाले वर्ष के दौरान, कंपनी को केंद्र/राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए निर्धारित कोई अनुदान या सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई, जिसके लिए लागू लेखांकन मानकों के तहत अलग से लेखांकन करना आवश्यक हो। तदनुसार, निधियों के उपयोग में विचलन या ऐसे अनुदानों पर अर्जित ब्याज के लेखांकन का प्रश्न ही नहीं उठता। वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए यह निर्देश कंपनी पर लागू नहीं है।	लागू नहीं। स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

क्र. सं.	निर्देश / जाँच किए गए क्षेत्र	संविधिक लेखापरीक्षकों के प्रत्युत्तर / टिप्पणियां	स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
IV	क्या कंपनी ने प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की है? यदि हाँ, तो क्या कंपनी ने इन जोखिमों को कम करने के लिए कोई जोखिम प्रबंधन नीति बनाई है? यदि हाँ, (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? (ख) क्या कंपनी ने अपनी डेटा आस्तियों की पहचान की है और क्या उनका उचित रूप से मूल्यांकन किया गया है?	कंपनी ने निम्नलिखित प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की है: (i) क्रेडिट जोखिम – अवसंरचना ऋण पोर्टफोलियो में उधारकर्ता द्वारा चूक या आस्ति गुणवत्ता में गिरावट का जोखिम; (ii) बाजार जोखिम – जिसमें ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और चलनिधि जोखिम शामिल हैं; (iii) परिचालन संबंधी जोखिम – अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, प्रणालियों और कार्मिकों से उत्पन्न होने वाला जोखिम; (iv) ब्याज दर जोखिम – उद्योग में ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम। (v) नियामकीय और अनुपालन संबंधी जोखिम – भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के विनियमों और अन्य लागू कानूनों का अनुपालन न करने का जोखिम। **जोखिम प्रबंधन नीतिः** कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसकी समय–समय पर समीक्षा की जाती है। इस नीति में विभिन्न जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी और शमन शामिल हैं। (क) वैश्विक सर्वोत्तम कार्यपद्धतियां: जोखिम प्रबंधन नीति वैश्विक सर्वोत्तम कार्यपद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू बेसल तृतीय ढांचे के दिशानिर्देश, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश और वित्तीय क्षेत्र आकलन समिति की सिफारिशें शामिल हैं। यह नीति, जहां तक लागू हो, वित्तीय सततता बोर्ड (एफएसबी) और बैंकिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप है। (ख) डेटा आस्तियां: कंपनी ने अपनी प्रमुख डेटा आस्तियों की पहचान की है, जिसमें ऋण पोर्टफोलियो संबंधी डेटा, उधारकर्ताओं की वित्तीय जानकारी, संपार्श्विक संबंधी डेटा, परिचालन संबंधी डेटा और कर्मचारी संबंधी डेटा शामिल हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा के अंतर्गत आने वाले वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा डेटा आस्तियों का औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा मूल्यांकन अनिवार्य करने वाली कोई नियामकीय आवश्यकता लागू नहीं है। कंपनी के पास अपनी डेटा आस्तियों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त आईटी सुरक्षा और डेटा अभिशासन नीतियां हैं।	लागू नहीं। स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

क्र. सं.	निर्देश / जाँच किए गए क्षेत्र	संविधिक लेखापरीक्षकों के प्रत्युत्तर / टिप्पणियां	स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
V	क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा सेबी, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सीईआरटी–इन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अन्य लागू नियमों और विनियमों का, जहां भी लागू हो, अनुपालन कर रही है? यदि नहीं, तो विचलन के मामलों को उजागर किया जा सकता है।	लेखापरीक्षा में की गई प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, लागू विनियमों के साथ कंपनी की अनुपालन स्थिति निम्नलिखित है: **(i) सेबी – एलडीओआर विनियम, 2015 [महत्वपूर्ण गैर–अनुपालन की पहचान]:** आईआईएफसीएल के गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। सेबी (एलडीओआर) विनियम, 2015 के विनियम 33 के साथ पठित विनियम 52 के अंतर्गत, तिमाही अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षकों या पेशेवर सनदी लेखाकार द्वारा की जानी आवश्यक है। **क) मानक का गलत अनुप्रयोग:** (एसआरई) 2410 का गलत अनुप्रयोग: 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही/अवधि के लिए, कंपनी ने एक बाहरी पेशेवर को सीमित समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया, जिसका चयन और नियुक्ति प्रबंधन द्वारा आंतरिक रूप से की गई थी और जो कंपनी का भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नहीं है। उक्त पेशेवर ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी समीक्षा कार्यों पर मानक (एसआरई) 2410 के तहत तैयार की गई सीमित समीक्षा रिपोर्ट जारी की। एसआरई 2410, जिसका शीर्षक 'संस्था के स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा की गई अंतरिम वित्तीय जानकारी की समीक्षा' है, केवल संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षक पर लागू होता है। जो पेशेवर संस्था का सांविधिक लेखापरीक्षक नहीं है, उसे ऐसी समीक्षा एसआरई 2400 के तहत करनी होती है और स्वयं को 'स्वतंत्र पेशेवर' के रूप में वर्णित करना होता है, न कि 'स्वतंत्र लेखापरीक्षक' के रूप में। गैर–सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा एसआरई 2410 का उपयोग लागू पेशेवर मानकों का मूलभूत उल्लंघन है। **ख) हितधारकों के समक्ष भ्रामक प्रस्तुतीकरण:** उक्त पेशेवर द्वारा प्रस्तुत सीमित समीक्षा रिपोर्ट में उन्हें 'स्वतंत्र लेखापरीक्षक' के रूप में दर्शाया गया है, जिससे निदेशक मंडल, लेखापरीक्षा समिति, स्टॉक एक्सचेंजों, निवेशकों और नियामकों के समक्ष यह गलत धारणा उत्पन्न होती है कि समीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी। यह सभी हितधारकों के समक्ष गंभीर महत्वपूर्ण गलत प्रस्तुतीकरण है।	**महत्वपूर्ण गैर–अनुपालन** सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संबंध में एक महत्वपूर्ण विचलन की पहचान की गई है। यह 30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही की सीमित समीक्षा से संबंधित है, जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक के अलावा एक पेशेवर द्वारा गलत मानक (एसआरई 2400 के बजाय एसआरई 2410) का उपयोग करते हुए किया गया था। साथ ही, स्टॉक एक्सचेंजों और नियामकों को प्रस्तुत रिपोर्ट में स्वयं को 'स्वतंत्र लेखापरीक्षक' के रूप में भ्रामक रूप से दर्शाया गया था।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

क्र. सं.	निर्देश / जाँच किए गए क्षेत्र	संविधिक लेखापरीक्षकों के प्रत्युत्तर / टिप्पणियां	स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
		अन्य लागू विनियमों के संबंध में, हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणियां निम्नलिखित हैं: **क) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए):** कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जिसमें सांविधिक विवरणियां दाखिल करना, सांविधिक रजिस्टरों का रखरखाव और अन्य अनुपालन आवश्यकताएं शामिल हैं। **ख) भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक):** भा.रि.बैंक के साथ पंजीकृत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–अवसंरचना ऋण निधि होने के नाते, कंपनी ने आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों और समय–समय पर जारी अन्य दिशानिर्देशों सहित लागू भा.रि.बैंक विनियमों का सामान्यतः अनुपालन किया है। **ग) सीईआरटी–इन / इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय:** कंपनी ने लागू सीईआरटी–इन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में सूचना सुरक्षा नीतियां और आईटी अभिशासन तंत्र स्थापित किए हैं, जिसमें साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताएं भी शामिल हैं।	

कृते **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 315104E

हस्ता/–
सीए कमल कु. चंदुका
साझेदार
सदस्यता सं.: 058790
यूडीआईएनः 26058790XJTNDB4589

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 005593ɛ

हस्ता/–
सीए अमित तिवारी
साझेदार
सदस्यता सं.: 408603
यूडीआईएनः 26408603QFVWUH2163

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.07.2026

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि के स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 (एफ) में संदर्भित जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों से संबंधित है।

हमने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के साथ–साथ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षा किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का प्रबंधन भारतीय लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के सुचारू और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हों। इनमें कंपनी की नीतियों का पालन, उसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, तथा कंपनी अधिनियम 2023 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की ज़िम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी ("मार्गदर्शन टिप्पणी") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है, जहां तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं। ये मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए हो और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हो।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण खामी की संभावना का आकलन करना और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है।

चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी के जोखिमों का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(1) कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान का उचित विवरण, सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करने वाले अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं;

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

(2) यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन–देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिनमें मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों को अनुचित रूप से दरकिनार करने की संभावना शामिल है त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतियाँ हो सकती हैं जिनका पता नहीं चल पाता है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के भविष्य के अवधियों के लिए अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के "राय के आधार" पैराग्राफ में की गई टिप्पणियों के अधीन, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2026 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित हैं।

कृते **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 315104E

हस्ता/–
सीए कमल कु. चंदुका
साझेदार
सदस्यता सं.: 058790
यूडीआईएनः 26058790XJTNDB4589

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 005593ब

हस्ता/–
सीए अमित तिवारी
साझेदार
सदस्यता सं.: 408603
यूडीआईएनः 26408603QFVWUH2163

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.07.2026

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों के अनुसार की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 315104E

हस्ता/–
सीए कमल कु. चंदुका
साझेदार
सदस्यता सं.: 058790
यूडीआईएनः 26058790XJTNDB4589

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 005593ɛ

हस्ता/–
सीए अमित तिवारी
साझेदार
सदस्यता सं.: 408603
यूडीआईएनः 26408603QFVWUH2163

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.07.2026

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की लेखापरीक्षक रिपोर्ट

सेवा में

निदेशक मंडल
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
पांचवीं मंजिल, पार्ट ए और बी, ब्लॉक बी
पूर्वी किदवई नगर,
नई दिल्ली –110023

हम, एबीपी एंड एसोसिएट्स और एडीबी एंड कंपनी ("संयुक्त लेखापरीक्षक"), ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण (जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल है), इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है, जो 'कंपनी अधिनियम, 2013 (यथासंशोधित) ("अधिनियम")' की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं (इसके बाद "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित)।

भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जो कंपनी पर लागू सीमा तक हैं, जैसा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि

1. .कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के के व्यवसाय में लगी हुई है और इसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–1(क) के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीकरण संख्या एन–14.03288 दिनांक 09.09.2013 के माध्यम से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है।
2. कंपनी अपने प्रमुख व्यवसाय मानदंड (वित्तीय आस्ति/आय पैटर्न) के अनुसार 31 मार्च 2025 तक ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्र को जारी रखने की हकदार है।
3. कंपनी मास्टर निदेश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में निर्धारित आवश्यक निवल स्वामित्व वाली निधि संबंधी आवश्यकता को पूरा कर रही है।
4. निदेशक मंडल ने 11 अगस्त 2025 को 31.03.2026 को समाप्त वर्ष के लिए कोई जमा स्वीकार न करने संबंधी संकल्प पारित किया है।
5. कंपनी ने वर्ष 2025–26 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।
6. वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के मान्यता और मापन संबंधी सिद्धांतों के अनुसार, उसके तहत जारी संबंधित नियमों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निदेशों के साथ पढ़े जाने पर, तैयार किए गए हैं।

तदनुसार, कंपनी अपने ऋण परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान और उनके वर्गीकरण के लिए हानि भत्ता की गणना हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पद्धति का पालन कर रही है। वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए किसी तंत्र को अपनाने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के नियामकीय अनुपालन को देखते हुए, कंपनी को मास्टर निदेश, 2016 के अनुसार संदिग्ध और डूबत ऋणों के लिए इंड एएस 109 के तहत हानि का प्रावधान करना आवश्यक है। अतः, कंपनी अपनी नीति के अनुसार आईआरएसीपी मानदंडों और ईसीएल पद्धति के बीच प्रावधान में अंतर के अनुपालन के संबंध में निदेशों का पालन कर रही है।

7. (i) बैंक को प्रस्तुत तिमाही विवरणी, जिसे डीएनबीएस–3 के रूप में जाना जाता है, में प्रकट की गई पूंजी पर्याप्तता अनुपात की सही गणना की गई है और ऐसा अनुपात बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुरूप है।

(ii) कंपनी ने 30 जून 2025, 30 सितंबर 2025, 31 दिसंबर 2025 और 31 मार्च 2026 को समाप्त तिमाहियों के लिए डीएनबीएस–3 में पूंजी निधि, जोखिम परिसंपत्तियों/एक्सपोजर और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का तिमाही विवरणी, अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर, निर्धारित अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया है।

8. कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश में परिभाषित गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसी–एमएफआई) नहीं है।

हस्ताक्षरित प्रति इस रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख के बाद घटित घटनाओं के लिए इस रिपोर्ट को अद्यतन करने का हमारा कोई उत्तरदायित्व नहीं है। साथ ही, यह रिपोर्ट उक्त निदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार केवल कंपनी के संदर्भ के लिए जारी की गई है और इसका उपयोग या वितरण किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना है।

कृते **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 315104E

हस्ता/–
सीए कमल कु. चंदुका
साझेदार
सदस्यता सं.: 058790
यूडीआईएनः 26058790XJTNDB4589

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 005593ɞ

हस्ता/–
सीए अमित तिवारी
साझेदार
सदस्यता सं.: 408603
यूडीआईएनः 26408603QFVWUH2163

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.07.2026

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

31 मार्च 2026 वर्ष के लिए स्टैंडअलोन तुलन पत्र का विवरण

सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2026 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 तक (लेखापरीक्षित)
I	**आस्तियां**			
1	**वित्तीय आस्तियां**			
(क)	नकद और नकद समकक्ष	2A	74,110.35	43,602.48
(ख)	उपरोक्त (क) के अलावा बैंक बैलेंस	2B	5,55,879.13	2,13,932.87
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	3	1,74,673.79	1,35,382.74
(घ)	ऋण	4	80,05,357.02	68,12,481.76
(ङ)	निवेश	5	9,22,127.48	8,39,461.46
(च)	अन्य वित्तीय आस्ति	6	57,753.87	46,750.72
	कुल वित्तीय आस्तियां (1)		**97,89,901.64**	**80,91,612.03**
2	**गैर–वित्तीय आस्ति**			
(क)	चालू कर आस्तियां (निवल)	7	1,056.59	2,921.65
(ख)	आस्थगित कर आस्ति (निवल)	8	15,382.73	17,228.88
(ग)	आस्ति, संयंत्र और उपकरण	9	36,629.69	22,057.28
(घ)	पूंजी कार्य प्रगति पर है	9A	2,217.96	15,333.67
(ङ)	अन्य अमूर्त आस्तियां	10	784.27	975.27
(च)	अन्य गैर–वित्तीय आस्तियां	11	2,103.87	7,085.51
	कुल गैर वित्तीय आस्तियां (2)		**58,175.11**	**65,602.26**
	कुल आस्तियां (1+2)		**98,48,076.75**	**81,57,214.29**
II	**देयताएं और इक्विटी**			
क	**देयताएं**			
1	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	ऋण प्रतिभूतियां	12	33,60,545.40	30,05,336.50
(ख)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	13	45,42,276.10	33,54,748.17
(ग)	अन्य वित्तीय देयताएं	14	1,35,427.19	1,22,969.96
	कुल वित्तीय देयताएं (क–1)		80,38,248.69	64,83,054.63
2	**गैर वित्तीय देयताएं**			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	15	4,905.84	15,725.16
(ख)	प्रावधान	16	4,915.54	4,889.42
(ग)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	17	10,198.05	14,085.16
	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं (क–2)		**20,019.43**	**34,699.74**
	कुल देयताएं (क)		**80,58,268.12**	**65,17,754.37**
ख	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	18	9,99,991.62	9,99,991.62
(ख)	अन्य इक्विटी	19	7,89,816.97	6,39,468.30
	कुल इक्विटी (ख)		**17,89,808.59**	**16,39,459.92**
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख)		**98,48,076.75**	**81,57,214.29**

1 से 28 तक के नोट्स के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी इसी दिनांक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह./–
कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 315104E

ह./–
कृते एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 005593C

ह./–
सीए कमल कुमार चंडूका
भागीदार
सदस्यता संख्या: 058790

ह./–
सीए अमित तिवारी
भागीदार
डीआईएन: 408603

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर स

ह./–
रोहित ऋषि
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 11524681

ह./–
पलाश श्रीवास्तव
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 2007911

ह./–
रुचि सिंघल
(महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: 17837

ह./–
राजीव मुखिजा
(मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

31 मार्च 2026 वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लाभ और हानि का विवरण

सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	समाप्त वर्ष	
			31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
क	**संचालन से राजस्व**			
(क)	ब्याज आय	**20**	6,92,087.63	6,00,757.97
(ख)	शुल्क और कमीशन आय	**21**	5,161.07	5,626.89
(ग)	उचित मूल्य में परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	**22**	(1,007.16)	12,254.58
	संचालन से कुल राजस्व (क)		**6,96,241.54**	**6,18,639.44**
ख	**अन्य आय**	**23**	1,21,857.68	55,785.49
	कुल आय I (क+ख)		**8,18,099.22**	**6,74,424.93**
II	**व्यय**			
(क)	वित्तीय लागत	**24**	4,57,407.40	4,03,030.19
(ख)	शुल्क और कमीशन व्यय	**25**	5,613.66	5,404.62
(ग)	वित्तीय साधनों पर ह्रास	**26**	(16,566.36)	(16,048.29)
(घ)	कर्मचारी लाभ व्यय	**27**	7,412.43	7,525.73
(ड़)	मूल्य ह्रास, परिशोधन और हानि	**9,10**	1,427.34	1,118.32
(च)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		4,054.46	2,597.59
(छ)	अन्य व्यय	**28**	1,60,367.72	40,586.88
(ज)	**कुल व्यय II**		**6,19,716.65**	**4,44,215.04**
	असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (I-II)		**1,98,382.57**	**2,30,209.89**
	असाधारण मदे		-	47,343.03
	लाभ/(हानि) कर पूर्व (I–II)		**1,98,382.57**	**2,77,552.92**
	कर व्यय:			
	(i) चालू कर			
	– चालू वर्ष		(56,705.84)	(54,626.83)
	– पूर्व वर्ष		(1,889.63)	(6.91)
	(ii) आस्थगित कर		(1,844.93)	(6,441.75)
	कुल कर व्यय (i+ii)		**(60,440.41)**	**(61,075.49)**
	निरंतर परिचालनों से या निरंतर संचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**1,37,942.17**	**2,16,477.43**
	बंद संचालित वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		-	-
	बंद संचालन के लिए कर व्यय		-	-
	बंद संचालन के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात्)		-	-
	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)		**1,37,942.17**	**2,16,477.43**
	अन्य व्यापक आय			
	क. (i) आइटम जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	– लाभ/(हानि) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्मूल्यांकन		4.80	(468.12)
	– परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित आयकर		(1.21)	117.82
	अन्य व्यापक आय/(व्यय) (क)		3.59	(350.30)
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		**1,37,945.76**	**2,16,127.13**
	मूल और तनुकृत प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10 प्रति अंकित मूल्य)			
	1. निरंतर संचालन के लिए (₹ में)	**1(ख)(6)**	1.38	2.16
	2. बंद संचालन के लिए (₹ में)		-	-
	3. निरंतर एवं बंद संचालन के लिए (₹ में)		1.38	2.16

1 से 28 तक के नोट्स के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी इसी दिनांक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह./–
कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 315104E

ह./–
कृते एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 005593C

ह./–
सीए कमल कुमार चंडूका
भागीदार
सदस्यता संख्या: 058790

ह./–
सीए अमित तिवारी
भागीदार
डीआईएन: 408603

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर स

ह./–
रोहित ऋषि
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 11524681

ह./–
पलाश श्रीवास्तव
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 2007911

ह./–
रुचि सिंघल
(महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: 17837

ह./–
राजीव मुखिजा
(मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

31 मार्च 2026 वर्ष के लिए स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह का विवरण

सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
(i)	**कर से पूर्व शुद्ध लाभ**		1,98,382.57	2,77,552.92
	समायोजन हेतु:			
(ii)	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		1,427.34	1,118.32
(iii)	प्रावधान/बट्टे खाते में डालना:		14,196.51	11,944.10
(iv)	प्रावधान/अपलिखित		-	-
(v)	उधार पर विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव हानि/(लाभ)		1,36,613.51	22,735.84
(vi)	अचल आस्तियों की बिक्री पर हानि / (लाभ)		-	-
(vii)	ऋण और अग्रिमों पर अर्जित और देय ब्याज		-	1,060.17
(viii)	ब्याज उपार्जित लेकिन उधार पर देय नहीं		15,252.76	16,372.74
(ix)	ब्याज पर आयकर		(1,889.63)	(6.91)
क	**कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ**		**3,63,983.05**	**3,30,777.18**
(i)	उधार संचालन से नकदी प्रवाह		(12,09,490.76)	(19,19,786.95)
(ii)	परिचालन निवेशों में वृद्धि		16,923.96	(72,047.42)
(iii)	(वृद्धि)/व्यापार प्राप्तियों में कमी		(31,044.69)	(9,532.18)
(iv)	(वृद्धि)/अन्य परिचालन आस्तियों में कमी		(3,41,946.26)	5,57,940.25
(v)	अन्य परिचालन देनदारियों में/(कमी)		(21,752.32)	(6,940.84)
	कर से पहले के कार्यों से नकदी प्रवाह		**(12,23,327.03)**	**(11,19,589.97)**
	भुगतान किया गया कर (निवल)		(51,800.00)	(38,901.98)
	संचालन से निवल नकद	**A**	**(12,75,127.04)**	**(11,58,491.94)**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
(i)	संयंत्र, आस्ति और उपकरण की खरीद		(15,808.73)	(1,275.55)
(ii)	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य में (वृद्धि)/कमी		13,115.71	(6,544.19)
(iii)	निवेशों में (वृद्धि)/कमी		(97,795.39)	(1,42,015.21)
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद	**B**	**(1,00,488.43)**	**(1,49,834.95)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
(i)	शेयर पूंजी के निर्गम/आवंटन से प्राप्तियां		-	-
(ii)	ऋणों से शुद्ध प्राप्ति/(भुगतान)		10,50,914.42	6,31,154.08
(iii)	ऋण प्रतिभूतियों से शुद्ध प्राप्ति/(भुगतान)		3,55,208.90	7,16,000.00
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	**C**	**14,06,123.32**	**13,47,154.08**
	नकद और नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)		**30,507.85**	**38,827.20**
	जोड़ें: नकद और नकद समतुल्य खोलना		43,602.48	4,775.28
	नकद और नकद समतुल्य समाप्त करना		**74,110.35**	**43,602.48**
	समापन नकद और नकद समतुल्य में शामिल हैं: –			
(i)	नकद		-	-
(ii)	चालू खाते		**74,110.35**	**43,602.48**
	कुल		**74,110.35**	**43,602.48**

उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण, भारतीय लेखांकन मानक 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

1) पूर्ववर्ती अवधि के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है, ताकि उन्हें रिपोर्टिंग अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप तुलनीय बनाया जा सके।

2) निम्नलिखित बैंक शेषराशियाँ कंपनी के स्वतंत्र उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं:

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान अन्य बैंक शेषराशियों में ₹ (341,946.26) लाख की वृद्धि/(कमी) तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 557,940.25 लाख की वृद्धि/(कमी) में 31 मार्च 2026 को ₹ शून्य लाख (31 मार्च 2025 को ₹ शून्य लाख) की राशि शामिल है, जिस पर बॉण्ड के ब्याज भुगतान हेतु ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2026 को ₹ 5,05,392 लाख (31 मार्च 2025 को ₹ 2,09,400 लाख) की राशि शामिल है, जिस पर अधिविकर्ष सुविधा हेतु ग्रहणाधिकार अंकित किया गया है।

हमारी इसी दिनांक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह./–
कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 315104E

ह./–
कृते एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 005593C

ह./–
सीए कमल कुमार चंडूका
भागीदार
सदस्यता संख्या: 058790

ह./–
सीए अमित तिवारी
भागीदार
डीआईएन: 408603

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर स

ह./–
रोहित ऋषि
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 11524681

ह./–
पलाश श्रीवास्तव
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 2007911

ह./–
रुचि सिंघल
(महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: 17837

ह./–
राजीव मुखिजा
(मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2025 तक का शेष	9,99,991.62
पूर्व अवधि की त्रुटि के सुधार के परिणामस्वरूप इक्विटी शेयर पूंजी में समायोजन	-
1 अप्रैल 2025 तक का पुनः–प्रतिपादित शेष	9,99,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2026 तक का शेष	**9,99,991.62**

ख अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										कुल
	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर बांड/ रिडेम्पशन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व	स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि	कॉरपोरेट समाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	निधि आरक्षित निधि बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के तहत	अन्य व्यापक आय	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2025 को शेष राशि	**585.14**	**235.50**	**54,568.28**	**(20,317.05)**	**2,16,690.68**	**3,691.45**	**122.45**	**1,14,831.82**	**(1,075.19)**	**2,70,135.22**	**6,39,468.30**
पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	585.14	235.50	54,568.28	(20,317.05)	2,16,690.68	3,691.45	122.45	1,14,831.82	(1,075.19)	2,70,135.22	6,39,468.30
वर्ष का मुनाफा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37,942.17	1,37,942.17
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37,942.17	1,37,942.17
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-	-	-	-	(141.38)	-	-	3.59	(71,531.83)	(71,669.62)
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि	-	-	-	12,402.83	-	-	-	-	-	-	12,402.83
अवितरित लाभ में अंतरण	-	-	105.99	-	-	-	-	-	-	247.37	353.36
अवितरित लाभ में अंतरण	-	-	-	-	42,410.32	1,533.07	-	27,588.43	-	-	71,531.83
31 मार्च 2026 को शेष राशि	**585.14**	**235.50**	**54,462.29**	**(7,914.22)**	**2,59,101.00**	**5,083.14**	**122.45**	**1,42,420.26**	**(1,071.59)**	**3,36,792.93**	**7,89,816.97**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2024 को शेष	9,99,991.62
पूर्व अवधि की त्रुटि के सुधार के परिणामस्वरूप इक्विटी शेयर पूंजी में समायोजन	-
1 अप्रैल 2024 तक का पुनः–प्रतिपादित शेष	9,99,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2025 तक का शेष	**9,99,991.62**

ख अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										कुल
	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर बांड/ रिडेम्पशन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व	स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि	कॉरपोरेट समाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	निधि आरक्षित निधि बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के तहत	अन्य व्यापक आय	प्रतिधारित आय	
1 अप्रैल, 2024 तक शेष राशि	**585.14**	**235.50**	**54,568.28**	**(17,025.08)**	**1,77,588.70**	**297.14**	**122.45**	**71,536.34**	**(724.88)**	**1,39,449.56**	**2,87,816.28**
पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	**585.14**	**235.50**	**54,568.28**	**(17,025.08)**	**1,77,588.70**	**297.14**	**122.45**	**71,536.34**	**(724.88)**	**1,39,449.56**	**2,87,816.26**
वर्ष का मुनाफा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,16,477.44	1,55,160.72
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,16,477.44**	**1,55,160.72**
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	(350.31)	(85,791.78)	(86,142.09)
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि	-	-	-	(3,291.97)	-	-	-	-	-	-	(3,291.97)
अवितरित में अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अवितरित लाभ से अंतरण	-	-	-	-	39,101.98	3,394.31	-	43,295.49	-	-	85,791.78
31 मार्च 2025 को शेष राशि	**585.14**	**235.50**	**54,568.28**	**(20,317.05)**	**2,16,690.68**	**3,691.45**	**122.45**	**1,14,831.82**	**(1,075.19)**	**2,70,135.22**	**6,39,468.30**

हमारी इसी दिनांक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह./–
कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 315104E

ह./–
सीए कमल कुमार चंडूका
भागीदार
सदस्यता संख्या: 058790

ह./–
कृते एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 005593C

ह./–
सीए अमित तिवारी
भागीदार
डीआईएन: 408603

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर स

ह./–
रोहित ऋषि
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 11524681

ह./–
पलाश श्रीवास्तव
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 2007911

ह./–
रुचि सिंघल
(महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: 17837

ह./–
राजीव मुखिजा
(मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)

नोट 2: नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क)	**नकद और नकदी के समतुल्य**		
(i)	नकदी	-	-
(ii)	बैंकों के पास शेष	74,110.35	43,602.48
	उप–कुल (क)	**74,110.35**	**43,602.48**
(ख)	**उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस**		
(i)	बैंकों के साथ सावधि जमा (बिना भार के)	50,487.13	4,532.87
(ii)	बॉन्ड पर अघोषित आय के लिए बैंकों के पास चिन्हित बैलेंस	-	-
(iii)	बांड के ब्याज भुगतान के विरुद्ध प्रतिभूति के रूप में धारित	-	-
(iv)	बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा लेने का संकल्प लिया	5,05,392.00	2,09,400.00
	उप–कुल (ख)	**5,55,879.13**	**2,13,932.87**
	योग	**6,29,989.48**	**2,57,535.35**

नोट 3: व्युत्पन्न वित्तीय लिखते

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		काल्पनिक राशि	उचित मूल्य	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य
	व्युत्पन्नः				
	क्रॉस करेंसी स्वैप	2,69,289.38	99,647.94	4,79,480.79	1,24,863.15
	स्वैप केवल मूलधन	7,25,527.64	75,025.85	4,77,287.21	10,519.59
	(नोट संख्या (1(ख) 22.3 देखें)				
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**9,94,817.02**	**1,74,673.79**	**9,56,768.00**	**1,35,382.74**

नोट 4: ऋण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को परिशोधित लागत	31.03.2025 को परिशोधित लागत
(क)	**ऋण**		
(i)	**सावधि ऋण**		
I	**अवसंरचनात्मक ऋणः मानक आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष ऋण	18,68,519.82	16,26,864.41
ग.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	16,50,891.32	18,86,116.71
घ.	पुनर्वित्त योजना	23,86,907.04	21,86,120.00
ङ.	इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बॉन्ड (इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के तौर पर गिने जाते हैं)	22,32,577.60	12,13,451.83
II	**अवसंरचनात्मक ऋणः उप–मानक आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	-	23,678.72
III	**अवसंरचनात्मक ऋणः संदिग्ध आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	13,363.75	53,102.58
ख.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	19,193.32	1,016.94
	कुल (क) सकल	**81,71,452.86**	**69,90,351.13**
	घटाएँ: हानि हानि भत्ता (नोट 1(ख) 43 देखें)	1,60,728.91	1,75,544.54
	घटाएं: विनियोजन हेतु लंबित राशि''	5,366.93	2,324.83
	कुल (क) निवल	**80,05,357.02**	**68,12,481.76**
(ख)	(i) मूर्त आस्ति और अमूर्त आस्ति द्वारा प्रतिभूत	36,51,685.80	40,92,391.13
	(ii) अप्रतिभूत	**45,19,767.06**	28,97,960.00
	कुल (ख) सकल	81,71,452.86	69,90,351.13
	घटाएँ: हानि हानि भत्ता (नोट 1(ख) 43 देखें)	1,60,728.91	1,75,544.54
	घटाएं: विनियोग लंबित राशि^^	**5,366.93**	2,324.83
	कुल (ख) सकल	80,05,357.02	68,12,481.76
(ग)	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	29,77,608.69	17,50,750.00
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के अलावा	**51,93,844.17**	52,39,601.13
	कुल (ग) सकल	81,71,452.86	69,90,351.13
(घ)	(i) भारत में ऋण	81,71,452.86	69,90,351.13
	(ii) भारत के बाहर ऋण	**-**	-
	कुल (ग) सकल	81,71,452.86	69,90,351.13
	घटाएँ: हानि हानि भत्ता (नोट 1(ख) 43 देखें)	1,60,728.91	1,75,544.54
	घटाएं: विनियोग लंबित राशि^^	**5,366.93**	**2,324.83**
	कुल (ग) निवल	**80,05,357.02**	**68,12,481.76**
	कुल	**80,05,357.02**	**68,12,481.76**

फुटनोट

क्षेत्र	सुरक्षा के क्षेत्र का विवरण#	राशि (₹ लाख में)	
बिजली और अन्य क्षेत्र	गिरवी रखना: उधारकर्ता की वर्तमान एवं भविष्य की सभी अचल संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से प्रथम समानुपातिक प्रभार। दृष्टिबंधक: उधारकर्ता की मशीनरी एवं संयंत्र आदि सहित सभी चल संपत्तियों पर दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम समानुपातिक प्रभार। शेयरों का न्यूनतम 51% गिरवी रखना। एस्क्रो खाता तथा उधारकर्ता के सभी अधिकारों, स्वामित्व एवं हितों पर समानुपातिक प्रभार।	19,15,968.45	18,32,072.30
सड़क और हवाई अड्डा (पीपीपी)	परियोजना से वार्षिकी एवं टोल संग्रह प्राप्त करने का अधिकार। एस्क्रो खाता तथा उधारकर्ता के सभी अधिकारों, स्वामित्व एवं हितों पर समानुपातिक प्रभार। दृष्टिबंधक: उधारकर्ता की सभी चल संपत्तियों पर दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम समानुपातिक प्रभार।	17,35,717.35	22,60,318.83
पुनर्वित्तपोषण योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थान तथा अवसंरचना परियोजनाओं के बॉन्ड	असुरक्षित	45,19,767.06	28,97,960.00
	कुल#	**81,71,452.86**	**69,90,351.13**

^ऊपर प्रतिभूति संबंधी विवरण वाले फुटनोट में दी गई अवसंरचना ऋण की राशि में 31 मार्च 2026 को ₹6,74,836.23 लाख (31 मार्च 2025 को ₹5,52,584.50 लाख) की राशि शामिल है, जो एक वर्ष के भीतर देय ऋण की राशि है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2026 तक अग्रिमों के विरुद्ध ₹1,60,728.91 लाख (31 मार्च 2025 तक ₹1,75,544.54 लाख) का कुल प्रावधान किया गया है।

*अवसंरचना परियोजनाओं के बॉन्ड में किए गए निवेश को 22 सितंबर 2021 के भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र के अनुसार ऋण एवं अग्रिम के रूप में माना गया है। उक्त पत्र के अनुसार, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बॉन्ड/डिबेंचर में अभिदान के माध्यम से किया गया निवेश, जिसमें पुनर्वित्तपोषण भी शामिल है, चाहे परियोजना कार्यान्वयनाधीन हो अथवा पूर्ण हो चुकी हो, को कुल परिसंपत्तियों के न्यूनतम 75% को अवसंरचना ऋणों में लगाने के उद्देश्य से अवसंरचना ऋण के रूप में माना जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के 1 अप्रैल 2014 से लागू होने तथा 20 मई 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदन के अनुसरण में, मुख्य महाप्रबंधक–मुख्य वित्तीय अधिकारी तथा कंपनी सचिव को प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक माना गया है। तदनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को दिए गए स्टाफ ऋण को संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 31 मार्च 2026 को ऋण की कुल राशि ₹0.25 लाख (31 मार्च 2025 को ₹3.85 लाख) थी।

^^विनियोजन हेतु लंबित राशि को देय तिथि पर औरध्या ऋण के पूर्व भुगतान के समय ब्याजध्मूलधन के विरुद्ध ऋण खातों में समायोजित किया जा सकता है।

नोट 5: निवेश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को						31.03.2025 को					
		परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर					परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर				
			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	कुल		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	कुल
	सरकारी प्रतिभूत (अनुद्धृत) (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (फुटनोट ख और ग देखें)												
(i)	6.29% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2030	88,760.00	-	-	-	-	88,760.00	88,760.00	-	-	-	-	88,760.00
(ii)	6.34% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2031	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00
(iii)	6.34% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2032	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00
(iv)	6.39% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2033	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00
(v)	6.39% (अहस्तांतरणीय) विषेश भारत सरकार सुरक्षा 2034	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00
(vi)	6.44% (अहस्तांतरणीय) विषेश भारत सरकार प्रतिभूति 2035	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00
(vii)	7.12% मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति (एसजीएस) – 25–09–2036	50,060.00	-	-	-	-	50,060.00	50,060.00	-	-	-	-	50,060.00
(viii)	7.11% महाराष्ट्र राज्य सरकार प्रतिभूति (एसजीएस) – 25–09–2036	50,060.00	-	-	-	-	50,060.00	50,060.00	-	-	-	-	50,060.00
(ix)	6.76% Maharashtra SGS 23-04-2037	48,773.49	-	-	-	-	48,773.49	-	-	-	-	-	-
(x)	6.72% Maharashtra SGS 23-04-2038	49,057.40	-	-	-	-	49,057.40	-	-	-	-	-	-
		7,27,710.89	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,27,710.89**	**6,29,880.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6,29,880.00**
	ऋण प्रतिभूतियाँ												
क.	**ऋणों में निवेश (असूचीबद्ध) (पूर्ण रूप से चुकता) (फुटनोट ख एवं ग देखें)**												
(i)	बंसल पाथवेस (मंगावान–चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड के ऋण	-	-	6,078.00	-	-	6,078.00	-	-	6,078.00	-	-	6,078.00
(ii)	बंसल पाथवेस (एन.आर.आर.–1) प्राइवेट लिमिटेड के ऋण	-	-	7,276.00	-	-	7,276.00	-	-	7,276.00	-	-	7,276.00
(iii)	बंसल पाथवेस (एन.आर.आर.–2) प्राइवेट लिमिटेड के ऋण	-	-	11,184.00	-	-	11,184.00	-	-	11,184.00	-	-	11,184.00
(iv)	मीनाक्षी एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के ऋण	-	-	6,346.14	-	-	6,346.14	-	-	7,932.68	-	-	7,932.68
		-	-	30,884.14	-	-	30,884.14	-	-	32,470.68	-	-	32,470.68
क.	**इक्विटी लिखतें इक्विटी लिखत – गैर–उद्धृत (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (फुटनोट ख और ग देखें)**												

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को						31.03.2025 को					
		परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर				कुल	परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर				कुल
			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	
	राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड	-	-	411.03	-	-	411.03	-	-	411.03	-	-	411.03
	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा आयोजित)	-	-	4,765.00	-	-	4,765.00	-	-	4,765.00	-	-	4,765.00
		-	-	5,176.02	-	-	5,176.02	-	-	5,176.02		-	5,176.02
ख.	**पूर्ण सहायक स्वामित्व (लागत पर निवेश)**												
(i)	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	-	-	-	-	1,03,076.15	1,03,076.15		-	-	-	1,03,076.15	1,03,076.15
(ii)	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-	1,250.00	1,250.00		-	-	-	1,250.00	1,250.00
(iii)	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	-	-	-	-	475.00	475.00		-	-	-	475.00	475.00
		-	-	-	-	1,04,801.15	1,04,801.15		-	-	-	1,04,801.15	1,04,801.15
	अन्य												
	उद्यम पूंजी में निवेश (अनुद्धृत) (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (फुटनोट बी और सी देखें)												
क.	आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट II (पूरी तरह से भुगतान किया गया)												
(i)		-	-	566.06	-	-	566.06	-	-	601.56	-	-	601.56
		-	-	566.06	-	-	566.06	-	-	601.56		-	601.56
ख.	सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश (अनुद्धृत) (पूरी तरह से भुगतान किया गया) (फुटनोट ङ देखें)												
(i)	एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट–एससी 276–सीरीज I)	-	-	-	-	-	-	-	-	12,160.01	-	-	12,160.01
(ii)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0001	-	-	39,485.40	-	-	39,485.40	-	-	39,485.40	-	-	39,485.40
(iii)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0008	-	-	2,647.22	-	-	2,647.22	-	-	2,901.45	-	-	2,901.45
(iv)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0009	-	-	1,866.61	-	-	1,866.61	-	-	3,467.93	-	-	3,467.93
(v)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0010	-	-	3,375.16	-	-	3,375.16	-	-	3,944.09	-	-	3,944.09
(vi)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0013	-	-	4,557.65	-	-	4,557.65	-	-	4,557.65	-	-	4,557.65
(vii)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0017	-	-	3,447.06	-	-	3,447.06	-	-	3,447.06	-	-	3,447.06
(viii)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0019	-	-	13,944.09	-	-	13,944.09	-	-	14,956.26	-	-	14,956.26
(ix)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0022	-	-	3,931.35	-	-	3,931.35	-	-	3,672.10	-	-	3,672.10
		-	-	73,254.54	-	-	73,254.54	-	-	88,591.97	-	-	88,591.97
	कुल (क) सकल	**7,27,710.89**	**-**	**1,09,880.77**	**-**	**1,04,801.15**	**9,42,392.80**	**6,29,880.00**	**-**	**1,26,840.23**	**-**	**1,04,801.15**	**8,61,521.37**
(i)	विदेशी निवेश		-	-	-	1,03,076.15	1,03,076.15		-	-	-	1,03,076.15	1,03,076.15
(ii)	भारत में निवेश	**7,27,710.89**	**-**	**1,09,880.77**	**-**	**1,725.00**	**8,39,316.66**	**6,29,880.00**	**-**	**1,26,840.23**	**-**	**1,725.00**	**7,58,445.23**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को						31.03.2025 को					
		परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर					परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर				
			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	कुल		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	कुल
	कुल (ख)	**7,27,710.89**	**-**	**1,09,880.77**	**-**	**1,04,801.15**	**9,42,392.80**	**6,29,880.00**	**-**	**1,26,840.23**	**-**	**1,04,801.15**	**8,61,521.37**
	कुल (क) के साथ मिलान करने के लिए (ख)	7,27,710.89	-	1,09,880.77	-	1,04,801.15	8,32,512.04	6,29,880.00	-	1,26,840.23	-	1,04,801.15	6,29,880.00
	घटाः हानि के लिए भत्ता (ग)	**-**	**-**	**20,265.32**	**-**	**-**	**20,265.32**	**-**	**-**	**22,059.91**	**-**	**-**	**22,059.91**
	कुल निवल घ = (क) – (ग)	**7,27,710.89**	**-**	**89,615.45**	**-**	**1,04,801.15**	**9,22,127.48**	**6,29,880.00**	**-**	**1,04,780.32**		**1,04,801.15**	**8,39,461.46**

क्षति के लिए भत्ताः **(₹ लाख में)**

विवरण	31.03.2026 को						31.03.2025 को					
	परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर					परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर				
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	कुल		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	कुल
आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा आयोजित)	-	-	4,191.05	-	-	4,191.05	-	-	4,191.05	-	-	4,191.05
बंसल पाथवेज (मंगवां–चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	-	-	4,779.68	-	-	4,779.68	-	-	4,892.09	-	-	4,892.09
बंसल पाथवेज एनआरआर 1 में ऋण	-	-	4,451.99	-	-	4,451.99	-	-	4,736.88	-	-	4,736.88
बंसल पाथवेज एनआरआर 2 में ऋण	-	-	5,072.96	-	-	5,072.96	-	-	5,689.90	-	-	5,689.90
मीनाक्षी एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	-	-	1,769.63	-	-	1,769.63	-	-	2,549.99	-	-	2,549.99
कुल	**-**	**-**	**20,265.32**	**-**	**-**	**20,265.32**	**-**	**-**	**22,059.91**	**-**	**-**	**22,059.91**

फुटनोटः

(क) **असूचीबद्ध निवेशों की समेकित राशि – लागत/पुस्तक मूल्य के आधार पर** **9,22,127.48** **8,39,461.46**

(ख) **वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग एवं रेटिंग में परिवर्तनः**

"आईआईएफसीएल के घरेलू ऋण साधनों को 'AAA' रेटिंग प्राप्त है – जो क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए आरएफकेके ब्रिकवर्क्स जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सर्वोच्च रेटिंग है।
वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन या अवनयन नहीं हुआ है।"

नोट 6: अन्य वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
क.	**अग्रिमों**		
	कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम	3,840.11	2,912.00
	सुरक्षा जमा का भुगतान	42.18	37.15
	अन्य	13,891.45	10,727.80
	उप–कुल (क)	**17,773.75**	**13,676.93**
ख.	**ऋण और अग्रिमों पर अर्जित और देय ब्याज**	-	-
	उप–कुल (ख)	-	-
ग.	**अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:**		
	बैंकों में सावधि जमा	7,586.47	5,185.44
	बांड	3,179.75	17,071.65
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	29,213.90	10,816.69
	ऋण और अग्रिम	**39,980.11**	**33,073.77**
	उप–कुल (ग)	**57,753.87**	**46,750.72**
	कुल (क)+(ख)+(ग)		

*वित्तीय विवरणों के टिप्पणियों के नोट 1(ख)(5) देखें।

नोट 7: चालू कर आस्ति (निवल)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(i)	वसूली योग्य निवल आयकर	793.41	2,665.83
(ii)	वसूली योग्य वस्तु और सेवा कर	263.16	255.81
	कुल	**1,056.58**	**2,921.65**

नोट 8: आस्थगित कर आस्ति (निवल)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(I)	**आस्थगित कर आस्तियों के कारण:**		
(i)	कर के लिए प्रस्तावित विविध देयता खाते (ब्याज पूंजीकरण) में जमा किया गया ब्याज	-	1,166.85
(ii)	अपेक्षित ऋण हानि	14,384.38	15,671.16
(iii)	अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान	-	-
(iv)	मूल्यह्रास और परिशोधन	2,105.91	1,574.89
(v)	बीमार अवकाश हेतु प्रावधान	100.79	111.01
(vi)	चिकित्सा सहायता योजना हेतु प्रावधान	381.60	344.18
(vii)	कर्मचारियों/डब्ल्यूटीडीएस हेतु पीएलआई का प्रावधान	7.07	44.80
(viii)	अवकाश किराए में रियायत का प्रावधान	33.47	31.59
	आस्थगित कर आस्तियां	**17,013.22**	**18,944.48**
(II)	**आस्थगित कर देयताओं के खाते में :**		
(i)	संज्ञी देयता खाते में जमा ब्याज (ब्याज का पूंजीकरण), कर हेतु प्रस्तुत	167.09	-
(ii)	वे व्यय जिनमें टीडीएस नहीं काटा गया	-	-
(iii)	अन्य	1,463.40	1,715.62
	आस्थगित कर देयताएं	**1,630.49**	**1,715.62**
	आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं) (निवल)	**15,382.73**	**17,228.88**

नोट 9: संपत्ति, संयत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	31.03.2026 को	01.04.2025 को	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	31.03.2026 को	31.03.2026 को	31.03.2025 को
मूर्त संपत्तियां										
भवन**	27,701.73	15,711.48	-	**43,413.21**	5,967.52	1,114.86	-	**7,082.38**	**36,330.83**	21,734.21
संयंत्र एवं मशीनरी	113.66	1.42	-	**115.09**	104.05	1.09	-	**105.14**	**9.95**	9.62
विद्युत उपकरण	346.41	-	-	**346.41**	329.09	-	-	**329.09**	**17.32**	17.32
फर्नीचर और फिटिंग	594.94	-	-	**594.94**	485.98	26.22	-	**512.20**	**82.74**	108.96
वाहनों	105.66	26.96	-	**132.61**	78.20	8.45	-	**86.66**	**45.95**	27.45
कार्यालय उपकरण	343.94	-	-	**343.94**	321.71	2.02	-	**323.73**	**20.21**	22.23
कम्पुटर हार्डवेयर	276.08	68.87	-	**344.95**	138.60	83.69	-	**222.28**	**122.66**	137.48
कुल	**29,482.42**	**15,808.73**	**-**	**45,291.15**	**7,425.14**	**1,236.33**	**-**	**8,661.48**	**36,629.69**	**22,057.28**
विगत वर्ष	29,128.49	353.93	-	29,482.42	6,393.03	1,032.10	-	7,425.14	22,057.28	22,735.46

नोट 9क : पूंजीगत कार्य प्रगति

(₹ लाख में)

मूल्यह्रास	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	31.03.2025 को	अतिरिक्त	निपटानध समायोजन	31.03.2026 को	31.03.2025 को	वर्ष हेतु	कटौती / बदलाव	31.03.2026 को	31.03.2026 को	31.03.2025 को
पूंजीगत कार्य प्रगति	15,333.67	2,879.96	15,995.67	**2,217.96**	-	-	-	-	**2,217.96**	15,333.67
कुल	**15,333.67**	**2,879.96**	**15,995.67**	**2,217.96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,217.96**	**15,333.67**
विगत वर्ष	8,789.48	6,544.19	-	15,333.67	-	-	-	-	15,333.67	8,789.48

सीडब्ल्यूआईपी एजिंग	अवधि के अनुसार निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में राशि				कुल
सीडब्ल्यूआईपी	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाओं की प्रगति	2,217.96	-	-	-	**2,217.96**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
योग	**2,217.96**	-	-	-	**2,217.96**
पिछला वर्ष	6,544.19	8,789.48	-	-	**15,333.67**

नोट 10: अमूर्त आस्तियां

(₹ लाख में)

मूल्यह्रास	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	31.03.2025 को	अतिरिक्त	निपटान/ समायोजन	31.03.2026 को	31.03.2025 को	वर्ष हेतु	कटौती / बदलाव	31.03.2026 को	31.03.2026 को	31.03.2025 को
कम्पुटर हार्डवेयर*	2,040.30	-	-	**2,040.30**	1,065.03	191.00	-	**1,256.03**	**784.27**	975.27
कुल	**2,040.30**	**-**	**-**	**2,040.30**	**1,065.03**	**191.00**	**-**	**1,256.03**	**784.27**	**975.27**
विगत वर्ष	1,118.68	921.62	-	2,040.30	978.80	86.23	-	1,065.03	975.26	139.88

* कंपनी के पास धारित अमूर्त परिसंपत्तियां आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्तियों के अतिरिक्त अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां हैं।

** एनबीसीसी लिमिटेड ने आईआईएफसीएल को किदवई नगर परिसर में (वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र एवं पार्किंग स्लॉट) लीजहोल्ड आधार पर तथा नौरोजी नगर परिसर में (वाणिज्यिक क्षेत्र एवं पार्किंग स्लॉट) फ्रीहोल्ड आधार पर निर्मित स्थान आवंटित किया है। परिसरों के अधिग्रहण के लिए आईआईएफसीएल द्वारा भुगतान की गई राशि को लेखा पुस्तकों में पूंजीकृत किया गया है। चूंकि किदवई नगर परिसर के संबंध में लीज समझौता अभी निष्पादित किया जाना बाकी है, इसलिए आईआईएफसीएल ने 30 वर्षों की लीज अवधि में उक्त राशि का परिशोधन किया है। इसके अतिरिक्त, नौरोजी नगर परिसर के लिए हस्तांतरण विलेख भी अभी निष्पादित किया जाना बाकी है।

वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों का कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है (पिछला वर्ष – शून्य)।

नोट 11: अन्य गैर वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(i)	पूर्वदत्त व्यय	120.87	98.92
(ii)	अन्य अग्रिम	867.91	6,986.58
(iii)	उपदान (निधिबद्ध)	137.69	-
(iv)	अवकाश नकदीकरण (निधिबद्ध)	977.40	-
	कुल	**2,103.87**	**7,085.51**

नोट 12: ऋण प्रतिभूतियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(क)	**अन्य**				
I	**सुरक्षित बॉण्ड्स^**				
(i)	79,110 (31 मार्च 2025 को 79,110) 8.30% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 28 मार्च 2026 को मोचन योग्य हैं।	-	-	791.10	791.10
(ii)	10,500 (31 मार्च 2025 को 10,500) 9.41% कर योग्य बॉन्ड, सीरीज एक्स, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 27 जुलाई 2037 को मोचन योग्य हैं।	1,05,000.00	1,05,000.00	10,000.00	10,000.00
(iii)	500 (31 मार्च 2025 को 500) 9.36% कर योग्य बॉन्ड, सीरीज एक्स, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 27 जुलाई 2042 को मोचन योग्य हैं।	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(iv)	1,000 (31 मार्च 2025 को 1,000) 7.38% कर–मुक्त बॉन्ड, सीरीज तृतीय–बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 15 नवंबर 2027 को मोचन योग्य हैं।	10,000.00	10,000.00	67,411.62	67,411.62
(v)	3,400 (31 मार्च 2025 को 3,400) 7.41% कर–मुक्त बॉन्ड, सीरीज तृतीय–सी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 15 नवंबर 2032 को मोचन योग्य हैं।	34,000.00	34,000.00	8,683.91	8,683.91
(vi)	500 (31 मार्च 2025 को 500) 7.38% कर–मुक्त बॉन्ड, सीरीज चतुर्थ–बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 21 नवंबर 2027 को मोचन योग्य हैं।	5,000.00	5,000.00	3,615.54	3,615.54
(vii)	210 (31 मार्च 2025 को 210) 7.41% कर–मुक्त बॉन्ड, सीरीज चतुर्थ–सी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 21 नवंबर 2032 को मोचन योग्य हैं।	2,100.00	2,100.00	1,040.64	1,040.64

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(viii)	68,77,081 (31 मार्च 2025 को 67,41,162) 7.36% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज प्रथम, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 22 जनवरी 2028 को मोचन योग्य हैं।	68,770.81	68,770.81	63,030.00	63,030.00
(ix)	7,32,472 (31 मार्च 2025 को 8,68,391) 7.86% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज प्रथम, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 22 जनवरी 2028 को मोचन योग्य हैं।	7,324.72	7,324.72	1,15,970.00	1,15,970.00
(x)	1,03,89,938 (31 मार्च 2025 को 1,01,62,809) 7.40% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज तृतीय, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 22 जनवरी 2033 को मोचन योग्य हैं।	1,03,899.38	1,03,899.38	1,12,970.00	1,12,970.00
(xi)	11,74,286 (31 मार्च 2025 को 14,01,415) 7.90% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज तृतीय, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 22 जनवरी 2033 को मोचन योग्य हैं।	11,742.86	11,742.86	890.09	890.09
(xii)	3,86,252 (31 मार्च 2025 को 3,61,554) 7.02% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच द्वितीय – सीरीज द्वितीय, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 26 मार्च 2028 को मोचन योग्य हैं।	3,862.52	3,862.52	30,353.30	30,353.30
(xiii)	79,366 (31 मार्च 2025 को 1,04,064) 7.52% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच द्वितीय – सीरीज द्वितीय, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 26 मार्च 2028 को मोचन योग्य हैं।	793.66	793.66	15,713.11	15,713.11
(xiv)	82,275 (31 मार्च 2025 को 42,472) 7.08% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच द्वितीय – सीरीज तृतीय, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 26 मार्च 2033 को मोचन योग्य हैं।	822.75	822.75	679.08	679.08
(xv)	1,50,890 (31 मार्च 2025 को 1,90,693) 7.58% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच द्वितीय – सीरीज तृतीय, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 26 मार्च 2033 को मोचन योग्य हैं।	1,508.90	1,508.90	27,989.22	27,989.22
(xvi)	6,303 (31 मार्च 2025 को 6,303) 8.26% कर–मुक्त बॉन्ड, सीरीज पंचम–बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 23 अगस्त 2028 को मोचन योग्य हैं।	63,030.00	63,030.00	14,109.50	14,109.50

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xvii)	20 (31 मार्च 2025 को 20) 8.19% कर–मुक्त बॉन्ड, सीरीज पंचम–सी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 23 अगस्त 2033 को मोचन योग्य हैं।	200.00	200.00	1,228.07	1,228.07
(xviii)	11,597 (31 मार्च 2025 को 11,597) 8.46% कर–मुक्त बॉन्ड, सीरीज षष्ठम–बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 30 अगस्त 2028 को मोचन योग्य हैं।	1,15,970.00	1,15,970.00	1,59,584.86	1,59,584.86
(xix)	265 (31 मार्च 2025 को 265) 8.37% कर–मुक्त बॉन्ड, सीरीज षष्ठम–सी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 30 अगस्त 2033 को मोचन योग्य हैं।	2,650.00	2,650.00	27,110.62	27,110.62
(xx)	11,297 (31 मार्च 2025 को 11,297) 8.48% कर–मुक्त बॉन्ड, सीरीज सप्तम–बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 5 सितंबर 2028 को मोचन योग्य हैं।	1,12,970.00	1,12,970.00	34,000.00	34,000.00
(xxi)	30,35,330 (31 मार्च 2025 को 30,35,330) 8.38% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज 2ए, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 12 नवंबर 2028 को मोचन योग्य हैं।	30,353.30	30,353.30	2,100.00	2,100.00
(xxii)	2,12,973 (31 मार्च 2025 को 89,009) 8.38% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज 2बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 12 नवंबर 2028 को मोचन योग्य हैं।	2,129.73	2,129.73	1,01,628.09	1,01,628.09
(xxiii)	14,47,347 (31 मार्च 2025 को 15,71,311) 8.63% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज 2बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 12 नवंबर 2028 को मोचन योग्य हैं।	14,473.47	14,473.47	14,014.15	14,014.15
(xxiv)	18,68,982 (31 मार्च 2025 को 18,68,982) 8.50% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज 3ए, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 12 नवंबर 2033 को मोचन योग्य हैं।	18,689.82	18,689.82	424.72	424.72
(xxv)	4,31,754 (31 मार्च 2025 को 1,59,113) 8.50% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज 3बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 12 नवंबर 2033 को मोचन योग्य हैं।	4,317.54	4,317.54	1,906.93	1,906.93

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xxvi)	21,47,867 (31 मार्च 2025 को 24,20,508) 8.75% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज 3बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 12 नवंबर 2033 को मोचन योग्य हैं।	21,478.67	21,478.67	200.00	200.00
(xxvii)	27,98,922 (31 मार्च 2025 को 27,98,922) 8.48% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच द्वितीय – सीरीज 2ए, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 22 जनवरी 2029 को मोचन योग्य हैं।	27,989.22	27,989.22	2,650.00	2,650.00
(xxviii)	75,43,989 (31 मार्च 2025 को 75,43,989) 8.66% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच द्वितीय – सीरीज 3ए, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 22 जनवरी 2034 को मोचन योग्य हैं।	75,439.89	75,439.89	1,591.13	1,591.13
(xxix)	1,90,894 (31 मार्च 2025 को 67,908) 8.48% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच द्वितीय – सीरीज 2बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 22 जनवरी 2029 को मोचन योग्य हैं।	1,908.94	1,908.94	18,689.82	18,689.82
(xxx)	12,87,964 (31 मार्च 2025 को 14,10,950) 8.73% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच द्वितीय – सीरीज 2बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 22 जनवरी 2029 को मोचन योग्य हैं।	12,879.64	12,879.64	24,205.08	24,205.08
(xxxi)	11,65,808 (31 मार्च 2025 को 5,15,765) 8.66% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज 3बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 22 जनवरी 2034 को मोचन योग्य हैं।	11,658.08	11,658.08	5,157.65	5,157.65
(xxxii)	47,93,189 (31 मार्च 2025 को 54,43,232) 8.91% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम – सीरीज 3बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 22 जनवरी 2034 को मोचन योग्य हैं।	47,931.89	47,931.89	75,439.89	75,439.89
(xxxiii)	1,59,58,486 (31 मार्च 2025 को 1,59,58,486) 8.55% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच तृतीय – सीरीज 2ए, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 27 मार्च 2029 को मोचन योग्य हैं।	1,59,584.86	1,59,584.86	54,432.32	54,432.32
(xxxiv)	12,59,825 (31 मार्च 2025 को 12,59,825) 8.55% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच तृतीय – सीरीज 3, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 27 मार्च 2034 को मोचन योग्य हैं।	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xxxv)	3,29,038 (31 मार्च 2025 को 1,22,807) 8.55% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच तृतीय – सीरीज 2बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 27 मार्च 2029 को मोचन योग्य हैं।	3,290.38	3,290.38	12,873.11	12,873.11
(xxxvi)	25,04,831 (31 मार्च 2025 को 27,11,062) 8.80% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच तृतीय – सीरीज 2बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 27 मार्च 2029 को मोचन योग्य हैं।	25,048.31	25,048.31	1,254.70	1,254.70
(xxxvii)	2,61,357 (31 मार्च 2025 को 1,25,470) 8.55% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 27 मार्च 2034 को मोचन योग्य हैं।	2,613.57	2,613.57	1,05,000.00	1,05,000.00
(xxxviii)	11,51,424 (31 मार्च 2025 को 12,87,311) 8.80% कर–मुक्त बॉन्ड, ट्रेंच प्रथम, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, जो 27 मार्च 2034 को मोचन योग्य हैं।	11,514.24	11,514.24	5,000.00	5,000.00
		11,38,545.40	**11,38,545.40**	**11,39,336.50**	**11,39,336.50**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
II	**अप्रतिभूति बांड^**				
(i)	15,000 7.17% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 12 मार्च 2032 को मोचन योग्य हैं।	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00
(ii)	5,000 7.46% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, जो 31 मई 2033 को मोचन योग्य हैं।	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(iii)	2,00,000 7.53% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 18 सितंबर 2038 को मोचन योग्य हैं।	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00
(iv)	2,00,000 7.69% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 26 अक्टूबर 2038 को मोचन योग्य हैं।	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00
(v)	1,00,000 7.67% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 8 दिसंबर 2038 को मोचन योग्य हैं।	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00
(vi)	1,50,000 7.34% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 14 मार्च 2039 को मोचन योग्य हैं।	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00
(vii)	2,00,000 7.51% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 25 अप्रैल 2039 को मोचन योग्य हैं।	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(viii)	1,02,500 7.41% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 26 जून 2039 को मोचन योग्य हैं।	1,02,500.00	1,02,500.00	1,02,500.00	1,02,500.00
(ix)	51,500 7.39% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 1 अगस्त 2039 को मोचन योग्य हैं।	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00
(x)	96,000 7.37% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 2 सितंबर 2034 को मोचन योग्य हैं।	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
(xi)	1,58,500 7.26% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 7 नवंबर 2034 को मोचन योग्य हैं।	1,58,500.00	1,58,500.00	1,58,500.00	1,58,500.00
(xii)	74,500 7.47% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 7 नवंबर 2027 को मोचन योग्य हैं।	74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00
(xiii)	55,000 7.35% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 20 दिसंबर 2034 को मोचन योग्य हैं।	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
(xiv)	74,000 7.47% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 20 मार्च 2028 को मोचन योग्य हैं।	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
(xv)	1,04,000 7.56% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 20 मार्च 2028 को मोचन योग्य हैं।	1,04,000.00	1,04,000.00	1,04,000.00	1,04,000.00
(xvi)	1,00,000 7.28% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 27 मार्च 2032 को मोचन योग्य हैं।	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00
(xvii)	2,00,000 7.08% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 15 मई 2035 को मोचन योग्य हैं।	2,00,000.00	2,00,000.00	-	-
(xviii)	1,56,000 6.99% बॉन्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, जो 15 जून 2030 को मोचन योग्य हैं।	1,56,000.00	1,56,000.00	-	-
	कुल सकल (क)	**22,22,000.00**	**22,22,000.00**	**18,66,000.00**	**18,66,000.00**
	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	**33,60,545.40**	**33,60,545.40**	**30,05,336.50**	**30,05,336.50**
	भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियां	33,60,545.40	33,60,545.40	30,05,336.50	30,05,336.50
		-	-	-	-
	कुल सकल (ख)	**33,60,545.40**	**33,60,545.40**	**30,05,336.50**	**30,05,336.50**
	कुल (ख), (क) से मिलान योग्य	**33,60,545.40**	**33,60,545.40**	**30,05,336.50**	**30,05,336.50**

^ आईआईएफसीएल द्वारा जारी सभी सुरक्षित और असुरक्षित बॉन्ड अपरिवर्तनीय हैं तथा सममूल्य पर मोचन योग्य हैं। इसके अतिरिक्त, सुरक्षित बॉन्ड कंपनी के सभी खातों, जिसमें कंपनी की वर्तमान एवं भविष्य की किसी भी प्रकृति की प्राप्य राशियां शामिल हैं, से संबंधित सभी अधिकारों, स्वामित्व, हितों, लाभों, दावों और मांगों द्वारा समानुपाती आधार पर सुरक्षित हैं।

वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग तथा रेटिंग में परिवर्तन

आईआईएफसीएल की घरेलू ऋण प्रतिभूतियों को क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए तथा ब्रिकवर्क्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा "एएए" रेटिंग प्रदान की गई है, जो इन एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च रेटिंग है। वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

#	असुरक्षित बॉन्ड भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं। 31 मार्च 2026 को शून्य (31 मार्च 2025 को ₹3,00,000 लाख), जो रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर देय राशि थी। वे बॉन्ड अथवा डिबेंचर जिनका मोचन किया गया है और जिन्हें आईआईएफसीएल के पास पुनः जारी करने का अधिकार है।	शून्य	शून्य
	31 मार्च 2026 को ₹5,05,392 (31 मार्च 2025 को ₹2,09,400 लाख) की सावधि जमा रसीदों की गिरवी द्वारा सुरक्षित।	शून्य	शून्य

नोट 13: उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
क)	**सावधि ऋण**				
	अप्रतिभूत ऋण:				
(i)	**बैंकों से**				
क.	अल्पकालिक ऋण	12,33,101.40	12,33,101.40	15,63,248.07	15,63,248.07
ख.	दीर्घकालिक ऋण	12,99,743.32	12,99,743.32	2,20,000.00	2,20,000.00
(ii)	**अन्य पक्षों से**				
क.	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	11,79,891.22	11,79,891.22	10,64,015.50	10,64,015.50
ख.	आईबीआरडी (विश्व बैंक)	1,03,510.16	1,03,510.16	1,01,728.52	1,01,728.52
ग.	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)	1,38,515.99	1,38,515.99	1,30,353.39	1,30,353.39
घ.	क्रैडिएन्स्टाल्ट फर विडेरूफुबाऊ (केएफडब्ल्यू)	14,529.01	14,529.01	12,807.08	12,807.08
ङ.	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी	2,04,052.62	2,04,052.62	2,14,970.21	2,14,970.21
च.	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीसी)	1,54,050.00	1,54,050.00	-	-
ख)	**मांग पर चुकाने योग्य ऋण**		-		
	सुरक्षित ऋण:				
i)	बैंकों से*	2,14,882.39	2,14,882.39	47,625.41	47,625.41
	(31 मार्च 2026 को ₹ 2,09,400 लाख की सावधि जमा रसीदों को गिरवी रखकर सुरक्षित (31 मार्च 2025 तक ₹ 2,12,300 लाख))				
	कुल (क)	**45,42,276.10**	**45,42,276.10**	**33,54,748.17**	**33,54,748.17**
	भारत में उधार	27,47,727.11	27,47,727.11	18,30,873.48	18,30,873.48
	भारत–एफसी ऋण के बाहर उधार	17,94,548.99	17,94,548.99	15,23,874.71	15,23,874.71
	कुल (ख) के साथ मिलान करने के लिए (क)	**45,42,276.10**	**45,42,276.10**	**33,54,748.17**	**33,54,748.17**

लंबी अवधि के ऋणों की चुकौती की शर्तें

i) एशियाई विकास बैंक

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि ($ लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	3000	रातोंरात एसओएफआर +20 आधार अंक	15.12.2012	15.06.2032	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रत्येक किस्त
II	2000	रातोंरात एसओएफआर +20 आधार अंक	15.06.2014	15.12.2033	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रत्येक किस्त
III	2100	रातोंरात एसओएफआर +20 आधार अंक	15.12.2014	15.06.2034	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 0.827816% से शुरू होकर अधिकतम 5.550311% तक बढ़ती हुई किस्तें।
IV	2500	रातोंरात एसओएफआर +30 आधार अंक	15.12.2015	15.06.2035	अर्ध–वार्षिक	
V	2400	रातोंरात एसओएफआर +40 आधार अंक	15.12.2016	15.06.2036	अर्ध–वार्षिक	
VI	4000	रातोंरात एसओएफआर +40 आधार अंक	15.03.2018	15.03.2033	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.173900% से शुरू होकर अधिकतम 4.559913% तक बढ़ती हुई किस्तें।
VII	3000	रातोंरात एसओएफआर +50 आधार अंक	01.05.2023	01.05.2038	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.173900% से शुरू होकर अधिकतम 4.559913% तक बढ़ती हुई किस्तें।
VIII	5000	रातोंरात एसओएफआर +50 आधार अंक	01.06.2029	01.06.2044	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किस्त ऋण राशि के 3.225806% की होगी।
योग	**24000**					

ii) आईबीआरडी (विश्व बैंक)

अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि ($ लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
1950*	6एम यूएसडी एसओएफआर + परिवर्तनशील वृद्धि	15.04.2017	15.04.2037	अर्ध–वार्षिक	15.10.2036 तक ऋण राशि का 2.44% और 15.04.2037 को 2.40% की किश्त

* 18 दिसंबर 2013 को इसकी लाइन ऑफ क्रेडिट के पुनर्गठन के कारण आईबीआरडी (विश्व बैंक) के ऋण की राशि घटकर $1,950 लाख रह गई है, जिसमें $10,000 लाख की ऋण राशि के निरस्तीकरण का विवरण शामिल है।

iii) क्रैडिएन्स्टाल्ट फर विडेरूफुबाऊ (केएफडब्ल्यू)

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि (यूरो लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	165.89	0.75%	30.06.2020	30.06.2050	अर्ध–वार्षिक	- यूरो 271,000 से 30.06.2020 तक 30.12.2021 - यूरो 272,000 से 30.06.2022 तक 30.12.2049 और यूरो 272581.03 on 30.06.2050
II	334.11	4.99%	30.06.2015	30.06.2020	अर्ध–वार्षिक	- यूरो 3,037,000 से 30.06.2015 to 30.06.2018 - यूरो 3,038,000 से 30.12.2018 to 30.12.2019 a और यूरो 3,038,418.97 on 30.06.2020
कुल	**500.00**					

iv) यूरो इंवेस्टमैंट बैंक

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि (यूरो लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	350.00	6 मिलियन यूरीबोर +0.275% का संपूर्ण प्रसार	22.06.2020	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किस्त 11,66,666.67 यूरो
II	400.00	6 मिलियन यूरीबोर +0-436% का संपूर्ण प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
III	400.00	6 मिलियन यूरीबोर +0.426% का संपूर्ण प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
IV	850.00	6 मिलियन यूरीबोर +0.346% का संपूर्ण प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किस्त 30,35,714.29 यूरो
कुल	**2000.00**					

v) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि (यूरो लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
भाग–I	10,000.00	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर 0.10% की फ्लोर और 6.208% की उच्चतम सीमा के साथ	20.03.2022	20.03.2036	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि की पहली किश्त 3.448328: और उसके बाद ऋण राशि के 3.448274: की किश्तें।
भाग–II	90,000.00	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर 0.10% की फ्लोर और 6.208% की उच्चतम सीमा के साथ	20.03.2022	20.03.2036	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि की पहली किश्त 3.448328: और उसके बाद ऋण राशि के 3.448274: की किश्तें।

vi) सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि (जापानी येन लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति एवं राशि
I	1,60,000.00	टीओएनए . 0.8491%	25.07.2025	25.07.2030	प्रत्येक ऋण की अंतिम परिपक्वता तिथि पर एकमुश्त पुनर्भुगतान
II	1,00,000.00	टीओएनए . 0.8491%	11.11.2025	11.11.2030	प्रत्येक ऋण की अंतिम परिपक्वता तिथि पर एकमुश्त पुनर्भुगतान

नोट 14: अन्य वित्तीय देनदारियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
	ब्याज उपार्जित लेकिन उधार पर देय नहीं		
(i)	बांड और सावधि ऋण पर	1,30,499.67	1,15,246.91
(ii)	प्रतिभूति जमाएं प्राप्त	63.93	1.43
(iii)	अन्य	4,863.58	7,721.63
	कुल	**1,35,427.19**	**1,22,969.96**

नोट 15: चालू कर देनदारियां (निवल)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(i)	आय कर (निवल)	4,905.84	15,725.16
	कुल	**4,905.84**	**15,725.16**

नोट 16: प्रावधान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i)	अवकाश नकदीकरण	-	-
(ii)	बीमारी की अवकाश	400.47	441.09
(iii)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	1,516.21	1,367.54
(iv)	अवकाश किराया छूट	133.00	125.53
(v)	वेतन संशोधन	2,332.38	1,642.64
	कर्मचारियों/डब्ल्यूटीडीएस को पीएलआई	28.08	178.00
(vii)	नवीन श्रम संहिता के संबंध में उपदान	65.63	-
(i)	**अन्य**		
	एनपीए की ओर से व्यय	439.77	1,134.61
	कुल	**4,915.54**	**4,889.42**

नोट 17: अन्य गैर–वित्तीय देयताए

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क)	**अन्य देयताएं**		
(i)	देय सांविधिक देयताएं	772.76	423.43
(ii)	बांड पर दावा न किया गया ब्याज	0.69	0.69
(iii)	देय प्रतिबद्धता शुल्क	186.30	-
(iv)	विविध देनदारी खाता (ब्याज पूंजीकरण)*	3,725.97	9,026.24
(v)	अन्य	5,512.32	4,634.81
	कुल	**10,198.05**	**14,085.16**

*इस राशि में भारतीय रिजर्व बैंक के "कोविड–19 विनियामक पैकेज" संबंधी परिपत्र के अनुसार मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक आईआईएफसीएल के उधारकर्ताओं को प्रदान की गई स्थगन अवधि भी शामिल है।

नोट 18: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
क	**प्राधिकृत**		
	₹10/प्रत्येक के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2025 तक ₹10/– प्रत्येक के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर)	**10,00,000.00**	**10,00,000.00**
	निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त		
ख	10 रू. प्रत्येक के 9,999,916,230 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (31 मार्च 2025 को 10 रू. प्रत्येक के 9,999,916,230 इक्विटी शेयर)	9,99,991.62	9,99,991.62
	कुल	**9,99,991.62**	**9,99,991.62**

फुटनोट:

क. रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
	शेयरों की संख्या	(₹ लाख में)	शेयरों की संख्या	(₹ लाख में)
रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में बकाया शेयर	9,99,99,16,230	9,99,991.62	9,99,99,16,230	9,99,991.62
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	9,99,99,16,230	9,99,991.62	9,99,99,16,230	9,99,991.62

ख) उन शेयरधारकों का विवरण, जो 5% से अधिक शेयर रखते हैं:–

विवरण	31 मार्च 2026 को प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर		31 मार्च 2025 को प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर	
	शेयरों की संख्या	धारित %	शेयरों की संख्या	धारित %
भारत के राष्ट्रपति	9,99,99,16,230	100.00%	9,99,99,16,230	100.00%

(ग) प्रवर्तकों की शेयरधारिता का प्रकटीकरण

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	(₹ लाख में)	शेयरों की संख्या	(₹ लाख में)	
भारत के राष्ट्रपति	9,99,99,16,230	100.00%	9,99,99,16,230	100.00%	-

नोट 19: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क)	**पूँजी आरक्षित निधि (गैर–चालू प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ)**		
	प्रारंभिक शेष	585.14	585.14
	जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से अंतरण	-	-
	अंतिम शेष	**585.14**	**585.14**
(ख)	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बॉण्ड्स पर)**		
	प्रारंभिक शेष	235.50	235.50
	जोड़ें: वर्ष के दौरान	-	-
	अंतिम शेष	**235.50**	**235.50**
(ग)	**डिबेंचर/बॉण्ड रिडेम्पशन रिजर्व**		
	प्रारंभिक शेष	54,568.28	54,568.28
	घटाएँ: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष में अंतरण	105.99	-
	अंतिम शेष	**54,462.29**	**54,568.28**
(घ)	**नकदी प्रवाह हेज आरक्षित**		
	प्रारंभिक शेष	(20,317.05)	(17,025.08)
	जोड़ें: वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह हेज आरक्षित	12,402.83	(3,291.97)
	घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि तथा लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष में अंतरण	-	-
	अंतिम शेष	**(7,914.22)**	**(20,317.05)**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(ङ)	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
(i)	**विशेष आरक्षित निधि धारा 36(1)(viii), आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत (फुटनोट 1)**		
	प्रारंभिक शेष	2,16,690.68	1,77,588.70
	जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष में अंतरण (शुद्ध)	42,410.32	39,101.98
	अंतिम शेष	**2,59,101.00**	**2,16,690.68**
(ii)	**स्टाफ वेलफेयर रिजर्व (फुटनोट 2)**		
	प्रारंभिक शेष	3,394.31	297.14
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष में अंतरण	1,533.07	3,097.17
	घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि तथा लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष में अंतरण	141.38	-
	अंतिम शेष	**4,786.00**	**3,394.31**
(iii)	**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व रिजर्व (फुटनोट 3)**		
	प्रारंभिक शेष	122.45	122.45
	घटाएँ: उपयोग की गई राशि	-	-
	अंतिम शेष	**122.45**	**122.45**
(iv)	**रिजर्व फंड धारा 45–IC, आरबीआई, अधिनियम 1934 के अंतर्गत (फुटनोट 4)**		
	प्रारंभिक शेष	1,14,831.82	71,536.34
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष में अंतरण	27,588.43	43,295.49
	अंतिम शेष	**1,42,420.26**	**1,14,831.82**
(च)	**लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष**		
	प्रारंभिक शेष	2,69,357.17	1,38,724.60
	जोड़ें: कर पश्चात लाभ	1,37,942.17	2,16,477.44
	जोड़ें: स्टाफ वेलफेयर रिजर्व से अंतरण	141.38	-
	जोड़ें: डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से अंतरण	105.99	-
	घटाएँ: स्टाफ वेलफेयर रिजर्व में अंतरण	1,533.07	3,097.17
	घटाएँ: विशेष आरक्षित निधि में अंतरण – धारा 36(1)(viii), आयकर अधिनियम 1961	42,410.32	39,101.98
	घटाएँ: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन लाभ/(हानि)	(3.59)	350.31
	घटाएँ: रिजर्व फंड धारा 45–IC में अंतरण	27,588.43	43,295.49
	अंतिम शेष	**3,36,018.55**	**2,69,357.17**
	कुल	**7,89,816.97**	**6,39,468.30**

फुटनोट:

1 प्रतिभूति प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों के निर्गम पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

2 विशेष आरक्षित निधि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत भारत में अवसंरचना सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक वैधानिक आरक्षित निधि है।

3 कर्मचारी कल्याण आरक्षित निधि कर्मचारियों के बीच खेलकूद, सांस्कृतिक तथा अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है।

4 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किए जाने वाले सीएसआर व्यय के संबंध में सीएसआर आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया है। दिनांक 3 जुलाई 2015 के पत्र के माध्यम से सीएसआर आरक्षित निधि के सृजन को जारी रखने तथा उसके उपयोग के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर पर व्यय की जाने वाली राशि के अतिरिक्त, स्पष्टीकरण हेतु यह मामला सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को भेजा गया था। डीपीई से उत्तर अभी भी प्राप्त होना शेष है।

5 आरक्षित निधि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अनुसार बनाई जाती है।

नोट 20: ब्याज आय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर	
		31.03.2026	31.03.2025
क)	**ब्याज पर ऋण**		
(i)	प्रत्यक्ष उधार के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज	1,57,732.25	1,47,750.16
(ii)	पुनर्वित्त योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	1,45,294.96	1,43,395.92
(iii)	टेकआउट वित्तपोषण योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	1,53,110.74	1,52,159.19
(iv)	दंडात्मक ब्याज	209.64	171.43
(v)	अवसंरचना बॉन्ड एवं इनविट ऋणों पर ब्याज	1,55,197.59	78,653.78
ख)	**निवेश से ब्याज आय**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	45,355.25	37,394.89
ग)	**बैंकों में जमाराशियों पर ब्याज**	35,187.19	41,232.59
	कुल	**6,92,087.63**	**6,00,757.97**

नोट 21: शुल्क और कमीशन आय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
(i)	**अग्रिम शुल्क**	2,145.36	3,038.99
(ii)	प्रक्रिया शुल्क	207.00	356.00
(iii)	पूर्व भुगतान शुल्क	1,116.15	250.11
(iv)	ऋण संवृद्धि से शुल्क	195.00	451.07
(v)	अन्य शुल्क	1,497.55	1,530.71
	कुल	**5,161.07**	**5,626.89**

नोट 22: उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
	(क) लाभ या हानि – लाभ–हानि विवरण के माध्यम से (उचित मूल्य) पर मापे गए वित्तीय साधनों पर		
	(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-
	(ii) वित्तीय साधनों पर, जिन्हें लाभ–हानि विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर माप हेतु नामित किया गया है	(1,007.16)	12,254.58
	उचित मूल्य में हुए कुल शुद्ध लाभ/(हानि) (ख)	**(1,007.16)**	**12,254.58**
	उचित मूल्य में परिवर्तन*: (ग)		
	साकार	-	-
	असाकार	(1,007.16)	12,254.58
	उचित मूल्य में हुए कुल शुद्ध लाभ/(हानि) (ख) का (ग) से मिलान	**(1,007.16)**	**12,254.58**
	*इस अनुसूची में दर्शाए गए उचित मूल्य में परिवर्तन ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न परिवर्तनों के अतिरिक्त हैं।		

नोट 23: अन्य आय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
	अन्य		
(i)	अपलिखित ऋणों की वसूली	32,091.75	26,678.86
(ii)	सरकार द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा रसीदों का साकार मूल्य	-	16,834.35
(iii)	विदेशी मुद्रा लेन–देन एवं अनुवाद पर शुद्ध लाभ	-	-
(iv)	स्वैप सौदों पर लाभ	79,545.77	11,528.21
(v)	विविध आय	10,220.15	744.06
	कुल	**1,21,857.68**	**55,785.49**

नोट 24: वित्त लागत

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	
		31.03.2026	31.03.2025
क)	**उधारी पर ब्याज**		
(ii)	बैंक उधारी पर ब्याज	1,21,272.06	1,10,906.39
(iii)	बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण पर ब्याज	81,079.00	87,073.66
ख)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**	2,54,595.21	2,04,496.38
ग)	**अन्य ब्याज व्यय**		
i)	आयकर पर ब्याज	461.13	553.75
	कुल	**4,57,407.40**	**4,03,030.19**

नोट 25: शुल्क और कमीशन व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
(i)	सरकारी गारंटी शुल्क	4,879.81	4,671.57
(ii)	बांड शोधन व्यय	259.83	733.05
(iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	474.02	-
	कुल	**5,613.66**	**5,404.62**

नोट 26: वित्तीय लिखतों पर ह्रास

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	
		31.03.2026	31.03.2025
(i)	**ऋण**	(14,815.63)	(14,511.48)
(ii)	निवेश	(1,794.59)	(1,594.83)
(iii)	अनुत्पादक परिसंपत्तियों की ओर से किए गए व्यय	43.86	58.03
	कुल	**(16,566.36)**	**(16,048.29)**

नोट 27: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
(i)	**वेतन और मजदूरी**	6,901.58	6,992.49
(ii)	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	311.67	452.06
(iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	199.17	81.18
	कुल	**7,412.43**	**7,525.73**

नोट 28 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागतें	28.22	69.88
(ii)	मुद्रा और लेखन सामग्री	35.53	27.55
(iii)	विज्ञापन और प्रचार	72.83	40.18
(iv)	निदेशक की फीस, भत्ते और खर्चे	13.60	13.95
(v)	लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे	28.00	20.86
(vi)	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	733.79	331.23
(vii)	बीमा	1.81	4.24
(viii)	अन्य खर्चे		
क)	विदेशी मुद्रा लेनदेन और रूपांतरणों पर निवल हानि	1,36,613.51	22,735.84
ख)	अन्य व्यय	6,224.92	3,403.65
ग)	बट्टे खाते में डाली गई ऋण राशि (नोट 1(ख)(20(क)) देखें,	16,615.50	13,939.51
	कुल	**1,60,367.72**	**40,586.88**

नोट 1: 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अन्य टिप्पणियां

आईआईएफसीएल भारत में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिवासित और निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, प्लेट ए और बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

आईआईएफसीएल की स्थापना व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। स्थापना के बाद से, आईआईएफसीएल विशेष प्रयोजन माध्यम के जरिए व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना, जिसे सामान्यतः एसआईएफटीआई के रूप में संदर्भित किया जाता है, द्वारा शासित था। भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2026 के पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि एसआईएफटीआई अब आईआईएफसीएल या उसकी किसी भी सहायक कंपनी पर लागू नहीं है और कंपनी का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा नियामकीय ढांचे के अधीन परिचालन और वित्तीय निर्णय ले सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर 2013 को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – गैर–जमा – अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी–एनडी–आईएफसी) के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या एन–14.03288 जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल को सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने की अनुमति दी है।

(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार

1.1 लेखांकन परिपाटी: आईआईएफसीएल अपने वित्तीय विवरण गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के भाग III में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करता है। वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर और ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय इनके

क. अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां,

ख. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

ग. लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं

घ. परिभाषित लाभ योजनाएं उचित मूल्य पर मापी गई योजना परिसंपत्तियां

उपरोक्त सभी मदों का मापन संबंधित इंड एएस के अनुसार, जहाँ आवश्यक अथवा अनुमत हो, उचित मूल्य पर किया गया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं तथा सभी आंकड़े, जहाँ अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निकटतम रुपये लाख तक पूर्णांकित की गई हैं।

1.2 अनुमानों का उपयोग: सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार के लिए प्रबंधन को अनुमान और अवधारणा बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों और उनके प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यथ की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें परिणाम वास्तविक होते हैं।

आईआईएफसीएल ने रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भावी तथा अनुमान अनिश्चितता के अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में कोई अवधारणा नहीं बनाई है, जिससे अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देयताओं की अग्रणीत राशियों में महत्वपूर्ण समायोजन होने का जोखिम हो।

2. अनुपालन का विवरण

आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय की अवधारणा के आधार पर और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के तहत भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.111(ई) दिनांक 16 फरवरी 2015, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के तहत राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.365(ई) दिनांक 30 मार्च 2016 द्वारा अधिसूचित इंड एएस की आवश्यकताओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा समय–समय पर जारी अन्य लागू नियामकीय दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुरूप तैयार किए जाते हैं।

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को आम तौर पर तुलन–पत्र में सकल मूल्य के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। उन्हें केवल तभी ऑफसेट और निवल मूल्य के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, जब भावी घटना पर निर्भर हुए बिना मान्य राशियों को ऑफसेट करने के लिए बिना शर्त कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होने के अलावा, पक्षकार निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में निवल आधार पर निपटान करने का इरादा रखते हैं:

- सामान्य व्यवसाय कामकाज

- चूक की घटना
- आईआईएफसीएल और/या उसके समकक्षों के दिवालियापन या अशोधन क्षमता की घटना

मास्टर नेटिंग व्यवस्था (जैसे आईएसडीएएस) के साथ व्युत्पन्नी परिसंपत्तियों और देयताओं को केवल तभी निवल मूल्य पर प्रस्तुत किया जाता है जब वे उपर्युक्त सभी मानदंडों के लिए नेटिंग की पात्रता को पूरा करते हैं, न कि केवल चूक की स्थिति में।

4. आय/व्यय की मान्यता

4.1 परिशोधित लागत पर मापे गए सभी वित्तीय लिखतों, बिक्री हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत ब्याज–वहन करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों तथा एफवीटीपीएल के रूप में नामित वित्तीय लिखतों के लिए, ब्याज आय अथवा ब्याज व्यय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि के अनुसार मान्यता दी जाती है। इस गणना में वित्तीय लिखत की सभी अनुबंधात्मक शर्तों (जैसे अग्रिम भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखा जाता है तथा ऐसे सभी शुल्क एवं अतिरिक्त लागतें शामिल की जाती हैं जो सीधे तौर पर लिखत से संबंधित हों और ईआईआर का अभिन्न अंग हों, परंतु भविष्य की ऋण हानियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का वहन मूल्य ह्रास हानि के कारण कम किया जाता है, तब भी ब्याज आय को उसी ब्याज दर का उपयोग करते हुए मान्यता दी जाती है, जिसका उपयोग ह्रास हानि को मापने के लिए भविष्य के नकद प्रवाहों को छूट देने हेतु किया गया था।

4.2 स्वीकृत ऋणों पर अग्रिम शुल्क आय को उन मामलों में उपार्जन आधार पर आय माना जाएगा जहां आवंटित राशि पर ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4.3 कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार को व्यय के रूप में तब लेखांकित किया जाता है जब ऋण की निकासी ऋण करार के अनुसार स्वीकृत ऋण राशि से कम होती है।

4.4 उधारकर्ता के खातों में वसूली संबंधित ऋण करारों के अनुसार विनियोजित की जाती है।

4.5 बट्टे खाते में डाली गई ऋण परिसंपत्तियों से वसूली को वसूली प्राप्ति के वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

4.6 लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर लाभांश को उपार्जन आधार पर लेखांकित किया जाता है। हालाँकि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के बाद ही प्राप्त होता है।

4.7 पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय के 0.1% से अधिक नहीं है, उसे चालू वर्ष की आय व्यय माना जाएगा।

4.8 आंशिक ऋण संवर्धन गारंटी शुल्क को लेखा वर्ष में उपार्जन आधार पर तब मान्य किया जाता है, जब वसूली का युक्तिसंगत अधिकार स्थापित हो जाता है। अग्रिम रूप से प्राप्त कोई भी आंशिक ऋण संवर्धन गारंटी शुल्क स्थगित कर दिया जाता है और उसे उपार्जन अवधि में आय के रूप में मान्य किया जाता है।

4.9 अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट या किसी अन्य शुल्क सहित आय को तभी मान्य किया जाता है जब वह वास्तव में वसूल की जाती है। ऐसी कोई भी आय जो परिसंपत्ति के अनर्जक होने से पहले मान्य की गई हो और वसूल न की गई हो, को वापस कर दिया जाता है। अर्थात् लेखांकन से रिवर्स कर दिया जाता है।

4.10 आयकर रिफंड पर ब्याज को वास्तविक आधार पर लेखांकित किया जाता है, अर्थात आयकर प्रतिदाय प्राप्ति के वर्ष में इसे आय के रूप में माना जाता है।

5. वित्तीय लिखतें

5.1 मान्यता और प्रारंभिक मापन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक मान्यता निपटान तिथि पर करती है। किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है तथा यदि वह एफवीटीपीएल के अंतर्गत नहीं है, तो उसके अधिग्रहण अथवा निर्गम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लेन–देन लागत को भी इसमें जोड़ा जाता है।

5.2 वर्गीकरण:

क. वित्तीय परिसंपत्तियां:

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकदी समतुल्य, बैंक बैलेंस, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कंपनियों/कर्मचारियों को दिए गए ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम राशि, प्रतिभूति जमा वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर, किसी वित्तीय परिसंपत्ति को निम्नलिखित पर वर्गीकृत किया जाता है:

क. परिशोधित लागत:

वित्तीय लिखतों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जहां:

- उनके लिए ऐसी संविदात्मक शर्तें होती हैं, जो निर्दिष्ट तारीखों पर नकदी प्रवाह करती हैं, जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करती हैं, तथा
- वे एक ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने

के लिए धारण करके प्राप्त किया जाता है।

इन लिखतों को शुरू में उचित मूल्य और सीधे तौर पर आरोप्य लेनदेन लागतों पर मान्य किया जाता है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है। क्रेडिट ह्रास का मापन टिप्पणी 5.7 वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास में वर्णित तीन चरणीय अपेक्षित क्रेडिट ह्रास मॉडल पर आधारित है

ख. व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्यः

वित्तीय लिखतों को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, जहांः

- उनके लिए ऐसी संविदात्मक शर्तें होती हैं, जो निर्दिष्ट तारीखों पर नकदी प्रवाह करती हैं, जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करती हैं, तथा
- वे एक ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारित की जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने और वित्तीय परिसंपत्तियों का विक्रय, दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

इन लिखतों को शुरू में उचित मूल्य और सीधे तौर पर जिम्मेदार लेनदेन लागतों पर मान्य किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन से होने वाले लाभ और हानि को इक्विटी के एक अलग घटक के भीतर अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है। हानि या रिवर्सल, ब्याज राजस्व और विदेशी मुद्रा लाभ और हानि को लाभ और हानि में मान्य किया जाता है। निपटान के बाद, अन्य व्यापक आय में पहले से मान्य संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से आय विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट ह्रास का मापन तीन चरण अपेक्षित क्रेडिट ह्रास मॉडल पर आधारित है जैसा कि परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लागू होता है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

- व्यापार के लिए धारित मदें;
- संविदात्मक शर्तों वाली ऋण लिखत जो केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्य किया जाता गाता है, साथ ही लेन–देन की लागत को आय विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है है। इसके बाद, उन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और किसी भी लाभ या हानि को आय विवरण में मान्य किया जाता है। जहां एक वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहां प्रतिपक्षकार की ऋण योग्यता को दर्शाने के लिए एक ऋण मूल्यांकन समायोजन शामिल किया जाता है, जो ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है।

यापार के लिए धारित वित्तीय लिखतें

किसी वित्तीय लिखत को व्यापार के लिए धारित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि उसे मुख्य रूप से निकट अवधि में बेचने या पुनर्खरीद करने के उद्देश्य से अधिग्रहित या व्यय किया गया हो. या वह वित्तीय लिखतों के पोर्टफोलियो का हिस्सा हो, जिन्हें एक साथ प्रबंधित किया जाता है और जिसके लिए अल्पावधि लाभ लेने का साक्ष्य हो, या वह एक व्युत्पन्नी हो जोअर्हक हेज संबंध में न हो।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक मान्यता पर, आईआईएफसीएल अपरिवर्तनीय रूप से एक वित्तीय परिसंपत्ति को नामित कर सकता है जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीओसीआई पर एफबीटीपीएल के रूप में मापे जाने की आवश्यकताओं को पूरा करती है, यदि ऐसा करने से ऐसी कोई लेखांकन विसंगति समाप्त हो जाती है या महत्वपूर्ण रूप से कम हो जाती है जो अन्यथा उत्पन्न हो सकती है।

घ. इक्विटी लिखतें

ऐसे इक्विटी लिखतों में निवेश, जो न तो व्यापार के लिए धारित होते हैं और न ही आईआईएफसीएल द्वारा ऐसे व्यावसायिक संयोजन में आकस्मिक प्रतिफल के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, जिस पर इंड एएस 103 'व्यावसायिक संयोजन' लागू होता है, उचित मूल्य के माध्यम से अन्य व्यापक आय में मापे जाते हैं, जहां प्रबंधन द्वारा अपरिवर्तनीय विकल्प का चयन किया गया है। अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत राशियों को बाद में लाभ या हानि में अंतरित नहीं किया जाता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में तब तक मान्यता दी जाती है, जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के किसी भाग की वसूली का प्रतिनिधित्व न करता हो।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को एफवीटीपीएलके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

तदंतर माप

संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए धारित परिसंपत्तियां, जहां वे नकदी प्रवाह केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऋण निवेश पर लाभ या हानि जिसे बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, उसे लाभ या हानि में मान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति को विमान्य कर दिया जाता है या यह ह्रास हो जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके वित्त आय में शामिल किया जाता है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्य किए जाते हैं। हालांकि, कंपनी आय विवरण में ब्याज आय, ह्रास हानि और वापसी और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को मान्य करती है।

पुनर्वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों को उनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय उस अवधि के जब आईआईएफसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन कर देता है।

ख. वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं किसी अन्य इकाई को नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति सौंपने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का आदान–प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व है, जो कि कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हैं।

वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य में से लेनदेन लागत घटाकर मान्य किया जाता है, जो सीधे वित्तीय देयताओं के निर्गम पर आरोप्य होती है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक होता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत्तों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग हैं। आय (लेनदेन लागतों का निवल) और मोचन राशि के बीच किसी भी अंतर को ईआईआर का उपयोग करके उधार की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

तदंतर माप

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताओं को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।लाभ और हानि को लाभ या हानि विवरण में ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से और तब मान्य किया जाता है जब देयताओं को विमान्य कर दिया जाता है। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

संविदागत नकदी प्रवाह को केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान के रूप में परिभाषित करना:

इस मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, 'मूलधन' को प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ब्याज को धनराशि के समय मूल्य और किसी विशेष समय अवधि के दौरान बकाया मूल राशि से जुड़े ऋण जोखिम और अन्य बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों (जैसे चलनिधि जोखिम और प्रशासनिक लागत) के साथ–साथ लाभ मार्जिन के लिए प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है।

ग. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत ऐसे करार होते हैं, जिनका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित कीमत, सूचकांक या अन्य चर से प्राप्त होता है और इनमें सामान्यतः स्वैप, फॉरवर्ड दर करार, वायदा और विकल्प जैसे लिखत शामिल होते हैं। आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा में उधारी से संबंधित विदेशी विनिमय दर में होने वाले उतार–चढ़ाव के कारण उत्पन्न जोखिम को कम करने के लिए, जहां लागू हो, हेजिंग करारों की प्रकृति के व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों में प्रवेश करता है। इन करारों को तुलन–पत्र में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और इन्हें व्यापार के लिए रखे गए व्युत्पन्नी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, सिवाय इसके कि उन्हें किसी प्रभावी हेज संबंध के हिस्से के रूप में नामित किया गया हो और हेजिंग व्युत्पन्नी के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। किसी व्युत्पन्नी का वहन मूल्य करार की पूरी अवधि के दौरान उचित मूल्य पर पुनर्मापा जाता है। व्युत्पन्नी को तब परिसंपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है, जब उसका उचित मूल्य धनात्मक हो और देयता के रूप में तब दर्शाया जाता है, जब उसका उचित मूल्य ऋणात्मक हो।

क. जहाँ भी कंपनी ने वायदा संविदा या ऐसा लिखत, जो सारतः वायदा विनिमय संविदा की प्रकृति का है, किया है, वहां वायदा दर और वायदा विनिमय संविदा की तारीख को विनिमय दर के बीच के अंतर को इंड एएस–21 के अनुसार करार की अवधि के दौरान आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख. विदेशी मुद्रा ऋणों पर लिए गए हेज को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों (अर्थात् प्राकृतिक हेज) के समायोजन के बाद एफआईएफओ आधार पर समायोजित किया जाता है।

ग. ब्याज दर स्वैप सहित वायदा विनिमय संविदाओं को रद्द करने या उनका नवीनीकरण करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष की आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ. कंपनी द्वारा किए गए जेपीवाई येन में ब्याज दर स्वैप लेन–देन के संबंध में, कंपनी तुलन–पत्र की तारीख को बाजार मूल्यांकन हानि का प्रावधान करती है।

ड. वायदा संविदा के आरंभ के समय की हाजिर विनिमय दर और अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व की चुकौती के समय की हाजिर विनिमय दर के बीच अंतर के कारण होने वाले अधिशेष या घाटे को, हेजिंग करार के अनुसार प्रतिपक्ष से वसूल की गई या प्रतिपक्ष को भुगतान की गई राशि के रूप में, ऐसे ऋण की चुकौती के समय लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेन–देन है) और स्वैप करार (उपर्युक्त ऋणों से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि से बचाव हेतु) को अलग–अलग लेन–देन माना जाता है।

छ. विदेशी मुद्रा में उधारी को भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 21, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार पुनः वर्णित किया जाता है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जून 2015 में जारी "व्युत्पन्नी करारों के लेखांकन" संबंधी मार्गदर्शिका को कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया जा रहा है। रिपोर्टिंग तारीख को विदेशी मुद्रा में उधारी की राशि पर, पिछली रिपोर्टिंग तारीख से तथा अवधि के दौरान उधारी आहरण की तारीख से विनिमय दर में होने वाले किसी भी परिवर्तन को व्युत्पन्नी करारों के उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी जाती है। व्युत्पन्नी करारों का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षों द्वारा प्रदान किया जाता है।

मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार, नकदी प्रवाह हेज के तहत, हेजिंग लिखत को उचित मूल्य पर मापा जाता है, लेकिन कोई भी लाभ याहानि जिसे प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे इक्विटी में (जैसे कि नकदी प्रवाह हेज आरक्षित), मान्य किया जाता है। इसका उद्देश्य लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में अस्थिरता से बचना है जब हेज किए गए मद पर लाभ या हानि उसमें प्राप्त नहीं होती है।

5. विमान्यीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियां

आईआईएफसीएल किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब निरस्त कर देता है, जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या वह ऐसे लेनदेन में संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित कर देता है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ हस्तांतरित हो जाते हैं, या जिसमें आईआईएफसीएल स्वामित्व के सभी जोखिम और लाभ को न तो हस्तांतरित करता है और न ही अपने पास रखता है, और वह वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण भी नहीं रखता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऋण परिसंपत्तियों के मामले में:

(क) जिन परियोजनाओं में परियोजना प्राधिकरण द्वारा रियायत संविदा (सीए) समाप्त कर दिया गया है, उस खाते को उस वित्तीय वर्ष में विमान्य कर दिया जाता है, जिसमें संविदा समाप्त की गई है। है।

(ख) जिन परियोजनाओं में रियायतग्राही द्वारा रियायत संविदा (सीए) समाप्त कर दिया गया है, वहां मामले के तथ्यों और गुण–दोष के आधार पर ह्रास की जाती है।

(ग) ऐसे मामलों में, जहां परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों आदि की मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय परिसंपत्ति का कुछ मूल्य वसूल किया जा सकता है, वहां कमी की सीमा तक ह्रास की जाती है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के अनुसार लागू और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/131 डीबीआर संख्या बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017–18 दिनांक 12 फरवरी 2018 के अनुसरण में वापस ली गई मानी गई सामरिक ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), दबावग्रस्त आस्तियों की सतत संरचना की योजना (एस4ए), सामरिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना से बाहर या किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्गठन/निपटान प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर, किसी ऋण आस्ति को अपहचानित कर दिया जाता है, यदि उस ऋण परिसंपत्ति को 5 वर्ष से अधिक समय से अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है या परियोजना का अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन 4 वर्ष से अधिक समय से विलंबित है, जब तक कि ऋण आस्ति की बिक्री/वसूली के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध न हो।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य करने पर, परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि (या विमान्य की गई परिसंपत्ति के हिस्से को आबंटित अग्रणीत राशि) और (i) प्राप्त प्रतिफल (किसी नई परिसंपत्ति को प्राप्त करने में से किसी नई देयता को घटाकर) और (ii) ओसीआई में मान्यता प्राप्त किसी संचयी लाभ या हानि के योग के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

एफवीओसीआई के रूप में नामित इक्विटीनिवेश प्रतिभूतियों के संबंध में ओसीआई में मान्य कोई भी संचयी लाभ हानि, ऐसी प्रतिभूतियों के विमान्य होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य नहीं होती है। हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्तियों में कोई भी हित जो विमान्य करने के लिए योग्य है जिसे कंपनी द्वारा बनाया या बनाए रखा जाता है उसे एक अलग परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

आईआईएफसीएल किसी वित्तीय देयता को तब विमान्य करता है, जब उसके संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन या निरसन कर दिया जाता है अथवा वे समाप्त हो जाते हैं। ऐसी वित्तीय देयता, जिसका निपटान कर दिया गया है या जिसे किसी अन्य पक्ष को अंतरित किया गया है, की वहन राशि और भुगतान किए गए प्रतिफल, जिसमें अंतरित की गई कोई गैर–नकदी आस्ति या ग्रहण की गई देयताएं भी शामिल हैं, के बीच के अंतर को लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय या वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

किसी मौजूदा उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच ऐसे ऋण लिखतों का आदान–प्रदान, जिनकी शर्तें पर्याप्त रूप से भिन्न हैं, मूल वित्तीय देयता के निपटान और नई वित्तीय देयता की मान्यता के रूप में लेखांकित किया जाता है। इसी प्रकार, किसी मौजूदा वित्तीय

देयता या उसके किसी भाग की शर्तों में महत्वपूर्ण संशोधन (चाहे वह देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण हुआ हो या नहीं) को मूल वित्तीय देयता के निपटान और नई वित्तीय देयता की मान्यता के रूप में लेखांकित किया जाता है।

5.4 संशोधनः

वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि किसी वित्तीय परिसंपत्ति की शर्तों को संशोधित किया जाता है, तो कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है या नहीं। यदि नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर है, तो मूल वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गए माने जाते हैं। इस मामले में, मूल वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्य कर दिया जाता है और उचित मूल्य पर एक नई वित्तीय परिसंपत्ति को मान्य किया जाता है।

यदि परिशोधित लागत पर किए गए संशोधित परिसंपत्ति के नकदी प्रवाह में पर्याप्त अंतर नहीं है, तो संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्ति विमान्य नहीं होती है। इस मामले में, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना करती है और सकल वहन राशि को समायोजित करने से उत्पन्न राशि को लाभ और हानि के विवरण में संशोधन लाभ या हानि के रूप में मान्य करती है। वित्तीय परिसंपत्ति की सकल वहन राशि की पुनर्गणना पुनःनिर्धारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य के रूप में की जाएगी, जिसे वित्तीय परिसंपत्ति की मूल प्रभावी ब्याज दर (या खरीदी गई या उत्पन्न क्रेडिट ह्रास वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्रेडिट समायोजित प्रभावी ब्याज दर) या, जब लागू हो, संशोधित प्रभावी ब्याज दर पर छूट दी जाती है। यदि ऐसा संशोधन उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण किया जाता है, तो लाभ या हानि को हानि के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

5.5 उचित मूल्य मापन

वित्तीय लिखतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उचित मूल्य पर तुलन–पत्र में दर्शाया जाता है।

'उचित मूल्य' वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या किसी देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा, जो मापन की तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच व्यवस्थित लेनदेन में मुख्य या, इसकी अनुपस्थिति में, सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में होता है, जिस तक कंपनी की उस तिथि तक पहुंच होती है। देयता का उचित मूल्य उसके गैर–निष्पादन जोखिम को दर्शाता है।

जब ऐसा कोई उपलब्ध होता है, तो कंपनी उस लिखत के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य का उपयोग करके लिखत के उचित मूल्य को मापती है। एक बाजार को सक्रिय उस स्थिति में माना जाता है यदि परिसंपत्ति या देयता के लिए लेनदेन पर्याप्त आवृत्ति और मात्रा के साथ होता है ताकि निरंतर आधार पर मूल्य निर्धारण की जानकारी मिल सके।

यदि किसी सक्रिय बाजार में कोई उद्धृत मूल्य नहीं है, तो आईआईएफसीएल मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है जो प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को अधिकतम करता है और अवलोकनीय इनपुट के उपयोग को न्यूनतम करता है। चुनी गई मूल्यांकन तकनीक में वे सभी कारक शामिल होते हैं जिन्हें बाजार प्रतिभागी किसी लेनदेन का मूल्य निर्धारण करते समय ध्यान में रखते हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय लिखत के उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य आम तौर पर लेनदेन मूल्य अर्थात् दिए गए या प्राप्त किए गए प्रतिफल का उचित मूल्य होता है। यदि आईआईएफसीएल यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य लेनदेन मूल्य से भिन्न है और उचित मूल्य न तो किसी समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य द्वारा प्रमाणित है और न ही किसी ऐसे मूल्यांकन तकनीक पर आधारित है जिसके लिए किसी भी अप्राप्य इनपुट को माप के संबंध में महत्वहीन माना जाता है, तो वित्तीय लिखत को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मापा जाता है, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को स्थगित करने के लिए समायोजित किया जाता है। इसके बाद, उस अंतर को उचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

मांग विशेषता (जैसे मांग जमा) वाली वित्तीय देयता का उचित मूल्य मांग पर देय राशि है।

अनुद्धृत इक्विटी का उचित मूल्यांकन आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध जानकारी की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए नीचे दिए गए दृष्टिकोण, पदानुक्रम के क्रम में जिसमें वे दिखाई देते हैं, के आधार पर किया जाता हैः

क. कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों से निवेशित इकाई के विस्तृत मूल्य पर।

ख. यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध न हो तो एक रुपए पर।

अवसंरचना ऋण निधियों और वैकल्पिक निवेश निधियों की इकाइयों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश – ऋण एक्सपोजर के अंतरण संबंधी निदेश, 2021 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया है। 29 मार्च 2025 के संशोधन के परिणामस्वरूप, ऐसी प्रतिभूति रसीदों का समय–समय पर उस आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जो उक्त लिखतों को दिए गए वसूली मूल्यांकनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, ऐसी एसआर की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उपर्युक्त भा.रि.बैंक निदेशों के अनुपालन में संबंधित एआरसी द्वारा घोषित एनएवी के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

5.6 उचित मूल्य मापन के लिए मूल्यांकन तकनीकें

यह दर्शाने के लिए कि उचित मूल्य कैसे निकाले गए हैं, वित्तीय लिखतों को मूल्यांकन तकनीकों के पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- स्तर 1 के वित्तीय लिखत – वे वित्तीय लिखत, जिनमें मूल्यांकन में उपयोग किए गए इनपुट समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में उपलब्ध ऐसे अयोजित उद्धृत मूल्यों से प्राप्त होते हैं, जिन तक कंपनी की मापन तारीख को पहुंच होती है। कंपनी बाजारों को केवल तभी सक्रिय मानती है, जब समान परिसंपत्तियों या देयताओं की मात्रा और चलनिधि के संबंध में पर्याप्त व्यापारिक गतिविधियां हों और तुलन–पत्र की तारीख को बाध्यकारी तथा प्रयोग किए जा सकने वाले मूल्य उद्धरण उपलब्ध हों।
- स्तर 2 के वित्तीय लिखत – वे वित्तीय लिखत, जिनके मूल्यांकन में उपयोग किए गए और महत्वपूर्ण इनपुट, लिखत की पूरी अवधि के दौरान उपलब्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीयबाजार डेटा से प्राप्त होते हैं। ऐसे इनपुट में सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों या देयताओं के उद्धृत मूल्य, निष्क्रिय बाजारों में समान लिखतों के उद्धृत मूल्य और उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य अवलोकनीय इनपुट, जैसे ब्याज दरें और लब्धि वक्र, निहित अस्थिरताएं तथा क्रेडिट स्प्रोड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्ति की स्थिति या स्थान अथवा मूल्यांकित लिखत के साथ तुलनीय मदों से उसकी संबद्धता की सीमा के लिए समायोजन आवश्यक हो सकते हैं। हालांकि, यदि ऐसे समायोजन ऐसे अप्रेक्षणीय इनपुट पर आधारित हैं, जो संपूर्ण मापन के लिए महत्वपूर्ण हैं, तो आईआईएफसीएल लिखतों को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।
- स्तर 3 के वित्तीय लिखत – वे वित्तीय लिखत, जिनमें एक या अधिक ऐसे अप्रेक्षणीय इनपुट शामिल होते हैं, जो समग्र रूप से मापन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।

5.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास

आईआईएफसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) को मापने के लिए तीन–चरणीय दृष्टिकोण लागू करता है, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है:

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत और उचित मूल्य पर मापे गए ऋण लिखत;
- ऋण प्रतिबद्धताएं; और
- वित्तीय गारंटी संविदाएं।

इक्विटी निवेश पर कोई ईसीएल मान्यता प्राप्त नहीं है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में परिवर्तन के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है:

चरण 1: 12 माह का ईसीएल

वे सभी जोखिम जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है तथा जो आरंभ से ही ऋण ह्रास नहीं हैं, उन्हें इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

चरण 2: आजीवन ईसीएल– ऋण–ह्रासित नहीं

वे सभी जोखिम जिनमें प्रारंभिक मान्यता के पश्चात ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, किंतु जो ऋण–ह्रासित नहीं हैं, इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। 30 दिनों से अधिक बकाया को ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि माना जाता है।

चरण 3: आजीवन अपेक्षित ऋण हानि – ऋण–ह्रासित

वे सभी जोखिम, जिन्हें तब ऋण–ह्रासित आंका जाता है जब एक या अधिक ऐसी घटनाएँ घटित हो चुकी हों जिनका उस परिसंपत्ति के अनुमानित भावी नकद प्रवाहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, इस चरण में वर्गीकृत किए जाते हैं। जिन जोखिमों को ऋण–ह्रासित माना जाता है, उनके लिए आजीवन ईसीएल मान्यता दी जाती है तथा ब्याज आय की गणना सकल वहन मूल्य के बजाय परिशोधित लागत (प्रावधान घटाकर) पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके की जाती है।

ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रावधान आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी, जो निम्नानुसार है

i. मानक परिसंपत्तियाँ: वर्षांत पर बकाया ऋण राशि, जिसमें देय न हुई परंतु संचित ब्याज राशि भी शामिल है, पर 0.40% की दर से सामान्य प्रावधान किया जाता है।

ii. उप–मानक परिसंपत्तियाँ: कुल बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की दर से सामान्य प्रावधान किया जाता है।

iii. संदिग्ध परिसंपत्तियाँ

(क) अग्रिम की वह राशि, जो उस प्रतिभूति के वसूल योग्य मूल्य से कवर नहीं है, जिस पर कंपनी का वैध प्रत्यावर्तन अधिकार है, उसके लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि तक परिसंपत्ति संदिग्ध बनी रही है, उसके आधार पर सुरक्षित भाग अर्थात् बकाया राशि के अनुमानित वसूल योग्य मूल्य के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है:

अवधि जिसके लिए आस्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30
तीन वर्ष से अधिक	50

iv. हानि परिसंपत्तियाँ

सम्पूर्ण परिसंपत्ति को बट्टे खाते में दिया जाता है। तथापि, यदि किसी भी कारणवश परिसंपत्ति को खातों में बनाए रखने की अनुमति दी जाती है, तो बकाया संपूर्ण राशि पर 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाता है।

v. पुनर्गठित ऋण परिसंपत्तियाँ

निम्नलिखित मामलों में, पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें उचित मूल्य में कमी (डिमिन्यूशन इन फेयर वैल्यू) पर प्रावधान भी शामिल है:

(क) 24 जनवरी 2014 से प्रभावी रूप से पुनर्गठित परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान 5% की दर से किया जाएगा।

(ख) 23 जनवरी 2014 को विद्यमान पुनर्गठित बकाया ऋणों का स्टॉक (सभी कंपनियों के लिए) के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, प्रावधान 5% की दर से किया जाएगा।

वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण हेतु चरण का निर्धारण

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता के पश्चात जोखिमों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के आधार पर तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण रिपोर्टिंग तिथि पर तथा प्रारंभिक मान्यता की तिथि पर अपेक्षित जीवनकाल के दौरान चूक होने के जोखिम की तुलना करके किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु कंपनी ऐसी युक्तिसंगत एवं समर्थनीय जानकारी पर विचार करती है, जो प्रासंगिक हो तथा बिना अत्यधिक लागत या प्रयास के उपलब्ध हो।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आने पर कोई जोखिम चरण 1 से चरण 3 तक स्थानांतरित हो सकता है। यदि किसी बाद की अवधि में परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है और पूर्व में आंकी गई ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि उलट जाती है, तो ऐसा जोखिम पुनः निम्न चरण में आ सकता है। 30 दिनों से कम बकाया वाले जोखिमों को चरण 1 में माना जाता है।

चरण 1 में मानी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान 12–माह अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के आधार पर किया जाता है। जबकि चरण 2 एवं चरण 3 में मानी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान आजीवन अपेक्षित ऋण हानि मॉडल के आधार पर गणना किया जाता है। जब किसी परिसंपत्ति की वसूली संभव नहीं रहती, तो उसे संबंधित प्रावधान के विरुद्ध मान्यता से हटाया जाता है। ऐसे परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्ति सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने तथा हानि की राशि निर्धारित किए जाने के पश्चात की जाती है।

तथापि, यह एक प्रतिवाद योग्य धारणा है कि चूक 90 दिनों से अधिक बकाया होने से पहले नहीं होता है, जब तक कि इकाई के पास ऐसी युक्तिसंगत एवं समर्थनीय जानकारी उपलब्ध न हो, जो यह दर्शाती हो कि किसी विशेष वित्तीय साधन के लिए अधिक विलंबित चूक मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त चूक की परिभाषा सभी वित्तीय लिखतों पर समान रूप से लागू की जाती है, जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो जाए जो यह दर्शाए कि किसी विशिष्ट वित्तीय लिखत के लिए कोई अन्य चूक परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, यदि निम्नलिखित में से कोई भी घटना घटित होती है, तो खाते को ऋण–ह्रासित माना जाएगा और उसे चरण 3 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा:

- खाता 90 दिनों से अधिक बकाया हो;
- आईआईएफसीएल द्वारा ऋण दायित्व के संकटग्रस्त पुनर्संरचनाकरण को सहमति दी गई हो, जहाँ मूलधन, ब्याज अथवा (जहाँ लागू हो) शुल्क की महत्वपूर्ण माफी अथवा स्थगन के कारण वित्तीय दायित्व में कमी होने की संभावना हो।

बकाया दिनों की गणना उस अवधि के आधार पर की जाती है, जितने दिनों तक ब्याज औरध्या मूलधन का भुगतान नहीं किया गया हो, कोई बिल अतिदेय बना रहा हो, कोई खाता निरंतर स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक बना रहा हो, अथवा खाते मेंउपलब्ध क्रेडिट राशि खाते पर लगाए गए ब्याज से कम हो।

निम्न ऋण जोखिम की धारणा

इंड एएस 101 "वित्तीय लिखत" के अनुसार,''अनुच्छेद 5.5.10 के प्रयोजनों के लिए किसी वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम को निम्न माना जाता है, यदि उस वित्तीय लिखत में चूक का जोखिम कम हो, उधारकर्ता के पास निकट अवधि में अपने अनुबंधात्मक नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की सुदृढ़ क्षमता हो, तथा दीर्घ अवधि में आर्थिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन होने पर भी, आवश्यक नहीं कि उधारकर्ता की अपने अनुबंधात्मक नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हो (अनुच्छेद बी5.5.22)। इसके अतिरिक्त, यद्यपि इसमें 'निवेश–ग्रेड' की बाह्य रेटिंग को निम्न ऋण जोखिम का उदाहरण बताया गया है, तथापि यह भी स्वीकार किया गया है कि किसी वित्तीय साधन को निम्न ऋण जोखिम वाला माने जाने के लिए उसका बाह्य रूप से रेटेड होना अनिवार्य नहीं है (अनुच्छेद बी5.5.23)।

तदनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी वित्तीय लिखत को निम्न ऋण जोखिम वाला माना जाता है:

- शून्य अप्रत्याशित हानि जैसा कि शून्य विनियामक जोखिम भार द्वारा संकेतित जहाँ विनियामक जोखिम भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि 0% होती है, वहाँ अपेक्षित हानि भी शून्य होगी। ऐसे मामलों में अपेक्षित ऋण हानि शून्य होगी। इस श्रेणी के परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण हैं–घरेलू संप्रभु तथा अंतरराष्ट्रीय रेटिंग "एए" या उससे बेहतर वाले विदेशी संप्रभुता
- निम्न अप्रत्याशित हानि जैसा कि 20% विनियामक जोखिम भार द्वारा संकेतितरू 20% जोखिम भार से संबंधित पोर्टफोलियो के लिए अप्रत्याशित हानि कम होती है, अतः अपेक्षित हानि भी अत्यंत कम होती है। तथापि, ईसीएल शून्य से भिन्न हो सकती है, अथवा अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शा सकते हैं कि ऐसे परिसंपत्ति वर्ग/पोर्टफोलियो के लिए चूक दर शून्य है। इस श्रेणी के परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण हैं जैसा कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग "ए" वाले विदेशी संप्रभु, घरेलू अनुसूचित आईआईएफसीएल (जो पूंजी पर्याप्तता की विनियामक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, उन्हें निम्न ऋण जोखिम वाला नहीं माना जाएगा), बाह्य रूप से रेटेड घरेलू "एएए" कॉरपोरेट्स तथा स्टाफ ऋण। इन पोर्टफोलियो के लिए प्रेक्षित चूक दरें भी शून्य पाई गई हैं।

इन विवरणों के प्रयोजनार्थ, सभी स्टाफ ऋणों को निम्न ऋण जोखिम वाला माना गया है।

पोर्टफोलियो में प्रयुक्त विभाजन का स्तर

विभाजन, जोखिम मापदंडों के अनुप्रयोग के उद्देश्य से आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) मॉडलों के अनुरूप किया गया है। तथापि, भविष्य उन्मुख आकलनों के लिए, आईआईएफसीएल कुछ उप–पोर्टफोलियो को व्यापक श्रेणियों में समूहित कर सकता है अथवा कुछ मामलों में सामान्य जोखिम कारकों के आधार पर उन्हें उप–खंडों में विभाजित कर सकता है।

ईसीएल का मापन

अपेक्षित ऋण हानियाँ निष्पक्ष तथा संभाव्यता–भारित अपेक्षित हानि के अनुमानों से व्युत्पन्न की जाती हैं और निम्नानुसार मापी जाती हैं

- रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण–ह्रासित न होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान होने वाली सभी नकद कमी के वर्तमान मूल्य के रूप में, जिसे प्रभावी ब्याज दर से छूटित किया जाता है। नकद कमी से आशय अनुबंध के अनुसार आईआईएफसीएल को देय नकद प्रवाह और आईआईएफसीएल द्वारा प्राप्त होने की अपेक्षित नकद प्रवाह के बीच का अंतर है।
- रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण–ह्रासित वित्तीय परिसंपत्तियाँः सकल वहन मूल्य और प्रभावी ब्याज दर से छूटित अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के रूप में।
- अप्रयुक्त ऋण प्रतिबद्धताएँः उस अंतर के वर्तमान मूल्य के रूप में, जो उस स्थिति में आईआईएफसीएल को देय अनुबंधात्मक नकद प्रवाह और आईआईएफसीएल द्वारा प्राप्त होने की अपेक्षित नकद प्रवाह के बीच होता है, यदि प्रतिबद्धता आहरित की जाती है।
- वित्तीय गारंटी अनुबंध धारक को प्रतिपूर्ति हेतु अपेक्षित भुगतानों से, आईआईएफसीएल द्वारा अपेक्षित वसूली योग्य राशियों को घटाने के पश्चात शेष राशि के रूप में।

अपेक्षित ऋण हानियाँ लाभ–हानि विवरण में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते के माध्यम से मान्यता दी जाती हैं। अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण साधनों के मामले में, ईसीएल का मापन परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू त्रि–स्तरीय दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है। आईआईएफसीएल प्रावधान शुल्क को लाभ–हानि विवरण में मान्यता देता है तथा उसके समतुल्य राशि को अन्य समग्र आय में मान्यता देता है इस प्रक्रिया में तुलन पत्र में परिसंपत्ति के वहन मूल्य में कोई कमी नहीं की जाती है।

ह्रासित आरक्षित निधिः

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2019–20/170 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार, आईआईएफसीएल को इंड एएस के अंतर्गत अपेक्षित ह्रास भत्ते धारण करने होंगे। साथ ही, समानांतर रूप से आईआईएफसीएल आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान (आईआरएसीपी) से संबंधित प्रचलित सावधानीपूर्ण मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण बनाए रखेगा तथा उधारकर्ता/लाभार्थी–वार वर्गीकरण, मानक एवं पुनर्संरचित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, एनपीए की आयु–निर्धारण आदि सहित प्रावधानों की गणना करेगा।

जहाँ इंड एएस 109 के अंतर्गत निर्धारित ह्रास भत्ता, आईआरएसीपी के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) से कम हो, वहाँ आईआईएफसीएल को कर पश्चात निवल लाभ या हानि से उस अंतर की राशि एक पृथक 'ह्रास आरक्षित निधि' में अंतरण करना होगा। 'ह्रास आरक्षित निधि' में शेष राशि को विनियामक पूंजी के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित से किसी भी प्रकार की निकासी अनुमत नहीं होगी।

5.8 त्वरित प्रावधानीकरण

आईआईएफसीएल, एक विवेकपूर्ण ऋणदाता के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों/इंड एएस 109 के अनुसार अपेक्षित ऋण हानि की गणना के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर प्रतिभूतिकृत/अप्रतिभूतिकृत भागों पर निर्धारित प्रतिशत लागू करते हुए की जाने वाली सामान्य प्रावधान प्रक्रिया के अतिरिक्त, अपेक्षित वसूली परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण–दर–प्रकरण त्वरित प्रावधान पर भी विचार करता है।

ऐसे असाधारण मामलों में, जहाँ प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान पर्याप्त प्रतीत होता है, किंतु प्रबंधन के मत में ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हों जो वसूली की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हों, वहाँ त्वरित प्रावधान का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसे मामलों में, प्रबंधन विवेकपूर्ण उपाय के रूप में त्वरित प्रावधान पर प्रकरण–दर–प्रकरण निर्णय लेता है। त्वरित प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित मानकों पर निर्भर करता है:

- परियोजना की स्थिति।
- प्रवर्तक की निधि प्रविष्ट करने की क्षमता।
- उपलब्ध मूर्त प्रतिभूति, नकद प्रवाह एवं रियायतें।
- वसूली हेतु संघ द्वारा उठाए गए कदम।
- प्रबंधन की धारणा।

उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित खाते में किया जाने वाला प्रावधान 10% से 100% तक हो सकता है।

6. पट्टा

परिचालन पट्टे (ऑपरेटिंग लीज) के अंतर्गत देय पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार (स्ट्रेट–लाइन बेसिस) पर लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

7. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को अधिग्रहण लागत पर दर्शाया जाता है, जिसमें दैनिक रखरखाव से संबंधित लागतें शामिल नहीं होती हैं, तथा उससे संचित मूल्यह्रास और मूल्य में संचित ह्रास घटाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को निपटान के समय अथवा जब उनके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता से हटाया जाता है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्ति पर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना निपटान से प्राप्त निवल आय और परिसंपत्ति के वहन मूल्य के अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति की मान्यता समाप्ति की तिथि पर लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

8. अमूर्त परिसंपत्तियाँ एवं विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

पृथक रूप से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता के समय उनकी लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित अमूर्तन तथा, यदि कोई हो, संचित ह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

पहले से पूंजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर किया गया पश्चातवर्ती व्यय तब पूंजीकृत किया जाता है, जब वह किसी विद्यमान परिसंपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों में वृद्धि करता हो, तथा ऐसे व्यय का अमूर्तन भावी आधार पर किया जाता है।

आंतरिक उपयोग हेतु अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) और जिससे महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की अपेक्षा हो, को तब अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जब वह उपयोग हेतु तैयार हो जाए।

विकास पर किया गया व्यय, यदि इंड एएस 38 जैसा कि 'अमूर्त परिसंपत्तियाँ' के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है अन्यथा, ऐसे व्यय को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर अथवा जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता से हटाया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्ति पर उत्पन्न लाभ या हानि को निपटान से प्राप्त शुद्ध आय और परिसंपत्ति के वहन मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा परिसंपत्ति की मान्यता समाप्ति के समय लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

9. मूल्य ह्रास/परिशोधन

मूल्यह्रास की गणना संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की लागत पर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान अवशिष्ट मूल्य तक लिखित अवमूल्यन पद्धति के अनुसार की जाती है। उपयोगी जीवन का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार किया जाता है।

आईआईएफसीएल के कार्यालय परिसर का अमूर्तन 30 वर्षों की पट्टा अवधि के दौरान किया गया है।

परिशोधन की गणना अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान अवशिष्ट मूल्य तक घटाने हेतु सीधी रेखा पद्धति के अनुसार की जाती है। पट्टे पर प्राप्त परिसंपत्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवन की गणना पट्टा समाप्ति अवधि के आधार पर की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन सीमित अथवा असीमित के रूप में किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का अमूर्तन उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए अमूर्तन अवधि एवं अमूर्तन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कम–से–कम एक बार की जाती है। उपयोगी जीवन में अपेक्षित परिवर्तन अथवा परिसंपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की उपभोग की अपेक्षित प्रवृत्ति में परिवर्तन को, यथोचित रूप से अमूर्तन अवधि या पद्धति में परिवर्तन करके लेखांकित किया जाता है, जिन्हें लेखा अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों पर अमूर्तन व्यय को आय विवरण में एक पृथक मद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अनुसूची *III* के अनुसार उपयोगी जीवन

परिसंपत्ति का विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	30 वर्ष	-
कंप्यूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ		
लैपटॉप / कंप्यूटर	3 वर्ष	5%
सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	5%
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10 वर्ष	5%
वाहन	8 वर्ष	5%
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5 वर्ष	5%

10. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

आईआईएफसीएल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करता है कि किसी गैर–वित्तीय परिसंपत्ति में ह्रास का कोई संकेत है या नहीं। इस आकलन के अनुसार निर्धारित ह्रास को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

11. लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी)

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, आईआईएफसीएल बैंकों को आमतौर पर कंसोर्टियम सदस्यों के पक्ष में लाभार्थियों के हित में ऋणदाताओं की ओर से लेटर ऑफ क्रेडिट / वित्तीय गारंटी जारी किए जाने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करता है। एलओसी को प्रारंभिक रूप से वित्तीय विवरणों में 'अन्य दायित्व' के अंतर्गत उचित मूल्य पर, अर्थात् प्राप्त प्रीमियम के बराबर, मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, प्रत्येक गारंटी के अंतर्गत आईआईएफसीएल के दायित्व का मापन निम्नलिखित में से जो अधिक हो, उसके आधार पर किया जाता है जैसा कि प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि, जिसमें से आय विवरण में मान्यता प्राप्त संचयी परिशोधन घटाया गया हो अथवा गारंटी के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय दायित्व के निपटान हेतु आवश्यक व्यय का सर्वोत्तम अनुमान। वित्तीय गारंटियों से संबंधित दायित्व में किसी भी वृद्धि को आय विवरण में ऋण हानि व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्राप्त प्रीमियम को गारंटी की अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर आय विवरण में निवल शुल्क एवं कमीशन आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

12. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधान तब मान्यता प्राप्त किए जाते हैं, जब आईआईएफसीएल पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा निहित) विद्यमान हो, उस दायित्व के निपटान हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो, तथा दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जहाँ धन के समय–मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, वहाँ आईआईएफसीएल दायित्व–विशिष्ट वर्तमान दरों को प्रतिबिंबित करने वाली कर–पूर्व छूट दर पर अपेक्षित नकद प्रवाहों को छूटित कर प्रावधान का स्तर निर्धारित करता है। किसी भी प्रावधान से संबंधित व्यय को, किसी भी प्रतिपूर्ति को घटाकर, लाभ–हानि विवरण में अन्य परिचालन व्ययों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

आकस्मिक देयता तब मान्यता एवं प्रकटीकरण किया जाता है, जब:

क. किसी पूर्व घटना से उत्पन्न संभावित दायित्व हो, जिसका अस्तित्व समूह के नियंत्रण से बाहर किसी एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने अथवा न होने से पुष्ट होगा अथवा

ख. किसी पूर्व घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व हो, जिसे इसलिए मान्यता नहीं दी गई हो क्योंकि उसके निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

जहाँ किसी संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व के संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना अत्यंत दूरस्थ हो, वहाँ न तो कोई प्रावधान किया जाता है और न ही कोई प्रकटीकरण।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं की जाती हैं। तथापि, आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर आकलन किया जाता है और यदि यह लगभग सुनिश्चित हो जाए कि आर्थिक लाभों का अंतःप्रवाह होगा, तो जिस अवधि में यह परिवर्तन होता है, उसी अवधि में परिसंपत्ति तथा संबंधित आय को मान्यता दी जाती है।

प्रतिबद्धताएँ उन बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को सम्मिलित करती हैं, जिनके अंतर्गत किसी ग्राहक को ऋण प्रदान करने हेतु किए गए समझौतों के अनुसार ऋण विस्तार किया जाना है, बशर्ते कि अनुबंध में स्थापित किसी भी शर्त का उल्लंघन न हुआ हो।

13. आय पर कर

13.1 चालू कर

चालू कर परिसंपत्तियाँ एवं देयता, वर्तमान तथा पूर्ववर्ती वर्षों के लिए, उस राशि पर मापे जाते हैं, जिसके कर प्राधिकरणों से वसूल किए जाने अथवा उन्हें भुगतान किए जाने की अपेक्षा हो। इस राशि की गणना के लिए प्रयुक्त कर दरें एवं कर कानून वे होते हैं, जो रिपोर्टिंग तिथि तक भारत में, जहाँ आईआईएफसीएल संचालित होता है तथा करयोग्य आय अर्जित करता है, अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित हों।

इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित चालू आयकर को इक्विटी में ही मान्यता दी जाती है, न कि लाभ–हानि विवरण में। प्रबंधन समय–समय पर कर रिटर्न में लिए गए रुखों का मूल्यांकन करता है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहाँ लागू कर विनियमों की व्याख्या आवश्यक हो, तथा जहाँ उपयुक्त हो, वहाँ प्रावधान स्थापित करता है।

13.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वहन मूल्यों और करयोग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त उनके संबंधित कर आधारों के बीच उत्पन्न अस्थायी अंतरों पर मान्यता दी जाती है तथा इसका लेखांकन तुलन पत्र देयता पद्धति के अनुसार किया जाता है।आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ सामान्यतः सभी कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त की जाती हैं, जहाँ यह संभाव्य हो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिनके विरुद्ध ऐसे कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियाँ एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट समायोजित किए जा सकेंगे। आस्थगित कर परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की प्रत्येक तुलन–पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक कम कर दी जाती है, जिस सीमा तक यह संभावना नहीं रहती है कि पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं देयता उन कर दरों पर मापे जाते हैं, जिनके उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा हो, जिसमें दायित्व का निपटान किया जाएगा अथवा परिसंपत्ति को साकार किया जाएगा, और यह मापन उन कर दरों (तथा कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है, जो तुलन पत्र तिथि तक अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित हों।

14. प्रति शेयर अर्जन

आईआईएफसीएल अपनी साधारण इक्विटी शेयरों के लिए मूल तथा परिशोधित प्रति शेयर आय (ईपीएस) का प्रस्तुतीकरण करता है। मूल ईपीएस की गणना, आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य लाभ अथवा हानि को, अवधि के दौरान प्रचलित साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। परिशोधित ईपीएस का निर्धारण, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य लाभ अथवा हानि तथा प्रचलित साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या को, सभी परिशोधनकारी संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित करके किया जाता है, जिनमें कर्मचारियों को प्रदान किए गए शेयर विकल्प शामिल हैं।

15. कर्मचारी हितलाभ

15.1 सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस लेखा अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, उनके बिना छूट वाली मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

15.2 कर्मचारियों के वेतन से कटौती किए गए भविष्य निधि अंशदान तथा उस पर नियोक्ता का अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा किया जाता है।

15.3 परिभाषित अंशदान योजनाओं के अंतर्गत एनपीएस से संबंधित कर्मचारी लाभों को योजना में योगदान हेतु कंपनी के छूट रहित दायित्व के आधार पर मान्यता दी जाती है। यह अंशदान आईडीबीआई बैंक, जो एनपीएस सुविधा के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदाता है, को भुगतान किया जाता है तथा संबंधित अवधि के लिए व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

15.4 सेवा–उपरांत तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवाएँ प्रदान की गई हों। यह व्यय देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर, बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है।

15.5 सेवांत लाभ को तत्काल व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

15.6 बीमांकिक मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ अथवा हानि को, जिस अवधि में वे घटित होती हैं, उसी अवधि में अन्य समग्र आय में मान्यता दी जाती है।

15.7 कर्मचारी लाभ दायित्वों, यथा बीमारी अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत तथा चिकित्सा सहायता योजना के लिए, रिपोर्टिंग तिथि तक की अवधि हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

15.8 ग्रेच्युटी का प्रावधान, एलआईसी की समूह ग्रेच्युटी योजना के अंतर्गत आईआईएफसीएल एम्प्लॉइज ग्रुप ग्रेच्युटी फंड (ट्रस्ट) के माध्यम से एलआईसी को देय राशि के आधार पर किया गया है।

15.9 अवकाश नकदीकरण का प्रावधान एलआईसी की समूह अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत देय राशि के आधार पर किया गया है।

15.10 जहाँ नियुक्ति की शर्तों के अनुसार लागू हो, वहाँ कार्यकारी निदेशकों के लिए अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी तथा बीमारी अवकाश के प्रावधान का उपार्जन अनुमानित देयता की राशि के आधार पर किया गया है।

16. महत्वपूर्ण लेखांकन संबंधी अवधारणाएं एवं अनुमान

आईआईएफसीएल की लेखा नीतियों के अनुप्रयोग में निर्णय, अनुमान एवं धारणाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि भिन्न धारणाएँ अथवा अनुमान अपनाए जाते, तो परिणामी मूल्य भिन्न होते, जिससे आईआईएफसीएल की निवल परिसंपत्तियों एवं आय पर प्रभाव पड़ता। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की गई धारणाएँ उस तिथि पर उपलब्ध सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित होती हैं। यद्यपि आईआईएफसीएल के पास ऐसे आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि अनुमानों का मापन विश्वसनीय रूप से किया जाए, तथापि वास्तविक राशियाँ इन अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं। अनुमानों एवं अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों में किए गए संशोधनों को उस अवधि में तथा उन भविष्य की अवधियों में मान्यता दी जाती है, जिन पर ऐसे संशोधनों का प्रभाव पड़ता है। वे लेखा नीतियाँ, जो निर्णय, अनुमान एवं धारणाओं के उपयोग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं, निम्नानुसार निर्दिष्ट की गई हैं।

उचित मूल्य मापन

वित्तीय लिखतों का एक महत्वपूर्ण भाग तुलन पत्र में उचित मूल्य पर वहन किया जाता है। उचित मूल्य वह मूल्य है, जो मापन तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच सुव्यवस्थित लेन–देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त किया जाएगा अथवा किसी दायित्व के हस्तांतरण हेतु भुगतान किया जाएगा। जहाँ किसी वित्तीय परिसंपत्ति या देयता का वर्गीकरण उसे उचित मूल्य पर मापे जाने का परिणाम देता है, वहाँ यथासंभव उचित मूल्य का निर्धारण उस सर्वाधिक लाभकारी सक्रिय बाजार में उद्धृत बोली या प्रस्ताव मूल्य के संदर्भ से किया जाता है, जिस तक आईआईएफसीएल की तत्काल पहुँच हो। आवश्यकतानुसार, उचित मूल्य में ऋण जोखिम के लिए समायोजन भी सम्मिलित किया जाता है। किसी सक्रिय बाजार में उद्धृत शुद्ध खुली स्थिति, जो एक वित्तीय देयता हो, के लिए उचित मूल्य वर्तमान प्रस्ताव मूल्य तथा किसी वित्तीय परिसंपत्ति के लिए बोली मूल्य होता है, जिसे धारित अथवा निर्गत साधन की इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहाँ किसी विशेष परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाजार उपलब्ध न हो, वहाँ आईआईएफसीएल उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु मूल्यांकनतकनीकों का उपयोग करता है, जिनमें हाल के स्वतंत्र लेन–देन से प्राप्त लेन–देन मूल्य, छूटित नकद प्रवाह विश्लेषण, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल तथा अन्य मूल्यांकन तकनीकें शामिल हैं, जो रिपोर्टिंग तिथि पर विद्यमान बाजार परिस्थितियों एवं जोखिमों पर आधारित होती हैं। इस प्रक्रिया में, उचित मूल्य का अनुमान ऐसी मूल्यांकन तकनीक के माध्यम से किया जाता है, जिसमें अवलोकनीय बाजार इनपुट्स काअधिकतम उपयोग तथा इकाई–विशिष्ट इनपुट्स पर न्यूनतम निर्भरता हो। प्रारंभिक मान्यता के समय किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य सामान्यतः लेन–देन मूल्य (अर्थात् दी गई या प्राप्त की गई प्रतिफल राशि का उचित मूल्य) होता है, जब तक कि उस साधन का उचित मूल्य उसी साधन में अन्य अवलोकनीय वर्तमान बाजार लेन–देन से तुलना द्वारा (बिना किसी संशोधन या पुनर्पैकेजिंग के) सिद्ध न हो, अथवा ऐसी मूल्यांकन तकनीक पर आधारित न हो, जिसके चर केवल अवलोकनीय बाजारों के आंकड़ों को सम्मिलित करते हों। जब ऐसा साक्ष्य उपलब्ध होता है, तब आईआईएफसीएल प्रारंभिक मान्यता (अर्थात् प्रथम दिन) पर लेन–देन मूल्य और उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ–हानि विवरण में मान्यता देता है।

ऋणों एवं अग्रिमों पर ह्रास हानि

ऋणों एवं अग्रिमों के लिए ह्रास हानि का निर्धारण करते समय भावी नकद प्रवाहों की राशि एवं समय–निर्धारण के आकलन में प्रबंधन द्वारा निर्णय (जजमेंट) की आवश्यकता होती है। इन नकद प्रवाहों के अनुमान में आईआईएफसीएल उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति तथा प्रतिभूति के शुद्ध वसूल योग्य मूल्य के संबंध में निर्णय करता है। ये अनुमान अनेक कारकों के संबंध में की गई धारणाओं पर आधारित होते हैं तथा वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में क्षतिग्रस्तता भत्ते में परिवर्तन हो

सकता है। ह्रास का सामूहिक आकलन ऋण पोर्टफोलियो से संबंधित आंकड़ों (जैसे ऋण गुणवत्ता, बकाया स्तर, ऋण उपयोग, ऋण–से–प्रतिभूति अनुपात आदि), जोखिम संकेन्द्रण तथा आर्थिक आंकड़ों (जिसमें बेरोजगारी स्तर, अचल संपत्ति मूल्य सूचकांक, देश जोखिम एवं विभिन्न व्यक्तिगत समूहों का प्रदर्शन शामिल है) को ध्यान में रखकर किया जाता है।

ऋण क्षतिग्रस्तता के अतिरिक्त अन्य प्रावधान

कर्मचारी देयताओं, पुनर्संरचना लागतों तथा वाद–विवाद संबंधी प्रावधानों जैसी विभिन्न भावी देयताओं के संबंध में प्रावधान बनाए जाते हैं। कुछ प्रावधानों में विभिन्न घटनाओं के संभावित परिणामों तथा अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। इन प्रावधानों का मापन लेन–देन के अंतिम परिणामों के संबंध में प्रबंधन के निर्णयों के प्रयोग को सम्मिलित करता है। जिन भुगतानों के एक वर्ष से अधिक समय बाद होने की अपेक्षा है, उन्हें ऐसी छूट दर पर छूटित किया जाता है, जो वर्तमान ब्याज दरों तथा उस प्रावधान से संबंधित विशिष्ट जोखिमों, दोनों को प्रतिबिंबित करती हो।

ऋण एवं अग्रिम

ऋण एवं अग्रिमों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर, प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अतिरिक्त लेन–देन लागत सहित किया जाता है, तथा तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए इन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

17. उधार एंव ऋण प्रतिभूतियां

उधार एवं निर्गत ऋण प्रतिभूतियों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर, उनसे संबंधित अतिरिक्त प्रत्यक्ष लेन–देन लागत घटाकर किया जाता है तथा तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए इन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ समूह द्वारा देयताओं को एफवीटीपीएल पर नामित किया गया हो।

18. उधार लेने की लागत

विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों पर उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में आरोपित किया जाता है। विनिमय अंतर की वह राशि, जो स्थानीय मुद्रा में लिए गए उधारों पर ब्याज और विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों पर ब्याज के अंतर से अधिक नहीं होती है, को उधार लागत माना जाता है तथा इंड एएस 23 – उधार लागत के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है। शेष विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को इंड एएस 21 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है।

इस प्रयोजन हेतु, स्थानीय मुद्रा में लिए गए उधारों की ब्याज दर के रूप में कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की ब्याज दर को माना जाता है।

19. सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनी वह इकाई होती है, जिस पर कंपनी का नियंत्रण होता है। नियंत्रण तब माना जाता है, जब कंपनी के पास उस इकाई पर शक्ति हो, वह उस इकाई के साथ अपने संलग्नता से परिवर्तनीय प्रतिफलों के प्रति अनावृत्त हो अथवा उन पर अधिकार रखती हो, तथा अपनी उस शक्ति का उपयोग कर उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हो।

शक्ति का प्रदर्शन उन विद्यमान अधिकारों के माध्यम से होता है, जो प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता प्रदान करते हैं, अर्थात् वे गतिविधियाँ जो इकाई के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

सहायक कंपनियों में निवेशों को लागत पर वहन किया जाता है। इस लागत में निवेश प्राप्त करने हेतु चुकाई गई कीमत तथा उससे सीधे संबंधित व्यय शामिल होते हैं।

इंड एएस में संक्रमण की तिथि पर, कंपनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार सहायक कंपनियों में निवेश के वहन मूल्य को इंड एएस 101 के अंतर्गत अनुमानित लागत के रूप में माना है।

20. विदेशी मुद्रा लेन–देन

20.1 विदेशी मुद्रा में होने वाले व्यय एवं आय को, लेन–देन की तिथि पर बैंकों द्वारा प्रचलित विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है।

20.2 निम्नलिखित शेष राशियों को खातों के समापन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों (आरबीआई संदर्भ दरों) पर भारतीय मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है:

(क) स्वीकृत विदेशी मुद्रा ऋणों एवं विदेशी मुद्रा उधारों पर क्रमशः उपार्जित किन्तु देय न हुई आय या व्यय।

(ख) विदेशी मुद्रा में जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट से संबंधित आकस्मिक देयता

20.3 विदेशी मुद्रा ऋण देयता को रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित आरबीआई संदर्भ दर पर भारतीय मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है। उत्पन्न विनिमय अंतर को लेखा मानक 11 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव के अनुसार लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

20.4 विदेशी मुद्रा ऋण परिसंपत्तियों, दायित्वों तथा उपार्जित/उपार्जित किन्तु देय न हुई आय एवं व्यय पर वास्तविक/संपरिवर्तन लाभ या हानि को लाभ–हानि विवरण में जमा/प्रभारित किया जाता है।

21. व्युत्पन्न लिखतों का लेखांकन

21.1 जहाँ भी कंपनी ने वायदा संविदा या ऐसा लिखत, जो सारतः वायदा विनिमय संविदा की प्रकृति का है, किया है, वहां वायदा दर और वायदा विनिमय संविदा की तारीख की विनिमय दर के बीच के अंतर को भारतीय लेखांकन मानक–21 के अनुसार संविदा की अवधि के दौरान आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

21.2 विदेशी मुद्रा ऋणों पर लिए गए हेज को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों (अर्थात् प्राकृतिक हेज) के समायोजन के बाद प्रथम आगत, प्रथम निर्गत आधार पर समायोजित किया जाता है।

21.3 ब्याज दर स्वैप सहित फॉरवर्ड विनिमय करारों को रद्द करने या उनका नवीनीकरण करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष की आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

21.4 कंपनी द्वारा किए गए जापानी येन में ब्याज दर स्वैप लेन–देन के संबंध में, कंपनी तुलन–पत्र की तारीख को बाजार मूल्यांकन हानि का प्रावधान करती है।

21.5 फॉरवर्ड करार के आरंभ के समय की हाजिर विनिमय दर और अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व के पुनर्भुगतान के समय की हाजिर विनिमय दर के बीच अंतर के कारण होने वाले अधिशेष या घाटे को, हेजिंग करार के अनुसार प्रतिपक्ष से वसूल की गई या प्रतिपक्ष को भुगतान की गई राशि के रूप में, ऐसे ऋण के पुनर्भुगतान के समय लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

21.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेन–देन है) और स्वैप करार (उपर्युक्त ऋणों से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि से बचाव के लिए) को अलग–अलग लेन–देन माना जाता है।

21.7 विदेशी मुद्रा में उधारी को भारतीय लेखांकन मानक 21, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार पुनः अभिव्यक्त किया जाता है।

आईसीएआई द्वारा जून 2015 में जारी "व्युत्पन्नी संविदाओं के लेखांकन" संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी 1 अप्रैल 2016 से लागू है तथा कंपनी द्वारा इसे 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से अपनाया गया है। रिपोर्टिंग तिथि पर, पिछली रिपोर्टिंग तिथि से तथा अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा उधार की निकासी की तिथि से, विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में होने वाले किसी भी परिवर्तन को व्युत्पन्नी संविदाओं के उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है तथा उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि कैश फ्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है। व्युत्पन्नी संविदाओं का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षों द्वारा प्रदान किया जाता है।

उक्त मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार, कैश फ्लो हेज के अंतर्गत हेजिंग साधन को उचित मूल्य पर मापा जाता है, परंतु जो लाभ या हानि एक प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित होती है, उसे इक्विटी में, अर्थात् कैश फ्लो हेज रिजर्व में मान्यता दी जाती है। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ–हानि विवरण में अस्थिरता से बचना है, जब हेज किए गए मदों पर लाभ या हानि अभी साकार नहीं हुई होती।

22. राजस्व अनुदानों का लेखांकन

22.1 अनुदानों को लाभ–हानि विवरण में 'अन्य आय' के रूप में, उन अवधियों में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित लागतें वहन की जाती हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति हेतु ये अनुदान अभिप्रेत हों, बशर्ते कि अनुदान स्वीकृति से संबद्ध शर्तों के अनुपालन तथा अनुदान राशि की प्राप्ति के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध हो।

22.2 पूर्ववर्ती अवधियों में पहले से किए गए व्यय के संबंध में प्राप्त अनुदानों को, अनुदान की स्वीकृति के वर्ष में लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

22.3 वर्ष के अंत में अनुदान की कोई भी अप्रयुक्त राशि, यदि हो, तो उसे चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाहों का विवरण अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत कर–पूर्व लाभ को गैर–नकदी प्रकृति के लेन–देन के प्रभावों तथा पूर्ववर्ती या भावी नकदी प्राप्तियों अथवा भुगतानों से संबंधित किसी भी स्थगन या उपार्जन के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से संबंधित नकद प्रवाहों को अलग–अलग दर्शाया जाता है।

(ख) वित्तीय विवरणों के लिए अन्य टिप्पणियां

1. पूर्व अवधि की आय और व्यय (इंडएएस–8) जिन्हें लाभ और हानि विवरण में नियमित शीर्षों के अंतर्गत शामिल किया गया है, निम्नानुसार है (टिप्पणी 28 देखें):

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(क) आय		
ऋण और अग्रिम पर आय	-	-
दंडस्वरूप ब्याज	-	-
अन्य प्रभार	-	-
	-	**-**
(क) व्यय		
स्थापना एवं अन्य व्यय	-	-
मूल्यह्रास	-	-
कुल (ख)	**-**	**-**
चालू वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से शुद्ध प्रभाव (क)–(ख)	-	-

2. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

3. भारतीय लेखांकन मानक 19 श्कर्मचारी हितलाभश (इंड एएस–19) के अंतर्गत प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक 19 ''कर्मचारी हितलाभ'' के अनुसार, लेखांकन मानक में परिभाषित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:–

क. ग्रेच्युटी योजना (वित्तपोषित): गेच्युटी देयता सेवानिवृत्ति, सेवाकाल में मृत्यु या सेवा से त्यागपत्र देने की स्थिति में किए जाने वाले भविष्य के भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है। इसका प्रावधान आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी निधि के नाम से गठित न्यास के माध्यम से समूह गेच्युटी योजना के अंतर्गत एलआईसी को देय राशि के आधार पर किया गया है। आईआईएफसीएल एलआईसी की समूह गेच्युटी योजना के अंतर्गत कर्मचारियों की गेच्युटी देयता की राशि का भुगतान करता है और इंड एएस 19 "कर्मचारी लाभ" की आवश्यकताओं के अनुसार, इंड एएस 19 के आस्ति सीमा संबंधी प्रावधानों के तहत वसूलनीय और अनुमत सीमा तक बीमांकिक रूप से निर्धारित निवल परिभाषित लाभ स्थिति को मान्यता देता है।

I. ग्रेच्युटी योजना हेतु धारणाएं:

	31st मार्च 2026	31st मार्च 2025
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012 –14)	100% आईएएलएम (2012 –14)
आहरण दर	1% से 3% अवधि के आधार पर	1% से 3% अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.78%	6.99%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50%

II. परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषणः

(₹ लाख)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	597.98
क)	0.50: की वृद्धि के कारण प्रभाव	(31.42)
ख)	0.50: की कमी के कारण प्रभाव	34.11
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	597.98
क)	0.50: की वृद्धि के कारण प्रभाव	8.17
ख)	0.50: की कमी के कारण प्रभाव	(7.56)

मृत्यु दर और कर्मचारियों के सेवा से हटने के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए बीमांकक द्वारा इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान किए जा रहे पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलताएं लागू नहीं हैं।

आईआरडीए परिपत्र संख्या आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/सीआईआर/123/06/2013 दिनांक 28 जून 2013 के अनुसार, मौजूदा पॉलिसी में कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा जा सकता है। अतः, आईआईएफसीएल ने पूर्ववर्ती पॉलिसी संख्या 331776 के अतिरिक्त नए कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी अर्थात पॉलिसी संख्या 103001183 ली है।

(₹ लाख)

क्र.सं.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	597.98	629.93
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	735.67	645.85
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	137.69	15.92
	योजनागत आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	645.85	599.81
ख)	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	51.69	46.04
ग)	मृत्यु प्रभार	-	-
घ)	नियोक्ता का अंशदान	78.13	-
ङ)	भुगतान किए गए लाभ	(40.00)	-
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	735.67	645.85
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	629.93	545.43
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	44.03	39.38
घ)	सेवा लागत	45.09	52.32
ङ)	पिछली सेवा लागत, जिसमें कटौती से होने वाले लाभ/हानियां शामिल हैं	-	-
च)	प्रदत्त लाभ	(40.00)	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(81.07)	(7.21)

क्र.सं.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	597.98	629.93
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(15.92)	(54.37)
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	45.09	52.32
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	(1.11)	(3.93)
ङ)	पुनः मापन	(87.62)	(9.93)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	(78.13)	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(137.69)	(15.92)
	वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(54.05)	15.75
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(27.02)	(22.95)

ख. अर्जित अवकाश देयता: किसी कर्मचारी को मिलने वाली अर्जित छुट्टी वह अवधि होती है जो कर्मचारी ने अर्जित की है, जिसमें कर्मचारी द्वारा वास्तव में ली गई छुट्टी की अवधि को घटा दिया जाता है। यह ड्यूटी के ग्यारहवें हिस्से के बराबर अर्जित की जाती है।आईआईएफसीएल ने इंड एएस 19 "कर्मचारी लाभ" की आवश्यकताओं के अनुसार, इंड एएस 19 के आस्ति सीमा संबंधी प्रावधानों के तहत वसूलनीय और अनुमत सीमा तक बीमांकिक रूप से निर्धारित निवल परिभाषित लाभ स्थिति को मान्यता दी है।

अवकाश नकदीकरण योजना हेतु धारणाएं:

	31st मार्च 2026	31st मार्च 2025
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012 –14)	100% आईएएलएम (2012 –14)
आहरण दर	1% से 3% अवधि के आधार पर	1% से 3% अवधि के आधार
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.78%	6.99%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण। (₹ लाख)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1,217.69**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(67.95)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	72.01
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1,217.69**
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	73.94
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(68.73)

मृत्यु दर और सेवा से हटने के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान किए जा रहे पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं हैं।

(₹ लाख)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,217.69	1,247.39
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2,195.09	1,767.44
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	977.40	520.04
	योजनागत आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	1,767.44	1,182.39
ख)	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	149.84	118.48
ग)	मृत्यु प्रभार	-	-
घ)	नियोक्ता का अंशदान	445.74	466.57
ङ)	भुगतान किए गए लाभ	(167.92)	-
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2,195.09	1,767.44
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,247.39	980.39
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	87.19	70.78
घ)	सेवा लागत	128.66	129.42
ङ)	पिछली सेवा लागत, जिसमें कटौती से होने वाले लाभ/हानियां शामिल हैं	-	-
च)	प्रदत्त लाभ	(167.92)	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(77.64)	66.80
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,217.69	1,247.39
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(520.04)	(202.00)
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	128.66	129.42
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	(36.35)	(14.58)
ङ)	पुनः मापन	(103.94)	33.69
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	(445.74)	(466.57)
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(977.40)	(520.04)
	वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(117.28)	32.06
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	39.64	34.74

I. अन्य कर्मचारी हितलाभ (अवित्तपोषित)

अन्य कर्मचारी हितलाभों (अवित्तपोषित)के लिए बीमांकिक अवधारणाएं

ग) **अवकाश यात्रा रियायतः** कंपनी के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी, जिन्होंने यात्रा किए जाने की तारीख को एक वर्ष की सेवा, जिसमें निरंतर अस्थायी सेवा भी शामिल है, पूरी कर ली है, इस सुविधा के लिए पात्र हैं। यह रियायत दो वर्षों के प्रत्येक चक्र में एक बार

स्वीकार्य होगी और ऐसे पहले चक्र की शुरुआत उस महीने की पहली तारीख से होगी, जिसमें कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है, लेकिन इसका लाभ कर्मचारी द्वारा अस्थायी सेवा/परिवीक्षा अवधि सहित एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद ही लिया जा सकता है।

अवकाश यात्रा रियायत हेतु धारणाएं:

	31st मार्च 2026	31st मार्च 2025
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012 –14)	100% आईएएलएम (2012 –14)
आहरण दर	1% से 3% अवधि के आधार पर	1% से 3% अवधि के आधार
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.78%	6.99%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	133.00
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(5.51)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	5.57

मृत्यु दर और सेवा से हटने के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान किए जा रहे पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं हैं।

(₹ लाख)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	133.00	125.53
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	(133.00)	(125.53)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	125.53	105.73
ख)	ब्याज लागत	-	7.63
ग)	सेवा लागत	8.77	27.76
घ)	प्रदत्त लाभ	35.54	(312.64)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	297.04
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	(285.86)	125.53
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	125.53	105.73
ख)	कुल सेवा लागत	35.54	27.76
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	8.77	7.63

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
घ)	पुनः मापन	249.02	297.04
ङ)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(285.86)	(312.64)
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	133.00	125.53
	वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(16.69)	4.27
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	265.71	292.77

घ) रुग्णता अवकाशः रुग्णता अवकाश आधे वेतन पर दी जाती है। जहां किसी कर्मचारी ने कंपनी में कम से कम तीन वर्ष की सेवा की है, वहां कर्मचारी के अनुरोध पर, उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान, अधिकतम वर्षों तक आधे वेतन पर रुग्णता अवकाश लेने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी अवकाश को कर्मचारी के रुग्णता अवकाश खाते में कर्मचारी द्वारा ली गई अवकाश की अवधि के दोगुने के रूप में दर्ज की जाती है।

रुग्णता अवकाश योजना हेतु धारणाएं:

	31st मार्च 2026	31st मार्च 2025
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012–14)	100% आईएएलएम (2012–14)
आहरण दर	आयु के आधार पर 1% से 3% तक	आयु के आधार पर 1% से 3% तक
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.78%	6.99%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाख)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	400.47
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(22.76)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	24.12
ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	400.47
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	24.77
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(23.02)

मृत्यु दर और सेवा से हटने के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान किए जा रहे पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं हैं।

(₹ लाख)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	400.47	441.09
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	(400.47)	(441.09)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	441.09	321.34
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	30.83	23.20
घ)	सेवा लागत	38.44	44.17
ङ)	पिछली सेवा लागत, जिसमें कटौती से होने वाले लाभ/हानियां शामिल हैं	-	-
च)	प्रदत्त लाभ	-	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(109.90)	52.38
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	400.47	441.09
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	441.09	321.34
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	38.44	44.17
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	30.83	23.20
ङ)	पुनः मापन	(109.90)	52.38
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	400.47	441.09
	वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(39.30)	11.98
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(70.60)	40.40

ङ) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से शुरू): भारतीय लेखांकन मानक–19 के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) देयता का बीमांकिक मूल्यांकन। कंपनी के पास सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजनाहेतु धारणाएं:

	31st मार्च 2026	31st मार्च 2025
मृत्यु दर	100% आईएएलएम (2012 –14)	100% आईएएलएम (2012 –14)
आहरण दर	आयु के आधार पर 1% से 3% तक	आयु के आधार पर 1% से 3% तक
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.78%	6.99%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण (₹ लाख)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,516.21
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(21.38)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	23.49

मृत्यु दर और सेवा से हटने के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है।

भुगतान किए जा रहे पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं हैं।

(₹ लाख)

	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,516.21	1,367.54
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	(1,516.21)	(1,367.54)
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,367.54	1,160.01
ख)	ब्याज लागत	95.59	83.75
ग)	सेवा लागत	82.64	81.37
घ)	प्रदत्त लाभ	(44.34)	(16.70)
ङ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	14.78	59.11
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,516.21	1,367.54
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	1,367.54	1,160.01
ख)	कुल सेवा लागत	82.64	81.37
ग)	निवल ब्याज लागत (आय)	95.59	83.75
घ)	पुनः मापन	14.78	59.11
ङ)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
च)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(44.34)	(16.70)
छ)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	1,516.21	1,367.54
	वर्गीकरण बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय धारणा में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(151.98)	38.33
ग)	अनुभव समायोजन से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	166.76	20.78

ज) नियत अंशदान योजनाः

(क) पेंशनः

कंपनी कर्मचारियों के प्रति अपनी पेंशन की जिम्मेदारी के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में पहले से नियत दर पर कर्मचारियों के टियर–आईएनपीएस खाते (पेंशन खाते) में नियत अंशदान देती है।

(ख) भविष्य निधि:

कंपनी ईपीएफओ को भविष्य निधि के खाते में नियत अंशदान देती है। कंपनी का अनुमान है कि इस संबंध में निकट भविष्य में कोई देयता नहीं आएगी और इसलिए, आगे कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया।

3) प्रत्येक कर्मचारी लाभ के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि निम्नानुसार है:

(₹ लाख)

कर्मचारी लाभ	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
अर्जित अवकाश पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	77.64	(66.80)
उपदान पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	81.07	7.21
एलएफसी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(249.02)	(297.04)
पीआरएमबी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(14.78)	(59.11)
एसएल पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	109.90	(52.38)
कुल	4.80	(468.12)

4. कंपनी का मुख्य व्यवसाय अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण/पुनर्वित्तपोषण प्रदान करना है और कंपनी के पास भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक–108, परिचालन खंडों के अनुसार एक से अधिक रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

5. **भारतीय लेखांकन मानक–24, संबंधित पक्ष प्रकटीकरण** के अनुसार, संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन के प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं

क) प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

i. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री रोहित ऋषि - प्रबंध निदेशक (04.02.2026 से प्रभावी)

श्री पलाश श्रीवास्तव - उप प्रबंध निदेशक

निदेशकों के अलावा

श्री राजीव मुखीजा - मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ

सुश्री रुचि सिंघल - महाप्रबंधक –कंपनी सचिव

ii. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी:

(क) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड

(ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(ग) आईआईएफसीएलएसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

ख) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त हुआ) के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन:

(₹ लाख)

क्रमं	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(क)	**प्रबंधकीय पारिश्रमिक (पूर्णकालिक निदेशक)**		
	(i) **श्री रोहित ऋषि (प्रबंध निदेशक)#**		
	पारिश्रमिक	7.19	-
	(ii) **श्री पलाश श्रीवास्तव (उप प्रबंध निदेशक)**		
	पारिश्रमिक	53.55	3.34
	(iii) **श्री पी आर जयशंकर (पूर्व प्रबंध निदेशक)** *		
	पारिश्रमिक	9.83	52.08
	(iv) **श्री पवन के कुमार (पूर्व उप प्रबंध निदेशक)** @		
	पारिश्रमिक	-	30.25

क्रसं	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(ख)	**प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निदेशकों के अलावा)**		
	(i) **श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक– सीएफओ)**		
	पारिश्रमिक	84.37	104.41
	(ii) **सुश्री रुचि सिंघल (महाप्रबंधक–सीएस)** $		
	पारिश्रमिक	60.69	55.99
	(iii) **श्री रूपेश कुमार (उप महाप्रबंधक–सीएस)** %		
	पारिश्रमिक	-	66.88
	(iv) **श्री अभिनरूप सिंह (सहायक महाप्रबंधक–सीएस)** ^		
	पारिश्रमिक	-	44.50
(ग)	**सहायक/संबद्ध कंपनियों से प्राप्त/प्राप्य किराया**		
	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	108.46	113.39
	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	-	107.63
(घ)	**सहायक कंपनियों से किराये के अतिरिक्त प्राप्त/प्राप्य राशियाँ:**		
	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड		38.55
	आईआईएफसीएलएसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	-	0.99
	आईआईएफसीएल (यूके) लिमिटेड	23.06	-
(ड)	**बैठक शुल्क:**		
	श्री समीर जेरामभाई बोगरा	13.60	13.95

4 फरवरी 2026 से प्रभावी, ' 28 मई 2025 तक,/ 30 सितंबर 2024 तक,+ 19 दिसंबर 2024 से प्रभावी,: 18 दिसंबर 2024 तक,' 14 मई 2024 तक

ग) बकाया राशि (₹ लाख)

क्रसं	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
i)	**समता अंशों में निवेश**		
	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां:		
	(क) आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	103,076.15	103,076.15
	(ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	475.00	475.00
	(ग) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	1,250.00	1,250.00
	सहायक/सहयोगी कंपनियों से वसूली योग्य राशि		
	(क) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	50.79	89.46
	(ख) आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	(16.86)	-
	(ग) आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	0.19	3.73
	केएमपी को अग्रिम	0.25	3.85

6. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक–33, प्रति शेयर आय के अनुसार, प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत) निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	
	शेयर	राशि लाख में	शेयर	राशि लाख में
शेयर का नाममात्र मूल्य (₹)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयरों की संख्या (लाख में)	99,999.16		99,999.16	
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) (हर का भाजक)	99,999.16		99,999.16	
निवल लाभ (कर पश्चात) (अंश) (₹ लाख में)		137,945.76		216,127.13
प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत) (₹)(जारी परिचालन से)		1.38		2.16
प्रति शेयर आय (मूल और तनुकृत) (₹)(बंद किए गए परिचालन से)		-		-

7. कंपनी के पास मौजूद अचल परिसंपत्तियों को "कॉरपोरेट परिसंपत्तियां" माना जाता है, न कि "नकदी सृजन करने वाली इकाइयां", जैसा कि इंड एएस–36, "परिसंपत्तियों की हानि" में परिभाषित किया गया है। 31 मार्च 2026 तक ऐसी कोई घटना या परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जो परिसंपत्तियों में किसी हानि का संकेत देता हो।

(8) (क) भारतीय लेखांकन मानक 37 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस–37)" के तहत प्रकटीकरण

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
प्रस्तावित वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष	1,642.64	1,054.92
अवधि के दौरान वृद्धि	759.74	587.72
चालू देयताओं में भुगतान/अंतरित की गई राशि	70.00	-
अप्रयुक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन	-	-
अंतिम शेष	2,332.38	1,642.64
मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	27,560.41	19,622.53
अवधि के दौरान वृद्धि	7,030.87	7,937.88
अंतिम शेष	34,591.28	27,560.41
अवमानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	2,367.87	-
अवधि के दौरान वृद्धि	2,367.87	2,367.87
एनपीए बट्टे खाते डालने के कारण प्रावधान प्रतिलेखन	-	-
अंतिम शेष	-	2,367.87
पुर्नगठित परिसंपत्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	1,520.71	6,819.57
अवधि के दौरान वृद्धि/समायोजन	(800.35)	(5,298.86)
एनपीए बट्टे खाते डालने के कारण प्रावधान प्रतिलेखन		-
अंतिम शेष	720.35	1,520.71

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
संदिग्ध परिसंपत्तियों के प्रति प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	22,189.36	37,598.21
अवधि के दौरान वृद्धि/समायोजन	10,367.72	7,528.17
एनपीए बट्टे खाते डालने के कारण प्रावधान प्रतिलेखन	-	(7,880.68)
अंतिम शेष	32,557.08	22,189.36
निवेशों में ह्रास के लिए प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	22,059.91	23,654.75
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
निवेशों की बिक्री के कारण समायोजित प्रावधान	1,794.59	1,594.83
अंतिम शेष	**20,265.32**	**22,059.91**

(ख) अन्य प्रकटीकरण:

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
आयकर (निवल)		
प्रारंभिक शेष	15,725.16	7,356.12
अवधि के दौरान वृद्धि	40,980.82	47,271.02
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	51,800.00	38,901.98
अंतिम शेष	**4,905.98**	**15,725.16**
अवकाश यात्रा रियायत		
प्रारंभिक शेष	125.53	105.73
अवधि के दौरान वृद्धि	293.33	332.44
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	285.86	312.64
अंतिम शेष	**133.00**	**125.53**
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
प्रारंभिक शेष	1,367.54	1,160.01
अवधि के दौरान वृद्धि	193.01	224.23
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	44.34	16.70
अंतिम शेष	**1,516.21**	**1,367.54**
अवकाश नकदीकरण		
प्रारंभिक शेष	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	-	-
अंतिम शेष	**-**	**-**
रुग्णता अवकाश		
प्रारंभिक शेष	441.09	321.34
अवधि के दौरान वृद्धि	(40.63)	119.75
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	-	-
अंतिम शेष	**400.47**	**441.09**

9. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया हैं) निम्नानुसार हैं

(₹ लाख)

क्र सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(क)	**(ए) कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे**		
	(i) आयकर विभाग द्वारा 28 दिसंबर 2018 के आदेश के माध्यम से किए गए निर्धारण वर्ष 2016–17 के आयकर देयताओं की मांग।	632.66	682.33
	(ii) आयकर विभाग द्वारा 30 मार्च 2023 को आयकर पोर्टल पर की गई निर्धारण वर्ष 2016–17 के आयकर देयताओं की मांग।	174.58	174.58
	(iii) आयकर विभाग द्वारा की गई निर्धारण वर्ष 2017–18 के आयकर देयताओं की मांग।	51.65	51.65
	(iv) आयकर विभाग द्वारा 27 मार्च 2025 की सूचना के माध्यम से की गई निर्धारण वर्ष 2020–21 के आयकर बकाया की मांग।	5,131.21	2665.81
	(v) आयकर विभाग द्वारा 13 मार्च 2026 के आदेश के माध्यम से की गई निर्धारण वर्ष 2024–25 के आयकर बकाया की मांग।	7,656.32	-
	(vi) सेवा कर देयताओं की मांग–आपत्ति के साथ ब्याज सहित मांग का भुगतान किया गया।	71.52	71.52
	(vii) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए जीएसटी की मांग।	0.90	0.90
	(viii) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए जीएसटी की मांग।	270.76	270.76
	(ix) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए जीएसटी की मांग।	872.45	872.45
	(x) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए जीएसटी की मांग।	104.35	104.35
	(बी) गारंटी		
	(ग) अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:	Nil	Nil
	(प) शाख पत्र (एलसी) जारी करने के लिए चुकौती आश्वासन पत्र (कंपनी ने संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने के लिए संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने के लिए संबंधित अग्रणी बैंकों/सदस्य बैंक को एलसी की राशि जारी करने के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं।	1,06,854.67*	80,225.98
	(पप) ऋण वृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	21,782.30	22,413.10
(ख)	**(ए) पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया:**		
	पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (अग्रिमों का निवल)	2,462.78	2,932.44
	(बी) अन्य प्रतिबद्धताएं:		
	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निष्पादित किए जाने वाले शेष करारों की अनुमानित राशि (अग्रिमों को घटाने के बाद)	4,827.90	2,396.11

* इसमें 34,701.00 लाख की राशि शामिल है, जो 3,00,000 लाख की सीमा में से इंडियन बैंक द्वारा जारी किए गए साख–पत्र की राशि है।

10. विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय

(₹ लाख)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(क) विदेशी मुद्रा में आय (वास्तविक प्राप्ति, आईआरएस व्युत्पन्नी संविदाओं के तहत प्राप्त ब्याज को छोड़कर):		
ब्याज	-	-
प्राप्त अनुदान	-	-
प्राप्त लाभांश	-	-
कुल	-	-
(ख) ब्याज और अन्य मामलों के कारण विदेशी मुद्राओं में व्यय (वास्तविक व्यय):		
उधार पर ब्याज	81,079.00	87,073.66
प्रतिबद्धता शुल्क	-	-
विदेश यात्रा	-	-
अन्य व्यय	-	-
कुल	**81,079.00**	**87,073.66**

11. उद्यम पूंजी इकाइयों में निवेश

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट ष् की वेंचर कैपिटल इकाइयों में शून्य निवेश किया है (31 मार्च 2025 को ₹शून्य), जिसे कंपनी ने आईडीएफसी और सिटी बैंक के साथ मिलकर प्रवर्तित किया है (31 मार्च 2026 तक कंपनी द्वारा किए गए निवेश की संचयी राशि ₹9,247.56 लाख है)। ₹10,000 लाख की कुल प्रतिबद्धता में से, कंपनी ने इस वेंचर में निवेशक के रूप में अंशदान किया है और उसका संयुक्त नियंत्रण नहीं है। चूंकि निधि में वितरित किए जाने योग्य कोई लाभ नहीं है, इसलिए ऐसे निवेशों के संबंध में लेखा बहियों में कोई आय मान्यता नहीं की गई है। हालांकि, कंपनी को 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान वेंचर कैपिटल इकाइयों के मोचन के संबंध में ₹35.50 लाख (31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹शून्य) की राशि प्राप्त हुई है, जिसमें भुगतान किया गया कर ₹शून्य (31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹शून्य लाख) शामिल है।

12. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹1,846.14 लाख की निवल आस्थगित कर आस्ति का प्रत्यावर्तन किया है (आस्थगित कर देयता में ₹85.13 लाख की कमी और आस्थगित कर आस्ति में ₹1,931.27 लाख की कमी)।

13. कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, 31 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार कोई भी आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता नहीं है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम के रूप में पंजीकृत है।

विवरण इस प्रकार है:

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
प्रत्येक वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को चुकाई न गई मूल राशि और उस पर लगने वाला ब्याज (अलग से दिखाया जाएगा)	-	-
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत खरीदार द्वारा दिए गए ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान तय दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि	-	-
भुगतान करने में हुई देरी के लिए देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान तय दिन के बाद चुकाई गई है) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के तहत बताए गए ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में जमा हुआ और बाकी बचा हुआ ब्याजय और	-	-

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
आगे के वर्षों में भी बकाया और चुकाने लायक ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक ऊपर बताई गई ब्याज की राशि असल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के तौर पर डिसअलाउंस के उद्देश्य से नहीं दी जाती।	-	-

14. व्युत्पन्नी लेनदेन

क. कंपनी ने बहुपक्षीय संस्थानों से विदेशी मुद्रा में ली गई उधारी पर अस्थिर ब्याज दरों के साथ–साथ विदेशी विनिमय दर में उतार–चढ़ाव से संबंधित जोखिमों से बचाव के लिए समग्र करार अर्थात् क्रॉस–करेंसी स्वैप (मूलधन और ब्याज) किए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

(₹ लाख)

संस्थान	पारस्परिक मुद्रा स्वैप की राशि	
	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):–		
अमरीकी डालर	3,045.38	4,947.00
भारतीय रुपया	288,257.91	423,371.39
आईबीआरडी विश्व बैंक:–		
अमरीकी डालर	-	1,078.99
भारतीय रुपया	-	92,341.65

सभी हेज 100% प्रभावी हैं यानी कोई निष्प्रभावी नहीं है।

हेज अनुपातः हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच आर्थिक संबंध है, क्योंकि वायदा संविदाओं, ब्याज दर स्वैप और क्रॉस–करेंसी स्वैप करारों की शर्तें विदेशी मुद्रा में ली गई उधारी की शर्तों से मेल खाती हैं। कंपनी ने हेज संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात निर्धारित किया है, क्योंकि वायदा संविदाओं, ब्याज दर स्वैप और क्रॉस–करेंसी स्वैप से संबंधित अंतर्निहित जोखिम, हेज किए गए जोखिम घटकों के समान हैं। हेज की अप्रभाविता मुख्य रूप से कंपनी या प्रतिपक्ष के ऋण जोखिम में परिवर्तन होने पर उत्पन्न हो सकती है।

प्रतिपक्षी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपर्युक्त करारों के मार्केट–टू–मार्केट (एम2एम) मूल्यांकन और अन्य मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2026 को निवल एम2एम लाभ ₹1,74,673.79 लाख है (₹1,74,673.79 लाख का सकल लाभ घटाकर ₹शून्य लाख का सकल नुकसान) और 31 मार्च 2025 को एम2एम लाभ ₹1,35,382.74 लाख है (₹1,36,327.97 लाख का सकल लाभ घटाकर ₹945.23 लाख का सकल नुकसान)।

वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2012 को समाप्त होने के दौरान, कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति से विदेशी मुद्रा ऋण की उस सीमा तक, जिसे हेज किया गया है, लेखांकन के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले सही लेखांकन उपचार पर राय मांगी थी। इस संबंध में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने 22 सितंबर 2015 के पत्र के माध्यम से इस मामले में अपनी राय प्रदान की। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने जून 2015 में "व्युत्पन्नी करारों के लेखांकन" पर मार्गदर्शी टिप्पणी भी जारी की थी, जो 1 अप्रैल 2016 से लागू है और कंपनी द्वारा इसे 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया जा रहा है। रिपोर्टिंग तारीख को विदेशी मुद्रा में उधारी की राशि पर पिछली रिपोर्टिंग तारीख से तथा अवधि के दौरान उधारी आहरण की तारीख से विनिमय दर में होने वाले किसी भी परिवर्तन को व्युत्पन्नी करारों के उचित मूल्य के विरुद्ध सेट–ऑफ किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि के रूप में मान्यता दी जाती है। व्युत्पन्नी करारों का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षों द्वारा प्रदान किया जाता है।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने 26 दिसंबर 2016 के पत्र के माध्यम से भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) को व्युत्पन्नी संबंधी मार्गदर्शिका लागू करते समय हेज करारों के बाजार मूल्यांकन/उचित मूल्य के संबंध में आईआईएफसीएल के समक्ष आने वाली समस्याओं से अवगत कराया था, जिसकी एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजी गई थी। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के 3 मई 2017 के पत्र के अनुसार, यह मामला आईसीएआई की अनुसंधान समिति को भेजा गया है।

हेज किए गए ऋण के उस हिस्से का विवरण, जिसे इंड एएस–21 के अनुरूप समापन दर पर पुनः अभिव्यक्त किया गया है, निम्नानुसार है:

(₹ लाख)

संस्थान	हेज किए गए ऋण के हिस्से की राशि	
	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):–		
अमरीकी डालर	10,815.82	11,514.56
भारतीय रुपया	1,023,763.52	985,432.21
आईबीआरडी विश्व बैंक:–		
अमरीकी डालर	1,059.82	1,187.99
भारतीय रुपया	100,316.52	101,670.02
यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)		
यूरो	100.00	256.67
भारतीय रुपया	10,900.64	23,696.65
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी (जेआईसीए)		
येन	71,036.40	-
भारतीय रुपया	42,089.07	–
सुमितो मोमित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एसएमबीसी)		
येन	147,948.38	-
भारतीय रुपया	87,659.42	-

डेरिवेटिव अनुबंधों के लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का प्रकटीकरण:-

(₹ लाख)

I. परिसंपत्तियां	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)
प्राप्य (व्यापारिक एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
अन्य मौद्रिक परिसंपत्तियां (जैसे विदेशी मुद्रा में दिए गए आईसीडी/ऋण)	-	-	-	-	-	-	-
कुल प्राप्य (क)	-	-	-	-	-	-	-
डेरिवेटिव अनुबंधों द्वारा हेज (ख)	-	-	-	-	-	-	-
अनहेज्ड प्राप्य (ग = क - ख)	-	-	-	-	-	-	-

II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2026			वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)
देय (व्यापारिक एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
उधार (ईसीबी एवं अन्य)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	94.6543 109.006 0.5925	13,558.83 1,404.00 604,392.60	1,283,401.37 153,045.00 358,102.62	85.5814 92.3246 0.5675	13,621.80 1,550.63 378,831.86	1,165,772.55 143,161.35 214,970.21
कुल देय (घ)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	94.6543 109.006 0.5925	13,558.83 1,404.00 604,392.60	1,283,401.37 153,045.00 358,102.62	85.5814 92.3246 0.5675	13,621.80 1,550.63 378,831.86	1,165,772.55 143,161.35 214,970.21
डेरिवेटिव अनुबंधों द्वारा हेज (ङ)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	94.6543 109.006 0.5925	11,875.64 100.00 218,984.78	1,124,080.04 10,900.64 129,748.48	85.5814 92.3246 0.5675	12,702.55 256.67 -	1,087,102.23 23,696.65 -
अनहेज्ड देय (च = घ–ङ)	यूएसडी यूरो जेपीवाई	94.6543 109.006 0.5925	1,683.19 1,304.00 385,407.82	159,321.33 142,144.36 228,354.13	85.5814 92.3246 0.5675	919.25 1,293.96 378,831.86	78,670.32 119,464.70 214,970.21

III. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धताएं	विदेशी मुद्रा	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2026			वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025		
		विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)	विनिमय दर	विदेशी मुद्रा में राशि	राशि (लाख में)
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिबद्धताएं	-	-	-	-	-	-	-
कुल (छ)	-	-	-	-	-	-	-
डेरिवेटिव अनुबंधों द्वारा हेज (ज)	-	-	-	-	-	-	-
अनहेज्ड देय (झ= छ–ज)	-	-	-	-	-	-	-
कुल अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (ञ= ग+छ+झ)	-	-	-	-	-	-	-

ख) विदेशी मुद्रा ऋणों की अनहेज्ड स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ लाख)

संस्था	अनहेज्ड स्थिति की राशि	
	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2026	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):–		
अमरीकी डालर	1,649.45	918.52
भारतीय रुपया	156,127.70	78,608.02
क्रेडिटनश्टाल्ट फ्यूर वीदारआउफबाउ (केएफडब्ल्यू):–		
यूरो	133.29	138.73
भारतीय रुपया	14,529.01	12,807.80
आईबीआरडी विश्व बैंक:–		
अमरीकी डालर	33.74	0.73
भारतीय रुपया	3,193.64	62.30
यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)		
यूरो	1,170.71	1,155.24
भारतीय रुपया	127,615.35	106,656.89
जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसी (जेआईसीए)		
जापानी येन	273,356.20	378,831.86
भारतीय रुपया	161,963.55	214,970.21
सुमितो मोमित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एसएमबीसी)		
जापानी येन	112,051.62	-
भारतीय रुपया	66,390.58	-

ग) लेखांकन नीति 20 के अनुसार, खातों के समापन की तारीख को प्रचलित विनिमय दरें (अर्थात् आईबीआई संदर्भ दरें) निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विनिमय दर	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2026	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025
1	भारतीय रूपया/अमेरिकी डॉलर	94.6543	85.5814
2	भारतीय रूपया/यूरो	109.006	92.3246
3	भारतीय रूपया/जापानी येन	0.5925	0.5675

15. बॉन्ड मोचन आरक्षित निधि का सृजन

घ) निजी रूप से रखे गए बॉन्ड के संबंध में : चूंकि कंपनी को केंद्र सरकार की दिनांक 14 जनवरी 2009 की अधिसूचना संख्या S.O.143 (E) (F.NO.3/5/2008) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) के अर्थ में सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है, इसलिए भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2013 को जारी परिपत्र संख्या 04/2013 के अनुसार निजी रूप से रखे गए बॉन्ड के संबंध में बॉन्ड मोचन आरक्षित निधि सृजित करना आवश्यक नहीं है।

ख) सार्वजनिक रूप से जारी बॉन्ड के संबंध में: कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से वित्त वर्ष 2012–13 में ₹ 1,000 अंकित मूल्य वाले कर–मुक्त बॉन्ड, कुल ₹ 3,15,631.89 लाख वित्त वर्ष 2013–14 में ₹ 6,87,754.25 लाख तथा वित्त वर्ष 2010–11 में ₹ 9,096.18 लाख के दीर्घकालिक अवसंरचना बॉन्ड जारी किए, जिनकी कुलराशि ₹ 10,12,482.32 लाख है।

कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 18(7)(ब)(ii) के अनुसार, आरबीआई (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45–II के अंतर्गत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी के लिए कंपनी को डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि (डीआरआर) सृजित करनी होगी। वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) विनियम, 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी

डिबेंचर के मूल्य का 25% डीआरआर की 'पर्याप्तता' होगी तथा निजी रूप से रखे गए डिबेंचर के मामले में आवश्यक नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2026 तक ₹54,462.29 लाख (31 मार्च 2025 तक ₹54,568.28 लाख) की बॉन्ड मोचन आरक्षित निधि सृजित की है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 19 अगस्त 2019 की अधिसूचना द्वारा कंपनी (शेयर पूंजी एवं डिबेंचर) नियमों में संशोधन किया है और तदनुसार कंपनी को अब मोचन योग्य गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर डिबेंचर मोचन आरक्षित निधि सृजित करना आवश्यक नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता समझौते में निहित प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुसार, यह बताया जाता है कि कंपनी ने ऐसे व्यक्तियों, सहयोगियों तथा फर्मों/कंपनियों को ऋण एवं ऋण के स्वरूप में अग्रिम नहीं दिए हैं, जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी ऋणी ने कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया है।

16. (क) आरबीआई ने आईआईएफसीएल को सार्वजनिक जमा राशियाँ स्वीकार किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्था का व्यवसाय करने के लिए दिनांक 9 सितंबर 2013 का पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया।

(ख) आरबीआई द्वारा एनबीएफसी एंड आईएफसी के लिए जारी विवेकपूर्ण मानदंड कंपनी पर लागू हैं।

(ग) कंपनी ने 31 मार्च 2026 के दौरान किसी भी ऋण खाते का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण नहीं किया है और 31 मार्च 2026 को इन खातों में कोई बकाया शेष नहीं है (31 मार्च 2025 को ₹ शून्य)। 31 मार्च 2026 को इन खातों में प्रतिभूति के मूल्य में कोई कमी नहीं है य नोट 1(।)(5.7)(अ) देखें।

17. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल हैं:

(₹ लाख)

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2026	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025
लेखा परीक्षा शुल्क	15.00	12.00
कराधान संबंधी मामले	2.40	2.40
प्रमाणन कार्य	2.50	1.06
सीमित समीक्षा	8.10	5.40
कुल	**28.00**	**20.86**

18. विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए लंबित आयकर निर्धारण की स्थिति निम्नानुसार है:

निर्धारण वर्ष	स्थिति
2016-17	धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 28.12.2018 का निर्धारण आदेश 28.12.2018 को प्राप्त हुआ। निर्धारण आदेश में की गई अस्वीकृतियों के विरुद्ध 25.01.2019 को सीआईटी (क) के समक्ष अपील दायर की गई तथा ₹137 लाख की कर मांग का 20% विरोध स्वरूप जमा किया गया और ₹46.71 लाख की राशि निर्धारण वर्ष 2011–12 के रिफंड से समायोजित की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी (क) के समक्ष अपील दायर की गई। धारा 250 सहपठित धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26.03.2025 को आदेश जारी किया गया, जिसमें अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। सीआईटी (क) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की गई।
	धारा 154 के अंतर्गत ₹519.18 लाख की अतिरिक्त राशि प्रस्तावित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ, जो धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के अतिरिक्त दावे से संबंधित था। इसके विरुद्ध 20.01.2023 को उत्तर प्रस्तुत किया गया। आईआईएफसीएल को धारा 154 के अंतर्गत इसी प्रकार का नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें ₹1,500.18 लाख की कर योग्य आय जोड़ी गई। आईआईएफसीएल ने 27 अप्रैल 2023 को उक्त आदेश के विरुद्ध सीआईटी (क) के समक्ष अपील दायर की। धारा 250 के अंतर्गत दिनांक 26.09.2024 का आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें दायर अपील को खारिज कर दिया गया। सीआईटी (क) द्वारा धारा 250 के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध 29.11.2024 को आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की गई, जो वर्तमान में लंबित है।
	उपर्युक्त दोनों अपीलों के संबंध में आईटीएटी ने 11.02.2026 को सामान्य आदेश जारी किया, जिसमें ₹1,556 लाख के आदेश को खारिज करते हुए ₹1,772 लाख की अस्वीकृति के लिए मामले को ।ब के पास पुनः भेज दिया गया।

निर्धारण वर्ष	स्थिति
2017-18	आईआईएफसीएल को आयकर विभाग द्वारा धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 17.12.2019 को पारित निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें ₹50.67 लाख के व्यय मद को अस्वीकृत किया गया। आईआईएफसीएल ने विलंब की माफी के लिए आवेदन सहित 15.03.2023 को सीआईटी (क) के समक्ष अपील दायर की। विलंब की माफी स्वीकृत नहीं होने के आधार पर सीआईटी (क) के समक्ष दायर अपील खारिज कर दी गई।
	धारा 154 के अंतर्गत ₹421.12 लाख की अतिरिक्त राशि प्रस्तावित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ, जो धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के अतिरिक्त दावे से संबंधित था। इसके विरुद्ध 12.12.2022 को उत्तर प्रस्तुत किया गया। आईआईएफसीएल को धारा 154 के अंतर्गत इसी प्रकार का नोटिस प्राप्त हुआ। इसका उत्तर 7 सितंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया। आईआईएफसीएल को धारा 154 के अंतर्गत दिनांक 31.05.2023 का एक अन्य आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें उत्तर पर विचार किए बिना ₹1,216.83 लाख की कर योग्य आय जोड़ी गई। सीआईटी (क) के समक्ष अपील लंबित थी और 05.12.2024 को धारा 250 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया, जिसमें आईआईएफसीएल के पक्ष में अपील स्वीकार की गई। विभाग ने उक्त आदेश के विरुद्ध आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की, जिसे पुनः आईआईएफसीएल के पक्ष में स्वीकार किया गया।
	धारा 148। के अंतर्गत दिनांक 01.03.2024 का नोटिस जारी किया गया। 05.12.2024 को धारा 250 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया, जिसमें आईआईएफसीएल के पक्ष में अपील स्वीकार की गई। धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में 25.06.2024 को ITR दाखिल किया गया। धारा 147 के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पत्र संख्या ITBA/AST/S/61/2024–25/1066229074(1), दिनांक 28.06.2024 के माध्यम से प्रारंभ की गई। दिनांक 04.12.2024, 14.12.2024, 22.12.2024, 24.12.2024 तथा 09.01.2025 के कई नोटिस जारी किए गए और उनके उत्तर आईटी पोर्टल पर अपलोड किए गए। धारा 147 के अंतर्गत 13.02.2025 को आदेश जारी किया गया, जिसमें ₹1,49,23,530/– की अस्वीकृति की गई। 13.03.2025 को सीआईटी (क) के समक्ष अपील दायर की गई। 25.11.2025 को सीआईटी (क) द्वारा आईआईएफसीएल की अपील खारिज करते हुए आदेश जारी किया गया। सीआईटी (क) के आदेश के विरुद्ध 22.01.2026 को आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की गई। 18.05.2026 तक आईटीएटी द्वारा उक्त मामले की सुनवाई की गई।
2018-19	धारा 148। के अंतर्गत दिनांक 17.08.2024 का नोटिस जारी किया गया। दिनांक 17.08.2024 के कारण बताओ नोटिस का उत्तर निर्धारित तिथि 26.08.2024 को प्रस्तुत किया गया। धारा 148।(क) के अंतर्गत दिनांक 31.08.2024 को आदेश पारित किया गया तथा 31.08.2024 के नोटिस के माध्यम से धारा 148 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसकी उत्तर प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि 30.11.2024 थी। धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में 29.11.2024 को ITR दाखिल किया गया। धारा 147 के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पत्र संख्या ITBA / AST/S/61/2025–26/1075729795(1), दिनांक 22.04.2025 के माध्यम से प्रारंभ की गई। दिनांक 15.05.2025, 16.05.2025, 29.05.2025, 17.09.2025 तथा 25.09.2025 के कई नोटिस जारी किए गए और उनका आईटी पोर्टल पर विधिवत उत्तर दिया गया। अधिनियम की धारा 147 सहपठित धारा 144ठ के अंतर्गत 19.02.2026 को आदेश जारी किया गया, जिसमें ₹29,48,28,5410/– की आय का निर्धारण किया गया और कोई अतिरिक्त राशि नहीं जोड़ी गई।
2020-21	कर लेखा परीक्षक द्वारा TAR में रिपोर्ट की गई आकस्मिक देयताओं की अस्वीकृति के कारण ₹26,65,81,260/– की मांग सृजित करते हुए 27.03.2025 को मांग नोटिस जारी किया गया। इन्हीं मुद्दों के आधार पर 04.08.2025 को एक अन्य मांग नोटिस जारी किया गया, जिससे मांग बढ़कर ₹51,31,20,590 हो गई। मांग नोटिस के विरुद्ध 18.04.2026 को धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दायर किया गया। ब्ब्ब द्वारा जारी सूचना आदेश के माध्यम से 19.05.2026 को मांग घटाकर ₹42,000 कर दी गई।
2024-25	24.06.2025 के नोटिस के माध्यम से फेसलेस निर्धारण कार्यवाही प्रारंभ की गई और इस संबंध में जारी नोटिसों के विरुद्ध विभाग को उत्तर प्रस्तुत किए गए। 13.03.2026 को धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया, जिसमें ₹2,23,28,64,899/– की अस्वीकृति करने के बाद ₹17,54,66,45,529/– की आय का निर्धारण किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध 10.04.2026 को सीआईटी (क) के समक्ष अपील दायर की गई।

19. अन्य प्रकटीकरण:

(क) 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹16,615.50 लाख की राशि वाले 3 ऋण खातों को बट्टे खाते में डाला (31 मार्च 2025 तक 7 ऋण खातों में ₹13,939.51 लाख की राशि बट्टे खाते में डाली गई थी)। कृपया टिप्पणी 1(क)(5.3) देखें।

(ख) आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशों के मूल्य में कमी के संबंध में ₹20,265.32 लाख का प्रावधान किया, जिसका विवरण निम्नानुसार हैरू

- अधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (एपीएनआरएल): वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, कंपनी ने मेसर्स आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड से संबंधित ₹ 52,000.00 लाख के बकाया ऋण मूलधन तथा उस पर ₹ 2,545.99 लाख के ब्याज एवं अन्य अतिदेय राशियों को ₹ 38,884.95 लाख के प्रतिफल पर एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी), जो एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है, को बेच दिया। इस प्रतिफल में ₹ 108.18 लाख की अग्रिम प्राप्ति, एपीएनआरएल की ₹ 9,710.71 लाख की इक्विटी शेयर पूँजी (अर्थात् ₹ 10 अंकित मूल्य वाले पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर) तथा ₹ 38,884.95 लाख की प्रतिभूति रसीदें शामिल थीं।
- ईएआरसी ने उसी समय एपीएनआरएल के ₹ 10 अंकित मूल्य वाले कुल 4,945.70 लाख इक्विटी शेयर ₹ 1.2045 प्रति शेयर की दर से खरीदे, जिनका कुल मूल्य ₹ 595.72 लाख था। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने ईएआरसी द्वारा उसे भुगतान की गई एपीएनआरएल के इक्विटी शेयरों की बिक्री कीमत को उचित मूल्य माना। परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2018 तक आईआईएफसीएल के पास शेष एपीएनआरएल इक्विटी शेयरों का मूल्य ₹ 1.2045 प्रति शेयर निर्धारित किया गया तथा निवेशों के मूल्य में कमी के लिए ₹ 4,191.05 लाख का प्रावधान किया गया। आईआईएफसीएल ने उपलब्ध नवीनतम उचित मूल्यांकन के आधार पर इक्विटी शेयर पूँजी का मूल्यांकन किया है।
- मेसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड: रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप, ₹ 8,000.00 लाख के बकाया ऋण में से ₹ 6,078.00 लाख का निपटान नए रियायतग्राही, बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी 0.01% वार्षिक कूपन दर वाले वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचरों के माध्यम से किया गया। शेष ₹ 1,922.00 लाख का बकाया ऋण नए रियायतग्राही, बंसल पाथवेज (मंगावन–चाकघाट) प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाना था। तदनुसार, निवेशों के मूल्य में कमी के लिए ₹ 4,779.68 लाख का प्रावधान किया गया। बंसल पाथवेज (मंगावन–चाकघाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डिबेंचर उनकी प्राप्ति की तारीख से 25 वर्ष बाद सममूल्य पर चुकाए जाने हैं।
- एमईपी नागपुर रिंग रोड–1 प्राइवेट लिमिटेड: 31 मार्च 2021 तक आईआईएफसीएल का ₹ 10,087.84 लाख का कुल बकाया मूलधन बंसल पाथवेज नागपुर रिंग रोड–1 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने ऊपर लिया गया। इसमें ₹ 2,811.84 लाख का सावधि ऋण तथा 0.01: कूपन दर वाले ₹ 7,276 लाख के डिबेंचर शामिल थे। तदनुसार, डिबेंचरों पर ₹ 4,451.99 लाख का प्रावधान किया गया।
- एमईपी नागपुर रिंग रोड–2 प्राइवेट लिमिटेड: 31 मार्च 2021 तक आईआईएफसीएल का ₹ 11,184.00 लाख का बकाया मूलधन बंसल पाथवेज नागपुर रिंग रोड–2 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 0.01: कूपन दर वाले डिबेंचरों के रूप में अपने ऊपर लिया गया। तदनुसार, इन डिबेंचरों पर ₹ 5,072.96 लाख का प्रावधान किया गया।
- मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड: आईआईएफसीएल का मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड में ₹ 22,137.32 लाख का मूलधन बकाया था। वर्ष 2019 में इस परियोजना को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत भेजा गया। वेदांता लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दिवाला समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने 10 अगस्त 2023 को स्वीकृति प्रदान की। इसके परिणामस्वरूप, आईआईएफसीएल को ₹ 14.93 करोड़ की अग्रिम राशि तथा ₹ 79.32 करोड़ के डिबेंचर प्राप्त हुए। इन डिबेंचरों पर निवेशों के मूल्य में कमी के लिए ₹ 1,769.63 लाख का प्रावधान किया गया।

(ग) 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार निवेश एवं सुरक्षा रसीदों का प्रकटीकरण: (₹ लाख)

विवरण		विगत 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	5 वर्ष से पहले लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	8 साल से पहले जारी किए गए प्रतिभूति रसीदें
(i)	बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य अंतर्निहित	73,254.54	-	-
	(i) धारित प्रावधान हेतु	-	-	-
(ii)	अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य अंतर्निहित के रूप में	-	-	-
	(ii) धारित प्रावधान हेतु	-	-	-
कुल (i) + (ii)		**73,254.54**	**-**	**-**

20. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर व्यय से संबंधित प्रकटीकरण

(क) सीएसआर व्यय में सम्मिलित विभिन्न व्यय मदों का विवरण (ब्रेक–अप): **(₹ लाख में)**

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजना का विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
01	जिला प्रशासन, चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश सरकार	अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग स्थित नायांग गाँव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन का निर्माण	-	124.66
02	जिला प्रशासन, मयूरभंज, ओडिशा	मयूरभंज, ओडिशा में नशामुक्ति एवं महिला सशक्तिकरण केंद्र	125.00	-
03	जिला प्रशासन, मयूरभंज, ओडिशा	अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में 4 स्वास्थ्य उप-केंद्रों का निर्माण	676.81	-
04	जिला परिषद, धौलपुर (राजस्थान)	धौलपुर (राजस्थान) में 50 डिजिटल संविधान घर (डीएसजी)	292.71	-
05	मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद	गुना (मध्य प्रदेश) के सरकारी विद्यालयों में 10 स्मार्ट कक्षाएँ (ई–पाठशाला)	43.00	-
06	समृद्ध ग्रामीण अभियान सोसाइटी	भरतपुर (राजस्थान) में हथौड़ी बावड़ी का जीर्णोद्धार	99.00	-
07	यूसीएसआरए* में स्थानांतरित		2,817.94	2,472.93
	कुल		**4,054.46**	**2,597.59**

क्योंकि यह राशि प्रगतिशील परियोजनाओं की है, इसलिए इसे 30.04.2026 को व्यय हेतु शेष सीएसआर लेखा में अंतरित कर दिया गया है (पिछले वर्ष 30.04.2025 को)।

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण:

1. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय कुल राशि ₹1,236.52 लाख

(₹ लाख में)

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2026			वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025		
	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना शेष	कुल	नकद में	नकद में भुगतान किया जाना शेष	कुल
(i) किसी आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण'	1,236.52	2,470.40	3,706.92	124.66	2,165.42	2,290.08
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	0	347.54	347.54	-	307.51	307.51
कुल	**1,236.52**	**2,817.94**	**4,054.46**	**124.66**	**2,472.93**	**2,597.59**

ii. वर्ष के अंत में कमी– शून्य (राशि ₹2,817.94 यूसीएसआरए को अंतरित कर दी गई है)

iii. विगत वर्ष की कुल कमी–शून्य

iv. कमी का कारण– आईआईएफसीएल की सीएसआर परियोजनाओं की पहचान पारदर्शी, बहु–चरणीय मूल्यांकन एवं अनुमोदन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है, जिसके अंतर्गत समुचित जाँच–पड़ताल और मूल्यांकन के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश सीएसआर पहलें बहुवर्षीय परियोजनाएँ होती हैं तथा उनका प्रारंभ स्थानीय प्राधिकरणों और वैधानिक निकायों से आवश्यक मंजूरियाँ एवं अनुमोदन प्राप्त करने सहित कार्यान्वयन संबंधी शर्तों की पूर्ति पर निर्भर करता है। अतः स्वीकृत सीएसआर राशि का पूर्ण उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में संभव नहीं हो पाता है और अप्रयुक्त राशि को अनुमोदित परियोजनाओं के समयबद्ध एवं उचित कार्यान्वयन हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में अप्रयुक्त सीएसआर खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

v. सीएसआर गतिविधियों की प्रकृतिः वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरणीय स्थिरता, विरासत संरक्षण, सड़क सुरक्षा तथा सामुदायिक बुनियादी ढाँचे के विकास के क्षेत्रों में सीएसआर पहलें संचालित कीं।

vi. संबंधित पक्षकार लेनदेन का विवरण जैसे प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट को अंशदान– लागू नहीं

vii. यदि संविदागत दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, तो वर्ष के दौरान प्रावधान में परिवर्तन अलग से दर्शाया जाएगा–₹ 4,827.90 लाख

21. गैर–बैंकिंग वित्तीय (नॉन–डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) कंपनीज प्रूडेंशियल नॉर्म्स (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2007 के पैराग्राफ 13 के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त जानकारी का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	
	बकाया राशि	बकाया राशि	बकाया राशि	बकाया राशि
देयता पक्षः				
(1) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गयाः				
(क) डिबेंचर : प्रतिभूत : अप्रतिभूत (सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने के अलावा)	1,138,545.40 2,222,000.00	-	11,39,336.50 1,866,000.00	-
(ख) आस्थगित ऋण	-	-	-	-
(ग) सावधि ऋण	1,794,549.00		1,523,874.69	
(घ) अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और उधार	-	-	-	-
(ड़) वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-
(च) सार्वजनिक जमा	-	-	-	-
(छ) अन्य ऋण (अल्पकालिक बैंक ऋण)	2,747,725.20	-	1,830,873.48	-
(2)(च) उपरोक्त का ब्रेक–अप (बकाया सार्वजनिक जमा सहित उस पर संचित ब्याज जिसे अभी तक नहीं चुकाया गया):				
(क) असुरक्षित डिबेंचरों के रूप में	-	-	-	-
(ख) आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचरों के रूप में अर्थात् ऐसे डिबेंचर जिनमें सुरक्षा के मूल्य में न्यूनता का अभाव हो	-	-	-	-
(ग) अन्य सार्वजनिक जमा	-	-	-	-

	बकाया राशि	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
आस्ति पक्ष :		
(3) ऋण और अग्रिम राशि का ब्रेक अप, जिसमें बिन प्राप्तियाँ शामिल हैं [नीचे (5) में शामिल नहीं है]:		
(क) प्रतिभूत	3,651,685.30	4,092,391.13
(ख) अप्रतिभूत	4,519,767.06	2,897,960.00
(4) पट्टे पर दी गई आस्ति और किराए पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य आस्तियों की गणना		
(i) विविध देनदारों के तहत पट्टा किराया सहित पट्टा आस्ति		
(क) वित्तीय पट्टा	-	-
(ख) प्रचालन पट्टा	-	-
(ii) विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉकः		
(क) किराए पर आस्ति		-
(ख) जब्त की गई आस्ति	-	-
(iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गिने जाने वाले अन्य ऋण		
(क) ऋण जहां आस्ति को पुनः कब्जे में कर लिया गया है	-	-
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-	-
(5) निवेश की विवरण		
वर्तमान निवेशः		
1. उद्धृतः		
(i) शेयरः (क) इक्विटी	-	-
(ख) वरीयता/प्राथमिकता	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
2. गैर–उद्धृतः		
(i) शेयरः (क) इक्विटी	-	-
(ख) वरीयता/प्राथमिकता	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
दीर्घकालिक निवेशः		
1. सूचीबद्धः		
(i) शेयरः (क) इक्विटी	-	-
(ख) वरीयता/प्राथमिकता	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-

	बकाया राशि	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
2. गैर-सूचीबद्ध:		
(i) शेयर: (क) इक्विटी (ख) वरीयता/प्राथमिकता	109,977.17	109,977.17
(ii) डिबेंचर और बांड	30,884.14	32,470.68
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	727,710.89	629,880.00
(v) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी के विरुद्ध अग्रिम) (वेंचर कैपिटल यूनिटों में निवेश)	566.06	601.56
(vi) सुरक्षा रसीदों में निवेश	73,254.54	88,591.97
कुल	**9,113,845.66**	**7,851,872.51**

(6) उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणग्राही समूह–वार वर्गीकरण:

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2026 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	3,579,858.74	4,430,865.21	8,010,723.95
कुल	**3,579,858.74**	**4,430,865.21**	**8,010,723.95**

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2025 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	3,958,186.83	2,856,619.76	6,814,806.59
कुल	**3,958,186.83**	**2,856,619.76**	**6,814,806.59**

(7) अंश एवं प्रतिभूतियाँ (कोटेड और अनकोटेड दोनों) में सभी निवेश (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशकसमूह–वार वर्गीकरण:

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2026 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	104,801.15	104,801.15
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	-	817,326.34	817,326.34

श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2025 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	104,801.15	104,801.15
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	-	734,660.31	734,660.31

(8) अन्य जानकारी

विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(i) सकल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबंधित पक्ष	-	-
(ख) संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	32,557.08	77,798.24
(ii) निवल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबंधित पक्ष		
(ख) संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	-	24,340.56
(iii) कर्ज चुकाव में अर्जित आस्ति	शून्य	शून्य

22. भारतीय रिजर्व बैंक (एनबीएफसी–स्केल आधारित विनियम) दिशानिर्देश, 2023 दिनांक 19.10.2023 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण

22.1 पूंजी (होल्डिंग कंपनी)

विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
सीआरएआर (%)	20.53%	23.44%
सीआरएआर–टियर I पूंजी (%)	19.28%	22.19%
सीआरएआर–टियर II पूंजी (%)	1.25%	1.25%
टियर II पूंजी के रूप में संकलित अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
शाश्वत ऋण साधनों के निर्गम से संकलित राशि	-	-

22.2 निवेश

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
1	निवेश का मूल्य		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	942,392.80	861,521.38
(क)	भारत में	839,316.66	758,445.23
(ख)	भारत के बाहर	103,076.15	103,076.15
(ii)	मूल्यह्रास के प्रावधान		
(क)	भारत में	20,265.32	22,059.91
(ख)	भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेश का निवल मूल्य	922,127.48	839,461.46

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
(क)	भारत में	819,051.33	734,660.33
(ख)	भारत के बाहर	103,076.15	103,076.15
2	निवेशों के मूल्यह्रास हेतु रखे गए प्रावधानों में परिवर्तन		
(i)	प्रारंभिक शेष	22,059.91	23,654.75
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / प्रतिलेखन	1,794.59	1,594.83
(iv)	अंतिम शेष	**20,265.32**	**22,059.91**

22.3 डेरिवेटिव

डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर:

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक है कि वे डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का विवरण दें, जिसमें विशेष रूप से डेरिवेटिव के उपयोग की सीमा, उनसे जुड़े जोखिमों तथा उनके द्वारा पूरे किए जाने वाले व्यावसायिक उद्देश्यों का उल्लेख हो। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के दिशानिर्देशों (यथासंशोधित) के अनुपालन में इसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

(क) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों से उत्पन्न मुद्रा एवं ब्याज दर संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है। कंपनी ने हेजिंग नीति लागू की है, जो संसाधन एवं ट्रेजरी नीति का एक हिस्सा है तथा जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। कंपनी के डेरिवेटिव लेनदेन इस नीति द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसमें अंतर्निहित देयताओं के अनुरूप हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय साधनों का विवरण दिया गया है।

(ख) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों से उत्पन्न ब्याज दर एवं मुद्रा संबंधी जोखिमों (बाजार जोखिम) की हेजिंग तथा उन्हें कम करने के उद्देश्य से डेरिवेटिव लेनदेन करता है।

(ग) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों से उत्पन्न विनिमय दर एवं ब्याज दर संबंधी जोखिमों की हेजिंग के लिए ही डेरिवेटिव लेनदेन करता है, किसी अन्य उद्देश्य से नहीं। निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन की शर्तें संबंधित अंतर्निहित देयताओं की शर्तों के अनुरूप रखी जाती हैं। हेजिंग के प्रारंभ में शर्तों के मिलान की अवधारणा के माध्यम से इस प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है।

(घ) आईआईएफसीएल डेरिवेटिव लेनदेन की स्थिति तथा उनके बाजार मूल्यांकन (एमटीएम) की जानकारी मासिक आधार पर वरिष्ठ प्रबंधन को और अर्धवार्षिक आधार पर निदेशक मंडल को देता है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल के संसाधन एवं ट्रेजरी सलाहकारों द्वारा एमटीएम की स्वतंत्र निगरानी भी अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है।

(ङ) आईआईएफसीएल की बही-खातों में एक्सचेंज पर कारोबार किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव की राशि शून्य है।

(च) आईआईएफसीएल अपनी विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिम स्थितियों की हेजिंग के लिए क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दर्शाए गए आँकड़ों को अलग-अलग वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूलधन एवं ब्याज के नकदी प्रवाह से संबंधित सौदे समेकित आधार पर दर्ज किए जाते हैं।

(छ) हेजिंग एवं गैर-हेजिंग लेनदेन के लेखांकन, आय, प्रीमियम एवं छूट की मान्यता, बकाया अनुबंधों के मूल्यांकन, प्रावधान, संपार्श्विक तथा ऋण जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित लेखांकन नीति का प्रकटीकरण लेखांकन नीति 1(क)(5.2) में किया गया है।

(ज) निदेशक मंडल की प्रबंधन एवं निवेश समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित संसाधन एवं ट्रेजरी नीति के अनुसार, आईआईएफसीएल कुल एक्सपोज़र के 65–70% तक अपनी जोखिम स्थिति को हेज करके रखेगा। इसके अतिरिक्त, अग्रिम प्रीमियम से होने वाली बचत को समायोजित करने के बाद खुली स्थिति से उत्पन्न विनिमय दर उतार-चढ़ाव का अंतर किसी भी समय कंपनी की निवल संपत्ति के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो के आधार पर रुपये का मूल्य 5% या उससे अधिक गिरता है, तो आईआईएफसीएल अपनी जोखिम स्थिति का लगभग 75% हेज करके रखेगा।

जोखिम प्रबंधन संरचना

(क) आईआईएफसीएल निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढाँचे के अनुसार जोखिमों का प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल की संसाधन एवं ट्रेजरी नीति को निदेशक मंडल की प्रबंधन एवं निवेश समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुमोदित किया जाता है। ये नीतियाँ एवं ढाँचे मार्गदर्शक मानदंड प्रदान करते हैं, जिनके आधार पर आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों के कारण उत्पन्न मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु निर्णय लेता है।

(ख) आईआईएफसीएल ने व्यावसायिक परिचालनों में जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए निदेशक मंडल स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति तथा परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ समिति) का भी गठन किया है। एएलसीओ समिति तरलता एवं ब्याज दर संबंधी जोखिमों की निगरानी करती है, जिसमें परिसंपत्तियों से प्राप्तियों तथा ऋण चुकौती संबंधी दायित्वों की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक तरलता स्थिति का आवधिक विश्लेषण शामिल है। डेरिवेटिव लेनदेन में देयताओं की हेजिंग के लिए क्रॉस-करेंसी स्वैप तथा मुद्रा स्वैप शामिल हैं। ये लेनदेन हेजिंग के उद्देश्य से किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टेबाजी के उद्देश्य से।

संबंधित जोखिमों के प्रकार

(क) जोखिमों के प्रकार

(I) ऋण जोखिम: ऋण जोखिम में उधारकर्ता की ऋण गुणवत्ता में गिरावट के कारण होने वाली हानि तथा ऋण या अग्रिम के अंतर्गत संविदात्मक पुनर्भुगतान करने में उधारकर्ता की चूक का जोखिम शामिल है। आईआईएफसीएल ने अवसंरचना क्षेत्र में ऋण प्रदान करने से संबंधित ऋण जोखिम के प्रबंधन हेतु एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढाँचा लागू किया है।

(II) बाजार जोखिम: बाजार जोखिम से तात्पर्य किसी वित्तीय साधन या वित्तीय साधनों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण होने वाली हानि के जोखिम से है। बाजार जोखिम में मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर में किसी भी परिवर्तन या उतार-चढ़ाव के कारण मुद्रा जोखिम उत्पन्न होता है। ब्याज दर जोखिम मुख्यतः समय के साथ ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। आईआईएफसीएल की व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत बाजार जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम विद्यमान हैं।

(III) तरलता जोखिम: तरलता जोखिम वह जोखिम है, जिसमें संस्था उचित लागत पर धन उधार लेकर वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने या लेनदेन निष्पादित करने में असमर्थ रहती है। इसमें बाजार तरलता जोखिम तथा वित्तपोषण तरलता जोखिम शामिल हो सकते हैं। आईआईएफसीएल पर्याप्त नकदी एवं विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ बनाए रखकर तथा पर्याप्त संयुक्त ऋण सीमाओं के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है।

(IV) परिचालन जोखिम: परिचालन जोखिम से तात्पर्य अपर्याप्त प्रणालियों एवं नियंत्रणों, सूचना प्रणाली की कमियों, मानवीय त्रुटियों या प्रबंधन की विफलता के कारण होने वाली हानि के जोखिम से है। आईआईएफसीएल की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य इन जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करना है।

(ख) तनाव परीक्षण:

आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा विनिमय दरों तथा ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली वित्तीय हानि के जोखिम का प्रबंधन करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है।

निम्नलिखित परिदृश्यों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो पर किए गए दबाव परीक्षणों तथा आय पर उनके संभावित प्रभाव का विवरण इस प्रकार है:

मान्यताएँ

31.03.2026 को लागू संदर्भ विनिमय दर (आधार स्थिति) के आधार पर रुपये के मूल्य में प्रतिशत गिरावट की मान्यता ली गई है। तदनुसार, विभिन्न शॉक परिदृश्यों के अंतर्गत मूल्यह्रास के बाद की विनिमय दरें निम्नानुसार हैं:

विनिमय दर यानी प्रति आईएनआर		आघात परिदृश्य		
	बेस केस	आधारभूत	मध्यम	जटिल
	आरबीआई संदर्भ दर (31.03.2026)	5%	10%	20%
यूएसडी	94.6543	99.3870	104.1197	113.5852
ईयूआर	109.0064	114.4567	119.9070	130.8077
जेपीवाई	0.5925	0.6221	0.6518	0.7110

बेंचमार्क दरें (एसओएफआर/यूरिबोर) तथा विभिन्न आघात परिदृश्यों के अंतर्गत दरें निम्नानुसार हैं:

बेंचमार्क ब्याज दर		आघात परिदृश्य		
	बेस केस	आधारभूत	मध्यम	जटिल
	बेंचमार्क ब्याज दरें (31.03.2026)	0.5%	1.00%	2.00%
एसओएफआर	3.86%	4.36%	4.86%	5.86%
यूरिबोर	2.48%	2.98%	3.48%	4.48%

पूर्ण मुद्रा स्वैप के माध्यम से हेज किए गए पोर्टफोलियो को आईएनआर के अवमूल्यन से अप्रभावित माना गया है।

विदेशी मुद्रा उधारियों पर ब्याज दर जोखिम के स्ट्रेस टेस्ट के लिए, शॉक परिदृश्य ब्याज दर के बेंचमार्क घटक में अपेक्षित वृद्धि के प्रतिशत को दर्शाते हैं। ब्याज दर के स्प्रेड घटक को स्थिर (अपरिवर्तित) माना गया है।

ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभाव केवल अनहेज्ड राशि तथा पीओएस के माध्यम से हेज की गई राशि पर ही लागू माना गया है।

परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन आधार परिदृश्य की तुलना में शॉक परिदृश्यों के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय अथवा आय में कमी के रूप में किया गया है।

भारतीय रूपये के मूल्यह्रास के कारण होने वाले प्रभाव

विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव ब्याज भुगतान और ऋण के भुगतान दोनों पर पड़ता है। हालांकि, फुल करेंसी स्वैप के जरिए हेज किए गए उधार विदेशी मुद्रा दरों में उतार–चढ़ाव से अप्रभावित रहते हैं।

क.) अनहेजेड और पीओएस हेजेड उधार पर ब्याज भुगतान पर भारतीय रूपये के मूल्यह्रास का प्रभाव

(₹ लाख में)

आघात परिदृश्य	आधारभूत	मध्यम	जटिल
	5%	10%	20%
यूएसडी	22.25	44.50	88.99
ईयूआर	2.69	5.38	10.75
जेपीवाई	1.29	2.59	5.17
कुल	**26.23**	**52.46**	**104.92**

2. असुरक्षित बकाया मूलधन पर भारतीय रुपये के मूल्यह्रास का प्रभाव:

(₹ करोड़)

आघात परिदृश्य	आधारभूत	मध्यम	जटिल
	5%	10%	20%
यूएसडी	79.66	159.32	318.64
ईयूआर	76.52	153.04	306.09
जेपीवाई	152.39	304.78	609.56
कुल	**308.57**	**617.14**	**1234.29**

3. भारतीय रुपये के मूल्यह्रास का कुल प्रभाव (क + ख): (₹ करोड़)

आघात परिदृश्य	आधारभूत	मध्यम	जटिल
	5%	10%	20%
यूएसडी	101.91	203.82	407.64
ईयूआर	79.21	158.42	316.84
जेपीवाई	153.68	307.36	614.73
कुल	**334.80**	**669.60**	**1339.21**

अनहेजेड और पीओएस हेजेड उधार पर ब्याज भुगतान पर भारतीय रूपये के मूल्यह्रास का प्रभाव

(₹ लाख में)

आघात परिदृश्य	आधारभूत	मध्यम	जटिल
ब्याज दर में परिवर्तन	0.50%	1.00%	2.00%
यूएसडी	49.76	99.51	199.03
ईयूआर	9.31	18.61	37.22
जेपीवाई	17.91	35.81	71.62
कुल	76.97	153.94	307.87

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों पर रुपये के मूल्यह्रास से होने वाला कुल अनुमानित प्रभाव आधारभूत परिदृश्य में ₹ 334.80 करोड़, मध्यम परिदृश्य में ₹ 669.60 करोड़ तथा गंभीर परिदृश्य में ₹ 1,339.21 करोड़ है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज दरों में क्रमशः 0.5% (आधारभूत परिदृश्य), 1.0% (मध्यम परिदृश्य) तथा 2.0% (गंभीर परिदृश्य) की वृद्धि मानते हुए, अनुमानित प्रभाव क्रमशः ₹ 76.97 करोड़, ₹ 153.94 करोड़ तथा ₹ 307.87 करोड़ है।

वायदा ब्याज दर समझौता/ब्याज दर अदला–बदली समझौता (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(i)	कल्पित मूलधन का स्वैप करार	994,817.02	956,768.00
(ii)	हानियाँ जो उपगत होंगी यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे	-	-
(iii)	स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण*	संदर्भ*	संदर्भ*
(iv)	स्वैप बही का उचित मूल्य	174,673.79	135,382.74

*कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वैप अनुबंध करती है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप अनुबंध, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में निर्धारित ऋण जोखिम सीमा के भीतर हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ लाख में))

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूलधन राशि)	994,817.02	994,817.02	956,768.00	956,768.00
	बचाव व्यवस्था के लिए	994,817.02	994,817.02	956,768.00	956,768.00
(ii)	बाजार से बाजार स्थितियां (1)	174,673.79	174,673.79	135,382.74	135,382.74
	क. आस्ति (+)	174,673.79	174,673.79	136,327.97	136,327.97
	ख. देयताएं (–)	-	-	945.23	945.23
(iii)	ऋण एक्सपोजर	-	-	-	-
(iv)	बिना बचाव वाले एक्सपोजर	5,29,819.82	5,29,819.82	413,122.10	413,122.10

22.4 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरणः

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल	-	-
(iii)	समस्त प्रतिफल	-	-
(iv)	पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल (लाभ)/हानि	-	-

22.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(i)	बेचे गए खातों की संख्या	2	-
(ii)	कुल बकाया	10,759.00	-
(iii)	कुल प्राप्त प्रतिफल	3,973.00*	-

*इसमें बकाया मूलधन शामिल है तथा ब्याज एवं अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।

22.6 आस्ति देयता प्रबंधनः

31 मार्च 2026 को आस्ति और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(₹ लाख में)

विवरण	1 दिन से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन	1 महीने से 2 महीने से ज्यादा	2 महीने से 3 महीने से ज्यादा	3 महीने से 6 महीने से ज्यादा	6 महीने से 1 साल से ज्यादा	1 साल से 3 साल से ज्यादा	3 साल से 5 साल से ज्यादा	5 साल से ज्यादा	कुल
जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	-	56.00	8,379.19	51,500.96	23,775.03	136,671.00	427,000.10	1,803,414.00	1,450,226.00	4,270,430.58	8,171,452.86
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	88,760.00	6,38,950.89	727,710.89
उधारियाँ / उधारी	-	-	-	-	-	-	-	917,879.56	156,000.00	2,286,665.84	3,360,545.40
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	-	-	4,503.96	7,158.87	34,659.03	22,652.20	70,229.01	294,660.67	485,374.42	875,310.84	1,794,548.99
बैंकों से उधारियाँ	33,137.84	382,495.39	0.00	326,826.88	538,351.64	167,319.00	0.00	1,239,596.36	60,000.00	0.00	2,747,727.11

31 मार्च 2025 की स्थिति में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की कुछ मदों की परिपक्वता रूपरेखाः

(₹ लाख में)

विवरण	1 दिन से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन	1 महीने से 2 महीने से ज्यादा	2 महीने से 3 महीने से ज्यादा	3 महीने से 6 महीने से ज्यादा	6 महीने से 1 साल से ज्यादा	1 साल से 3 साल से ज्यादा	3 साल से 5 साल से ज्यादा	5 साल से ज्यादा	कुल
जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	2.54	922.54	6,003.60	27,276.37	20,431.83	60,336.55	436,691.07	985,638.32	1,261,557.45	4,191,490.86	6,990,351.13
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,29,880.00	6,29,880.00
उधारियाँ / उधारी	-	-	-	-	-	-	791.10	348,251.71	569,627.85	2,086,665.84	3,005,336.50
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	-	-	9,519.52	5,618.45	30,007.66	11,007.07	57,207.53	240,253.68	260,874.80	909,385.98	1,523,874.69
बैंकों से उधारियाँ	47625.48	-	74,700.00	742,548.00	746,000.00	-	-	220,000.00	-	-	18,30,873.48

22.7 एक्सपोजर

22.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

31 मार्च 2026 (पिछले वर्ष शून्य) तक कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश नहीं है।

22.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजरः

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	-	-
(ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–उन्मुख म्युचुअल निधि की इकाइयों में निवेश के लिए स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां प्राथमिक सुरक्षा शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों के अलावा 'अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है;	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकर्स को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को दिए गए ऋणों को कम करना;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधियों में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	566.06	601.56

22.8 अतिरिक्त प्रकटीकरणः प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लाभ और हानि के वितरण में परिलक्षित प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(i)	एनपीए के लिए प्रावधान	20,265.32	22,059.91
(ii)	आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	32,557.08	53,457.67
(iii)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्गठित खातों और एसडीआर खातों सहित)	60,440.55	61,075.48
(iv)	मानक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान (पुनर्गठित खातों एवं SDR खातों सहित)	129,315.45	122,086.87

22.9 अग्रिमों का संकेंद्रण, एक्सपोजर और एनपीएः

(i) अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	4,423,960.82	4,146,112.68
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	54.14%	59.31%

(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल एक्सपोजर	4,423,960.82	4,146,112.68
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	54.14%	59.31%

(iii) एनपीए का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	32,557.08	67,538.08

(iv) क्षेत्रवार–एनपीए

क्र.सं.	क्षेत्र	एनपीए का सेक्टर % उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में	
		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2	एमएसएमई	-	-
3	कॉर्पोरेट उधारकर्ता	0.40%	1.11%
4	सेवाएं	-	-
5	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6	ऑटो ऋण	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(v) एनपीए में परिवर्तन

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(i)	निवल एनपीए से निवल अग्रिम (%)		0.00%	0.35%
(i)	निवल एनपीए से सकल अग्रिम (%)		0.00%	0.35%
(ii)	एनपीए परिवर्तन (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	77,798.24	82,315.97
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड/प्रत्यावर्तन	-	23,678.72
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	45,241.16	28,196.46
	(घ)	अंतिम शेष	32,557.08	77,798.24
(iii)	निवल एनपीए परिवर्तन			
	(क)	प्रारंभिक शेष	24,340.56	23,439.27
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड/प्रत्यावर्तन	-	11,666.75
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	24,340.56	10,765.46
	(घ)	अंतिम शेष	-	24,340.56
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार–चढाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	53,457.67	58,876.70
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड/प्रत्यावर्तन	(20,900.60)	9,123.17
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	-	14,542.20
	(घ)	अंतिम शेष	32,557.08	53,457.67

22.10 ग्राहकों की शिकायत

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(क)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	149	223
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	149	223
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

22.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण

क्र.सं.	प्रकटीकरण	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय नियामक से प्राप्त पंजीकरण / लाइसेंस / प्राधिकरण	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190DL2006GOI144520
(ii)	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और साल के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन	कंपनी द्वारा जारी किए गए घरेलू बॉन्ड्स को विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा AAA (स्टेबल) रेटिंग प्रदान की गई है। वर्तमान वर्ष 2025–25 के दौरान रेटिंग में कोई भी माइग्रेशन (परिवर्तन) नहीं हुआ है।
(iii)	किसी नियामक द्वारा लगाया गया दंड, यदि कोई हो,	शून्य
(iv)	सूचना अर्थात क्षेत्र, देश और संयुक्त उद्यम भागीदार	
	(क) संयुक्त उद्यम	कोई नहीं
	(ख) विदेशी सहायक कंपनियां	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी लंदन, यूनाइटेड किंगडम से संचालित होती है और भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है।

22.12 पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र	अन्य (₹ लाख में)					कुल (₹ लाख में)				
	आस्ति वर्गीकरण		कुल	कुल	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	योग
	विवरण													
1	01.04.2025 को पुनर्गठित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या			2.00	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	2.00
		बकाया राशि			22,177.56	-	-	-	22,177.56	22,177.56	-	-	-	22,177.56
		उस पर प्रावधान			1,520.71	-	-	-	1,520.71	1,520.71	-	-	-	1,520.71
2	31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान किया गया नवीन पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वे पुनर्गठित मानक अग्रिम, जिन पर वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार लागू नहीं रहता तथा इसलिए 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि में उन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान पुनर्गठित खातों का राइट–ऑफ / पूर्व भुगतान	उधारकर्ताओं की संख्या			1.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	1.00
		बकाया राशि			14,017.13	-	-	-	14,017.13	14,017.13	-	-	-	14,017.13
		उस पर प्रावधान			800.35	-	-	-	800.35	800.35	-	-	-	800.35
7	31 मार्च 2026 को पुनर्गठित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या			1.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	1.00
		बकाया राशि			8,160.43	-	-	-	8,160.43	8,160.43	-	-	-	8,160.43
		उस पर प्रावधान			720.35	-	-	-	720.35	720.35	-	-	-	720.35

22.13 विदेशी आस्ति (विदेश में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के लिए)

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य भागीदार	देश	कुल आस्ति ($ में राशि)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	शून्य, आईआईएफसीएल के पास आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की कोई विदेशी आस्ति नहीं है।

23. एनबीएफसी पर भारतीय रिजर्व बैंक के पैमाने आधारित विनियमन के अनुसार प्रकटीकरण:

क) रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश: आईआईएफसीएल का रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश टिप्पणी 1 (ख) 23.7.1 में प्रकट किया गया है।

ख) पूंजी बाजार में निवेश: आईआईएफसीएल का पूंजी बाजार में निवेश टिप्पणी 1 (ख) 23.7.2 में प्रकट किया गया है।

ग) खंडवार जोखिम

क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	कुल जोखिम (जिसमें बैलेंस शीट एवं बैलेंस शीट के बाहर का जोखिम शामिल है)	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल जोखिम के अनुपात में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल जोखिम (जिसमें बैलेंस शीट एवं बैलेंस शीट के बाहर का जोखिम शामिल है)	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल जोखिम के अनुपात में सकल एनपीए का प्रतिशत
कॉरपोरेट क्षेत्र	8,278,307.53	32,557.08	0.39%	7,070,577.11	77,798.24	1.10%

*इसमें बकाया शेष राशि तथा साख–पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) की बकाया राशि शामिल है।

(घ) समूह के भीतर जोखिमगत एक्सपोजर: आईआईएफसीएल के समूह के भीतर जोखिमगत एक्सपोजर का प्रकटीकरण टिप्पणी 1(ख) 5(ग) में किया गया है।

(ङ) असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर: आईआईएफसीएल के असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का प्रकटीकरण टिप्पणी 1(ख) 14(ख) में किया गया है।

(च) लागू गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का उल्लंघन करने का विवरण:

(क) 31.03.2026 तक सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची–शून्य।

(ख) 31.03.2026 तक सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची–शून्य।

(ग) 31.03.2026 तक सीमा से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची–शून्य।

(घ) 31.03.2026 तक सीमा से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची–शून्य।

(छ) संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण: आईआईएफसीएल के संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण टिप्पणी 1(ख) 5(ख) में किया गया है।

(ज) शिकायतों का प्रकटीकरण: आईआईएफसीएल की शिकायतों का प्रकटीकरण टिप्पणी 1(ख) 23.10 में किया गया है। इसके अतिरिक्त, शिकायतों के आधारों की संख्या को 'अन्य' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

(झ) अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन: शून्य।

(ञ) परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण में विसंगति: शून्य।

24. पूँजी प्रबंधन

भारतीय लेखा मानक–1 (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति) के पैरा 134 से 136 की आवश्यकताओं के अनुसार पूँजी प्रबंधन संबंधी प्रकटीकरण के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि आईआईएफसीएल एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी–आईएफसी) है। अतः आईआईएफसीएल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के अनुसार पूँजी, जिसे स्वामित्वगत निधि कहा जाता है, बनाए रखना आवश्यक है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनीदृप्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली कंपनी तथा जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार, स्वामित्वगत निधि में चुकता इक्विटी पूँजी, इक्विटी में अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर, मुक्त आरक्षित निधियाँ, शेयर प्रीमियम खाते की शेष राशि तथा परिसंपत्तियों की बिक्री से

प्राप्त अधिशेष को दर्शाने वाली पूँजीगत आरक्षित निधियाँ शामिल हैं। इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित आरक्षित निधियों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संचित हानि की शेष राशि, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य तथा, यदि कोई हो, आस्थगित राजस्व व्यय घटाया जाता है।

भारत सरकार ने समय–समय पर आईआईएफसीएल में पूँजी का निवेश किया है, जिससे कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूँजी संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम हुई है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल लाभांश के वितरण पर निर्णय लेते समय पूँजी अर्थात् शुद्ध स्वामित्वगत निधियों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखता है तथा भारत सरकार के निर्देशों का पालन करता है। रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान पूँजी प्रबंधन के उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

31 मार्च 2026 को आईआईएफसीएल का पूँजी पर्याप्तता अनुपात 20.53% था, जबकि 31 मार्च 2025 को यह 23.44% था। (संदर्भ:टिप्पणी 1(ख) 22.1)

25. वित्त मंत्रालय के निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. सं. 5/2/2016–पॉलिसी, दिनांक 18 नवंबर 2024 के माध्यम से 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूँजी पुनर्गठन संबंधी दिशानिर्देश' जारी किए। इन दिशानिर्देशों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश भुगतान, बोनस शेयर जारी करने, शेयरों की पुनर्खरीद तथा शेयरों के विभाजन का प्रावधान है। बोनस शेयर जारी करने तथा शेयरों के विभाजन से संबंधित दिशानिर्देश आईआईएफसीएल पर लागू नहीं होते हैं।

26. वित्त मंत्रालय के निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा 18 नवंबर 2024 को जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूँजी पुनर्गठन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कर–पश्चात लाभ (पीएटी) का न्यूनतम 30: अथवा निवल संपत्ति का 4:–इनमें से जो भी अधिक हो–वार्षिक लाभांश के रूप में देना आवश्यक है, बशर्ते कि लागू किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित सीमा का पालन किया जाए।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने 21 सितंबर 2016 के पत्र के माध्यम से भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक कम–से–कम तीन वर्षों के लिए लाभांश भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया था। इसके बाद, आईआईएफसीएल ने 19 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक लाभांश भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया। आईआईएफसीएल के पत्र के संबंध में भारत सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या त्तध्2021–22ध्59, क्व्ः।ब्त्म्ब्छव.23ध्21.02.067ध्2021–22, दिनांक 24 जून 2021 के अनुसार, किसी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए लाभांश घोषित करने हेतु यह न्यूनतम शर्त निर्धारित की गई है कि पिछले लगातार तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष, जिसमें उस वित्तीय वर्ष का समापन भी शामिल है जिसके लिए लाभांश घोषित किया जाना प्रस्तावित है, उसकी शुद्ध गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनएनपीए) 6: से कम हों।

उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के अनुसार, आईआईएफसीएल लाभांश घोषित करने के लिए पात्र नहीं था। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के संबंध में, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने क्रमशः 28 मार्च 2024 तथा 18 दिसंबर 2024 को आयोजित बैठकों में भारत सरकार से लाभांश भुगतान से छूट प्रदान करने का अनुरोध करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। तदनुसार, प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। आईआईएफसीएल के पत्र के संबंध में भारत सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के संबंध में, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 27 मार्च 2026 को आयोजित बैठक में भारत सरकार से लाभांश भुगतान से छूट प्रदान करने का अनुरोध करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। तदनुसार, प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। आईआईएफसीएल के पत्र के संबंध में भारत सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

27. नीति संख्या 1(क)(5.2(क)(क)) के अनुसार, ऋण परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित अग्रिम शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क, जो कुल आय के 0.5: से अधिक नहीं है, को प्रारंभ में उपार्जन आधार पर लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

28. एनबीसीसी लिमिटेड ने आईआईएफसीएल को किदवई नगर परिसर में निर्मित क्षेत्र (वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र एवं पार्किंग स्थल) पट्टाधिकार के आधार पर तथा नौरोजी नगर परिसर में निर्मित क्षेत्र (वाणिज्यिक क्षेत्र एवं पार्किंग स्थल) पूर्ण स्वामित्व के आधार पर आवंटित किया है। आवंटन की शर्तों के अनुसार, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, बिक्री प्रतिफल पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), अन्य संबंधित शुल्क, भू–लगान तथा संपत्ति कर का भुगतान एनबीसीसी द्वारा मांग किए जाने पर किया जाना है।

29. भारत सरकार ने 9 फरवरी 2012 के पत्र के माध्यम से आईआईएफसीएल को सूचित किया कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी), जिसे पहले दिल्ली–मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) के नाम से जाना जाता था, की 41% इक्विटी का अधिग्रहण आईआईएफसीएल द्वारा किया जाएगा। यह निर्णय इस तथ्य के

बावजूद लिया गया कि आईआईएफसीएल की गतिविधियों के संचालन हेतु लागू व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना (सिफ्टी) के अंतर्गत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना आईआईएफसीएल के अधिदेश में शामिल नहीं था।

एनआईसीडीसी की इक्विटी में बाद में किए गए अतिरिक्त निवेश के परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2012–13 में आईआईएफसीएल की शेयरधारिता घटकर 4.1% रह गई। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने इस निवेश का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया है।

30. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 27 मार्च 2020 तथा 17 अप्रैल 2020 को जारी कोविड–19 नियामकीय पैकेज संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को 29 फरवरी 2020 तक मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत सभी सावधि ऋणों की किस्तों के भुगतान पर तीन महीने की स्थगन अवधि प्रदान करने की अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने में उधारकर्ताओं की सहायता करना था।

प्रारंभ में, 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच देय सभी किस्तों, जिनमें मूलधन एवं ब्याज आदि शामिल थे, के भुगतान पर तीन महीने की स्थगन अवधि प्रदान की गई। 22 मई 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इस अवधि को तीन महीने और बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक कर दिया। स्थगन अवधि के दौरान ऋण की बकाया राशि पर ब्याज का उपार्जन जारी रहा। जिन खातों में स्थगन अवधि प्रदान की गई थी, उनमें इस अवधि के दौरान बकाया अवधि की गणना स्थिर रखी गई। ऋणदाताओं के लिए अपने ग्राहकों को स्थगन सुविधा देने से पहले निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति लागू करना आवश्यक था। ऋणदाताओं ने ग्राहकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए अलग–अलग तरीके अपनाए, जिनमें स्वैच्छिक चयन (ऑप्ट–इन) तथा स्वतः लागू होने के बाद बाहर निकलने का विकल्प (ऑप्ट–आउट) शामिल थे।

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुसार, आईआईएफसीएल ने पात्र मामलों में मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए स्वीकृत सावधि ऋणों के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान पर स्थगन सुविधा प्रदान की। ऐसे मामलों में सुविधा के अंतर्गत सृजित राशि का पुनर्भुगतान मूल सावधि ऋण की निर्धारित पुनर्भुगतान अवधि के भीतर किया जाना तय किया गया।

30 सितंबर 2020 को समाप्त अवधि के दौरान, आईआईएफसीएल ने 1 जुलाई 2015 के निर्देश संख्या DCB-BPD (PCB) MC No- 12 / 09.14.000 / 2015–16 के अनुसार, संबंधित मामलों को पुनर्गठन के रूप में वर्गीकृत किए बिना, स्थगन सुविधा वाले ऋण खातों में आस्थगित ब्याज आय को मान्यता दी। आईआईएफसीएल ने 12 नवंबर 2020 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से यह मार्गदर्शन मांगा कि आईआईएफसीएल द्वारा ब्याज आय की मान्यता नियामकीय प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का उत्तर अभी प्रतीक्षित है।

परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2021 तक आईआईएफसीएल ने स्थगन सुविधा वाले ऋण खातों में स्थगन अवधि से संबंधित ₹ 45,914.50 लाख की अप्राप्त ब्याज आय की मान्यता को वास्तविक प्राप्ति होने तक एहतियातन स्थगित रखा।

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, आईआईएफसीएल को ₹ 5,747.07 लाख की पुनर्भुगतान राशि प्राप्त हुई।

31. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 07.04.2021 को जारी "कोविड–19 नियामकीय पैकेज की अवधि समाप्त होने के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं आय की मान्यता" संबंधी परिपत्र के निर्देशों के अनुसार, बैंकों को 01.03.2020 से 31.08.2020 की स्थगन अवधि के दौरान कार्यशील पूँजी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले उधारकर्ताओं सहित सभी उधारकर्ताओं से वसूल किए गए 'ब्याज पर ब्याज' को वापस करना अथवा समायोजित करना आवश्यक है। यह निर्देश उन सभी उधारकर्ताओं पर लागू होता है, जिन्होंने स्थगन सुविधा का पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल भी लाभ नहीं उठाया था।

इन निर्देशों के अनुपालन में, विभिन्न ऋण सुविधाओं के लिए वापस की जाने वाली अथवा समायोजित की जाने वाली राशि की गणना की कार्यप्रणाली भारतीय बैंक संघ ने अन्य उद्योग प्रतिभागियों एवं संबंधित संस्थाओं के परामर्श से अंतिम रूप दी, ताकि सभी ऋणदाता संस्थाएँ इसे अपना सकें। तदनुसार, भारतीय बैंक संघ ने 19.04.2021 के अपने पत्र के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अंतिम रूप दी गई गणना–पद्धति की जानकारी दी। इसके अनुसार, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 2,500 लाख की अनुमानित ब्याज पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दी। इस ब्याज आय की राशि का लाभ अभी तक उधारकर्ताओं को नहीं दिया गया है।

32. कंपनी ने संबंधित सूचना ज्ञापनों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूलधन एवं अर्जित ब्याज के लिए सदैव पर्याप्त प्रतिभूति आवरण बनाए रखा है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च 2026 तथा 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्षों के दौरान ऋण प्रतिभूतियों एवं उन पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

33. भारतीय रिजर्व बैंक के 29 मार्च 2025 के परिपत्र संख्या आरबीआई / डीओआर / 2024–25 / 135 डीओआर–एसटीआर–आरईसी–72 / 21–04–048 / 2024–25 के अनुसार, सरकारी गारंटी प्राप्त प्रतिभूति रसीदों से संबंधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उस वर्ष लाभ–हानि खाते में अतिरिक्त प्रावधान को वापस लेने की अनुमति है, जिसमें ऋण को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को उसके शुद्ध बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है, बशर्ते प्रतिफल में केवल नकद राशि तथा भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदें शामिल हों।

ऐसी प्रतिभूति रसीदों का समय–समय पर मूल्यांकन संबंधित एआरसी द्वारा घोषित शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाना चाहिए, जो उन प्रतिभूतियों के लिए प्राप्त वसूली रेटिंग को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। 31.03.2026 को भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों के उचित मूल्यांकन के कारण आईआईएफसीएल ने ₹ 1,007.16 लाख की अप्राप्त हानि को लाभ–हानि विवरण में दर्ज किया है।

34. कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। बेनामी लेन–देन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 45) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के संबंध में कंपनी के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही प्रारंभ की गई है और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

35. कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था, जिसमें विदेशी संस्था भी शामिल है (जिसे 'मध्यस्थ' कहा गया है), को उधार ली गई निधियों, शेयर प्रीमियम अथवा किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से कोई अग्रिम राशि नहीं दी है, ऋण नहीं दिया है और न ही निवेश किया है। ऐसा कोई लेन–देन इस समझ के साथ नहीं किया गया है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की ओर से अथवा उसके द्वारा किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थियों') को ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा।

कंपनी को किसी व्यक्ति अथवा संस्था, जिसमें विदेशी संस्था भी शामिल है ('निधि प्रदाता'), से ऐसी कोई महत्वपूर्ण राशि, चाहे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्राप्त नहीं हुई है, जिसके संबंध में यह समझ हो, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निधि प्रदाता की ओर से अथवा उसके द्वारा किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ('अंतिम लाभार्थियों') को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की सुविधा प्रदान करेगी।

36. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत कंपनी रजिस्टर से हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं किया गया है।

37. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टोकरेंसी अथवा आभासी मुद्रा में न तो कारोबार किया है और न ही निवेश किया है।

38. किसी भी बैंक, वित्तीय संस्था, सरकार अथवा सरकारी प्राधिकरण द्वारा कंपनी को जानबूझकर ऋण चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

39. ऐसे कोई लेन–देन नहीं हैं, जिन्हें लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया हो और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष के दौरान कर निर्धारण में आय के रूप में समर्पित अथवा प्रकट किया गया हो।

40. कर व्यय तथा लेखांकन लाभ का भारतीय कर दर से गुणा करने पर प्राप्त राशि का मिलान (भारतीय लेखा मानक–12):

कर व्यय तथा कर–पूर्व लाभ पर भारत की लागू कॉर्पोरेट कर दर के गुणनफल के बीच सामंजस्य निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	198,382.57	277,552.92
सांविधिक आयकर दर	25.17%	25.17%
अपेक्षित आयकर व्यय	49,928.93	69,854.52
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) के तहत कटौती का लाभ	**-**	**-**
निवल प्रावधान अस्वीकृत	(3,728.80)	(3,652.25)
आयकर की गैर–अनुमति	20,924.85	1,467.80
विगत वर्ष के आयकर	(1,889.63)	(6.91)
अन्य	(2,950.01)	11,362.82
आस्थगित कर	(1,844.93)	(6,441.75)
कर व्यय	**(60,440.41)**	**(61,075.48)**

41. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह के लिए देनदारियों का समाधानः

(₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2025 को ओपनिंग बैलेंस	नकदी प्रवाह (शुद्ध)	अन्य परिवर्तन'	31 मार्च 2026 तक क्लोजिंग बैलेंस
उधारी	3,354,748.17	1,050,915.10	136,612.83	4,542,276.10
ऋण प्रतिभूतियों	3,005,336.50	355,208.90	-	3,005,336.50

*अन्य बदलावों में दीर्घकालिक उधार को फिर से शुरू करना, सहायक उधार लागत का समायोजन शामिल है।

विवरण	1 अप्रैल 2024 को ओपनिंग बैलेंस	नकदी प्रवाह (शुद्ध)	अन्य परिवर्तन*	31 मार्च 2025 तक क्लोजिंग बैलेंस
उधारी	2,700,858.25	631,154.08	22,735.84	3,354,748.17
ऋण प्रतिभूतियों	2,289,336.50	716,000.00	-	3,005,336.50

42. वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का उचित मूल्य मापन पदानुक्रम जिसे परिशोधन लागत (एमोर्टाइज्ड कॉस्ट)/ उचित मूल्य पर मापा गया है:

क. उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1– इनपुट समान परिसंपत्तियों या दायित्वों के लिए एक्टिव बाजारों में कोटेड कीमतें (बिना एडजस्ट की हुई) हैं, जिन्हें कंपनी मापन दिनांक की तिथि को प्रयोग कर सकती है।

स्तर 2– स्तर 1 में शामिल कोटेड कीमतों के अलावा, ऐसे इनपुट जो परिसंपत्तियों या दायित्वों के लिए प्रत्यक्ष सीधे या अप्रत्यक्ष (यानी कीमतों से प्राप्त)रूप से देखे जा सकते हैं। इस श्रेणी में ऐसे लिखत शामिल हैं जिनका वैल्यूएशन इन तरीकों से किया जाता है: समान लिखतके लिए एक्टिव बाजारों में कोटेड बाजार कीमतें या ऐसे बाजारों में समान या मिलते–जुलते लिखतके लिए कोटेड कीमतें जिन्हें कम एक्टिव माना जाता हैय या अन्य वैल्यूएशन तकनीकें जिनमें सभी महत्वपूर्ण इनपुट प्रत्यक्ष सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बाजार डेटा से देखे जा सकते हैं।

स्तर 3– इनपुट परिसंपत्तियों या दायित्वों के वैल्यूएशन के लिए अनदेखे इनपुट हैं, जिन्हें कंपनी मापन की तिथि पर प्रयोग कर सकती है। इस श्रेणी में वे सभी लिखत शामिल हैं जिनके लिए वैल्यूएशन तकनीक में ऐसे इनपुट शामिल हैं जो देखे नहीं जा सकते हैं और अनदेखे इनपुट का इंस्ट्रूमेंट के वैल्यूएशन पर काफी प्रभाव पड़ता है। इस कैटेगरी में ऐसे लिखत शामिल हैं जिनका वैल्यूएशन समान लिखत के लिए कोटेड कीमतों के आधार पर किया जाता है, जिनके लिए लिखत के बीच अंतर को दिखाने के लिए महत्वपूर्ण अनदेखे एडजस्टमेंट या मान्यताओं की आवश्यकता होती है। वैल्यूएशन तकनीकों में नेट प्रेजेंट वैल्यू और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, इनकम अप्रोच, समान लिखत के साथ तुलना जिनके लिए देखे जा सकने वाले बाजार मूल्य मौजूद हैं, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल और अन्य वैल्यूएशन मॉडल शामिल हैं।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्तिः			
परिशोधन लागत	-	-	9,525,612.41
एफवीटीपीएल	-	247,928.33	16,360.90
वित्तीय देयताः			
परिशोधन लागत	-	-	8,038,248.69

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्तिः			
परिशोधन लागत	-	-	7,851,448.98
एफवीटीपीएल	-	223,974.71	16,188.35
वित्तीय देयताः			
परिशोधन लागत	-	-	6,483,054.63

ख. परिशोधन लागत (एमोर्टाइज्डकॉस्ट) पर मापी गई वित्तियोंपरिसंपत्तियों और दायित्वों का उचित मूल्यः

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026		31.03.2025	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्ति	9,789,901.64	9,789,901.64	8,091,612.03	8,091,612.03
वित्तीय देयताएं	8,038,248.69	8,038,248.69	6,483,054.63	6,483,054.63

कंपनी विभिन्न प्रतिपक्षों (काउंटर पार्टियों), मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग वाले वित्तीय संस्थानों के साथ व्युत्पन्न वित्तीय लिखत करती है। क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप का वैल्यूएशन वैल्यूएशन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, जिसमें बाजार में देखे जा सकने वाले इनपुट का उपयोग किया जाता है। मॉडल में विभिन्न इनपुट शामिल हैं, जिसमें प्रतिपक्षों की क्रेडिट गुणवत्ता, विदेशी मुद्रा स्पॉट और फॉरवर्ड दरें, मुद्रा के यील्डकर्व, ब्याज दर कर्व और अंतर्निहित इंस्ट्रूमेंट के फॉरवर्ड दर कर्व शामिल हैं। प्रतिपक्षों क्रेडिट जोखिम में बदलाव का हेज संबंधों में नामित डेरिवेटिव के लिए हेज प्रभावशीलता मूल्यांकन पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा।

43. चरण–वार उधारी और ह्रास हानि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
31 मार्च 2026 तक				
कुल एक्सपोजर	8,138,074.94	633.06	32,557.08	8,171,265.08
हानि भत्ता	127,681.53	490.30	32,557.08	160,728.91
ईसीएल %	1.57%	77.45%	100.00%	1.97%
31 मार्च 2025 तक				
कुल एक्सपोजर	6,865,717.85	46,560.99	77,798.24	6,990,077.07
हानि भत्ता	97,941.45	22,941.08	53,457.67	175,544.54
ईसीएल %	1.43%	49.27%	68.71%	2.51%

44. आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानों का समन्वय तथा चरण–वार अपेक्षित ऋण हानि का प्रकटीकरण:

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष

(₹ लाख में)

भारतीय रिजर्व बैंके के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखाकंन मानक के अनुसार सकल धारणीय राशि	भारतीय लेखाकंन मानक 109 में अपेक्षित हानि भत्ता(प्रावधान)	निवल धारणीय राशि	आईआरसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखाकंन मानक 109 के प्रावधानों एवं आईआरसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	8,138,074.94	127,681.53	8,010,393.41	34,966.36	92,715.17
	चरण 2	633.06	490.30	142.76	345.27	145.03
उप–योग	एफआईटीएल	1,143.62	1,143.62	-	1,143.62	-
		8,139,851.62	129,315.45	8,010,536.17	36,455.25	92,860.20
गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
उप–योग	चरण 3					
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	-	-	-	-	-
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	32,557.08	32,557.08	-	32,557.08	-
संदिग्ध उप–योग		32,557.08	32,557.08	-	32,557.08	-
हानि	चरण 3	-	-	-	-	-
एनपीए का उप–योग		32,557.08	32,557.08	-	32,557.08	-
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताओं आदि जैसी अन्य मदें, जो इंड एएस 109 के दायरे में आती हैं, लेकिन वर्तमान आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।	चरण 1					
	उप–योग					
	चरण 3					
उप–योग		-	-	-	-	-
	चरण 1	8,138,074.94	127,681.53	8,010,393.41	34,966.36	92,715.17
	एफआईटीएल	1,143.62	1,143.62	-	1,143.62	-
	चरण 2	633.06	490.30	142.76	345.27	145.03
	चरण 3	32,557.08	32,557.08	-	32,557.08	-
	कुल	8,172,408.70	161,872.53	8,010,536.17	69,012.33	92,860.20

31 मार्च 2025 को

(₹ लाख में)

आरबीआई के मानदंडों के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	भारतीय लेखा मानक 109 के तहत आवश्यक हानि भत्ते (प्रावधान)	शुद्ध वहन राशि	आईआरएसीपी नियमों के अनुसार जरूरी प्रावधान	इंड एएस 109 प्रोविजन और आईआरए सीपी नॉर्म्स के बीच अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	6,865,717.85	99,145.79	6,766,572.06	27,560.41	71,585.38
	चरण 2	46,560.99	22,941.08	23,619.91	1,520.71	21,420.37
	एफआईटीएल	1,753.55	1,753.55	-	1,753.55	-
उप–योग		6,914,032.39	123,840.42	6,790,191.97	30,834.67	93,005.76
गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
	चरण 3	23,678.72	11,666.75	12,011.97	2,367.87	9,298.88
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	-	-	-	-	-
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	54,119.52	41,790.93	12,328.59	22,189.36	19,601.57
संदिग्ध उप–योग		54,119.52	41,790.93	12,328.59	22,189.36	19,601.57
हानि	चरण 3	0	0	0	0	0
एनपीए का उप–योग		77,798.24	53,457.67	24,340.56	24,557.23	28,900.44
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताओं आदि जैसी अन्य मदें, जो इंड एएस 109 के दायरे में आती हैं, लेकिन वर्तमान आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान (आईआर एसीपी) मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।	अवस्था 1			0		0
	चरण 2			0		0
	चरण 3			0		0
उप–योग		0	0	0	0	0
	चरण 1	6,865,717.85	99,145.79	6,766,572.06	27,560.41	71,585.38
	एफआईटीएल	1,753.55	1,753.55	-	1,753.55	-
	चरण 2	46,560.99	22,941.08	23,619.91	1,520.71	21,420.37
	चरण 3	77,798.24	53,457.67	24,340.56	24,557.23	28,900.44
	कुल	6,991,830.63	177,298.10	6,814,532.53	55,391.90	121,906.20

45. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुसार, 31 मार्च 2026 की स्थिति में लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा एवं लिक्विडिटी कवरेज अनुपात संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत लिक्विडिटी जोखिम का सार्वजनिक प्रकटीकरण:

प्रतिपक्ष के आधार पर वित्तपोषण का संकेंद्रण (उधारियाँ)

दिनांक	संख्या का महत्वपूर्ण प्रतिपक्षी*	मात्रा (रु. में करोड़)	% की देनदारियां
31.03.2026	15	60,595.22	76.68%

*महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्ष/महत्त्वपूर्ण लिखत/उत्पाद से तात्पर्य ऐसे एकल प्रतिपक्ष अथवा संबद्ध या सहयोगी प्रतिपक्षों के ऐसे समूह से है, जिसकी कुल देयताओं में कुल हिस्सेदारी 1% से अधिक हो।

शीर्ष 10 ऋणदाता (राशि ₹ करोड़ में तथा कुल उधारी के प्रतिशत के रूप में)

क्र.सं.	विवरण*	31.03.2026 को	
		राशि (₹ लाख)	उधार का कुल %
1	एशियाई विकास बैंक	11,798.91	15.35%
2	भारतीय स्टेट बैंक	7,494.32	9.75%
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	7,257.71	9.44%
4	पंजाब नेशनल बैंक	6,000.00	7.80%
5	जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी	2,040.53	2.65%
6	बैंक ऑफ बड़ौदा	2,000.00	2.60%
7	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन	1,540.50	2.00%
8	यूरोपीय निवेश बैंक	1,385.16	1.80%
9	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,379.00	1.79%
10	विश्व बैंक	1,035.10	1.35%
	कुल	41,931.22	54.54%

*बकाया बैंक उधारियों तथा बहुपक्षीयधद्विपक्षीय ऋणों के आधार पर।

महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्ष/महत्त्वपूर्ण लिखत/उत्पाद से तात्पर्य ऐसे एकल प्रतिपक्ष अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के ऐसे समूह से है, जिनकी कुल देयताओं में सामूहिक हिस्सेदारी 1: से अधिक हो।

महत्त्वपूर्ण लिखत/उत्पाद के आधार पर वित्तपोषण का संकेंद्रण

क्र.सं.	विवरण*	31.03.2026 को	
		राशि (₹ करोड़)	उधार का कुल %
1	**ऋण प्रतिभूतियाँ**		
	कर–योग्य घरेलू बॉण्ड	23,320.00	30.33%
	कर–मुक्त घरेलू बॉण्ड	10,285.46	13.38%
	घरेलू अवसंरचना बॉण्ड	0	0.00%
	वाणिज्यिक पत्र	0	0.00%
	उप–योग (1)	33,605.46	43.71%
2	**उधारियाँ**		
	रुपया सावधि ऋण	12,331.03	15.60%
	अल्पकालिक ऋण	12,997.47	16.45%
	विदेशी मुद्रा ऋण	17,945.49	22.71%
	सावधि जमा के बदले ओवरड्राफ्ट	2,148.82	2.72%
	उप–योग (2)	45,422.81	57.48%
	कुल (1+2)	**79,028.27**	**100.00%**

स्टॉक अनुपात

मानदंड	31.03.2026 को
कुल उधारियों की तुलना में वाणिज्यिक पत्र	0.00%
कुल देयताओं की तुलना में वाणिज्यिक पत्र	0.00%
कुल परिसंपत्तियों की तुलना में वाणिज्यिक पत्र	0.00%
कुल उधारियों की तुलना में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर	42.52%
कुल देयताओं की तुलना में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर	41.70%
कुल परिसंपत्तियों की तुलना में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर	34.12%
कुल उधारियों की तुलना में अन्य अल्पकालिक देयताएँ	15.60%
कुल देयताओं की तुलना में अन्य अल्पकालिक देयताएँ	15.30%
कुल परिसंपत्तियों की तुलना में अन्य अल्पकालिक देयताएँ	12.52%

लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन हेतु संस्थागत व्यवस्था

आईआईएफसीएल अपनी संसाधन एवं कोषागार नीति के अनुसार व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल में लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन उसकी परिसंपत्ति–दायित्व प्रबंधन रूपरेखा (एएलएम नीति) के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए संगठनात्मक व्यवस्था निम्नानुसार हैरू

- निदेशक मंडल
- जोखिम प्रबंधन समिति
- परिसंपत्ति–दायित्व प्रबंधन समिति
- जोखिम प्रबंधन विभाग

इसके अतिरिक्त, जोखिम प्रबंधन समिति निदेशक मंडल स्तर की एक समिति है, जिसमें गैर–कार्यकारी निदेशक, प्रबंध निदेशक तथा आईआईएफसीएल के उप प्रबंध निदेशक शामिल हैं। यह समिति लिक्विडिटी जोखिम सहित आईआईएफसीएल के समक्ष विद्यमान समग्र जोखिमों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

आईआईएफसीएल न केवल अपनी लिक्विडिटी की स्थिति का निरंतर आकलन करता है, बल्कि विभिन्न मान्यताओं के अंतर्गत भविष्य में लिक्विडिटी की आवश्यकताओं में होने वाले संभावित बदलावों का भी निम्नलिखित साधनों एवं तकनीकों के माध्यम से विश्लेषण करता हैरू

- समयावधि के अनुसार वर्गीकरण एवं संबंधित मान्यताएँ
- नकदी प्रवाह का आकलन–संरचनात्मक लिक्विडिटी रिपोर्ट
- गतिशील लिक्विडिटी रिपोर्ट
- सीमाओं की निगरानी
- स्टॉक–आधारित दृष्टिकोण–लिक्विडिटी अनुपात
- लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर)
- लिक्विडिटी जोखिम के लिए दबाव परीक्षण रूपरेखा
- वित्तपोषण रणनीति
- मुद्रा जोखिम
- आकस्मिक वित्तपोषण योजना

लिक्विडिटी कवरेज अनुपात का प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत ₹5,000 करोड़ से अधिक परिसंपत्ति आकार वाली सभी गैर–जमा स्वीकार करने वाली एनबीएफसी के लिए लिक्विडिटी कवरेज अनुपात (एलसीआर) लागू किया गया है।

इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एनबीएफसी के पास उच्च गुणवत्ता वाली पर्याप्त तरल परिसंपत्तियाँ (एचक्यूएलए) उपलब्ध हों, ताकि वे अगले 30 दिनों तक जारी रहने वाली किसी भी गंभीर लिक्विडिटी दबाव की स्थिति का सामना कर सकें।

दिशानिर्देशों के अनुसार, लिक्विडिटी कवरेज अनुपात की गणना अगले 30 कैलेंडर दिनों के दौरान उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों के कुल स्टॉक को शुद्ध नकदी बहिर्वाह (दबाव की स्थिति में अनुमानित नकदी बहिर्वाह में से अनुमानित नकदी अंतर्वाह घटाने के बाद) से विभाजित करके की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसी तरल परिसंपत्तियों से है, जिन्हें मूल्य में बहुत कम या बिना किसी हानि के आसानी से बेचा जा सकता है, तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा दबाव की स्थिति में धन प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, 01.12.2024 से आईआईएफसीएल के लिए न्यूनतम 100: लिक्विडिटी कवरेज अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। आईआईएफसीएल ने बैंकों में चालू खातों की शेष राशि तथा पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियाँ बनाए रखी हैं।

31.03.2026 को समाप्त तिमाही के लिए आँकड़े उस तिमाही के दौरान दैनिक प्रेक्षणों के साधारण औसत के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं।

उपलब्ध आँकड़ों से स्पष्ट है कि वर्तमान में आईआईएफसीएल का लिक्विडिटी कवरेज अनुपात नियामकीय निर्धारित 100% की सीमा के अनुरूप है।

लिक्विडिटी कवरेज अनुपात प्रकटीकरण प्रारूप–31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	जून 2025 को समाप्त तिमाही		सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही		दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही		मार्च 2026 को समाप्त तिमाही	
		कुल अभारित मान (औसत)	कुल भारित मान (औसत)	कुल अभारित मान (औसत)	कुल भारित मान (औसत)	कुल अभारित मान (औसत)	कुल भारित मान (औसत)	कुल अभारित मान (औसत)	कुल भारित मान (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियाँ									
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्ति (एचक्युएलए)	1700.14	1700.14	2784.71	2784.71	2870.09	2870.09	2231.89	2231.89
नकदी बहिर्वाह									
2	डिपॉजिट (डिपॉजिट लेने वाली कंपनियों के लिए)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	असुरक्षित थोक वित्तपोषण	-	-	-	-	-	-	-	-
4	सुरक्षित थोक वित्तपोषण	3990.70	4589.31	5665.90	6515.79	7517.95	8645.64	5248.30	6035.55
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिनमें	-	-	-	-	-	-	-	-
(i)	व्युत्पन्न उधारी (डेरिवेटिव एक्सपोजर) और दूसरी कोलैटरल जरूरतों से जुड़े आउटफ्लो	-	-	11.85	13.63	0.30	0.35	-	-
(ii)	ऋण उत्पाद पर फंडिंग के नुकसान से जुड़ा आउटफ्लो	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	ऋण और लिक्विडिटी सुविधाएं	735.19	845.47	926.83	1065.85	1238.13	1423.85	1206.43	1387.39
6	अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	223.18	256.66	70.40	80.96	205.47	236.29	366.75	421.77
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	-	-	-	-	-	-	-	-
8	**कुल नकदी बहिर्वाह**	4949.07	5691.43	6674.98	7676.23	8961.85	10306.13	6821.48	7844.70
नकदी प्रवाह									
9	सुरक्षित ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-
10	पूरी तरह से प्रदर्शन करने वाले एक्सपोजर से इनफ्लो	306.30	229.73	72.11	54.08	91.52	68.64	1685.16	1263.87
11	अन्य नकदी प्रवाह	7508.39	5631.29	8904.85	6678.64	9940.74	7455.555	8364.73	6273.55
12	कुल नकदी प्रवाह	7814.69	5861.02	8976.96	6732.72	10032.26	7524.20	10049.89	7537.42
कुल समायोजित मूल्य									
13	कुल (एचक्यूएलए)	1700.14	1700.14	2784.71	2784.71	2870.09	2870.09	2231.89	2231.89
14	कुल शुद्ध नकदी बहिर्वाह	1422.86	1422.86	1919.06	1919.06	2781.93	2781.93	1961.18	1961.18
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)	119.49	119.49	145.11	145.11	103.17	103.17	113.80	113.80

*01.01.2026 से 31.03.2026 तक की अवधि का औसत

46. निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा निदेशकों के रिश्तेदारों को दिए गए ऋणों का प्रकटीकरण

विवरण	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2026	वर्ष समाप्त 31 मार्च 2025
निदेशकों और उनके रिश्तेदार*	-	-
निदेशकों और उनके रिश्तेदारों से जुड़ी संस्थाएं	-	-
वरिष्ठ अधिकारी और उनके रिश्तेदार	-	-

*इसमें संबंधित निदेशकों के सेवा शर्तों के अनुसार ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

47. 21 जुलाई 2021 को दिनांकित आईआईएफसीएल के पत्र के प्रत्युत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्ट किया कि अवसंरचना परियोजनाओं हेतु बांड/डिबेंचर की सदस्यता के माध्यम से किया गया निवेश, जिसमें पुनर्वित्त भी शामिल है–चाहे परियोजनाएँ निर्माणाधीन हों अथवा पूर्ण–आईआईएफसीएल द्वारा अपनी कुल परिसंपत्तियों के न्यूनतम 75% को 'अवसंरचना ऋण' के रूप में परिनियोजित करने के उद्देश्य से 'अवसंरचना ऋण' माना जाएगा।

तदनुसार, आईआईएफसीएल ने सकल एनपीए (जीएनपीए) एवं शुद्ध एनपीए (एनएनपीए) अनुपातों के निर्धारण हेतु अवसंरचना परियोजनाओं के बांडों में की गई सदस्यता राशि को सम्मिलित किया।

हालाँकि, 31 मार्च 2023 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई की प्रारंभिक निरीक्षण एवं जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई कि कंपनी ने एनपीए अनुपातों की गणना करते समय बांडों में किए गए निवेश को ऋण एवं अग्रिम के रूप में शामिल किया है, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए अनुपात कम प्रदर्शित हुआ है।

इस संदर्भ में, आईआईएफसीएल ने आरबीआई को यह अवगत कराया है कि अवसंरचना परियोजनाओं के बांडों की सदस्यता को ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अतः सकल एवं शुद्ध एनपीए के निर्धारण हेतु ऋण एवं अग्रिम–जिसमें अवसंरचना परियोजनाओं के बांडों की सदस्यता राशि भी सम्मिलित है–को आधार बनाया गया है।

यदि अवसंरचना परियोजनाओं के बांडों की सदस्यता को ऋण एवं अग्रिम से पृथक रखा जाए, तो 31 मार्च 2026 को आईआईएफसीएल का सकल एनपीए 0.55% तथा शुद्ध एनपीए शून्य होगा (31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए क्रमशः 1.35% एवं 0.42%)।

48. धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत ऋण परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरणः

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
1	इंड भारत पावर (मद्रास) लिमिटेड	25 फरवरी 2015	31 दिसंबर 2016	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • तूतीकोरिन में 660 मेगावाट (1x660 मेगावाट) क्षमता के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना। **एनपीए घोषित किए जाने के कारण** • उधारकर्ता ने उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं, बैलेंस ऑफ प्लांट (बीओपी) आदि को कुछ अग्रिम भुगतान किए थे तथा शेष राशि का उपयोग किए जाने तक उसे सावधि जमा (एफडी) में रखा था। एक्सिस बैंक ने टीआरए बैंक के रूप में कार्य किया था। हालाँकि, उधारकर्ता की समूह कंपनियों ने कंसोर्टियम द्वारा वितरित धनराशि से बनाई गई इन सावधि जमाओं के विरुद्ध लगभग ₹577 करोड़ के अल्पकालिक ऋण प्राप्त किए थे। कंसोर्टियम ने उधारकर्ता और एक्सिस बैंक (टीआरए बैंक) को इस प्रकार अन्यत्र उपयोग की गई धनराशि वापस करने की सलाह दी, लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, सिविल / बीओपी ठेकेदार (सोकेओ पावर) को दिए गए लगभग ₹350 करोड़ के अग्रिम भुगतान का एक हिस्सा उधारकर्ता की समूह कंपनियों को वापस कर दिया गया, जिनका उपयोग भी परियोजना के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। • उधारकर्ता ने भुगतान के संबंध में कुछ प्रतिबद्धताएँ कीं, हालाँकि, इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई।	**धोखाधड़ी का कारण** • ऋणदाताओं के कंसोर्टियम ने फॉरेंसिक लेखापरीक्षा करने के लिए प्राइस वाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) को नियुक्त किया था, जिसमें लेखापरीक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ लेन-देन को दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 66 के तहत धोखाधड़ी वाले लेन-देन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने 22.03.2018 को खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी सूचना दी। **जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • ऋणदाताओं द्वारा फरवरी 2018 में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने 03.10.2018 को संदर्भ संख्या 196 के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। सीबीआई ने मामले की समीक्षा के लिए दिसंबर 2018 में बैठक बुलाई थी। • गृह मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने खाते को सीबीआई, बीएसएफबी, दिल्ली को अंतरित कर दिया और सीबीआई ने 29.04.2019 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। • सीबीआई ने 16 आरोपियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया, जिनमें श्री के. रघु रामा कृष्णा राजू (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक) और मधुसूदना रेड्डी (निदेशक) शामिल हैं। **कानूनी स्थिति/आगे की कार्यवाही** • टीआरए और संशोधित टीआरए के तहत अपने संविदात्मक दायित्वों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक के विरुद्ध स्थायी एवं अनिवार्य निषेधाज्ञा तथा क्षतिपूर्ति हेतु वाद 02.04.2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। कार्यवाही चल रही है। • उधारकर्ता को अगस्त 2017 में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, गारंटर के विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए सितंबर 2018 में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में आवेदन दायर किया गया। उधारकर्ता की दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में, समाधान आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना के गुण-दोषों पर विचार करने के बाद,

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
				• इंड-बाराथ पावर (मद्रास) लिमिटेड को ऋणों के लगातार भुगतान में चूक, ऋण दायित्वों को पूरा करने में असमर्थता तथा अंततः दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत दिवाला कार्यवाही शुरू होने के कारण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया।	ऋणदाताओं की समिति ने समाधान योजना से असहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने दिनांक 22.04.2019 के आदेश द्वारा खाते को परिसमापन हेतु भेज दिया। • वर्तमान में कंपनी परिसमापन के अधीन है, जिस पर रोक लगी हुई है। 09.04.2021 को माननीय एनसीएलटी ने धारा 66 के आवेदन में एक आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध दोनों ऋणदाताओं और परिसमापक ने एनसीएलएटी में अपील दायर की है, जिन पर आज की तारीख तक निर्णय लंबित है। • आईआईएफसीएल द्वारा प्रवर्तक कंपनी इंड भरत पावर इंफ्रा लिमिटेड के विरुद्ध सीआईआरपी शुरू की गई थी। हालांकि, माननीय एनसीएलएटी, चेन्नई पीठ ने 05.04.2023 के अंतरिम आदेश के माध्यम से ऋणदाताओं की समिति को निर्देश दिया कि "अगली सुनवाई की तारीख तक वह संबंधित मामले में आगे की कार्यवाही न करे।" 14.07.2025 के ई-मेल के अनुसार, सूचित किया गया कि "भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के अनुरोध पर माननीय एनसीएलएटी ने उक्त अपील को पूर्व-सूचीबद्ध किया था और वह 14 जुलाई 2025 को सूचीबद्ध थी।" अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने बहस शुरू की और मामला अब 29.05.2026 को सूचीबद्ध है। • कर्मचारी जवाबदेही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किसी कर्मचारी को जवाबदेह नहीं पाया गया।
2.	गंगोत्री झाबुआ जोबट कुक्षी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	14 फरवरी 2012	31 मार्च 2018	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • आईआईएफसीएल ने मध्य प्रदेश राज्य में राज्य राजमार्ग-39 के झाबुआ जोबट कुक्षी सड़क खंड को 0.00 किमी से 92.42 किमी (लंबाई 95.00 किमी) तक निर्माण-संचालन - हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर दो लेन में विकसित करने की परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए मैसर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित परियोजना के लिए ₹39.11 करोड़ का रुपया सावधि ऋण स्वीकृत और वितरित किया था।	**धोखाधड़ी का कारण** • फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एफएआर) के निष्कर्षों के आधार पर, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 21.12.2019 को आयोजित बैठक में खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने को मंजूरी दी थी। इसकी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई। **जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • आईआईएफसीएल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास शिकायत भेजी थी। हालांकि, सीबीआई ने शिकायत वापस करते हुए मुख्य बैंक द्वारा नई शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। आईआईएफसीएल ने मुख्य बैंक से मामले में नई शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया। • मुख्य बैंक, अर्थात् निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने नई दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दर्ज की। हालांकि, आर्थिक अपराध शाखा ने यह कहते हुए शिकायत बंद कर दी कि "जांच के दौरान वर्तमान मामले में कोई संज्ञेय अपराध बनता हुआ नहीं पाया गया।"

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
				एनपीए का कारण • परियोजना ने अगस्त 2018 में वाणिज्यिक परिचालन की तारीख प्राप्त कर ली थी। हालांकि, टोल संग्रह प्रारंभिक अनुमानों से कम रहा।	• खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत न किए जाने के संबंध में मुख्य बैंक ने सूचित किया कि धोखाधड़ी की राशि की वसूली/बट्टे खाते में डालने की प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए वे खाते को धोखाधड़ी के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं कर सकते। • इस बीच, सतर्कता विभाग की त्रैमासिक संरचित बैठक के दौरान टीम को आगे की कार्रवाई के बारे में केंद्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श करने की सलाह दी गई। **कानूनी स्थिति/आगे की कार्यवाही** • आईआईएफसीएल ने मार्च 2020 में ऋण वसूली अधिकरण में वाद दायर किया था। • मुख्य बैंक भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में है। • ऋणदाता परियोजना को समाप्त करने के लिए प्राधिकरण के साथ भी लगातार अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं। • कर्मचारी जवाबदेही संबंधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किसी भी कर्मचारी को जवाबदेह नहीं पाया गया।
3.	टॉपवर्थ टोलवेज (बेला) प्राइवेट लिमिटेड	03 फरवरी 2014	31 दिसंबर 2016	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • मध्य प्रदेश राज्य में सतना-बेला (एनएच-75) के 155.40 किमी से 198.600 किमी तक चार लेन वाले मार्ग का निर्माण, विकास, प्रबंधन और रखरखाव बीओटी आधार पर। परियोजना मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआरडीसी) द्वारा प्रदान की गई थी। **एनपीए का कारण** • परियोजना निर्धारित समय-सीमा से पीछे चल रही थी। • एमपीआरडीसी ने 29.05.2017 के अपने पत्र के माध्यम से रियायत करार समाप्त कर दिया था। • अग्रणी बैंक ने ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी), मुंबई में मूल आवेदन (ओए) दायर किया है।	**धोखाधड़ी का कारण** • फॉरेंसिक लेखापरीक्षक ने निम्नलिखित जानकारी दी थी: o 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार, 2013-14 में टॉपवर्थ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड (मूल/धारक कंपनी तथा ईपीसी ठेकेदार) को परिचालन अग्रिम और उपकरण अग्रिम के रूप में भुगतान की गई ₹42 करोड़ की प्रत्येक राशि में से ₹45.75 करोड़ अभी भी बकाया थे। o ₹8 करोड़ के असुरक्षित ऋणों का समायोजन टॉपवर्थ इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की ₹4.05 करोड़ की प्राप्य राशि और ₹3.95 करोड़ के उपकरण अग्रिमों से किया गया। o कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में करूर वैश्य बैंक में एक चालू खाता खोला और उसमें ₹5.79 करोड़ जमा किए, जिसे एस्क्रो व्यवस्था से बाहर अंतरित किया गया। • मुख्य बैंक ने परियोजना खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया। • मुख्य बैंक के अनुरूप आईआईएफसीएल ने भी परियोजना खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया और इसकी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को दी। **जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • मुंबई नगर दीवानी न्यायालय के 2020 के नोटिस ऑफ मोशन 519 के आदेश के अनुसार, ऋणदाताओं को उधारकर्ता कंपनी के खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किए जाने के आधार पर कोई भी जल्दबाजी

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					वाली कार्रवाई करने से रोका गया है। आईआईएफसीएल नियमित रूप से मामले का अनुसरण कर रहा है, लेकिन आगे कोई अद्यतन जानकारी नहीं है और रोक जारी है। **कानूनी स्थिति/आगे की कार्यवाही** • आईआईएफसीएल ने जनवरी 2019 में ऋण वसूली अधिकरण में मूल आवेदन दायर किया था (ओए 30/2021)। कार्यवाही चल रही है। • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने टॉपवर्थ टोलवेज (बेला) प्राइवेट लिमिटेड के कॉरपोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर श्री अभय नरेंद्र लोढ़ा के विरुद्ध दिवाला समाधान प्रक्रिया दायर की थी, जिसमें आईआईएफसीएल ने अपने दावे प्रस्तुत किए हैं। • कर्मचारी जवाबदेही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किसी कर्मचारी को जवाबदेह नहीं पाया गया।
4.	रांची एक्सप्रेसवेज लिमिटेड	26 अगस्त 2011	31 दिसंबर 2017	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • मधुकोन समूह द्वारा प्रोत्साहित इस परियोजना के अंतर्गत झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के चरण-III के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के राँची–रड़गाँव–जमशेदपुर खंड पर किलोमीटर 114.00 से किलोमीटर 277.500 तक सड़क को चार लेन का बनाया जाना था। इस परियोजना का क्रियान्वयन निर्माण, संचालन एवं हस्तांतरण आधार पर वार्षिकी मॉडल के अंतर्गत किया जाना था। रियायत प्रदान करने वाला प्राधिकरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। **एनपीए का कारण** • मार्गाधिकार की अनुपलब्धता, पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृतियाँ प्राप्त न होने तथा प्रवर्तकों द्वारा समय पर अपनी इक्विटी पूँजी का निवेश न किए जाने के कारण परियोजना प्रभावित हुई। • वर्तमान तिथि तक परियोजना में लगभग 50.24% भौतिक प्रगति हासिल की गई है।	**धोखाधड़ी का कारण** • फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, उधारकर्ता कंपनी के निदेशकों ने लेखा परीक्षकों के साथ मिलीभगत करके तथा प्रवर्तक समूह की कंपनियों के खातों का उपयोग करते हुए बैंकों के संघ से धोखाधड़ीपूर्वक ऋण राशि आहरित की। इस षड्यंत्र के परिणामस्वरूप, ₹264.01 करोड़ की राशि इक्विटी/अधीनस्थ ऋण के अंतर्गत धनराशि के चक्रीय हस्तांतरण, मोबिलाइजेशन अग्रिमों एवं सामग्री अग्रिमों के विचलन तथा सहमत शर्तों के अनुसार परियोजना कार्यों के लिए राशि का उपयोग न किए जाने के कारण अन्यत्र हस्तांतरित कर दी गई। आईआईएफसीएल सहित बैंकों के सभी संघीय ऋणदाताओं ने इस खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया है। **जाँच एजेंसी को रिपोर्ट किए जाने की स्थिति** • उच्च न्यायालय के निर्देश पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिनांक 12.03.2019 को इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है तथा जाँच जारी है। • ऋण वसूली अधिकरण, हैदराबाद में दिनांक 15.06.2020 को वाद दायर किया गया। कार्यवाही जारी है। • दिनांक 22.12.2023 को खाते को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में स्वीकार किया गया। आईआईएफसीएल के दावों को अनंतिम रूप से स्वीकार किया गया है। वर्तमान में, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा कार्यवाही पर स्थगन लगाया गया है। • मध्यस्थता कार्यवाही: कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई थी। कंपनी ने

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					लगभग ₹8,200.00 करोड़ के दावे प्रस्तुत किए थे, जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लगभग ₹2,860.00 करोड़ के प्रतिदावे प्रस्तुत किए थे। • दिनांक 15.05.2025 को आयोजित संयुक्त ऋणदाता बैठक में अग्रणी बैंक ने सूचित किया कि कंपनी ने मध्यस्थता समिति की फीस का भुगतान नहीं किया है, जिससे आगे की कार्यवाही बाधित होगी। • कर्मचारियों की जवाबदेही निर्धारित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तथा किसी भी कर्मचारी को जवाबदेह नहीं पाया गया।
5.	सेव एलएसवाई हाईवेज लिमिटेड	30 नवंबर 2011	30 सितंबर 2016	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • एसएच-57 के दिल्ली-सहारनपुर-यमुनोत्री (उत्तराखंड सीमा तक) खंड (10.911 किमी से 217.000 किमी) का चार लेन में विस्तार। **एनपीए का कारण** • परियोजना को रियायत प्रदान करने वाले प्राधिकरण अर्थात यूपीएसएचए द्वारा समाप्त कर दिया गया।	**धोखाधड़ी का कारण और जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • फरवरी 2017 में यूपीएसएचए ने धन के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कंपनी के निदेशकों, ऋणदाताओं के एलआईई और सनदी लेखाकारों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के पुलिस प्राधिकरण के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके क्रम में आईआईएफसीएल को अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) से पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उक्त परियोजना खाते से संबंधित जानकारी/दस्तावेज मांगे गए थे। आईआईएफसीएल इन्हें प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। • आईआईएफसीएल ने मुख्य बैंक के अनुरूप खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया है। • सीबीआई के पास शिकायत दर्ज की गई थी। **कानूनी स्थिति/आगे की कार्यवाही** • ऋणदाताओं ने 10.08.2017 को डीआरटी, हैदराबाद में संयुक्त वसूली वाद दायर किया है। कार्यवाही चल रही है। • ऋणदाताओं को एनएआरसीएल से आस्ति खरीदने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। आईआईएफसीएल ने स्विस चैलेंज प्रक्रिया संचालित करने के लिए मुख्य बैंक को अपना अधिदेश दिया है। • मुख्य बैंक ने स्विस चैलेंज प्रक्रिया के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी की है। • स्विस चैलेंज आयोजित करने पर कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। • कोई प्रति-बोली प्राप्त न होने के कारण ऋणदाताओं ने मार्च 2024 में एनएआरसीएल को ऋण अंतरित कर दिया। ऋण एक्सपोजर का अंतरण "जैसा है, जहां है", "जो कुछ है" और "बिना किसी सहारे के" आधार पर किया गया, अर्थात तनावग्रस्त ऋण से जुड़े ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम, कानूनी जोखिम या किसी अन्य प्रकार के जोखिम भी क्रेता/अर्जक (एनएआरसीएल) को अंतरित कर दिए गए।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					• आईआईएफसीएल को कंसोर्टियम में अपना हिस्सा प्राप्त हो गया है। • कर्मचारी जवाबदेही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किसी कर्मचारी को जवाबदेह नहीं पाया गया।
6.	जस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड	19 नवंबर 2011	31 अक्टूबर 2013	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • बिहार के बांका जिले में अभिजीत समूह की 1320 मेगावाट (2*660 मेगावाट) सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना। • नवंबर 2012 से परियोजना रुकी हुई थी और भौतिक प्रगति 28% थी। **एनपीए का कारण** • 30.10.2013 को आईआई एफसीएल के साथ खाता एनपीए श्रेणी में वर्गीकृत किया गया, क्योंकि अगस्त 2012 में परियोजना को आवंटित कैप्टिव कोयला ब्लॉक अगस्त 2012 में कोयला ब्लॉक आवंटन संबंधी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में सामने आया था।	**धोखाधड़ी का कारण** • फॉरेंसिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ कहा है कि उधार ली गई निधियां कोई आस्ति बनाए बिना उधारकर्ता कंपनी से समूह कंपनियों को अंतरित की गईं और बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से उधार ली गई निधियों का उपयोग उन उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए उन्हें उधार लिया गया था। • पीएनबी (दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता) ने खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया और मार्च 2019 में सीबीआई के पास शिकायत दर्ज की। फॉरेंसिक लेखापरीक्षा के आधार पर आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 29 जून 2020 को हुई बैठक में खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया। **जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • पीएनबी (दूसरे सबसे बड़े ऋणदाता) ने मार्च 2019 में सीबीआई के पास शिकायत दर्ज की। सीबीआई ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। पीएनबी ने सूचित किया कि नागपुर सिविल न्यायालय द्वारा रोक होने का उल्लेख करते हुए सीबीआई ने शिकायत वापस कर दी। पीएनबी ने यह भी बताया कि उसने कोई नई सीबीआई शिकायत दर्ज नहीं की है। आईआईएफसीएल नियमित रूप से मामले का अनुसरण कर रहा है, लेकिन आगे कोई अद्यतन जानकारी नहीं है और रोक जारी है। **कानूनी स्थिति/आगे की कार्यवाही** • आईआईएफसीएल ने पीएफसी और एसबीबीजे के साथ मिलकर एसीआरई द्वारा दिल्ली के ऋण वसूली अधिकरण में दायर वाद में भाग लिया है। • अक्टूबर 2016 में ऋण वसूली अधिकरण में वसूली आवेदन दायर किया गया था। मामले में 18.05.2026 को बहस के लिए सुनवाई निर्धारित है। • 20.01.2017 को ऋणदाताओं द्वारा किए गए संयुक्त स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि संयंत्र और मशीनरी गायब थी। उधारकर्ता को पुलिस शिकायत दर्ज कराने और बीमा दावा प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। हालांकि, कोई उत्तर नहीं मिला। • तदनुसार, आईआईएफसीएल ने 02.02.2017 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी किया।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					• पीएनबी द्वारा अक्टूबर 2019 में परियोजना को सीआईआरपी के अंतर्गत भेजा गया और इसे एनसीएलटी, कोलकाता में स्वीकार किया गया। रुचि की कोई अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त न होने के कारण ऋणदाताओं की समिति ने परिसमापन के लिए अपनी सहमति दी। परिसमापन के अंतर्गत कार्यवाही चल रही है। परिसमापन कार्यवाही एनसीएलटी, कोलकाता में जारी है। इसके अलावा, एनसीएलएटी और दिल्ली उच्च न्यायालय में अपीलें दायर की गई हैं। • कर्मचारी जवाबदेही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किसी कर्मचारी को जवाबदेह नहीं पाया गया।
7.	रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	01 मार्च 2016	31 दिसंबर 2017	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • परियोजना में चरणबद्ध तरीके से संचार प्रौद्योगिकी का उन्नयन शामिल था। चरण । में दूरसंचार विभाग (डीओटी) से स्पेक्ट्रम प्राप्त करने पर व्यय और चरण ॥ में 2जी/3जी/बीडब्ल्यूए तथा डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं से संबंधित मौजूदा दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार और क्षमता संवर्धन पर व्यय शामिल था। • आईआईएफसीएल ने चरण ॥ परियोजना के आंशिक वित्तपोषण में भाग लिया था। • भारतीय स्टेट बैंक को मुख्य बैंक और जेएलएफ संयोजक के रूप में रखते हुए 02/06/2017 से एक संयुक्त ऋणदाता मंच (जेएलएफ) गठित किया गया था। • कंपनी को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत भेजा गया था।	**धोखाधड़ी का कारण** • फॉरेंसिक लेखापरीक्षक (मैसर्स बीडीओ इंडिया एलएलपी) ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में देखा कि ₹15,436 करोड़ तक की उधार ली गई निधियों का उपयोग स्वीकृति पत्रों की शर्तों का अनुपालन न करते हुए किया गया। **जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • आईआईएफसीएल ने मार्च 2021 में खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया और 15.06.2021 को भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी सूचना दी। • मुख्य बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने सीबीआई के पास शिकायत दर्ज की। सीबीआई की शिकायत में आईआईएफसीएल का नाम शामिल करने के संबंध में भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 06.01.2021 के अंतरिम आदेश के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक को "यथास्थिति" बनाए रखने का निर्देश दिया था। • इसके बाद, मुख्य बैंक ने 31.05.2023 के ई-मेल के माध्यम से सूचित किया कि बैंक द्वारा धोखाधड़ी के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर 27.03.2023 के हालिया उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12.05.2023 के अपने आदेश के माध्यम से खाते को "धोखाधड़ी" घोषित करने की भारतीय स्टेट बैंक की कार्रवाई को रद्द कर दिया। अतः आगे की कार्रवाई करने से पहले मामले की पुनः जांच की जानी थी।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
				एनपीए का कारण • उच्च लागत, दूरसंचार क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा संपूर्ण दूरसंचार उद्योग में व्याप्त वित्तीय दबाव के कारण यह खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गया। • कुछ दूरसंचार सर्किलों में विभिन्न टैरिफ योजनाओं के युक्तिकरण तथा कुछ क्षेत्रों में नए ग्राहकों की संख्या में धीमी वृद्धि के कारण कुल आय में कमी आई।	• इस बीच, 12.10.2023 को हुई ऋणदाताओं की बैठक में चर्चा के अनुसार, आईआईएफसीएल ने अन्य ऋणदाताओं के अनुरूप उधारकर्ता/निदेशकों को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए। आईआईएफसीएल को उधारकर्ता/निदेशकों से प्राप्त प्रश्नों का आईआईएफसीएल द्वारा उत्तर दिया गया। • भारतीय स्टेट बैंक (मुख्य बैंक) ने 20 जून 2025 के ई-मेल के माध्यम से ऋणदाताओं को सूचित किया कि उसने 13.06.2025 के एफआईसी के माध्यम से आरसीओएम और उसके प्रवर्तक निदेशक-अनिल अंबानी के खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा, भारतीय स्टेट बैंक ने 19.09.2025 के ई-मेल के माध्यम से सूचित किया कि आरटीएल को जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया गया है और आरसीओएम की प्रक्रिया चल रही है। • भारतीय स्टेट बैंक ने 18.08.2025 को सीबीआई के पास शिकायत दर्ज की, जिसमें उसकी लगभग ₹2,929 करोड़ की देय राशि का उल्लेख किया गया। शिकायत में अन्य ऋणदाताओं की देय राशियां भी शामिल थीं, जिनमें आईआईएफसीएल की ₹248 करोड़ की देय राशि भी शामिल थी। इसके बाद, सीबीआई ने 21.08.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। • आईआईएफसीएल ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के नेतृत्व वाली परियोजना के चरण II में भाग लिया था। • बीओबी ने 24.02.2026 को सीबीआई के पास अलग शिकायत भी दर्ज की, जिसमें उसकी ₹2,223 करोड़ की देय राशि का उल्लेख किया गया। इसके बाद, सीबीआई ने 25.02.2026 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। • वर्तमान में जांच चल रही है। • चूंकि आईआईएफसीएल खाते को धोखाधड़ी के रूप में बनाए हुए है, इसलिए बीओबी के अनुरूप, धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) ने मार्च 2026 में हुई बैठक में उधारकर्ता के विरुद्ध सीबीआई के समक्ष शिकायत दर्ज करने की सलाह दी है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					कानूनी स्थिति/आगे की कार्यवाही • आईआईएफसीएल ने आरसीओएम के समाधान पेशेवर के समक्ष प्रपत्र सी के माध्यम से ₹328.59 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, चूंकि आरसीओएम, आरटीएल, आरआईटीएल और रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) द्वारा 16.06.2016 को आईआईएफसीएल की ओर से एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में बंधक विलेख निष्पादित किया गया था, आईआईएफसीएल ने आरआईटीएल, आरटीएल और आरसीआईएल के समाधान पेशेवरों के समक्ष दावा दायर किया था। • आरसीओएम और आरटीएल के लिए यूवीएआरसी तथा आरआईटीएल के लिए आरडीपीपीएसएल द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के पक्ष में 100% बहुमत से मतदान किया गया और आदेश के लिए समाधान पेशेवर द्वारा इसे एनसीएलटी, मुंबई में दायर किया गया। • आरसीओएम की सहायक कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की योजना अगस्त 2021 में प्रस्तुत की गई थी। रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (आरपीपीएमएसएल) द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को ऋणदाताओं की समिति ने मंजूरी दी। • एनसीएलटी ने आरआईटीएल के लिए आरडीपीपीएसएल की योजना को मंजूरी दी। अन्य दो संस्थाओं की समाधान योजनाओं को अभी मंजूरी मिलना बाकी है। • आईआईएफसीएल ने रिलायंस डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड प्रोजेक्ट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अपने अवसंरचना परियोजना प्रभाग के माध्यम से प्रस्तुत समाधान योजना के अनुसार रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड (आरआईटीएल) की कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के संबंध में समाधान पेशेवर को कोई-देयता-नहीं प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है, जो अभी प्राप्त होना बाकी है। • आरआईटीएल में स्वीकृत समाधान योजना में आईआईएफसीएल का हिस्सा लगभग ₹29 करोड़ (अर्थात ₹3,720 करोड़ का 0.80%) और आरसीआईएल में ₹3.77 करोड़ (अर्थात 0.83%) है। • कर्मचारी जवाबदेही संबंधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किसी कर्मचारी को जवाबदेह नहीं पाया गया।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
8.	ट्रांस्ट्रॉय ओबेदुल्लागंज बैतूल टोलवेज लिमिटेड	08 जनवरी 2013	31 दिसंबर 2016	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-69 के ओबेदुल्लागंज से बैतूल खंड को 2.800 किमी से 8.300 किमी और 20.700 किमी से 137.000 किमी तक (लगभग 121.36 किमी लंबाई) चार लेन में विकसित किया जाना था, जिसमें 8.300 किमी से 20.700 किमी तक वन्यजीव अभयारण्य को छोड़कर तथा 28.000 किमी से 61.500 किमी तक बाईपास को पक्के कंधे के साथ दो लेन के रूप में छोड़कर, एनएचडीपी चरण III के अंतर्गत डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) परियोजना के रूप में निष्पादित किया जाना था। • परियोजना एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई थी और निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन की तारीख 30.04.2015 थी। • आईआईएफसीएल ने परियोजना के लिए ₹160.00 करोड़ की सावधि ऋण सहायता स्वीकृत की थी।	**धोखाधड़ी का कारण** • फॉरेंसिक लेखापरीक्षक (मैसर्स सारथ एसोसिएट्स) ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया कि: • प्रवर्तक के अंशदान और बैंक ऋणों की कुल ₹453.48 करोड़ की राशि के अंतिम उपयोग का पूरी तरह सत्यापन नहीं किया जा सका, क्योंकि उधारकर्ता ने पूरी निधि ईपीसी ठेकेदार, अर्थात ट्रांस्ट्रॉय इंडिया लिमिटेड, को अंतरित कर दी थी और ईपीसी ठेकेदार ने ओबेदुल्लागंज और बैतूल सड़क परियोजना पर किए गए व्यय के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं किया। • ₹90.93 करोड़ की राशि आईडीसी प्रभारों के भुगतान में उपयोग की गई। ₹38.48 करोड़ को स्थल पर किए गए व्यय के रूप में दावा किया गया, लेकिन ऐसे व्यय के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। ₹324.07 करोड़ की शेष राशि का किसी सहायक दस्तावेज से स्वतंत्र रूप से सत्यापन नहीं किया जा सका। • एफएआर के निष्कर्षों के आधार पर आईआईएफसीएल ने जून 2021 में खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया। **जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • मुख्य बैंक ने सूचित किया कि उसने सभी सदस्य बैंकों की ओर से 30.09.2021 को दिल्ली स्थित सीबीआई के पास संयुक्त शिकायत दर्ज की थी। हालांकि, सीबीआई ने कुछ प्रश्न उठाए और मुख्य बैंक को शिकायत सीबीआई, बेंगलुरु में पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। • मुख्य बैंक ने 31.01.2023 और 09.11.2023 को सीबीआई के पास संशोधित शिकायत प्रस्तुत की। • मुख्य बैंक ने सूचित किया कि सीबीआई की शिकायत चौथी बार 30.05.2024 को प्रस्तुत की गई। हालांकि, सीबीआई, बीएसएफबी, बेंगलुरु ने 09.08.2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय के 27.03.2023 के एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल मामले के आदेश का हवाला देते हुए शिकायत वापस कर दी।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
				एनपीए का कारण • एनएचएआई ने 18.10.2016 को रियायतग्राही द्वारा परियोजना राजमार्ग को छोड़ देने, परियोजना के चरणबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त न करने, परियोजना राजमार्ग को यातायात योग्य स्थिति में बनाए न रखने और स्वतंत्र अभियंता को शुल्क का भुगतान न करने का हवाला देते हुए परियोजना समाप्त कर दी। • इसके अलावा, ऋणदाताओं की देय राशियों की सेवा न करने के कारण 31.12.2016 से आईआईएफसीएल के साथ खाता एनपीए हो गया।	• माननीय उच्चतम न्यायालय के 27.03.2023 के आदेश के अनुपालन में मुख्य बैंक ने 09.01.2025 और 08.07.2025 को क्रमशः उधारकर्ता/निदेशकों को कारण बताओ नोटिस और कारण बताओ नोटिस के उत्तरों पर प्रत्युत्तर नोटिस जारी किए। • आईआईएफसीएल ने भी 30.07.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किए और निदेशकों से उत्तर प्राप्त हुए। • संशोधित सीबीआई शिकायत प्रस्तुत की गई, लेकिन सीबीआई, नई दिल्ली ने 14.08.2025 के पत्र के माध्यम से यह कहते हुए शिकायत वापस कर दी कि "हमारे बैंक द्वारा शिकायत को धोखाधड़ी के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया है।" मुख्य बैंक शिकायत वापस किए जाने का कारण जानने के लिए सीबीआई के साथ लगातार संपर्क में है। आज की तारीख तक सीबीआई अधिकारियों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। आईआईएफसीएल इस मामले में मुख्य बैंक के साथ लगातार संपर्क में है। • एसपीवी के नामित निदेशक श्री श्रीधर चेरुकुरी के अनुरोध पर, उनके कारण बताओ नोटिस के उत्तर में, फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उसके अनुलग्नकों की एक प्रति उन्हें फिर से साझा की गई। साथ ही, एससीबीएमएफ के निर्णय के अनुसार उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी सूचित किया गया था। हालांकि, बैठक निर्धारित करने के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ। • तदनुसार, मार्च 2026 में हुई एससीबीएमएफ की बैठक में खाते को धोखाधड़ी के रूप में बनाए रखने का निर्णय लिया गया। **कानूनी स्थिति/आगे की कार्यवाही** • ऋणदाताओं, जिनमें आईआईएफसीएल भी शामिल है, की बकाया देय राशियों की अदायगी के लिए उधारकर्ता/प्रवर्तकों/प्रायोजकों/गारंटरों के विरुद्ध अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी किया गया।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					अक्टूबर 2017 में हैदराबाद के ऋण वसूली अधिकरण में संयुक्त वसूली वाद दायर किया गया था, जिसका ओए संख्या 678/2017 है और जिसमें निपटान की अनुमति दी गई। ऋण वसूली अधिकरण के आदेश के अनुसार, कंपनी ऋण वसूली अधिकरण के वाद में मूल आवेदन (ओए) में किए गए कंसोर्टियम के दावों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, परियोजना में कोई संपार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है। ऋणदाताओं द्वारा वसूली तंत्र तलाशा जा रहा है। • कर्मचारी जवाबदेही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किसी कर्मचारी को जवाबदेह नहीं पाया गया।
9.	ट्रांस्ट्रॉय होस्कोटे डोब्बासपेट टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	02 सितंबर 2013	30 सितंबर 2017	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • कर्नाटक राज्य में एनएच-207 के होस्कोटे - डोब्बासपेट खंड (58.300 किमी से 138.320 किमी) की मौजूदा सड़क को डीबीएफओटी आधार पर चार लेन में विकसित करना। • परियोजना एनएचएआई द्वारा प्रदान की गई थी। निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन की तारीख 08.02.2016 थी। • आईआईएफसीएल ने ₹112.00 करोड़ की सावधि ऋण सहायता स्वीकृत की थी। **एनपीए का कारण** • एनएचएआई ने मई 2017 में रियायतग्राही द्वारा परियोजना राजमार्ग को छोड़ देने, परियोजना के चरणबद्ध लक्ष्यों को प्राप्त न करने, सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजना राजमार्ग को यातायात	**धोखाधड़ी का कारण** • फॉरेंसिक लेखापरीक्षक (मैसर्स सारथ एसोसिएट्स) ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में देखा कि: • ईपीसी ठेकेदार (ट्रांस्ट्रॉय इंडिया) फॉरेंसिक लेखापरीक्षा के दौरान व्यय किए जाने के प्रमाण के रूप में एसपीवी द्वारा अंतरित निधियों के अभिलेख और सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा, जबकि इन्हें उपलब्ध कराने के लिए बार-बार प्रयास किए गए थे। इसके अलावा, वह यह स्पष्ट करने में भी विफल रहा कि कुल परियोजना लागत की 44.70% निधि के उपयोग के बावजूद कुल परियोजना का केवल 11.34% कार्य ही क्यों पूरा हुआ और निधि उपयोग तथा कार्य पूर्णता के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था। ईपीसी ठेकेदार द्वारा निधियों के विचलन की संभावना है। इसके अलावा, किए गए व्ययों का कोई उचित औचित्य नहीं दिया गया और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में भी सहयोग नहीं किया गया। • एफएआर के निष्कर्षों के आधार पर आईआईएफसीएल ने जून 2021 में खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया। **जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • आईआईएफसीएल ने अन्य संघीय ऋणदाताओं के अनुरूप मुख्य बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) को हैदराबाद की सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करने के

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
				योग्य स्थिति में बनाए न रखने और स्वतंत्र अभियंता को शुल्क का भुगतान न करने का हवाला देते हुए परियोजना समाप्त कर दी। • इसके अलावा, ऋणदाताओं की देय राशियों की सेवा न करने के कारण 30.09.2017 से आईआईएफसीएल के साथ खाता एनपीए हो गया।	लिए अधिदेश दिया था। मुख्य बैंक ने सूचित किया कि उसने 25.10.2021 को आवश्यक कार्रवाई के लिए दस्तावेज सीबीआई, दिल्ली को भेजे थे। हालांकि, सीबीआई ने कुछ प्रश्न उठाए और मुख्य बैंक को शिकायत सीबीआई, बेंगलुरु में पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। • मुख्य बैंक ने 19.01.2023 और 09.11.2023 को सीबीआई के पास संशोधित शिकायत प्रस्तुत की। • मुख्य बैंक ने चौथी बार 15.05.2024 को सीबीआई की शिकायत प्रस्तुत की। हालांकि, सीबीआई, बीएसएफबी, बेंगलुरु ने 09.08.2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय के 07.03.2023 के एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल मामले के आदेश का हवाला देते हुए शिकायत वापस कर दी। • माननीय उच्चतम न्यायालय के 27.03.2023 के आदेश के अनुपालन में मुख्य बैंक ने 09.01.2025 और 23.06.2025 को क्रमशः उधारकर्ता/निदेशकों को कारण बताओ नोटिस और कारण बताओ नोटिस के उत्तरों पर प्रत्युत्तर नोटिस जारी किए। • आईआईएफसीएल ने भी 30.07.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किए, लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। • चूंकि निर्धारित समय के भीतर उधारकर्ता या निदेशकों की ओर से कारण बताओ नोटिसों के विरुद्ध कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, एससीबीएमएफ ने दिसंबर 2025 में हुई बैठक में खाते को धोखाधड़ी के रूप में बनाए रखने का निर्णय लिया। • इस बीच, मुख्य बैंक ने संशोधित सीबीआई शिकायत प्रस्तुत की। सीबीआई ने ऋणदाताओं से दस्तावेजों की उपलब्धता की पुष्टि करने को कहा। यद्यपि आईआईएफसीएल ने दस्तावेजों की उपलब्धता की पुष्टि की थी, मुख्य बैंक ने 04.11.2025 के ई-मेल के माध्यम से सूचित किया कि शेष ऋणदाताओं से दस्तावेजों की उपलब्धता के संबंध में उत्तर न मिलने के कारण सीबीआई ने शिकायत वापस कर दी और पत्र के साथ एक अनुलग्नक प्रस्तुत करने को कहा।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					कानूनी स्थिति/आगे की कार्यवाही • ऋणदाताओं, जिनमें आईआईएफसीएल भी शामिल है, की बकाया देय राशियों की अदायगी के लिए उधारकर्ता/प्रवर्तकों/प्रायोजकों/गारंटरों के विरुद्ध अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी किया गया। 15.12.2018 को हैदराबाद के ऋण वसूली अधिकरण में संयुक्त वसूली वाद दायर किया गया था, जिसमें निपटान की अनुमति दी गई। • ऋण वसूली अधिकरण के आदेश के अनुसार, कंपनी ऋण वसूली अधिकरण के वाद में मूल आवेदन (ओए) में किए गए कंसोर्टियम के दावों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, परियोजना में कोई संपार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है। ऋणदाताओं द्वारा वसूली तंत्र तलाशा जा रहा है। • कर्मचारी जवाबदेही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किसी कर्मचारी को जवाबदेह नहीं पाया गया।
10.	ट्रांस्ट्रॉय भोपाल-बियावरा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	02.09.2013	31.01.2016	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के भोपाल-बियावरा खंड (316.10 किमी से 423.40 किमी) को डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) टोल आधार पर चार लेन में विकसित करना। • परियोजना एमपीआर डीसी द्वारा प्रदान की गई थी। परियोजना की निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन की तारीख 12.08.2014 निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में 20.05.2016 तक बढ़ाया गया। • आईआईएफसीएल ने उक्त परियोजना खाते के लिए ₹100.00 करोड़ की सावधि ऋण सहायता स्वीकृत की थी। **एनपीए का कारण** • एमपीआरडीसी ने मई 2016 में परियोजना को समाप्त कर दिया, जिसमें परियोजना के चरणबद्ध लक्ष्य प्राप्त न करना, स्वतंत्र अभियंता	**धोखाधड़ी का कारण** फॉरेंसिक लेखापरीक्षक (मैसर्स सारथ एसोसिएट्स) ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया कि: ₹711.59 करोड़ की कुल अनुमानित परियोजना लागत में से उधारकर्ता ने ₹499.92 करोड़, अर्थात 70.25%, व्यय किए थे, जबकि एलआईई रिपोर्ट के अनुसार केवल 43.15% कार्य पूरा हुआ था जबकि एमपीआरडीसीएल के पत्र में स्वतंत्र अभियंता द्वारा प्रमाणित पूर्णता केवल 18.64% थी। ईपीसी ठेकेदार इस अंतर का औचित्य सिद्ध नहीं कर सका और परियोजना पर किए गए ऐसे व्ययों के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध कराने में भी विफल रहा। ईपीसी ठेकेदार फॉरेंसिक लेखापरीक्षा के दौरान व्यय किए जाने के प्रमाण के रूप में एसपीवी द्वारा अंतरित निधियों के अभिलेख और सहायक दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा। इसके अलावा, वह यह स्पष्ट करने में भी विफल रहा कि कुल परियोजना लागत की 70.25% निधि के उपयोग के बावजूद कुल परियोजना का केवल 43.15% कार्य ही क्यों पूरा हुआ और निधि उपयोग तथा कार्य पूर्णता के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों था। ईपीसी ठेकेदार द्वारा निधियों के विचलन की संभावना है। इसके अलावा, किए गए व्ययों का कोई उचित औचित्य नहीं दिया गया और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में भी सहयोग नहीं किया गया। • एफएआर के निष्कर्षों के आधार पर आईआईएफसीएल ने जून 2021 में खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
				के शुल्क के संबंध में प्राधिकरण की देय राशि का भुगतान न करना, वित्तीय समापन प्राप्त करने में विलंब आदि तथा परियोजना स्थल पर निर्माण कार्य में तेजी लाने में विफलता का उल्लेख किया गया। • इसके अलावा, ऋणदाताओं की देय राशियों की सेवा न करने के कारण 31.01.2016 से आईआईएफसीएल के साथ खाता एनपीए हो गया।	**जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • आईआईएफसीएल ने अन्य संघीय ऋणदाताओं के साथ मिलकर मुख्य बैंक (सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) को हैदराबाद की सीबीआई के पास शिकायत दर्ज करने के लिए अधिदेश दिया था। मुख्य बैंक ने सूचित किया कि उसने 13.10.2021 को आवश्यक कार्रवाई के लिए दस्तावेज सीबीआई, दिल्ली को भेजे थे। • हालांकि, सीबीआई ने 06.01.2022 के पत्र के माध्यम से कुछ कमियां बताते हुए शिकायत वापस कर दी। • कंपनी और निदेशकों के विरुद्ध संशोधित सीबीआई शिकायत 04.02.2023 को सीबीआई, नई दिल्ली में प्रस्तुत की गई। हालांकि, सीबीआई, नई दिल्ली ने कुछ कमियों का उल्लेख करते हुए शिकायत वापस कर दी। • मुख्य बैंक ने 28.05.2024 को चौथी बार सीबीआई शिकायत प्रस्तुत की। हालांकि, सीबीआई, बीएसएफबी, बेंगलुरु ने 09.08.2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय के 27.03.2023 के एसबीआई बनाम राजेश अग्रवाल मामले के आदेश का हवाला देते हुए शिकायत वापस कर दी। • माननीय उच्चतम न्यायालय के 27.03.2023 के आदेश के अनुपालन में मुख्य बैंक ने 09.01.2025 और 08.07.2025 को क्रमशः उधारकर्ता/निदेशकों को कारण बताओ नोटिस और कारण बताओ नोटिस के उत्तरों पर प्रत्युत्तर नोटिस जारी किए। • आईआईएफसीएल ने भी 30.07.2025 को निदेशकों/प्रवर्तक/उधारकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किए। दोनों निदेशकों से उत्तर प्राप्त हुए। • आईआईएफसीएल द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्राप्त उत्तर की सामग्री के आधार पर एससीबीएमएफ ने दिसंबर 2025 में हुई बैठक में निर्णय लिया कि धोखाधड़ी का वर्गीकरण वापस नहीं लिया जाना चाहिए। • इस बीच, संशोधित सीबीआई शिकायत प्रस्तुत की गई। तथापि, सीबीआई, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 14.08.2025 के पत्र के माध्यम से यह कहते हुए शिकायत वापस कर दी कि "हमारे बैंक द्वारा शिकायत को धोखाधड़ी के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया गया है।" अग्रणी बैंक ने नई दिल्ली के नोडल अधिकारी से अनुरोध किया कि वे शिकायत लौटाए जाने के कारणों पर सीबीआई के साथ चर्चा करें, क्योंकि इसी प्रकार के एक अन्य खाते, मेसर्स ट्रांसस्ट्रॉय होसकोटे डोब्बासपेट टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड, के मामले में शिकायत को आगे की जाँच हेतु संसाधित किया गया था। तथापि, आज की तारीख तक सीबीआई के अधिकारियों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					कानूनी स्थिति/आगे की कार्यवाही • ऋणदाताओं, जिनमें आईआईएफसीएल भी शामिल है, की बकाया देय राशियों की अदायगी के लिए उधारकर्ता/प्रवर्तकों/प्रायोजकों/गारंटरों के विरुद्ध अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी किया गया। 16.10.2017 को हैदराबाद के ऋण वसूली अधिकरण में संयुक्त वसूली वाद दायर किया गया था। • ऋण वसूली अधिकरण के आदेश के अनुसार, कंपनी ऋण वसूली अधिकरण के वाद में मूल आवेदन (ओए) में किए गए कंसोर्टियम के दावों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, परियोजना में कोई संपार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है। ऋणदाताओं द्वारा वसूली तंत्र तलाशा जा रहा है। • कर्मचारी जवाबदेही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किसी कर्मचारी को जवाबदेह नहीं पाया गया।
11.	कीरतपुर नेर चौक एक्सप्रेसवेज लिमिटेड	05-जून-2012	31-दिसंबर-2018	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्यों में एनएचडीपी चरण III के अंतर्गत एनएच-21 के कीरतपुर-नेर चौक खंड को 73.200 किमी से 186.500 किमी तक डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) (टोल) आधार पर चार लेन में विकसित और निर्मित करना। **एनपीए का कारण** • प्राधिकरण द्वारा भूमि के अधिकार (आरओडब्लू) उपलब्ध कराने में देरी, रेलवे ओवरब्रिज तथा वन संबंधी मंजूरी प्रदान करने में विलंब जैसी बाध्यताओं को पूरा न किए जाने के कारण परियोजना के पूर्ण होने में देरी हुई। • नवंबर 2016 से परियोजना का कार्य पूरी तरह ठप पड़ा हुआ था तथा यह अभी तक वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि प्राप्त नहीं कर पाई थी। स्वतंत्र अभियंता की रिपोर्ट के अनुसार, परियोजना की भौतिक प्रगति 63.23% थी। • रियायतग्राही ने 23 जनवरी 2019 को समाप्ति नोटिस जारी किया था।	**धोखाधड़ी का कारण** • ऋणदाताओं द्वारा फॉरेंसिक लेखापरीक्षक (मैसर्स प्रकाश वेद एंड कंपनी) को नियुक्त किया गया था। फॉरेंसिक लेखापरीक्षक ने अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित निष्कर्ष दिया: o आर.बी.आई और विभिन्न एजेंसियों द्वारा समूह खातों के संबंध में की गई विभिन्न जांचों के अनुसार, यह पाया गया कि समूह की एक कंपनी आईएफआईएन वित्तपोषण के कारोबार में लगी हुई थी और उसने विभिन्न संस्थाओं/समूह कंपनियों को धन उधार दिया, जिन्होंने आगे आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड को ऋण दिया और इस प्रकार किसी एक कंपनी या समूह कंपनी में ऋण संकेंद्रण संबंधी आर.बी.आई के निर्देशों को दरकिनार किया गया। इन समूह कंपनियों ने माध्यम के रूप में कार्य करते हुए यह सुनिश्चित किया कि आईएफआईएन से लिए गए ऋण का चुकौती तब तक नहीं करना होगा जब तक आईटीएनएल उन्हें भुगतान न कर दे। निष्कर्षों के अनुसार, आईटीएनएल को मूल रूप से दिए गए ऋण के समनुदेशन के माध्यम से आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड की विशेष प्रयोजन संस्थाओं पर एक्सपोजर लिया गया था। o यह भी देखा गया कि एसपीवी की कुछ परियोजनाएं इसलिए समाप्त कर दी गईं क्योंकि एसपीवी द्वारा उन्हें समनुदेशित ऋणों के चुकौती के लिए निधियां उत्पन्न करने की कोई संभावना नहीं थी। नकदी प्रवाह में असंगति के कारण कंपनी ने अपर्याप्त निधियों के चलते गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूलधन और ब्याज की ₹20.91 करोड़ की देय राशि के भुगतान में चूक की। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
				• चूंकि यह खाता आईएल एंड एफएस की एक इकाई का है, इसलिए इसे अन्य समूह संस्थाओं के साथ एनसीएलटी को भेजा गया है। एनसीएलएटी द्वारा लगाए गए स्थगन के कारण इस समय 'आईएल एंड एफएस' और उसकी 348 समूह कंपनियों के विरुद्ध कोई वसूली/कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी।	अनुमोदित नीति नहीं थी और निवेश समीक्षा समिति तथा जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें भी नहीं हुई थीं। o कंपनी के अधिकारियों ने ऋणदाताओं को एनएचएआई के साथ समाप्ति करार के आह्वान के बारे में भी सूचित किया। इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप परियोजना का पतन हुआ और इसे घटिया आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया। • उपरोक्त के आधार पर, कंसोर्टियम के मुख्य बैंक ने 29.09.2021 के ई-मेल के माध्यम से कंसोर्टियम को सूचित किया कि उसने 22.09.2021 को कीरतपुर नेर चौक एक्सप्रेसवेज लिमिटेड (केएनसीईएल) के खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया था। • तदनुसार, मामला आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल की 12 नवंबर 2021 को हुई बैठक में रखा गया और निदेशक मंडल ने खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने का संकल्प लिया। **जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • आईआईएफसीएल ने कंसोर्टियम के ऋणदाताओं की ओर से संयुक्त शिकायत दर्ज करने के लिए मुख्य ऋणदाता को अधिदेश दिया। मुख्य बैंक ने 07.07.2022 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि शिकायत सीबीआई में दर्ज की गई थी। इसके बाद, सीबीआई ने 29.12.2023 के पत्र के माध्यम से 27.03.2023 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप शिकायत वापस कर दी। • माननीय उच्चतम न्यायालय के 27.03.2023 के आदेश के अनुपालन में आईआईएफसीएल और अन्य संघीय ऋणदाताओं ने उधारकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस के उत्तर में उधारकर्ता से प्राप्त उत्तर को मुख्य बैंक ने संतोषजनक नहीं पाया और सीबीआई के साथ संशोधित शिकायत दायर करने का निर्णय लिया गया। • आईआईएफसीएल द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्राप्त उत्तर को भी संतोषजनक नहीं पाया गया और दस्तावेज खाते में धोखाधड़ी की घोषणा की समीक्षा का

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					आधार नहीं बनते थे। तदनुसार, दिसंबर 2025 में हुई एससीबीएमएफ की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, आईआईएफसीएल खाते को धोखाधड़ी के रूप में बनाए हुए है। • इस बीच, संशोधित शिकायत दायर करने के लिए मुख्य बैंक ने सभी संघीय ऋणदाताओं से अधिदेश मांगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सभी ऋणदाताओं ने मुख्य बैंक को अधिदेश प्रदान किया। • मुख्य बैंक के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के दौरान उसने सूचित किया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सीबीआई) ने एनसीएलएटी के उस आदेश का उल्लेख किया है, जिसके द्वारा पेशेवर निदेशकों को संरक्षण दिया गया है, जिसके कारण बैंक उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तदनुसार, उसने पूछा है कि क्या मुख्य बैंक/सदस्य बैंकों ने कंपनी और उसके निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए एनसीएलएटी का रुख किया है। • मामले पर चर्चा करने और आगे की राह तय करने के लिए मुख्य बैंक ने संकेत दिया कि वह अप्रैल 2026 में एक संयुक्त ऋणदाता बैठक आयोजित करेगा। **कानूनी स्थिति/आगे की कार्यवाही** • एनसीएलटी ने 24.02.2021 के आदेश के माध्यम से एनएचएआई और कीरतपुर नेर चौक एक्सप्रेसवेज लिमिटेड (केएनसीईएल) के बीच समझौते के संबंध में आईएल एंड एफएस समूह के लिए अनुमोदित संशोधित वितरण ढांचे के अनुसार वितरण हेतु केएनसीईएल में ₹672.62 करोड़ की राशि मंजूर की थी। • एनएचएआई ने 31.03.2021 को एस्क्रो खाते में ₹662.53 करोड़ जारी किए। आईआईएफसीएल को 09.04.2021 को ₹122.80 करोड़ की अपनी हिस्सेदारी प्राप्त हुई। • कर्मचारी जवाबदेही की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और किसी कर्मचारी को जवाबदेह नहीं पाया गया।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
12.	सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड	25.06.2007	30.06.2016	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • परियोजना को पीएमडीओ सुविधा के अंतर्गत स्वीकृत किया गया था। आईआईएफसीएल ने 25.06.2007 को गुजरात के सूरत के निकट एक कपड़ा पार्क के लिए सामान्य अवसंरचना सुविधा को स्थापित करने हेतु परियोजना को ₹2.51 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। • पीएमडीओ सुविधा के अंतर्गत एसएसवाईपीएल को ₹51.74 करोड़ का सावधि ऋण वितरित किया गया। • परियोजना ने अगस्त 2011 में परिचालन शुरू किया। **एनपीए का कारण** • कार्य आदेश प्राप्त करने में लगातार कठिनाई के कारण एफआईटीएल पर ब्याज का भुगतान प्रवर्तकों ने अपने स्रोतों से किया। इसके बाद 30.06.2016 को खाता एनपीए घोषित हो गया।	**धोखाधड़ी का कारण और जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • पीएमडीओ के ऋणदाताओं ने इस खाते की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा करने के लिए दिल्ली की सनदी लेखाकार फर्म एसपी चोपड़ा को नियुक्त किया। एसपी चोपड़ा ने धोखाधड़ी के पहलू के संबंध में कोई निष्कर्ष दिए बिना उधारकर्ता को असहयोगी घोषित किया। • उधारकर्ता के असहयोगी होने और धोखाधड़ी के पहलू पर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सदस्य ऋणदाताओं ने आस्ति प्रबंधक को किसी अन्य सनदी लेखाकार फर्म को नियुक्त करने और लेखापरीक्षा का दायरा केवल पीएमडीओ ऋण के उपयोग तक सीमित रखने की सलाह दी। तदनुसार, एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी, दिल्ली को उपर्युक्त दायरे के साथ परियोजना की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया और रिपोर्ट ऋणदाताओं के बीच साझा की गई। हालांकि, एएसए ने संकेत दिया कि दिए गए सीमित दायरे के कारण रिपोर्ट में धोखाधड़ी के पहलू के संबंध में निष्कर्ष निकालना कठिन होगा। • इस बीच, एसपी चोपड़ा की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर पंद्रह ऋणदाताओं में से इंडियन बैंक, पीएनबी और केनरा बैंक ने उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद क्रमशः 09.02.2024, 25.07.2024 और 07.12.2024 को खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया। इसके अलावा, पीएनबी ने 04.11.2024 को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की और जांच चल रही है। पीएनबी के अनुरोध के अनुसार, आस्ति प्रबंधक आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली के साथ सत्यापन के लिए मूल ऋण दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। • सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एसएसवाईपीएल और उसके निदेशकों को खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया और श्री बाबूलाल

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					जैन तथा श्री कार्तिक जैन (पार्क के निदेशक) से एसपी चोपड़ा की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा में की गई टिप्पणियों पर आपत्तियां प्राप्त कीं। आस्ति प्रबंधक के कई प्रयासों के बावजूद एसपी चोपड़ा ने पार्क के निदेशकों द्वारा फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उठाई गई आपत्तियों का अभी तक उत्तर नहीं दिया है। • आईडीबीआई बैंक ने संकेत दिया कि वह भी एसपी चोपड़ा की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने की प्रक्रिया में था और उसने जुलाई 2025 के अंत में एसएसवाईपीएल के निदेशकों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया। • सेंट्रल बैंक और आईडीबीआई बैंक दोनों ने अभी तक खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित नहीं किया है। • इस बीच, 17 अप्रैल 2026 को आयोजित पीएमडीओ सुविधा की ऋण समिति की 79वीं बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, यह निर्णय लिया गया कि सूरत सुपर यार्न पार्क लिमिटेड की नई फॉरेंसिक लेखापरीक्षा एएआर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार फर्म के माध्यम से कराई जाएगी। • इस बीच, आईआईएफसीएल ने दिसंबर 2025 में उधारकर्ता, प्रवर्तकों/निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। आईआईएफसीएल द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर में प्राप्त उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर, मार्च 2025 में हुई धोखाधड़ी के मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) की बैठक की सिफारिश के आधार पर, आईआईएफसीएल ने खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित कर दिया है। • लागू आर.बी.आई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, आईआईएफसीएल ने 07.04.2026 को एफएमआर-1 के माध्यम से खाते को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किया है। इसके अलावा, आईआईएफसीएल आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के पास शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					• मामले की सूचना एचसीएमडी को दी गई है और कर्मचारी जवाबदेही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। **कानूनी स्थिति/आगे की कार्यवाही** • मूल आवेदन (ओए) 30 मई 2019 को ऋण वसूली अधिकरण-II, अहमदाबाद में ओए संख्या 898/19 के माध्यम से दायर किया गया था। मामला अंतिम सुनवाई के चरण में है, जो नवंबर 2026 में निर्धारित है।
13.	युवराज पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	08.10.2009	30.06.2016	**परियोजना की पृष्ठभूमि** • पीएमडीओ सुविधा ने ₹95.21 करोड़ का ऋण (आईआईएफसीएल की हिस्सेदारी लगभग ₹5.19 करोड़) एकीकृत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्रबंधन सुविधा स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया था, जिसमें कडियम, वेमोगिरी ग्राम मंडल में 13 मेगावाट का एमएसडब्ल्यू आधारित विद्युत संयंत्र तथा राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश के निडाडावोलु और समालकोटा में तीन-तीन एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण और कम्पोस्टिंग संयंत्र शामिल थे। **एनपीए का कारण** • परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के कारण ऋण खाते का फरवरी 2013 से पुनर्गठन किया गया। प्रवर्तक श्री एम.वी.एस. रामू पुनर्गठन की शर्तों के अनुसार इक्विटी का अंशदान नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप पुनर्गठन योजना का कार्यान्वयन विफल हो गया।	**धोखाधड़ी का कारण और जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति** • चेन्नई के सनदी लेखाकार सुरि एंड कंपनी ने आईएल एंड एफएस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत/उपलब्ध कराए गए अभिलेखों और जानकारी के आधार पर परियोजना की फॉरेंसिक लेखापरीक्षा की। • एम/एस युवराज पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, उसके निदेशकों और गारंटरों तथा अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई धोखाधड़ी, संपत्ति के बेईमानी से दुरुपयोग, आपराधिक न्यासभंग और अन्य अपराधों के संबंध में 29.03.2022 को यूबीआई द्वारा सीबीआई के पास संयुक्त शिकायत दर्ज की गई थी, जो 25.08.2015 की फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताए गए संबंधित निष्कर्षों पर आधारित थी। • <u>29.03.2022 की शिकायत पर सीबीआई ने निम्नलिखित टिप्पणी की:</u> 1) बैंक ने शिकायत में यह घोषणा नहीं की थी कि प्रस्तावित आरोपियों को उचित अवसर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के 27.03.2023 के निर्णय के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि बैंकों द्वारा उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया था। 2) शिकायतकर्ता बैंक ने शिकायत दर्ज करने के लिए सभी सदस्य बैंकों से अधिदेश प्राप्त नहीं किया था। 3) सीबीआई टीम द्वारा संबंधित शाखा के दौरे के दौरान यह पाया गया कि बैंक और उधारकर्ता के बीच निष्पादित कुछ प्रासंगिक दस्तावेज और करार शिकायतकर्ता बैंक के पास उपलब्ध नहीं थे।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
				परिणामस्वरूप, 30.06.2016 को खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया।	• इसके बाद, यूबीआई ने उधारकर्ता के विरुद्ध सीबीआई के पास व्यक्तिगत रूप से शिकायत शुरू की और बाद में पीएमडीओ के अंतर्गत कुछ ऋणदाताओं ने इस मामले में यूबीआई के पक्ष में अपना अधिदेश दिया। पीएमडीओ सुविधा के अंतर्गत सभी ऋणदाताओं से अधिदेश न होने के कारण सीबीआई ने यूबीआई द्वारा की गई शिकायत पर विचार नहीं किया और इसलिए आगे कार्यवाही नहीं हो सकी। • यूबीआई ने मई 2025 में पीएमडीओ की पूरी सुविधा के बजाय अपने ऋण हिस्से के लिए उधारकर्ता के विरुद्ध सीबीआई के पास नई शिकायत दर्ज की, जिसे सीबीआई ने यह कहते हुए लेने से मना कर दिया कि खाते में लेखांकन मानकों का अनुपालन न करना या कंपनी अधिनियम, 2013 का उल्लंघन था, जो दीवानी प्रकृति के मामले थे और खाते में कोई आपराधिक अपराध नहीं पाया गया। यूबीआई ने संकेत दिया कि फॉरेंसिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की टिप्पणियां और रिपोर्ट सीबीआई के साथ साझा की गई थीं, लेकिन उसने मामले को लेने से मना कर दिया। • इसके बाद, कुछ ऋणदाताओं ने केनरा बैंक से पीएमडीओ के ऋणदाताओं की ओर से सीबीआई शिकायत संभालने का अनुरोध किया। केनरा बैंक ने सूचित किया कि वह उधारकर्ता के विरुद्ध सीबीआई में मामला दर्ज नहीं करेगा क्योंकि (क) इस मामले में उसके प्राधिकरण से कोई अनुमोदन उपलब्ध नहीं था और (ख) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) ने पिछली बैठक में सूचित किया था कि उधारकर्ता के विरुद्ध उसकी शिकायत को सीबीआई ने लेने से मना कर दिया था। • आईआईएफसीएल ने 30 जनवरी 2026 को उधारकर्ता, प्रवर्तकों/निदेशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए, हालांकि कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। • तदनुसार, मार्च 2025 में हुई एससीबीएमएफ की बैठक की सिफारिश के आधार पर आईआईएफसीएल ने खाते को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया है।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति की तारीख	एनपीए की तारीख	संक्षिप्त पृष्ठभूमि	कानूनी स्थिति / आगे की कार्यवाही / जांच प्राधिकारी को रिपोर्ट करने की स्थिति / वसूली की स्थिति आदि।
					• लागू आर.बी.आई दिशानिर्देशों के अनुसार, आईआईएफसीएल ने 07.04.2026 को एफएमआर-1 के माध्यम से खाते को धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किया है। • इसके अलावा, आईआईएफसीएल आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के पास शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में है। • मामले की सूचना एचसीएमडी को दी गई है और कर्मचारी जवाबदेही की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। **कानूनी स्थिति** • शेष ऋण राशि की वसूली के लिए मूल आवेदन (ओए) 10 अप्रैल 2015 को ऋण वसूली अधिकरण, विशाखापत्तनम में संख्या 760/16 के माध्यम से दायर किया गया था। माननीय पीओ के आदेश के आधार पर, वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) संख्या 110/2024 जारी किया गया और उधारकर्ता तथा अन्य प्रतिवादियों को मांग नोटिस जारी किए।

49. आईआईएफसीएल को मानव संसाधन संबंधी मामलों में दायर 2 मामलों को छोड़कर ऋण मामलों में वसूली वादों से संबंधित लंबित मुकदमों के मामलों से कोई वित्तीय प्रभाव होने की अपेक्षा नहीं है।

50. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक समझा गया, वहां पुनर्गठित किया गया है।

हमारी इसी दिनांक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह./–
कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 315104E

ह./–
कृते एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 005593C

ह./–
सीए कमल कुमार चंडूका
भागीदार
सदस्यता संख्या: 058790

ह./–
सीए अमित तिवारी
भागीदार
डीआईएन: 408603

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर स

ह./–
रोहित ऋषि
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 11524681

ह./–
पलाश श्रीवास्तव
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 2007911

ह./–
रुचि सिंघल
(महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: 17837

ह./–
राजीव मुखिजा
(मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा 23 जुलाई 2026 दिनांकित संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है, जो उनकी पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 29 मई 2026 का स्थान लेती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा वैधानिक लेखापरीक्षक के कार्यपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षक तथा कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जांच तक सीमित रही है। पूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा उठाई गई कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए वैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहता हूं, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरी राय में वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं:

क वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

क.1 आस्तियां: ₹98,48,076.75 लाख

गैर-वित्तीय आस्तियां: ₹58,175.11 लाख

पूंजीगत कार्य प्रगति पर: ₹2,217.96 लाख (टिप्पणी 9क)

कंपनी ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित अपने कार्यालय परिसर में आंतरिक सज्जा और फिट-आउट कार्यों के निष्पादन के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत ₹2,149.72 लाख थी और 20 मार्च 2026 तक एनबीसीसी को कुल ₹1,666.19 लाख का भुगतान किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, एनबीसीसी ने 20 मार्च 2026 को परियोजना की आगामी उपलब्धि के लिए ₹311.55 लाख का अतिरिक्त मांग पत्र/आरए बिल प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच कंपनी द्वारा की गई थी और एमओयू के प्रावधानों के अनुसार उसे जारी करने के लिए पात्र माना गया था। उक्त राशि का भुगतान बाद में 2 अप्रैल 2026 को किया गया।

हालांकि, वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी ने ₹311.55 लाख की मांग को मान्यता नहीं दी और पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत केवल ₹1,666.19 लाख दर्ज किए, जिसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी और संबंधित देयता में ₹311.55 लाख की कमी दर्शाई गई।

इसके अतिरिक्त, परियोजना 'सुपर' (एसएपी उन्नयन, संवर्धन और पुनर्सज्जा) के संबंध में, 31 मार्च 2026 तक हासिल की गई तीन उपलब्धियों के विरुद्ध मैसर्स एक्सेंचर द्वारा ₹746.65 लाख के बिल जारी किए गए थे। पहली उपलब्धि हासिल होने पर ₹149.33 लाख की राशि, जिसका बिल वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किया गया था, सीडब्ल्यूआईपी में दर्ज करने के बजाय आय में प्रभारित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में केवल ₹551.76 लाख (₹45.56 लाख के जीएसटी

इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाने के बाद) दर्ज किए गए हैं। तदनुसार, पहली उपलब्धि से संबंधित ₹149.33 लाख की राशि को लेखांकन नीति 4.7 के अनुसार चालू वर्ष के दौरान ठीक किया जाना आवश्यक था।

अतः, उपर्युक्त के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी में ₹460.88 लाख की कमी, देयताओं में ₹311.55 लाख की कमी और वर्ष के लाभ में ₹149.33 लाख की कमी दर्शाई गई है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता./-
(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कॉरपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जुलाई 2026

1. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के एकल वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

आस्तियां: ₹98,48,076.75 लाख

गैर-वित्तीय आस्तियां: ₹58,175.11 लाख

पूंजीगत कार्य प्रगति पर: ₹2,217.96 लाख (टिप्पणी 9क)

कंपनी ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित अपने कार्यालय परिसर में आंतरिक सज्जा और फिट-आउट कार्यों के निष्पादन के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत ₹2,149.72 लाख थी और 20 मार्च 2026 तक एनबीसीसी को कुल ₹1,666.19 लाख का भुगतान किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, एनबीसीसी ने 20 मार्च 2026 को परियोजना की आगामी उपलब्धि के लिए ₹311.55 लाख का अतिरिक्त मांग पत्र/आरए बिल प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच कंपनी द्वारा की गई थी और एमओयू के प्रावधानों के अनुसार उसे जारी करने के लिए पात्र माना गया था। उक्त राशि का भुगतान बाद में 2 अप्रैल 2026 को किया गया।

हालांकि, वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी ने ₹311.55 लाख की मांग को मान्यता नहीं दी और पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत केवल ₹1,666.19 लाख दर्ज किए, जिसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी और संबंधित देयता में ₹311.55 लाख की कमी दर्शाई गई।

इसके अतिरिक्त, परियोजना 'सुपर' (एसएपी उन्नयन, संवर्धन और पुनर्सज्जा) के संबंध में, 31 मार्च 2026 तक हासिल की गई तीन उपलब्धियों के विरुद्ध मैसर्स एक्सेंचर द्वारा ₹746.65 लाख के बिल जारी किए गए थे। पहली उपलब्धि हासिल होने पर ₹149.33 लाख की राशि, जिसका बिल वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किया गया था, सीडब्ल्यूआईपी में दर्ज करने के बजाय आय में प्रभारित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में केवल ₹551.76 लाख (₹45.56 लाख के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाने के बाद) दर्ज किए गए हैं। तदनुसार, पहली उपलब्धि से संबंधित ₹149.33 लाख की राशि को लेखांकन नीति 4.7 के अनुसार चालू वर्ष के दौरान ठीक किया जाना आवश्यक था।

अतः, उपर्युक्त के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी में ₹460.88 लाख की कमी, देयताओं में ₹311.55 लाख की कमी और वर्ष के लाभ में ₹149.33 लाख की कमी दर्शाई गई है।

आईआईएफसीएल की कार्ययोजना:

यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की टिप्पणी के अनुसरण में, लेखा बहियों में आवश्यक सुधारात्मक लेखांकन समायोजन किए गए हैं।

आईआईएफसीएल के नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कार्यालय परिसर में आंतरिक सज्जा और फिट-आउट कार्यों के संबंध में, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को देय ₹311.55 लाख की राशि को 07.08.2026 दिनांकित जर्नल वाउचर के माध्यम से एसएपी में पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) में अंतरित किया गया है। संबंधित वाउचर संदर्भ के लिए संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, परियोजना सुपर (एसएपी उन्नयन, संवर्धन और पुनर्सज्जा) के संबंध में ₹126.55 लाख (जीएसटी को छोड़कर) की राशि को 13.08.2026 दिनांकित जर्नल वाउचर के माध्यम से एसएपी में पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) में अंतरित किया गया है। जीएसटी घटक को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पहले ही व्यय के रूप में दर्ज किया जा चुका था और तदनुसार, उपर्युक्त ₹126.55 लाख की राशि, जीएसटी को छोड़कर, सीडब्ल्यूआईपी में अंतरित की गई है। संबंधित वाउचर संदर्भ के लिए संलग्न है।

अतः, उपर्युक्त परियोजनाओं से संबंधित व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत उचित रूप से दर्शाने के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन किए गए हैं।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित वित्तीय विवरणों पर संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

(भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर संशोधित)

प्रति,
सदस्यगण
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
नई दिल्ली

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर संशोधित रिपोर्ट (संशोधन को * द्वारा चिह्नित किया गया है)

राय

1. हमने **इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** ("इसके बाद "धारक कंपनी" के रूप में संदर्भित") और उसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" के रूप में संदर्भित) के साथ संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि का विवरण (जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल है), समेकित इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (इसके बाद "समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित है)। हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए धारक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर 29.05.2026 दिनांकित अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी की थी, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की अनंतिम टिप्पणियों के अनुसरण में, हम "अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" अनुभाग में संशोधन करते हुए यह संशोधित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, जिसमें घटक इकाइयों की सीएआरओ रिपोर्टों में की गई क्वालिफिकेशन/प्रतिकूल टिप्पणियों के संबंध में कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3(गगप) के तहत रिपोर्टिंग, शाखा कार्यालयों से संबंधित अधिनियम की धारा 143(3)(ग) के तहत रिपोर्टिंग और पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (यथासंशोधित) के नियम 11 का संदर्भ शामिल है। यह रिपोर्ट 29.05.2026 दिनांकित पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेती है।

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा नीचे दिए गए अन्य मामलों के अनुभाग में संदर्भित तीन सहायक कंपनियों के पृथक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के तहत अपेक्षित जानकारी निर्धारित तरीके से प्रदान करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों ("भा.रि.बैंक दिशानिर्देश") तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समूह की वित्तीय स्थिति, उसके समेकित निवल लाभ और अन्य वित्तीय जानकारी तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसके समेकित निवल लाभ (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), समेकित नकदी प्रवाह और समेकित इक्विटी में परिवर्तनों का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

2. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का आगे वर्णन हमारी रिपोर्ट के "समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी" अनुभाग में किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

संहिता के अनुसार कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों से स्वतंत्र हैं तथा कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन करते हैं, और हमने इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य तथा नीचे दिए गए "अन्य मामले" अनुभाग में संदर्भित उनकी रिपोर्ट के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के आधार के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

3. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय के अनुसार, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था और इन पर अपनी राय व्यक्त करते समय हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
ऋणों और अग्रिमों का मूल्यह्रास (अपेक्षित ऋण हानि) 31 मार्च, 2026 तक कुल ऋणः रु. 86,688.76 करोड़ 31 मार्च, 2026 तक ईसीएल प्रावधानः रु. 2,447.13 करोड़ (समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 5 का संदर्भ लें)	
अवसंरचना ऋणों के मूल्यह्रास का आकलन भारतीय इंड एएस 109 वित्तीय लिखतों द्वारा निर्धारित अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल का उपयोग करके किया जाता है। चूंकि अवसंरचना परियोजनाओं में लंबी परिपक्वता अवधि होती है और वे नियामकीय देरी तथा लागत में बढ़ोतरी के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसलिए मूल्यह्रास का अनुमान लगाने में प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। जटिलता ऋण के चरण निर्धारण मानदंड (ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की पहचान), चूक की संभावना (पीडी), चूक की स्थिति में हानि (एलजीडी), चूक की स्थिति में जोखिम (ईएडी) की गणना करने तथा भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखने वाले व्यापक आर्थिक चरों को शामिल करने में निहित है।	इस क्षेत्र के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं थीं: क. कंपनी की ईसीएल संबंधी अनुमोदित नीतियों को प्राप्त कर उनका अध्ययन किया और वित्तीय लिखतों के मूल्यह्रास के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया तथा यह सुनिश्चित किया कि वे भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) के दिशानिर्देशों और इंड एएस 109 – वित्तीय लिखतों ("इंड एएस 109") के अनुरूप हैं; ख. मूल्यह्रास प्रावधान प्रक्रिया का चरण–दर–चरण निरीक्षण किया तथा प्रमुख इनपुट (जिसमें 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार ऋण बही भी शामिल है) की पूर्णता और सटीकता तथा मूल्यह्रास प्रावधान की गणना, लेखांकन और निगरानी के लिए विचार किए गए अनुमानों पर प्रमुख नियंत्रणों की रूपरेखा का आकलन और उनकी परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। इन नियंत्रणों में, अन्य बातों के साथ, ऋण पोर्टफोलियो के चरण निर्धारण, साथ ही जर्नल प्रविष्टियां करने और प्रकटीकरण तैयार करने संबंधी नियंत्रण शामिल थे; ग. कंपनी द्वारा अपनाई गई मॉडलिंग तकनीकों, जिनमें प्रमुख इनपुट और अनुमान शामिल हैं, की समझ प्राप्त की। चूंकि मॉडलिंग संबंधी अनुमान और मानदंड ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित थे, इसलिए हमने आकलन किया कि क्या ऐतिहासिक अनुभव वर्तमान परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है और पोर्टफोलियो में हाल ही में हुए मूल्यह्रास के मद्देनजर प्रासंगिक था;

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
	घ. ऋण पोर्टफोलियो का विभिन्न श्रेणियों और चूक के विभिन्न स्तरों में अनुमान, वर्गीकरण और चरण निर्धारण करने के लिए कंपनी द्वारा उपयोग किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों और इनपुट आंकड़ों का आकलन किया तथा चूक की संभावना (पीडी) और चूक की स्थिति में हानि (एलजीडी) दरों के निर्धारण के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया; ङ. पीडी (चूक की संभावना) और एलजीडी (चूक की स्थिति में हानि) दरों के निर्धारण के लिए उपयोग किए गए इनपुट आंकड़ों का नमूना परीक्षण किया और आंकड़ों का मूल लेखा–बही तथा अभिलेखों से मिलान किया; च. कंपनी द्वारा किए गए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) प्रावधान की गणना की अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया; छ. 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार ईसीएल गणना में शामिल ऋणों की पूर्णता का परीक्षण किया, जिसके लिए ऐसे आंकड़ों का ऋण बही रजिस्टर के अनुसार शेष राशियों से मिलान किया गया; ज. समेकित वित्तीय विवरणों में इंड एएस 109 – 'वित्तीय लिखत' की आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधन द्वारा किए गए प्रकटीकरणों की उपयुक्तता का आकलन किया; और झ. प्रबंधन एवं अभिशासर हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों से इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किए कि क्या उनका मानना है कि अपेक्षित ऋण हानि की गणना में उपयोग किए गए महत्वपूर्ण अनुमान उचित हैं।
व्युत्पन्न लिखतों का मूल्यांकन एवं हेज लेखांकन – 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार कुल व्युत्पन्न परिसंपत्तियाँ: ₹ 1,746.64 करोड़ – 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार कुल व्युत्पन्न देयताएँ: शून्य – 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि: ₹ (79.15) करोड़ (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या ..... का संदर्भ लें।)	

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक की प्रतिक्रिया
कंपनी विदेशी मुद्रा में उधारी और ब्याज दर संबंधी जोखिमों से उत्पन्न जोखिमों से बचाव के लिए क्रॉस–करेंसी स्वैप, ब्याज दर स्वैप और वायदा विनिमय करार सहित व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों में प्रवेश करती है। व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों का मूल्यांकन और इंड एएस 109 – वित्तीय लिखतों के अंतर्गत हेज लेखांकन का अनुप्रयोग प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णय, अनुमान संबंधी अनिश्चितता और विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों के उपयोग से जुड़ा होता है। उचित मूल्य का निर्धारण विभिन्न बाजार में देखे जा सकने वाले इनपुट, जैसे विदेशी मुद्रा दरें, ब्याज दर प्रतिफल वक्र, छूट कारक और प्रतिपक्षी कोटेशनों पर निर्भर करता है तथा कुछ मामलों में भविष्य की बाजार और आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित अनुमानों पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा, हेज लेखांकन के लिए हेज संबंधों का औपचारिक दस्तावेजीकरण, हेज की प्रभावशीलता का निरंतर आकलन तथा नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि और लाभ एवं हानि के विवरण में लाभ और हानि की पहचान से संबंधित जटिल लेखांकन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए: व्युत्पन्नी जोखिमों की महत्वपूर्णता, मूल्यांकन पद्धतियों में शामिल जटिलता, प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय और उपयोग किए गए अनुमान, बाहरी प्रतिपक्षों द्वारा किए गए मूल्यांकनों की भागीदारी, और समेकित वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव	व्युत्पन्नी लिखतों के मूल्यांकन और हेज लेखांकन के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं थे: क. कंपनी की व्युत्पन्नी लेनदेन, मूल्यांकन पद्धतियों और हेज लेखांकन से संबंधित नीतियों, प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रणों की समझप्राप्त की तथा यह आकलन किया कि ये लागू इंड एएस 109, इंड एएस 21 और संबंधित नियामकीय दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप थे या नहीं; ख. व्युत्पन्नी संविदाओं और हेज संबंधों के प्राधिकरण, अभिलेखन, मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग से संबंधित प्रमुख आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा का आकलन किया और उनकी परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया; ग. नमूना आधार पर व्युत्पन्नी करारों और अंतर्निहित उधारी संबंधी दस्तावेजों को प्राप्त कर उनका निरीक्षण किया, ताकि यह आकलन किया जा सके कि व्युत्पन्नी लेनदेन का उचित रूप से अभिलेखन किया गया था और वे संविदात्मक दस्तावेजों द्वारा समर्थित थे; घ. प्रबंधन की मूल्यांकन पद्धति की उपयुक्तता का आकलन किया और उचित मूल्यों के निर्धारण में उपयोग किए गए प्रमुख इनपुट तथा अनुमानों, जिनमें विदेशी मुद्रा दरें, प्रतिफल वक्र, छूट दरें और प्रतिपक्षी कोटेशन शामिल हैं, की तर्कसंगतता का मूल्यांकन किया; ङ. प्रबंधन द्वारा नामित हेज संबंधों का आकलन किया कि क्या वे इंड एएस 109 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसमें औपचारिक हेज दस्तावेजीकरण और हेज की प्रभावशीलता का आकलन शामिल है। संगठन द्वारा नियुक्त प्रेशेवर से प्रमाणपत्र प्राप्त किया। च. नमूना आधार पर व्युत्पन्नी के मूल्यांकन समायोजनों, हेज आरक्षित निधि के लेखांकन तथा लाभ एवं हानि के विवरण में संबंधित लाभ/हानि की पहचान से संबंधित जर्नल प्रविष्टियों और लेखांकन प्रक्रियाओं का परीक्षण किया; छ. व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतों, मूल्यांकन तकनीकों, उचित मूल्य श्रेणीक्रम, हेज लेखांकन और संबंधित जोखिमों के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों का आकलन किया कि क्या वे इंड एएस 107 और इंड एएस 109 की लागू प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप थे; ज. समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त व्युत्पन्नी जोखिमों और हेज संबंधों की पूर्णता तथा अनुमानों और मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता के संबंध में प्रबंधन और अभिशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से लिखित अभ्यावेदन प्राप्त किए;

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

4. अन्य जानकारी हेतु मूल कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण, निदेशक मंडल की रिपोर्ट जिसमें निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, व्यावसायिक उत्तरदायित्व और सततता रिपोर्ट, कॉरपोरेट अभिशासन और शेयरधारक संबंधी जानकारी में शामिल जानकारी सम्मिलित है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इन रिपोर्टोंके इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना और ऐसा करते समय यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी से महत्वपूर्ण रूप से असंगत है अथवा अन्यथा उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण प्रतीत होता है।

जब ऐसी अन्य जानकारी हमें उपलब्ध कराई जाएगी और हम उसे पढ़ेंगे तथा यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले की सूचना अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को देना आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की जिम्मेदारी

5. मूल कंपनी का निदेशक मंडल ऐसे समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जो समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय कार्यनिष्पादन, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों, भा.रि.बैंक दिशानिर्देशों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं। समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव, समूह की आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग, युक्तिसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान करने और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, उनके कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं, जो लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे और समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं, ताकि वे सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करें और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हों तथा जिनका उपयोग मूल कंपनी के निदेशकों द्वारा उपर्युक्त अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय, समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह के निरंतर व्यवसाय संचालन की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, निरंतर व्यवसाय संचालन से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करने और निरंतर व्यवसाय संचालन के आधार पर लेखांकन करने के लिए उत्तरदायी हैं, जब तक कि संबंधित निदेशक मंडल समूह को परिसमाप्त करने या उसका परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

समूह में शामिल संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय परिणाम, समग्र रूप से, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलतबयानी से मुक्त हैं और ऐसी लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखापरीक्षा में महत्वपूर्ण गलत विवरण होने पर उसका हमेशा पता चल जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा में व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते है:

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

- समेकित वित्तीय परिणामों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना और उन्हें निष्पादित करना, तथा ऐसा पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के आधार के लिए पर्याप्त हो। धोखाधड़ी के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चलने का जोखिम, त्रुटि के कारण होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण को दरकिनार करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करते हैं।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की युक्तिसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- निदेशक मंडल द्वारा कार्यशील संस्था के आधार पर लेखांकन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निर्धारित करना कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, जो समूह की कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय में संशोधन करना आवश्यक है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह एककार्यशील संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर सकता है।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- समूह के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त और उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, ताकि समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त की जा सके। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के संबंध में, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक अपने द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी हैं। इस संबंध में हमारे उत्तरदायित्वों का आगे विवरण इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य मामले" शीर्षक वाले अनुभाग में दिया गया है।

महत्वपूर्णता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि समेकितवित्तीय विवरणों के उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (प) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों; और (पप) समेकितवित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों जिनमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान अभिज्ञात करते हैं, को भी अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को संप्रेषित करते है।

हम अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों को एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और हम उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के संबंध में उनसे संवाद करते हैं जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित रक्षोपायों के बारे में भी संसूचित करते हैं।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ संप्रेषित किए गए मामलों में से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं, जो चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं, जब तक कि कानून या विनियमन के तहत उस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रतिबंधित न हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित न करें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से सार्वजनिक हित में होने वाले लाभों की तुलना में अधिक होने की युक्तिसंगत अपेक्षा होगी।

अन्य मामले

7. आईआईएफसीएल तीन सहायक कंपनियों वाली धारक कंपनी है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश
1.	**आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड**	भारत
2.	**आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड**	भारत
3.	**आईआईएफसीएल यूके लिमिटेड**	यूनाइटेड किंगडम

हमने दो भारतीय सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 को कुल आस्तियां ₹6,263.83 लाख, कुल राजस्व ₹1,956.45 लाख और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹85.11 लाख की निवल नकदी प्रवाह राशि दर्शाई गई है, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में ध्यान में रखा गया है। इन पृथक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इन सहायक कंपनियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के तहत हमारी रिपोर्ट, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

हमने एक सहायक कंपनी, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड, के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2026 को कुल आस्तियां ₹8,26,104.56 लाख, कुल राजस्व ₹52,219.86 लाख, कुल निवल लाभ/(हानि) ₹9,050.61 लाख और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹8,314.77 लाख का निवल नकदी अंतर्वाह/(बहिर्वाह) दर्शाया गया है, जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों में ध्यान में रखा गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा संबंधित देश में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है और उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है। धारक कंपनी के प्रबंधन ने एक संकलन लेखापरीक्षक की सहायता से, ऐसी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को संबंधित देश में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (इंड एएस) में परिवर्तित किया है। हमने प्रबंधन द्वारा किए गए इन रूपांतरण समायोजनों की लेखापरीक्षा की है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक इस सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, तथा अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (11) के तहत हमारी रिपोर्ट, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा प्रबंधन द्वारा तैयार और हमारे द्वारा लेखापरीक्षित रूपांतरण समायोजनों पर आधारित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के कारण समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('सीएआरओ') के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जिन्हें लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, तथा कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों और समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों के संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्टों और अचल आस्तियों के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पर हमारे विचार के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि संबंधित लेखापरीक्षकों ने अपनी सीएआरओ रिपोर्टों में निम्नलिखित क्वालिफिकेशन/प्रतिकूल टिप्पणियां

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

की हैं, साथ ही उन कंपनियों का विवरण और सीएआरओ रिपोर्ट के उन पैराग्राफों की संख्या दी गई है जिनमें ऐसी क्वालिफिकेशनया प्रतिकूल टिप्पणियां शामिल हैं:'(क) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (धारक कंपनी – स्टैंडअलोन) – अनुलग्नक क: पैराग्राफ (i)(क)(i) – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की स्थिति को छोड़कर उचित अभिलेख रखे गए हैं; पैराग्राफ (i)(ग) – अचल संपत्तियों के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं; और पैराग्राफ (अपप)(ख) – विवादों के कारण जमा नहीं की गई सांविधिक देयताओं का विवरण; और (ख) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनी) – अनुलग्नक क: पैराग्राफ (i)(क)(क) – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली आस्तियों के उचित अभिलेख नहीं रखे गए हैं; पैराग्राफ (i)(ख) – वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया; और पैराग्राफ (गपअ)(क) – व्यापार प्राप्य राशियों के असमाधित शेष से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में एक नियंत्रण कमजोरी देखी गई। उपर्युक्त के अलावा, समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों की सीएआरओ रिपोर्टों में कोई अन्य क्वालिफिकेशनया प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

9. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा और "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित एक विदेशी सहायक कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार के आधार पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं;

(ख) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए कानून के अनुसार अपेक्षित उचित लेखा बहियां रखी हैं।

(ग) 'धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों का कोई शाखा कार्यालय नहीं है। अत:, इस संबंध में कि क्या अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (8) के तहत कंपनी के लेखापरीक्षक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेखापरीक्षित कंपनी के किसी शाखा कार्यालय के लेखों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय हमने उससे किस प्रकार निपटा है, रिपोर्टिंग की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है और अधिनियम की धारा 143(3)(ग) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती है;

(घ) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ और हानि का विवरण (जिसमें अन्य व्यापक आय भी शामिल है), समेकित इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन के लिए रखी गई संबंधित लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

(ड) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का, यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पढ़े जाने पर, अनुपालन करते हैं;

(च) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 05–06–2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार, निदेशकों की निरर्हता के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं;

(छ) भारत में निगमित कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी पृथक रिपोर्ट **"अनुलग्नक क"** में देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक राय व्यक्त करती है।

(ज) भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 5 जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463(ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। अत:, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होती है।

(झ) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के 'नियम 11 के अनुसार, जिसे कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2021 द्वारा संशोधित किया गया है, लागू सीमा तक, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर तथा "अन्य मामले" पैराग्राफ में उल्लिखित सहायक संस्थाओं के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों सहित अन्य वित्तीय जानकारी पर विचार करने के आधार पर:

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

i) समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण किया गया है – समेकित वित्तीय विवरणों के नोट्स में **नोट 31 (I)** का संदर्भ लें;

ii) दीर्घकालिक करारों पर लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार, यदि कोई हो, तो महत्वपूर्ण पूर्वानुमेय हानियों के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है – कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों से संबंधित ऐसी मदों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों की **नोट 5 और 18** का संदर्भ लें; और

iii) कंपनी द्वारा विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा निधि में अंतरित की जाने वाली कोई राशि नहीं थी।

iv) क) कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, ने हमें अभ्यावेदन दिया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं, ("मध्यस्थ") को या उसमें, चाहे उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या निधियों के किसी अन्य स्रोत या प्रकार से, कोई निधि अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी गई है या निवेश नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रदान करेगा।

ख) कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरण अलेखापरीक्षित हैं, ने हमें अभ्यावेदन दिया है कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं, ("निधि प्रदान करने वाले पक्ष") से ऐसी कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी या उसकी कोई सहायक कंपनी निधि प्रदान करने वाले पक्ष द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थियों") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की कोई व्यवस्था प्रदान करेगी।

ग) परिस्थितियों में हमारे द्वारा उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपर्युक्त (क) और (ख) में दिए गए नियम 11(ङ) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदनों में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v) समूह ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है; अतः समूह पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

vi) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) के तहत लेखापरीक्षा ऑडिट ट्रेलपर रिपोर्टिंग संबंधी कार्यान्वयन मार्गदर्शन (संशोधित 2024 संस्करण) के अनुसार की गई हमारी जांच के आधार पर, जिसमें नमूना जांच भी शामिल थी, तथा अधिनियम के तहत जिन सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की गई है, उनके संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा की गई जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी और ऊपर संदर्भित उसकी सहायक कंपनियों ने अपनी लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें लेखापरीक्षा ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) दर्ज करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेन–देन के लिए यह सुविधा पूरे वर्ष संचालित रही है।

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

इसके अलावा, अपनी लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखापरीक्षा ऑडिट ट्रेल की सुविधा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला और कंपनी ने रिकॉर्डों को बनाए रखने संबंधी सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा ऑडिट ट्रेल को सुरक्षित रखा है।

कृते **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 315104E

हस्ता/–
सीए कमल कु. चंदुका
साझेदार
सदस्यता सं.: 058790
यूडीआईएनः 26058790XJTNDB4589

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 005593ब

हस्ता/–
सीए अमित तिवारी
साझेदार
सदस्यता सं.: 408603
यूडीआईएनः 26408603QFVWUH2163

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.07.2026

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को सम तिथि के स्वतंत्र लेखापरीक्षककी रिपोर्ट के अनुच्छेद 9 में संदर्भित जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित है।

हमने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ("धारक कंपनी") और उसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से "समूह" के रूप में संदर्भित) की 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ की गई है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियाँ

धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन अपने–अपने संस्थानों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखा गया है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्प, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, जो इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्यरत थे, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित है।

लेखापरीक्ष की ज़िम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी ("मार्गदर्शन टिप्पणी") और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है, जहां तक ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं। ये मानक और मार्गदर्शन नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और उसे इस प्रकार निष्पादित करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए हो और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हो।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण खामी की संभावना का आकलन करना और आकलन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण समेकित वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी के जोखिमों का आकलन भी शामिल है।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

1. कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन–देन और निपटान का उचित विवरण , सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करने वाले अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं;

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

2. यह उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेन–देन को सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और
3. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों में मिलीभगत या प्रबंधन द्वारा अनुचित रूप से नियंत्रणों को दरकिनार करने की संभावना भी शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण उत्पन्न हो सकते हैं और उनका पता नहीं चल सकता है।

इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन को भविष्य की अवधियों तक लागू करने पर यह जोखिम बना रहता है कि परिस्थितियों में बदलाव के कारण ऐसे नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, मुख्य लेखापरीक्षा रिपोर्ट के "राय के आधार" पैराग्राफ में की गई टिप्पणियों के अधीन, धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2026 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्यरत थे, जो संबंधित संस्थाओं द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंडों पर आधारित हैं तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शिका में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हैं।

कृते **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 315104E

हस्ता/–
सीए कमल कु. चंदुका
साझेदार
सदस्यता सं.: 058790
यूडीआईएनः 26058790XJTNDB4589

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 005593ɛ

हस्ता/–
सीए अमित तिवारी
साझेदार
सदस्यता सं.: 408603
यूडीआईएनः 26408603QFVWUH2163

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.07.2026

एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आर–13, तीसरी मंजिल,
राजौरी गार्डन,
नई दिल्ली– 110027

एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
पहली मंजिल, महावीर गौशाला परिसर,
के.के. रोड, मौदहापारा,
रायपुर 492–001 (छ.ग.)

अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,
निदेशक मंडल
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
5वीं मंजिल, भाग ए एवं बी, ब्लॉक बी
ईस्ट किदवई नगर,
नई दिल्ली–110023

हम, एबीपी एंड एसोसिएट्स तथा एडीबी एंड कंपनी (संयुक्त लेखापरीक्षक), ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा जारी निर्देशों/उप–निर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित करते हैं कि हमने जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का अनुपालन किया है।

हमने उक्त विवरण की जाँच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी विशेष प्रयोजनों के लिए रिपोर्टों या प्रमाणपत्रों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार की है। इस मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार, हमारे लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना आवश्यक है।

हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा एवं समीक्षा तथा अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा कार्य करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण–की लागू प्रासंगिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कृते **एबीपी एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 315104E

हस्ता/–
सीए कमल कु. चंदुका
साझेदार
सदस्यता सं.: 058790
यूडीआईएनः 26058790HQVMST7229

कृते **एडीबी एंड कंपनी**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएनः 005593ब

हस्ता/–
सीए अमित तिवारी
साझेदार
सदस्यता सं.: 408603
यूडीआईएनः 26408603JLAWMG8917

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 मई 2026

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

31 मार्च 2026 वर्ष के लिए समेकित तुलन पत्र का विवरण

सीआईएन सं. **U67190DL2006GOI144520**

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2026 तक (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 तक (लेखापरीक्षित)
I	**आस्तियां**			
1	**वित्तीय आस्तियां**			
(क)	नकद और नकद समकक्ष	2क	96,193.17	58,524.43
(ख)	उपरोक्त (क) के अलावा बैंक बैलेंस	2ख	9,15,918.74	5,27,356.36
(ग)	व्युत्पन्न वित्तीय साधन	3	1,74,673.79	1,35,382.74
(घ)	प्राप्त	4	784.95	699.48
(ङ)	ऋण	5	84,18,795.95	71,48,623.92
(च)	निवेश	6	8,18,475.18	7,36,986.94
(छ)	अन्य वित्तीय आस्ति	7	90,067.07	76,657.46
	कुल वित्तीय आस्तियां (1)		**1,05,14,908.85**	**86,84,231.33**
2	**गैर–वित्तीय आस्ति**			
(क)	चालू कर आस्तियां (निवल)	8	3,197.45	4,042.09
(ख)	आस्थगित कर आस्ति (निवल)	9	15,568.78	17,315.21
(ग)	आस्ति, संयंत्र और उपकरण	10	36,682.64	22,111.68
(घ)	पूंजी कार्य प्रगति पर है	10क	2,217.96	15,333.67
(ङ)	संपत्ति के उपयोग के अधिकार	10ख	25.16	-
(च)	अन्य अमूर्त आस्तियां	11	785.26	977.16
(छ)	अन्य गैर–वित्तीय आस्तियां	12	2,227.86	10,487.41
	कुल गैर वित्तीय आस्तियां (2)		**60,705.11**	**70,267.23**
	कुल आस्तियां (1+2)		**1,05,75,613.96**	**87,54,498.56**
II	**देयताएं और इक्विटी**			
क	**देयताएं**			
1	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	देय	13	164.65	225.84
(ख)	ऋण प्रतिभूतियां	14	37,39,162.60	33,47,662.10
(ग)	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	15	48,27,299.09	35,68,701.67
(घ)	अन्य वित्तीय देयताएं	16	1,39,854.48	1,26,156.39
	कुल वित्तीय देयताएं (1)		**87,06,480.82**	**70,42,746.00**
2	**गैर वित्तीय देयताएं**			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	17	18,098.33	29,820.04
(ख)	प्रावधान	18	5,363.23	5,423.78
(ग)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	19	12,878.43	16,087.30
	कुल गैर वित्तीय आस्तियां (2)		**36,339.99**	**51,331.12**
	कुल आस्तियां (1+2)		**87,42,820.81**	**70,94,077.12**
B	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	20	9,99,991.62	9,99,991.62
(ख)	अन्य इक्विटी	21	8,32,801.50	6,60,429.82
	कुल इक्विटी (ख)		**18,32,793.12**	**16,60,421.44**
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख)		**1,05,75,613.96**	**87,54,498.56**

1 से 29 तक के नोट्स के समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी इसी दिनांक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह./–
कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 315104E

ह./–
कृते एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 005593C

ह./–
सीए कमल कुमार चंडूका
भागीदार
सदस्यता संख्या: 058790

ह./–
सीए अमित तिवारी
भागीदार
डीआईएन: 408603

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर स

ह./–
रोहित ऋषि
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 11524681

ह./–
पलाश श्रीवास्तव
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 2007911

ह./–
रुचि सिंघल
(महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: 17837

ह./–
राजीव मुखिजा
(मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

31 मार्च 2026 वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि का विवरण

सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	को समाप्त वर्ष	
			31.03.2026 (लेखापरीक्षित)	31.03.2025 (लेखापरीक्षित)
	संचालन से राजस्व			
(क)	ब्याज आय	**21**	7,44,083.28	6,64,689.33
(ख)	शुल्क और कमीशन आय	**22**	6,886.65	7,667.42
I	**परिचालन से कुल राजस्व (क+ख)**		**7,50,969.93**	**6,72,356.75**
II	**अन्य आय**	**23**	1,22,081.24	55,957.83
III	**कुल आय (I+III)**		**8,73,051.18**	**7,28,314.58**
IV	**व्यय**			
(क)	वित्तीय लागत	**24**	4,88,638.80	4,48,792.09
(ख)	शुल्क और कमीशन व्यय	**25**	9,060.64	11,501.34
(ग)	फेयर वैल्यू में बदलाव से शुद्ध (लाभ)/नुकसान	**26**	1,007.16	(12,254.58)
(घ)	वित्तीय साधनों पर मूल्य–ह्रास	**27**	(9,540.99)	(56,938.34)
(ङ)	कर्मचारी लाभ व्यय	**28**	9,638.30	9,679.52
(च)	मूल्यह्रास, परिशोधन और मूल्य–ह्रास	**9,10**	1,447.78	1,137.70
(छ)	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		4,054.46	2,597.59
(ज)	अन्य व्यय	**29**	1,61,323.88	41,561.31
	कुल व्यय II		**6,65,630.03**	**4,46,076.64**
V	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (I-II)**		**2,07,421.15**	**2,82,237.94**
VI	असाधारण मदे		-	47,343.03
VII	**लाभ/(हानि) कर पूर्व (I–II)**		**2,07,421.15**	**3,29,580.97**
	कर व्यय:			
	(i) चालू कर		(56,592.42)	(59,988.14)
	(ii) पूर्ववर्ती वर्षों के कर समायोजन		(1,889.50)	14.94
	(iii) आस्थगित कर		(1,957.01)	(6,464.25)
VIII	**कुल कर व्यय (i+ii+iii)**		**(60,438.94)**	**(66,437.45)**
IX	**जारी कामकाज से वर्ष का लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**1,46,982.21**	**2,63,143.53**
	बंद किए गए ऑपरेशन्स से मुनाफा/(नुकसान)		-	-
	बंद किए गए ऑपरेशन्स का टैक्स खर्च		-	-
X	**बंद किए गए ऑपरेशन्स से मुनाफा/(नुकसान) (टैक्स के बाद)**		-	-
XI	**बंद किए गए ऑपरेशन्स से मुनाफा/(नुकसान) (टैक्स के बाद) (IX+X)**		**1,46,982.21**	**2,63,143.53**
XII	**बंद किए गए ऑपरेशन्स से मुनाफा/(नुकसान) (टैक्स के बाद) (ओसीआई)**			
	क. (i) मद जिन्हें लाभ और हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	– लाभ/(हानि) परिभाषित लाभ दायित्व का पुनर्मूल्यांकन		69.85	(541.34)
	– परिभाषित लाभ दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित आयकर		(13.56)	134.61
	अन्य व्यापक आय/(व्यय) (क)		**56.28**	**(406.74)**
XIII	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (XI+XII)**		**1,47,038.49**	**2,62,736.79**
XIV	**मूल और तनुकृत प्रति इक्विटी शेयर (₹ 10 प्रति अंकित मूल्य)**			
	1. निरंतर संचालन के लिए (₹ में)	**1(ख)(8)**	1.47	2.63
	2. बंद संचालन के लिए (₹ में)		-	-
	3. निरंतर एवं बंद संचालन के लिए (₹ में)		1.47	2.63

1 से 29 तक के नोट्स के समेकित वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

हमारी इसी दिनांक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह./–
कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 315104E

ह./–
कृते एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 005593C

ह./–
सीए कमल कुमार चंडूका
भागीदार
सदस्यता संख्या: 058790

ह./–
सीए अमित तिवारी
भागीदार
डीआईएन: 408603

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर स

ह./–
रोहित ऋषि
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 11524681

ह./–
पलाश श्रीवास्तव
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 2007911

ह./–
रुचि सिंघल
(महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: 17837

ह./–
राजीव मुखिजा
(मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

31 मार्च 2026 वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण

सीआईएन सं. U67190DL2006GOI144520

(₹ लाख में)

क्रं.सं.	विवरण		31.03.2026 को समाप्त वर्ष	31.03.2025 को समाप्त वर्ष
क	**प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह**			
(i)	कर से पूर्व निवल लाभ समायोजन हेतु		2,07,421.15	3,29,580.97
(ii)	मूल्यह्रास/क्षतिपूर्ति एवं परिशोधन व्यय		1,447.78	1,137.70
(iii)	प्रावधान/राइट–ऑफ		(16,219.39)	(40,464.56)
(iv)	ऋण एवं अग्रिमों पर उपार्जित एवं देय ब्याज		-	1,060.17
(v)	उधार पर उपार्जित किंतु देय नहीं ब्याज		16,427.68	15,441.08
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ		**2,09,077.21**	**3,06,755.36**
(i)	ऋण परिचालन से नकदी प्रवाह		(12,59,598.13)	(16,20,363.80)
(ii)	निवेशों की बिक्री/(निवेश में वृद्धि)		16,923.96	(72,047.42)
(iii)	**व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी**		(85.47)	(190.31)
(iv)	अन्य परिचालन परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी		(32,038.29)	(2,065.66)
(v)	अन्य बैंक शेषराशियों में (वृद्धि)/कमी		(3,87,600.45)	6,19,241.22
(vi)	अन्य परिचालन देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		(14,063.75)	6,101.87
	कर से पहले के कार्यों से नकदी प्रवाह		**(14,67,384.91)**	**(7,62,568.73)**
	भुगतान किया गया कर (निवल)		(58,481.93)	(59,973.20)
	संचालन से निवल नकद	**क**	**(15,25,866.84)**	**(8,22,541.93)**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
(i)	संयंत्र, आस्ति और उपकरण की खरीद		(15,831.46)	(1,292.25)
(ii)	संयंत्र, संपत्ति एवं उपकरण की बिक्री		(0.22)	-
(iii)	निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य में (वृद्धि)/कमी		13,115.71	(6,544.19)
(iv)	निवेशों में (वृद्धि)/कमी		(96,617.61)	(1,02,446.62)
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद	**ख**	**(99,333.58)**	**(1,10,283.06)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
(i)	शेयर पूंजी के निर्गम/आवंटन से प्राप्तियां		-	-
(ii)	ऋणों से शुद्ध प्राप्ति/(भुगतान)		12,58,597.42	7,01,095.41
(iii)	ऋण प्रतिभूतियों से शुद्ध प्राप्ति/(भुगतान)		3,91,500.50	2,81,280.85
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	**ग**	**16,50,097.92**	**9,82,376.26**
घ	**विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर का प्रभाव**	**घ**	**12,771.25**	**2,371.89**
	नकद और नकद समतुल्य में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)		**37,668.75**	**51,923.15**
	जोड़ें: नकद और नकद समतुल्य खोलना		58,524.43	6,601.30
	नकद और नकद समतुल्य समाप्त करना		**96,193.17**	**58,524.43**
	समापन नकद और नकद समतुल्य में शामिल हैं: –			
(i)	नकद		0.18	0.04
(ii)	चालू खाते		74,67 9.64	348.83
(iii)	फ्लेक्सी जमा खाते		21,513.34	58,175.57
	कुल		**96,193.17**	**58,524.43**

उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकदी प्रवाह विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

1) पूर्ववर्ती अवधि के आंकड़ों को, जहाँ आवश्यक हो, रिपोर्टिंग अवधि की प्रस्तुति के अनुरूप बनाने के लिए पुनःसमूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

2) निम्नलिखित बैंक शेषराशियाँ कंपनी द्वारा स्वतंत्र उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं:

वर्ष 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के लिए अन्य बैंक शेषराशियों में ₹(3,87,600.45) लाख की वृद्धि/(कमी) तथा वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए ₹6,19,241.22 लाख की वृद्धि/(कमी) में 31 मार्च 2026 को ₹शून्य लाख (31 मार्च 2025 को ₹शून्य लाख) शामिल हैं, जिन पर बॉण्ड के ब्याज भुगतान के लिए लियन अंकित है तथा 31 मार्च 2026 को ₹5,05,392 लाख (31 मार्च 2025 को ₹2,09,400 लाख) शामिल हैं, जिन पर ओवरड्राफ्ट के लिए लियन अंकित है।

हमारी इसी दिनांक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह./–
कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 315104E

ह./–
कृते एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 005593C

ह./–
सीए कमल कुमार चंडूका
भागीदार
सदस्यता संख्या: 058790

ह./–
सीए अमित तिवारी
भागीदार
डीआईएन: 408603

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर स

ह./–
रोहित ऋषि
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 11524681

ह./–
पलाश श्रीवास्तव
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 2007911

ह./–
रुचि सिंघल
(महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: 17837

ह./–
राजीव मुखिजा
(मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2025 तक का शेष	9,99,991.62
पूर्व अवधि की त्रुटि के सुधार के परिणामस्वरूप इक्विटी शेयर पूंजी में समायोजन	-
1 अप्रैल 2025 तक का पुनः–प्रतिपादित शेष	9,99,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2026 तक का शेष	**9,99,991.62**

ख अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										प्रतिधारित आय	कुल
	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर बांड / रिडेम्पशन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व	स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि	कॉरपोरेट समाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर विदेशी मुद्रा	मूल्यह्रास रॉयल निधि	भारतीय रिजर्व अधिनियम बैंक, 1934 की धारा 45–विज्ञान के अंतर्गत यूक्रेनी निधि		
1 अप्रैल, 2025 को शेष राशि	**585.14**	**235.50**	**54,568.28**	**(20,317.05)**	**2,16,690.69**	**3,394.82**	**122.45**	**18,084.32**	**1,01,230.76**	**1,14,831.82**	**1,71,003.09**	**6,60,429.82**
पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-									-	-
रिपोर्टिंग अवधि वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	**585.14**	**235.50**	**54,568.28**	**(20,317.05)**	**2,16,690.69**	**3,394.82**	**122.45**	**18,084.32**	**1,01,230.76**	**1,14,831.82**	**1,71,003.09**	**6,60,429.82**
वर्ष का मुनाफा	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47,195.53	1,47,195.53
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर घटाकर)	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**1,47,195.53**	**1,47,195.53**
इस अवधि के दौरान इस्तेमाल की गई राशि	-	-	-	-	-	(139.15)	-	-			(71,536.59)	(71,675.73)
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-	-	12,402.83								12,402.83
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि								12,771.25				12,771.25
अवितरित लाभ में अंतरण	-	-	(105.99)	-	-	-	-	-			247.37	141.38
अवितरित लाभ में अंतरण				-	42,410.32	1,537.55	-	-	-	27,588.43	-	71,536.31
31 मार्च 2026 को शेष राशि	**585.14**	**235.50**	**54,462.29**	**(7,914.22)**	**2,59,101.02**	**4,793.21**	**122.45**	**30,855.57**	**1,01,230.76**	**1,42,420.26**	**2,46,909.41**	**8,32,801.50**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2024 तक का शेष	9,99,991.62
पूर्व अवधि की त्रुटि के सुधार के परिणामस्वरूप इक्विटी शेयर पूंजी में समायोजन	-
1 अप्रैल 2024 तक का पुनः–प्रतिपादित शेष	9,99,991.62
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2025 तक का शेष	**9,99,991.62**

ख अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष										प्रतिधारित आय	कुल
	पूंजीगत आरक्षित निधि	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	डिबेंचर बांड/ रिडेम्पशन आरक्षित निधि	नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व	स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि	कॉरपोरेट समाजिक उत्तरदायित्व आरक्षित निधि	विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर विदेशी मुद्रा	मूल्यह्रास रॉयल निधि	भारतीय रिजर्व अधिनियम बैंक, 1934 की धारा 45–विज्ञान के अंतर्गत यूक्रेनी निधि		
1 अप्रैल, 2024 को शेष राशि	**585.14**	**235.50**	**54,568.28**	**(17,025.08)**	**1,77,588.70**	**297.16**	**122.45**	**15,712.43**	**1,01,230.76**	**71,536.34**	**(6,222.12)**	**3,98,629.56**
पूर्व अवधि की त्रुटियां	-	-									-	-
रिपोर्टिंग अवधि वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्निर्धारित शेष राशि	**585.14**	**235.50**	**54,568.28**	**(17,025.08)**	**1,77,588.70**	**297.16**	**122.45**	**15,712.43**	**1,01,230.76**	**71,536.34**	**(6,222.12)**	**3,98,629.56**
वर्ष का मुनाफा	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63,143.54	2,63,143.54
अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (आयकर घटाकर)	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**2,63,143.54**	**2,63,143.54**
इस अवधि के दौरान इस्तेमाल की गई राशि	-	-	-	-	-	(5.29)	-	-			(86,226.19)	(86,231.47)
अवधि के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-	-	(3,291.97)								(3,291.97)
अवधि के दौरान नकदी प्रवाह बचाव व्यवस्था आरक्षित निधि								2,371.89				2,371.89
अवितरित लाभ में अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-			10.80	10.81
अवितरित लाभ में अंतरण				-	39,101.98	3,400.02	-	-	-	43,295.49	-	85,797.49
31 मार्च 2025 को शेष राशि	**585.14**	**235.50**	**54,568.28**	**(20,317.05)**	**2,16,690.69**	**3,691.88**	**122.45**	**18,084.32**	**1,01,230.76**	**1,14,831.82**	**1,70,706.04**	**6,60,429.82**

विवरण के लिए नोट 21 देखें

हमारी इसी दिनांक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह./–
कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 315104E

ह./–
सीए कमल कुमार चंडूका
भागीदार
सदस्यता संख्या: 058790

ह./–
कृते एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 005593C

ह./–
सीए अमित तिवारी
भागीदार
डीआईएन: 408603

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर स

ह./–
रोहित ऋषि
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 11524681

ह./–
पलाश श्रीवास्तव
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 2007911

ह./–
रुचि सिंघल
(महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: 17837

ह./–
राजीव मुखिजा
(मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)

नोट 2: नकद और नकद समकक्ष

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क)	**नकद और नकदी के समतुल्य**		
(i)	नकदी	0.18	0.04
(ii)	बैंकों के पास शेष	74,679.64	348.82
(iii)	बैंकों के साथ सावधि जमा (बिना भार के)	21,513.34	58,175.57
	कुल	**96,193.17**	**58,524.43**

नोट 2ख: 2क के उपर अन्य बैंक बैलेंस के अलावा

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
	अन्य बैंक बैलेंस		
(i)	बैंकों के साथ सावधि जमा (बिना भार के) (मूल परिपक्वता तीन माह से अधिक एवं बारह माह तक)	4,10,522.24	3,17,951.86
(ii)	बॉन्ड पर दावा न की गई ब्याज राशि हेतु बैंकों में आरक्षित शेष	-	-
(iii)	बॉन्ड के ब्याज भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में रखी गई राशि	-	-
(iv)	बैंक गारंटी के विरुद्ध	4.50	4.50
(v)	बैंकों से ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने हेतु गिरवी रखी गई राशि	5,05,392.00	2,09,400.00
	कुल	**9,15,918.74**	**5,27,356.36**

नोट 3: व्युत्पन्न वित्तीय लिखते

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		काल्पनिक राशि	उचित मूल्य	काल्पनिक राशि	उचित मूल्य
	आस्तियां				
	अन्य व्युत्पन्न:				
(क)	क्रॉस करेंसी स्वैप	2,69,289.38	99,647.94	4,79,480.79	1,24,863.15
(ख)	स्वैप केवल मूलधन (नोट संख्या 22.3 देखें)	7,25,527.64	75,025.85	4,77,287.21	10,519.59
	कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	**9,94,817.02**	**1,74,673.79**	**9,56,768.00**	**1,35,382.74**

टिप्पणी: परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य वित्तीय विवरण में व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

नोट 4: व्यापार प्राप्तियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
	अच्छे माने जाने वाले प्राप्य, असुरक्षितरू		
(क)	संबंधित पाटियों	70.74	79.80
(ख)	अन्य	714.21	619.68
	कुल	**784.95**	**699.48**

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क)	6 माह से कम	541.60	699.48
(ख)	6 माह से 1 वर्ष	243.35	-
(ग)	1 से 2 वर्ष	-	-
(घ)	2 से 3 वर्ष	-	-
(ङ)	3 वर्ष से अधिक		
	कुल	**784.95**	**699.48**

नोट 5: ऋण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क)	**ऋण**		
(i)	**सावधि ऋण**		
I	**अवसंरचनात्मक ऋणः मानक आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष ऋण	22,86,009.94	20,62,406.64
ख.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	16,50,891.32	18,86,116.71
ग.	पुनर्वित्त योजना	23,86,907.04	21,86,120.00
घ.	इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बॉन्ड (इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग के तौर पर गिने जाते हैं)	22,32,577.60	12,13,451.83
II	**अवसंरचनात्मक ऋणः उप–मानक आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	-	23,678.72
III	**अवसंरचनात्मक ऋणः संदिग्ध आस्तियां**		
क.	प्रत्यक्ष उधार	93,296.81	53,102.58
ख.	टेकआउट फाइनेंसिंग योजना	19,193.32	1,016.94
	कुल (क) सकल	**86,68,876.04**	**74,25,893.41**
	घटाएँः हानि भत्ता (नोट 1 देखें)**(ख) 30)**	2,44,713.16	2,74,944.67
	घटाएँः विनियोजन के लिए लंबित राषि	5,366.93	2,324.83
	कुल (क) निवल	**84,18,795.95**	**71,48,623.92**
(ख)	(i) मूर्त आस्ति और अमूर्त आस्ति द्वारा प्रतिभूत	41,49,108.98	45,27,933.42
	(ii) अप्रतिभूत	45,19,767.06	28,97,960.00
	कुल (ख) सकल	**86,68,876.04**	**74,25,893.42**
	घटाएँः हानि हानि भत्ता (नोट 1(ख) 43 देखें)	2,44,713.16	2,74,944.68
	घटाएंः विनियोग लंबित राशि^^	5,366.93	2,324.83
	कुल (ख) सकल	**84,18,795.96**	**71,48,623.92**
(ग)	**भारत में ऋण**		
	(i) सार्वजनिक क्षेत्र	29,77,608.69	17,50,750.00
	(ii) पब्लिक क्षेत्र के अलावा	56,91,267.35	56,75,143.42
	कुल (ग) सकल	**86,68,876.04**	**74,25,893.42**
	घटाएंः इंपेयरमेंट लॉस अलाउंस	2,44,713.16	2,74,944.67
	घटाएंः विनियोजन के लिए लंबित राशि	5,366.93	2,324.83
	कुल (ग) निवल	**84,18,795.95**	**71,48,623.92**
	कुल	**84,18,795.95**	**71,48,623.92**

फुटनोट:

क्षेत्र	सुरक्षा के क्षेत्र का विवरण#	राशि (₹ लाख में)	
बिजली और अन्य क्षेत्र	मार्टगेज (बंधक): उधारकर्ता की सभी अचल आस्तियों, वर्तमान और भविष्य के बंधक के रूप में पहला परी–पासु प्रभार। दृष्टिबंधकः संयंत्र और मशीनरी आदि सहित ऋणी की सभी चल आस्तियों को दृष्टिबंधक के रूप में पहला परी–पासु प्रभार। शेयरों की गिरवी न्यूनतम 51%	24,13,391.63	22,67,614.59
सड़क और हवाई अड्डा (पीपीपी)	परियोजना की वार्षिकी और टोल संग्रह प्राप्त करने का अधिकार एस्क्रो खाता और ऋण लेने वाले के सभी अधिकार और शीर्षक और हित समान हैं दृष्टिबंधकः उधारकर्ता की सभी चल आस्तियों के दृष्टिबंधक के रूप में पहला परी–पासु प्रभार।	1735717.35306	2260318.83
पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थान और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बांड	असुरक्षित	45,19,767.06	28,97,960.00
	कुल	**86,68,876.04**	**74,25,893.42**

*भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 22 सितंबर 2021 के पत्र के अनुसार, अवसंरचना परियोजनाओं के बॉण्ड/डिबेंचर में निवेश, जिसमें पुनर्वित्तपोषण हेतु सदस्यता के माध्यम से किया गया निवेश भी शामिल है, चाहे परियोजना कार्यान्वयनाधीन हो अथवा पूर्ण हो चुकी हो, को ऋण एवं अग्रिम के रूप में माना जाता है। इसे कुल परिसंपत्तियों के न्यूनतम 75% को अवसंरचना ऋणों में लगाने के उद्देश्य से अवसंरचना ऋण माना जाएगा।

नोट 6: निवेश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को						31.03.2025 को					
		परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर				कुल	परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर				कुल
			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	
	म्यूचुअल फंड												
(i)	आईएएमसीएल द्वारा म्यूचुअल फंड निवेश	-	-	1,148.84		-	1,148.84	-	-	2,326.62		-	2,326.62
		-		**1,148.84**	**-**	**-**	**1,148.84**	**-**			**-**		**2,326.62**
	सरकारी प्रतिभूत												
(i)	6.29% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2030	88,760.00	-	-	-	-	88,760.00	88,760.00	-	-	-	-	88,760.00
(ii)	6.34% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2031	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00
(iii)	6.34% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2032	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00
(iv)	6.39% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2033	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00
(v)	6.39% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2034	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00
(vi)	6.44% (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार सुरक्षा 2035	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00	88,200.00	-	-	-	-	88,200.00
(vii)	7.12% मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति (एसजीएस) – 25–09–2036	50,060.00	-	-	-	-	50,060.00	50,060.00	-	-	-	-	50,060.00
(viii)	7.12% मध्य प्रदेश राज्य सरकार प्रतिभूति (एसजीएस) – 25–09–2036	50,060.00	-	-	-	-	50,060.00	50,060.00	-	-	-	-	50,060.00
(ix)	6.76% महाराष्ट्र राज्य सरकारी प्रतिभूति–23–04–2037	48,773.49	-	-	-	-	48,773.49	-	-	-	-	-	-
(x)	6.72% महाराष्ट्र राज्य सरकारी प्रतिभूति–23–04–2038	49,057.40	-	-	-	-	49,057.40	-	-	-	-	-	-
		7,27,710.89	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,27,710.89**	**6,29,880.00**			**-**		**6,29,880.00**
	ऋण प्रतिभूतियाँ												
	ऋणों में निवेश (असूचीबद्ध) (पूर्ण रूप से चुकता)												
(i)	बंसल पाथवेस (मंगावान–चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड के ऋण	-	-	6,078.00	-	-	6,078.00	-	-	6,078.00	-	-	6,078.00
(ii)	बंसल पाथवेस (एन.आर.आर.–1) प्राइवेट लिमिटेड के ऋण	-	-	7,276.00	-	-	7,276.00	-	-	7,276.00	-	-	7,276.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को						31.03.2025 को					
		परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर					परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर				
			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	कुल		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	कुल
(iii)	बंसल पाथवेस (एन.आर.आर.–2) प्राइवेट लिमिटेड के ऋण	-	-	11,184.00	-	-	11,184.00	-	-	11,184.00	-	-	11,184.00
(iv)	मीनाक्षी एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के ऋण	-	-	6,346.14	-	-	6,346.14	-	-	7,932.68	-	-	7,932.68
		-		**30,884.14**	**-**	**-**	**30,884.14**	**-**		**32,470.68**	**-**	**-**	**32,470.68**
	इक्विटी लिखतें												
क.	इक्विटी लिखत – गैर–उद्धृत												
(i)	दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड	-	-	411.03		-	411.03	-	-	411.03	-	-	411.03
(ii)	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा आयोजित)	-	-	4,765.00		-	4,765.00	-	-	4,765.00	-	-	4,765.00
		-		**5,176.02**		**-**	**5,176.02**	**-**		**5,176.02**			**5,176.02**
	अन्य												
क.	**उद्यम पूंजी में निवेश (अनुद्धृत) (पूरी तरह से भुगतान किया गया)**												
(i)	आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट II (पूरी तरह से भुगतान किया गया)	-	-	566.06		-	566.06	-	-	601.56	-	-	601.56
	सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश (अनुद्धृत) (पूरी तरह से भुगतान किया गया)					-							
ख.	एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट–एससी 276–सीरीज I)					-							
(i)	एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी ट्रस्ट–एससी 276–सीरीज I)	-	-	-	-	-	-	-	-	12,160.01	-	-	12,160.01
(ii)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0001	-	-	39,485.40	-	-	39,485.40	-	-	39,485.40	-	-	39,485.40
(iii)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0008	-	-	2,647.22	-	-	2,647.22	-	-	2,901.45	-	-	2,901.45
(iv)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0009	-	-	1,866.61	-	-	1,866.61	-	-	3,467.93	-	-	3,467.93
(v)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0017	-	-	3,375.16	-	-	3,375.16	-	-	3,944.09	-	-	3,944.09
(vi)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0010	-	-	4,557.65	-	-	4,557.65	-	-	4,557.65	-	-	4,557.65
(vii)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0013	-	-	3,447.06	-	-	3,447.06	-	-	3,447.06	-	-	3,447.06
(viii)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0019	-	-	13,944.09	-	-	13,944.09	-	-	14,956.26	-	-	14,956.26
(ix)	एनएआरसीएल ट्रस्ट–0022	-	-	3,931.35	-	-	3,931.35	-	-	3,672.10	-	-	3,672.10
		-	-	**73,254.54**	-	-	**73,254.54**	-	-	**88,591.97**	-	-	**88,591.97**
	कुल (क) सकल	**7,27,710.89**		**1,11,029.61**	**-**	**-**	**8,38,740.50**	**6,29,880.00**	**-**	**1,26,840.23**	**-**	**-**	**7,59,046.85**
	घटाएँ: हानि के लिए भत्ता (ग)		-	20,265.32	-	-	20,265.32	-	-	22,059.91	-	-	22,059.90
	कुल निवल घ = (क) – (ग)	**7,27,710.89**	**-**	**90,764.29**			**8,18,475.18**	**6,29,880.00**	**-**	**1,04,780.32**	**-**	**-**	**7,36,986.94**

हानि के लिए भत्ता का विवरणः

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को						31.03.2025 को					
		परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर					परिशोधन लागत	उचित मूल्य पर				
			अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	कुल		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से	लाभ और हानि के माध्यम से निष्पक्ष मूल्य पर नामित	अन्य	कुल
(i)	आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (आईआईएफसीएल की ओर से सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा आयोजित)	-	-	4,191.05	-	-	4,191.05	-	-	4,191.05	-	-	4,191.05
(ii)	बंसल पाथवेज (मंगवां–चकघाट) प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	-	-	4,779.68	-	-	4,779.68	-	-	4,892.09	-	-	4,892.09
(iii)	बंसल पाथवेज एनआरआर 1 में ऋण	-	-	4,451.99	-	-	4,451.99	-	-	4,736.88	-	-	4,736.88
(iv)	बंसल पाथवेज एनआरआर 2 में ऋण	-	-	5,072.96	-	-	5,072.96	-	-	5,689.90	-	-	5,689.90
(v)	मीनाक्षी एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड में डिबेंचर	-	-	1,769.63	-	-	1,769.63	-	-	2,549.99	-	-	2,549.99
	कुल	**-**	**-**	**20,265.32**	**-**	**-**	**20,265.32**	**-**	**-**	**22,059.91**	**-**	**-**	**22,059.91**

फुटनोटः

(क) **सूचीबद्ध निवेशों की कुल राशि–लागतध्पुस्तकीय मूल्य**

(i) लागत/पुस्तकीय मूल्य

(ii) बाजार मूल्य

	8,18,475.18	7,36,986.94

(क) **गैर–सूचीबद्ध निवेशों की कुल राशि–लागत/पुस्तकीय मूल्य**

(ख) व्यक्तिगत निवेशों के मूल्यांकन के लिए टिप्पणी 1(क)(5) देखें। एफवीटीपीएल और एफवीटीओसीआई के अंतर्गत कोई निवेश निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग) **वर्ष के दौरान ऋण मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा निर्धारित रेटिंग एवं रेटिंग में परिवर्तनः**

आईआईएफसीएल की घरेलू ऋण प्रतिभूतियों को क्रिसिल, केयर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और ब्रिकवर्क्स जैसी ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा "एएए" रेटिंग प्रदान की गई है, जो उच्चतम रेटिंग है।

कंपनी को स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा बीबीबी–/निगेटिव/ए–3 रेटिंग की पुष्टि की गई है, जो संप्रभु रेटिंग के समकक्ष है।

वर्ष के दौरान रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

नोट 7: अन्य वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
क.	**अग्रिमों**		
(i)	कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम	3,977.23	3,103.14
(ii)	सुरक्षा जमा का भुगतान	**62.25**	**54.63**
(iii)	अन्य	**13,908.69**	**11,929.30**
	उप–कुल (क)	**17,948.17**	**15,087.07**
ख.	**ऋण और अग्रिमों पर अर्जित और देय ब्याज**	**-**	**-**
	उप–कुल (ख)	**-**	**-**
ग.	**अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:**		
(i)	बैंकों में सावधि जमा	11,195.98	7,783.44
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	**3,179.75**	**17,071.65**
(iii)	ऋण और अग्रिम	**57,743.18**	**36,715.30**
	उप–कुल (ग)	**72,118.91**	**61,570.39**
	कुल (क)+(ख)+(ग)	**90,067.07**	**76,657.45**

नोट 7: आस्थगित कर आस्ति (निवल)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(i)	वसूल की जाने वाली निवल आयकर राशि	1,821.86	2,714.96
(ii)	वसूल किया जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर	1,366.91	1,208.70
(iii)	वसूल किया जाने वाला निवल अग्रिम कर	8.68	118.42
	कुल	**3,197.45**	**4,042.09**

टिप्पणी 9: आस्थगित कर परिसंपत्ति

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(I)	**आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:**		
(i)	विविध देनदारियों खाते में जमा ब्याज (पूंजीकृत ब्याज), जिसे कर हेतु प्रस्तुत किया गया है	-	1,166.85
(ii)	अपेक्षित ऋण हानि	-	15,671.16
(iii)	अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	14,384.38	25.79
(iv)	मूल्यह्रास	2,105.91	1,573.01
(v)	बीमारी अवकाश के लिए प्रावधान	100.79	111.01
(vi)	चिकित्सा सहायता योजना के लिए प्रावधान	381.60	370.51
(vii)	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	-	15.16
(viii)	अवकाश यात्रा रियायत के लिए प्रावधान	33.47	41.29
(ix)	उपदान के लिए प्रावधान	**-**	**16.59**
(x)	आईएएमसीएल की आस्थगित कर परिसंपत्ति	93.36	(5.36)
(xi)	डब्ल्यूटीडी/कर्मचारियों को लाभ–आधारित प्रोत्साहन के लिए प्रावधान	7.07	44.80
(xiii)	आईपीएल की आस्थगित कर परिसंपत्ति	92.70	-
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**17,199.28**	**19,030.82**
(II)	**आस्थगित कर देयता:**		
(i)	विविध देनदारियों खाते में जमा ब्याज (पूंजीकृत ब्याज), जिसे कर हेतु प्रस्तुत किया गया है	167.09	-
(ii)	जिन व्ययों पर स्रोत पर कर कटौती नहीं की गई है	-	-
(iii)	अन्य	1,463.40	1,715.62
	आस्थगित कर देयता	**1,630.49**	**1,715.62**
	आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता)–शुद्ध	**15,568.78**	**17,315.21**

नोट 10: संपत्ति, संयत्र और उपकरण

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	31.03.2026 को	01.04.2025 को	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	31.03.2026 को	31.03.2026 को	31.03.2025 को
मूर्त आस्ति										
भवन	27,701.73	15,711.48	-	43,413.21	5,967.52	1,114.86	-	7,082.38	36,330.83	21,734.21
संयंत्र एवं मशीनरी	144.85	1.42	(1.99)	148.27	135.18	1.09	(1.98)	138.26	10.01	9.67
फर्नीचर और फिटिंग	653.10	7.95	-	661.04	535.84	38.18	-	574.02	87.02	117.26
वाहनों	123.33	26.96	-	150.28	94.06	8.85	-	102.92	47.36	29.26
कार्यालय उपकरण	357.43	0.70	-	358.13	333.59	2.71	0.00	336.30	21.84	23.84
कम्पुटर हार्डवेयर	361.86	79.35	-	441.20	212.40	93.36	-	305.77	135.43	149.45
पट्टाधारित विकास	100.96	15.27	-	116.23	61.85	21.56	-	83.41	32.83	39.12
विद्युत उपकरण	346.41	-	-	346.41	329.09	-	-	329.09	17.32	17.32
कुल	**29,789.66**	**15,843.13**	**(1.99)**	**45,634.79**	**7,669.50**	**1,280.62**	**(1.98)**	**8,952.14**	**36,682.65**	**22,120.12**

नोट 10क : पूंजीगत कार्य प्रगति

(₹ लाख में)

मूल्यह्रास	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	31.03.2025 को	अतिरिक्त	निपटानध समायोजन	31.03.2026 को	31.03.2025 को	वर्ष हेतु	कटौती / बदलाव	31.03.2026 को	31.03.2026 को	31.03.2025 को
कुल	**15,333.67**	**2,879.96**	**15,995.67**	**2,217.96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2,217.96**	**15,333.67**

एजिंग सीडब्लूआईपी	निम्न अवधि के लिए सीडब्लू आईपी में राशि				कुल
सीडब्लूआईपी	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	2,217.96	-	-	-	2,217.96
अस्थाई रुप से स्थगित परियोजना	-	-	-	-	-
कुल	**2,217.96**	**-**	**-**	**-**	**2,217.96**

टिप्पणी 10(ख): उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	31.03.2026 को	01.04.2025 को	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	31.03.2026 को	31.03.2026 को	31.03.2025 को
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति	-	30.04	-	30.04	-	4.88	-	4.88	25.16	-
कुल	**-**	**30.04**	**-**	**30.04**	**-**	**4.88**	**-**	**4.88**	**25.16**	**-**

नोट 10: अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2025 को	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	31.03.2026 को	01.04.2025 को	अतिरिक्त	निपटान / समायोजन	31.03.2026 को	31.03.2026 को	31.03.2025 को
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	2,049.28	0.07	-	2,049.34	1,072.10	192.21	0.21	1,264.10	785.24	977.17
कुल	**2,049.28**	**0.07**	**-**	**2,049.34**	**1,072.10**	**192.21**	**0.21**	**1,264.10**	**785.24**	**977.17**

नोट 12: अन्य गैर वित्तीय आस्तियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(i)	पूर्वदत्त व्यय	162.82	3,462.01
(ii)	पूर्वदत्त कर्मचारी लागत	38.34	38.82
(iii)	अन्य अग्रिम	911.60	6,986.58
(iv)	उपदान (निधिकृत)	137.69	
(v)	अवकाश नकदीकरण (निधिकृत)	977.40	-
	कुल	**2,227.86**	**10,487.41**

टिप्पणी 13: अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
	व्यापार देयताएँ		
(i)	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएँ	89.09	2.10
(ii)	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त अन्य लेनदारों की कुल बकाया देयताएँ	75.56	223.74
	कुल	**164.65**	**225.84**

	व्यापार देयताओं का आयु–वार विश्लेषण	31.03.2026	31.03.2025
(क)	1 वर्ष से कम	159.96	225.84
(ख)	1 से 2 वर्ष	4.69	-
(ग)	2 से 3 वर्ष		
	कुल	**164.65**	**225.84**

नोट 14: ऋण प्रतिभूतियां

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
I	**प्रतिभूति बॉण्ड्स^**				
(i)	₹79,110 (31 मार्च 2025 को ₹79,110)–8.30% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 28/03/2026 को प्रतिदेय।	-	-	791.10	791.10
(ii)	₹10,500 (31 मार्च 2025 को ₹10,500)–9.41% करयोग्य बॉण्ड, सीरीज X, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 27/07/2037 को प्रतिदेय।	1,05,000.00	1,05,000.00	10,000.00	10,000.00
(iii)	₹500 (31 मार्च 2025 को ₹500)–9.36% करयोग्य बॉण्ड, सीरीज X, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 27/07/2042 को प्रतिदेय।	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
(iv)	₹1,000 (31 मार्च 2025 को ₹1,000)–7.38% कर–मुक्त बॉण्ड, सीरीज III-B, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 15/11/2027 को प्रतिदेय।	10,000.00	10,000.00	67,411.62	67,411.62
(v)	₹3,400 (31 मार्च 2025 को ₹3,400)–7.41% कर–मुक्त बॉण्ड, सीरीज III-C, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 15/11/2032 को प्रतिदेय।	34,000.00	34,000.00	8,683.91	8,683.91
(vi)	₹500 (31 मार्च 2025 को ₹500)–7.38% कर–मुक्त बॉण्ड, सीरीज IV–B, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 21/11/2027 को प्रतिदेय।	5,000.00	5,000.00	3,615.54	3,615.54
(vii)	₹210 (31 मार्च 2025 को ₹210)–7.41% कर–मुक्त बॉण्ड, सीरीज IV–C, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 21/11/2032 को प्रतिदेय।	2,100.00	2,100.00	1,040.64	1,040.64
(viii)	₹68,77,081 (31 मार्च 2025 को ₹67,41,162)–7.36% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच I – सीरीज I, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 22/01/2028 को प्रतिदेय।	68,770.81	68,770.81	63,030.00	63,030.00
(ix)	₹7,32,472 (31 मार्च 2025 को ₹8,68,391)–7.86% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच I – सीरीज I, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 22/01/2028 को प्रतिदेय।	7,324.72	7,324.72	1,15,970.00	1,15,970.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(x)	₹1,03,89,938 (31 मार्च 2025 को ₹1,01,62,809)–7.40% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच **I** – सीरीज **III**, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 22/01/2033 को प्रतिदेय।	1,03,899.38	1,03,899.38	1,12,970.00	1,12,970.00
(xi)	₹11,74,286 (31 मार्च 2025 को ₹14,01,415)–7.90% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच I – सीरीज III, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 22/01/2033 को प्रतिदेय।	11,742.86	11,742.86	890.09	890.09
(xii)	₹3,86,252 (31 मार्च 2025 को ₹3,61,554)–7.02% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच II – सीरीज II, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 26/03/2028 को प्रतिदेय।	3,862.52	3,862.52	30,353.30	30,353.30
(xiii)	₹79,366 (31 मार्च 2025 को ₹1,04,064)–7.52% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच II – सीरीज II, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 26/03/2028 को प्रतिदेय।	793.66	793.66	15,713.11	15,713.11
(xiv)	₹82,275 (31 मार्च 2025 को ₹42,472)–7.08% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच II – सीरीज III, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 26/03/2033 को प्रतिदेय।	822.75	822.75	679.08	679.08
(xv)	₹1,50,890 (31 मार्च 2025 को ₹1,90,693)–7.58% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच II – सीरीज III, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 26/03/2033 को प्रतिदेय।	1,508.90	1,508.90	27,989.22	27,989.22
(xvi)	₹6,303 (31 मार्च 2025 को ₹6,303)–8.26% कर–मुक्त बॉण्ड, सीरीज V–B, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 23/08/2028 को प्रतिदेय।	63,030.00	63,030.00	14,109.50	14,109.50
(xvii)	₹20 (31 मार्च 2025 को ₹20)–8.19% कर–मुक्त बॉण्ड, सीरीज V–C, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 23/08/2033 को प्रतिदेय।	200.00	200.00	1,228.07	1,228.07
(xviii)	₹11,597 (31 मार्च 2025 को ₹11,597)–8.46% कर–मुक्त बॉण्ड, सीरीज VI-B, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 30/08/2028 को प्रतिदेय।	1,15,970.00	1,15,970.00	1,59,584.86	1,59,584.86
(xix)	₹265 (31 मार्च 2025 को ₹265)–8.37% कर–मुक्त बॉण्ड, सीरीज VI-C, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 30/08/2033 को प्रतिदेय।	2,650.00	2,650.00	27,110.62	27,110.62

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xx)	₹11,297 (31 मार्च 2025 को ₹11,297)–8.48% कर–मुक्त बॉण्ड, सीरीज VII–B, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 05/09/2028 को प्रतिदेय।	1,12,970.00	1,12,970.00	34,000.00	34,000.00
(xxi)	₹30,35,330 (31 मार्च 2025 को ₹30,35,330)–8.38% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच 1 – सीरीज 2।, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 12/11/2028 को प्रतिदेय।	30,353.30	30,353.30	2,100.00	2,100.00
(xxii)	₹2,12,973 (31 मार्च 2025 को ₹89,009)–8.38% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच 1 – सीरीज 2बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 12/11/2028 को प्रतिदेय।	2,129.73	2,129.73	1,01,628.09	1,01,628.09
(xxiii)	₹14,47,347 (31 मार्च 2025 को ₹15,71,311)–8.63% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच 1 – सीरीज 2बी, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 12/11/2028 को प्रतिदेय।	14,473.47	14,473.47	14,014.15	14,014.15
(xxiv)	₹18,68,982 (31 मार्च 2025 को ₹18,68,982)–8.50% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच 1 – सीरीज 3क, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 12/11/2033 को प्रतिदेय।	18,689.82	18,689.82	424.72	424.72
(xxv)	₹4,31,754 (31 मार्च 2025 को ₹1,59,113)–8.50% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच 1 – सीरीज 3ख, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 12/11/2033 को प्रतिदेय।	4,317.54	4,317.54	1,906.93	1,906.93
(xxvi)	₹21,47,867 (31 मार्च 2025 को ₹24,20,508)–8.75% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच 1 – सीरीज 3ख, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 12/11/2033 को प्रतिदेय।	21,478.67	21,478.67	200.00	200.00
(xxvii)	₹27,98,922 (31 मार्च 2025 को ₹27,98,922)–8.48% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच II – सीरीज 2।, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 22/01/2029 को प्रतिदेय।	27,989.22	27,989.22	2,650.00	2,650.00
(xxviii)	₹75,43,989 (31 मार्च 2025 को ₹75,43,989)–8.66% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच II – सीरीज 3क, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 22/01/2034 को प्रतिदेय।	75,439.89	75,439.89	1,591.13	1,591.13

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xxix)	₹1,90,894 (31 मार्च 2025 को ₹67,908)–8.48% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच II – सीरीज 2ख, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 22/01/2029 को प्रतिदेय।	1,908.94	1,908.94	18,689.82	18,689.82
(xxx)	₹12,87,964 (31 मार्च 2025 को ₹14,10,950)–8.73% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच II – सीरीज 2ख, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 22/01/2029 को प्रतिदेय।	12,879.64	12,879.64	24,205.08	24,205.08
(xxxi)	₹11,65,808 (31 मार्च 2025 को ₹5,15,765)–8.66% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच I – सीरीज 3ख, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 22/01/2034 को प्रतिदेय।	11,658.08	11,658.08	5,157.65	5,157.65
(xxxii)	₹47,93,189 (31 मार्च 2025 को ₹54,43,232)–8.91% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच I – सीरीज 3ख, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 22/01/2034 को प्रतिदेय।	47,931.89	47,931.89	75,439.89	75,439.89
(xxxiii)	₹1,59,58,486 (31 मार्च 2025 को ₹1,59,58,486)–8.55% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच III – सीरीज 2क, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 27/03/2029 को प्रतिदेय।	1,59,584.86	1,59,584.86	54,432.32	54,432.32
(xxxiv)	₹12,59,825 (31 मार्च 2025 को ₹12,59,825)–8.55% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच III – सीरीज 3, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 27/03/2034 को प्रतिदेय।	12,598.25	12,598.25	12,598.25	12,598.25
(xxxv)	₹3,29,038 (31 मार्च 2025 को ₹1,22,807)–8.55% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच III – सीरीज 2ख, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 27/03/2029 को प्रतिदेय।	3,290.38	3,290.38	12,873.11	12,873.11
(xxxvi)	₹25,04,831 (31 मार्च 2025 को ₹27,11,062)–8.80% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच III – सीरीज 2ख, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 27/03/2029 को प्रतिदेय।	25,048.31	25,048.31	1,254.70	1,254.70
(xxxvii)	₹2,61,357 (31 मार्च 2025 को ₹1,25,470)–8.55% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच I, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 27/03/2034 को प्रतिदेय।	2,613.57	2,613.57	1,05,000.00	1,05,000.00
(xxxviii)	₹11,51,424 (31 मार्च 2025 को ₹12,87,311)–8.80% कर–मुक्त बॉण्ड, ट्रांच I, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1,000, 27/03/2034 को प्रतिदेय।	11,514.24	11,514.24	5,000.00	5,000.00
		11,38,545.40	**11,38,545.40**	**11,39,336.50**	**11,39,336.50**

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
II	**असुरक्षित बॉण्ड^**				
(i)	400–अमेरिकी डॉलर 10 लाख अंकित मूल्य वाले प्रत्येक बॉण्ड पर 6 माह की अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर से संबद्ध ब्याज, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभिदत्त, 29/01/2029 को प्रतिदेय।	3,78,617.20	3,78,617.20	3,42,325.60	3,42,325.60
(ii)	₹15,000–7.17% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 12/03/2032 को प्रतिदेय।	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00
(iii)	₹5,000–7.46% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 31/05/2033 को प्रतिदेय।	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
(iv)	₹2,00,000–7.69% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹10 लाख, 26/10/2038 को प्रतिदेय।	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00
(v)	₹2,00,000–7.69% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 26/10/2038 को प्रतिदेय।	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00
(vi)	₹1,00,000–7.67% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 26/10/2038 को प्रतिदेय।	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00
(vii)	₹1,50,000–7.34% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 14/03/2039 को प्रतिदेय।	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00	1,50,000.00
(viii)	₹2,00,000–7.51% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 25/04/2039 को प्रतिदेय।	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00	2,00,000.00
(ix)	₹1,02,500–7.41% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 26/06/2039 को प्रतिदेय।	1,02,500.00	1,02,500.00	1,02,500.00	1,02,500.00
(x)	₹51,500–7.39% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 01/08/2039 को प्रतिदेय।	51,500.00	51,500.00	51,500.00	51,500.00
(xi)	₹96,000–7.37% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 02/09/2034 को प्रतिदेय।	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
(xii)	₹1,58,500–7.26% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 07/11/2034 को प्रतिदेय।	1,58,500.00	1,58,500.00	1,58,500.00	1,58,500.00
(xiii)	₹74,500–7.47% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 07/11/2027 को प्रतिदेय।	74,500.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00
(xiv)	₹55,000–7.35% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 20/12/2034 को प्रतिदेय।	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
(xv)	₹74,000–7.47% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 20/03/2028 को प्रतिदेय।	74,000.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
(xvi)	₹1,04,000–7.56% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 20/03/2028 को प्रतिदेय।	1,04,000.00	1,04,000.00	1,04,000.00	1,04,000.00
(xvii)	₹1,00,000–7.28% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 27/03/2032 को प्रतिदेय।	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00	1,00,000.00
(xviii)	₹2,00,000–7.08% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 15/05/2035 को प्रतिदेय।	2,00,000.00	2,00,000.00	-	-
(xix)	₹1,56,000–6.99% बॉण्ड, प्रत्येक का अंकित मूल्य ₹1 लाख, 15/06/2030 को प्रतिदेय।	1,56,000.00	1,56,000.00		
	कुल सकल (क)	**26,00,617.20**	**26,00,617.20**	**22,08,325.60**	**22,08,325.60**
	कुल सकल (क)	**37,39,162.60**	**37,39,162.60**	**33,47,662.10**	**33,47,662.10**
	भारत में ऋण प्रतिभूतियाँ	33,60,545.40	33,60,545.40	22,89,336.50	22,89,336.50
	भारत के बाहर ऋण प्रतिभूतियाँ	3,78,617.20	3,78,617.20	10,58,325.60	10,58,325.60
	कुल सकल (ख)	**37,39,162.60**	**37,39,162.60**	**33,47,662.10**	**33,47,662.10**
	कुल (ख), (क) से मिलान हेतु	**37,39,162.60**	**37,39,162.60**	**33,47,662.10**	**33,47,662.10**

नोट 15: उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को		31.03.2025 को	
		परिशोधन लागत	कुल	परिशोधन लागत	कुल
क)	**सावधि ऋण**				
(i)	**अप्रतिभूत ऋण:**				
क.	अल्पकालिक ऋण	12,33,101.40	12,33,101.40	15,63,248.07	15,63,248.07
ख.	अन्य ऋण–आईआईएफसी यूके	2,85,022.98	2,85,022.98	2,13,953.49	2,13,953.49
ग.	दीर्घकालिक ऋण	12,99,743.32	12,99,743.32	2,20,000.00	2,20,000.00
(ii)	**अन्य पक्षों से असुरक्षित ऋण:**				
क.	एशियाई विकास बैंक (एडीबी)	11,79,891.22	11,79,891.22	10,64,015.50	10,64,015.50
ख.	आईबीआरडी (विश्व बैंक)	1,03,510.16	1,03,510.16	1,01,728.52	1,01,728.52
ग.	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)	1,38,515.99	1,38,515.99	1,30,353.39	1,30,353.39
घ.	क्रैडिएन्स्टाल्ट फर विडेरूफुबाऊ (केएफडब्ल्यू)	14,529.01	14,529.01	12,807.08	12,807.08
ङ.	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी	2,04,052.62	2,04,052.62	2,14,970.21	2,14,970.21
च.	सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (एसएमबीएस)	1,54,050.00	1,54,050.00	-	-
ख)	**मांग पर चुकाने योग्य ऋण सुरक्षित ऋण:**				
i)	बैंकों से* (31 मार्च 2026 को ₹ 2,09,400 लाख की सावधि जमा रसीदों को गिरवी रखकर सुरक्षित (31 मार्च 2025 तक ₹ 2,12,300 लाख))	2,14,882.39	2,14,882.39	47,625.41	47,625.41
	कुल (क)	**48,27,299.09**	**48,27,299.09**	**35,68,701.67**	**35,68,701.67**
	भारत में उधार	27,47,727.11	27,47,727.11	18,30,873.47	18,30,873.47
	भारत–एफसी ऋण के बाहर उधार	20,79,571.98	20,79,571.98	17,37,828.21	17,37,828.21
	कुल	**48,27,299.09**	**48,27,299.09**	**35,68,701.67**	**35,68,701.67**

लंबी अवधि के ऋणों की चुकौती की शर्तें

I) एशियाई विकास बैंक

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि ($ लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	3000	ओवरनाइट एसओएफआर +20bps	15.12.2012	15.06.2032	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रत्येक किस्त
II	2000	ओवरनाइट एसओएफआर +20bps	15.06.2014	15.12.2033	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि के 2.50% की प्रत्येक किस्त
III	2100	ओवरनाइट एसओएफआर +20bps	15.12.2014	15.06.2034	अर्ध–वार्षिक	बलूनिंग किश्तें 0.827816% से शुरू होकर 5.55031% ऋण राशि तक
IV	2500	ओवरनाइट एसओएफआर +30bps	15.12.2015	15.06.2035	अर्ध–वार्षिक	
V	2400	ओवरनाइट एसओएफआर +40bps	15.12.2016	15.06.2036	अर्ध–वार्षिक	
VI	4000	ओवरनाइट एसओएफआर +40bps	15.03.2018	15.03.2033	अर्ध–वार्षिक	बलूनिंग किश्तें 2.173900% से शुरू होकर ऋण राशि के 4.559913% तक
VII	3000	ओवरनाइट एसओएफआर +50bps	01.05.2023	01.05.2038	अर्ध–वार्षिक	बलूनिंग किश्तें 2.173900% से शुरू होकर ऋण राशि के 4.559913% तक
VIII	5000	ओवरनाइट एसओएफआर +50bps	01.06.2029	01.06.2044	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि की प्रत्येक किस्त 3.225806%
कुल	**24000**					

ii) आईबीआरडी (विश्व बैंक)

अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि ($ लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
1950*	6एम यूएसडी एसओएफआर + परिवर्तनशील वृद्धि	15.04.2017	15.04.2037	अर्ध–वार्षिक	15.10.2036 तक ऋण राशि का 2.44: और 15.04.2037 को 2.40: की किश्त

*18 दिसंबर 2013 को इसकी लाइन ऑफ क्रेडिट के पुनर्गठन के कारण आईबीआरडी (विष्व बैंक) के ऋण की राषि घटकर $1,950 लाख रह गई है, जिसमें $10,000 लाख की ऋण राषि के निरस्तीकरण का विवरण षामिल है।

क्रैडिएन्स्टाल्ट फर विडेरूफुबाऊ (केएफडब्ल्यू)

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि (यूरो लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	165.89	0.75%	30.06.2020	30.06.2050	अर्ध–वार्षिक	– यूरो 271,000 30.06.2020 से 30.12.2021 तक – 30.06.2022 से 30.12.2049 तक यूरो 272,000 और 30.06.2050 को यूरो 272581.03
II	334.11	4.99%	30.06.2015	30.06.2020	अर्ध–वार्षिक	– 30.06.2015 से 30.06.2018 तक यूरो 3,037,000 – 30.12.2018 से 30.12.2019 तक यूरो 3,038,000 और 30.06.2025 को यूरो 3,038,418.97
कुल	**500.00**					

iv) यूरो इंवेस्टमैंट बैंक

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि (यूरो लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
I	350.00	6 मिलियन यूरीबोर +0.275% का संपूर्ण प्रसार	22.06.2020	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किस्त 11,66,666.67 यूरो
II	400.00	6 मिलियन यूरीबोर +0-436% का संपूर्ण प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
III	400.00	6 मिलियन यूरीबोर +0.426% का संपूर्ण प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किस्त 14,28,571.43 यूरो
IV	850.00	6 मिलियन यूरीबोर +0.346% का संपूर्ण प्रसार	21.06.2021	20.12.2034	अर्ध–वार्षिक	प्रत्येक किस्त 30,35,714.29 यूरो
कुल	**2000.00**					

v) जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि (जापानी येन लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति	पुर्नभुगतान की राशि
भाग–I	10,000.00	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर 0.10% की फ्लोर और 6.208% की उच्चतम सीमा के साथ	20.03.2022	20.03.2036	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि की पहली किश्त 3.448328: और उसके बाद ऋण राशि के 3.448274: की किश्तें।
भाग–II	90,000.00	6एम जेपीवाई एलआईबीओआर 0.10% की फ्लोर और 6.208% की उच्चतम सीमा के साथ	20.03.2022	20.03.2036	अर्ध–वार्षिक	ऋण राशि की पहली किश्त 3.448328: और उसके बाद ऋण राशि के 3.448274: की किश्तें।

vi) सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन

ट्रैंच	अनुबंध के अनुसार किश्त ऋण राशि (जापानी येन लाख में)	ब्याज दर	पुर्नभुगतान का प्रारंभ	पुर्नभुगतान की समाप्ति	पुर्नभुगतान की आवृत्ति एवं राशि
I	1,60,000.00	टीओएनए . 0.8491%	25.07.2025	25.07.2030	प्रत्येक ऋण की अंतिम परिपक्वता तिथि पर एकमुश्त पुनर्भुगतान
II	1,00,000.00	टीओएनए . 0.8491%	11.11.2025	11.11.2030	प्रत्येक ऋण की अंतिम परिपक्वता तिथि पर एकमुश्त पुनर्भुगतान

नोट 16: अन्य वित्तीय देनदारियां

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
क	**उपार्जित ब्याज**		
(i)	बांड और सावधि ऋण पर	1,34,835.35	1,18,407.67
ख	**अन्य**		
(i)	प्रतिभूति जमाएं प्राप्त	63.93	1.43
(ii)	अन्य	4,955.21	7,747.30
	कुल	**1,39,854.49**	**1,26,156.39**

टिप्पणी 17: चालू कर देयताएँ

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(i)	आयकर के लिए प्रावधान	13,192.49	14,094.88
(ii)	आयकर (शुद्ध)	4,905.84	15,725.16
	कुल	**18,098.34**	**29,820.04**

नोट 18: प्रावधान

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
(i)	अवकाश नकदीकरण	95.28	124.27
(ii)	बीमारी की अवकाश	400.47	441.09
(iii)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	1,606.44	1,463.51
(iv)	अवकाश किराया छूट	178.82	173.88
(v)	वेतन संशोधन	2,466.86	1,817.19
(vi)	उपदान	81.88	91.22
(vii)	कर्मचारियों/डब्ल्यूटीडीएस को पीएलआई	28.08	178.00
(viii)	नए श्रम संहिता के कारण उपदान	65.63	-
	अन्य		
(i)	एनपीए की ओर से व्यय	439.77	1,134.61
	कुल	**5,363.23**	**5,423.78**

नोट 19: अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क)	**अन्य देयताएं**		
(i)	देय सांविधिक देयताएं	2,003.11	1,457.55
(ii)	बांड पर दावा न किया गया ब्याज	0.69	0.69
(iii)	देय प्रतिबद्धता शुल्क	186.30	-
(iv)	विविध देनदारी खाता (ब्याज पूंजीकरण)*	3,725.97	9,026.24
(v)	अन्य	6,962.35	5,602.82
	कुल	**12,878.43**	**16,087.30**

*यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक सर्कुलर "कोविड–19 विनियामक पैकेज" के अनुसार आईआईएफसीएल के उधारकर्ताओं को मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक प्रदान की गई स्थगन अवधि को सम्मिलित करती है।

नोट 20: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
क	**प्राधिकृत** ₹10/प्रत्येक के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2025 तक ₹10/– प्रत्येक के 10,000,000,000 इक्विटी शेयर)	**10,00,000.00**	**10,00,000.00**
ख	**निर्गत, अभिदत्त और प्रदत्त** 10 रू. प्रत्येक के 9,999,916,230 के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर (31 मार्च 2025 को 10 रू. प्रत्येक के 9,999,916,230 इक्विटी शेयर)	9,99,991.62	9,99,991.62
	कुल	**9,99,991.62**	**9,99,991.62**

फुटनोट:

क) रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
	शेयरों की संख्या	(₹ लाख में)	शेयरों की संख्या	(₹ लाख में)
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में बकाया शेयर	9,99,99,16,230	9,99,991.62	9,99,99,16,230	9,99,991.62
रिपोर्टिंग अवधि के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया शेयर	9,99,99,16,230	9,99,991.62	9,99,99,16,230	9,99,991.62

ख) प्रत्येक ऐसे शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण, जिसके पास 5% से अधिक शेयर हैं:

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	
	शेयरों की संख्या	धारित %	शेयरों की संख्या	धारित %
भारत के राष्ट्रपति	9,99,99,16,230	100.00%	9,99,99,16,230	100.00%

ग) प्रमोटरों की शेयरधारिता का प्रकटीकरण

विवरण	31.03.2026 को समाप्त वर्ष		31.03.2025 को समाप्त वर्ष		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	
भारत के राष्ट्रपति	9,99,99,16,230	100.00%	9,99,99,16,230	100.00%	-

नोट 19: अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(क)	**पूँजी आरक्षित निधि (गैर–चालू प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ)**		
	प्रारंभिक शेष	585.14	585.14
	जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से अंतरण	-	-
	अंतिम शेष	**585.14**	**585.14**
(ख)	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता (बॉण्ड्स पर)**		
	प्रारंभिक शेष	235.50	235.50
	जोड़ें: वर्ष के दौरान	-	-
	अंतिम शेष	**235.50**	**235.50**
(ग)	**डिबेंचर/बॉण्ड रिडेम्पशन रिजर्व**		
	प्रारंभिक शेष	54,568.28	54,568.28
	घटाएँ: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष में अंतरण	105.99	
	अंतिम शेष	**54,462.29**	**54,568.28**
(घ)	**नकदी प्रवाह हेज आरक्षित**		
	प्रारंभिक शेष	(20,317.05)	(17,025.08)
	जोड़ें: वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह हेज आरक्षित	12,402.83	(3,291.97)
	अंतिम शेष	**(7,914.22)**	**(20,317.05)**
(ङ)	**अन्य आरक्षित निधियाँ**		
(i)	**विशेष आरक्षित निधि धारा 36(1)(viii), आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत (फुटनोट 1)**		
	प्रारंभिक शेष	2,16,690.69	1,77,588.70
	जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष में अंतरण (शुद्ध)	42,410.32	39,101.98
	अंतिम शेष	**2,59,101.01**	**2,16,690.69**

क्र.सं.	विवरण	31.03.2026 को	31.03.2025 को
(ii)	**स्टाफ वेलफेयर रिजर्व (फुटनोट 2)**		
	प्रारंभिक शेष	3,394.82	297.16
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष में अंतरण	1,537.55	3,400.02
	घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि तथा लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष में अंतरण	139.15	302.36
	अंतिम शेष	**4,793.22**	**3,394.82**
(iii)	**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) रिजर्व (फुटनोट 3)**		
	प्रारंभिक शेष	122.45	122.45
	घटाएँ: उपयोग की गई राशि	-	-
	अंतिम शेष	**122.45**	**122.45**
(iv)	**रिजर्व फंड धारा 45–IC, आरबीआई, अधिनियम 1934 के अंतर्गत (फुटनोट 4)**		
	प्रारंभिक शेष	18,084.32	15,712.43
	जोड़ें: लाभ और हानि खाते के अधिशेष में अंतरण	12,771.25	2,371.89
	अंतिम शेष	30,855.57	18,084.32
(v)	**हानि समायोजन आरक्षित निधि (पाद टिप्पणी 5)**		
	प्रारंभिक शेष	1,01,230.76	1,01,230.76
	वर्ष के दौरान समायोजन जोड़े/घटाएँ	-	-
	अंतिम शेष	**1,01,230.76**	**1,01,230.76**
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधि (पाद टिप्पणी 6)		
	प्रारंभिक शेष	1,14,831.82	71,536.34
	लाभ एवं हानि खाते के अधिशेष से अंतरण: जोड़ें	27,588.43	43,295.49
	अंतिम शेष	**1,42,420.26**	**1,14,831.82**
(च)	**प्रतिधारित आय**		
	प्रारंभिक शेष	1,71,003.09	(6,222.12)
	जोड़ें: कर पश्चात लाभ	1,47,195.53	2,63,143.54
	जोड़ें: स्टाफ वेलफेयर रिजर्व से अंतरण	141.38	297.07
	जोड़ें: इंड एएस समायोजन	-	10.80
	जोड़ें: डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से अंतरण	105.99	-
	घटाएँ: स्टाफ वेलफेयर रिजर्व में अंतरण	1,542.03	3,400.02
	घटाएँ: विषेश आरक्षित निधि में अंतरण – धारा 36(1)(viii), आयकर अधिनियम 1961	42,410.32	39,101.98
	घटाएँ: पूर्व–संचालनकालीन गिफ्ट एसईजेड व्यय	-	4.33
	घटाएँ: हानि भत्ता आरक्षित निधि में अंतरण	0.11	0.11
	घटाएँ: पूर्ववर्ती अवधि की मद	33.19	2.96
	घटाएँ: कर समायोजन	18.79	14.57
	घटाएँ: परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मूल्यांकन लाभ/(हानि)	(56.28)	406.74
	घटाएँ: रिजर्व फंड धारा 45–IC में अंतरण	27,588.43	43,295.49
	अंतिम शेष	**2,46,909.41**	**1,71,003.09**
	कुल	**8,32,801.39**	**6,60,429.82**

फुटनोट:

1 सिक्योरिटीज प्रीमियम उस अतिरिक्त राषि का प्रतिनिधित्व करता है जो कंपनी को इक्विटी षेयरों और डेट सिक्योरिटीज को उनकी मूल कीमत से अधिक मूल्य पर जारी करने पर प्राप्त होती है। सिक्योरिटीज प्रीमियम खाते में उपलब्ध राषि का उपयोग कंपनीज एक्ट, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

2 विषेश आरक्षित निधि भारत में बुनियादी ढांचे की सुविधा के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने वाली कंपनियों द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत बनाए रखने के लिए आवष्यक वैधानिक आरक्षित निधि है।

3 स्टाफ वेलफेयर आरक्षित निधि को कर्मचारियों, खेल, सांस्कृतिक और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के बीच बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

4 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से, आईआईएफसीएल ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवष्यक सीएसआर व्यय के लिए सीएसआर आरक्षित निधि नहीं बनाया है और 3 जुलाई 2015 के पत्र के माध्यम से इस मुद्दे को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) को संदर्भित किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार सीएसआर के तहत खर्च की जाने वाली राषि के अलावा सीएसआर आरक्षित निधि बनाने और इसके उपयोग को जारी रखने पर स्पश्टीकरण के लिए डीपीई से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है .

5. आरक्षित निधि निधि आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45–आईसी के अनुसार बनाया गया है।

नोट 21: ब्याज आय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों पर	
		31.03.2026	31.03.2025
क)	प्रत्यक्ष उधार के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज		
(i)	पीएमडीओ योजना के तहत ऋण पर ब्याज	1,91,579.54	1,92,897.31
(ii)	पुनर्वित्त योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	1,45,294.96	1,43,395.92
(iii)	टेकआउट वित्तपोषण योजना के तहत ऋण और अग्रिम पर ब्याज	1,53,110.74	1,52,159.19
(iv)	दंडात्मक ब्याज	209.64	171.43
(v)	अवसंरचनात्मक बांड पर ब्याज	1,55,197.59	78,653.78
ख)	**निवेश से ब्याज आय**		
(i)	सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	45,355.25	37,394.89
ग)	**बैंकों में जमाराशियों पर ब्याज**	53,335.55	60,016.82
	कुल	**7,44,083.28**	**6,64,689.33**

नोट 22: शुल्क और कमीशन आय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
(i)	**अग्रिम शुल्क**	2,352.84	3,213.57
(ii)	प्रक्रिया शुल्क	207.00	356.00
(iii)	पूर्व भुगतान शुल्क	1,116.15	250.11
(iv)	क्रेडिट संवर्धन से शुल्क	195.00	451.07
(v)	परामर्श एवं सेवा शुल्क	1,414.65	1,674.14
(vi)	निवेश प्रबंधन शुल्क	-	-
(vii)	अन्य शुल्क	1,601.01	1,722.53
	कुल	**6,886.65**	**7,667.42**

नोट 23: अन्य आय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
	अन्य		
(i)	अपलिखित ऋणों की वसूली	32,091.75	26,678.86
(ii)	सरकार द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा रसीदों का साकार मूल्य	-	16,834.35
(iii)	विविध आय	10,431.79	896.90
(iv)	कर्मचारी ऋण पर ब्याज आय का अप्रत्याहरण	-	12.23
(v)	विदेशी मुद्रा लेन–देन एवं अनुवाद पर शुद्ध लाभ	-	-
(vi)	स्वैप सौदों पर लाभ	79,545.77	11,528.21
(vii)	आयकर वापसी पर ब्याज	11.93	7.28
	कुल	**1,22,081.24**	**55,957.83**

नोट 24: वित्त लागत

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	
		31.03.2026	31.03.2025
क)	**उधारी पर ब्याज**		
(ii)	बैंक उधारी पर ब्याज	1,52,503.45	1,56,668.30
(iii)	बहुपक्षीय संस्थानों से प्राप्त ऋण पर ब्याज	81,079.00	87,073.66
ख)	**ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**	2,54,595.21	2,04,496.38
ग)	**अन्य ब्याज व्यय**		
i)	आयकर पर ब्याज	461.13	553.75
	कुल	**4,88,638.80**	**4,48,792.09**

नोट 25: शुल्क और कमीशन व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
(i)	सरकारी गारंटी शुल्क	8,326.78	10,768.30
(ii)	बांड शोधन व्यय	259.83	733.05
(iii)	प्रतिबद्धता शुल्क	474.02	-
	कुल	**9,060.64**	**11,501.34**

टिप्पणी 26: उचित मूल्य में परिवर्तन पर शुद्ध (लाभ)/हानि

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय उपकरणों पर शुद्ध (लाभ)/हानि		
	(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर	-	-
	(ii) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित वित्तीय उपकरणों पर	1,007.16	(12,254.58)
	उचित मूल्य में परिवर्तन से कुल शुद्ध (लाभ)/हानि	**1,007.16**	**(12,254.58)**
	उचित मूल्य में परिवर्तन*		
	– साकार	-	-
	– असाकार	1,007.16	(12,254.58)
	उचित मूल्य में परिवर्तन से कुल शुद्ध (लाभ)/हानि	**1,007.16**	**(12,254.58)**

*इस अनुसूची में उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तन ब्याज आयध्व्यय के कारण होने वाले परिवर्तनों के अतिरिक्त हैं।

नोट 27: वित्तीय लिखतों पर ह्रास

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		परिशोधन लागत पर मापे गए वित्तीय लिखतों पर	
		31.03.2026	31.03.2025
(i)	ऋण	(7,790.26)	(55,401.54)
(ii)	निवेश	(1,794.59)	(1,594.83)
(iii)	अनुत्पादक परिसंपत्तियों की ओर से किए गए व्यय	43.86	58.03
	कुल	**(9,540.99)**	**(56,938.34)**

नोट 28: कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
(i)	वेतन और मजदूरी	8,959.11	8,960.18
(ii)	भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	462.24	608.52
(iii)	कर्मचारी कल्याण व्यय	216.94	106.86
(iv)	कर्मचारी कल्याण व्यय	-	3.96
	कुल	**9,638.30**	**9,679.52**

नोट 29 : अन्य व्यय

(₹ लाख में)

क्र. सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2026	31.03.2025
(i)	किराया, कर और ऊर्जा लागतें	199.81	292.16
(ii)	मुद्रा और लेखन सामग्री	36.97	35.52
(iii)	विज्ञापन और प्रचार	72.83	40.18
(iv)	निदेशक की फीस, भत्ते और खर्चे	18.30	19.75
(v)	लेखापरीक्षकों की फीस और खर्चे	195.64	147.57
(vi)	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	975.25	348.24
(vii)	बीमा	24.32	23.45
(viii)	अन्य खर्चे		
क)	विदेशी मुद्रा लेनदेन और रूपांतरणों पर निवल हानि	1,36,613.51	22,735.84
ख)	अन्य व्यय	6,571.75	3,979.10
ग)	बट्टे खाते में डाली गई ऋण राशि (नोट 1(ख)(20(क)) देखें,	16,615.50	13,939.51
	कुल	**1,61,323.88**	**41,561.31**

नोट 1: 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अन्य टिप्पणियां

आईआईएफसीएल भारत में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिवासित और निगमित एक सार्वजनिक कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 5वीं मंजिल, प्लेट ए और बी, ब्लॉक 2, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

आईआईएफसीएल की स्थापना व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। स्थापना के बाद से, आईआईएफसीएल विशेष प्रयोजन माध्यम के जरिए व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना, जिसे सामान्यतः एसआईएफटीआई के रूप में संदर्भित किया जाता है, द्वारा शासित था। भारत सरकार ने 15 अप्रैल 2026 के पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि एसआईएफटीआई अब आईआईएफसीएल या उसकी किसी भी सहायक कंपनी पर लागू नहीं है और कंपनी का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा नियामकीय ढांचे के अधीन परिचालन और वित्तीय निर्णय ले सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितंबर 2013 को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – गैर–जमा – अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी–एनडी–आईएफसी) के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र संख्या एन–14.03288 जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईआईएफसीएल को सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने की अनुमति दी है।

(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. तैयार करने का आधार

1.1 समेकित वित्तीय विवरणों में इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (मूल कंपनी) तथा इसकी सहायक कंपनियों इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड), आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एवं आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (सामूहिक रूप से "समूह") के 31 मार्च 2026 की स्थिति में तथा उसी तिथि को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरण सम्मिलित हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

i) कंपनी एवं इसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, दायित्वों, आय एवं व्ययों की समान मदों के बही मूल्यों को पंक्ति–दर–पंक्ति जोड़ते हुए समेकित किया गया है तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर इंड एएस 110 के अनुसार समूह के भीतर के लेन–देन से उत्पन्न अवास्तविक लाभ अथवा हानि को समायोजित/हटाने के पश्चात समेकन किया गया है।

ii) विदेशी सहायक कंपनी की मौद्रिक एवं अमौद्रिक, दोनों प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं का रूपांतरण समापन विनिमय दर पर किया गया है।

iii) विदेशी सहायक कंपनी की आय एवं व्यय मदों का अंतरण रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के मध्य लेन–देन की तिथि पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ विनिमय दर पर अंतरण किया गया है।

iv) इस प्रक्रिया से उत्पन्न समस्त विनिमय अंतर को विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित में संचित किया गया है।

1.2 **निम्नलिखित सहायक कंपनियों के पृथक वित्तीय विवरणों को समेकित वित्तीय विवरणों में समेकित किया गया है:**

सहायक कंपनियों का नाम	पंजीकरण का देश	वर्तमान अवधि	पिछली अवधि
		स्वामित्व हित का अनुपात (%)	स्वामित्व हित का अनुपात (%)
आईआईएफसीएल यूके लिमिटेड	यूनाइटेड किंगडम	100%	100%
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	भारत	100%	100%
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	भारत	100%	100%

1.3 पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी, अर्थात् आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड, के वित्तीय विवरणों को मूल कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु भारत में लागू सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुसार रूपांतरित किया गया है।

1.4 लेखांकन परिपाटीः आईआईएफसीएल अपने वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प् के खंड प्प् में गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए प्रदत्त प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करता है। वित्तीय विवरणों को प्रोद्भवन आधार एवं ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किया गया है, सिवाय इसके–

क. अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीओआईसी) पर वर्गीकृत वित्तीय परिसंपत्तियाँ,

ख. व्युत्पन्नी वित्तीय लिखत,

ग. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर नामित वित्तीय परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ,

घ. परिभाषित लाभ योजनाएँ – योजना परिसंपत्तियाँ उचित मूल्य पर मापी गईं।

उपरोक्त सभी मदों का मापन संबंधित इंड एएस के अनुसार, जहाँ आवश्यक अथवा अनुमत हो, उचित मूल्य पर किया गया है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए गए हैं तथा सभी आंकड़े, जहाँ अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निकटतम रुपये लाख तक पूर्णांकित की गई हैं।

1.5 **अनुमानों का उपयोगः** सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान एवं धारणाएँ करनी होती हैं, जो वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गई राशियों तथा उनके प्रकटीकरण, और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों एवं अनुमानों के मध्य अंतर को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें परिणाम वास्तविक रूप से प्रकट होते हैं।

आईआईएफसीएल द्वारा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के संबंध में कोई ऐसी धारणा नहीं की गई है तथा न ही अनुमान संबंधी अनिश्चितता के ऐसे प्रमुख स्रोत हैं, जिनसे आगामी वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वहन मूल्य में महत्वपूर्ण समायोजन होने का पर्याप्त जोखिम उत्पन्न हो।

2. अनुपालन का विवरण

आईआईएफसीएल के वित्तीय विवरण चालू अवधारणा के आधार पर तैयार किए गए हैं तथा कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अंतर्गत भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुरूप हैं, जैसा कि राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर 111(ई) दिनांक 16 फरवरी 2015, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर 365(ई) दिनांक 30 मार्च 2016, तथा भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा समय–समय पर जारी अन्य लागू विनियामक दिशानिर्देशों/निदेशों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को आम तौर पर तुलन पत्र में सकल मूल्य के रूप में रिपोर्ट किया जाता है। उन्हें केवल तभी ऑफसेट और निवल मूल्य के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, जब भावी घटना पर निर्भर हुए बिना मान्य राशियों को ऑफसेट करने के लिए बिना शर्त कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होने के अलावा, पक्षकार निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में निवल आधार पर निपटान करने का इरादा रखते हैं:

- सामान्य व्यवसाय कामकाज
- चूक की घटना
- आईआईएफसीएल और/या उसके समकक्षों के दिवालियापन या अशोधन क्षमता की घटना

मास्टर नेटिंग व्यवस्था (जैसे आईएसडीएएस) के साथ व्युत्पन्नी परिसंपत्तियों और देयताओं को केवल तभी निवल मूल्य पर प्रस्तुत किया जाता है जब वे उपर्युक्त सभी मानदंडों के लिए नेटिंग की पात्रता को पूरा करते हैं, न कि केवल चूक की स्थिति में।

4. आय/व्यय की मान्यता

4.1 परिशोधित लागत पर मापे गए सभी वित्तीय लिखतों, बिक्री हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत ब्याज–वहन करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों तथा एफवीटीपीएल के रूप में नामित वित्तीय लिखतों के लिए, ब्याज आय अथवा ब्याज व्यय को प्रभावी ब्याज

दर (ईआईआर) विधि के अनुसार मान्यता दी जाती है। इस गणना में वित्तीय लिखत की सभी अनुबंधात्मक शर्तों (जैसे अग्रिम भुगतान विकल्प) को ध्यान में रखा जाता है तथा ऐसे सभी शुल्क एवं अतिरिक्त लागतें शामिल की जाती हैं जो सीधे तौर पर लिखत से संबंधित हों और ईआईआर का अभिन्न अंग हों, परंतु भविष्य की ऋण हानियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। जब किसी वित्तीय परिसंपत्ति अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का वहन मूल्य ह्रास हानि के कारण कम किया जाता है, तब भी ब्याज आय को उसी ब्याज दर का उपयोग करते हुए मान्यता दी जाती है, जिसका उपयोग ह्रास हानि को मापने के लिए भविष्य के नकद प्रवाहों को छूट देने हेतु किया गया था।

4.2. स्वीकृत ऋणों पर प्राप्त अग्रिम शुल्क आय को, जहाँ ऋण दस्तावेज स्वीकृत राशि पर हस्ताक्षरित किए गए हों, उपार्जन आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

4.3. कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क को, ऋण समझौते के अनुसार, जब ऋण की आहरण राशि स्वीकृत ऋण राशि से कम हो, तब व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

4.4. उधारकर्ता के खातों में की गई वसूली को संबंधित ऋण समझौतों के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाता है।

4.5. बट्टे खाते में डाली गई ऋण परिसंपत्तियों से की गई वसूली को वसूली प्राप्त होने वाले वर्ष में आय के रूप में माना जाता है।

4.6. लाभांश को उपार्जन आधार पर लेखांकित किया जाता है, जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है। तथापि, अंतिम लाभांश प्राप्त करने का अधिकार केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा उसके अनुमोदन के पश्चात ही उत्पन्न होता है।

4.7. पूर्व अवधि से संबंधित आय/व्यय, जो कुल आय के 0.1% से अधिक नहीं है, को चालू वित्तीय वर्ष की आयध्व्यय के रूप में माना जाता है।

4.8. आंशिक ऋण संवर्धन गारंटी शुल्क को उस लेखा वर्ष में उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है, जब वसूली का युक्तिसंगत अधिकार स्थापित हो जाता है। अग्रिम रूप से प्राप्त किसी भी आंशिक ऋण संवर्धन गारंटी शुल्क को स्थगित किया जाता है तथा उपार्जन की अवधि के दौरान आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

4.9. अनर्जक परिसंपत्तियों (एनपीए) पर ब्याज/छूट अथवा किसी अन्य शुल्क सहित आय को केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब वह वास्तव में प्राप्त हो जाए। परिसंपत्ति के अनर्जक होने से पूर्व मान्यता प्राप्त तथा अभी तक अप्राप्त ऐसी किसी भी आय को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

4.10. आयकर रिफंड पर प्राप्त ब्याज को वास्तविक आधार पर लेखांकित किया जाता है, अर्थात् आयकर रिफंड प्राप्त होने वाले वर्ष में इसे आय के रूप में माना जाता है।

5. वित्तीय लिखतें:

5.1 मान्यता और प्रारंभिक मापन:

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं की प्रारंभिक मान्यता निपटान तिथि पर करती है। किसी वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है तथा यदि वह एफवीटीपीएल के अंतर्गत नहीं है, तो उसके अधिग्रहण अथवा निर्गम से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लेन–देन लागत को भी इसमें जोड़ा जाता है।

5.2 वर्गीकरण:

क. वित्तीय परिसंपत्तियां:

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समतुल्य, बैंक बैलेंस, सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के अलावा अन्य कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश, सहायक कंपनियों/कर्मचारियों को दिए गए ऋण, कर्मचारियों को अग्रिम राशि, प्रतिभूति जमा वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

प्रारंभिक मान्यता के समय, किसी वित्तीय परिसंपत्ति को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

क. परिशोधित लागत:

वित्तीय लिखतों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है, जहां:

- इनके अनुबंधात्मक प्रावधान ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करते हों जो निर्दिष्ट तिथियों पर केवल बकाया मूलधन तथा उस पर ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हों तथा

- इन्हें ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारण किया गया हो, जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकद प्रवाहों की वसूली के लिए धारण करना हो।

ऐसे लिखतों को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर, प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध लेन–देन लागत सहित मान्यता दी जाती है, जिनका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक हो। ऋण ह्रास का मापन, टिप्पणी 6.7 – वित्तीय परिसंपत्तियों का ह्रास में वर्णित तीन–स्तरीय अपेक्षित ऋण हानि मॉडल पर आधारित है।

ख. अन्य समग्र आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य

वित्तीय लिखतों को अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर तब मापा जाता है, जहाँ

- इनके अनुबंधात्मक प्रावधान ऐसे नकद प्रवाह उत्पन्न करते हों जो निर्दिष्ट तिथियों पर केवल बकाया मूलधन तथा उस पर ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हों तथा
- इन्हें ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत धारण किया गया हो, जिसका उद्देश्य अनुबंधात्मक नकद प्रवाहों की वसूली तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री, दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाना हो।

ऐसे लिखतों को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर, प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध लेन–देन लागत सहित, मान्यता दी जाती है तत्पश्चात इन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में परिवर्तन से उत्पन्न लाभ एवं हानियों को इक्विटी के एक पृथक घटक के अंतर्गत अन्य समग्र आय में शामिल किया जाता है। ह्रास हानियाँ अथवा उनका प्रत्यावर्तन, ब्याज आय तथा विदेशी मुद्रा से उत्पन्न लाभ एवं हानियाँ लाभ–हानि खाते में मान्यता प्राप्त करती हैं। निपटान के समय, अन्य समग्र आय में पूर्व में मान्यता प्राप्त संचयी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से आय विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।ऋण ह्रास का मापन परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू त्रि–स्तरीय अपेक्षित ऋण हानि मॉडल के आधार पर किया जाता है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्यः

- व्यापार के लिए धारित मदें;
- संविदात्मक शर्तों वाली ऋण लिखत जो केवल मूलधन और ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर धारित वित्तीय लिखतों को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा उनसे संबंधित लेन–देन लागतों को उत्पन्न होते ही आय विवरण में मान्यता दी जाती है। तत्पश्चात, इन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है और उससे उत्पन्न किसी भी लाभ अथवा हानि को उसी समय आय विवरण में मान्यता दी जाती है। जहाँ किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उचित मूल्य पर मापा जाता है, वहाँ प्रतिपक्ष की ऋण–योग्यता को प्रतिबिंबित करने हेतु एक ऋण मूल्यांकन समायोजन शामिल किया जाता है, जो ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में होने वाले परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है।

<u>व्यापार हेतु धारित वित्तीय लिखतें</u>

किसी वित्तीय लिखत को व्यापार हेतु धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यदि उसे मुख्यतः निकट भविष्य में बेचने या पुनर्खरीद करने के उद्देश्य से अधिग्रहित अथवा वहन किया गया हो, या वह ऐसे वित्तीय लिखतों के पोर्टफोलियो का हिस्सा हो जिन्हें एक साथ प्रबंधित किया जाता है और जिनके संबंध में अल्पकालिक लाभ अर्जन के साक्ष्य उपलब्ध हों, अथवा वह ऐसा व्युत्पन्नी लिखत हो जो किसी योग्य हेजिंग संबंध में न हो।

इसके अतिरिक्त, प्रारंभिक मान्यता के समय, आईआईएफसीएल किसी ऐसी वित्तीय परिसंपत्ति को, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीओसीआई पर मापने की आवश्यकताओं को पूरा करती हो, अपरिवर्तनीय रूप से एफवीटीपीएल के रूप में नामित कर सकता है, यदि ऐसा करने से उस लेखांकन विसंगति को समाप्त या पर्याप्त रूप से कम किया जा सके जो अन्यथा उत्पन्न होती।

घ इक्विटी लिखत

इक्विटी लिखतों में ऐसे निवेश, जिन्हें न तो व्यापार हेतु धारित किया गया हो और न ही वे ऐसे आकस्मिक प्रतिफल हों जिन्हें आईआईएफसीएल द्वारा ऐसे व्यवसाय संयोजन में मान्यता दी गई हो, जिस पर इंड एएस 103 – व्यवसाय संयोजन लागू होता है, उन्हें प्रबंधन द्वारा अपरिवर्तनीय विकल्प चुने जाने की स्थिति में अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। अन्य समग्र आय में प्रदर्शित राशियों को पश्चात् लाभ या हानि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। ऐसे निवेशों पर प्राप्त

लाभांश को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है, जब तक कि वह लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के किसी भाग की वसूली का प्रतिनिधित्व न करता हो।

अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को एफवीटीपीएलके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

तदंतर माप

ऐसी परिसंपत्तियाँ, जिन्हें अनुबंधात्मक नकद प्रवाहों की वसूली के उद्देश्य से धारित किया गया हो और जहाँ ये नकद प्रवाह केवल मूलधन तथा उस पर ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हों, परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। ऐसी ऋण निवेश परिसंपत्ति, जिसे परवर्ती रूप से परिशोधित लागत पर मापा गया हो, के निपटान अथवा ह्रास की स्थिति में उत्पन्न लाभ अथवा हानि को लाभ या हानि लेखा में मान्यता दी जाती है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर विधि के माध्यम से वित्तीय आय में शामिल किया जाता है, जिसका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक हो।

अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों को अन्य समग्र आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। तथापि, कंपनी ब्याज आय, ह्रास हानियाँ एवं उनका प्रत्यावर्तन, तथा विदेशी मुद्रा से उत्पन्न लाभ अथवा हानि को आय विवरण में मान्यता देती है।

<u>पुनर्वर्गीकरण</u>

वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता के पश्चात पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है, सिवाय उस अवधि के, जब आईआईएफसीएल वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु अपने व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन करता है।

ख. वित्तीय देयताएं

कंपनी की वित्तीय देयताएं ऐसे अनुबंधात्मक दायित्व हैं, जिनके अंतर्गत किसी अन्य इकाई को नकद या कोई अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्रदान करना अथवा किसी अन्य इकाई के साथ ऐसी शर्तों पर वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं का आदान–प्रदान करना शामिल है, जो कंपनी के लिए संभावित रूप से प्रतिकूल हों।

वर्गीकरण, प्रारंभिक मान्यता एवं मापन

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर, उनसे संबंधित तथा निर्गम से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध लेन–देन लागत घटाकर मान्यता दी जाती है, जिनका प्रभाव कुल आय के 0.5% से अधिक हो। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी भी छूट या प्रीमियम तथा उन शुल्कों या लागतों को ध्यान में रखकर की जाती है, जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का अभिन्न अंग हों। प्राप्तियों (लेन–देन लागत घटाकर) और मोचन राशि के बीच का अंतर उधार की अवधि के दौरान ईआईआर विधि का उपयोग करते हुए लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

तदंतर माप

प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) विधि का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। देयताओं के निपटान के समय तथा ईआईआरपरिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न लाभ एवं हानियों को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। ईआईआरपरिशोधन को लाभ–हानि विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

केवल मूलधन एवं ब्याज के भुगतान का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुबंधात्मक नकद प्रवाह की परिभाषाः

इस मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए, 'मूलधन' को प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ब्याज को धनराशि के समय मूल्य और किसी विशेष समय अवधि के दौरान बकाया मूल राशि से जुड़े ऋण जोखिम और अन्य बुनियादी उधार जोखिमों और लागतों (जैसे चलनिधि जोखिम और प्रशासनिक लागत) के साथ–साथ लाभ मार्जिन के लिए प्रतिफल के रूप में परिभाषित किया गया है।

ग. व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें:

व्युत्पन्नी वित्तीय लिखतें ऐसी संविदाएं हाती हैं, जिनका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित मूल्य, सूचकांक अथवा अन्य चर से व्युत्पन्न होता है, और सामान्यतः इनमें स्वैप, अग्रिम दर करार, वायदा तथा विकल्प जैसी लिखत शामिल होती हैं। आईआईएफसीएल, जहाँ लागू हो, विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों से संबंधित विनिमय दर में होने वाले उतार–चढ़ाव से उत्पन्न जोखिम को कम करने हेतु हेजिंग प्रकृति के व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों में प्रवेश करता है। ऐसे अनुबंधों को तुलन पत्र में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है तथा, जहाँ इन्हें प्रभावी हेज संबंध का भाग नामित नहीं किया गया हो, वहाँ इन्हें व्यापार हेतु वर्गीकृत किया जाता है; जबकि प्रभावी हेज संबंध का भाग नामित किए जाने की स्थिति में इन्हें हेजिंग व्युत्पन्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किसी व्युत्पन्नी लिखत का

वहन मूल्य अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान उचित मूल्य पर पुनरू मापा जाता है। उचित मूल्य सकारात्मक होने पर व्युत्पन्नी लिखतों को परिसंपत्ति के रूप में तथा उचित मूल्य नकारात्मक होने पर देयताओं के रूप में दर्शाया जाता है।

क. जहाँ भी कंपनी ने वायदा संविदा अथवा कोई लिखत में प्रवेश किया है जो वस्तुतः वायदा विदेशी मुद्रा संविदा की प्रकृति का है, वहाँ वायदा दर एवं वायदा विदेशी मुद्रा संविदा की तिथि पर विनिमय दर के मध्य अंतर को इंड एएस–21 के अनुसार संविदा की अवधि के दौरान आय अथवा व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख. विदेशी मुद्रा ऋणों पर लिए गए हेज को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों (अर्थात् प्राकृतिक हेज) के समायोजन के पश्चात एफआईएफओ आधार पर समायोजित किया जाता है।

ग. वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं के निरस्तीकरण अथवा नवीनीकरण, जिसमें ब्याज दर स्वैप भी सम्मिलित हैं, से उत्पन्न किसी भी लाभ अथवा हानि को संबंधित वर्ष की आय अथवा व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

घ. कंपनी द्वारा जापानी येन में किए गए ब्याज दर स्वैप लेन–देन के संबंध में, तुलप पत्र तिथि पर मार्क–टू–मार्केट हानि का प्रावधान किया जाता है।

ङ. वायदा अनुबंध के प्रारंभ पर स्पॉट विनिमय दर एवं अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण देयता की चुकौती के समय की स्पॉट विनिमय दर के अंतर के कारण उत्पन्न अधिशेष अथवा कमी, जो हेजिंग अनुबंध के अनुसार प्रतिपक्ष से प्राप्त अथवा उसे भुगतान की जाती है, को ऐसे ऋण की चुकौती के समय लाभ अथवा हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

च. विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेन–देन है) तथा उक्त ऋणों से उत्पन्न किसी भी हानि के विरुद्ध हेज करने हेतु किया गया स्वैप अनुबंध, दोनों को पृथक लेन–देन के रूप में माना जाता है।

छ. विदेशी मुद्रा उधारों का पुनर्मापन भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस–21), विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव के अनुसार किया जाता है।

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जून 2015 में जारी "व्युत्पन्नी संविदाओं के लेखांकन" संबंधी मार्गदर्शन नोट को कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से लागू किया गया है। रिपोर्टिंग तिथि पर, पिछली रिपोर्टिंग तिथि से तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उधार आहरण की तिथि से विदेशी मुद्रा उधार राशि पर विनिमय दर में हुए किसी भी परिवर्तन को व्युत्पन्नी संविदाओं के उचित मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाता है तथा उससे उत्पन्न किसी भी लाभ अथवा हानि को नकद प्रवाह हेज आरक्षित के रूप में मान्यता दी जाती है। व्युत्पन्नी संविदाओं का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

मार्गदर्शी टिप्पणी के अनुसार, नकद प्रवाह हेज के अंतर्गत हेजिंग लिखत को उचित मूल्य पर मापा जाता है, किंतु वह लाभ अथवा हानि जिसे प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित किया जाता है, उसे इक्विटी में (जैसे नकद प्रवाह हेज आरक्षित) मान्यता दी जाती है। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ–हानि विवरण में अस्थिरता से बचना है, जब हेज की गई मदों पर उत्पन्न लाभ अथवा हानियाँ उस अवधि में वास्तविक रूप से साकार नहीं होतीं।

5.3 विमान्यीकरण:

वित्तीय परिसंपत्तियां

आईआईएफसीएल किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब मान्यता से हटाता है, जब उस वित्तीय परिसंपत्ति से संबंधित अनुबंधात्मक नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, अथवा जब वह ऐसे लेन–देन में अनुबंधात्मक नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों का हस्तांतरण करता है, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित लगभग सभी जोखिम एवं प्रतिफल हस्तांतरित हो जाते हैं, या ऐसे लेन–देन में जिसमें आईआईएफसीएल न तो स्वामित्व से जुड़े लगभग सभी जोखिम एवं प्रतिफल हस्तांतरित करता है और न ही उन्हें बनाए रखता है तथा वह वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण भी बनाए नहीं रखता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऋण परिसंपत्तियों के मामले में:

क) जिन परियोजनाओं में परियोजना प्राधिकरण द्वारा रियायत समझौता (सीए) समाप्त कर दिया गया है, उन परियोजनाओं से संबंधित खाते को उस वित्तीय वर्ष में मान्यता से हटाया) जाता है, जिसमें अनुबंध समाप्त किया गया हो।

ख) जिन परियोजनाओं में रियायत समझौता (सीए) रियायतधारी द्वारा समाप्त किया गया है, उन मामलों में प्रकरण के गुण–दोष एवं तथ्यों के आधार पर ह्रास किया जाता है।

ग) जिन मामलों में परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों आदि से प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रस्ताव के आधार पर वित्तीय परिसंपत्ति का कोई निश्चित मूल्य आंका जा सकता है, वहाँ कमी की सीमा तक ह्रास किया जाता है।

घ) रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (एसडीआर), संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के सतत संरचनाकरण की योजना (एस4ए), अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियमों के अनुसार लागू बाह्य रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) योजना के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर–जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं. आरबीआई/131 डीबीआर सं. बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017–18 दिनांक 12 फरवरी 2018 के अनुसार वापस लिया गया माना गया है–या किसी अन्य पारस्परिक रूप से सहमत पुनर्गठन/समझौता प्रक्रिया के अंतर्गत न आने वाले मामलों में, यदि ऋण परिसंपत्ति को 5 वर्ष से अधिक अवधि तक अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, अथवा परियोजना के नियोजित वाणिज्यिक संचालन में 4 वर्ष से अधिक की देरी हुई हो, और जब तक ऋण परिसंपत्ति की बिक्री/प्राप्ति के लिए कोई ठोस प्रस्ताव उपलब्ध न हो, तब ऐसी ऋण परिसंपत्ति को मान्यता से हटाया जाता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त किए जाने पर, परिसंपत्ति के वहन मूल्य (या मान्यता समाप्त किए गए परिसंपत्ति के भाग को आवंटित वहन मूल्य) और (प) प्राप्त प्रतिफल (जिसमें प्राप्त कोई नई परिसंपत्ति, ग्रहण किए गए किसी नए दायित्व को घटाकर, शामिल है) तथा (पप) ओसीआई में पूर्व में मान्यता प्राप्त किसी भी संचयी लाभ अथवा हानि के योग के बीच का अंतर लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ओसीआई के माध्यम से एफवीओसीआई पर नामित इक्विटी निवेश प्रतिभूतियों के संबंध में ओसीआई में मान्यता प्राप्त किसी भी संचयी लाभ अथवा हानि को ऐसी प्रतिभूतियों की मान्यता समाप्ति पर लाभ–हानि विवरण में मान्यता नहीं दी जाती है। हस्तांतरित की गई वित्तीय परिसंपत्तियों में कंपनी द्वारा सृजित अथवा बनाए रखी गई ऐसी कोई भी रुचि, जो मान्यता समाप्ति के योग्य हो, को पृथक परिसंपत्ति अथवा दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय देयताएं

आईआईएफसीएल किसी वित्तीय दायित्व की मान्यता समाप्त तब करता है, जब उससे संबंधित अनुबंधात्मक दायित्वों का निर्वहन हो जाता है, उन्हें रद्द कर दिया जाता है अथवा वे समाप्त हो जाते हैं। जिस वित्तीय दायित्व को समाप्त किया गया हो अथवा किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित किया गया हो, उसके वहन मूल्य और चुकाए गए प्रतिफल (जिसमें हस्तांतरित कोई गैर–नकद परिसंपत्ति अथवा ग्रहण की गई देयताएं भी शामिल हैं) के बीच का अंतर लाभ–हानि विवरण में अन्य आय अथवा वित्तीय लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

मौजूदा उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच ऋण लिखतों का ऐसा विनिमय, जिसकी शर्तें पर्याप्त रूप से भिन्न हों, को मूल वित्तीय दायित्व की समाप्ति तथा एक नए वित्तीय दायित्व की मान्यता के रूप में लेखांकित किया जाएगा। इसी प्रकार, किसी मौजूदा वित्तीय देयता अथवा उसके किसी भाग की शर्तों में किया गया कोई महत्वपूर्ण संशोधन (चाहे वह देनदार की वित्तीय कठिनाई के कारण हो या न हो) को भी मूल वित्तीय देयता की समाप्ति तथा नए वित्तीय देयता की मान्यता के रूप में लेखांकित किया जाएगा।

5.4 संशोधन:

वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि किसी वित्तीय परिसंपत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाता है, तो कंपनी यह मूल्यांकन करती है कि संशोधित परिसंपत्ति से उत्पन्न नकद प्रवाह पर्याप्त रूप से भिन्न हैं या नहीं। यदि नकद प्रवाह पर्याप्त रूप से भिन्न हों, तो मूल वित्तीय परिसंपत्ति से संबंधित अनुबंधात्मक नकद प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त माने जाते हैं। ऐसे मामलों में, मूल वित्तीय परिसंपत्ति को मान्यता से हटाया जाता है तथा नई वित्तीय परिसंपत्ति को उसके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

यदि परिशोधित लागत पर वहन की गई संशोधित परिसंपत्ति के नकद प्रवाह पर्याप्त रूप से भिन्न नहीं होते हैं, तो ऐसे संशोधन के परिणामस्वरूप वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त नहीं की जाती है। ऐसे मामलों में, कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति के सकल वहन मूल्य की पुनर्गणना करती है तथा सकल वहन मूल्य में समायोजन से उत्पन्न राशि को लाभ–हानि विवरण में संशोधन लाभ अथवा हानि के रूप में मान्यता देती है। वित्तीय परिसंपत्ति का सकल वहन मूल्य पुनः वार्तित अथवा संशोधित अनुबंधात्मक नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के रूप में पुनर्गणना किया जाता है, जिसे वित्तीय परिसंपत्ति की मूल प्रभावी ब्याज दर (या खरीदी गई अथवा उत्पन्न की गई ऋण–ह्रासित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए ऋण–समायोजित प्रभावी ब्याज दर) अथवा, जहाँ लागू हो, संशोधित प्रभावी ब्याज दर पर छूटित किया जाता है। यदि ऐसा संशोधन उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाइयों के कारण किया गया हो, तो उससे उत्पन्न लाभ अथवा हानि को ह्रास हानियों के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अन्य मामलों में, इसे ब्याज आय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

5.5 उचित मूल्य मापन

वित्तीय लिखतों का एक महत्वपूर्ण भाग तुलन पत्र में उचित मूल्य पर वहन किया जाता है।

'उचित मूल्य' वह मूल्य है, जो मापन तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच सुव्यवस्थित लेन–देन में, कंपनी को उपलब्ध मुख्य बाजार में (या उसके अभाव में, सर्वाधिक लाभकारी बाजार में) किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त किया जा सकता है अथवा किसी देयता के हस्तांतरण हेतु भुगतान किया जाएगा। किसी देयता का उचित मूल्य उसके गैर–निष्पादन जोखिम को भी प्रतिबिंबित करता है।

जहाँ उपलब्ध हो, कंपनी किसी साधन के उचित मूल्य का मापन उस साधन के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य का उपयोग करके करती है। किसी बाजार को सक्रिय तब माना जाता है, जब परिसंपत्ति या दायित्व के लिए लेन–देन पर्याप्त आवृत्ति और मात्रा में होते हों, जिससे निरंतर आधार पर मूल्य निर्धारण संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सके।

यदि किसी सक्रिय बाजार में उद्धृत मूल्य उपलब्ध न हो, तो आईआईएफसीएल ऐसे मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो प्रासंगिक अवलोकनीय इनपुट्स के उपयोग को अधिकतम और अवलोकन–रहित इनपुट्स के उपयोग को न्यूनतम करती हों। चयनित मूल्यांकन तकनीक में वे सभी कारक सम्मिलित किए जाते हैं, जिन्हें बाजार प्रतिभागी किसी लेन–देन का मूल्य निर्धारित करते समय ध्यान में रखते हैं।

प्रारंभिक मान्यता के समय किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य सामान्यतः लेन–देन मूल्य होता है, अर्थात् दी गई या प्राप्त की गई प्रतिफल राशि का उचित मूल्य। यदि आईआईएफसीएल यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य, लेन–देन मूल्य से भिन्न है तथा यह उचित मूल्य न तो किसी सक्रिय बाजार में समान परिसंपत्ति या दायित्व के लिए उद्धृत मूल्य से सिद्ध होता है और न ही ऐसी मूल्यांकन तकनीक पर आधारित है, जिसमें कोई भी अवलोकन–रहित इनपुट मापन की दृष्टि से नगण्य हो, तो वित्तीय साधन को प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मापा जाता है तथा प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य और लेन–देन मूल्य के बीच के अंतर को स्थगित करने हेतु समायोजन किया जाता है। तत्पश्चात, उस अंतर को उपयुक्त आधार पर लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

मांग विशेषता वाले वित्तीय देयता (जैसे मांग जमा) का उचित मूल्य मांग पर देय राशि के बराबर होता है।

अनसूचीबद्ध इक्विटी निवेशों का उचित मूल्य, आईआईएफसीएल के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, निम्नलिखित पदानुक्रम में निर्धारित किया जाता है:

क. कंपनी के नवीनतम उपलब्ध वित्तीय विवरणों से निवेशित इकाई के विस्तृत मूल्य पर।

ख. यदि नवीनतम वित्तीय विवरण उपलब्ध न हो तो एक रुपए पर।

अवसंरचना ऋण निधियों और वैकल्पिक निवेश निधियों की इकाइयों का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध निवल आस्ति मूल्य के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूति रसीदों (एसआर) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निदेश – ऋण एक्सपोजर के अंतरण संबंधी निदेश, 2021 के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जिन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया है। 29 मार्च 2025 के संशोधन के परिणामस्वरूप, ऐसी प्रतिभूति रसीदों का समय–समय पर उस आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) द्वारा घोषित निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, जो उक्त लिखतों को दिए गए वसूली मूल्यांकनों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। तदनुसार, ऐसी एसआर की वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उपर्युक्त भा.रि.बैंक निदेशों के अनुपालन में संबंधित एआरसी द्वारा घोषित एनएवी के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

5.6 उचित मूल्य मापन के लिए मूल्यांकन तकनीकें

उचित मूल्यों की गणना किस प्रकार की गई है, यह दर्शाने के उद्देश्य से वित्तीय साधनों को मूल्यांकन तकनीकों के एक पदानुक्रम के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसका सारांश निम्नानुसार है:

- **स्तर 1 वित्तीय लिखत:** वे लिखत, जिनके मूल्यांकन में प्रयुक्त इनपुट मापन तिथि पर कंपनी को उपलब्ध सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं के लिए बिना किसी समायोजन के उद्धृत मूल्य होते हैं। कंपनी किसी बाजार को केवल तभी सक्रिय मानती है, जब समान परिसंपत्तियों अथवा दायित्वों के संबंध में पर्याप्त मात्रा एवं लिक्विडिटी के साथ व्यापारिक गतिविधियाँ उपलब्ध हों तथा बैलेंस शीट तिथि पर बाध्यकारी एवं प्रवर्तनीय मूल्य उद्धरण उपलब्ध हों।
- **स्तर 2 वित्तीय लिखत:** वे लिखत, जिनके मूल्यांकन में प्रयुक्त महत्वपूर्ण इनपुट ऐसे बाजार आँकड़ों से व्युत्पन्न होते हैं जो साधन के संपूर्ण जीवनकाल में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अवलोकनीय हों। ऐसे इनपुट्स में सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों अथवा दायित्वों के लिए उद्धृत मूल्य, निष्क्रिय बाजारों में समान साधनों के लिए उद्धृत मूल्य, तथा उद्धृत मूल्यों के अतिरिक्त अन्य अवलोकनीय इनपुट जैसे ब्याज दरें एवं यील्ड कर्व, निहित अस्थिरताएँ तथा क्रेडिट स्प्रेड शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, परिसंपत्ति की स्थिति या स्थान अथवा मूल्यांकित साधन से तुलनीय मदों से उसके संबंध की सीमा के लिए समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। तथापि, यदि ऐसे समायोजन अवलोकन–रहित इनपुट्स पर आधारित हों जो समग्र मापन के लिए महत्वपूर्ण हों, तो आईआईएफसीएल ऐसे साधनों को स्तर 3 के रूप में वर्गीकृत करेगा।

- **स्तर 3 के वित्तीय लिखत:** वे लिखत, जिनके मूल्यांकन में एक या अधिक ऐसे अवलोकन–रहित इनपुट सम्मिलित हों, जो समग्र मापन के लिए महत्वपूर्ण हों।

5.7 वित्तीय संपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

आईआईएफसीएल निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है, अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के मापन हेतु त्रि–स्तरीय दृष्टिकोण अपनाता है:

- परिशोधित लागत पर तथा अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण लिखत;
- ऋण प्रतिबद्धताएँ; तथा
- वित्तीय गारंटी अनुबंध।

इक्विटी निवेशों पर किसी भी प्रकार की अपेक्षित ऋण हानि मान्यता नहीं की जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता के पश्चात ऋण जोखिम में हुए परिवर्तन के आधार पर निम्नलिखित तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है:

चरण 1: 12 माह का ईसीएल

वे सभी जोखिम जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है तथा जो आरंभ से ही ऋण ह्रास नहीं हैं, उन्हें इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

चरण 2: आजीवन ईसीएल– ऋण–ह्रासित नहीं

वे सभी जोखिम जिनमें प्रारंभिक मान्यता के पश्चात ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, किंतु जो ऋण–ह्रासित नहीं हैं, इस चरण के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। 30 दिनों से अधिक बकाया को ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि माना जाता है।

चरण 3: आजीवन अपेक्षित ऋण हानि – ऋण–ह्रासित

वे सभी जोखिम, जिन्हें तब ऋण–ह्रासित आंका जाता है जब एक या अधिक ऐसी घटनाएँ घटित हो चुकी हों जिनका उस परिसंपत्ति के अनुमानित भावी नकद प्रवाहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, इस चरण में वर्गीकृत किए जाते हैं। जिन जोखिमों को ऋण–ह्रासित माना जाता है, उनके लिए आजीवन ईसीएल मान्यता दी जाती है तथा ब्याज आय की गणना सकल वहन मूल्य के बजाय परिशोधित लागत (प्रावधान घटाकर) पर प्रभावी ब्याज दर लागू करके की जाती है।

ऋण परिसंपत्तियों पर ईसीएल की गणना भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रावधान आवश्यकताओं के अनुरूप की जाएगी, जो निम्नानुसार है

i. मानक परिसंपत्तियाँ: वर्षांत पर बकाया ऋण राशि, जिसमें देय न हुई परंतु संचित ब्याज राशि भी शामिल है, पर 0.40% की दर से सामान्य प्रावधान किया जाता है।

ii. उप–मानक परिसंपत्तियाँ: कुल बकाया राशि पर 10 प्रतिशत की दर से सामान्य प्रावधान किया जाता है।

iii. संदिग्ध परिसंपत्तियाँ

(क) अग्रिम की वह राशि, जो उस प्रतिभूति के वसूल योग्य मूल्य से कवर नहीं है, जिस पर कंपनी का वैध प्रत्यावर्तन अधिकार है, उसके लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाता है।

(ख) उपर्युक्त मद (क) के अतिरिक्त, जिस अवधि तक परिसंपत्ति संदिग्ध बनी रही है, उसके आधार पर सुरक्षित भाग अर्थात् बकाया राशि के अनुमानित वसूल योग्य मूल्य के 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का प्रावधान निम्नानुसार किया जाता है:

अवधि जिसके लिए आस्ति को संदिग्ध माना गया है	प्रावधान का प्रतिशत
एक वर्ष तक	20
एक से तीन वर्ष	30
तीन वर्ष से अधिक	50

iv. हानि परिसंपत्तियाँ

सम्पूर्ण परिसंपत्ति को बट्टे खाते में दिया जाता है। तथापि, यदि किसी भी कारणवश परिसंपत्ति को खातों में बनाए रखने की अनुमति दी जाती है, तो बकाया संपूर्ण राशि पर 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाता है।

v. पुनगर्ठित ऋण परिसंपत्तियाँ

निम्नलिखित मामलों में, पुनगर्ठित मानक परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा, जिसमें उचित मूल्य में कमी (डिमिन्यूशन इन फेयर वैल्यू) पर प्रावधान भी शामिल है

(क) 24 जनवरी 2014 से प्रभावी रूप से पुनगर्ठित परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान 5% की दर से किया जाएगा।

(ख) 23 जनवरी 2014 को विद्यमान पुनगर्ठित बकाया ऋणों का स्टॉक (सभी कंपनियों के लिए) के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, प्रावधान 5% की दर से किया जाएगा।

वित्तीय परिसंपत्ति के वर्गीकरण हेतु चरण का निर्धारण

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता के पश्चात जोखिमों में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के आधार पर तीन चरणों में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण रिपोर्टिंग तिथि पर तथा प्रारंभिक मान्यता की तिथि पर अपेक्षित जीवनकाल के दौरान चूक होने के जोखिम की तुलना करके किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु कंपनी ऐसी युक्तिसंगत एवं समर्थनीय जानकारी पर विचार करती है, जो प्रासंगिक हो तथा बिना अत्यधिक लागत या प्रयास के उपलब्ध हो।

परिसंपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट आने पर कोई जोखिम चरण 1 से चरण 3 तक स्थानांतरित हो सकता है। यदि किसी बाद की अवधि में परिसंपत्ति की गुणवत्ता में सुधार होता है और पूर्व में आंकी गई ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि उलट जाती है, तो ऐसा जोखिम पुनः निम्न चरण में आ सकता है। 30 दिनों से कम बकाया वाले जोखिमों को चरण 1 में माना जाता है।

चरण 1 में मानी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान 12–माह अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) के आधार पर किया जाता है। जबकि चरण 2 एवं चरण 3 में मानी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान आजीवन अपेक्षित ऋण हानि मॉडल के आधार पर गणना किया जाता है। जब किसी परिसंपत्ति की वसूली संभव नहीं रहती, तो उसे संबंधित प्रावधान के विरुद्ध मान्यता से हटाया जाता है। ऐसे परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्ति सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने तथा हानि की राशि निर्धारित किए जाने के पश्चात की जाती है।

तथापि, यह एक प्रतिवाद योग्य धारणा है कि चूक 90 दिनों से अधिक बकाया होने से पहले नहीं होता है, जब तक कि इकाई के पास ऐसी युक्तिसंगत एवं समर्थनीय जानकारी उपलब्ध न हो, जो यह दर्शाती हो कि किसी विशेष वित्तीय साधन के लिए अधिक विलंबित चूक मानदंड अधिक उपयुक्त है। इन उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त चूक की परिभाषा सभी वित्तीय लिखतों पर समान रूप से लागू की जाती है, जब तक कि ऐसी जानकारी उपलब्ध न हो जाए जो यह दर्शाए कि किसी विशिष्ट वित्तीय लिखत के लिए कोई अन्य चूक परिभाषा अधिक उपयुक्त है।

तदनुसार, यदि निम्नलिखित में से कोई भी घटना घटित होती है, तो खाते को ऋण–ह्रासित माना जाएगा और उसे चरण 3 में स्थानांतरित कर दिया जाएगाः

- खाता 90 दिनों से अधिक बकाया हो;
- आईआईएफसीएल द्वारा ऋण दायित्व के संकटग्रस्त पुर्नसंरचनाकरण को सहमति दी गई हो, जहाँ मूलधन, ब्याज अथवा (जहाँ लागू हो) शुल्क की महत्वपूर्ण माफी अथवा स्थगन के कारण वित्तीय दायित्व में कमी होने की संभावना हो।

बकाया दिनों की गणना उस अवधि के आधार पर की जाती है, जितने दिनों तक ब्याज औरध्या मूलधन का भुगतान नहीं किया गया हो, कोई बिल अतिदेय बना रहा हो, कोई खाता निरंतर स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक बना रहा हो, अथवा खाते मेंउपलब्ध क्रेडिट राशि खाते पर लगाए गए ब्याज से कम हो।

निम्न ऋण जोखिम की अवधारणा

इंड एएस 101 "वित्तीय लिखत" के अनुसार,''अनुच्छेद 5.5.10 के प्रयोजनों के लिए किसी वित्तीय लिखत पर ऋण जोखिम को निम्न माना जाता है, यदि उस वित्तीय लिखत में चूक का जोखिम कम हो, उधारकर्ता के पास निकट अवधि में अपने अनुबंधात्मक नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की सुदृढ़ क्षमता हो, तथा दीर्घ अवधि में आर्थिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियों में प्रतिकूल परिवर्तन होने पर भी, आवश्यक नहीं कि उधारकर्ता की अपने अनुबंधात्मक नकद प्रवाह दायित्वों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हो (अनुच्छेद बी5.5.22)। इसके अतिरिक्त, यद्यपि इसमें 'निवेश–ग्रेड' की बाह्य रेटिंग को निम्न ऋण जोखिम का उदाहरण बताया गया है, तथापि यह भी स्वीकार किया गया है कि किसी वित्तीय साधन को निम्न ऋण जोखिम वाला माने जाने के लिए उसका बाह्य रूप से रेटेड होना अनिवार्य नहीं है (अनुच्छेद बी5.5.23)।

तदनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी वित्तीय लिखत को निम्न ऋण जोखिम वाला माना जाता है:

- शून्य अप्रत्याशित हानि जैसा कि शून्य विनियामक जोखिम भार द्वारा संकेतित जहाँ विनियामक जोखिम भार के अनुसार अनुमानित अप्रत्याशित हानि 0% होती है, वहाँ अपेक्षित हानि भी शून्य होगी। ऐसे मामलों में अपेक्षित ऋण हानि शून्य होगी। इस श्रेणी के परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण हैं–घरेलू संप्रभु तथा अंतरराष्ट्रीय रेटिंग "एए" या उससे बेहतर वाले विदेशी संप्रभुता
- निम्न अप्रत्याशित हानि जैसा कि 20% विनियामक जोखिम भार द्वारा संकेतितरू 20% जोखिम भार से संबंधित पोर्टफोलियो के लिए अप्रत्याशित हानि कम होती है, अतः अपेक्षित हानि भी अत्यंत कम होती है। तथापि, ईसीएल शून्य से भिन्न हो सकती है, अथवा अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शा सकते हैं कि ऐसे परिसंपत्ति वर्ग/पोर्टफोलियो के लिए चूक दर शून्य है। इस श्रेणी के परिसंपत्ति वर्गों के उदाहरण हैं जैसा कि अंतरराष्ट्रीय रेटिंग "ए" वाले विदेशी संप्रभु, घरेलू अनुसूचित आईआईएफसीएल (जो पूंजी पर्याप्तता की विनियामक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, उन्हें निम्न ऋण जोखिम वाला नहीं माना जाएगा), बाह्य रूप से रेटेड घरेलू "एएए" कॉरपोरेट्स तथा स्टाफ ऋण। इन पोर्टफोलियो के लिए प्रेक्षित चूक दरें भी शून्य पाई गई हैं।

इन विवरणों के प्रयोजनार्थ, सभी स्टाफ ऋणों को निम्न ऋण जोखिम वाला माना गया है।

पोर्टफोलियो में प्रयुक्त विभाजन का स्तर

विभाजन, जोखिम मापदंडों के अनुप्रयोग के उद्देश्य से आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) मॉडलों के अनुरूप किया गया है। तथापि, भविष्य उन्मुख आकलनों के लिए, आईआईएफसीएल कुछ उप–पोर्टफोलियो को व्यापक श्रेणियों में समूहित कर सकता है अथवा कुछ मामलों में सामान्य जोखिम कारकों के आधार पर उन्हें उप–खंडों में विभाजित कर सकता है।

ईसीएल का मापन

अपेक्षित ऋण हानियाँ निष्पक्ष तथा संभाव्यता–भारित अपेक्षित हानि के अनुमानों से व्युत्पन्न की जाती हैं और निम्नानुसार मापी जाती हैं

- रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण–ह्रासित न होने वाली वित्तीय परिसंपत्तियाँ वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल के दौरान होने वाली सभी नकद कमी के वर्तमान मूल्य के रूप में, जिसे प्रभावी ब्याज दर से छूटित किया जाता है। नकद कमी से आशय अनुबंध के अनुसार आईआईएफसीएल को देय नकद प्रवाह और आईआईएफसीएल द्वारा प्राप्त होने की अपेक्षित नकद प्रवाह के बीच का अंतर है।
- रिपोर्टिंग तिथि पर ऋण–ह्रासित वित्तीय परिसंपत्तियाँः सकल वहन मूल्य और प्रभावी ब्याज दर से छूटित अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के वर्तमान मूल्य के बीच के अंतर के रूप में।
- अप्रयुक्त ऋण प्रतिबद्धताएँः उस अंतर के वर्तमान मूल्य के रूप में, जो उस स्थिति में आईआईएफसीएल को देय अनुबंधात्मक नकद प्रवाह और आईआईएफसीएल द्वारा प्राप्त होने की अपेक्षित नकद प्रवाह के बीच होता है, यदि प्रतिबद्धता आहरित की जाती है।
- वित्तीय गारंटी अनुबंध धारक को प्रतिपूर्ति हेतु अपेक्षित भुगतानों से, आईआईएफसीएल द्वारा अपेक्षित वसूली योग्य राशियों को घटाने के पश्चात शेष राशि के रूप में।

अपेक्षित ऋण हानियाँ लाभ–हानि विवरण में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान खाते के माध्यम से मान्यता दी जाती हैं। अन्य समग्र आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण साधनों के मामले में, ईसीएल का मापन परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लागू त्रि–स्तरीय दृष्टिकोण के अनुसार किया जाता है। आईआईएफसीएल प्रावधान शुल्क को लाभ–हानि विवरण में मान्यता देता है तथा उसके समतुल्य राशि को अन्य समग्र आय में मान्यता देता है इस प्रक्रिया में तुलन पत्र में परिसंपत्ति के वहन मूल्य में कोई कमी नहीं की जाती है।

ह्रासित आरक्षित निधिः

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र आरबीआई/2019–20/170 दिनांक 13 मार्च 2020 के अनुसार, आईआईएफसीएल को इंड एएस के अंतर्गत अपेक्षित ह्रास भत्ते धारण करने होंगे। साथ ही, समानांतर रूप से आईआईएफसीएल आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान (आईआरएसीपी) से संबंधित प्रचलित सावधानीपूर्ण मानदंडों के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण बनाए रखेगा तथा उधारकर्ता/लाभार्थी–वार वर्गीकरण, मानक एवं पुनर्संरचित परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान, एनपीए की आयु–निर्धारण आदि सहित प्रावधानों की गणना करेगा।

जहाँ इंड एएस 109 के अंतर्गत निर्धारित ह्रास भत्ता, आईआरएसीपी के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) से कम हो, वहाँ आईआईएफसीएल को कर पश्चात निवल लाभ या हानि से उस अंतर की राशि एक पृथक 'ह्रास आरक्षित निधि' में अंतरण करना होगा। 'ह्रास आरक्षित निधि' में शेष राशि को विनियामक पूंजी के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना इस आरक्षित से किसी भी प्रकार की निकासी अनुमत नहीं होगी।

5.8 त्वरित प्रावधानीकरण

आईआईएफसीएल, एक विवेकपूर्ण ऋणदाता के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों/इंड एएस 109 के अनुसार अपेक्षित ऋण हानि की गणना के तहत परिसंपत्ति वर्गीकरण के आधार पर प्रतिभूतिकृत/अप्रतिभूतिकृत भागों पर निर्धारित प्रतिशत लागू करते हुए की जाने वाली सामान्य प्रावधान प्रक्रिया के अतिरिक्त, अपेक्षित वसूली परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण–दर–प्रकरण त्वरित प्रावधान पर भी विचार करता है।

ऐसे असाधारण मामलों में, जहाँ प्रचलित भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान पर्याप्त प्रतीत होता है, किंतु प्रबंधन के मत में ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हों जो वसूली की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती हों, वहाँ त्वरित प्रावधान का प्रस्ताव किया जाता है। ऐसे मामलों में, प्रबंधन विवेकपूर्ण उपाय के रूप में त्वरित प्रावधान पर प्रकरण–दर–प्रकरण निर्णय लेता है।

त्वरित प्रावधान मुख्यतः निम्नलिखित मानकों पर निर्भर करता है:

- परियोजना की स्थिति।
- प्रवर्तक की निधि प्रविष्ट करने की क्षमता।
- उपलब्ध मूर्त प्रतिभूति, नकद प्रवाह एवं रियायतें।
- वसूली हेतु संघ द्वारा उठाए गए कदम।
- प्रबंधन की धारणा।

उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, संबंधित खाते में किया जाने वाला प्रावधान 10% से 100% तक हो सकता है।

6. पट्टा

परिचालन पट्टे (ऑपरेटिंग लीज) के अंतर्गत देय पट्टा भुगतानों को पट्टा अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार (स्ट्रेट–लाइन बेसिस) पर लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

7. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को अधिग्रहण लागत पर दर्शाया जाता है, जिसमें दैनिक रखरखाव से संबंधित लागतें शामिल नहीं होती हैं, तथा उससे संचित मूल्यह्रास और मूल्य में संचित ह्रास घटाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों को निपटान के समय अथवा जब उनके उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता से हटाया जाता है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्ति पर उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि (जिसकी गणना निपटान से प्राप्त निवल आय और परिसंपत्ति के वहन मूल्य के अंतर के रूप में की जाती है) को परिसंपत्ति की मान्यता समाप्ति की तिथि पर लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

8. अमूर्त परिसंपत्तियाँ एवं विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

पृथक रूप से अर्जित अमूर्त परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता के समय उनकी लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत पर, संचित अमूर्तन तथा, यदि कोई हो, संचित ह्रास घटाकर दर्शाया जाता है।

पहले से पूंजीकृत अमूर्त परिसंपत्तियों पर किया गया पश्चातवर्ती व्यय तब पूंजीकृत किया जाता है, जब वह किसी विद्यमान परिसंपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों में वृद्धि करता हो, तथा ऐसे व्यय का अमूर्तन भावी आधार पर किया जाता है।

आंतरिक उपयोग हेतु अधिग्रहीत सॉफ्टवेयर की लागत (जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) और जिससे महत्वपूर्ण भविष्य के आर्थिक लाभ प्राप्त होने की अपेक्षा हो, को तब अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जब वह उपयोग हेतु तैयार हो जाए।

विकास पर किया गया व्यय, यदि इंड एएस 38 जैसा कि 'अमूर्त परिसंपत्तियाँ' के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है अन्यथा, ऐसे व्यय को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

किसी अमूर्त परिसंपत्ति को निपटान पर अथवा जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता से हटाया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता समाप्ति पर उत्पन्न लाभ या हानि को निपटान से प्राप्त शुद्ध आय और परिसंपत्ति के वहन मूल्य के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा परिसंपत्ति की मान्यता समाप्ति के समय लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

9. मूल्य ह्रास/परिशोधन

मूल्यह्रास की गणना संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की लागत पर उनके अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान अवशिष्ट मूल्य तक लिखित अवमूल्यन पद्धति के अनुसार की जाती है। उपयोगी जीवन का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार किया जाता है।

आईआईएफसीएल के कार्यालय परिसर का अमूर्तन 30 वर्षों की पट्टा अवधि के दौरान किया गया है।

परिशोधन की गणना अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन के दौरान अवशिष्ट मूल्य तक घटाने हेतु सीधी रेखा पद्धति के अनुसार की जाती है। पट्टे पर प्राप्त परिसंपत्ति के मामले में, अनुमानित उपयोगी जीवन की गणना पट्टा समाप्ति अवधि के आधार पर की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन सीमित अथवा असीमित के रूप में किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का अमूर्तन उनके उपयोगी आर्थिक जीवन के दौरान किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए अमूर्तन अवधि एवं अमूर्तन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कम–से–कम एक बार की जाती है। उपयोगी जीवन में अपेक्षित परिवर्तन अथवा परिसंपत्ति में निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की उपभोग की अपेक्षित प्रवृत्ति में परिवर्तन को, यथोचित रूप से अमूर्तन अवधि या पद्धति में परिवर्तन करके लेखांकित किया जाता है, जिन्हें लेखा अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों पर अमूर्तन व्यय को आय विवरण में एक पृथक मद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

अनुसूची III के अनुसार उपयोगी जीवन

परिसंपत्ति का विवरण	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	30 वर्ष	-
कंप्यूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग इकाइयाँ		
लैपटॉप/कंप्यूटर	3 वर्ष	5%
सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष	5%
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10 वर्ष	5%
वाहन	8 वर्ष	5%
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	5 वर्ष	5%

10. गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षतिग्रस्तता

आईआईएफसीएल प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करता है कि किसी गैर–वित्तीय परिसंपत्ति में ह्रास का कोई संकेत है या नहीं। इस आकलन के अनुसार निर्धारित ह्रास को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

11. लेटर ऑफ कंफर्ट (एलओसी)

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, आईआईएफसीएल बैंकों को आमतौर पर कंसोर्टियम सदस्यों के पक्ष में लाभार्थियों के हित में ऋणदाताओं की ओर से लेटर ऑफ क्रेडिट/वित्तीय गारंटी जारी किए जाने हेतु लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करता है। एलओसी को प्रारंभिक रूप से वित्तीय विवरणों में 'अन्य दायित्व' के अंतर्गत उचित मूल्य पर, अर्थात् प्राप्त प्रीमियम के बराबर, मान्यता दी जाती है। प्रारंभिक मान्यता के पश्चात, प्रत्येक गारंटी के अंतर्गत आईआईएफसीएल के दायित्व का मापन निम्नलिखित में से जो अधिक हो, उसके आधार पर किया जाता है जैसा कि प्रारंभिक रूप से मान्यता प्राप्त राशि, जिसमें से आय विवरण में मान्यता प्राप्त संचयी परिशोधन घटाया गया हो अथवा गारंटी के परिणामस्वरूप उत्पन्न किसी वित्तीय दायित्व के निपटान हेतु आवश्यक व्यय का सर्वोत्तम अनुमान। वित्तीय गारंटियों से संबंधित दायित्व में किसी भी वृद्धि को आय विवरण में ऋण हानि व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। प्राप्त प्रीमियम को गारंटी की अवधि के दौरान सीधी रेखा आधार पर आय विवरण में निवल शुल्क एवं कमीशन आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

12. प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधान तब मान्यता प्राप्त किए जाते हैं, जब आईआईएफसीएल पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक अथवा निहित) विद्यमान हो, उस दायित्व के निपटान हेतु आर्थिक लाभों से युक्त संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना हो, तथा दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सके। जहाँ धन के समय–मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण हो, वहाँ आईआईएफसीएल दायित्व–विशिष्ट वर्तमान दरों को प्रतिबिंबित करने वाली कर–पूर्व छूट दर पर अपेक्षित नकद प्रवाहों को छूटित कर प्रावधान का स्तर निर्धारित करता है। किसी भी प्रावधान से संबंधित व्यय को, किसी भी प्रतिपूर्ति को घटाकर, लाभ–हानि विवरण में अन्य परिचालन व्ययों के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

आकस्मिक देयता तब मान्यता एवं प्रकटीकरण किया जाता है, जबः

(क) किसी पूर्व घटना से उत्पन्न संभावित दायित्व हो, जिसका अस्तित्व समूह के नियंत्रण से बाहर किसी एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने अथवा न होने से पुष्ट होगा अथवा

(ख) किसी पूर्व घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व हो, जिसे इसलिए मान्यता नहीं दी गई हो क्योंकि उसके निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना नहीं है अथवा दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

जहाँ किसी संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व के संबंध में संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना अत्यंत दूरस्थ हो, वहाँ न तो कोई प्रावधान किया जाता है और न ही कोई प्रकटीकरण।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं की जाती हैं। तथापि, आकस्मिक परिसंपत्तियों का निरंतर आकलन किया जाता है और यदि यह लगभग सुनिश्चित हो जाए कि आर्थिक लाभों का अंतःप्रवाह होगा, तो जिस अवधि में यह परिवर्तन होता है, उसी अवधि में परिसंपत्ति तथा संबंधित आय को मान्यता दी जाती है।

प्रतिबद्धताएँ उन बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को सम्मिलित करती हैं, जिनके अंतर्गत किसी ग्राहक को ऋण प्रदान करने हेतु किए गए समझौतों के अनुसार ऋण विस्तार किया जाना है, बशर्ते कि अनुबंध में स्थापित किसी भी शर्त का उल्लंघन न हुआ हो।

13. आय पर कर

13.1 चालू कर

चालू कर परिसंपत्तियाँ एवं देयता, वर्तमान तथा पूर्ववर्ती वर्षों के लिए, उस राशि पर मापे जाते हैं, जिसके कर प्राधिकरणों से वसूल किए जाने अथवा उन्हें भुगतान किए जाने की अपेक्षा हो। इस राशि की गणना के लिए प्रयुक्त कर दरें एवं कर कानून वे होते हैं, जो रिपोर्टिंग तिथि तक भारत में, जहाँ आईआईएफसीएल संचालित होता है तथा करयोग्य आय अर्जित करता है, अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित हों।

इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित चालू आयकर को इक्विटी में ही मान्यता दी जाती है, न कि लाभ–हानि विवरण में। प्रबंधन समय–समय पर कर रिटर्न में लिए गए रुखों का मूल्यांकन करता है, विशेषकर उन परिस्थितियों में जहाँ लागू कर विनियमों की व्याख्या आवश्यक हो, तथा जहाँ उपयुक्त हो, वहाँ प्रावधान स्थापित करता है।

13.2 आस्थगित कर

आस्थगित कर को कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों एवं देयताओं के वहन मूल्यों और करयोग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त उनके संबंधित कर आधारों के बीच उत्पन्न अस्थायी अंतरों पर मान्यता दी जाती है तथा इसका लेखांकन तुलन पत्र देयता पद्धति के अनुसार किया जाता है।आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ सामान्यतः सभी कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों, अप्रयुक्त कर हानियों तथा अप्रयुक्त कर क्रेडिट के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त की जाती हैं, जहाँ यह संभाव्य हो कि भविष्य में पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिनके विरुद्ध ऐसे कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर, अप्रयुक्त कर हानियाँ एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिट समायोजित किए जा सकेंगे। आस्थगित कर परिसंपत्तियों के वहन मूल्य की प्रत्येक तुलन–पत्र तारीख को समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक कम कर दी जाती है, जिस सीमा तक यह संभावना नहीं रहती है कि पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके विरुद्ध अस्थायी अंतरों का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं देयता उन कर दरों पर मापे जाते हैं, जिनके उस अवधि में लागू होने की अपेक्षा हो, जिसमें दायित्व का निपटान किया जाएगा अथवा परिसंपत्ति को साकार किया जाएगा, और यह मापन उन कर दरों (तथा कर कानूनों) के आधार पर किया जाता है, जो तुलन पत्र तिथि तक अधिनियमित अथवा पर्याप्त रूप से अधिनियमित हों।

14. प्रति शेयर अर्जन

आईआईएफसीएल अपनी साधारण इक्विटी शेयरों के लिए मूल तथा परिशोधित प्रति शेयर आय (ईपीएस) का प्रस्तुतीकरण करता है। मूल ईपीएस की गणना, आईआईएफसीएल के इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य लाभ अथवा हानि को, अवधि के दौरान प्रचलित साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। परिशोधित ईपीएस का निर्धारण, इक्विटी शेयरधारकों को आरोप्य लाभ अथवा हानि तथा प्रचलित साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या को, सभी परिशोधनकारी संभावित साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित करके किया जाता है, जिनमें कर्मचारियों को प्रदान किए गए शेयर विकल्प शामिल हैं।

15. कर्मचारी हितलाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस लेखा अवधि में, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं, उनके बिना छूट वाली मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

15.2 कर्मचारियों के वेतन से कटौती किए गए भविष्य निधि अंशदान तथा उस पर नियोक्ता का अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा किया जाता है।

15.3 परिभाषित अंशदान योजनाओं के अंतर्गत एनपीएस से संबंधित कर्मचारी लाभों को योजना में योगदान हेतु कंपनी के छूट रहित दायित्व के आधार पर मान्यता दी जाती है। यह अंशदान आईडीबीआई बैंक, जो एनपीएस सुविधा के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) सेवा प्रदाता है, को भुगतान किया जाता है तथा संबंधित अवधि के लिए व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता है।

15.4 सेवा–उपरांत तथा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवाएँ प्रदान की गई हों। यह व्यय देय राशियों के वर्तमान मूल्य पर, बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित किया जाता है।

15.5 सेवांत लाभ को तत्काल व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

15.6 बीमांकिक मूल्यांकन से उत्पन्न लाभ अथवा हानि को, जिस अवधि में वे घटित होती हैं, उसी अवधि में अन्य समग्र आय में मान्यता दी जाती है।

15.7 कर्मचारी लाभ दायित्वों, यथा बीमारी अवकाश, अवकाश यात्रा रियायत तथा चिकित्सा सहायता योजना के लिए, रिपोर्टिंग तिथि तक की अवधि हेतु बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया गया है।

15.8 ग्रेच्युटी का प्रावधान, एलआईसी की समूह ग्रेच्युटी योजना के अंतर्गत आईआईएफसीएल एम्प्लॉइज ग्रुप ग्रेच्युटी फंड (ट्रस्ट) के माध्यम से एलआईसी को देय राशि के आधार पर किया गया है।

15.9 अवकाश नकदीकरण का प्रावधान एलआईसी की समूह अवकाश नकदीकरण योजना के अंतर्गत देय राशि के आधार पर किया गया है।

15.10 जहाँ नियुक्ति की शर्तों के अनुसार लागू हो, वहाँ कार्यकारी निदेशकों के लिए अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी तथा बीमारी अवकाश के प्रावधान का उपार्जन अनुमानित देयता की राशि के आधार पर किया गया है।

16. महत्वपूर्ण लेखांकन अवधारणाएं एवं अनुमान

आईआईएफसीएल की लेखा नीतियों के अनुप्रयोग में निर्णय, अनुमान एवं धारणाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। यदि भिन्न धारणाएँ अथवा अनुमान अपनाए जाते, तो परिणामी मूल्य भिन्न होते, जिससे आईआईएफसीएल की निवल परिसंपत्तियों एवं आय पर प्रभाव पड़ता। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की गई धारणाएँ उस तिथि पर उपलब्ध सर्वोत्तम अनुमानों पर आधारित होती हैं। यद्यपि आईआईएफसीएल के पास ऐसे आंतरिक नियंत्रण तंत्र विद्यमान हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि अनुमानों का मापन विश्वसनीय रूप से किया जाए, तथापि वास्तविक राशियाँ इन अनुमानों से भिन्न हो सकती हैं। अनुमानों एवं अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमानों में किए गए संशोधनों को उस अवधि में तथा उन भविष्य की अवधियों में मान्यता दी जाती है, जिन पर ऐसे संशोधनों का प्रभाव पड़ता है। वे लेखा नीतियाँ, जो निर्णय, अनुमान एवं धारणाओं के उपयोग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं, निम्नानुसार निर्दिष्ट की गई हैं।

- **उचित मूल्य मापन**

  वित्तीय लिखतों का एक महत्वपूर्ण भाग तुलन पत्र में उचित मूल्य पर वहन किया जाता है। उचित मूल्य वह मूल्य है, जो मापन तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच सुव्यवस्थित लेन–देन में किसी परिसंपत्ति की बिक्री पर प्राप्त किया जाएगा अथवा किसी दायित्व के हस्तांतरण हेतु भुगतान किया जाएगा। जहाँ किसी वित्तीय परिसंपत्ति या देयता का वर्गीकरण उसे उचित मूल्य पर

मापे जाने का परिणाम देता है, वहाँ यथासंभव उचित मूल्य का निर्धारण उस सर्वाधिक लाभकारी सक्रिय बाजार में उद्धृत बोली या प्रस्ताव मूल्य के संदर्भ से किया जाता है, जिस तक आईआईएफसीएल की तत्काल पहुँच हो। आवश्यकतानुसार, उचित मूल्य में ऋण जोखिम के लिए समायोजन भी सम्मिलित किया जाता है। किसी सक्रिय बाजार में उद्धृत शुद्ध खुली स्थिति, जो एक वित्तीय देयता हो, के लिए उचित मूल्य वर्तमान प्रस्ताव मूल्य तथा किसी वित्तीय परिसंपत्ति के लिए बोली मूल्य होता है, जिसे धारित अथवा निर्गत साधन की इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है। जहाँ किसी विशेष परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाजार उपलब्ध न हो, वहाँ आईआईएफसीएल उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु मूल्यांकनतकनीकों का उपयोग करता है, जिनमें हाल के स्वतंत्र लेन–देन से प्राप्त लेन–देन मूल्य, छूटित नकद प्रवाह विश्लेषण, विकल्प मूल्य निर्धारण मॉडल तथा अन्य मूल्यांकन तकनीकें शामिल हैं, जो रिपोर्टिंग तिथि पर विद्यमान बाजार परिस्थितियों एवं जोखिमों पर आधारित होती हैं। इस प्रक्रिया में, उचित मूल्य का अनुमान ऐसी मूल्यांकन तकनीक के माध्यम से किया जाता है, जिसमें अवलोकनीय बाजार इनपुट्स काअधिकतम उपयोग तथा इकाई–विशिष्ट इनपुट्स पर न्यूनतम निर्भरता हो। प्रारंभिक मान्यता के समय किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य सामान्यतः लेन–देन मूल्य (अर्थात् दी गई या प्राप्त की गई प्रतिफल राशि का उचित मूल्य) होता है, जब तक कि उस साधन का उचित मूल्य उसी साधन में अन्य अवलोकनीय वर्तमान बाजार लेन–देन से तुलना द्वारा (बिना किसी संशोधन या पुनर्पैकेजिंग के) सिद्ध न हो, अथवा ऐसी मूल्यांकन तकनीक पर आधारित न हो, जिसके चर केवल अवलोकनीय बाजारों के आंकड़ों को सम्मिलित करते हों। जब ऐसा साक्ष्य उपलब्ध होता है, तब आईआईएफसीएल प्रारंभिक मान्यता (अर्थात् प्रथम दिन) पर लेन–देन मूल्य और उचित मूल्य के बीच के अंतर को लाभ–हानि विवरण में मान्यता देता है।

- **ऋणों एवं अग्रिमों पर मूल्य ह्रास शुल्क**

  ऋणों एवं अग्रिमों के लिए ह्रास हानि का निर्धारण करते समय भावी नकद प्रवाहों की राशि एवं समय–निर्धारण के आकलन में प्रबंधन द्वारा निर्णय (जजमेंट) की आवश्यकता होती है। इन नकद प्रवाहों के अनुमान में आईआईएफसीएल उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति तथा प्रतिभूति के शुद्ध वसूल योग्य मूल्य के संबंध में निर्णय करता है। ये अनुमान अनेक कारकों के संबंध में की गई धारणाओं पर आधारित होते हैं तथा वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में क्षतिग्रस्तता भत्ते में परिवर्तन हो सकता है। ह्रास का सामूहिक आकलन ऋण पोर्टफोलियो से संबंधित आंकड़ों (जैसे ऋण गुणवत्ता, बकाया स्तर, ऋण उपयोग, ऋण–से–प्रतिभूति अनुपात आदि), जोखिम संकेन्द्रण तथा आर्थिक आंकड़ों (जिसमें बेरोजगारी स्तर, अचल संपत्ति मूल्य सूचकांक, देश जोखिम एवं विभिन्न व्यक्तिगत समूहों का प्रदर्शन शामिल है) को ध्यान में रखकर किया जाता है।

- **ऋण क्षतिग्रस्तता के अतिरिक्त अन्य प्रावधान**

  कर्मचारी देयताओं, पुनर्संरचना लागतों तथा वाद–विवाद संबंधी प्रावधानों जैसी विभिन्न भावी देयताओं के संबंध में प्रावधान बनाए जाते हैं। कुछ प्रावधानों में विभिन्न घटनाओं के संभावित परिणामों तथा अनुमानित भावी नकद प्रवाहों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। इन प्रावधानों का मापन लेन–देन के अंतिम परिणामों के संबंध में प्रबंधन के निर्णयों के प्रयोग को सम्मिलित करता है। जिन भुगतानों के एक वर्ष से अधिक समय बाद होने की अपेक्षा है, उन्हें ऐसी छूट दर पर छूटित किया जाता है, जो वर्तमान ब्याज दरों तथा उस प्रावधान से संबंधित विशिष्ट जोखिमों, दोनों को प्रतिबिंबित करती हो।

- **ऋण एवं अग्रिम**

  ऋण एवं अग्रिमों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर, प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अतिरिक्त लेन–देन लागत सहित किया जाता है, तथा तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए इन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

17. उधार और ऋण प्रतिभूतियां

उधार एवं निर्गत ऋण प्रतिभूतियों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर, उनसे संबंधित अतिरिक्त प्रत्यक्ष लेन–देन लागत घटाकर किया जाता है तथा तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करते हुए इन्हें परिशोधित लागत पर मापा जाता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ समूह द्वारा देयताओं को एफवीटीपीएल पर नामित किया गया हो।

18. उधार लागत

विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों पर उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ–हानि विवरण में आरोपित किया जाता है। विनिमय अंतर की वह राशि, जो स्थानीय मुद्रा में लिए गए उधारों पर ब्याज और विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों पर ब्याज के अंतर से अधिक नहीं होती है, को उधार लागत माना जाता है तथा इंड एएस 23 – उधार लागत के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है। शेष विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को इंड एएस 21 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है।

इस प्रयोजन हेतु, स्थानीय मुद्रा में लिए गए उधारों की ब्याज दर के रूप में कंपनी द्वारा लिए गए बैंक ओवरड्राफ्ट की ब्याज दर को माना जाता है।

19. सहायक कंपनी में निवेश

सहायक कंपनी वह इकाई होती है, जिस पर कंपनी का नियंत्रण होता है। नियंत्रण तब माना जाता है, जब कंपनी के पास उस इकाई पर शक्ति हो, वह उस इकाई के साथ अपने संलग्नता से परिवर्तनीय प्रतिफलों के प्रति अनावृत्त हो अथवा उन पर अधिकार रखती हो, तथा अपनी उस शक्ति का उपयोग कर उन प्रतिफलों को प्रभावित करने की क्षमता रखती हो।

शक्ति का प्रदर्शन उन विद्यमान अधिकारों के माध्यम से होता है, जो प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की क्षमता प्रदान करते हैं, अर्थात् वे गतिविधियाँ जो इकाई के प्रतिफलों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

सहायक कंपनियों में निवेशों को लागत पर वहन किया जाता है। इस लागत में निवेश प्राप्त करने हेतु चुकाई गई कीमत तथा उससे सीधे संबंधित व्यय शामिल होते हैं।

इंड एएस में संक्रमण की तिथि पर, कंपनी ने पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार सहायक कंपनियों में निवेश के वहन मूल्य को इंड एएस 101 के अंतर्गत अनुमानित लागत के रूप में माना है।

20. विदेशी मुद्रा लेन–देन

20.1 विदेशी मुद्रा में होने वाले व्यय एवं आय को, लेन–देन की तिथि पर बैंकों द्वारा प्रचलित विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है।

20.2 निम्नलिखित शेष राशियों को खातों के समापन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों (आरबीआई संदर्भ दरों) पर भारतीय मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है:

(क) स्वीकृत विदेशी मुद्रा ऋणों एवं विदेशी मुद्रा उधारों पर क्रमशः उपार्जित किन्तु देय न हुई आय या व्यय।

(ख) विदेशी मुद्रा में जारी किए गए लेटर ऑफ कम्फर्ट से संबंधित आकस्मिक देयता

20.3 विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व को रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित आरबीआई संदर्भ दर पर भारतीय मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है। उत्पन्न विनिमय अंतर को लेखा मानक 11 – विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव के अनुसार लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

20.4 विदेशी मुद्रा ऋण परिसंपत्तियों, दायित्वों तथा उपार्जित/उपार्जित किन्तु देय न हुई आय एवं व्यय पर वास्तविक/संपरिवर्तन लाभ या हानि को लाभ–हानि विवरण में जमा/प्रभारित किया जाता है।

21. व्युत्पन्नी लिखतों का का लेखांकन

21.1 जहाँ भी कंपनी ने वायदा संविदा या ऐसा लिखत, जो सारतः वायदा विनिमय संविदा की प्रकृति का है, किया है, वहां वायदा दर और वायदा विनिमय संविदा की तारीख की विनिमय दर के बीच के अंतर को भारतीय लेखांकन मानक–21 के अनुसार संविदा की अवधि के दौरान आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

21.2 विदेशी मुद्रा ऋणों पर लिए गए हेज को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋणों (अर्थात् प्राकृतिक हेज) के समायोजन के बाद प्रथम आगत, प्रथम निर्गत आधार पर समायोजित किया जाता है।

21.3 ब्याज दर स्वैप सहित फॉरवर्ड विनिमय करारों को रद्द करने या उनका नवीनीकरण करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को वर्ष की आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

21.4 कंपनी द्वारा किए गए जापानी येन में ब्याज दर स्वैप लेन–देन के संबंध में, कंपनी तुलन–पत्र की तारीख को बाजार मूल्यांकन हानि का प्रावधान करती है।

21.5 फॉरवर्ड करार के आरंभ के समय की हाजिर विनिमय दर और अंतर्निहित विदेशी मुद्रा ऋण दायित्व के पुनर्भुगतान के समय की हाजिर विनिमय दर के बीच अंतर के कारण होने वाले अधिशेष या घाटे को, हेजिंग करार के अनुसार प्रतिपक्ष से वसूल की गई या प्रतिपक्ष को भुगतान की गई राशि के रूप में, ऐसे ऋण के पुनर्भुगतान के समय लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

21.6 विदेशी मुद्रा ऋण (जो एक अंतर्निहित लेन–देन है) और स्वैप करार (उपर्युक्त ऋणों से उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि से बचाव के लिए) को अलग–अलग लेन–देन माना जाता है।

21.7 विदेशी मुद्रा में उधारी को भारतीय लेखांकन मानक 21, विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार पुनः अभिव्यक्त किया जाता है।

आईसीएआई द्वारा जून 2015 में जारी "व्युत्पन्नी संविदाओं के लेखांकन" संबंधी मार्गदर्शन टिप्पणी 1 अप्रैल 2016 से लागू है तथा कंपनी द्वारा इसे 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से अपनाया गया है। रिपोर्टिंग तिथि पर, पिछली रिपोर्टिंग तिथि से तथा अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा उधार की निकासी की तिथि से, विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में होने वाले किसी भी परिवर्तन को व्युत्पन्नी संविदाओं के उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है तथा उत्पन्न कोई भी लाभ या हानि कैश फ्लो हेज रिजर्व के रूप में मान्यता दी जाती है। व्युत्पन्नी संविदाओं का उचित मूल्य संबंधित प्रतिपक्षों द्वारा प्रदान किया जाता है।

उक्त मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार, कैश फ्लो हेज के अंतर्गत हेजिंग साधन को उचित मूल्य पर मापा जाता है, परंतु जो लाभ या हानि एक प्रभावी हेज के रूप में निर्धारित होती है, उसे इक्विटी में, अर्थात् कैश फ्लो हेज रिजर्व में मान्यता दी जाती है। इसका उद्देश्य उस अवधि में लाभ–हानि विवरण में अस्थिरता से बचना है, जब हेज किए गए मदों पर लाभ या हानि अभी साकार नहीं हुई होती।

22. राजस्व अनुदान के लिए लेखांकन

22.1 अनुदानों को लाभ–हानि विवरण में 'अन्य आय' के रूप में, उन अवधियों में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित लागतें वहन की जाती हैं, जिनकी प्रतिपूर्ति हेतु ये अनुदान अभिप्रेत हों, बशर्ते कि अनुदान स्वीकृति से संबद्ध शर्तों के अनुपालन तथा अनुदान राशि की प्राप्ति के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध हो।

22.2 पूर्ववर्ती अवधियों में पहले से किए गए व्यय के संबंध में प्राप्त अनुदानों को, अनुदान की स्वीकृति के वर्ष में लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

22.3 वर्ष के अंत में अनुदान की कोई भी अप्रयुक्त राशि, यदि हो, तो उसे चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाहों का विवरण अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंतर्गत कर–पूर्व लाभ को गैर–नकदी प्रकृति के लेन–देन के प्रभावों तथा पूर्ववर्ती या भावी नकदी प्राप्तियों अथवा भुगतानों से संबंधित किसी भी स्थगन या उपार्जन के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी की परिचालन, निवेश तथा वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न नकद प्रवाहों को अलग–अलग दर्शाया जाता है।

(ख) समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित अन्य टिप्पणियाँ

1. (क) समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु निम्नलिखित सहायक कंपनियों को सम्मिलित किया गया है: इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यू.के.) लिमिटेड, यूनाइटेड किंगडम में निगमित; आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, भारत में निगमितय तथा आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, भारत में निगमित।

(ख) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए हैं। सभी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण भी उसी अवधि, अर्थात 31 मार्च 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए हैं।

2. **पूर्व अवधि की आय एवं व्यय (भारतीय लेखा मानक–8), जिन्हें लाभ–हानि विवरण में नियमित मदों के अंतर्गत शामिल किया गया है, का विवरण निम्नानुसार है:**

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
आय		
ऋण एवं अग्रिमों पर आय	-	-
दंडात्मक ब्याज	-	-
अन्य शुल्क	-	-
कुल (क)	**-**	**-**
व्यय		
स्थापना एवं अन्य व्यय	-	-
वेतन एवं मजदूरी	-	-
कुल (ख)	**-**	**-**
चालू वर्ष के लाभ पर लाभ/(हानि) के माध्यम से शुद्ध प्रभाव [(क)–(ख)]	-	-

3. लेखांकन नीतियों में परिवर्तन:

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

4. भारतीय लेखांकन मानक 19 कर्मचारी हितलाभ (इंड एएस–19) के अंतर्गत प्रकटीकरण

भारतीय लेखांकन मानक 19 कर्मचारी हितलाभश के अनुसार, लेखांकन मानक में परिभाषित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:–

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड:

क) ग्रेच्युटी योजना (वित्तपोषित): ग्रेच्युटी देयता भावी भुगतानों के कारण उत्पन्न होती है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा में मृत्यु या वापसी की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। इसका प्रावधान आईआईएफसीएल कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी फंड के नाम पर ट्रस्ट के माध्यम से समूह ग्रेच्युटी योजना पर एलआईसी को देय राशि के आधार पर किया गया है। आईआईएफसीएल एलआईसी समूह ग्रेच्युटी योजना के तहत कर्मचारियों की ग्रेच्युटी देयता की राशि का भुगतान करता है। वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार ग्रेच्युटी देयता के बीमांकित मूल्यांकन की राशि का पता नहीं लगाया जा सका है।

I. उपदान योजना के लिए धारणा:

	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर आहरण दर	1% से 3% अवधि के आधार पर	1% से 3% अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.78%	6.99%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50%

II. परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण।

(₹ लाख में)

(क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	597.98
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(31.42)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	34.11
(ख) अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य		597.98
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	8.17
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(7.56)

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

आईआरडीए परिपत्र संख्या आईआरडीए/एसीटीएल/आरईजी/सीआईआर/123/06/2013 दिनांक 28 जून 2013 के अनुसार, मौजूदा पॉलिसी में कोई नया सदस्य नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए, आईआईएफसीएल ने नई पॉलिसी अर्थात पॉलिसी संख्या 331776 के अलावा नए कर्मचारियों के लिए पॉलिसी संख्या 103001183 का सब्सक्रिप्शन लिया।

(₹ लाख में)

क्र. स.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	597.98	629.93
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	735.67	645.85
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध आस्ति/(देयता)	137.69	15.92
	योजना आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	645.85	599.81
ख)	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	51.69	46.04
ग)	मृत्यु दर	-	-
घ)	नियोक्ता योगदान	78.13	-
ङ)	भुगतान किए गए लाभ	(40.00)	-
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	735.67	645.85
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	629.93	545.43
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	44.03	39.38
घ)	सेवा लागत	45.09	52.32
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	(40.00)	-
छ)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	(81.07)	(7.21)
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	597.98	629.93

क्र. स.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(15.92)	(54.37)
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	45.09	52.32
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	(1.11)	(3.93)
ङ)	पुनः मापन	(87.62)	(9.93)
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	(78.13)	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(137.69)	(15.92)
	विभाजित बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(54.05)	15.75
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(27.02)	(22.95)

क **अर्जित अवकाश देयता:** कर्मचारी को देय अर्जित अवकाश की गणना उस अवधि के आधार पर की जाती है, जिसे कर्मचारी ने अर्जित किया है, उसमें से कर्मचारी द्वारा वास्तव में लिए गए अवकाश की अवधि घटा दी जाती है। अर्जित अवकाश ड्यूटी की अवधि के प्रत्येक ग्यारहवें भाग के बराबर अर्जित होता है। आईआईएफसीएल ने भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" की आवश्यकताओं के अनुसार बीमांकिक आधार पर निर्धारित निवल परिभाषित लाभ स्थिति को, वसूली योग्य सीमा तक तथा इंड एएस 19 के परिसंपत्ति सीमा संबंधी प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत सीमा तक, मान्यता प्रदान की है।

अवकाश नकदीकरण योजना के लिए धारणाएं:

विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर आहरण दर	1% से 3% अवधि के आधार पर	1% से 3% अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.78%	6.99%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50 %

II. **परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता का विश्लेषण**

(₹ लाख में)

(क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,217.69
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(67.95)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	72.01
(ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,217.69
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	73.94
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(68.73)

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं और इसलिए इनके कारण होने वाले परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

क्र. स.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,217.69	1,247.39
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2,195.09	1,767.44
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध आस्ति/(देयता)	977.40	520.04
	योजना आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	1,767.44	1,182.39
ख)	योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	149.84	118.48
ग)	मृत्यु दर	-	-
घ)	नियोक्ता योगदान	445.74	466.57
ङ)	भुगतान किए गए लाभ	(167.92)	-
च)	अवधि के अंत में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	2,195.09	1,767.44
	लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,247.39	980.39
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	87.19	70.78
घ)	सेवा लागत	128.66	129.42
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	(167.92)	-
छ)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	(77.64)	66.80
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,217.69	1,247.39
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(520.04)	(202.00)
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	128.66	129.42
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	(36.35)	(14.58)
ङ)	पुनः मापन	(103.94)	33.69
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	(445.74)	(466.57)
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(977.40)	(520.04)
	विभाजित बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(117.28)	32.06
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	39.64	34.74

III. अन्य कर्मचारी हितलाभ (अवित्तपोषित)

अन्य कर्मचारी हितलाभों (अनधिकृत) के लिए बीमांकिक अवधारणाएं

ख) छुट्टी किराया रियायत: कंपनी के सभी पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने यात्रा की तारीख पर निरंतर अस्थायी सेवा सहित एक वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वे इस सुविधा के लिए पात्र हैं। यह रियायत दो वर्षों के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार स्वीकार्य होगी और ऐसे सेटब्लॉक का पहला भाग उस महीने की पहली तारीख से शुरू होगा जिसमें कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल होता है, लेकिन इसका लाभ केवल अस्थायी सेवा/परिवीक्षा अवधि सहित एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद ही उठाया जा सकता है।

अवकाश किराया रियायत के लिए धारणाएं:

	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर आहरण दर	1% से 3% अवधि के आधार पर	1% से 3% अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.78%	6.99%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण। अवकाश किराया रियायत के लिए मान्यताएँ:

(₹ लाख में)

(क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	133.00
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(5.51)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	5.57

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, इसलिए परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलताएं लागू नहीं होती हैं।

(₹ लाख में)

क्र. स.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	133.00	125.53
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध आस्ति/(देयता)	(133.00)	(125.53)
	योजना आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	125.53	105.73
ख)	ब्याज लागत	-	7.63
ग)	सेवा लागत	8.77	27.76
घ)	प्रदत्त लाभ	35.54	(312.64)
ङ)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	-	297.04
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	(285.86)	125.53

क्र. स.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	सेवा लागत	125.53	105.73
ख)	निवल ब्याज लागत (आय)	35.54	27.76
ग)	पुनः मापन	8.77	7.63
घ)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	249.02	297.04
ङ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
च)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(285.86)	(312.64)
छ)	द्विभाजन बीमांकिक दायित्व पर लाभ/हानि	133.00	125.53
	विभाजित बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(16.69)	4.27
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	265.71	292.77

क) रुग्णावकाशः रुग्णता अवकाश आधी अवकाश का भुगतान है। जहां किसी कर्मचारी ने कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए कंपनी में काम किया है, कर्मचारी को अनुरोध करने पर, कर्मचारी की सेवा की पूरी अवधि के दौरान, अधिकतम वर्षों तक अवकाश वेतन पर रुग्णता अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, ऐसी छुट्टी वेतन पर कर्मचारी के रुग्णता अवकाश खाते में कर्मचारी द्वारा ली गई अवकाश की अवधि के दोगुने के रूप में दर्ज की जाती है।

बीमारी अवकाश योजना के लिए धारणाएं:

	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
निकासी दर	1% से 3% अवधि के आधार पर	1% से 3% अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.78%	6.99%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता का विश्लेषण

(₹ लाख में)

(क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	400.47
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(22.76)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	24.12
(ख) वेतन वृद्धि में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	400.47
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	24.77
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	(23.02)

मृत्यु दर एवं निकासी से संबंधित संवेदनशीलताएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं अतः इनमें परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है। भुगतानाधीन पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर तथा जीवन प्रत्याशा से संबंधित संवेदनशीलताएँ लागू नहीं हैं।

(₹ लाख में

क्र. स.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	400.47	441.09
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल आस्ति/(देयता)	(400.47)	(441.09)
2.	**लाभ दायित्व में परिवर्तन**		
क)	अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	441.09	321.34
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	ब्याज लागत	30.83	23.20
घ)	सेवा लागत	38.44	44.17
ङ)	पिछली सेवा लागत जिसमें कटौती लाभ/हानि शामिल है	-	-
च)	भुगतान किए गए लाभ	-	-
छ)	दायित्व पर कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(109.90)	52.38
ज)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	400.47	441.09
3.	**निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन**		
क)	अवधि की शुरुआत में निवल परिभाषित लाभ देयता	441.09	321.34
ख)	अधिग्रहण समायोजन	-	-
ग)	कुल सेवा लागत	38.44	44.17
घ)	निवल ब्याज लागत (आय)	30.83	23.20
ङ)	पुनः मापन	(109.90)	52.38
च)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	-	-
छ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
ज)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	400.47	441.09
4.	**विभाजित बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि**		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(39.30)	11.98
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(70.60)	40.40

ङ) **सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) (सितंबर 2015 से शुरू)** इंड एएस–19 के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) देयता का बीमांकिक मूल्यांकन। कंपनी के पास सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

I. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) योजना के लिए धारणाएं:

मृत्यु दर	100 % आईएएलएम (2012 -14)	100 % आईएएलएम (2012 -14)
अवधि के आधार पर आहरण दर	1% से 3% अवधि के आधार पर	1% से 3% अवधि के आधार पर
छूट दर (प्रति वर्ष)	7.78%	6.99%
वेतन वृद्धि (प्रति वर्ष)	5.50%	5.50 %

परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता का विश्लेषण।

(क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव		
	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,516.21
क)	0.50% की वृद्धि के कारण प्रभाव	(21.38)
ख)	0.50% की कमी के कारण प्रभाव	23.49

मृत्यु दर एवं निकासी से संबंधित संवेदनशीलताएँ महत्वपूर्ण नहीं हैंय अतः इनमें परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है। भुगतानाधीन पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पूर्व पेंशन की वृद्धि दर तथा जीवन प्रत्याशा से संबंधित संवेदनशीलताएँ लागू नहीं हैं।

(₹ लाख में

क्र. स.	निवल परिभाषित लाभ (आस्ति)/देयता	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
क)	दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,516.21	1,367.54
ख)	योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	-	-
ग)	प्रावधान के रूप में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध आस्ति/(देयता)	(1,516.21)	(1,367.54)
	योजना आस्तियों में परिवर्तन		
क)	अवधि की शुरुआत में योजनागत आस्ति का उचित मूल्य	1,367.54	1,160.01
ख)	ब्याज लागत	95.59	83.75
ग)	सेवा लागत	82.64	81.37
घ)	प्रदत्त लाभ	(44.34)	(16.70)
ङ)	कुल बीमांकिक (लाभ)/बाध्यता पर हानि	14.78	59.11
च)	अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,516.21	1,367.54
	निवल परिभाषित लाभ दायित्व में परिवर्तन		
क)	सेवा लागत	1,367.54	1,160.01
ख)	निवल ब्याज लागत (आय)	82.64	81.37
ग)	पुनः मापन	95.59	83.75
घ)	निधि में भुगतान किया गया अंशदान	14.78	59.11
ङ)	उद्यम द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	-	-
च)	अवधि के अंत में निवल परिभाषित लाभ देयता	(44.34)	(16.70)
छ)	द्विभाजन बीमांकिक दायित्व पर लाभ/हानि	1,516.21	1,367.54
	विभाजित बीमांकिक लाभ/दायित्व पर हानि		
क)	जनसांख्यिकीय परिवर्तन से उत्पन्न होने पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	-
ख)	वित्तीय परिवर्तन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	(151.98)	38.33
ग)	अनुभव समायोजन से होने वाली बीमांकिक (लाभ)/हानि	166.76	20.78

आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेडः

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के शुरुआती और अंतिम बैलेंस का मिलानः

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(I)	**उपदान**		
	प्रारंभिक शेष	73.35	61.88
	ब्याज लागत	5.08	4.47
	वर्तमान सेवा लागत	5.40	4.85
	लाभ का भुगतान	-	(9.98)
	गणनात्मक लाभ/हानि	(19.52)	12.13
		64.31	73.35

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(II)	**छुट्टी नकदीकरण**		
	प्रारंभिक शेष	105.82	67.59
	ब्याज लागत	7.33	4.88
	वर्तमान सेवा लागत	6.57	10.12
	लाभ का भुगतान	(8.25)	(13.59)
	गणनात्मक लाभ/हानि	(34.75)	36.82
		76.72	105.82
(III)	**सेवानिवृत्ति के बाद का लाभ**		
	प्रारंभिक शेष	51.45	49.79
	ब्याज लागत	3.56	3.59
	वर्तमान सेवा लागत	7.60	5.11
	लाभ का भुगतान	-	-
	गणनात्मक लाभ/हानि	1.02	(7.04)
		63.63	51.45
(IV)	**छुट्टी यात्रा रियायत**		
	प्रारंभिक शेष	48.35	33.97
	ब्याज लागत	3.35	2.45
	वर्तमान सेवा लागत	5.29	4.79
	लाभ का भुगतान	(15.33)	(17.66)
	गणनात्मक लाभ/हानि	4.16	24.79
		45.82	48.34

उपदान और छुट्टी रियायत के प्रावधान के बदले कोई निवेश नहीं किया गया है।

गणनात्मक धारणाएं	31 मार्च 2026 के अनुसार
मूल्यांकन की विधिः	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि
छूट दर	7.22%
वेतन वृद्धि दर	5.50%
सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष
निकासी दर	30 वर्ष तक की कम आयु में 3%, 31 से 44 वर्ष की आयु के बीच 2%, और 44 वर्ष के बाद उच्च आयु वर्ग में क्रमशः घटकर 1% (ग्रेजुएटेड स्केल के अनुसार)
मृत्यु दर	इंडिया एश्योर्ड लाइव्स मृत्यु तालिका (2012–14)

संवेदनशीलता–विश्लेषणः

उपरोक्त संवेदनशीलता–विश्लेषण इस धारणा पर आधारित है कि किसी एक मान्यता में परिवर्तन किया गया है, जबकि अन्य सभी मान्यताओं को अपरिवर्तित रखा गया है। व्यवहार में ऐसी स्थिति सामान्यतः नहीं होती, क्योंकि कुछ मान्यताओं में परिवर्तन परस्पर संबंधित हो सकते हैं। परिभाषित लाभ दायित्व की प्रमुख बीमांकिक अवधारणाओं के प्रति संवेदनशीलता की गणना करते समय वही विधि, अर्थात् प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि, अपनाई गई है, जिसका उपयोग वित्तीय स्थिति विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना हेतु किया गया है।

आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेडः

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष के बीच सामंजस्य विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	उपदान (ग्रेच्युटी)		अवकाश नकदीकरण		सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		छुट्टी यात्रा रियायत	
	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	1,786.54	1,401.12	1,845.31	1,459.53	4,452.26	3,432.31	-	624.65
ब्याज लागत	123.81	100.32	127.88	104.50	308.54	245.76	-	-
वर्तमान सेवा लागत	142.17	171.34	150.12	174.73	215.23	427.86	-	-
लाभ का भुगतान	(795.98)	-	(488.00)	(126.48)	-	-	-	(584.00)
दायित्व पर गणनात्मक (लाभ)/हानि	500.69	113.76	220.07	233.03	(2,316.06)	346.33	-	(40.65)
अंतिम शेष	**1,757.23**	**1,786.54**	**1,855.38**	**1,845.31**	**2,659.97**	**4,452.26**	**-**	**-**

बीमांकिक अवधारणाएंः

	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
मूल्यांकन की विधिः	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि
छूट दर	7.08%	6.93%
वेतन वृद्धि दर	5.50%	5.50%
सेवानिवृत्ति आयु	60 साल	60 साल
निकासी दर	कम आयु वर्ग में 3% तथा ग्रेजुएटेड स्केल के अनुसार उच्च आयु वर्ग में क्रमशः घटकर 1%	कम आयु वर्ग में 3% तथा ग्रेजुएटेड स्केल के अनुसार उच्च आयु वर्ग में क्रमशः घटकर 1%
मृत्यु दर	इंडिया एश्योर्ड लाइव्स मृत्यु तालिका (2012–14)	इंडिया एश्योर्ड लाइव्स मृत्यु तालिका (2012–14)

संवेदनशीलता–विश्लेषण

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए – मान्यताओं में परिवर्तन के प्रभावः

परिवर्तन	मान्यताओं में परिवर्तन	ग्रैच्युटी	अवकाश नकदीकरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	छुट्टी यात्रा रियायत
छूट दर	+0.5%	(69.50)	(75.06)	(7.15)	ना
	-0.5%	72.87	77.78	8.34	ना
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	73.63	78.92	-	ना
	-0.5%	(70.84)	(75.92)	-	ना

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण इस पर आधारित है कि किसी एक मान्यता में परिवर्तन किया गया है तथा अन्य सभी मान्यताओं को अपरिवर्तित माना गया है। व्यवहार में ऐसी स्थिति सामान्यतः नहीं होती, क्योंकि कुछ मान्यताओं में होने वाले परिवर्तन आपस में परस्पर संबंधित हो सकते हैं। परिभाषित लाभ दायित्व की प्रमुख बीमांकिक अवधारणाएं के प्रति संवेदनशीलता की गणना करते समय वही विधि, अर्थात् प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट विधि, अपनाई गई है, जिसका उपयोग वित्तीय स्थिति विवरण में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ दायित्व की गणना के लिए किया गया है।

नियत योगदान योजनाः

(क) पेंशनः

कंपनी कर्मचारियों के प्रति अपनी पेंशन की जिम्मेदारी के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में पहले से नियत दर पर कर्मचारियों के टियर–I एनपीएस खाते (पेंशन खाते) में नियत योगदान देती है।

(ख) भविष्य निधिः

कंपनी ईपीएफओ को भविष्य निधि के खाते में नियत योगदान देती है। कंपनी का अनुमान है कि इस संबंध में निकट भविष्य में कोई देयता नहीं आएगी और इसलिए, आगे किसी प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया।

प्रत्येक कर्मचारी लाभ के लिए अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त राशि निम्नानुसार हैः

(₹ लाख में)

कर्मचारी लाभ	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
अर्जित अवकाश पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	110.19	(105.95)
उपदान पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	95.58	(6.06)
एलएफसी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(253.18)	(321.42)
पीआरएमबी पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	7.36	(55.53)
एसएल पर बीमांकिक लाभ/(हानि	109.90	(52.38)
कुल	**110.19**	**(541.34)**

5. कंपनी का मुख्य व्यवसाय अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्त/पुनर्वित्त उपलब्ध कराना है। कंपनी की यूके स्थित सहायक कंपनी, अर्थात इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यू.के.) लिमिटेड, भी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध कराने के व्यवसाय में संलग्न है, जबकि आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अवसंरचना परियोजना विकास एवं परामर्श गतिविधियों में संलग्न है तथा आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (आईएएमसीएल) की स्थापना म्यूचुअल फंड मार्ग के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स (आईडीएफएस) के प्रबंधन के उद्देश्य से की गई है। चूँकि आईएएमसीएल द्वारा अभी तक आईडीएफ का प्रबंधन प्रारंभ नहीं किया गया है, अतः इसके संबंध में खंड (सेगमेंट) संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी **भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 108** के अनुसार आवश्यक खंड संबंधी जानकारी नीचे प्रस्तुत की गई है।

(₹ लाख में)

विवरण	वित्तपोषण	परामर्श सेवाएँ	निवेश प्रबंधन शुल्क	कुल
संवर्ग रिपोर्टिंग से राजस्व				
संचालन से राजस्व	749,532.49	1,582.21	86.74	751,201.44
घटाएँः अंतर–सेगमेंट राजस्व	63.93	167.55		231.48
कुल परिचालन आय	749,468.56	1,414.65	86.74	750,969.93
कर–पूर्व लाभ	207,428.69	(98.19)	90.68	207,421.15
कर	(60,332.30)	(10.15)	(96.49)	(60,438.94)
कर–पश्चात लाभ	147,096.40	(108.33)	(5.81)	146,982.21
सेगमेंट परिसंपत्तियाँ	10,569,380.11	3,336.98	2,896.84	10,575,613.96
सेगमेंट दायित्व	8,742,021.73	682.30	116.83	8,742,820.81
नियोजित पूंजी	1,827,358.38	2,654.68	2,780.00	1,832,793.07
मूल्यह्रास एवं अमॉर्टाइजेशन	1,432.53	14.58	0.66	1,447.78
पूंजीगत व्यय	15,833.99	9.14	-	15,843.13
गैर–नकद व्यय	153,229.01	-	-	153,229.01

6. **भारतीय लेखा मानक (इंड एएस)–24 – संबंधित पक्ष प्रकटीकरण** के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन का विवरण नीचे दिया गया है।

क) प्रबंधकीय पारिश्रमिक और संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

(i) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्ण कालिक निदेशक

श्री रोहित ऋषि	– प्रबंध निदेशक (प्रभाव से 28.02.2026)
श्री पलाश श्रीवास्तव	– उप प्रबंध निदेशक
श्री विमलेश कुमार	– कार्यवाहक सीईओ
सुश्री आयुषी शर्मा	– प्रमुख वित्त, आईएएमसीएल
श्री मेहुल कृष्णकांत पटवारी	– अध्यक्ष कार्यकारिणी अफसर और निदेशक, आईपीएल

निदेशकों के अलावा

– श्री राजीव मुखीजा – मुख्य महाप्रबंधक–सीएफओ

– सुश्री रुचि सिंघल – महाप्रबंधक–कंपनी सचिव

ख) 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेन–देन (पिछली अवधिः 31 मार्च 2025 को समाप्त)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(क)	**प्रबंधकीय पारिश्रमिक (निर्देशक)**		
	(i) श्री रोहित ऋषि (प्रबंधन निदेशक) #		
	पारिश्रमिक	7.19	-
	(ii) श्री पी. आर. जयशंकर (पूर्व- प्रबंध निदेशक) *		
	पारिश्रमिक	9.83	52.08
	(III) श्री पलाश श्रीवास्तव (उप प्रबंध निदेशक)		
	पारिश्रमिक	53.55	3.34
	(IV) श्री पवन के कुमार (पूर्व उप प्रबंध निदेशक) @		
	पारिश्रमिक	-	30.24
	(V) श्री विमलेश कुमार (कार्यकारी अध्यक्ष कार्यकारिणी अधिकारी, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक	-	24.42
	(vi) श्री सतीश कुमार नागपाल (पूर्व- अध्यक्ष कार्यकारिणी अधिकारी, आईएएमसीएल		
	पारिश्रमिक	-	5.66
	(vii) श्री एस के शर्मा-हेड वित्त, आईएएमसीएल (6 दिसंबर 2024 से प्रभाव में और 12 दिसंबर 2025 तक)		
	पारिश्रमिक	14.68	6.71
	(VIII) सुश्री आयुषी शर्मा-हेड वित्त, आईएएमसीएल (नियुक्त प्रभावी 15 दिसंबर 2025)		
	पारिश्रमिक	14.68	6.71

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(ख)	**प्रबंधकीय पारिश्रमिक (अन्य बजाय निर्देशकों)**		
	(I) श्री राजीव मुखीजा (मुख्य महाप्रबंधक- सीएफओ))		
	पारिश्रमिक	84.37	104.41
	(II) सुश्री रुचि सिंघल (महाप्रबंधक – कंपनी सचिव)$		
	पारिश्रमिक	60.69	55.99
	(III) श्री रूपेश कुमार (उप महाप्रबंधक-कंपनी सचिव)%		
	पारिश्रमिक	-	66.88
	(IV) श्री अभिरूप सिंह (सहायक महाप्रबंधक-कंपनी सचिव)^		
	पारिश्रमिक	-	44.50
	(V) श्री अजय पी.एस. सैनी (कंपनी सचिव, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक	-	47.52
	(VI) श्री अशोक कुमार गांधी (प्रधान वित्त और सीएफओ, आईएएमसीएल)		
	पारिश्रमिक	-	5.03
	(VII) श्री मेहुल कृष्णकांत पटवारी - मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक, आईपीएल		
	पारिश्रमिक	30.33	55.00
(ग)	**पदेन आईपीएल के अल्पकालिक कार्यकारी अधिकारी निदेशक को चुकाया गया शुल्क**		
	समीर जेरमभाई बोगरा	13.60	13.95
	श्री संजीव चन्ना	1.50	2.10
	श्री हरीश कांत पारिख	1.40	1.70
	सुधीर आर्य	1.50	2.00

4 फरवरी 2026 से प्रभावी, * 28 मई 2025 तक, @ 30 सितंबर 2024 तक, $ 19 दिसंबर 2024 से प्रभावी, % 18 दिसंबर 2024 तक, ^ 14 मई 2024 तक

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के लागू होने के अनुसार, जो 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए सामान्य निर्देशों के क्लॉज 2 के अनुसार निम्नलिखित जानकारी दी गई है:

इकाई का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियाँ (अर्थात कुल परिसंपत्तियाँ घटा कुल दायित्व)		लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राशि (₹ लाख में)	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राशि (₹ लाख में)
	31.03.2026 को	31.03.2026 को	31.03.2025 को	31.03.2025 को
मूल कंपनी				
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	92.37%	1,789,744.68	93.64%	137,881.83
सहायक कंपनियाँ				
भारतीय				
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	0.14%	2,654.67	0.08%	116.24
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	0.14%	2,780.01	0.14%	203.13
विदेशी				

इकाई का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियाँ (अर्थात कुल परिसंपत्तियाँ घटा कुल दायित्व)		लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राशि (₹ लाख में)	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों का प्रतिशत	राशि (₹ लाख में)
	31.03.2026 को	31.03.2026 को	31.03.2025 को	31.03.2025 को
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	7.35%	142,350.99	6.15%	9,050.62
सभी सहायक कंपनियों में अल्पांश हित	-	-	-	-
सहयोगी कंपनियाँ (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय	-	-	-	-
विदेशी	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम (अनुपातिक समेकन / इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय	-	-	-	-
विदेशी	-	-	-	-

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं:

(₹ लाख में)

सहायक कंपनी का नाम	रिपोर्टिंग मुद्रा	शेयर पूंजी	रिजर्व और सरप्लस	कुल परिसंपत्तियाँ	कुल देनदारियाँ	टर्नओवर	टैक्स से पहले लाभ	टैक्स के लिए प्रावधान	टैक्स के बाद लाभ	शेयर धारिता
आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	₹ लाख में	475.00	2,076.05	3,336.98	682.30	1,834.87	15.60	(10.15)	52.32	100%
आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	₹लाख में	1,250.00	1,530.01	2,896.84	116.83	121.58	90.68	(96.49)	187.18	100%
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	₹ लाख में	103,076.15	39,442.39	826,104.55	683,753.56	52,219.86	8,942.50	108.11	9,050.61	100%
	यूएसडी डॉलर (मिलियन में)	150.00	0.39	872.76	722.37	57.69	9.43	0.12	9.55	

7. इंड एएस–116: पट्टा से संबंधित प्रावधान

(क) वित्तीय ऋण: शून्य

(ख) परिचालन ऋण: कंपनी ने कार्यालय परिसर को परिचालन पट्टा के अंतर्गत लिया है, जिनकी पट्टा अवधि अलग–अलग है। इन ऋणों से संबंधित आवश्यक प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
भविष्य के न्यूनतम लीज भुगतानों का कुल योग (सकल निवेश)	310.95	373.05
पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य	279.17	325.26
10 साल की जी–सेक यील्ड	7.14%	6.75%
भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतानों के कुल योग का परिपक्वता प्रोफाइल		
एक साल से ज्यादा नहीं	103.65	91.36
एक साल से ज्यादा लेकिन पाँच साल से ज्यादा नहीं	207.30	281.69
पाँच साल से ज्यादा	-	-
कुल	310.95	373.05

8. में शर्तें का इंडस्ट्रीज़ एएस-33, आय प्रति शेयर करना, जारी किए गए द्वारा संस्था का चार्टर्ड एकाउंटेंट का भारत, आय प्रति शेयर करना (बुनियादी और तनुकृत) है जैसा अंतर्गत:

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	
	शेयर	राशि ₹ लाख मे	शेयर	राशि ₹ लाख मे
शेयर का नाममात्र मूल्य (₹)	10/-		10/-	
इक्विटी शेयर की संख्या (संख्या लाख में)	99,999.16		99,999.16	
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) (अंश)	99,999.16		99,999.16	
#इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में संख्या) (हर) (डाइल्यूटेड)	99,999.16		99,999.16	
निवल लाभ (कर के बाद) (अंश)		147,038.49		262,736.79
प्रति शेयर आय (मूल) (₹) (सतत संचालन के लिए)		1.47		2.63
प्रति शेयर आय (तनुकृत) (₹) (सतत संचालन के लिए)		-		-
आय प्रति शेयर करना (बुनियादी और पतला) (₹)				
(अवरोधित परिचालन हेतु)				

9. कंपनी के पास विद्यमान नियत परिसंपत्तियों को 'कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां' माना जाता है, न कि 'कैशजेनरेटिंग यूनिट्स', जैसा कि इंड एएस–36 में "परिसंपत्तियों का ह्रास" पर बताया गया है। 31 मार्च 2026 तक, ऐसी कोई घटना या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिससे परिसंपत्तियोंमें कोई ह्रास दिखे।

10. (क) भारतीय लेखा मानक 37 के अंतर्गत प्रकटीकरण "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां (इंड एएस–37)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
प्रस्तावित वेतन संशोधन		
प्रारंभिक शेष	1,817.19	1,191.91
अवधि के दौरान वृद्धि	785.86	625.28
भुगतान / समायोजित राशि	102.26	-
अवमानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	33.93	-
अंतिम शेष	**2,466.86**	**1,817.19**
मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	28,776.22	21,117.55
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	7,030.87	7,658.67
प्रावधान वापस लेना	-	-
अंतिम शेष	**35,807.09**	**28,776.22**
मानक आस्तियों के प्रति आकस्मिक प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	-	-
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	-	-
प्रावधान वापस लेना	-	-
अंतिम शेष	**-**	**-**
सब–स्टैंडर्ड आस्तियों के विरूद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	1,520.71	6,819.57
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	(800.35)	(5,298.86)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
प्रावधान वापस लेना	-	-
अंतिम शेष	**720.35**	**1,520.71**
संदिग्ध आस्तियों के विरूद्ध प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	1,24,073.92	1,73,324.79
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	(29,187.62)	(41,370.19)
प्रावधान वापस लेना	-	7,880.68
अंतिम शेष	**94,886.30**	**1,24,073.92**
निवेश में कमी के लिए प्रावधान		
प्रारंभिक शेष	22,059.91	23,654.75
अवधि के दौरान जोड़/समायोजन	-	-
प्रावधान वापस लेना	1,794.59	1,594.83
अंतिम शेष	**20,265.32**	**22,059.91**

(ख) अन्य प्रकटीकरणः

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
आयकर (निवल)		
प्रारंभिक शेष	25,777.95	21,303.14
अवधि के दौरान वृद्धि	47,604.87	59,988.14
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	58,481.93	55,513.33
अंतिम शेष	**14,900.89**	**25,777.95**
यात्रा रियायत छूट		
प्रारंभिक शेष	173.88	145.94
अवधि के दौरान वृद्धि	306.13	367.15
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	301.19	339.21
अंतिम शेष	**178.82**	**173.88**
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ		
प्रारंभिक शेष	1,463.51	1,244.12
अवधि के दौरान वृद्धि	187.27	236.09
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	44.34	16.70
अंतिम शेष	**1,606.44**	**1,463.51**
अवकाश नकदीकरण		
प्रारंभिक शेष	124.27	82.19
अवधि के दौरान वृद्धि	(15.87)	56.90
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	3.37	14.82
अंतिम शेष	**95.28**	**124.27**
रुग्णावकाश		
प्रारंभिक शेष	441.09	321.34
अवधि के दौरान वृद्धि	(40.63)	119.75
अवधि के दौरान भुगतान/समायोजित राशि	-	-
अंतिम शेष	**400.47-**	**441.09**

11 आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया हैं) निम्नानुसार हैं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(क)	**(क) कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए दावे:**		
	(i) आयकर विभाग द्वारा 28 दिसंबर 2018 के आदेश के माध्यम से निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए की गई आयकर मांग।	632.66	682.33
	(ii) आयकर विभाग द्वारा आयकर पोर्टल पर 30 मार्च 2023 को निर्धारण वर्ष 2016–17 के लिए दर्शाई गई आयकर मांग।	174.58	174.58
	(iii) आयकर विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए की गई आयकर मांग।	51.65	51.65
	(iv) आयकर विभाग द्वारा 27 मार्च 2025 की सूचना के माध्यम से निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए की गई आयकर मांग।	5,131.21	2665.81
	(v) आयकर विभाग द्वारा 13 मार्च 2026 के आदेश के माध्यम से निर्धारण वर्ष 2024–25 के लिए की गई आयकर मांग।	7,656.32	-
	(vi) सेवा कर संबंधी मांग कृ ब्याज सहित मांग का भुगतान विरोधाधीन रहते हुए किया गया।	71.52	71.52
	(vii) वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी मांग।	0.90	0.90
	(viii) वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी मांग।	270.76	270.76
	(ix) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी मांग।	872.45	872.45
	(x) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संबंधी मांग।	104.35	104.35
	(ख) गारंटी		
	(ग) अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:	शून्य	शून्य
	(i) लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी करने के लिए चुकौती आश्वासन पत्र (कंपनी ने संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने के लिए संबंधित उधारकर्ताओं की ओर से एलसी जारी करने के लिए संबंधित अग्रणी बैंकों/सदस्य बैंक को एलसी की राशि जारी करने के लिए चुकौती आश्वासन पत्र जारी किए हैं।	1,06,854.67*	80,225.98
	(ii) ऋण वृद्धि योजना के तहत दी गई गारंटी	21,782.30	22,413.10
(ख)	**(क) पूँजीगत खाते पर निष्पादित शेष संविदाओं की अनुमानित राशि तथा प्रावधान होना:)**		
	पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि यअग्रिम राशि घटाने के बाद)।	2,462.78	2,932.44
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ:		
	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निष्पादित किए जाने हेतु शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिम राशि घटाने के बाद)।	4,827.90	2,396.11

*इसमें ₹ 3,00,000 लाख की सीमा में से इंडियन बैंक द्वारा जारी ₹ 34,701.00 लाख की साख–पत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) राशि शामिल है।

12. उद्यम पूँजी इकाइयों में निवेश

31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान, कंपनी ने आईडीएफसी, सिटी बैंक के साथ मिलकर कंपनी द्वारा प्रवर्तित आईडीएफसी प्रोजेक्ट इक्विटी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ट्रस्ट–II की उद्यम पूँजी इकाइयों में कोई निवेश नहीं किया (31 मार्च 2025 को भी ₹ शून्य)। इन इकाइयों में 31 मार्च 2026 तक कंपनी का संचयी निवेश ₹ 9,247.56 लाख है। ₹ 10,000 लाख की कुल प्रतिबद्ध ता में से कंपनी ने इस उद्यम में निवेशक के रूप में अंशदान किया है तथा इस पर उसका संयुक्त नियंत्रण नहीं है। निधि में वितरण योग्य लाभ उपलब्ध न होने के कारण, इन निवेशों के संबंध में लेखा पुस्तकों में कोई आय दर्ज नहीं की गई है।

तथापि, 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी को उद्यम पूँजी इकाइयों के मोचन के संबंध में ₹35.50 लाख की राशि प्राप्त हुई (31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹शून्य)। इसमें भुगतान किया गया कर ₹शून्य था (31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान भी ₹शून्य लाख)।

13. कंपनी ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹1,746.43 लाख की शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति को वापस लिया है (आस्थगित कर परिसंपत्ति में ₹1,831.55 लाख की कमी तथा आस्थगित कर देयता में ₹85.12 लाख की कमी)। पिछले वर्ष, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹6,329.14 लाख की शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति को वापस लिया था (आस्थगित कर परिसंपत्ति में ₹6,329.95 लाख की कमी तथा आस्थगित कर देयता में ₹0.82 लाख की कमी)।

14. कंपनी के पास उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक कोई भी आपूर्तिकर्ता अथवा सेवा प्रदाता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत नहीं है।

विवरण इस प्रकार हैं:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
प्रत्येक वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को चुकाई न गई मूल राशि और उस पर लगने वाला ब्याज (अलग से दिखाया जाएगा)	89.09	2.10
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अंतर्गत खरीदार द्वारा दिए गए ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान तय दिन के बाद आपूर्तिकर्ताको किए गए भुगतान की राशि	-	-
भुगतान करने में हुई देरी के लिए देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान तय दिन के बाद चुकाई गई है) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के तहत बताए गए ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में जमा हुआ और बाकी बचा हुआ ब्याजय और	-	-
आगे के वर्षों में भी बकाया और चुकाने लायक ब्याज की राशि, उस तारीख तक जब तक ऊपर बताई गई ब्याज की राशि असल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के तौर पर मनाही के उद्देश्य से नहीं दी जाती।	-	-

15. व्युत्पन्न लेनदेन

कंपनी ने बहुपक्षीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा उधार पर अस्थिर ब्याज दरों के साथ–साथ विदेशी मुद्रा 7 उतार–चढ़ाव से संबंधित जोखिमों से बचाव के लिए समग्र संविदा अर्थात क्रॉस करेंसी स्वैप (मूलधन और ब्याज) किए है, जो निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

संस्थान	पारस्परिक मुद्रा स्वैप की राशि	
	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):		
अमरीकी डॉलर	3,045.38	4,947.00
भारतीय मुद्रा	288,257.91	423,371.39
आईबीआरडी विश्व बैंक:		
अमरीकी डॉलर	-	1,078.99
भारतीय मुद्रा	-	92,341.65

सभी बचाव 100% प्रभावशील हैं यानी कोई निष्प्रभावी नहीं है।

बचाव अनुपातः बचाव किए गए आइटम और हेजिंगइंस्ट्रूमेंट के बीच एक इकोनॉमिक रिश्ता होता है क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्टरेटस्वैप और क्रॉस करेंसी स्वैपकॉन्ट्रैक्ट की शर्तें फॉरेन करेंसी उधार से मेल खाती हैं। कंपनी ने हेजिंग रिश्तों के लिए 1:1 का

बचाव रेश्यो बनाया है क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इंटरेस्टरेट स्वैप और क्रॉस करेंसी स्वैप का अंदरूनी रिस्क बचाव किए गए जोखिम घटकों जैसा ही है। बचाव बेअसर होना मुख्य रूप से तब हो सकता है जब कंपनी या प्रतिपक्ष के क्रेडिट रिस्क में कोई बदलाव हो।

प्रतिपक्षी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए मार्क–टू–मार्केट (एम2एम) मूल्यांकन तथा उपर्युक्त संविदाओं के अन्य मूल्यों के अनुसार, 31 मार्च 2026 को शुद्ध एम2एम लाभ ₹1,74,673.79 लाख है (सकल लाभ ₹1,74,673.79 लाख में से सकल हानि ₹शून्य लाख घटाने के बाद)। वहीं, 31 मार्च 2025 को एम2एम लाभ ₹1,35,382.74 लाख था (सकल लाभ ₹1,36,327.97 लाख में से सकल हानि ₹945.23 लाख घटाने के बाद)।

31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने बचाव की गई सीमा तक विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में लेखांकन शोधन के लिए कंपनी द्वारा अपनाए जाने वाले सही लेखांकन शोधन पर सलाह देने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय मांगी। इस संबंध में, आईसीएआई ने 22 सितंबर 2015 के पत्र के माध्यम से मामले में राय प्रदान की। आईसीएआई ने जून 2015 में "व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए लेखांकन" पर मार्गदर्शी टिप्पणी भी जारी की, जो 1 अप्रैल 2016 से लागू है और कंपनी द्वारा 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इसे लागू किया गया है। पिछली रिपोर्टिंग तारीख से इस रिपोर्टिंग तारीख तक विदेशी मुद्रा उधार की राशि पर विनिमय दर में कोई भी परिवर्तन और अवधि के दौरान ड्रॉपडाउन उधार की तारीख से, व्युत्पन्नी संविदाओं के उचित मूल्य के सापेक्ष सेट ऑफ किया जाता है और किसी भी लाभ या हानि को कैश फ्लो बचाव रिजर्व के रूप में मान्य किया जाता है।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने 26 दिसंबर 2016 के पत्र के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) को सूचित किया कि आईआईएफसीएल को व्युत्पन्नों पर गार्गदर्शी टिप्पणी लागू करते समय बचाव संपर्क पर बाजार–दर–बाजार/उचित मूल्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी एक प्रति भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजी गई है। 3 मई 2017 के उनके पत्र के अनुसार इस मामले को आईसीएआई की शोध समिति को भेज दिया गया है।

इंडएएस–21 के अनुरूप समापन दर पर पुनर्कथित ऋण के हेज्ड हिस्से का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

संस्थान	बचाव स्थिति की राशि	
	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):		
अमरीकी डॉलर	10,815.82	11,514.56
भारतीय मुद्रा	1,023,763.52	985,432.21
आईबीआरडी विश्व बैंक:		
अमरीकी डॉलर	1,059.82	1,187.99
भारतीय मुद्रा	100,316.52	101,670.02
यूरोपीयन निवेश बैंक:		
यूरो	100.00	256.67
भारतीय मुद्रा	10,900.64	23,696.65
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए)		
येन	71,036.40	-
भारतीय मुद्रा	42,089.07	–
सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एसएमबीसी)		
येन	147,948.38	-
भारतीय मुद्रा	87,659.42	-

व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार वित्तीय मुद्रा एक्सपोजर का प्रकटीकरण निम्नवत है:

(₹ लाख में)

I. आस्ति	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि (₹ लाख में)	विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि (₹ लाख में)
प्राप्य (व्यापार और अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
अन्य मौद्रिक आस्तियां (जैसे आईसीडी/एफसी में दिए गए ऋण)	-	-	-	-	-	-	-
कुल प्राप्य (क)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्न संविदाओं द्वारा बचाव (ख)	-	-	-	-	-	-	-
बिना बचाव वाले प्राप्य (ग = क – ख)	-	-	-	-	-	-	-

II. देयताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि (₹ लाख में)	विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि (₹ लाख में)
देय (व्यापार एवं अन्य)	-	-	-	-	-	-	-
उधार (ईसीबी और अन्य)	यूएसडी	94.6543	13,558.83	1,283,401.37	85.5814	13,621.80	1,165,772.55
	यूरो	109.006	1,404.00	153,045.00	92.3246	1,550.63	143,161.35
	जेपीवाई	0.5925	604,392.60	358,102.62	0.5675	378,831.86	214,970.21
कुल देय (घ)	यूएसडी	94.6543	13,558.83	1,283,401.37	85.5814	13,621.80	1,165,772.55
	यूरो	109.006	1,404.00	153,045.00	92.3246	1,550.63	143,161.35
	जेपीवाई	0.5925	604,392.60	358,102.62	0.5675	378,831.86	214,970.21
व्युत्पन्न संविदा द्वारा बचाव (ङ)	यूएसडी	94.6543	11,875.64	1,124,080.04	85.5814	12,702.55	1,087,102.23
	यूरो	109.006	100.00	10,900.64	92.3246	256.67	23,696.65
	जेपीवाई	0.5925	218,984.78	129,748.48	0.5675	-	-
बिना बचाव वाले देय (च = घ – ङ)	यूएसडी	94.6543	1,683.19	159,321.33	85.5814	919.25	78,670.32
	यूरो	109.006	1,304.00	142,144.36	92.3246	1,293.96	119,464.70
	जेपीवाई	0.5925	385,407.82	228,354.13	0.5675	378,831.86	214,970.21

III- आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं	विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष			विगत वर्ष		
		विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि (₹ लाख में)	विनिमय दर	राशि विदेशी मुद्रा में	राशि (₹ लाख में)
आकस्मिक देयताएं	-	-	-	-	-	-	-
प्रतिबद्धताएं	-	-	-	-	-	-	-
कुल (छ)	-	-	-	-	-	-	-
व्युत्पन्न संविदाओं द्वारा बचाव (ज)	-	-	-	-	-	-	-
बिना बचाव वाले भुगतान (झ = छ–ज)	-	-	-	-	-	-	-
कुल बिना बचाव वाले एफसी एक्सपोजर (ञ= ग+च+झ)	-	-	-	-	-	-	-

ख) विदेशी मुद्रा ऋणों की बिना बचाव वाली स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

संस्थान	बिना बचाव वाली स्थिति की राशि	
	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
एशियाई विकास बैंक (एडीबी):		
अमरीकी डॉलर	1,649.45	918.52
भारतीय मुद्रा	156,127.70	78,608.02
क्रेडिटनस्टाल्ट फुर विडेराउफबाउ (केएफडब्ल्यू)		
यूरो	133.29	138.73
भारतीय मुद्रा	14,529.01	12,807.80
आईबीआरडी विश्व बैंक:		
यूएसडी	33.74	0.73
भारतीय मुद्रा	3,193.64	62.30
यूरोपीयन निवेश बैंक (ईआईबी)		
यूरो	1,170.71	1,155.24
भारतीय मुद्रा	127,615.35	106,656.89
जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी (जेआईसीए)		
जेपीवाई	273,356.20	378,831.86
भारतीय रुपया	161,963.55	214,970.21
सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन (एसएमबीसी)		
जेपीवाई	112,051.62	-
भारतीय रुपया	66,390.58	-

ग) लेखा नीति 20 के अनुसार, खातों को बंद करने की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरें (अर्थात आरबीआई संदर्भ दरें) इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	विनिमय दर	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
1	यूएसडी/आईएनआर	94.6543	85.5814
2	यूरो/आईएनआर	109.006	92.3246
3	जेपीवाई/आईएनआर	0.5925	0.5675

16. बॉन्ड मोचन आरक्षिती का सृजन

(क) निजी तौर पर आबंटित बॉण्डों के संबंध मेंरू कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) के अंतर्गत केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 143 (ई) (फा. सं. 3/5/2008), दिनांक 14 जनवरी 2009 के माध्यम से कंपनी को सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है। अतः भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 11 फरवरी 2013 को जारी परिपत्र संख्या 04/2013 के अनुसार, कंपनी को निजी तौर पर आबंटित बॉण्डों के संबंध में बॉण्ड मोचन आरक्षित निधि सृजित करना आवश्यक नहीं है।

(ख) सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी बॉण्डों के संबंध मेंरू कंपनी ने सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से ₹1,000 अंकित मूल्य वाले कर–मुक्त बॉण्ड वित्तीय वर्ष 2012–13 में कुल ₹3,15,631.89 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल ₹6,87,754.25 लाख के जारी किए। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2010–11 में ₹9,096.18 लाख के दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्ड जारी किए गए। इस प्रकार, सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी बॉण्डों की कुल राशि ₹10,12,482.32 लाख है।

कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम 2014 के नियम 18 (7) (ख) (ii) के अनुसार, कंपनी आरबीआई (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 45–आईए के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी के लिए डिबेंचर मोचन आरक्षिती (डीआरआर) का सृजन करेगी, डीआरआर की पर्याप्तता वर्तमान सेबी (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008 के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी किए गए डिबेंचर के मूल्य का 25% होगी, और निजी तौर पर प्लेस्ड डिबेंचर के मामले में कोई डीआरआर आवश्यक नहीं है। तदनुसार, कंपनी ने 31 मार्च 2026 तक की स्थिति के अनुसार ₹54,462.29 लाख (31 मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार ₹54,568.28 लाख) का बॉन्ड मोचन आरक्षितका सूजन किया है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 19 अगस्त 2019 की अधिसूचना के तहत कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियमों में संशोधन किया है और तदनुसार कंपनी को अब मोचनीय असंपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर डिबेंचर मोचन आरक्षिती का सृजन करने की आवश्यकता नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्धता करार में निहित प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार, यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने व्यक्तियों, सहयोगियों और फर्मों कंपनियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, जिनमें निदेशकों के हित है। इसके अलावा, किसी भी ऋण (उधारकर्ता) ने कंपनी या उसकी सहायक कंपनी के शेयरों में कोई निवेश नहीं किया है।

(क) आरबीआई ने सार्वजनिक जमा स्वीकार किए बिना गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में व्यवसाय करने के लिए आईआईएफसीएल को दिनांक 9 सितंबर 2013 को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया।

(ख) एनबीएफसीआईएफसी के लिए आरबीआई द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंड कंपनी पर लागू होते हैं। एनबीएफसीआईएफसी के रूप में पंजीकरण पर, कंपनी, एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी होने के नाते, सरकार के परामर्श से एनबीएफसी विनियमों के विभिन्न तत्वों के अनुपालन के लिए एक रोडमैप तैयार करने और इसे भारतीय रिजर्व बैंक (गैर–बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जैसा कि आरबीआई द्वारा अधिसूचना संख्या डीएनबीएस. पीडी/सीसी संख्या 86/03.02. 089/2006–07 दिनांक 12 दिसंबर 2006 के माध्यम से निर्देशित किया गया था। आवश्यकता के अनुपालन में, कंपनी ने आरबीआई को दिनांक 21 नवंबर 2014 के पत्र के माध्यम से 1 जनवरी 2015 से आरबीआई विनियमन के विभिन्न तत्वों का अनुपालन करने के लिए रोडमैप प्रस्तुत किया है।

(ग) कंपनी ने 31 मार्च 2026 के दौरान शून्य ऋण खाते का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारित किया है, जिसमें 31 मार्च 2026 के दौरान शून्य बकाया शेष है (31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार शून्य) और 31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार इन खातों में प्रतिभूति के मूल्य में कोई कमी नहीं है (टिप्पणी 1 (क) (5.7) (अ) देखें)।

17. विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए आयकर निर्धारण की लंबित स्थिति निम्नानुसार है:

कर निर्धारण वर्ष	स्थिति
2016-17	निर्धारण आदेश, आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत, दिनांक 28.12.2018 को प्राप्त हुआ। निर्धारण आदेश में की गई अस्वीकृतियों के विरुद्ध 25.01.2019 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई। विरोधाधीन रहते हुए ₹137 लाख की कर मांग का 20% जमा किया गया तथा निर्धारण वर्ष 2011–12 के रिफंड से ₹46.71 लाख समायोजित किए गए। उक्त आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई। धारा 250 सहपठित धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26.03.2025 का आदेश जारी किया गया, जिसमें अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई।
	धारा 154 के अंतर्गत ₹519.18 लाख की अतिरिक्त राशि जोड़ने का प्रस्ताव करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ। यह नोटिस धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के अतिरिक्त दावे से संबंधित था, जिसके विरुद्ध 20.01.2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया। आईआईएफसीएल को इसी प्रकार का एक अन्य नोटिस धारा 154 के अंतर्गत प्राप्त हुआ, जिसमें करयोग्य आय में ₹1,500.18 लाख जोड़ने का प्रस्ताव था। आईआईएफसीएल ने 27 अप्रैल 2023 को उक्त आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। दिनांक 26.09.2024 को धारा 250 के अंतर्गत आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें अपील खारिज कर दी गई। इसके विरुद्ध 29.11.2024 को आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई, जो वर्तमान तिथि तक लंबित है।
	आयकर अपीलीय अधिकरण ने उपर्युक्त दोनों अपीलों के संबंध में 11.02.2026 को एक साझा आदेश जारी किया। इसमें ₹1,556 लाख से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए ₹1,772 लाख की अस्वीकृति के मामले को पुनर्विचार हेतु निर्धारण अधिकारी के पास वापस भेज दिया गया।
2017-18	आईआईएफसीएल को आयकर विभाग द्वारा 17.12.2019 को पारित धारा 143(3) के अंतर्गत निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें ₹50.67 लाख के व्यय को अस्वीकार किया गया था। आईआईएफसीएल ने विलंब माफी के आवेदन के साथ 15.03.2023 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। विलंब माफी की अनुमति न मिलने के आधार पर अपील खारिज कर दी गई।
	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत कटौती के अतिरिक्त दावे के संबंध में ₹421.12 लाख की राशि जोड़ने का प्रस्ताव करते हुए धारा 154 के अंतर्गत नोटिस प्राप्त हुआ, जिसके विरुद्ध 12.12.2022 को जवाब प्रस्तुत किया गया। आईआईएफसीएल को इसी प्रकार का एक अन्य नोटिस धारा 154 के अंतर्गत प्राप्त हुआ, जिसका जवाब 7 सितंबर 2023 को प्रस्तुत किया गया। इसके बाद, आईआईएफसीएल को 31.05.2023 को धारा 154 के अंतर्गत एक अन्य आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें प्रस्तुत जवाब पर विचार किए बिना करयोग्य आय में ₹1,216.83 लाख जोड़ दिए गए। इस आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील लंबित थी। 05.12.2024 को धारा 250 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया, जिसमें आईआईएफसीएल के पक्ष में निर्णय दिया गया। विभाग ने इस आदेश के विरुद्ध आयकर अपीलीय अधिकरण में अपील दायर की, जिसने भी आईआईएफसीएल के पक्ष में निर्णय दिया।
	धारा 148ए के अंतर्गत 01.03.2024 को नोटिस जारी किया गया। 05.12.2024 को धारा 250 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया, जिसमें आईआईएफसीएल के पक्ष में निर्णय दिया गया। धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिस के जवाब में 25.06.2024 को आयकर विवरणी दाखिल की गई। पत्र संख्या ITBA/AST/S/61/2024–25/1066229074(1), दिनांक 28.06.2024 के माध्यम से धारा 147 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस संबंध में 04.12.2024, 14.12.2024, 22.12.2024, 24.12.2024 तथा 09.01.2025 को कई नोटिस जारी किए गए, जिनके जवाब आयकर पोर्टल पर अपलोड किए गए। 13.02.2025 को धारा 147 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया, जिसमें ₹1,49,23,530 की राशि अस्वीकार की गई। इसके विरुद्ध 13.03.2025 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई। आयुक्त (अपील) ने 25.11.2025 को आदेश जारी कर आईआईएफसीएल की अपील खारिज कर दी। इसके विरुद्ध 22.01.2026 को आयकर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई। 18.05.2026 तक इस मामले की सुनवाई आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा की जा चुकी थी।

कर निर्धारण वर्ष	स्थिति
2018-19	धारा 148ए के अंतर्गत 17.08.2024 को नोटिस जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस के जवाब में निर्धारित तिथि 26.08.2024 को उत्तर प्रस्तुत किया गया। धारा 148ए(डी) के अंतर्गत 31.08.2024 को आदेश पारित किया गया तथा उसी दिन जारी नोटिस के माध्यम से धारा 148 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसके जवाब की अंतिम तिथि 30.11.2024 थी। धारा 148 के अंतर्गत जारी नोटिस के जवाब में 29.11.2024 को आयकर विवरण ी दाखिल की गई। पत्र संख्या ITBA/AST/S/61/2025-26/1075729795(1), दिनांक 22.04.2025 के माध्यम से धारा 147 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस संबंध में 15.05.2025, 16.05.2025, 29.05.2025, 17.09.2025 तथा 25.09.2025 को कई नोटिस जारी किए गए, जिनके जवाब आयकर पोर्टल पर विधिवत प्रस्तुत किए गए। अधिनियम की धारा 147 सहपठित धारा 144बी के अंतर्गत 19.02.2026 को आदेश जारी किया गया, जिसमें ₹ 2,94,82,85,410 की आय का निर्धारण किया गया तथा कोई अतिरिक्त राशि नहीं जोड़ी गई।
2020-21	कर लेखा परीक्षक द्वारा कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित आकस्मिक देयताओं को अस्वीकार किए जाने के कारण 27.03.2025 को ₹ 26,65,81,260 की मांग सृजित करते हुए मांग नोटिस जारी किया गया। इसी विषय पर 04.08.2025 को एक अन्य मांग नोटिस जारी किया गया, जिसमें मांग बढ़ाकर ₹ 51,31,20,590 कर दी गई। मांग नोटिस के विरुद्ध 18.04.2026 को धारा 154 के अंतर्गत सुधार आवेदन दायर किया गया। केंद्रीयकृत प्रसंस्करण केंद्र द्वारा जारी सूचना आदेश के परिणामस्वरूप 19.05.2026 तक मांग घटकर ₹ 42,000 रह गई।
2024-25	24.06.2025 को जारी नोटिस के माध्यम से फेसलेस निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस संबंध में विभाग द्वारा जारी नोटिसों के जवाब प्रस्तुत किए गए। 13.03.2026 को धारा 143(3) के अंतर्गत आदेश पारित किया गया, जिसमें ₹ 2,23,28,64,899 की राशि अस्वीकार करने के बाद ₹ 17,54,66,45,529 की आय का निर्धारण किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध 10.04.2026 को आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।

18. अन्य प्रकटीकरण:

18.1 31 मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के दौरान, कंपनी ने ₹16,615.50 लाख की राशि वाले 3 खातों को बट्टे खाते में डाला (31 मार्च, 2025 तक 7 ऋण खातों में ₹13,939.51 लाख)। टिप्पणी 1(क)(5.3) देखें।

18.2 आईआईएफसीएल ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त अवधि के लिए निवेश के मूल्य में कमी हेतु ₹20,265.32 लाख का प्रावधान निम्नानुसार किया था:

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, मेसर्स आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड (एपीएनआरएल) से संबंधित ₹52,000.00 लाख के बकाया ऋण मूलधन तथा उस पर ₹2,545.99 लाख के ब्याज एवं अन्य अतिदेय राशियों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ईएआरसी) को ₹38,884.95 लाख के प्रतिफल पर बेचा गया। इसमें ₹108.18 लाख की अग्रिम प्राप्ति, एपीएनआरएल की ₹9,710.71 लाख की इक्विटी शेयर पूंजी (₹10 अंकित मूल्य वाले पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर) तथा ₹38,884.95 लाख की सुरक्षा रसीदें शामिल थीं। इसी दौरान, ईएआरसी ने एपीएनआरएल के ₹10 अंकित मूल्य वाले कुल ₹4,945.70 लाख के इक्विटी शेयर ₹1.2045 प्रति शेयर की दर से खरीदे, जिनका कुल मूल्य ₹595.72 लाख था। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने ईएआरसी द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए भुगतान की गई कीमत को उचित मूल्य माना। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2018 तक एपीएनआरएल में आईआईएफसीएल के पास शेष इक्विटी शेयरों का मूल्य ₹1.2045 प्रति शेयर निर्धारित किया गया तथा निवेश के मूल्य में ₹4,191.05 लाख की कमी हेतु प्रावधान किया गया। आईआईएफसीएल ने इक्विटी शेयर पूंजी का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध उचित मूल्यांकन के आधार पर किया है।
- मेसर्स टॉपवर्थ टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में रियायतग्राही के प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप, ₹8,000.00 लाख के बकाया ऋण में से ₹6,078.00 लाख का निपटान नए रियायतग्राही, बंसल पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 0.01% वार्षिक कूपन दर वाले वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय मोचनीय डिबेंचरों के निर्गमन के माध्यम से किया गया। शेष ₹1,922.00 लाख का बकाया ऋण नए रियायतग्राही, बंसल पाथवेज (मंगावन-चाकघाट) प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाना था। तदनुसार, निवेश के मूल्य में ₹4,779.68 लाख की कमी हेतु प्रावधान किया गया, क्योंकि बंसल पाथवेज (मंगावन-चाकघाट) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी डिबेंचर, उनकी प्राप्ति के 25 वर्ष बाद सममूल्य पर चुकाए जाने हैं।
- एमईपी नागपुर रिंग रोड 1 प्राइवेट लिमिटेड में आईआईएफसीएल का 31.03.2021 तक ₹10,087.84 लाख का कुल बकाया मूलधन बंसल पाथवेज नागपुर रिंग रोड 1 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपने अधीन ले लिया गया। इसमें ₹2,811.84 लाख का सावधि ऋण तथा 0.01% कूपन दर वाले ₹7,276 लाख के डिबेंचर शामिल थे। तदनुसार, डिबेंचरों पर ₹4,451.99 लाख की राशि का प्रावधान किया गया।

- एमईपी नागपुर रिंग रोड 2 प्राइवेट लिमिटेड में आईआईएफसीएल का 31.03.2021 तक ₹11,184.00 लाख का बकाया मूलधन बंसल पाथवेज नागपुर रिंग रोड 2 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 0.01% कूपन दर वाले ₹11,184.00 लाख के डिबेंचरों के रूप में अपने अधीन ले लिया गया। तदनुसार, इन डिबेंचरों पर ₹5,072.96 लाख का प्रावधान किया गया।
- आईआईएफसीएल का मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड में ₹22,137.32 लाख का बकाया मूलधन था। वर्ष 2019 में इस परियोजना को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत भेजा गया। वेदांता लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत दिवाला समाधान योजना को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 10 अगस्त, 2023 को अनुमोदित किया। तदनुसार, आईआईएफसीएल को ₹14.93 करोड़ की अग्रिम राशि तथा ₹79.32 करोड़ के डिबेंचर प्राप्त हुए। इन डिबेंचरों पर ₹1,769.63 लाख की राशि का प्रावधान किया गया।

19. 31 मार्च 2026 तक निवेश एवं प्रतिभूति प्राप्ति का प्रकटीकरण:

(₹ लाख में)

विवरण		विगत 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	5 वर्ष से पहले लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर	8 साल से पहले जारी किए गए प्रतिभूति रसीदें
(i)	बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य अंतर्निहित	73,254.54	12,160.01	-
	(i) धारित प्रावधान हेतु	-	-	-
(ii)	अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों / गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य अंतर्निहित के रूप में	-	-	-
	(ii) प्राप्ति धारित प्रावधान हेतु	-	-	-
कुल (i) + (ii)		73,254.54	-	-

20. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर व्यय से संबंधित प्रकटीकरण

(क) सीएसआर व्यय में सम्मिलित विभिन्न व्यय मदों का विवरण (ब्रेक–अप): (₹ लाख में)

क्र. सं.	संगठन का नाम	परियोजना का विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
01	ज़िला प्रशासन चांगलांग, अरुणाचल प्रदेश सरकार	अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग स्थित नयांग गाँव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में विद्यालय भवन का निर्माण।	-	124.66
02	ज़िला प्रशासन, मयूरभंज, ओडिशा	ओडिशा के मयूरभंज में नशामुक्ति एवं महिला सशक्तिकरण केंद्र की स्थापना।	125.00	-
03	ज़िला प्रशासन, मयूरभंज, ओडिशा	अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में 4 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण।	676.81	-
04	जिला परिषद, धौलपुर (राजस्थान)	राजस्थान के धौलपुर में 50 डिजिटल संविधान घरों (डीएसजी) की स्थापना।	292.71	-
05	मध्य प्रदेश विज्ञान परिषद और तकनीकी	मध्य प्रदेश के गुना स्थित राजकीय विद्यालयों में 10 स्मार्ट कक्षाओं (ई-पाठशाला) की स्थापना।	43.00	-
06	समृद्ध ग्राम्य अभियान सोसाइटी	राजस्थान के भरतपुर में हथोड़ी बावड़ी (बावरी) का जीर्णोद्धार।	99.00	-
07	यूसीएसआरए* में स्थानांतरित		2,817.94	2,472.93
	कुल		**4,054.46**	**2,597.59**

*चूँकि यह राशि प्रगतिशील परियोजनाओं की है, इसलिए इसे 30.04.2026 को व्यय हेतु शेष सीएसआर लेखा में अंतरित कर दिया गया है (पिछले वर्ष 30.04.2025 को)।

ख) सीएसआर व्यय के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरणः

1. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय कुल राशि ₹1,236.52 लाख

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष			31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		
	नकद में भुगतान किया गया	नकद में भुगतान होना अभी बाकी है	कुल	नकद में भुगतान किया गया	नकद में भुगतान होना अभी बाकी है	कुल
(i) किसी आस्ति का निर्माण/ अधिग्रहण'	1,236.52	2470.40	3706.92	124.66	2,165.42	2,290.08
(ii) उपरोक्त (i) के अलावा अन्य उद्देश्य पर	0	347.54	347.54	-	307.51	307.51
कुल	**1,236.52**	**2,817.94**	**4,054.46**	**124.66**	**2,472.93**	**2,597.59**

ii. वर्ष के अंत में कमी– शून्य (राशि ₹2,817.94 यूसीएसआरए को अंतरित कर दी गई है)

iii. विगत वर्ष की कुल कमी–शून्य

iv. कमी का कारण– लागू नहीं

v. सीएसआर गतिविधि की प्रकृति– आईआईएफसीएल निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति के अनुरूप से कंपनीअधिनियम, 2013की अनुसूची VII में दी गई गतिविधियां।

vi. संबंधित पक्षकार लेनदेन का विवरण जैसे प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट को अंशदान– शून्य

vii. यदि संविदागत दायित्व में प्रवेश करने से उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, तो वर्ष के दौरान प्रावधान में परिवर्तन अलग से दर्शाया जाएगा–₹ 4,827.90 लाख

21. गैर–बैंकिंग वित्तीय (नॉन–डिपॉजिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) कंपनीज प्रूडेंशियल नॉर्म्स (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2007 के पैराग्राफ 13 के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त जानकारी का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	
	बकाया राशि	अति देय राशि	बकाया राशि	अति देय राशि
देयता पक्षः				
(1) गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित ब्याज सहित, लेकिन भुगतान नहीं किया गयाः				
(क) डिबेंचर : प्रतिभूत : अप्रतिभूत (सार्वजनिक जमा के अर्थ में आने के अलावा)	1,138,545.40 2,600,617.20	-	11,39,336.50 2,208,325.60	-
(ख) आस्थगित ऋण	-	-	-	-
(ग) सावधि ऋण	1,794,548.99	-	1,523,874.70	-
(घ) अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और उधार	-	-	-	-
(ड़) वाणिज्यिक पत्र	-	-	-	-
(च) सार्वजनिक जमा	-	-	-	-
(छ) अन्य ऋण (अल्पकालिक बैंक ऋण)	3,032,750.10	-	2,044,826.98	-
(ज) सकल ब्याज	134,835.35		118,407.67	
(2) उपरोक्त का ब्रेक–अप (बकाया सार्वजनिक जमा सहित उस पर संचित ब्याज जिसे अभी तक नहीं चुकाया गया):				
(क) असुरक्षित डिबेंचरों के रूप में	-	-	-	-
(ख) आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचरों के रूप में अर्थात् ऐसे डिबेंचर जिनमें सुरक्षा के मूल्य में न्यूनता का अभाव हो	-	-	-	-
(ग) अन्य सार्वजनिक जमा	-	-	-	-

	राशि बकाया	
	31 मार्च 2026 को	31 मार्च 2025 को
आस्ति पक्ष :		
(3) ऋण और अग्रिम राशि का ब्रेक अप, जिसमें बिन प्राप्तियाँ शामिल हैं [नीचे (5) में शामिल नहीं है]:		
(क) प्रतिभूत	4,149,108.98	45,27,933.37
(ख) अप्रतिभूत	4,519,767.06	28,97,960.00
(4) पट्टे पर दी गई आस्ति और किराए पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य आस्तियों की गणना		
(i) विविध देनदारों के तहत पट्टा किराया सहित पट्टा आस्ति		
(क) वित्तीय पट्टा	-	-
(ख) प्रचालन पट्टा	-	-
(ii) विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉकः		
(क) किराए पर आस्ति	-	-
(ख) जब्त की गई आस्ति	-	-
(iii) एएफसी गतिविधियों के लिए गिने जाने वाले अन्य ऋण		
(क) ऋण जहां आस्ति को पुनः कब्जे में कर लिया गया है	-	-
(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य ऋण	-	-
(5) निवेश की विवरण		
वर्तमान निवेशः		
1. उद्धृतः		
(i) शेयरः (क) इक्विटी	-	-
(ख) अधिमान	-	-
(ii) डिबेंचर और बांड	-	-
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	-	-
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
(v) अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-
2. गैर–उद्धृतः		
(i) शेयरः (क) इक्विटी	5,176.02	5,176.02
(ख) अधिमान		
(ii) डिबेंचर और बांड	30,884.14	32,470.68
(iii) म्यूचुअल निधि की इकाइयाँ	1,148.84	2,326.62
(iv) सरकारी प्रतिभूतियां	727,710.89	6,29,880.00
(v) अन्य (इक्विटी शेयर पूंजी के विरुद्ध अग्रिम) (वेंचर कैपिटल यूनिटों में निवेश)	566.06	601.56
(vi) सुरक्षा रसीदों में निवेश	73,254.54	88,591.97
कुल	**95,07,616.53**	**81,84,940.27**

(6) उपर्युक्त (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित परिसंपत्तियों का ऋणग्राही समूह–वार वर्गीकरण:			
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2025 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	4,002,281.09	4,421,881.79	8,424,162.89
कुल	**4,002,281.09**	**4,421,881.79**	**8,424,162.89**
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2025 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	42,94,328.98	28,56,619.76	71,50,948.74
कुल	**42,94,328.98**	**28,56,619.76**	**71,50,948.74**

(7) अंश एवं प्रतिभूतियाँ (उद्धत और गैर अद्धत दोनों) में सभी निवेश (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशकसमूह–वार वर्गीकरण:			
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2026 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	-	818,475.18	818,475.18
श्रेणी	प्रावधानों की निवल राशि (31 मार्च 2025 तक)		
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत	कुल
1. संबंधित पक्ष			
(क) सहायक कंपनियां	-	-	-
(ख) एक ही समूह में कंपनियां	-	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्ष	-	-	-
2. संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	-	736,986.94	736,986.94

(8) अन्य जानकारी		
विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
(i) सकल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबंधित पक्ष		
(ख) संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	112,490.13	209,941.52
(ii) निवल अनर्जक आस्तियां		
(क) संबंधित पक्ष		
(ख) संबंधित पक्षों के अतिरिक्त	17,603.84	57,293.35
(iii) कर्ज चुकाव में अर्जित आस्ति		

22. भारतीय रिजर्व बैंक (एनबीएफसी–स्केल आधारित विनियम) दिशानिर्देश, 2023 दिनांक 19.10.2023 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण

22.1 पूजी (होल्डिंग कंपनी)

विवरण	31 मार्च 2026 तक	31 मार्च 2025 तक
सीआरएआर (%)	20.53%	23.44%
सीआरएआर–टियर I पूंजी (%)	19.28%	22.19%
सीआरएआर–टियर II पूंजी (%)	1.25%	1.25%
टियर II पूंजी के रूप में संकलित अधीनस्थ ऋण की राशि	-	-
शाश्वत ऋण साधनों के निर्गम से संकलित राशि	-	-

22.2 निवेश

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
1	निवेश का मूल्य		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	838,740.50	759,046.85
(क)	भारत में	838,740.50	759,046.85
(ख)	भारत के बाहर	-	-
(ii)	मूल्यह्रास के प्रावधान		
(क)	भारत में	20,265.32	22,059.91
(ख)	भारत के बाहर	-	-
(iii)	निवेश का निवल मूल्य	818,475.18	736,986.94
(क)	भारत में	818,475.18	736,986.94
(ख)	भारत के बाहर	-	-
2	निवेश के मूल्यह्रास की दिशा में धारित प्रावधानों में उतार–चढ़ाव		
(i)	प्रारंभिक शेष	22,059.91	23,654.75
(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	-	-
(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते में डालना / प्रतिलेखन	1,794.59	1,594.83
(iv)	अंतिम शेष	20,265.32	22,059.91

22.3 व्युत्पन्न

व्युत्पन्न में जोखिमः

गुणात्मक प्रकटीकरण

एनबीएफसी के लिए यह आवश्यक है कि वे डेरिवेटिव से संबंधित अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों का विवरण दें, जिसमें विशेष रूप से डेरिवेटिव के उपयोग की सीमा, उनसे जुड़े जोखिमों तथा उनके द्वारा पूरे किए जाने वाले व्यावसायिक उद्देश्यों का उल्लेख हो। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के दिशानिर्देशों (यथासंशोधित) के अनुपालन में इसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

(क) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों से उत्पन्न मुद्रा एवं ब्याज दर संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है। कंपनी ने हेजिंग नीति लागू की है, जो संसाधन एवं कोषागार नीति का एक हिस्सा है तथा जिसे निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया है। कंपनी के डेरिवेटिव लेनदेन इस नीति द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसमें अंतर्निहित देयताओं के अनुरूप हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले वित्तीय साधनों का विवरण दिया गया है।

(ख) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों से उत्पन्न ब्याज दर एवं मुद्रा संबंधी जोखिमों (बाजार जोखिम) की हेजिंग तथा उन्हें कम करने के उद्देश्य से डेरिवेटिव लेनदेन करता है।

(ग) आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों से उत्पन्न विनिमय दर एवं ब्याज दर संबंधी जोखिमों की हेजिंग के लिए ही डेरिवेटिव लेनदेन करता है, किसी अन्य उद्देश्य से नहीं। निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन की शर्तें संबंधित अंतर्निहित देयताओं की शर्तों के अनुरूप रखी जाती हैं। हेजिंग के प्रारंभ में शर्तों के मिलान की अवधारणा के माध्यम से इस प्रभावशीलता का निर्धारण किया जाता है।

(घ) आईआईएफसीएल डेरिवेटिव लेनदेन की स्थिति तथा उनके बाजार मूल्यांकन (एमटीएम) की जानकारी मासिक आधार पर वरिष्ठ प्रबंधन को और अर्धवार्षिक आधार पर निदेशक मंडल को देता है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल के संसाधन एवं कोषागार सलाहकारों द्वारा एमटीएम की स्वतंत्र निगरानी भी अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है।

(ङ) आईआईएफसीएल की बही-खातों में विनिमय पर कारोबार किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव की राशि शून्य है।

(च) आईआईएफसीएल अपनी विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिम स्थितियों की हेजिंग के लिए क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप करता है। मात्रात्मक प्रकटीकरण में दर्शाए गए आँकड़ों को अलग-अलग वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि मूलधन एवं ब्याज के नकदी प्रवाह से संबंधित सौदे समेकित आधार पर दर्ज किए जाते हैं।

(छ) हेजिंग एवं गैर-हेजिंग लेनदेन के लेखांकन, आय, प्रीमियम एवं छूट की मान्यता, बकाया अनुबंधों के मूल्यांकन, प्रावधान, संपार्श्विक तथा ऋण जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित लेखांकन नीति का प्रकटीकरण लेखांकन नीति 1(क)(5.2) में किया गया है।

(ज) निदेशक मंडल की प्रबंधन एवं निवेश समिति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित संसाधन एवं कोषागार नीति के अनुसार, आईआईएफसीएल कुल एक्सपोज़र के 65–70% तक अपनी जोखिम स्थिति को हेज करके रखेगा। इसके अतिरिक्त, अग्रिम प्रीमियम से होने वाली बचत को समायोजित करने के बाद खुली स्थिति से उत्पन्न विनिमय दर उतार-चढ़ाव का अंतर किसी भी समय कंपनी की निवल संपत्ति के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो के आधार पर रुपये का मूल्य 5% या उससे अधिक गिरता है, तो आईआईएफसीएल अपनी जोखिम स्थिति का लगभग 75% हेज करके रखेगा।

जोखिम प्रबंधन संरचना

(क) आईआईएफसीएल निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढाँचे के अनुसार जोखिमों का प्रबंधन करता है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल की संसाधन एवं कोषागार नीति को निदेशक मंडल की प्रबंधन एवं निवेश समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष अनुमोदित किया जाता है। ये नीतियाँ एवं ढाँचे मार्गदर्शक मानदंड प्रदान करते हैं, जिनके आधार पर आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा ऋणों के कारण उत्पन्न मुद्रा जोखिम के प्रबंधन हेतु निर्णय लेता है।

(ख) आईआईएफसीएल ने व्यावसायिक परिचालनों में जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए निदेशक मंडल स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति तथा परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ समिति) का भी गठन किया है। एएलसीओ समिति तरलता एवं ब्याज दर संबंधी जोखिमों की निगरानी करती है, जिसमें परिसंपत्तियों से प्राप्तियों तथा ऋण चुकौती संबंधी दायित्वों की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक तरलता स्थिति का आवधिक विश्लेषण शामिल है। डेरिवेटिव लेनदेन में देयताओं की हेजिंग के लिए क्रॉस-करेंसी स्वैप तथा मुद्रा स्वैप शामिल हैं। ये लेनदेन हेजिंग के उद्देश्य से किए जाते हैं, न कि व्यापार या सट्टेबाजी के उद्देश्य से।

संबंधित जोखिमों के प्रकार

(क) जोखिमों के प्रकार

(I) ऋण जोखिम: ऋण जोखिम में उधारकर्ता की ऋण गुणवत्ता में गिरावट के कारण होने वाली हानि तथा ऋण या अग्रिम के अंतर्गत संविदात्मक पुनर्भुगतान करने में उधारकर्ता की चूक का जोखिम शामिल है। आईआईएफसीएल ने अवसंरचना क्षेत्र में ऋण प्रदान करने से संबंधित ऋण जोखिम के प्रबंधन हेतु एकीकृत जोखिम प्रबंधन ढाँचा लागू किया है।

(II) बाजार जोखिम: बाजार जोखिम से तात्पर्य किसी वित्तीय साधन या वित्तीय साधनों के पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य (कीमत) में प्रतिकूल परिवर्तन के कारण होने वाली हानि के जोखिम से है। बाजार जोखिम में मुद्रा जोखिम तथा ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर में किसी भी परिवर्तन या उतार-चढ़ाव के कारण मुद्रा जोखिम उत्पन्न होता है। ब्याज दर जोखिम मुख्यतः समय के साथ ब्याज दरों में होने वाले परिवर्तनों से उत्पन्न होता है। आईआईएफसीएल की व्यावसायिक गतिविधियों के अंतर्गत बाजार जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम विद्यमान हैं।

(III) तरलता जोखिम: तरलता जोखिम वह जोखिम है, जिसमें संस्था उचित लागत पर धन उधार लेकर वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने या लेनदेन निष्पादित करने में असमर्थ रहती है। इसमें बाजार तरलता जोखिम तथा वित्तपोषण तरलता जोखिम शामिल हो सकते हैं। आईआईएफसीएल पर्याप्त नकदी एवं विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ बनाए रखकर तथा पर्याप्त संयुक्त ऋण सीमाओं के माध्यम से वित्तपोषण की उपलब्धता सुनिश्चित करके तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है।

(IV) परिचालन जोखिम: परिचालन जोखिम से तात्पर्य अपर्याप्त प्रणालियों एवं नियंत्रणों, सूचना प्रणाली की कमियों, मानवीय त्रुटियों या प्रबंधन की विफलता के कारण होने वाली हानि के जोखिम से है। आईआईएफसीएल की परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य इन जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन करना है।

(ख) स्ट्रेस टेस्टः

आईआईएफसीएल विदेशी मुद्रा विनिमय दरों तथा ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली वित्तीय हानि के जोखिम का प्रबंधन करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन करता है।

निम्नलिखित परिदृश्यों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा ऋण पोर्टफोलियो पर किए गए दबाव परीक्षणों तथा आय पर उनके संभावित प्रभाव का विवरण इस प्रकार है:

मान्यताएँ

31.03.2026 को लागू संदर्भ विनिमय दर (आधार स्थिति) के आधार पर रुपये के मूल्य में प्रतिशत गिरावट की मान्यता ली गई है। तदनुसार, विभिन्न शॉक परिदृश्यों के अंतर्गत मूल्यह्रास के बाद की विनिमय दरें निम्नानुसार हैं:

विनिमय दर यानी प्रति आईएनआर		आघात परिदृश्य		
	बेस केस	आधारभूत	मध्यम	जटिल
	आरबीआई संदर्भ दर (31.03.2026)	5%	10%	20%
यूएसडी	94.6543	99.3870	104.1197	113.5852
ईयूआर	109.0064	114.4567	119.9070	130.8077
जेपीवाई	0.5925	0.6221	0.6518	0.7110

बेंचमार्क दरें (एसओएफआर/यूरिबोर) तथा विभिन्न आघात परिदृश्यों के अंतर्गत दरें निम्नानुसार हैं:

बेंचमार्क ब्याज दर	आघात परिदृश्य			
	बेस केस	आधारभूत	मध्यम	जटिल
	बेंचमार्क ब्याज दरें (31.03.2026)	0.5%	1.00%	2.00%
एसओएफआर	3.86%	4.36%	4.86%	5.86%
यूरिबोर	2.48%	2.98%	3.48%	4.48%

तनाव परीक्षण के उद्देश्य से, सीगल विकल्पों के माध्यम से मुद्रा जोखिम से बचाव किए गए हिस्से को असुरक्षित माना गया है, क्योंकि इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों से सीमित सुरक्षा उपलब्ध है।

पूर्ण मुद्रा स्वैप के माध्यम से मुद्रा जोखिम से बचाव किए गए पोर्टफोलियो को भारतीय रुपये के अवमूल्यन से अप्रभावित माना गया है।

विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों पर ब्याज दर जोखिम के तनाव परीक्षण के लिए, आघात परिदृश्यों में ब्याज दर के बेंचमार्क घटक में अपेक्षित प्रतिशत वृद्धि को दर्शाया गया है। ब्याज दर के प्रसार घटक को स्थिर माना गया है।

ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभाव केवल असुरक्षित राशि और पीओएस के माध्यम से जोखिम से बचाव की गई राशि पर माना गया है।

परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन, आधार परिदृश्य की तुलना में आघात परिदृश्यों के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय या आय में कमी के रूप में किया गया है।

भारतीय रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव

विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती, दोनों पर पड़ता है। हालाँकि, पूर्ण मुद्रा स्वैप के माध्यम से जोखिम से बचाव किए गए उधार विदेशी विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से अप्रभावित रहते हैं।

1. असुरक्षित और पीओएस के माध्यम से जोखिम से बचाव किए गए उधारों पर ब्याज भुगतान पर भारतीय रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव

(₹ लाख में)

आघात परिदृश्य	आधारभूत	मध्यम	जटिल
	5%	10%	20%
यूएसडी	22.25	44.50	88.99
ईयूआर	2.69	5.38	10.75
जेपीवाई	1.29	2.59	5.17
कुल	**26.23**	**52.46**	**104.92**

2. असुरक्षित बकाया मूलधन पर भारतीय रुपये के मूल्यह्रास का प्रभावः

(₹ करोड़)

आघात परिदृश्य	आधारभूत	मध्यम	जटिल
	5%	10%	20%
यूएसडी	79.66	159.32	318.64
ईयूआर	76.52	153.04	306.09
जेपीवाई	152.39	304.78	609.56
कुल	**308.57**	**617.14**	**1234.29**

3. भारतीय रुपये के मूल्यह्रास का कुल प्रभाव (क + ख):

(₹ करोड़)

आघात परिदृश्य	आधारभूत	मध्यम	जटिल
	5%	10%	20%
यूएसडी	101.91	203.82	407.64
ईयूआर	79.21	158.42	316.84
जेपीवाई	153.68	307.36	614.73
कुल	**334.80**	**669.60**	**1339.21**

असुरक्षित एवं आंशिक रूप से बचाव की गई जोखिमगत स्थिति पर बेंचमार्क ब्याज दरों (एसओएफआर/यूरिबोर) में परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड)

आघात परिदृश्य	आधारभूत	मध्यम	जटिल
ब्याज दर में परिवर्तन	0.50%	1.00%	2.00%
यूएसडी	49.76	99.51	199.03
ईयूआर	9.31	18.61	37.22
जेपीवाई	17.91	35.81	71.62
कुल	**76.97**	**153.94**	**307.87**

31.03.2026 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों पर रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण होने वाला कुल अनुमानित प्रभाव आधार परिदृश्य में ₹ 334.80 करोड़, मध्यम परिदृश्य में ₹ 669.60 करोड़ तथा गंभीर परिदृश्य में ₹ 1,339.21 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा ऋणों पर ब्याज दरों में क्रमशः 0.5% (आधार परिदृश्य), 1.0% (मध्यम परिदृश्य) तथा 2.0% (गंभीर परिदृश्य) की वृद्धि की मान्यता के अंतर्गत अनुमानित प्रभाव क्रमशः ₹ 76.97 करोड़, ₹ 153.94 करोड़ तथा ₹ 307.87 करोड़ है।

अग्रिम किराया समझौता/ब्याज पर अदला बदली

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(i)	कल्पित मूलधन का स्वैप करार	994,817.02	956,768.00
(ii)	हानियाँ जो उपगत होंगी यदि प्रतिपक्ष समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे	-	-
(iii)	स्वैप से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम का संकेंद्रण*	Refer *	Refer *
(iv)	स्वैप बही का उचित मूल्य	174,673.79	135,382.74

*कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वैप अनुबंध करती है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप अनुबंध, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति में निर्धारित ऋण जोखिम सीमा के भीतर हैं।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ लाख में))

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न	मुद्रा व्युत्पन्न	ब्याज दर व्युत्पन्न
(i)	व्युत्पन्न (काल्पनिक मूलधन राशि)	994,817.02	994,817.02	956,768.00	956,768.00
	बचाव व्यवस्था के लिए	994,817.02	994,817.02	956,768.00	956,768.00
(ii)	बाजार से बाजार स्थितियां (1)	174,673.79	174,673.79	135,382.74	135,382.74
	क. आस्ति (+)	174,673.79	174,673.79	136,327.97	136,327.97
	ख. देयताएं (–)	-	-	945.23	945.23
(iii)	ऋण एक्सपोजर	-	-	-	-
(iv)	बिना बचाव वाले एक्सपोजर	5,29,819.82	5,29,819.82	413,122.10	413,122.10

23.4 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(i)	खातों की संख्या	-	-
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल	-	-
(iii)	समस्त प्रतिफल	-	-
(iv)	पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	-	-
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल (लाभ)/हानि	-	-

23.5 बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(i)	बेचे गए खातों की संख्या	2	-
(ii)	कुल बकाया	10,759.00	-
(iii)	कुल प्राप्त प्रतिफल	3,973.00*	-

*इसमें बकाया मूलधन शामिल है तथा ब्याज एवं अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।

23.6 आस्ति देयता प्रबंधनः

31 मार्च 2026 को आस्ति और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का प्रतिमान

(₹ लाख में)

विवरण	1 दिन से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन	1 महीने से 2 महीने से ज्यादा	2 महीने से 3 महीने से ज्यादा	3 महीने से 6 महीने से ज्यादा	6 महीने से 1 साल से ज्यादा	1 साल से 3 साल से ज्यादा	3 साल से 5 साल से ज्यादा	5 साल से ज्यादा	कुल
जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	-	56.00	8,379.19	51,500.96	91,237.63	139,630.24	439,092.68	1,841,511.02	1,591,122.37	4,540,863.39	8,703,393.47
निवेश	-	-	-	-	10,411.97	10,411.97	352,477.54	-	88,760.00	638,950.89	1,101,012.37
उधारियाँ / उधारी	-	-	-	-	-	-	-	917,879.56	156,000.00	2,286,665.84	3,360,545.40
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	-	-	4,503.96	7,158.87	34,659.03	22,652.20	70,229.01	294,660.67	485,374.42	875,310.84	1,794,548.99
बैंकों से उधारियाँ	33,137.84	382,495.39	-	326,826.88	538,351.64	167,319.00	10,411.97	1,797,110.19	107,327.15	-	3,362,980.06

31 मार्च 2025 की स्थिति में परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की कुछ मदों की परिपक्वता रूपरेखाः

(₹ लाख में)

विवरण	1 दिन से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30/31 दिन	1 महीने से 2 महीने से ज्यादा	2 महीने से 3 महीने से ज्यादा	3 महीने से 6 महीने से ज्यादा	6 महीने से 1 साल से ज्यादा	1 साल से 3 साल से ज्यादा	3 साल से 5 साल से ज्यादा	5 साल से ज्यादा	कुल
जमा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अग्रिम	2.54	922.54	6,003.60	27,276.37	20,431.83	62,774.96	511,689.34	1,105,638.62	1,345,357.00	4,347,874.79	7,427,971.59
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629,880.00	629,880.00
उधारियाँ / उधारी	-	-	-	-	-	-	791.10	348,251.71	569,627.85	2,086,665.84	3,005,336.50
विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देनदारियाँ	-	-	9,519.52	5,618.45	30,007.66	11,007.07	57,207.53	240,253.68	260,874.80	909,385.98	1,523,874.69
बैंकों से उधारियाँ	47,625.48	-	74,700.00	742,548.00	746,000.00	-	-	314,995.35	461,283.75	-	2,387,152.58

23.7 एक्सपोजर

23.7.1 रियल एस्टेट क्षेत्र में एक्सपोजर

31 मार्च 2026 (पिछले वर्ष शून्य) तक कंपनी का रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश नहीं है।

23.7.2 पूंजी बाजार में एक्सपोजरः

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से कॉर्पोरेट ऋण में निवेश नहीं किया गया है;	-	-
(ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–उन्मुख म्युचुअल निधि की इकाइयों में निवेश के लिए स्पष्ट आधार पर अग्रिम;	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्व ारा प्रतिभूत सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम, जहां प्राथमिक सुरक्षा शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचर / इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल निधि की इकाइयों के अलावा 'अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है;	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकर्स को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों पर कंपनियों को दिए गए ऋणों को कम करना;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजी निधियों में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	566.06	601.56

23.8 अतिरिक्त प्रकटीकरण:प्रावधान और आकस्मिकताएं

(₹ लाख में)

क्र.सं.	लाभ और हानि के वितरण में परिलक्षित प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(i)	एनपीए के लिए प्रावधान	94,886.30	152,648.17
(ii)	आयकर का प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	60,438.94	66,437.45
(iii)	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान (पुनर्गठित खातों और एसडीआर खातों सहित)	150,970.48	122,296.51

23.9 अग्रिमों का संकेंद्रण, एक्सपोजर और एनपीए:

(i) अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	4,518,615.12	4,146,444.08
एनबीएफसी के कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	52.12%	55.84%

(ii) एक्सपोजर का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल एक्सपोजर	4,518,615.12	4,146,444.08
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत	52.12%	55.84%

(iii) एनपीए का संकेंद्रण

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
शीर्ष चार एनपीए खातों में कुल एक्सपोजर	105,204.98	131,066.91

(iv) क्षेत्र–वार एनपीए

क्र.सं.	क्षेत्र	एनपीए का सेक्टर % उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में	
		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	-	-
2	एमएसएमई	-	-
3	कॉर्पोरेट उधारकर्ता	1.30%	2.83%
4	सेवाएं	-	-
5	अप्रतिभूत व्यक्तिगत ऋण	-	-
6	ऑटो ऋण	-	-
7	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	-

(v) एनपीए की आवाजाही

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(i)	निवल एनपीए से सकल अग्रिम (%)		0.21%	0.79%
(ii)	एनपीए में उतार–चढाव (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	223,950.93	3,06,997.59
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड/प्रत्यावर्तन	-	23,678.72
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	111,460.80	120,734.79
	(घ)	अंतिम शेष	112,490.13	209,941.52
(iii)	एनपीए में उतार–चढाव			
	(क)	प्रारंभिक शेष	88,831.06	1,12,395.00
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड/प्रत्यावर्तन	-	11,666.75
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	42,422.69	66,768.40
	(घ)	अंतिम शेष	46,408.37	57,293.35
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार–चढाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	135,119.86	1,94,603.28
	(ख)	वर्ष के दौरान जोड/प्रत्यावर्तन	(20,900.60)	9,123.17
	(ग)	वर्ष के दौरान कटौती/बट्टे खाते में डालना	48,137.51	51,078.28
	(घ)	अंतिम शेष	66,081.76	152,648.17

23.10 ग्राहकों की शिकायत

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष
(क)	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	149	223
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	149	223
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	-	-

23.11 अतिरिक्त प्रकटीकरण

क्र.सं.	प्रकटीकरण	टिप्पणी
(i)	अन्य वित्तीय नियामक से प्राप्त पंजीकरण / लाइसेंस / प्राधिकरण	कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से प्राप्त कॉर्पोरेट पहचान संख्या U67190DL2006GOI144520
(ii)	क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और साल के दौरान रेटिंग का माइग्रेशन	कंपनी द्वारा जारी किए गए घरेलू बॉन्ड्स को विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा AAA (स्टेबल) रेटिंग प्रदान की गई है। वर्तमान वर्ष 2025–25 के दौरान रेटिंग में कोई भी माइग्रेशन (परिवर्तन) नहीं हुआ है।
(iii)	किसी नियामक द्वारा लगाया गया दंड, यदि कोई हो,	शून्य
(iv)	सूचना अर्थात क्षेत्र, देश और संयुक्त उद्यम भागीदार	
	(क) संयुक्त उद्यम	कोई नहीं
	(ख) विदेशी सहायक कंपनियां	आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी लंदन, यूनाइटेड किंगडम से संचालित होती है और भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वित्तपोषण करती है।

23.12 पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

क्र. सं.	पुनर्गठन का प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत	एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र	अन्य (₹ लाख में)					कुल (₹ लाख में)				
	आस्ति वर्गीकरण		कुल	कुल	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	योग	मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	योग
	विवरण													
1	01.04.2025 को पुनर्गठित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या			2.00	-	-	-	2.00	2.00	-	-	-	2.00
		बकाया राशि			22,177.56	-	-	-	22,177.56	22,177.56	-	-	-	22,177.56
		उस पर प्रावधान			1,520.71	-	-	-	1,520.71	1,520.71	-	-	-	1,520.71
2	31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान किया गया नवीन पुनर्गठन	उधारकर्ताओं की संख्या			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वे पुनर्गठित मानक अग्रिम, जिन पर वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार लागू नहीं रहता तथा इसलिए 31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि में उन्हें पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की संख्या												
		बकाया राशि			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	31 मार्च 2026 को समाप्त अवधि के दौरान पुनर्गठित खातों का राइट–ऑफ / पूर्व भुगतान	उधारकर्ताओं की संख्या			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि												
		उस पर प्रावधान			1.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	1.00
7	31 मार्च 2026 को पुनर्गठित खाते	उधारकर्ताओं की संख्या			14,017.13	-	-	-	14,017.13	14,017.13	-	-	-	14,017.13
		बकाया राशि			800.35	-	-	-	800.35	800.35	-	-	-	800.35
		उस पर प्रावधान			1.00	-	-	-	1.00	1.00	-	-	-	1.00

23.13 विदेशी आस्ति (विदेश में संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के लिए)

संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनी का नाम	संयुक्त उद्यम में अन्य भागीदार	देश	कुल आस्ति ($ में राशि)
आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड	कोई नहीं	यूनाइटेड किंगडम	शून्य, आईआईएफसीएल के पास आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड की कोई विदेशी आस्ति नहीं है।

24. एनबीएफसी पर भारतीय रिजर्व बैंक के पैमाने आधारित विनियमन के अनुसार प्रकटीकरणः

क) रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेशः आईआईएफसीएल का रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश टिप्पणी 1 (ख) 23.7.1 में प्रकट किया गया है।

ख) पूंजी बाजार में निवेशः आईआईएफसीएल का पूंजी बाजार में निवेश टिप्पणी 1 (ख) 23.7.2 में प्रकट किया गया है।

ग) खंडवार जोखिम

क्षेत्र	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
	कुल जोखिम (जिसमें तुलन पत्र एवं तुलन पत्र के बाहर का जोखिम शामिल है)	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल जोखिम के अनुपात में सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल जोखिम (जिसमें तुलन पत्र एवं तुलन पत्र के बाहर का जोखिम शामिल है)	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल जोखिम के अनुपात में सकल एनपीए का प्रतिशत
कॉरपोरेट क्षेत्र	8,775,730.71	112,490.13	1.29%	7,528,532.50	209,941.52	2.79%

*इसमें बकाया शेष राशि और बकाया ऋण पत्र शामिल है

घ) इंट्रा–ग्रुप एक्सपोजरः आईआईएफसीएल के इंट्रा ग्रुप एक्सपोजर का प्रकटीकरण टिप्पणी 1 (ख) 6 (ग) में किया गया है।

ङ) **असुरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजरः** आईआईएफसीएल के असुरक्षित विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रकटीकरण टिप्पणी 1 (बी) 15 (बी) में किया गया है।

च) लागू एनबीएफसी द्वारा पार की गई एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण।

क) 31.03.2026 तक सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची– शून्य

ख) 31.03.2026 तक सीमा से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची– शून्य

ग) 31.03.2026 तक सीमा से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची– शून्य

घ) 31.03.2026 तक सीमा से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची शून्य

छ) संबंधित पार्टी प्रकटीकरणः आईआईएफसीएल के संबंधित पार्टी प्रकटीकरण का प्रकटीकरण टिप्पणी 1 (बी) 6 में किया गया है।

ज) शिकायतों का प्रकटीकरणः आईआईएफसीएल की प्रकटीकरण शिकायतों का प्रकटीकरण टिप्पणी 1 (बी) 23.10 में किया गया है। इसके अलावा, शिकायतों के आधारों की संख्या को अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

छ) संविदा का उल्लंघनः शून्य

24. पूंजी प्रबंधन

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 1 के पैरा 134–136 की आवश्यकताओं के अनुसार पूंजी प्रबंधन के प्रकटीकरण के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि आईआईएफसीएल एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–अवसंरचना वित्त कंपनी (एनबीएफसी–आईएफसी) होने के नाते, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों के अनुसार पूंजी, जिसे स्वामित्व निधि कहा जाता है, बनाए रखने के लिए बाध्य है।

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश अनुसार–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा स्वीकार करने वाली कंपनी एवं जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार, स्वामित्व निधि से तात्पर्य चुकता इक्विटी पूंजी, अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय अधिमान शेयर, मुक्त आरक्षित निधियाँ, शेयर प्रीमियम खाते की शेष राशि तथा परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि पर उत्पन्न अधिशेष को दर्शाने वाली पूंजी आरक्षित निधियों से है। इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से सृजित आरक्षित निधियाँ शामिल नहीं हैं। इसमें से संचित हानियों की शेष राशि, अमूर्त परिसंपत्तियों का बही मूल्य तथा, यदि कोई हो, आस्थगित राजस्व व्यय घटाया जाता है।

भारत सरकार ने समय–समय पर आईआईएफसीएल में पूंजी निवेश किया है। इससे आईआईएफसीएल को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त, आईआईएफसीएल भारत

सरकार के निर्देशों के अधीन, लाभांश वितरण का निर्णय लेते समय पूंजी अर्थात् निवल स्वामित्व निधि पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखता है। रिपोर्टिंग वर्षों के दौरान पूंजी प्रबंधन से संबंधित उद्देश्यों, नीतियों अथवा प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

25. वित्त मंत्रालय के निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा 18 नवंबर, 2024 को जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के पूंजी पुनर्गठन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, सीपीएसई के लिए किसी भी मौजूदा कानूनी प्रावधान के अंतर्गत निर्धारित सीमा के अधीन, कर–पश्चात लाभ (पीएटी) का न्यूनतम 30: अथवा निवल संपत्ति का 4:, इनमें से जो भी अधिक हो, वार्षिक लाभांश के रूप में देना आवश्यक है।

इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने दिनांक 21 सितंबर, 2016 के पत्र के माध्यम से भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक कम–से–कम तीन वर्षों के लिए लाभांश भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया था। इसके पश्चात, आईआईएफसीएल ने दिनांक 19 सितंबर, 2019 के पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक लाभांश भुगतान से छूट देने का अनुरोध किया। आईआईएफसीएल के उक्त पत्रों के उत्तर की प्रतीक्षा है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या RBI/2021&22/59, DOR-ACC-REC-No-23/21-02-067/2021-22, दिनांक 24 जून, 2021 के अनुसार, किसी एनबीएफसी के लिए लाभांश घोषित करने हेतु यह न्यूनतम पात्रता शर्त है कि पिछले तीनों वर्षों में, जिसमें वह वित्तीय वर्ष भी शामिल है जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है, प्रत्येक वर्ष के अंत में निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनएनपीए) 6: से कम हों। उपर्युक्त पात्रता मानदंडों के अनुसार, आईआईएफसीएल लाभांश घोषित करने के लिए पात्र नहीं था। तदनुसार, आईआईएफसीएल ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लाभांश घोषित नहीं किया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के संबंध में, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने क्रमशः 28 मार्च, 2024 तथा 18 दिसंबर, 2024 को आयोजित बैठकों में भारत सरकार से लाभांश भुगतान से छूट प्रदान करने का अनुरोध करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। उक्त अनुरोध भारत सरकार को भेज दिया गया है। इस संबंध में आईआईएफसीएल के पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के संबंध में, आईआईएफसीएल के निदेशक मंडल ने 27 मार्च, 2026 को आयोजित बैठक में भारत सरकार से लाभांश भुगतान से छूट प्रदान करने का अनुरोध करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। उक्त अनुरोध भारत सरकार को भेज दिया गया है। इस संबंध में आईआईएफसीएल के पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है।

26. 27 मार्च, 2020 तथा 17 अप्रैल, 2020 को जारी कोविड–19 नियामकीय पैकेज संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 29 फरवरी, 2020 तक मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत सभी सावधि ऋणों की किस्तों के भुगतान पर तीन माह का स्थगन प्रदान करने की अनुमति दी थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण उत्पन्न कठिनाइयों को कम करने में ऋणकर्ताओं की सहायता करना था।

प्रारंभ में, 1 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 के बीच देय सभी किस्तों, जिनमें मूलधन एवa/अथवा ब्याज आदि शामिल थे, के भुगतान पर तीन माह का स्थगन प्रदान किया गया था। 22 मई, 2020 को आरबीआई ने इस स्थगन अवधि को तीन माह और बढ़ाकर 31 अगस्त, 2020 तक कर दिया। स्थगन अवधि के दौरान ऋण की बकाया राशि पर ब्याज अर्जित होता रहा। जिन खातों में स्थगन की सुविधा प्रदान की गई थी, उन सभी खातों की अतिदेय अवधि की गणना स्थगन अवधि के दौरान स्थिर रखी गई। ऋणदाताओं के लिए अपने ग्राहकों को यह सुविधा देने से पहले निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति लागू करना आवश्यक था। ऋणदाताओं ने स्थगन सुविधा प्रदान करने के लिए अलग–अलग तरीके अपनाए, जिनमें विकल्प चुनकर सुविधा प्राप्त करना (ऑप्ट–इन) अथवा विकल्प न चुनने पर सुविधा लागू होना (ऑप्ट–आउट) शामिल था।

आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, आईआईएफसीएल ने मार्च 2020 से अगस्त 2020 की अवधि के लिए पात्र सावधि ऋण खातों में ब्याज एवं मूलधन के भुगतान पर स्थगन सुविधा प्रदान की। ऐसे मामलों में सुविधा के अंतर्गत सृजित बकाया राशि का पुनर्भुगतान मूल सावधि ऋण की निर्धारित पुनर्भुगतान अवधि के भीतर किया जाना निर्धारित किया गया।

30 सितंबर, 2020 को समाप्त अवधि के दौरान, आईआईएफसीएल ने स्थगन सुविधा वाले ऋण खातों में आस्थगित ब्याज आय को मान्यता दी, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 जुलाई, 2015 के निर्देश संख्या डीसीबी-बीपीडी (पीसीबी) MC No-12/09.14.000/2015–16 के अनुसार इसे ऋण पुनर्गठन नहीं माना। आईआईएफसीएल ने 12 नवंबर, 2020 के पत्र के माध्यम से आरबीआई से यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया कि आईआईएफसीएल द्वारा ब्याज आय की मान्यता नियामकीय प्रावधानों के अनुरूप है। इस संबंध में आरबीआई के उत्तर की प्रतीक्षा है।

परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2021 तक आईआईएफसीएल ने स्थगन सुविधा वाले ऋण खातों से संबंधित स्थगन अवधि की ₹45,914.50 लाख की अप्राप्त ब्याज आय की मान्यता को वास्तविक वसूली होने तक सावधानीपूर्वक स्थगित रखा। 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान आईआईएफसीएल को ₹5,747.07 लाख का पुनर्भुगतान प्राप्त हुआ।

इसके अतिरिक्त, कोविड–19 नियामकीय पैकेज की समाप्ति के बाद परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं आय की मान्यता के संबंध में आरबीआई द्वारा 07.04.2021 को जारी परिपत्र के निर्देशों के अनुसार, बैंकों को स्थगन अवधि अर्थात् 01.03.2020 से 31.08.2020

के दौरान कार्यशील पूंजी सुविधाएँ प्राप्त करने वाले उधारकर्ताओं सहित सभी उधारकर्ताओं से वसूल किए गए 'ब्याज पर ब्याज' को वापस करना अथवा समायोजित करना था। यह निर्देश उन सभी उधारकर्ताओं पर लागू था, जिन्होंने स्थगन सुविधा का पूर्ण, आंशिक अथवा बिल्कुल भी लाभ नहीं लिया था।

इन निर्देशों के अनुपालन में, विभिन्न ऋण सुविधाओं के लिए वापस की जाने अथवा समायोजित की जाने वाली राशि की गणना की पद्धति भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने अन्य उद्योग प्रतिभागियोंधनिकायों के परामर्श से अंतिम रूप दी, ताकि सभी ऋणदाता संस्थान इसे अपना सकें। तदनुसार, आईबीए ने 19.04.2021 के अपने पत्र के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अंतिम रूप दी गई गणना पद्धति की जानकारी दी। इसके अनुसार, आईआईएफसीएल ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹2,500 लाख की अनुमानित 'ब्याज पर ब्याज' आय को मान्यता नहीं दी। उक्त ब्याज आय का लाभ अभी तक ऋणकर्ताओं को प्रदान नहीं किया गया है।

27. कर व्यय तथा लेखांकन लाभ का सामंजस्य (इंड एएस 12)

कर व्यय तथा कर–पूर्व लाभ पर भारत की लागू कॉर्पोरेट कर दर के गुणनफल के बीच सामंजस्य निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025
कर पूर्व लाभ	207,421.15	329,580.97
सांविधिक आयकर दर	25.17%	25.17%
अपेक्षित आयकर व्यय	52,203.75	82,948.94
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
आयकर अधिनियम की धारा 36(1) के तहत कटौती का लाभ	-	-
निवल प्रावधान अस्वीकृत	(1,960.65)	(14,330.24)
आयकर की गैर–अनुमति	20,930.16	(7,094.76)
विगत वर्ष के आयकर	(1,889.50)	14.94
अन्य	(6,887.80)	11,362.82
आस्थगित कर	(1,957.01)	(6,464.25)
कर व्यय	**60,438.94**	**66,437.45**

28. वित्तीय परिसंपत्तियों और दायित्व का उचित मूल्य मापन पदानुक्रमजिसे परिशोधन लागत (एमोर्टाइज्डकॉस्ट)/ उचित मूल्य पर मापा गया है:

28.1 उचित मूल्य पदानुक्रम

स्तर 1 – समान परिसंपत्तियों या दायित्वों के लिए सक्रिय बाजारों में उपलब्ध उद्धृत मूल्य।

स्तर 2 – स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा ऐसे इनपुट जो परिसंपत्ति या दायित्व के लिए प्रत्यक्ष रूप से (जैसे, कीमत के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (जैसे, बाजार मूल्यों से प्राप्त) देखे जा सकते हैं।

स्तर 3 – ऐसे इनपुट जो परिसंपत्ति या दायित्व के लिए बाजार के प्रेक्षणीय आंकड़ों पर आधारित नहीं होते (अप्रेक्षणीय इनपुट)।

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष		
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्ति:			
परिशोधन लागत	-	-	10,249,470.77
एफवीटीपीएल	-	73,254.54	192,183.53
वित्तीय देयता:			
परिशोधन लागत	-	-	8,706,480.82

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय आस्तिः			
परिशोधन लागत	-	-	84,41,741.65
एफवीटीपीएल	-	223,974.71	18,514.97
वित्तीय देयताः			
परिशोधन लागत	-	-	7,042,746.00

29.2 परिशोधन लागत (एमोर्टाइज्डकॉस्ट) पर मापी गई वित्तियोंपरिसंपत्तियों और दायित्वों का उचित मूल्यः

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2026		31.03.2025	
	वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय आस्ति	10,514,908.85	10,514,908.85	8,684,231.08	8,684,231.08
वित्तीय देयताएं	8,706,480.82	8,706,480.82	7,042,746.00	7,042,746.00

29 चरण–वार जोखिम और ह्रास हानि का विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
31 मार्च 2026 तक				
कुल एक्सपोजर	8,521,004.92	35,091.66	141,294.66	8,697,391.25
हानि भत्ता	128,067.32	21,759.55	94,886.30	244,713.16
ईसीएल %	1.50%	62.01%	67.15%	2.81%
31 मार्च 2025 तक				
कुल एक्सपोजर	7,169,670	46,561	235,297	7,451,529
हानि भत्ता	99,356	22,941	152,648	274,945
ईसीएल %	1.39%	49.27%	64.87%	3.69%

30. आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार प्रावधानों का समन्वय तथा चरण–वार अपेक्षित ऋण हानि का प्रकटीकरणः

31 मार्च 2026 को

(₹ लाख में)

भारतीय रिजर्व बैंके के मानदंडों के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण	भारतीय लेखाकंन मानक के अनुसार सकल धारणीय राशि	भारतीय लेखाकंन मानक 109 में अपेक्षित हानि भत्ता(प्रावधान)	निवल धारणीय राशि	आईआरसीपी मानदंडों के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	भारतीय लेखाकंन मानक 109 के प्रावधानों एवं आईआरसीपी मानदंडों के बीच अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	8,521,004.92	128,067.32	8,392,937.60	36,314.65	91,752.66
	चरण 2	35,091.66	21,759.55	13,332.12	483.10	21,276.44
	एफआईटीएल	1,143.62	1,143.62	-	1,143.62	-
उप–योग		8,557,240.20	150,970.48	8,406,269.72	37,941.38	113,029.11
गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
उप–मानक	**चरण 3**					
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	-	-	-	-	-
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	141,294.66	94,886.30	46,408.37	100,220.92	(5,334.63)
संदिग्ध उप–योग		141,294.66	94,886.30	46,408.37	100,220.92	(5,334.63)
हानि	**चरण 3**	-	-	-	-	-
एनपीए का उप–योग		141,294.66	94,886.30	46,408.37	100,220.92	(5,334.63)
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताओं आदि जैसी अन्य मदें, जो भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में आती हैं, लेकिन वर्तमान आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान संबंधी मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।	चरण 1					
	चरण 2					
	चरण 3					
उप–योग		-	-	-	-	-
	चरण 1	8,521,004.92	128,067.32	8,392,937.60	36,314.65	91,752.66
	एफआईटीएल	1,143.62	1,143.62	-	1,143.62	-
	चरण 2	35,091.66	21,759.55	13,332.12	483.10	21,276.44
	चरण 3	141,294.66	94,886.30	46,408.37	100,220.92	(5,334.63)
	कुल	**8,698,534.87**	**245,856.78**	**8,452,678.09**	**138,162.30**	**107,694.48**

31 मार्च 2025 को

(₹ लाख में)

आरबीआई के मानदंडों के अनुसार संपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसंपत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	भारतीय लेखा मानक 109 के तहत आवश्यक हानि भत्ते (प्रावधान)	शुद्ध वहन राशि	आईआरएसीपी नियमों के अनुसार जरूरी प्रावधान	इंड एएस 109 प्रोविजन और आईआरए सीपी नॉर्म्स के बीच अंतर
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादित परिसंपत्तियाँ						
मानक	चरण 1	7,169,670.23	99,355.76	7,070,314.47	28,776.22	70,579.54
	चरण 2	46,560.99	22,941.08	23,619.91	1,520.71	21,420.37
	एफआईटीएल	1,753.55	1,753.55	-	1,753.55	-
उप–योग		7,217,984.77	124,050.39	7,093,934.38	32,050.48	91,999.91
गैर–निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए)						
उप–मानक	**चरण 3**	23,678.72	11,666.75	12,011.97	2,367.87	9,298.88
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	चरण 3	-	-	-	-	-
1 से 3 वर्ष	चरण 3	33195.58497	20375.23486	12820.35012	9958.675492	10416.55936
3 वर्ष से अधिक	चरण 3	178422.9921	120605.8616	57817.13048	114115.2405	6490.621158
संदिग्ध उप–योग		211,618.58	140,981.10	70,637.48	124,073.92	16,907.18
हानि	**चरण 3**	0	0	0	0	0
एनपीए का उप–योग		235,297.30	152,647.85	82,649.45	126,441.79	26,206.06
गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताओं आदि जैसी अन्य मदें, जो भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में आती हैं, लेकिन वर्तमान आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान संबंधी मानदंडों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।	चरण 1			0		0
	चरण 2			0		0
	चरण 3			0		0
उप–योग		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	चरण 1	7,169,670.23	99,355.76	7,070,314.47	28,776.22	70,579.54
	एफआईटीएल	1,753.55	1,753.55	1,753.55	1,753.55	1,753.55
	चरण 2	46,560.99	22,941.08	23,619.91	1,520.71	21,420.37
	चरण 3	235,297.30	152,647.85	82,649.45	126,441.79	26,206.06
	कुल	**7,453,282.06**	**276,698.24**	**7,178,337.38**	**158,492.27**	**119,959.52**

31. यह भी सूचित किया जाता है कि

(क) कंपनी ने संबंधित सूचना ज्ञापन में उल्लिखित सुरक्षित गैर–परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) के मूलधन तथा अर्जित ब्याज के लिए सदैव पर्याप्त प्रतिभूति कवर बनाए रखा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 31 मार्च, 2026 तथा 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्षों के दौरान ऋण प्रतिभूतियों एवं उन पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं की है।

(ख) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है तथा बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत बेनामी संपत्ति रखने के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रारंभ या लंबित नहीं है।

(ग) कंपनी ने किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था भी शामिल है (जिसे आगे "मध्यस्थ" कहा गया है), को उधार ली गई निधियों, शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत अथवा प्रकार की निधियों से कोई अग्रिम राशि नहीं दी है, ऋण प्रदान नहीं किया है अथवा निवेश नहीं किया है, इस समझ के साथ कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (जिन्हें आगे "अंतिम लाभार्थी" कहा गया है) को ऋण देगा या उनमें निवेश करेगा अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था प्रदान करेगा। यह समझ लिखित रूप में दर्ज हो या किसी अन्य रूप में हो, दोनों ही स्थितियों में यह प्रावधान लागू है।

कंपनी को किसी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था भी शामिल है (जिसे आगे "निधि प्रदाता" कहा गया है), से ऐसी कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है, जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हो, इस समझ के साथ कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निधि प्रदाता द्वारा या उसकी ओर से किसी भी प्रकार से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थियों) को ऋण देगी या उनमें निवेश करेगी अथवा अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी प्रकार की अन्य व्यवस्था प्रदान करेगी। यह समझ लिखित रूप में दर्ज हो या किसी अन्य रूप में हो, दोनों ही स्थितियों में यह प्रावधान लागू है।

(घ) आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड तथा आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत नहीं हैं। इनके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण समेकन के उद्देश्य से अनुसूची III के भाग II के अनुसार तैयार किए गए हैं, जबकि आईआईएफसीएल एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है तथा इसके वित्तीय विवरण अनुसूची III के भाग III के अनुसार तैयार किए गए हैं।

(ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत रजिस्टर से हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

(च) नीति संख्या 1(क)(5.2)(क)(क) के अनुसार, ऋण परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित अग्रिम शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क अथवा अन्य कोई शुल्क, जो कुल आय के 0.5: से अधिक नहीं है, को प्रारंभ में लाभ एवं हानि विवरण में उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।

(छ) भारत सरकार ने दिनांक 9 फरवरी, 2012 के पत्र के माध्यम से आईआईएफसीएल को सूचित किया कि यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) की 41: इक्विटी का अधिग्रहण आईआईएफसीएल द्वारा किया जाएगा। यह निर्णय इस तथ्य के बावजूद लिया गया कि आईआईएफसीएल द्वारा अपनी गतिविधियाँ संचालित करने के लिए अपनाई जाने वाली व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण की योजना (सिफ्टी) के अंतर्गत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना आईआईएफसीएल के अधिदेश में शामिल नहीं था।

(ज) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टोकरेंसी अथवा आभासी मुद्रा में कोई कारोबार या निवेश नहीं किया है।

(झ) किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकार अथवा किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा कंपनी को जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ञ) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण के दौरान ऐसी कोई राशि आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं की गई है, जो वर्ष के दौरान कंपनी की लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं थी।

(ट) आईआईएफसीएल के दिनांक 21 जुलाई, 2021 के पत्र के प्रत्युत्तर में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए बॉन्ड/डिबेंचर की अभिदान के माध्यम से किए गए निवेश, जिसमें पुनर्वित्तपोषण भी शामिल है, चाहे वे निर्माणाधीन परियोजनाएँ हों अथवा पूर्ण हो चुकी परियोजनाएँ, आईआईएफसीएल की कुल परिसंपत्तियों का न्यूनतम 75: 'अवसंरचना ऋणों' में लगाने की आवश्यकता के प्रयोजन से 'अवसंरचना ऋण' माने जाएंगे।

तदनुसार, आईआईएफसीएल ने सकल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (सकल एनपीए) तथा निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (निवल एनपीए) अनुपातों के निर्धारण के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के बॉन्ड में अभिदान की राशि को शामिल किया।

हालाँकि, 31 मार्च, 2023 की वित्तीय स्थिति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रारंभिक निरीक्षण एवं जोखिम आकलन रिपोर्ट में यह टिप्पणी की कि कंपनी ने एनपीए अनुपातों की गणना करते समय बॉन्ड में अपने निवेश को ऋण एवं अग्रिम के भाग के रूप में शामिल किया था, जिसके परिणामस्वरूप ये अनुपात वास्तविक स्तर से कम दर्शाए गए। इस संबंध में, आईआईएफसीएल ने आरबीआई को अपना पक्ष प्रस्तुत किया कि अवसंरचना परियोजनाओं के बॉन्ड में अभिदान को ऋण एवं अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तदनुसार, सकल एनपीए तथा निवल एनपीए अनुपातों के निर्धारण के लिए अवसंरचना परियोजनाओं के बॉन्ड में अभिदान की राशि सहित ऋण एवं अग्रिम की कुल राशि को आधार माना जाता है।

(ठ) आईआईएफसीएल को ऋण खातों में वसूली के लिए दायर वादों सहित लंबित मुकदमों से किसी वित्तीय प्रभाव की आशंका नहीं है, सिवाय मानव संसाधन संबंधी मामलों में दायर दो मुकदमों के।

32. पिछले वर्ष के आँकड़े

जहाँ आवश्यक समझा गया है, वहाँ पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनर्समूहीकरण किया गया है।

फॉर्म एओसी–1

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष हेतु सहायक/सहायोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं का विवरण

भाग ''क'': सहायक कंपनियां

(₹ लाख/मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र. सं.	विवरण	I	II	III	
1	सहायक कंपनी का नाम	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लि.	आईआईएफसीएल ऐसेट मैनेमेंट कंपनी लि.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड	
				भारतीय रूपया	अमेरिकी डॉलर
2	वह तिथि, जिस दिन से सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया	14 फरवरी 2012	28 मार्च 2012	07 फरवरी 2008	
3	संबंधित सहायक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि वह होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में, संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा तथा विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं	अमेरिकी डॉलर (31 मार्च 2026 की विनिमय दरः 1 अमेरिकी डॉलर = ₹ 94.6543)	
5	शेयर पूंजी	475.00	1,250.00	103,076.15	150.00
6	आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2,179.69	1,350.01	39,274.85	0.04
7	कुल परिसंपत्तियाँ	3,336.99	2,896.84	826,104.56	871.29
8	कुल देयताएँ	682.30	116.83	683,753.56	720.89
9	निवेश	शून्य	शून्य	शून्य	
10	कारोबार	1,834.87	121.58	52,219.86	57.69
11	कर–पूर्व लाभ	5.45	90.68	8,942.50	9.43
12	कर हेतु प्रावधान	(10.15)	(96.49)	(108.11)	(0.12)
13	कर–पश्चात लाभ (अन्य समग्र आय सहित)	52.32	203.13	9,050.61	9.55
14	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य	शून्य	
15	शेयरधारण का प्रतिशत	100%	100%	100%	

टिप्पणियां:

1. सहायक कंपनियाँ जिन्हें अभी भी काम शुरू करना है – शून्य
2. सहायक कंपनियाँ जिन्हें वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया या बेच दिया गया – शून्य
3. भारतीय रुपए में परिवर्तन से पूर्व आईआईएफसी (यूके) लिमिटेड के वित्त में गैर–वित्तीय देयताओं मेंरिन आस्तियों पर प्रावधान के प्रकटीकरण हेतु समायोजन।

भाग "ख"रू सहयोगी संस्थाएँ एवं संयुक्त उद्यम

लागू नहीं

हमारी इसी दिनांक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

ह./–
कृते एबीपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 315104E

ह./–
कृते एडीबी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
पंजीकरण संख्या: 005593C

ह./–
सीए कमल कुमार चंडूका
भागीदार
सदस्यता संख्या: 058790

ह./–
सीए अमित तिवारी
भागीदार
डीआईएन: 408603

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29.05.2026

कृते इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर स

ह./–
रोहित ऋषि
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 11524681

ह./–
पलाश श्रीवास्तव
(उप प्रबंध निदेशक)
डीआईएन: 2007911

ह./–
रुचि सिंघल
(महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव)
सदस्यता संख्या: 17837

ह./–
राजीव मुखिजा
(मुख्य महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कॉर्पोरेट कार्य
ऑडिट भवन, आई.पी.एस्टेट
नई दिल्ली–110002

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
AUDIT BHAWAN, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

दिनांक / Date 05/08/2026

संख्याः एएमजी-II/28(4)/वार्षिक लेखापरीक्षा/IIFCL (CFS) (2025-26)/2026-27/ 235-236

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड,
5 वां तल, ब्लाक-2, प्लेट ए एवं बी, एनबीसीसी टॉवर
ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली- 110 023

विषय : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अन्तर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के साथ धारा 129 (4) के अन्तर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वार्षिक वित्तीय लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलगन पत्र अग्रेषित है।

भवदीय,

पवन
5/8/26

(डॉ पवन कुमार कोंडा)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

Ph. : +91-11-23702357 Fax : +91-11-23702359 Email : pdaica@cag.gov.in

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। बताया गया है कि लेखापरीक्षक ने 23 जुलाई 2026 की अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से ऐसा किया है, जो उनकी 29 मई 2026 की पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट का स्थान लेती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की, लेकिन उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी और आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सहायक कंपनियों) की पूरक लेखापरीक्षा नहीं की। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 139(5) और 143(6)(क) इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (यूके) लिमिटेड (सहायक कंपनी) पर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि यह एक विदेशी देश में वहाँ के संबंधित कानूनों के अंतर्गत निगमित संस्था है। ये धाराएँ उसके सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और पूरक लेखापरीक्षा के संचालन के संबंध में लागू नहीं होती हैं। तदनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने न तो इस कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इसकी पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यपत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक तथा कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक जाँच तक सीमित है। पूरक लेखापरीक्षा के दौरान मेरे द्वारा उठाई गई कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक ने लेखापरीक्षा रिपोर्ट को संशोधित किया है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूँगा, जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में समेकित वित्तीय विवरणों तथा संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होने के लिए आवश्यक हैं:

क वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

क.1 आस्तियां: ₹1,05,75,613.96 लाख

गैर-वित्तीय आस्तियां: ₹60,705.11 लाख

पूंजीगत कार्य प्रगति पर: ₹2,217 .96 लाख (टिप्पणी 10क)

कंपनी ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित अपने कार्यालय परिसर में आंतरिक सज्जा और फिट-आउट कार्यों के निष्पादन के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत ₹2,149.72 लाख थी और 20 मार्च 2026 तक एनबीसीसी को कुल ₹1,666.19 लाख का भुगतान किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, एनबीसीसी ने 20 मार्च 2026 को परियोजना की आगामी उपलब्धि के लिए ₹311.55 लाख का अतिरिक्त मांग पत्र/आरए बिल प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच कंपनी द्वारा की गई थी और एमओयू के प्रावधानों के अनुसार उसे जारी करने के लिए पात्र माना गया था। उक्त राशि का भुगतान बाद में 2 अप्रैल 2026 को किया गया।

हालांकि, वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी ने ₹311.55 लाख की मांग को मान्यता नहीं दी और पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत केवल ₹1,666.19 लाख दर्ज किए, जिसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी और संबंधित देयता में ₹311.55 लाख की कमी दर्शाई गई।

इसके अतिरिक्त, परियोजना 'सुपर' (एसएपी उन्नयन, संवर्धन और पुनर्सज्जा) के संबंध में, 31 मार्च 2026 तक हासिल की गई तीन उपलब्धियों के विरुद्ध मैसर्स एक्सेंचर द्वारा ₹746.65 लाख के बिल जारी किए गए थे। पहली उपलब्धि हासिल होने पर ₹149.33 लाख की राशि, जिसका बिल वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किया गया था, सीडब्ल्यूआईपी में दर्ज करने के बजाय आय में प्रभारित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में केवल ₹551.76 लाख (₹45.56 लाख के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाने के बाद) दर्ज किए गए हैं। तदनुसार, पहली उपलब्धि से संबंधित ₹149.33 लाख की राशि को लेखांकन नीति 4.7 के अनुसार चालू वर्ष के दौरान ठीक किया जाना आवश्यक था।

अंत:, उपर्युक्त के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी में ₹460.88 लाख (₹311.55 लाख + ₹149.33 लाख) की कमी, देयताओं में ₹311.55 लाख की कमी और वर्ष के लाभ में ₹149.33 लाख की कमी दर्शाई गई है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता./-
(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा
(उद्योग एवं कॉरपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05 अगस्त 2026

1. 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आईआईएफसीएल के एकल वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

आस्तियां: ₹1,05,75,613.96 लाख

गैर-वित्तीय आस्तियां: ₹60,705.11 लाख

पूंजीगत कार्य प्रगति पर: ₹2,217 .96 लाख (टिप्पणी 10क)

कंपनी ने नई दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित अपने कार्यालय परिसर में आंतरिक निर्माण और फिट-आउट कार्यों के निष्पादन के लिए एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया था। परियोजना की कुल स्वीकृत लागत ₹2,149.72 लाख थी और 20 मार्च 2026 तक एनबीसीसी को कुल ₹1,666.19 लाख का भुगतान किया जा चुका था। इसके अतिरिक्त, एनबीसीसी ने 20 मार्च 2026 को परियोजना की आगामी उपलब्धि के लिए ₹311.55 लाख का अतिरिक्त मांग पत्र/आरए बिल प्रस्तुत किया था, जिसकी जांच कंपनी द्वारा की गई थी और एमओयू के प्रावधानों के अनुसार उसे जारी करने के लिए पात्र माना गया था। उक्त राशि का भुगतान बाद में 2 अप्रैल 2026 को किया गया।

हालांकि, वर्ष 2025-26 के वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी ने ₹311.55 लाख की मांग को मान्यता नहीं दी और पूंजीगत कार्य प्रगति पर (सीडब्ल्यूआईपी) के अंतर्गत केवल ₹1,666.19 लाख दर्ज किए, जिसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी और संबंधित देयता में ₹311.55 लाख की कमी दर्शाई गई।

इसके अतिरिक्त, परियोजना 'सुपर' (एसएपी उन्नयन, संवर्धन और पुनर्सज्जा) के संबंध में, 31 मार्च 2026 तक हासिल की गई तीन उपलब्धियों के विरुद्ध मैसर्स एक्सेंचर द्वारा ₹746.65 लाख के बिल जारी किए गए थे। पहली उपलब्धि हासिल होने पर ₹149.33 लाख की राशि, जिसका बिल वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जारी किया गया था, सीडब्ल्यूआईपी में दर्ज करने के बजाय आय में प्रभारित कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीडब्ल्यूआईपी में केवल ₹551.76 लाख (₹45.56 लाख के जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटाने के बाद) दर्ज किए गए हैं। तदनुसार, पहली उपलब्धि से संबंधित ₹149.33 लाख की राशि को लेखांकन नीति 4.7 के अनुसार चालू वर्ष के दौरान ठीक किया जाना आवश्यक था।

अंत:, उपर्युक्त के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी में ₹460.88 लाख (₹311.55 लाख + ₹149.33 लाख) की कमी, देयताओं में ₹311.55 लाख की कमी और वर्ष के लाभ में ₹149.33 लाख की कमी दर्शाई गई है।

आईआईएफसीएल की कार्ययोजना:

यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) की टिप्पणी के अनुसरण में, लेखा बहियों में आवश्यक सुधारात्मक लेखांकन समायोजन किए गए हैं। नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आईआईएफसीएल के कार्यालय परिसर के आंतरिक साज-सज्जा और फिट-आउट कार्यों के संबंध में, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को देय राशि से संबंधित ₹311.55 लाख की राशि को 07.08.2026 के जर्नल वाउचर के माध्यम से एसएपी में निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में स्थानांतरित किया गया है। संदर्भ के लिए संबंधित वाउचर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, परियोजना सुपर (एसएपी उन्नयन, संवर्धन और पुनर्सज्जा) के संबंध में, ₹126.55 लाख की राशि (जीएसटी को छोड़कर) को 13.08.2026 के जर्नल वाउचर के माध्यम से एसएपी में निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में स्थानांतरित किया गया है। जीएसटी घटक को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पहले ही व्यय के रूप में लेखांकित किया जा चुका था और तदनुसार, जीएसटी को छोड़कर उपर्युक्त ₹126.55 लाख की राशि को सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित किया गया है। संदर्भ के लिए संबंधित वाउचर संलग्न है।

इस प्रकार, उपर्युक्त परियोजनाओं से संबंधित व्यय को सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत उचित रूप से दर्शाने के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन किए गए हैं।

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएनः U67190DL2006G0I144520

पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, ब्लॉक–2, प्लेट ए एण्ड बी, एनबीसीसी टॉवर,

ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

फोनः +91-11- 24662777, **फैक्सः** +91-11-20815125

सीआईएनः U67190DL2006G01144520

ईमेलः info@iifcl.in; **वेबसाइटः** www.iifcl.in

उपस्थिति पर्ची

उपस्थित होने वाले सदस्य का नाम (बड़े अक्षरों में)	
फोलियो	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (यदि सदस्य के स्थान पर प्रतिनिधि उपस्थित होता है तो बड़े अक्षरों में भरना अनिवार्य है)	

मैं एतद्द्वारा सोमवार, 28 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:30 बजे, सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में आयोजित कंपनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

टिप्पणीः

1. उपस्थिति पर्ची पर कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षर होने चाहिए। ऐसी पूर्ण और हस्ताक्षरित पर्ची/पर्चियों को बैठक स्थल पर कंपनी सचिव को सौंपा जाना चाहिए।
2. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया पहचान/सत्यापन के लिए फोटो पहचान पत्र साथ लाएं।
3. केवल व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित शेयरधारकों पर ही विचार किया जाएगा।
4. वार्षिक आम बैठक में कोई उपहार वितरित नहीं किए जाएंगे।

आई आई एफ सी एल
IIFCL

प्रपत्र संख्या एमजीटी 11

प्रतिनिधि प्रपत्र

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुपालन में]

सीआईएनः U67190DL2006GOI144520

कंपनी का नामः इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, ब्लॉक–2, प्लेट ए एण्ड बी, एनबीसीसी टॉवर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023

सदस्य(यों) का नामः	
पंजीकृत पताः	
ईमेल आई.डी.:	
फोलियो संख्या/क्लाइंट आईडीः	
डीपी आईडीः	

मै/हम उपरोक्त कंपनी के _____ शेयरों का/के सदस्य होने के नाते

1. नाम : _____
   पता : _____
   ईमेल आई.डी. : _____
   हस्ताक्षर : _____, अथवा के न आने पर
2. नाम : _____
   पता : _____
   ईमेल आई.डी. : _____
   हस्ताक्षर : _____, अथवा के न आने पर
3. नाम : _____
   पता : _____
   ईमेल आई.डी. : _____
   हस्ताक्षर : _____

मेरे/हमारे प्रॉक्सी के रूप में, नीचे दर्शाए गए प्रस्तावों के संबंध में मेरी/हमारी ओर से मतदान (मतपत्र द्वारा) करने तथा कंपनी की 21वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने के लिए, जो दोपहर 12:30 बजे सम्मेलन कक्ष, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 में आयोजित की जाएगी, तथा उक्त बैठक के किसी भी स्थगित सत्र में उपस्थित होने और मतदान करने हेतु नियुक्त किया जाता है।

संकल्प संख्या

1. _____
2. _____
3. _____

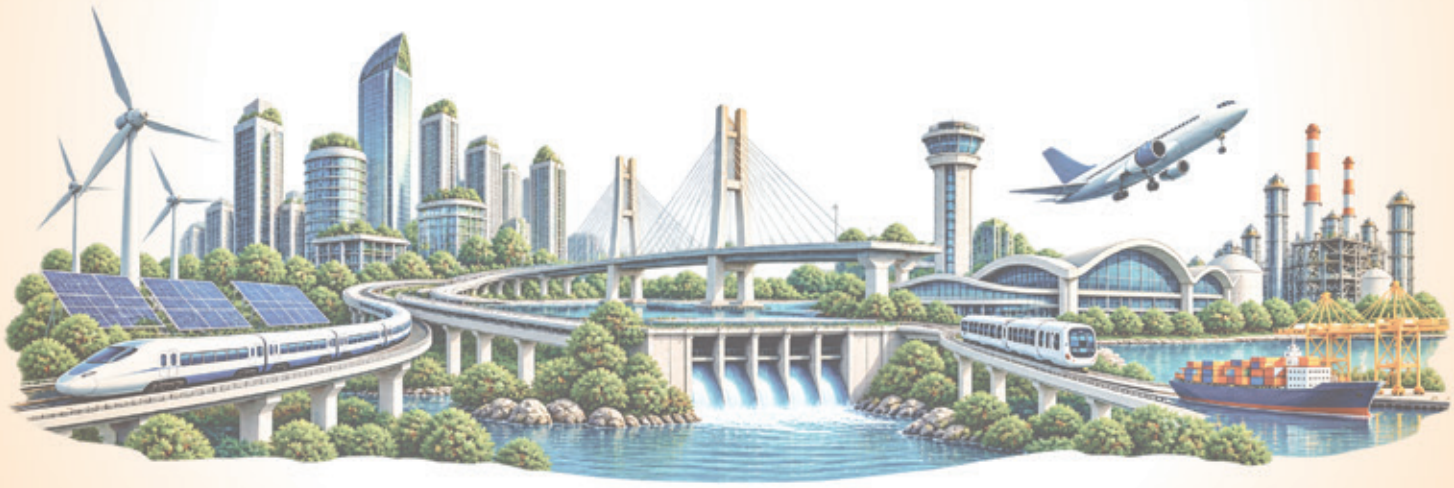
₹1 का राजस्व टिकट लगाएँ

2026 के ____ माह के _____ दिन हस्ताक्षरित

शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर

टिप्पणीः प्रॉक्सी का यह प्रपत्र तभी मान्य होगा, जब इसे विधिवत भरकर बैठक प्रारंभ होने से कम–से–कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कर दिया जाए।



आई आई एफ सी एल
IIFCL

इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

CIN:U67190DL2006GOI144520

5वीं मंज़िल, ऑफिस ब्लॉक 2, प्लेट A और B, NBCC टावर, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली - 110023
फ़ोन: +91-11-24662777; वेबसाइट: www.iifcl.in; ईमेल: information@iifcl.in